भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA

2021-22

भारतीय रिज़र्व बैंक

Reserve Bank of India

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुसार
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत
भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2021-22

भारतीय रिज़र्व बैंक

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2022
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400001 के लिए डॉ. स्नेहल एस. हेरवाडकर द्वारा प्रकाशित और उनके द्वारा ऐक्मे पैक्स और प्रिंट(I)प्रा.लि.,
ए विंग, गाला नं.73, विरवानी इंड्रस्ट्रियल इस्टेट, गोरेगाँव ईस्ट, मुंबई – 400063 में अभिकल्पित और मुद्रित।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

के.का.आनीअवि.बीआरडी. S1110/13.01.001/2022-23

27 दिसंबर 2022
6 पौष 1944 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय वित्त सचिव,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट की दो प्रतियां सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

शक्तिकान्त दास
27.12.22

शक्तिकान्त दास

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स : +91 22 2266 1784 ई-मेल : governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax : +91 22 2266 1784 E-mail : governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

विषय-वस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय I: परिप्रेक्ष्य		**1-7**
अध्याय II: वैश्विक बैंकिंग घटनाक्रम		**8-24**
1	भूमिका	8
2	वैश्विक समष्टि-आर्थिक स्थितियां	8
3	वैश्विक बैंकिंग नीतिगत घटनाक्रम	12
4	वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन	18
5	विश्व के सबसे बड़े बैंक	23
6	निष्कर्ष	24
अध्याय III: नीतिगत परिवेश		**25-43**
1	भूमिका	25
2	मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन	25
3	विनियामकीय नीतियां	29
4	पर्यवेक्षी नीतियाँ	37
5	प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण	38
6	वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा	39
7	ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेश	40
8	उपभोक्ता संरक्षण और खुदरा भागीदारी	41
9	भुगतान एवं निपटान प्रणाली	42
10	समग्र मूल्यांकन	43
अध्याय IV: वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन एवं प्रदर्शन		**44-94**
1	भूमिका	44
2	तुलन-पत्र विश्लेषण	44
3	वित्तीय प्रदर्शन	51
4	सुदृढ़ता संकेतक	56
5	क्षेत्रवार बैंक ऋण: वितरण तथा एनपीए	65
6	वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व का स्वरूप	72
7	कॉरपोरेट अभिशासन	73
8	भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन तथा भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन	74
9	भुगतान प्रणालियां तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	75
10	उपभोक्ता संरक्षण	78

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
11	वित्तीय समावेश	80
12	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	87
13	स्थानीय क्षेत्र के बैंक	89
14	लघु वित्त बैंक	90
15	भुगतान बैंक	91
16	समग्र मूल्यांकन	94
अध्याय V: सहकारी बैंकिंग घटनाक्रम		**95-116**
1	भूमिका	95
2	सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना	95
3	शहरी सहकारी बैंक	97
4	ग्रामीण सहकारी संस्थाएं	108
5	समग्र मूल्यांकन	116
अध्याय VI: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं		**117-151**
1	भूमिका	117
2	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	119
3	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	143
4	प्राथमिक व्यापारी	148
5	समग्र मूल्यांकन	151

बॉक्सों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम पर वित्तीय स्थितियों का असर	10
III.1	मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव और ऋण वृद्धि	27
III.2	जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त संबंधी सर्वेक्षण	32
III.3	एआरसी के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा	36
IV.1	वित्तीय स्थिरता पर बैंक की लाभप्रदता का प्रभाव	52
IV.2	बैंक की लाभप्रदता पर मौद्रिक नीति का प्रभाव	54
IV.3	बैंक समूहीकरण और प्रणालीगत जोखिम	66
V.1	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के निर्धारक	107
VI.1	एनबीएफसी के लिए नया विनियामकीय ढांचा	120

सारणियों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
III.1	एनबीएफसी-अपर लेयर के लिए बृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क	33
III.2	एनबीएफसी-यूएल द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	34
IV.1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र	45
IV.2	एससीबी के निवेश	48
IV.3	चुनिंदा देयताओं/ आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल	49
IV.4	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय और व्यय में रुझान	53
IV.5	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार	56
IV.6	एससीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता	56
IV.7	निजी आबंटन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन	58
IV.8	निवल स्थिर निधीकरण अनुपात	58
IV.9	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव	60
IV.10	बैंक समूह द्वारा ऋण आस्तियों का वर्गीकरण	60
IV.11	विभिन्न चैनलों के माध्यम से एससीबी के एनपीए की वसूली	62
IV.12	एआरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण	63
IV.13	रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी	64
IV.14	घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी	64
IV.15	प्रवर्तन कार्रवाइयाँ	65
IV.16	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय विनियोजन	65
IV.17	एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह	69
IV.18	बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	69
IV.19	पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम	70
IV.20	बैंकों के क्षेत्र-वार जीएनपीए	71
IV.21	बोर्ड की विभिन्न समितियों पर स्वतंत्र निदेशक	74
IV.22	भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन	74
IV.23	भुगतान प्रणाली संकेतक	76
IV.24	एटीएम की संख्या	77
IV.25	एटीएम का भौगोलिक वितरण: बैंक समूह-वार	78
IV.26	आरबीआईओ में शिकायतों की प्रकृति	79
IV.27	बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशि	80
IV.28	वित्तीय समावेश योजना में प्रगति	83
IV.29	एससीबी द्वारा नई खोली गई बैंक शाखाओं का स्तर-वार विश्लेषित-विवरण	85

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.30	टीआरईडीएस के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति	86
IV.31	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र	88
IV.32	आरआरबी द्वारा उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम	88
IV.33	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	88
IV.34	आरआरबी के पीएसएलसी लेनदेन	89
IV.35	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की प्रोफाइल	89
IV.36	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	90
IV.37	लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन पत्र	91
IV.38	लघु वित्त बैंकों द्वारा उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम	91
IV.39	लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	91
IV.40	भुगतान बैंकों का समेकित तुलन पत्र	92
IV.41	भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	92
IV.42	भुगतान बैंकों के चुनिंदा वित्तीय अनुपात	93
IV.43	भुगतान बैंकों के माध्यम से विप्रेषण	93
V.1	कृषि के लिए ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी	97
V.2	शहरी सहकारी बैंकों का टीयर-वार वितरण	98
V.3	शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र	99
V.4	जमाराशियों और अग्रिमों के आकार के अनुसार यूसीबी का विभाजन	101
V.5	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश	102
V.6	यूसीबी का रेटिंग-वार वितरण	103
V.7	यूसीबी का सीआरएआर-वार वितरण	103
V.8	यूसीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता	104
V.9	यूसीबी की अनर्जक आस्तियां	104
V.10	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	105
V.11	यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक	106
V.12	यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण का संघटन	106
V.13	ग्रामीण सहकारी संस्थानों का प्रोफाइल	109
V.14	राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	111
V.15	अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक	111
V.16	राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	112
V.17	राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	112

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.18	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	113
V.19	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	113
V.20	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	114
VI.1	नए विनियामकीय ढांचे के तहत गतिविधि के आधार पर एनबीएफसी का वर्गीकरण	120
VI.2	एनबीएफसी का स्वामित्व स्वरूप	122
VI.3	एनबीएफसी का संक्षिप्त तुलन पत्र	123
VI.4	वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी-एनडी-एसआई की देयताओं और आस्तियों के प्रमुख घटक	125
VI.5	एनबीएफसी द्वारा क्षेत्र-वार ऋण विनियोजन	128
VI.6	एनबीएफसी के उधार के स्रोत	129
VI.7	एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय मापदंड	134
VI.8	एचएफसी के स्वामित्व का स्वरूप	140
VI.9	एचएफसी का समेकित तुलनपत्र	140
VI.10	एचएफसी के वित्तीय मानदंड	142
VI.11	एआईएफआई द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	143
VI.12	एआईएफआई का तुलनपत्र	143
VI.13	वर्ष 2021-22 में एआईएफआई द्वारा जुटाये गए संसाधन	144
VI.14	एआईएफआई द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाये गए संसाधन	144
VI.15	एआईएफआई के संसाधनों का स्वरूप और निधियों का विनियोजन	145
VI.16	एआईएफआई का वित्तीय प्रदर्शन	146
VI.17	एआईएफआई के चुनिन्दा वित्तीय मापदंड	147
VI.18	प्राथमिक बाजार में पीडी का कार्यनिष्पादन	148
VI.19	जी-सेक द्वितीयक बाजार में एसपीडी का प्रदर्शन	149
VI.20	एसपीडी की निधियों के स्रोत और उपयोग	150
VI.21	एसपीडी का वित्तीय प्रदर्शन	150
VI.22	एसपीडी के वित्तीय संकेतक	150

चार्ट की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	समष्टि आर्थिक पृष्ठभूमि	9
II.2	मौद्रिक नीति दरें	10
II.3	निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण	19
II.4	आस्ति गुणवत्ता	20
II.5	प्रावधान कवरेज अनुपात	20
II.6	आस्तियों पर प्रतिलाभ	21
II.7	जोखिम-भारित आस्ति के लिए विनियामकीय पूंजी	21
II.8	लीवरेज अनुपात	22
II.9	बैंक की सेहत के बाज़ार-आधारित संकेतक	22
II.10	टीयर - I पूंजी के आधार पर शीर्ष 100 बैंकों का विभाजन	23
II.11	शीर्ष 100 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	24
II.12	शीर्ष 100 बैंकों की सुदृढ़ता	24
III.1	प्रमुख मौद्रिक नीतिगत दरें	29
IV.1	एससीबी की चुनिंदा समग्र राशियाँ	44
IV.2	तुलन पत्र की संरचना	46
IV.3	बचत और जमाराशियाँ	46
IV.4	उधार में वृद्धि	47
IV.5	अग्रिमों में वृद्धि	47
IV.6	वृद्धिशील ऋण- जनसंख्या समूह-वार	48
IV.7	ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात	49
IV.8	विभिन्न परिपक्वता खंडों में आस्तियों और देयताओं के अनुपात के बीच अंतराल	49
IV.9	भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएँ और आस्तियां	50
IV.10	बैंकों की तुलनपत्रेतर देयताएँ	51
IV.11	लाभप्रदता अनुपात	51
IV.12	एससीबी का जी-सेक प्रतिफल और गैर-ब्याज आय	54
IV.13	एससीबी का व्यय	55
IV.14	लाभप्रदता पर प्रावधानीकरण का प्रभाव	55
IV.15	एससीबी की आरडब्ल्यूए और आस्तियों की वृद्धि	57
IV.16	पूंजी पर्याप्तता	57
IV.17	लीवरेज और चलनिधि	58
IV.18	बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	59

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.19	जीएनपीए में कमी	59
IV.20	बड़े उधार खातों में दबाव की तुलना में समग्र दबाव	61
IV.21	पुनर्रचना	61
IV.22	एआरसी को दबावग्रस्त आस्ति की बिक्री	63
IV.23	बैंक समूह-वार धोखाधड़ी	65
IV.24	खुदरा ऋण	66
IV.25	आवास ऋण	67
IV.26	शिक्षा ऋण	68
IV.27	एमएसएमई बनाम बड़े उद्योग	68
IV.28	पीएसएलसी की व्यापारिक मात्रा	70
IV.29	संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर	71
IV.30	गैर-जमानती अग्रिमों का हिस्सा	72
IV.31	बैंक समूह-वार स्वामित्व स्वरूप	72
IV.32	पीएसबी में सरकार की हिस्सेदारी	72
IV.33	कुल पारिश्रमिक में परिवर्ती वेतन का हिस्सा	73
IV.34	सीईओ वेतन बनाम औसत कर्मचारी वेतन	74
IV.35	भुगतान प्रणालियों के घटक	75
IV.36	आरबीआई- डिजिटल भुगतान सूचकांक	76
IV.37	शिकायतों का वितरण	79
IV.38	जी-20 देशों में वित्तीय समावेश में प्रगति	81
IV.39	वित्तीय समावेश संकेतक	82
IV.40	एफबीसी का राज्यवार वितरण	83
IV.41	एफबीसी का बैंक समूह-वार वितरण	83
IV.42	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या	84
IV.43	पीएमजेडीवाई खातों का विवरण और औसत शेष	84
IV.44	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नई खोली गई बैंक शाखाओं का विभाजन	85
IV.45	एसएचजी - औसत वितरित ऋण, औसत ऋण बकाया और एसएचजी की औसत बचत	86
IV.46	प्रति बैंक शाखा क्षेत्रवार औसत जनसंख्या	87
IV.47	विविध आय में पीएसएलसी का योगदान	89
IV.48	पीबी की भुगतान प्रणाली लेनदेन	93
V.1	सहकारी बैंकों की संरचना	96

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.2	आस्ति के आकार के अनुसार सहकारी बैंकों का विभाजन	96
V.3	यूसीबी की संख्या	97
V.4	यूसीबी के समेकन अभियान	98
V.5	आस्ति वृद्धि	99
V.6	जमाराशि एवं अग्रिम: यूसीबी	100
V.7	ऋण – जमा अनुपात: यूसीबी बनाम एससीबी	100
V.8	आस्ति के आकार के अनुसार यूसीबी का विभाजन	100
V.9	यूसीबी की जमाराशियां और अग्रिम का वितरण	101
V.10	यूसीबी के निवेश	102
V.11	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और कारोबार का वितरण - रेटिंग के आधार पर	103
V.12	9 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले यूसीबी की हिस्सेदारी	103
V.13	बड़े उधार खातों में दबाव	105
V.14	लाभप्रदता संकेतक - एसयूसीबी बनाम एनएसयूसीबी	106
V.15	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार	107
V.16	दीर्घावधि बनाम अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं	109
V.17	अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की तुलना (तुलन-पत्र और वित्तीय-निष्पादन)	110
V.18	अल्पावधि सहकारी संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता: एक तुलना	114
V.19	दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां: एक तुलना	116
VI.1	रिज़र्व बैंक के विनियमन के तहत एनबीएफआई की संरचना	118
VI.2	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण और जीडीपी की *तुलना में* एनबीएफसी के ऋण	119
VI.3	एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पंजीकरण और निरसन	122
VI.4	एनबीएफसी ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण	124
VI.5	वर्गीकरण-वार एनबीएफसी-एनडी-एसआई: चुनिंदा संकेतक	125
VI.6	एनबीएफसी ऋण का वितरण	126
VI.7	एमएसएमई क्षेत्र को एनबीएफसी का ऋण	126
VI.8	वाहन ऋण- एनबीएफसी *बनाम* एससीबी	127
VI.9	स्वर्ण के एवज में अग्रिमों का वितरण: एनबीएफसी और एससीबी	127
VI.10	वर्गीकरण के अनुसार ऋण का क्षेत्रवार विभाजन	128
VI.11	विनियमित संस्थाओं में बकाया माइक्रो-क्रेडिट ऋण	129
VI.12	एनबीएफसी के उधारियों की चुकौती	129
VI.13	निजी एनबीएफसी का एनसीडी प्राइवेट प्लेसमेंट	130

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
VI.14	एनबीएफसी बॉन्ड का प्रतिफल: तदनुरूप परिपक्वता अवधि के जी-सेक पर स्प्रेड	130
VI.15	एनबीएफसी को बैंक ऋण, समूह-वार	131
VI.16	एनबीएफसी को बैंक ऋण की लिखतें	131
VI.17	एनबीएफसी-डी में जनता की जमाराशियाँ	132
VI.18	एनबीएफसी-डी में जमाराशियों का वितरण	132
VI.19	एनबीएफसी-एनडी-एसआई की ऋण बिक्री और प्रतिभूतिकरण	132
VI.20	एनबीएफसी की संरचनात्मक चलनिधि विवरणी	133
VI.21	एनबीएफसी के लाभप्रदता अनुपात	134
VI.22	एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लाभप्रदता संकेतक	134
VI.23	एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता	135
VI.24	एनबीएफसी का प्रावधान कवरेज अनुपात	135
VI.25	एनबीएफसी आस्तियों का वर्गीकरण	135
VI.26	अर्जक आस्तियों में चूक (डेलिंक्वेंसी)......................	136
VI.27	एनबीएफसी-एनडी-एसआई की अनर्जक आस्तियां	136
VI.28	एनबीएफसी की अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार वितरण	137
VI.29	एनबीएफसी-डी के सकल और निवल एनपीए अनुपात	137
VI.30	बड़े उधार खातों में दबाव	137
VI.31	एनबीएफसी क्षेत्र की पूंजीगत स्थिति	138
VI.32	एनबीएफसी का सीआरएआर – श्रेणीवार	138
VI.33	संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर	139
VI.34	एचएफसी और एससीबी द्वारा आवास क्षेत्र को क्रेडिट	139
VI.35	एचएफसी द्वारा जुटाए गए संसाधन	141
VI.36	एचएफसी में जनता की जमाराशियां	141
VI.37	एचएफसी में जनता की जमाराशियों का विभाजन	141
VI.38	एचएफसी के जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात	142
VI.39	एआईएफआई द्वारा जुटाये गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता	145
VI.40	चुनिन्दा एआईएफआई की दीर्घावधि पीएलआर संरचना	146
VI.41	एआईएफआई के वित्तीय अनुपात	146
VI.42	एआईएफआई के चुनिंदा वित्तीय मापदंड	147
VI.43	एआईएफआई के एनएनपीए अनुपात	147
VI.44	एआईएफआई का आस्ति वर्गीकरण	148
VI.45	पीडी के हामीदारी कमीशन की औसत दर	149
VI.46	एसपीडी की पूंजी और जोखिम-भारित आस्तियों की स्थिति	150

परिशिष्ट सारणियों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.1	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, एक नज़र में	152
IV.2	भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - लिखतों के प्रकार के आधार पर	153
IV.3	भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - लिखतों के प्रकार के आधार पर	154
IV.4	बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे: अवशिष्ट परिपक्वता और क्षेत्र	155
IV.5	भारत के अलावा अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	156
IV.6	भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	157
IV.7	किसान क्रेडिट कार्ड योजना*: राज्य-वार प्रगति	158
IV.8	संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार	160
IV.9	घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप	161
IV.10	भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन	164
IV.11	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम	165
IV.12	आरबीआई लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण	168
IV.13	सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रगति	172
IV.14	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य वित्तीय संकेतक: राज्य-वार	173
IV.15	आरआरबी- पीएसएल लक्ष्य और उपलब्धि- 2021-22	175
IV.16	रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी	176
V.1	अनुसूचित यूसीबी के चुनिंदा वित्तीय मानदंड	179
V.2	वित्तीय प्रदर्शन के संकेतक: अनुसूचित यूसीबी	181
V.3	राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के संकेतक	183
V.4	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाले प्रमुख संकेतक	184
V.5	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	185
V.6	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक – राज्य-वार	186
V.7	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों और उधारकर्ताओं का विवरण	188
V.8	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	189
V.9	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	190
V.10	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	191
V.11	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य वित्तीय संकेतक	192
V.12	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	193
V.13	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन	194

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.14	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	195
V.15	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य वित्तीय संकेतक	196
VI.1	एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र	197
VI.2	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन पत्र	198
VI.3	एनबीएफसी-डी का समेकित तुलन पत्र	199
VI.4	एनबीएफसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ऋण	200
VI.5	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का वित्तीय प्रदर्शन	201
VI.6	जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी का वित्तीय प्रदर्शन	202
VI.7	वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	203
VI.8	प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय प्रदर्शन	207
VI.9	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक	209

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एडी – 1	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – 1
एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं
एईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणालियां
एएफए	प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध
एआई/एमएल	कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग
एआईडी	सभी समावेशी निदेश
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
एएमएल	धन-शोधन निवारण
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक ऋण
एपीआर	वार्षिक प्रतिशत दर
एक्यूआर	आस्ति गुणवत्ता जांच
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
एआरडीएल-ईसी	एरर करेक्शन के साथ ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल
एएसआईएसओ	स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट
बीबीपीओयू	भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां
बीबीपीएस	भारत बिल भुगतान प्रणाली
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीसी-आईसीटी	कारोबारी प्रतिनिधि – सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी
बीसी	कारोबारी प्रतिनिधि
बीईआई	बैंकिंग प्रत्याशा सूचकांक
बीएफएससीआई	ब्लूमबर्ग अमेरिकी वित्तीय स्थिति सूचकांक
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीआईएसआईएच	बीआईएस इनोवेशन हब
बीओएस	बैंकिंग लोकपाल योजना

बीपीएस	आधार अंक
बीएसबीडीए	बुनियादी बचत बैंक जमा खाता
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सीएएसए	चालू खाता और बचत खाता
सीबीडीसी	केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीसी	संपर्क केंद्र
सीसीबी	पूंजी संरक्षण बफर
सीसीओ	मुख्य अनुपालन अधिकारी
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
सी-डी	ऋण-जमा
सीडीएस	ऋण चूक स्वैप
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीईपीसी	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष
सीईटी	सामान्य इक्विटी टीयर
सीएफएल	वित्तीय साक्षरता केंद्र
सीएफएसएस	कोर वित्तीय सेवा समाधान
सीजीएफएमयू	सूक्ष्म इकाई ऋण गारंटी निधि
सीआई	विश्वास अंतराल
सीआईसीईआरओ	सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च
सीआईसी	मूल निवेश कंपनी
सीआईसी	साख सूचना कंपनियां
सीआईएमएस	केंद्रीकृत सूचना और प्रबंधन प्रणाली
सीआईआरपी	कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीआईएसबीआई	बैंकिंग अवसंरचना के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली
सीएमबी	नकदी प्रबंधन बिल
सीएमई	पूंजी बाजार एक्सपोजर

सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीओवीएआर	जोखिम पर सशर्त मूल्य
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीएमआई	भुगतान और बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी समिति
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरए	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां
सीआरई	वाणिज्यिक स्थावर संपदा
सीआरई-आरएच	वाणिज्यिक स्थावर संपदा - आवासीय आवास
सीआरआईएलसी	बड़े ऋण से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार
सीआरएम	ऋण जोखिम शमन
सीआरएम	नकद पुनर्चक्रण मशीनें
सीआरओ	प्रमुख जोखिम अधिकारी
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएसआरडी	कॉरपोरेट सस्टेनबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव
सीवीए	ऋण मूल्यांकन समायोजन
डीएवाई-एनआरएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीबीयू	डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीएफआई	विकास वित्त संस्थान
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	निक्षेप बीमा निधि
डीएलए	डिजिटल उधार एप्लिकेशन
डीपी	चर्चा पत्र
डीपीआई	डिजिटल भुगतान सूचकांक

डी-एसआईबी	घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक
डीटीएच	डायरेक्ट-टू-होम
ईबीएलआर	बाह्य बेंचमार्क संबद्ध उधार दर
ईसीबी	यूरोपीय केंद्रीय बैंक
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीएल	प्रत्याशित ऋण हानि
ईसीएलजीएस	आपातकालीन ऋण गारंटी योजना
ईजीएआरसीएच	एक्स्पोनेंशियल जेनेरलाइज्ड ऑटोरिग्रेसिव कंडिशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी
ईएमडीई	उभरती बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ईएनडबल्यूआर	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य गोदाम रसीद
ईएसजी	पर्यावरणीय, समाज और गवर्नन्स
एक्जिम बैंक	भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफएडीए	फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन
एफएएस	वित्तीय पहुँच सर्वेक्षण
एफबीसी	नियत-स्थान कारोबारी प्रतिनिधि
एफबी	विदेशी बैंक
एफसीआई	वित्तीय स्थिति सूचकांक
एफसीएनआर (बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता-(बैंक)
एफसीएस-ओआईएस	विदेशी मुद्रा निपटान ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप
एफआई	वित्तीय संस्थाएं
एफआई-इंडेक्स	वित्तीय समावेश सूचकांक
एफआईपी	वित्तीय समावेश योजना
एफएलसी	वित्तीय साक्षरता केंद्र

एफएमआई	वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर
एफपीसी	उचित व्यवहार संहिता
एफआरआरआर	स्थायी दर रिवर्स रेपो
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडब्ल्यूएम	वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित
जीसीसी	सामान्य क्रेडिट कार्ड
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट
जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्तियां
जी-एसएपी	सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम
जी-सेक	सरकारी प्रतिभूतियाँ
एचएफसी	आवास वित्तीय कंपनियाँ
एचएफटी	व्यापार के लिए रखा गया
एचओ	प्रधान कार्यालय
एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
आईएसी	स्वतंत्र सलाहकार समिति
आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईसीसीडबल्यू	इंटरऑपरेबल कार्ड-रहित नकद निकासी
आईसीएमए	इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन
आई-डी	निवेश-जमा
आईएफआर	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आईआईएस	प्रतिभूतियों में निवेश
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएनआर	भारतीय रुपये
आईओ	आंतरिक लोकपाल
आईपीओ	आरंभिक सार्वजनिक निर्गम
आईआरबी	आंतरिक रेटिंग-आधारित
आईआरआरबीबी	बैंकिंग बही खाता में ब्याज दर जोखिम
आईएसएसबी	अंतरराष्ट्रीय धारणीयता मानक बोर्ड
आईवीआर	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केएफएस	मुख्य तथ्य विवरण
केएमपी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
केपीआई	मुख्य प्रदर्शन संकेतक
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
केयूए	केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र के बैंक
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलसीआर	चलनिधि/कवरेज अनुपात
एलईएफ	बृहत् एक्सपोजर फ्रेमवर्क
एलई	विधिक संस्था
एलआईबीओआर	लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
एलआर	कर्जभार (लीवरेज) अनुपात
एलएसपी	ऋण सेवा प्रदाता
एलटीवी	मूल्य की तुलना में ऋण
एम-सीबीडीसी	बहु-केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा
एमडी	मास्टर निदेश
एमआईबीओआर	मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
एमआईजीआर	न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग
एमएमएफ	मुद्रा बाजार निधि
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

एमटीएम	मार्क-टू-मार्केट
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएबीएफआईडी	राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण और विकास बैंक
एनएसीएच	राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनबीएफसी-एए	एनबीएफसी– खाता समूहक
एनबीएफसी-बीएल	एनबीएफसी बेस लेयर
एनबीएफसी-आईसीसी	एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनियां
एनबीएफसी-आईडीएफ	एनबीएफसी– इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज़ निधि
एनबीएफसी-आईएफसी	एनबीएफसी - इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी
एनबीएफसी-एमएफआई	एनबीएफसी – सूक्ष्म वित्त संस्थाएं
एनबीएफसी-एमएल	एनबीएफसी-मिडल लेयर
एनबीएफसी-एनओएफएचसी	एनबीएफसी गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एनबीएफसी-पी2पी	एनबीएफसी – समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-डी	जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी
एनबीएफसी-एनडी	जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-टीएल	एनबीएफसी टॉप लेयर
एनबीएफसी-यूएल	एनबीएफसी अपर लेयर
एनबीएफआई	गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता
एनबीएफआई	गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ
एनबीएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
एनसीसीडी	गैर-केंद्रीय समाशोधित व्युत्पन्नी

एनसीडी	अपरिवर्तनीय डिबेंचर
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनडीएस-ओएम	तयशुदा लेनदेन प्रणाली - ऑर्डर मिलान
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएँ
एनईडी	गैर - कार्यकारी निदेशक
एनजीएफएस	वित्तीय प्रणाली हरितकरण नेटवर्क
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईआई	निवल ब्याज आय
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
एनएनपीए	निवल अनर्जक आस्तियां
एनओएफ	निवल स्वाधिकृत निधि
एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीएल	अनर्जक ऋण
एनआरसी	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
एनआरओ	अनिवासी साधारण
एनएसएफआई	वित्तीय समावेश हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति
एनएसएफआर	निवल स्थिर निधीयन अनुपात
एनएसयूसीबी	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
एनडबल्यूआर	तयशुदा गोदाम रसीद
ओ-एआरआर	ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर
ओडी	ओवरड्राफ्ट
ओईएफ	निर्बंध निधि
ओएफसीबी	समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार
ओआईएस	ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप
ओएमओ	खुला बाजार परिचालन
ओएसडीटी	डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना

ओएसएनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना
ओटीसी	काउंटर पर
ओटीएस	एकमुश्त निपटान
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
पीबी	भुगतान बैंक
पीसीए	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
पीसीआर	प्रावधान कवरेज अनुपात
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीएलआई	उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन
पीएलआर	मूल उधार दर
पीएमएवाई-जी	प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण
पीएमएवाई-यू	प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी
पीएमसीबीएल	पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड
पीएमजेडीवाई	प्रधान मंत्री जन धन योजना
पीएमएल	धन शोधन निवारण
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसएल	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार
पीएसएलसी	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाण-पत्र
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक
क्यूबी	अर्हित क्रेता
आरबीआईएच	रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र
आरबी-आईओएस	रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना
आरडीजी	रिटेल डायरेक्ट गिल्ट
आरईई	स्थावर संपदा एक्सपोजर
आरई	विनियमित संस्था
आरएमसीबी	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरआर	आरक्षित अनुपात
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएस	विनियामकीय परीक्षण स्थल
आरएसए	पुनर्रचित मानक अग्रिम
आरटी	जोखिम सीमाएँ
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान
आरडबल्यूए	जोखिम भारित आस्तियां
एसएआरएफएईएसआई अधिनियम	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम
एसबीएम-जी	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
एसबीआर	स्केल आधारित विनियमन
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडीएफ	स्थायी जमा सुविधा
एसई	पर्यवेक्षित संस्थाएं
एसएफ/ एमएफ	छोटे और सीमांत किसान
एसएफबी	लघु वित्त बैंक
एसएफजी	स्थायी वित्त समूह
एसजीबी	सॉवरेन गोल्ड बांड
एसएचजी-बीएलपी	स्वयं-सहायता समूह बैंक-संबद्धता कार्यक्रम
एसएचजी	स्वयं-सहायता समूह
एसआईएएम	सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स
एसआईडीबीआई	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसएलएफ	विशेष चलनिधि सुविधा
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात

एसएलटीआरओ	विशेष तीन-वर्षीय दीर्घावधि रिपो परिचालन
एसएमए	विशेष उल्लेखनीय खाते
एसएमई	लघु और सूक्ष्म उद्यम
एसएमएफ	लघु एवं सीमांत किसान
एसपीडी	एकल प्राथमिक व्यापारी
एसपीओ	द्वितीय पक्ष विचार
एसआर	प्रतिभूति रसीद
एसएसबी	मानक निर्धारण निकाय
एसएसई	संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
टीबीटीएफ	इतने बड़े कि डूबे ना (टू-बिग-टू-फेल)
टीसीएफडी	जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण संबंधी कार्य बल
टीएलएसी	कुल हानि-सहनीय क्षमता
टीएलटीआरओ	लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन
टीआर	व्यापार रिपोजिटरी
टीआर	कुल पारिश्रमिक
टीआरईडीएस	व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली
टीआरईपीएस	त्रिपक्षीय रिपो लेनदेन और निपटान
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूएस	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसएफबी	यूनिटी स्माल फ़ाइनेंस बैंक
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वीएआर	वेक्टर ऑटो रिग्रेशन
वीएआर	जोखिम पर मूल्य
वीपी	परिवर्तनीय वेतन
वीआरआर	परिवर्तनीय दर रेपो
वीआरआरआर	परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो
डब्ल्यूएसी	भारित औसत लागत
डब्ल्यूएपी	भारित औसत प्रीमियम
डब्ल्यूईओ	वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
डब्ल्यूजीडीएल	डिजिटल ऋण पर कार्य समूह
डब्ल्यूओएस	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

I परिप्रेक्ष्य

विश्व भर में बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों को मुद्रास्फीति के वैश्वीकरण, मौद्रिक नीति के एक साथ सख़्त होने और वृद्धि के प्रति बने हुए भू-राजनीतिक जोखिमों से उत्पन्न प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि वर्तमान में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र बेहतर आस्ति गुणवत्ता ओर सुदृढ़ पूँजी बफ़र के साथ मजबूत और प्रत्यास्थी (रेजिलिएंट) बना हुआ है, फिर भी, नीति निर्माता गतिमान रूप से उभरती उन समष्टि आर्थिक स्थितियों को लेकर सजग हैं जो विनियमित संस्थाओं के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक का ध्यान इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ संभावित प्रणालीगत जोख़िमों को रोकने पर बना रहेगा।

I.1 2022 में, मुद्रास्फीति के वैश्वीकरण, ऊर्जा एवं खाद्य की कमी और दुनिया भर में मौद्रिक नीति के एक साथ सख्त होने से, वैश्विक वृद्धि और व्यापार के लिए परिदृश्य बिगड़ रहा है। पूँजी बहिर्गमन, मुद्रा मूल्यह्रास और आरक्षित निधि में क्षय के मिश्रण ने उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए संभावनाओं को बदतर किया है जिससे उनकी वित्तीय प्रणालियों को अधिक अनिश्चितताओं और अधोगामी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय स्थितियां तंग हो गई हैं, तथापि हाल में मुद्रास्फीति के शिखर पर आ चुके होने से जुड़ी प्रत्याशाओं से मनोभावों में सुधार हुआ है। यद्यपि वैश्विक बैंक मजबूत दिखते हैं, लेकिन कमजोर वृद्धि के साथ बढ़ते ब्याज दर के माहौल में आस्ति गुणवत्ता दबाव में आ सकती है। जैसे-जैसे प्रतिफल बढ़ेगा, बैंकों को अपने निवेश संविभाग पर मार्क-टू-मार्केट (एमटूएम) का खर्च उठाना पड़ सकता है और उच्चतर प्रावधानीकरण अपेक्षाएं उनकी लाभप्रदता पर चोट पहुँचा सकती हैं।

I.2 इस अत्यंत अनिश्चित वैश्विक परिवेश में, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मूलभूत समष्टि-आर्थिक आधार पर वृद्धि वेग के क्रमश: बलवान होने के संकेत दे रही है। 2021-22 और 2022-23 में भी अब तक ऋण की पुष्ट मांग के दम पर भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के तुलनपत्रों ने मजबूती से विस्तार प्राप्त किया है। उनकी आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता सुधरी है जबकि कम गिरावट और ऊँचे पूँजी बफ़र बैंकों में निवेशक विश्वास को दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं।

I.3 कोविड – 19 के कमजोर पड़ने के साथ 2021-22 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र के लाभ सुधरे। मजबूत पूँजी बफ़र, यथोचित प्रावधान और पर्याप्त तरलता से युक्त एनबीएफसी विस्तार के लिए तैयार हैं। फिर भी, आगे चलकर, तंग वित्तीय स्थितियों के मद्देनज़र एनबीएफसी को उधार की बढ़ती लागतों को लेकर सावधान रहना होगा। विनियामकीय मोर्चे पर, आकार आधारित (स्केल बेस्ड) विनियमन से इस क्षेत्र में स्वाभाविक सावयव समेकन (ऑर्गेनिक कॉन्सॉलिडेशन) के बढ़ते दायरे के साथ एनबीएफसी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

I.4 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग क्षेत्रों के सम्मुख आई चुनौतियों तथा आगे की राह पर एक विहंगम दृष्टि डालता है।

बैंक लाभप्रदता पर बढ़ती ब्याज दरों का प्रभाव

I.5 बढ़ती ब्याज दरों के परिवेश में, निकट भविष्य में बैंकों की निवल ब्याज आय (एनआईआई) में वृद्धि की प्रत्याशा की जा सकती है, जो जमाराशि दरों की तुलना में उधार की दरों में बेहतर संचरण का द्योतक होगा। दूसरी ओर, उच्च प्रतिफल से बैंकों के लिए उनके ट्रेजरी निवेश पर एमटीएम हानि की संभावना

बनती है, जिससे उनकी ब्याजेतर आय कम हो जाती है। एससीबी की लाभप्रदता पर बढ़ते प्रतिफल का असर परिपक्वता तक धारित संविभाग (एचटीएम पोर्टफोलियो) के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में वृद्धि के कारण कुछ हद तक कम हुआ है।[1] असर को कम करने वाला एक और कारक है निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) जिसे 2018 में शुरू किया गया था। संशोधित अवधि पर चुनिंदा बैंकों के सितंबर 2022 के अंत के आँकड़ों ने दर्शाया कि, यदि अन्य बातें पूर्ववत् रहें, तो प्रतिफल में वृद्धि से होने वाली एमटीएम क्षतियों हेतु आवश्यक प्रावधान करने के बाद भी बैंक पर्याप्त पूँजीकृत रहेंगे।

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

I.6 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का अधिनियमन भारत में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के प्रतिमानों में ध्रुवीय परिवर्तन था। तथापि हाल के वर्षों में, इस प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत दावों की तुलना में वसूली की दरों में गिरावट चिंता का कारण बनी है।[2] वसूली दर समग्र समष्टि आर्थिक परिवेश, इकाई और उसके क्षेत्र की विकास संभावनाओं के बारे में अवधारणा, और उस इकाई के आंतरिक मूल्य में क्षरण की सीमा सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। बहाली के व्यापक आधार पर पैर जमाने से, वित्तीय समाधान हेतु इन कारकों के अनुकूल होने की संभावना है।

I.7 आईबीसी जैसे सावर्जनिक नीलामी आधारित समाधान मॉडल में, हेयरकट की सीमा उस छूट (डिस्काउंट) को दर्शाती है जिसकी मांग बाजार दबावग्रस्त इकाई को एक कार्यशील संस्था के रूप में अधिगृहित करने के लिए करता है। चूँकि इन आस्तियों में पहले ही मूल्य नाश काफी हो गया होगा, तो संभव है कि स्वीकृत दावों की अर्जित मूल्य से तुलना इस समाधान प्रक्रिया के प्रभावी होने का समुचित संकेतक न हो। बल्कि, समाधान मूल्य की तुलना दबावग्रस्त आस्तियों के परिसमापन मूल्य से की जा सकती है। आँकड़े बताते हैं कि सितंबर 2022 के अंत की स्थिति के अनुसार उन मामलों में जहाँ वित्तीय लेनदारों (एफसी) ने कॉरपोरेट दिवाला और समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) प्रारंभ की, वहाँ आईबीसी के जरिये वसूली परिसमापन मूल्य के 201 प्रतिशत के आस-पास रही।

I.8 आईबीसी ढाँचे में समाधान आवेदन को स्वीकार करने के साथ-साथ अंतिम समाधान और परिसमापन में लगने वाला समय लगातार बढ़ा है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने हाल में सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किए जिनका उद्देश्य अर्जित मूल्य में सुधार करना, प्रक्रिया में विलंब को कम करना, उपलब्ध समय की कार्य-क्षमता को बढ़ाना और सूचना उपलब्धता में सुधार करना है। आईबीसी विनियमों में एक अन्य संशोधन द्वारा दिवाला पेशेवरों/व्यावसायिकों (प्रोफेशनल्स) के लिए कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहनों की शुरुआत की गई है जिससे दबावग्रस्त आस्तियों के प्राप्त मूल्य को उनके परिसमापन मूल्य के परे अधिकाधिक बढ़ाने तथा समय से उनके समाधान में सहायता मिलनी चाहिए।

I.9 पहले से तैयार दिवाला समाधान प्रक्रिया में कोर्ट से बाहर के समाधान प्रयासों और समाधान योजना के न्यायिक समापन के सर्वोत्तम पक्षों का मिश्रण है। यह व्यवस्था, जो केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए है, बढ़ाकर यदि सभी उधारकर्ताओं के लिए कर दी जाए तो रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण ढाँचे का प्रभावी पूरक हो सकती है। भारत में ऋण संविदाओं (क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स) में प्राय: प्रति-दायित्व और उधारकर्ता की मूल कंपनी व समूह कंपनियों द्वारा प्रदत्त ऋण जोख़िम कम करने वाले कवच (कवर) शामिल होते

[1] अक्टूबर 2020 में, बैंकों को (पहले के 19.5 प्रतिशत के बजाय) एनडीटीएल के 22 प्रतिशत की समग्र सीमा तक एचटीएम सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी, जिससे बैंकों के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश की गुंजाइश बढ़ी। अप्रैल 2022 में इस सीमा को और बढ़ाकर 23 प्रतिशत किया गया। यह व्यवस्था 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध कराई गई थी, जिसे बाद में 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था। एचटीएम सीमा को, 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ करते हुए, चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक बहाल किया जाएगा।

[2] 30 सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार, उन मामलों में वसूली कुल दावों का 33 प्रतिशत थी जहाँ सीआईआरपी की शुरुआत एफसी द्वारा की गई थी।

हैं। ऐसी प्रणाली में एक उधारकर्ता की चूक के चलते समूह कंपनियों द्वारा प्रति-चूकों की धारा फूटने की संभावना है जिससे वित्तीय प्रणाली के लिए समग्र रूप से ऋण जोख़िम बढ़ जाता है। एक समूह समाधान ढाँचा जिसमें एक ही कॉरपोरेट समूह से संबंधित उधारकर्ताओं के समाधान को यदि एक साथ लिया जाए तो संभव है कि यह आईबीसी के प्रभाव को बेहतर करने में सहायक हो।

दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

I.10 सितंबर 2021 में रिज़र्व बैंक ने मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए संशोधित ढाँचा जारी किया जिसमें न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण संबंधी अपेक्षाओं को सरल किया गया जबकि प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों हेतु पूँजीगत अपेक्षाओं का बासेल III मानकों से समंजन किया गया। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी /एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्तमान में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के प्रतिभूतिकरण की अनुमति लाइसेंस प्राप्त आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को है। दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए रिज़र्व बैंक एआरसी मार्ग के अतिरिक्त एक ढाँचा लाना चाहता है जो मानक आस्तियों हेतु संशोधित ढाँचे जैसा होगा। सितंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार, एक चर्चा पत्र (डीपी) जारी कर बाजार सहभागियों की टिप्पणी ली जाएगी।

निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

I.11 निवेश के मूल्यांकन के लिए वर्तमान दिशानिर्देश लगभग दो दशक पहले जारी किए गए थे। तब से, आकार और जटिलता में घरेलू वित्तीय बाजार कई गुना बढ़ गए हैं और इसलिए इनकी व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2022 में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर एक डीपी जारी किया। प्रस्तावित ढाँचे का उद्देश्य बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के साथ-साथ बढ़े हुए प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को दूर करना है। इसके प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ उचित मूल्य लाभ और हानियों का सममित निर्धारण, निवेश पोर्टफोलियो पर विभिन्न प्रतिबंधों को हटाना जैसे एचटीएम में निवेश की सीमा और एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों को एचटीएम बुक के तहत शामिल करने की अनुमति शामिल हैं। हितधारकों से प्राप्त राय के आधार पर जाँचे जा रहे प्रस्तावित दिशानिर्देश, बैंकों की स्वतंत्रता को बढ़ाने के साथ-साथ पारदर्शिता और बाजार अनुशासन को बढ़ावा देंगे।

प्रत्याशित ऋण हानि संबंधी ढाँचा

I.12 वर्तमान में भारत में बैंकों को उपगत (उठाई गई) हानि (इन्कर्ड लॉस) मॉडल के आधार पर ऋण हानि प्रावधान करना होता है जिसमें चूक होने के बाद प्रावधान किए जाते हैं। प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल नामक संशोधित पद्धति में ऋण संस्था को ऋण हानि के भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर प्रावधान करने हैं। अपने बैंकिंग समकक्षों के विपरीत, भारत में कुछ एनबीएफसी [3] ईसीएल पद्धति अपनाते हैं। बैंकों के लिए ईसीएल ढाँचे पर रिज़र्व बैंक की प्रस्तावित डीपी, सिद्धांत-आधारित दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करेगी जिसमें विनियामकीय अवलंब, आवश्यकतानुसार, पूरक का कार्य करेंगे।

बैंक स्वामित्व

I.13 भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से विलय के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के समेकन को आगे बढ़ा रही है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने दो पीएसबी के निजीकरण की मंशा की घोषणा की। कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं के साथ-साथ प्रबंधकीय और परिचालनीय लचीलेपन

[3] कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 4 द्वारा कवर की गई एनबीएफसी।

पर पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। आने वाले समय में यह पीएसबी और पीवीबी दोनों के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने और फूलने-फलने की अपेक्षित अपेक्षित गुंजाइश बनाएगा।

विनियामकीय परीक्षण स्थल

I.14 रिज़र्व बैंक ने 2019 में विनियामकीय परीक्षण स्थल (आरएस) की अवधारणा प्रस्तुत की ताकि नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं या कारोबार मॉडलों का सामान्यत: लाइव परंतु कुछ रक्षा-उपायों और निगरानी वाले नियंत्रित परिवेश में परीक्षण किया जा सके। अब तक घोषित आरएस वर्ग (कोहॉर्ट) के थीमों में 'खुदरा भुगतान', 'सीमापार भुगतान', 'एमएसएमई उधार' और 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और इसमें कमी' शामिल हैं। अब तक छह इकाइयां प्रथम वर्ग से एवं चार इकाइयां द्वितीय वर्ग से सफलतापूर्वक निकल चुकी हैं। तृतीय कोहार्ट के अंतर्गत चुनी गई इकाइयों का परीक्षण चल रहा है और चौथे वर्ग (कोहार्ट) के तहत परीक्षण चरण हेतु इकाइयों को चुनने के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। आरएस के तहत पाँचवें कोहार्ट को विषय तटस्थ (थीम न्यूट्रल) घोषित किया गया है जिसमें रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों से संबंधित नवोन्मेषी उत्पाद/ सेवाएं/प्रौद्योगिकी आवेदन कर सकते हैं। अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर, आरएस हेतु सक्षमकारी ढाँचे में बदलाव किए गए हैं ताकि इसे अधिक व्यापक और नवोन्मेष के अनुकूल बनाया जा सके। इसके अलावा, बंद वर्गों के विषयों के लिए आरएस में 'सदा सुलभ' ('ऑन टैप') एप्लिकेशन सुविधा शुरू की गई है ताकि निरंतर नवोन्मेष सुनिश्चित हो।

परोक्ष निगरानी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

I.15 अपनी परोक्ष निगरानी प्रणाली (ऑफ़-साइट मॉनिटरिंग सिस्टम) को पहले से तेज, अधिक व्यापक और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने में रिज़र्व बैंक सक्रियता से लगा रहा है। इस संबंध में एक प्रमुख पहल थी उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली – दक्ष (डीएकेएसएच) – की शुरुआत, जो पर्यवेक्षी कार्य प्रक्रियाओं के और आगे डिजटलीकरण के लिए एक पूर्णत: कार्यरत प्लेटफ़ॉर्म है। इस कड़ी में अन्य प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं: (ए) विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा स्वचालित डेटा रिपोर्टिंग और निगरानी साधनों के रूप में केंद्रीकृत सूचना और प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) का कार्यान्वयन; (बी) पर्यवेक्षी आसूचना (सुपरवाइज़री इन्टेलिजेंस) के पूरक के रूप में बिग डेटा का प्रयोग (सी) साइबर रेंज – साइबर सुरक्षा अभ्यास के लिए प्रयुक्त एक वर्चुअल नियंत्रित परिवेश और साधन – का कार्यान्वयन; (डी) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एई/एमएल) का प्रयोग करते हुए धोखाधड़ी संवेद्यता सूचकांक[4] डैशबोर्ड का विकास; और (ई) सभी पर्यवेक्षित इकाइयों की अपने-ग्राहक-को-जानिए (केवाईसी) और धन-शोधन निवारण (एएमएल) ढाँचे के लिए जोखिम आधारित पद्धति का मानकीकरण/ इष्टतमीकरण। क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता प्राप्त कार्यबल के विकास और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भी बल दिया जा रहा है।

विशिष्ट बैंकिंग

I.16 छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) ने जहाँ वित्तीय समावेश में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कुछ पीबी अभी भी लाभ-अलाभ की स्थिति पर नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी आधारित कारोबार मॉडल अब केवल इन्हीं की विशिष्टता नहीं रह गई है, लगभग सभी बैंक वित्तीय सेवाओं व उत्पादों की डिलिवरी को बेहतर करने व विस्तार देने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। इन प्रयासों को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना से बल मिला है। इस पृष्ठभूमि में, कुछ वर्गों में विशिष्ट (डिफ़रेंशिएटेड) बैंकिंग मॉडलों की व्यवहार्यता और इसकी निरंतरता को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि उनके कारोबारी

[4] वर्तमान में धोखाधड़ी संवेद्यता सूचकांक को बैंकों में संवेद्यता का पता लगाने के लिए बनाया गया है। आगे चलकर, सूचकांक का दायरा बढ़ाकर इसमें अन्य एसई को भी शामिल किया जा सकता है।

मॉडल पर्याप्त मजबूत हों तथा अच्छे अभिशासन और प्रौद्योगिकी मानकों का पालन हो ताकि प्रतिस्पर्धा के परिवेश में वे बचे रह सकें।

भुगतान और निपटान प्रणाली

I.17 रिज़र्व बैंक द्वारा हाल में किए गए अग्रसक्रिय उपायों ने भुगतान और निपटान परितंत्र में क्रांति ला दी है, उपभोक्ता अनुभव को बेहतर किया है, डिजिटल पहुँच को गहरा किया है और वित्तीय समावेश में सहायता की है। यूपीआई123 पे शुरू होने से देश में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन ग्राहकों को एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) की सुविधा मिली है। इसके अलावा, यूपीआई लाइट ने ऑन-डिवाइस वॉलेट के माध्यम से ऑफ़लाइन मोड में कम मूल्य के लेनदेन की सुविधा दी है। भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) से पात्र आर्थिक सहायता (सब्सिडी) राशि को बढ़ाया गया था और भुगतान स्वीकृति टचपॉइंट लगाने को और अधिक गति देने के लिए सब्सिडी दावा प्रक्रिया को सरल बनाया गया। रिज़र्व बैंक ने रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषण (रेमिटेंसेस) को कुछ शर्तों के अधीन भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से बिलर (लाभार्थी) के केवाईसी अनुपालित बैंक खाते में अंतरित करने की अनुमति दी। इससे भारत में अपने परिवारों की ओर से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिलों के भुगतान की सुविधा मिलने की उम्मीद है। यूपीआई के उपयोग से क्विक रेस्पॉन्स (क्यूआर) आधारित व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) भुगतान भूटान, सिंगापुर और यूएई में शुरू किए गए हैं। भुगतान प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजीसाथी हेल्पलाइन की स्थापना की गई। बारंबार होने वाले लेनदेन के लिए ई-मेंडेट सीमा में वृद्धि और कार्ड टोकनीकरण (टोकनाइजेशन) ने डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा को और मजबूती दी।

I.18 एक सक्षम भुगतान प्रणाली में अपेक्षित है कि फ़ीस का निर्धारण समुचित हो ताकि उपयोगकर्ताओं को अभिष्ट लागत एवं परिचालकों को प्रतिलाभ सुनिश्चित हो। अगस्त 2022 में, रिज़र्व बैंक ने एक चर्चा पत्र (डीपी) का प्रकाशन किया जिसमें भुगतान प्रणालियों में प्रभार संबंधी मौजूदा नियम बताए गए थे और साथ ही, अन्य विकल्प भी प्रस्तुत किए गए थे जिनके माध्यम से इस तरह के प्रभार लगाए जा सकते हैं। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, रिज़र्व बैंक अपनी नीतियों का स्वरूप बनाने और देश में विभिन्न भुगतान सेवाओं व गतिविधियों हेतु प्रभारों के ढाँचे को सुव्यवस्थित करने में प्रयासरत है। इससे भारत के पास एक ऐसी अत्याधुनिक भुगतान और निपटान प्रणाली सुनिश्चित होगी जो न केवल संरक्षित (सेफ़), सुरक्षित (सेक्योर), सक्षम और तेज बल्कि किफ़ायती भी हो।

फिनटेक

I.19 भारत में, पारंपरिक उधारदाताओं के साथ ऋण वितरण में साझेदारी, विशेषत: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, फिनटेक की सर्वाधिक परिवर्तनकारी भूमिकाओं में से एक हो सकती है। वर्तमान ऋण वितरण व्यवस्थाएं अधिकांशत: दस्तावेज आधारित हैं, जिसमें काम होने में काफी समय लगता है और बैंक शाखा के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें उधारदाताओं को उच्च परिचालन लागत और उधारकर्ताओं को विकल्प लागत झेलनी पड़ती है। इन चुनौतियों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक और रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) ने मिलकर कृषि-वित्त के डिजिटलीकरण की संकल्पना की। यह किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों को पूर्णत: डिजिटल और झंझट-मुक्त तरीके से वितरित करना संभव बनाएगा। नए केसीसी ऋणों के साथ-साथ प्रति उधारकर्ता एक सीमा तक ऐसे ऋणों का नवीकरण करने के लिए इस नवोन्मेष पर आधारित एक प्रायोगिक परियोजना मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में शुरू की गई थी। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक का विज़न एक एकीकृत और मानकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण और परिचालन है जिससे ग्रामीण और कृषि ऋण पर विशेष जोर देते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान की जा सके।

साइबर सुरक्षा जोखिम

I.20 डिजिटल भुगतान की अत्यधिक वृद्धि और वित्तीय परितंत्र के डिजिटलीकरण के विस्तार के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा के जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से, साइबर हमलों के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा और कार्मिकों के निरंतर कौशल-उन्नयन की सख्त जरूरत है। निरंतर ज्ञानार्जन और दूसरों से आगे रहना महत्वपूर्ण होगा।

I.21 रिज़र्व बैंक, पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को नई सुरक्षा चुनौतियों और साइबर खतरों से अवगत रखने के लिए अग्रसक्रिय कदम उठा रहा है। आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर जून 2022 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी मसौदा मास्टर निदेश (एमडी) को प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित किया जा रहा है। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए एक समेकित और अद्यतन आईटी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन ढाँचा प्रदान करने वाला एक मसौदा मास्टर निदेश (ड्राफ़्ट एमडी) सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अक्टूबर 2022 में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन और हरित वित्त

I.22 जलवायु परिवर्तन के कारण भौतिक और संक्रमण दोनों जोखिम हो सकते हैं जिनके प्रभाव किसी भी आरई की निरंतरता और वित्तीय सुदृढ़ता के साथ-साथ प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता पर पड़ सकते हैं। आरई को अपनी कारोबारी रणनीतियों और परिचालन में जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के संभावित प्रभाव को समझने और आकलन करने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करने एवं कार्यान्वित करने की जरूरत है। इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन और उनसे निपटने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त अभिशासन संरचनाओं तथा रणनीतिक ढाँचों की आवश्यकता होगी। आरई को अपने कर्मचारियों की उपयुक्त क्षमता निर्माण पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2022 में जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक डीपी जारी किया। डीपी में आरई को अपनी कारोबारी रणनीतियों के साथ-साथ अपने अभिशासन और जोखिम प्रबंधन ढाँचे में भी जलवायु व पर्यावरण संबंधी जोखिमों को शामिल करने की सिफारिश की गई। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, आरई को जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए एक भविष्योन्मुखी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के दिशा-निर्देश दिए गए।

I.23 धारणीय वित्त वर्गीकरणों (टैक्सोनॉमी) का उद्देश्य निवेशकों को यह समझने में मदद करना है कि कोई आर्थिक गतिविधि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ है या नहीं, और अल्प-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में सहायता करना है। इस तरह का वर्गीकरण स्थायी वित्त निधियों को भारत की ओर मोड़ने और उसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे धारणीय वित्त प्रवाहों का पता लगाना (ट्रैकिंग) भी अधिक आसान होगा। वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) विकसित करने के लिए सरकार के नेतृत्व में हितधारकों की ओर से समन्वित प्रयास अपेक्षित होंगे।

I.24 हरित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना या ग्रीन बॉन्ड जारी करके उनका पुनर्वित्तपोषण करना कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक दृढ़ संकेत देता है। 1 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सरकार ने 2022-23 के दौरान घरेलू बाजार में ₹16,000 करोड़ के सरकारी हरित (सॉवरिन ग्रीन) बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। ये उधार वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार के समग्र बाजार उधार का हिस्सा होंगे और प्राप्त राशि को हरित सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं में विनियोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने 09 नवंबर, 2022 को सरकारी हरित बॉन्ड ढाँचा (सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क) प्रकाशित किया है। इसके अलावा, नॉर्वे स्थित एक स्वतंत्र और विश्व प्रसिद्ध द्वितीय पक्ष विचार (एसपीओ) प्रदाता- सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च (सीआईसीईआरओ) - को ढाँचे का मूल्यांकन करने और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (आईसीएमए) के ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इसके सामंजस्य को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसने 'अच्छे' अभिशासन स्कोर के साथ ढाँचे को 'मध्यम हरित' (मीडियम ग्रीन) के रूप में रेट किया।

I.25 कुल मिलाकर, भारतीय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों ने कई आघातों के प्रति प्रत्यास्थता (रेजिलिएंस) प्रदर्शित की है, अर्थव्यवस्था के लक्षित क्षेत्रों के लिए महामारी के बाद के सार्वजनिक नीतिगत उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की है, और व्यापक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली को अवलंब प्रदान करते हुए वित्तीय सुदृढ़ता को संरक्षित किया है। जहां वित्त के क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेषों की वर्तमान लहर और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत चौदह उद्योगों को घरेलू समर्थन और आपूर्ति शृंखलाओं के वैश्विक पुनर्संतुलन से उत्पन्न होने वाले वृद्धि के नवीन अवसर नए कारोबार के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वहीं तकनीकजनित जटिल नेटवर्क, वैकल्पिक वित्त विकल्प और भू-राजनीतिक घटनाक्रम से उभरते जोखिमों के प्रति सजग रहना महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं के प्रति भी सतर्क रहने की जरूरत है। रिज़र्व बैंक की विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियां वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए गतिशील, सुदृढ़, प्रत्यास्थी (रेजिलिएंट) और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी।

II वैश्विक बैंकिंग घटनाक्रम

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद विभिन्न विनियामकीय और समष्टि-विवेकपूर्ण सुधारों के कार्यान्वयन की वजह से वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र 2021 और 2022 में अब तक वित्तीय रूप से मजबूत रहा है। शीर्ष 100 बैंकों ने स्वस्थ पूंजी बफर बनाए रखा, जबकि उनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ। हालांकि, हाल की अवधि में मौद्रिक नीति को आक्रामक रूप से सख्त करने से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए जोखिम पैदा हो गया है, जिसने वित्तीय स्थितियों को और अधिक कठिन बना दिया है। मध्यम अवधि की चुनौतियों में वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेषों का प्रभावी विनियमन और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम शामिल हैं।

1. भूमिका

II.1 यूरोप में युद्ध और वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण समकालिक और अग्र-प्रयुक्त मौद्रिक नीति सख्ती की वजह से अभूतपूर्व नीतिगत प्रोत्साहन और टीकाकरण की तीव्र गति के कारण वर्ष 2021 वाली वैश्विक बहाली को बनाए रखने की संभावनाएं मंद हो गई हैं। सन्निकट मुद्रास्फीति परिदृश्य के बारे में लगातार चिंता बने रहने से प्रवर्धित बाजार अस्थिरता वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिम को बढ़ा रही है। ज्यादा पूंजी और चलनिधि बफर ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ और स्थिर रहने में मदद की है। फिर भी, दुनिया भर में वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ गई है। इन कारकों की वजह से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी के बहिर्वाह में वृद्धि, विनिमय दरों में तेज मूल्यह्रास, आरक्षित निधि में कमी हुई है और समष्टि-आर्थिक संभावनाएं क्षीण हो गई हैं।

II.2 वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से बनाए गए पूंजी बफर की बदौलत वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र ने महामारी के आघातों का अच्छी तरह से सामना किया और महामारी के प्रभाव को कम करने में इसे विभिन्न विनियामकीय छूट का सहारा मिला। हालांकि, भू-राजनीतिक और महामारी से संबंधित चिंताओं के कारण तेजी से बदलते वैश्विक समष्टि-आर्थिक माहौल में बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ती ब्याज दरों और कर्ज चुकौती बोझ में संभावित वृद्धि से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यून राजकोषीय आय, बढ़ती चूक की संभावना और लाभप्रदता बिगड़ने से कमजोर आर्थिक परिदृश्य के प्रतिक्रियास्वरूप ऋण मांग - जो काफी हद तक प्रतिचक्रीय है – के दबे रहने की संभावना है।

II.3 इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय को पाँच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में वैश्विक समष्टि-वित्तीय स्थितियों का विहंगावलोकन दिया गया है। खंड 3 में हाल की वैश्विक बैंकिंग नीतिगत घटनाक्रम का जायजा लिया गया है। खंड 4 में वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है जबकि खंड 5 में दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खंड 6 में सामने आने वाली स्थितियों के साथ इस अध्याय के निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. वैश्विक समष्टि-आर्थिक स्थितियां

II.4 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डबल्यूईओ) के अपने अक्टूबर अपडेट में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जनवरी 2022 के बाद से लगातार तीन अधोगामी संशोधनों के बाद 2022 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर को 3.2 प्रतिशत पर रखा। इसने धुंधला पड़ते परिदृश्य के बढ़ते जोखिमों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के संवृद्धि पथ में बढ़ते विचलन को उजागर किया (चार्ट II.1ए)।

II.5 खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में तेज वृद्धि, मांग-आपूर्ति के असंतुलन और कुछ आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की निरंतरता के चलते वैश्विक मुद्रास्फीति के लिए अनुमान पिछले वर्ष के 4.7 प्रतिशत से ऊर्ध्वगामी संशोधन होकर वर्ष 2022 में 8.8 प्रतिशत हो गया है (चार्ट II.1बी)।

II.6 वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में वृद्धि एक वर्ष पहले के 10.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता घाटा (सीएडी) और अधिक बढ़ने की संभावना है, जो 2008 के जीएफसी के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है (चार्ट II.1सी)। जहां सरकारी कर्ज 2020 में महामारी के बाद के शीर्ष स्तर से कम हो गया है, वहीं यह अभी भी ऐतिहासिक औसत की तुलना में अधिक है (चार्ट II.1डी)।

II.7 दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने कीमत स्थिरता को बहाल करने के लिए मौद्रिक नीति सख्ती को अग्र-प्रयुक्त किया है। ईएमडीई में ब्राज़ील, चिली, मेक्सिको और रूस ने वर्ष 2021 में

चार्ट II.1: समष्टि-आर्थिक पृष्ठभूमि

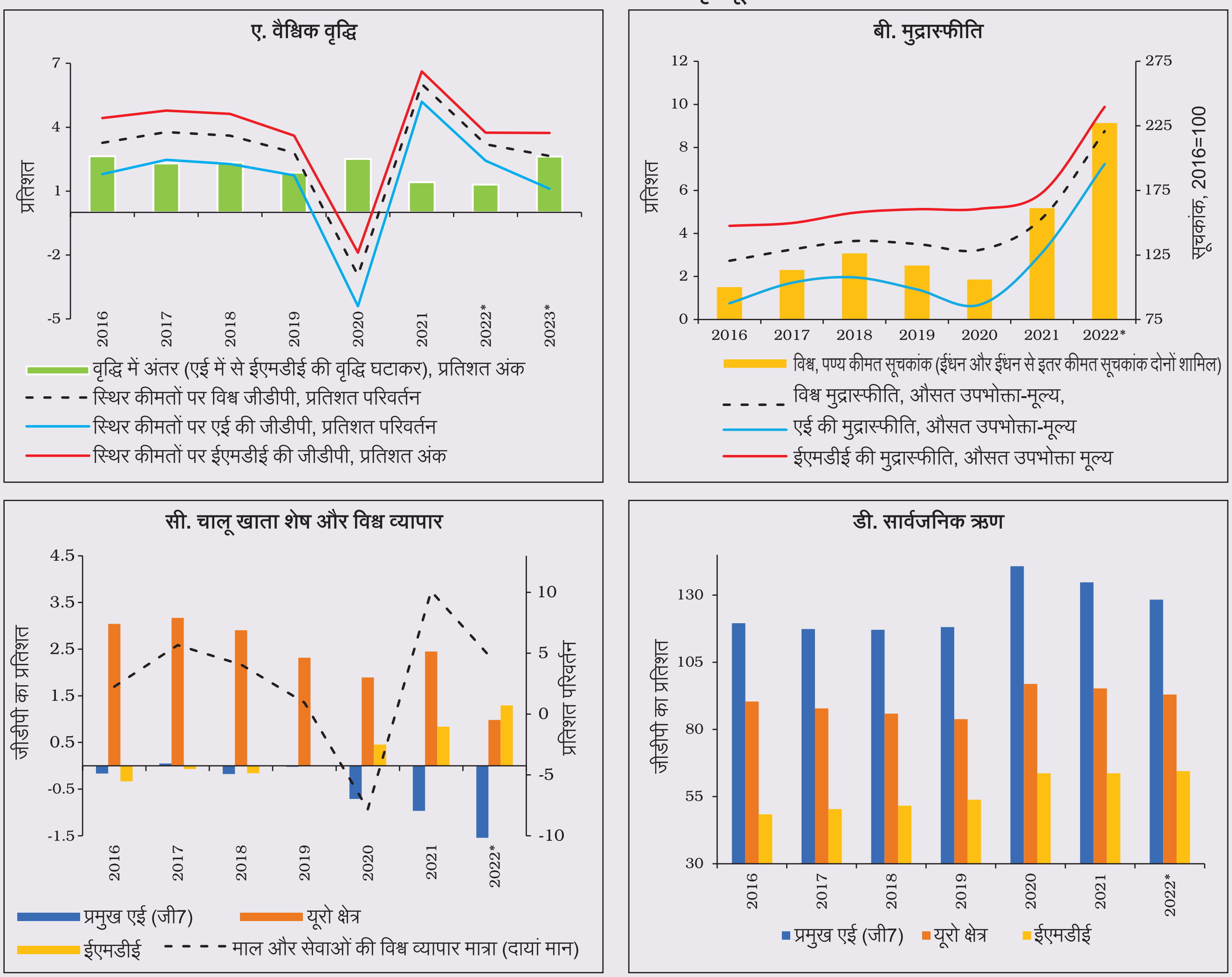

टिप्पणी: *: पूर्वानुमान।
स्रोत: विश्व आर्थिक परिदृश्य, आईएमएफ।

चार्ट II.2: मौद्रिक नीति दरें

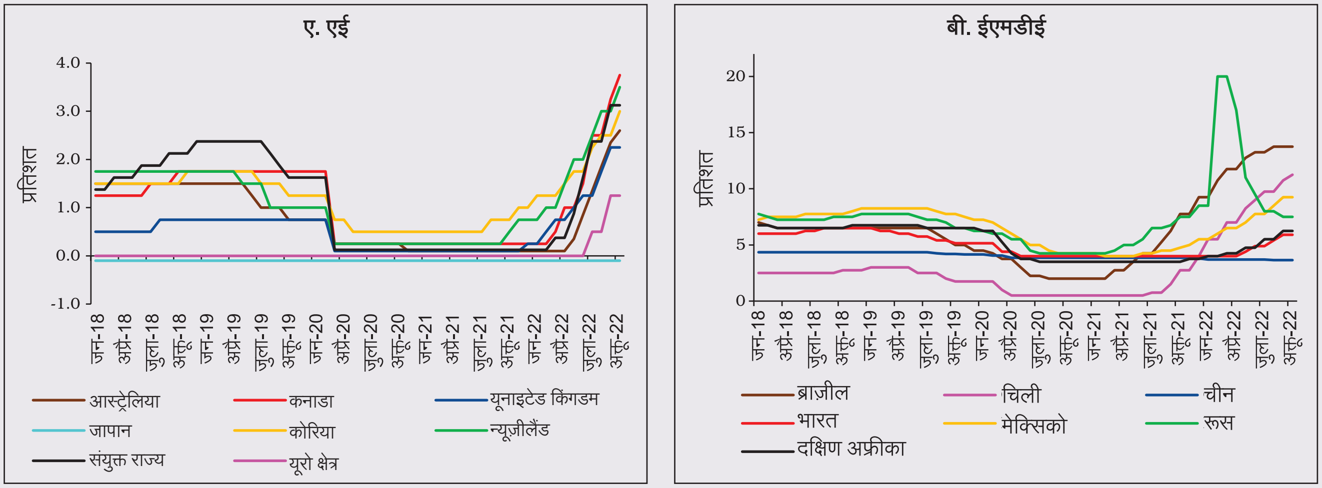

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक।

कई बार नीतिगत दरों को बढ़ाया है। ईएमई केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2022 की शुरुआत से ही निभावकारी रुख को वापस लेना शुरू कर दिया है (चार्ट II.2बी)।

II.8 दूसरी तरफ, एई ने बहुत धीरे-धीरे नीति को सामान्य करना शुरू किया जिसमें से अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने 2022 की शुरुआत में ही अपने दर वृद्धि चक्र शुरू कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिज़र्व ने मार्च 2022 में नीतिगत सख्ती शुरू कर दी और दिसंबर 2022 तक फेडरल फंड दर को बढ़ाकर 4.25- 4.50 प्रतिशत कर दिया (चार्ट II.2ए)।

II.9 यह स्पष्ट नहीं होने से कि विश्व स्तर पर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को कितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है, वर्ष 2023 का परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। नतीजतन, सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता में विश्वास कम होने से मुद्रास्फीति का प्रक्षेपवक्र के आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति के समकालिक और आक्रामक रूप से सख्त होने से वित्तीय स्थिति और कठोर हो गई है, जिससे वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए जोखिम पैदा हो गया है (बॉक्स II.1)।

बॉक्स II.1 बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम पर वित्तीय स्थितियों का असर

ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि जीएफसी और कोविड-19 महामारी जैसे आर्थिक संकट की अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की जोखिम बढ़ जाती है (चार्ट 1)।

वर्ष 2000 की पहली तिमाही से वर्ष 2022 की पहली तिमाही तक के कुल तिमाही आंकड़ों का उपयोग करके जी20 देशों के लिए निम्न चार-चर वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर) मॉडल अनुमानित किया गया:

$$Y_t = C + A_i \cdot Y_{t-i} + \varepsilon_t \quad \text{...(Eq.1)}$$

समीकरण 1 में, Y_t अमेरिकी वित्तीय स्थिति सूचकांक (एफसीआई)[1,2] के साथ-साथ जी20 देशों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि सहित अंतर्जात चर के वेक्टर को दर्शाता है। Y_t में एमएससीआई एडबल्यूसीआई बैंक सूचकांक की समय-भिन्न

(जारी)

[1] ब्लूमबर्ग अमेरिकी वित्तीय स्थिति सूचकांक (बीएफएससीआई) यू.एस. मनी, बॉन्ड और इक्विटी बाजारों में वित्तीय दबाव के समग्र स्तर को ट्रैक करता है और ऋण की उपलब्धता और लागत का आकलन करने में मदद करता है। मुद्रा बाजार, बॉन्ड बाजार और इक्विटी बाजार के लिए सूचकांक का भारांक 33.3 प्रतिशत है। एक धनात्मक मूल्य निभावकारी वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है, जबकि एक ऋणात्मक मूल्य 2008 से पहले की संकट अवधि के सापेक्ष सख्त वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है।

[2] डेटा स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 1: वैश्विक बैंकिंग प्रणाली जोखिम संकेतक

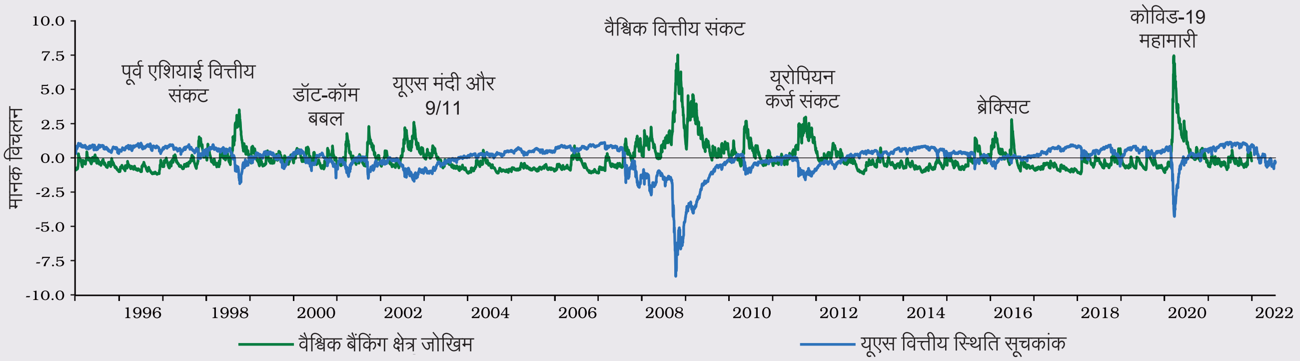

टिप्पणी: एमएससीआई एडबल्यूसीआई बैंक इक्विटी इंडेक्स का समय-भिन्न मानक विचलन - जिसमें 23 एई और 24 ईएमडीई से लार्ज और मिड-कैप बैंकिंग स्टॉक शामिल हैं - को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र (ग्रीन लाइन) में जोखिम के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में लिया गया है। अमेरिकी वित्तीय स्थिति सूचकांक का उपयोग वैश्विक वित्तीय स्थितियों (नीली रेखा) के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया गया है। शून्य माध्य और इकाई मानक विचलन के लिए डेटा को सामान्यीकृत किया गया है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अस्थिरता में सन्निहित बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम का एक प्रॉक्सी संकेतक भी शामिल है, जो एक एक्स्पोनेंशियल जेनरलाइज्ड ऑटोरिग्रेसिव कंडिशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (ईजीएआरसीएच) मॉडल का उपयोग करके अनुमानित है (बोलेर्सलेव, 1986; नेल्सन, 1991)। परिणाम से पता चलता है कि वैश्विक मुद्रास्फीति में एक मानक विचलन वृद्धि से मध्यम अवधि में बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम 1.5 अंक बढ़ जाता है (चार्ट 2ए)।

दूसरी ओर, जीडीपी वृद्धि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी अल्पावधि में बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम को कम करती है, हालांकि ऋण में उछाल के प्रतिक्रियास्वरूप मध्यम अवधि में वृद्धि हो सकती है जो अक्सर संवृद्धि में संकट के बाद की बहाली के साथ होती है (चार्ट 2बी)। एफसीआई को आघात, वित्तीय स्थितियों में सुगमता को दर्शाता है, वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम को 1.1 अंक कम कर देता है, जो मध्यम अवधि पर बना रहता है (चार्ट 2सी)।

चार्ट 2: वैश्विक आघातों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम की आवेग प्रतिक्रियाएं

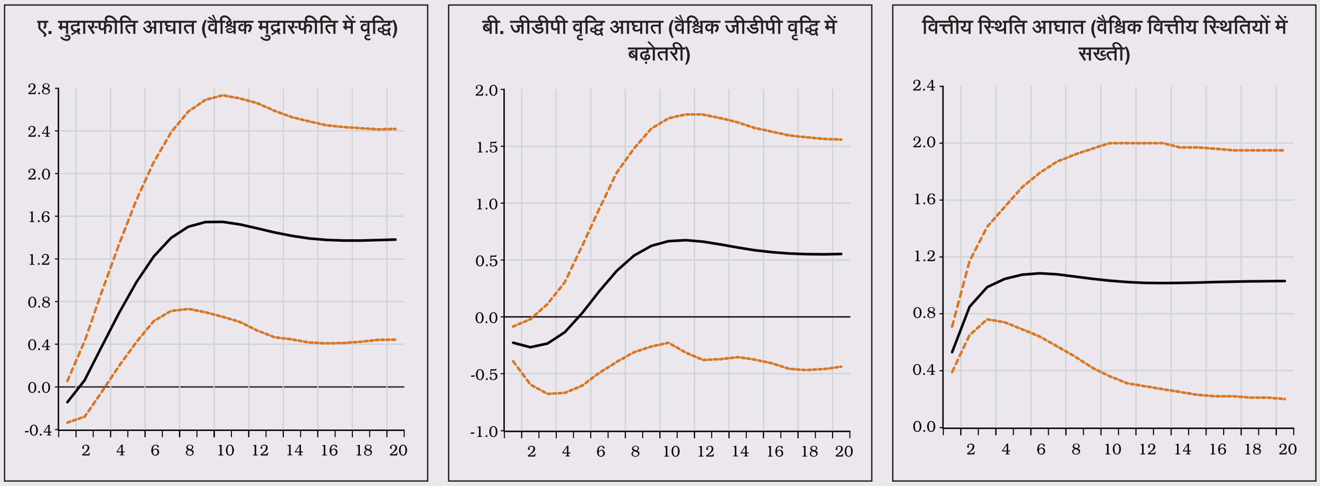

टिप्पणी: उपरोक्त चार्ट वैश्विक मुद्रास्फीति, वैश्विक संवृद्धि और वित्तीय स्थितियों में सामान्यीकृत एक मानक विचलन नवाचार के प्रति वैश्विक बैंकिंग प्रणाली जोखिम की संचित प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। Y-अक्ष प्रभाव को मानक विचलन संबंधों को मापता है जबकि x-अक्ष तिमाहियों में सीमा को प्रदर्शित करता है। 95% विश्वास अंतराल बैंड के साथ बिंदु अनुमान क्रमशः ठोस काली रेखा और बिंदीदार नारंगी रेखाओं में दिखाए गए हैं। 1000 बूटस्ट्रैप पुनरावृत्तियों के साथ हॉल के प्रतिशतक बूटस्ट्रैप का उपयोग करके मानक त्रुटियों की गणना की गई।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ

बोलेर्सलेव, टी. (1986), जेनरलाइज्ड ऑटोरेग्रेसिव कंडिशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी। *जर्नल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, 31*(3), 307-327

नेल्सन, डी. बी. (1991)। कंडिशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी इन एसेट रिटर्न्स: ए न्यू एप्रोच। *इकोनोमेट्रिका: जर्नल ऑफ इकोनोमेट्रिक सोसाइटी*, 347-370

3. वैश्विक बैंकिंग नीतिगत घटनाक्रम

II.10 वर्ष 2008 में जीएफसी के कारण हुए व्यवधानों के बाद, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के साथ समन्वय में जी20 ने वित्तीय सुधारों का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य उन दोषों को ठीक करना था, जिनके कारण जीएफसी हुआ। इसके चार मूल तत्व हैं: (i) सुदृढ़ वित्तीय संस्थाओं का निर्माण; (ii) इतने-बड़े-कि-न-डूबे (टू-बिग-टू-फेल/टीबीटीएफ) सुधार; (iii) डेरिवेटिव बाजारों को सुरक्षित बनाना; और (iv) गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) की सुदृढ़ता को बढ़ाना। तकनीकी नवोन्मेषों और जलवायु परिवर्तन जोखिमों के क्षेत्र में हाल के नीतिगत घटनाक्रम भी अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी पेश करते हैं।

सुदृढ़ वित्तीय संस्थाओं का निर्माण[3]

II.11 जनवरी 2023[4] में निर्धारित उत्कृष्ट बासेल III मानकों को अपनाने और कार्यान्वित करने की समय सीमा जैसे-जैसे करीब आ रही है, उस दिशा में और प्रगति की जा रही है। सितंबर 2021 से, छह अतिरिक्त सदस्य क्षेत्राधिकारों ने क्रेडिट जोखिम के लिए संशोधित मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और प्रत्येक चार अतिरिक्त सदस्य क्षेत्राधिकारों ने संशोधित आंतरिक रेटिंग-आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण, संशोधित परिचालन जोखिम फ्रेमवर्क और आउटपुट फ्लोर को अपनाया है। इसके अलावा, तीन अतिरिक्त सदस्य क्षेत्राधिकारों ने संशोधित ऋण मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) फ्रेमवर्क, बाजार जोखिम के लिए संशोधित न्यूनतम अपेक्षाएं, संशोधित लीवरेज अनुपात (2017 ऋण जोखिम परिभाषा) और वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (जी-एसआईबी) लीवरेज अनुपात बफर को अपनाया है।

लंबित चली आ रही उन मानकों में से सात और पूंजी मानक कार्यान्वयन पूरे किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के लिए बैंक एक्सपोजर हेतु पूंजी अपेक्षाएं और कुल हानि-सहनीय क्षमता (टीएलएसी) होल्डिंग मानक शामिल हैं। प्रकटीकरण मानकों के लिए, मुख्य रूप से निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) और बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए पांच और अंगीकरण देखने को मिला है। इस अवधि के दौरान घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के लिए फ्रेमवर्कऔर वृहद एक्सपोजर फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में प्रत्येक का एक-एक और अंगीकरण हुआ है।

इतने-बड़े-कि-न-डूबे (टू-बिग-टू-फेल/टीबीटीएफ) सुधार[5]

II.12 जी-एसआईबी समाधान योजना का ध्यान समाधान की तैयारियों को ठीक करने और इसका परीक्षण करने पर जा रहा है। वर्ष 2022 में, सभी देश में सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा कोविड-19 सहायता उपायों को जारी किए जाने के साथ-साथ बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों ने समष्टि-आर्थिक और वित्तीय अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया। कुछ बैंकों ने प्रतिबंधों के कारण प्रमुख सेवाओं तक अपनी पहुंच खो दी, जबकि बाजार के विश्वास में कमी के कारण कुछ अन्य में चलनिधि प्रवाह की समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ (गैर-प्रणालीगत) बैंकों इसका हल करने या परिनिर्धारण करने के लिए अधिकारियों को कदम उठाना पड़ा। चूंकि ईएमई के चार जी-एसआईबी द्वारा जनवरी 2025 तक टीएलएसी मानक का अनुपालन किया जाना बाकी है, इसलिए बाह्य टीएलएसी का निर्माण का कार्य जारी है। स्व-रिपोर्टिंग के अनुसार, अन्य सभी जी-एसआईबी वर्तमान में अंतिम टीएलएसी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं।

डेरिवेटिव बाजार को सुरक्षित बनाना

II.13 एफएसबी[6] ने पाया है कि 24 एफएसबी सदस्य क्षेत्राधिकारों में से 18 ने गैर-केंद्रीय समाशोधित व्युत्पन्नी (एनसीसीडी) के लिए अंतिम उच्चतर पूंजी अपेक्षाओं को लागू

[3] https://www.bis.org/bcbs/implementation/rcap_reports.htm

[4] यदि कोई अंतिम नियम प्रकाशित होता है तो किसी क्षेत्राधिकार को एक मानक के रूप में माना जाता है और यदि कोई अंतिम नियम प्रकाशित किया गया है तो एक मानक को कार्यान्वित कर दिया गया है और बैंकों द्वारा उसे कार्यान्वित किया जाता है।

[5] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P081222.pdf

[6] https://www.fsb.org/2022/11/otc-derivatives-market-reforms-implementation-progress-in-2022/

किया है। एनसीसीडी के लिए मार्जिन अपेक्षाएँ 16 क्षेत्राधिकारों में लागू हैं, 2 क्षेत्राधिकारों ने अंतिम मानकों को प्रकाशित किया है और 3 क्षेत्राधिकारों द्वारा वर्ष 2023 में अपेक्षाओं को कार्यान्वित किए जाने की उम्मीद है। ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव लेनदेन के लिए व्यापार रिपोर्टिंग अपेक्षाएं 23 एफएसबी सदस्य क्षेत्राधिकारों में लागू हैं और शेष क्षेत्राधिकारों[7] में व्यापार रिपोजिटरी (टीआर) को अधिकृत करने और क्षेत्राधिकार की आवश्यकताओं को लागू करने की तैयारी चल रही है। 17 एफएसबी सदस्य क्षेत्राधिकारों में केंद्रीय समाशोधन अपेक्षाएं लागू हैं और 13 एफएसबी सदस्य क्षेत्राधिकारों में प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग अपेक्षाएं लागू हैं।

गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों (एनबीएफआई) की सुदृढ़ता बढ़ाना

II.14 मानक निर्धारण निकायों (एसएसबी) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर एफएसबी एनबीएफआई क्षेत्र की सुदृढ़ता को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। यह उनकी चल रही निगरानी को मजबूत करके और जहां उपयुक्त हो, ऐसे जोखिमों को दूर करने के लिए नीतियां विकसित करके क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिमों को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

II.15 नवंबर 2022 में, एफएसबी ने गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता[8] की सुदृढ़ता बढ़ाने संबंधी एक प्रगति रिपोर्ट जारी की, जिसमें पिछले वर्ष की प्रगति और एसएसबी के साथ-साथ एफएसबी और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा एफएसबी के एनबीएफआई कार्य कार्यक्रम के तहत एनबीएफआई की सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए नियोजित कार्य का वर्णन है। एनबीएफआई कार्य कार्यक्रम के मुख्य फोकस में शामिल हैं: मुद्रा बाजार निधि (एमएमएफ) की सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए नीतिगत कार्य[9]; निर्बंध निधि (ओईएफ) में चलनिधि जोखिम और उसके प्रबंधन का आकलन; दबाव के दौरान मुख्य सरकार[10] और कॉर्पोरेट बॉन्ड[11] बाजारों में चलनिधि की संरचना और कारकों की जांच करना; केंद्रीय और गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित बाजारों में मार्जिन कॉल्स[12] के फ्रेमवर्क और गतिशीलता की जांच; यूएसडी क्रॉस-बॉर्डर फंडिंग में कमजोरियों का आकलन और ईएमई[13] में अतिसंवेदनशीलता के साथ पारस्परिक क्रिया।

जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण

II.16 तेजी से, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और नीति निर्माता जलवायु परिवर्तन को वित्तीय प्रणाली के लिए प्रणालीगत जोखिम के संभावित स्रोत के रूप में मान रहे हैं। ये जोखिम, जिनमें भौतिक, संक्रमण और देयता संबंधी जोखिम[14] शामिल हैं, सीमापार और सभी क्षेत्रों[15] सहित पूरे वित्तीय प्रणाली में संचरित हो सकते हैं।

II.17 हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के प्रयास क्षेत्राधिकार में बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में केंद्रीय बैंक या तो विचार कर रहे हैं या जलवायु परिवर्तन से वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों को दूर करने की योजना बना रहे हैं। जलवायु संबंधी जोखिमों के ऋण जोखिम को मापने में पर्याप्त रूप से सुसंगत, तुलनीय, ग्रैन्यलर और विश्वसनीय जलवायु आंकड़ों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

7 दक्षिण अफ्रीका

8 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P101122.pdf

9 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P111021-2.pdf

10 https://www.fsb.org/2022/10/liquidity-in-core-government-bond-markets/

11 https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD700.pdf

12 https://www.bis.org/bcbs/publ/d537.htm

13 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P260422.pdf

14 देयता जोखिम तब उत्पन्न होते हैं जब लोग या कारोबार उन नुकसानों के लिए मुआवजे की मांग करते हैं जो उन्हें जलवायु परिवर्तन से भौतिक या संक्रमण जोखिमों से पीड़ित हुए हों।

15 https://www.fsb.org/2022/10/supervisory-and-regulatory-approaches-to-climate-related-risks-final-report/

II.18 सामान्य संधारणीयता-संबंधी प्रकटीकरण अपेक्षाएं और जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण अपेक्षाएं ऐसे दो क्षेत्र हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय धारणीयता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) ने हाल ही में मानक प्रस्तावित किए हैं[16]। वे जलवायु-संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण संबंधी कार्यबल (टीसीएफडी) और उद्योग-आधारित प्रकटीकरण मानकों से संबंधित कार्य बल की सिफारिशों पर निर्मित हैं। इसका उद्देश्य सुसंगत, पूर्ण, तुलनीय और सत्यापन योग्य जानकारी के साथ स्थिरता प्रकटीकरण के वैश्विक आधार-रेखा मानक को विकसित करना है।

II.19 जून 2022 में बीसीबीएस ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों[17] के प्रभावी प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए 18 सिद्धांत जारी किए। इन सिद्धांतों में कॉर्पोरेट अभिशासन, आंतरिक नियंत्रण, जोखिम मूल्यांकन, प्रबंधन और रिपोर्टिंग जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य इस क्षेत्र में विषमता और विकसित प्रथाओं की डिग्री को देखते हुए, पर्याप्त लचीलापन बनाए रखते हुए, प्रथाओं में सुधार करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों और पर्यवेक्षकों के लिए एक सामान्य आधार-रेखा प्रदान करने में संतुलन हासिल करना है। इन सिद्धांतों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे बैंक या बैंकिंग क्षेत्र के आकार, जटिलता और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर आनुपातिक तरीके से बैंकिंग प्रणालियों की एक विविध श्रेणी द्वारा अपनाए जा सकते हैं।

II.20 जुलाई 2022 में, एफएसबी ने पहली बार जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों[18] को दूर करने के लिए एसएसबी और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया। रोडमैप के सभी चार ब्लॉक अर्थात फर्म-स्तरीय प्रकटीकरण, डेटा, भेद्यता विश्लेषण और विनियामकीय और पर्यवेक्षी साधनों का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए सामान्य मेट्रिक्स स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें फ़ॉरवर्ड-लुकिंग मेट्रिक्स और सुसंगत रूप में जलवायु-जोखिम संबंधी डेटा तक खुली पहुंच के लिए डेटा रिपॉजिटरी स्थापित करना शामिल है।

II.21 उसी महीने में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने घोषणा की कि वह यूरोसिस्टम के मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क[19] में जलवायु परिवर्तन के विषय को शामिल करेगा। संबंधित उपायों में शामिल हैं: (i) कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन; अधिक महत्वाकांक्षी कार्बन कटौती लक्ष्य और बेहतर जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण वाले निर्गमकर्ताओं की ओर ईसीबी के कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डिंग्स का रुख करना; (ii) उच्च कार्बन फुटप्रिंट वाली संस्थाओं द्वारा जारी आस्तियों की हिस्सेदारी को सीमित करना, जिसे यूरोसिस्टम से उधार लेते समय व्यक्तिगत प्रतिपक्षकारों द्वारा संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा जा सकता है; (iii) यूरोसिस्टम ऋण परिचालन में संपार्श्विक के रूप में कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव (सीएसआरडी) का अनुपालन करने वाली कंपनियों और देनदारों से विपणन योग्य आस्ति और ऋण दावों को स्वीकार करना; और (iv) जलवायु संबंधी जोखिमों को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए ईसीबी के जोखिम मूल्यांकन साधनों एवं क्षमताओं को और बढ़ाना।

II.22 नवंबर 2022 में, एफएसबी ने वित्तीय प्रणाली हरितकरण नेटवर्क (एनजीएफएस) के साथ एक संयुक्त रिपोर्ट[20] प्रकाशित की, जो विभिन्न वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा किए गए जलवायु परिदृश्य विश्लेषण के निष्कर्षों का संश्लेषण प्रदान करती है।

[16] https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/

[17] https://www.bis.org/press/p220615.htm

[18] https://www.fsb.org/2022/07/fsb-outlines-progress-made-on-addressing-financial-risks-from-climate-change/

[19] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220704~4f48a72462.en.html

[20] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P151122.pdf

सीमापार भुगतान को बढ़ाना

II.23 त्वरित और अधिक कुशल तरीके से सीमापार भुगतान के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रमुख चुनौतियों में उच्चतर लागत, निम्न गति, सीमित पहुंच और अपर्याप्त पारदर्शिता शामिल है। वर्ष 2021 में एफएसबी ने तीन खंडों - थोक सीमापार भुगतान; खुदरा सीमापार भुगतान; और विप्रेषण[21] के लिए 11 विश्व स्तरीय मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करके इन समस्याओं को दूर करना चाहा। इसके अलावा, जुलाई 2022 में एफएसबी ने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) प्रस्तावित किए और इन केपीआई[22] की गणना के लिए आंकड़ों की मौजूदा और संभावित स्रोतों की पहचान की। नवंबर 2022 में प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट में केपीआई और उनकी गणना में अंतर्निहित मुख्य डेटा स्रोतों की अधिक विस्तृत चर्चा की गई थी, जिसमें ठोस अंतराल, निगरानी कार्य को परिचालनगत करने के दृष्टिकोण शामिल थे[23]।

II.24 मई 2022 में, बीआईएस की भुगतान और बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी समिति (सीपीएमआई) ने प्रमुख भुगतान प्रणालियों, विशेष रूप से तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) सिस्टम की पहुंच व्यवस्था का स्व-मूल्यांकन करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रकाशित किया[24]। सीपीएमआई चलनिधि लागत और निपटान जोखिम को कम करते हुए सीमापार भुगतान की गति बढ़ाने के लिए अधिकार क्षेत्र में आरटीजीएस सिस्टम के परिचालन अवधि को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है[25]।

II.25 अगस्त 2022 में प्रकाशित एक पेपर[26] में, ईसीबी ने सीमापार भुगतान प्रणालियों के लिए छह[27] संभावित अवसरों की तुलना की, जो तत्काल, सस्ते, सार्वभौमिक होने और एक सुरक्षित निपटान माध्यम में व्यवस्थित होने पर खरे उतर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक एफएक्स रूपांतरण परत के माध्यम से आपस में जुड़ी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) और तत्काल घरेलू भुगतान प्रणाली सीमापार भुगतान के लिए 'रामबाण' (होली ग्रेल) सिद्ध हो सकती हैं।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

II.26 विश्व स्तर पर एक आम सहमति बन रही है कि यदि सीबीडीसी को सही ढंग से लागू किया जाता है, तो यह भुगतान विकल्पों में विविधता बढ़ा सकता है, सीमापार भुगतान को तेज और सस्ता बना सकता है, वित्तीय समावेश में वृद्धि कर सकता है और संभावित रूप से महामारी जैसे संकट के समय लक्षित लाभार्थियों को वित्तीय हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। अनेक केंद्रीय बैंक और सरकारें, वैध मुद्रा के डिजिटल संस्करण की खोज के लिए प्रयास कर रही हैं। कोविड-19 महामारी ने कम रिटर्न देने वाली वित्तीय आस्तियों के विकल्प के रूप में डिजिटल भुगतान में आशातीत वृद्धि और निजी क्रिप्टो करेंसी की तेज वृद्धी का समर्थन करने वाली स्थितियां बनाने में योगदान दिया। इस अनुभव ने केंद्रीय बैंकों को सीबीडीसी पर तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। सीबीडीसी पर बीआईएस सर्वेक्षण 2021[28] के परिणामों से पता चला कि 90 प्रतिशत केंद्रीय बैंक सक्रिय रूप से सीबीडीसी की क्षमता पर

[21] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131021-2.pdf

[22] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P060722.pdf

[23] https://www.fsb.org/2022/11/developing-the-implementation-approach-for-the-cross-border-payments-targets-final-report/

[24] https://www.bis.org/cpmi/publ/d202.htm

[25] https://www.bis.org/cpmi/publ/d203.htm

[26] टुवार्ड्स द होली ग्रैल ऑफ क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स। https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2693~8d4e580438.en.pdf?972bbc119868c193467dc86f4a7cf706 पर उपलब्ध है।

[27] इनमें शामिल हैं (i) आधुनिकीकृत प्रतिनिधि बैंकिंग; (ii) उभरते हुए सीमापार फिनटेक समाधान; (iii) बिटकॉइन; (iv) वैश्विक स्टेबलकॉइन्स ; (v) विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन लेयर से आपस में जुड़ी तत्काल भुगतान प्रणाली; (vi) विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन लेयर से आपस में जुड़ी सीबीडीसी।

[28] इस रिपोर्ट में 81 केंद्रीय बैंकों के सीबीडीसी कार्य में उनकी भागीदारी के साथ-साथ सीबीडीसी जारी करने के संबंध में उनकी अभिप्रेरणा और उनके इरादों के बारे में सर्वेक्षण के परिणाम को प्रस्तुत किया गया है। https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap125.pdf पर उपलब्ध है

शोध कर रहे थे, 62 प्रतिशत प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग कर रहे थे और 26 प्रतिशत प्रायोगिक परियोजनाओं को लागू कर रहे थे।

II.27 अक्टूबर 2021[29] में ईसीबी ने उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं तथा व्यापारियों और मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा तकनीकी सलाह के आधार पर डिजाइन और वितरण के संबंध में प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से डिजिटल यूरो परियोजना का एक अन्वेषण चरण शुरू किया। गोपनीयता सुनिश्चित करने और यूरो क्षेत्र के नागरिकों, मध्यवर्ती संस्थाओं और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम से बचने के डिजाइन विकल्पों को चिन्हित करते हुए अन्वेषण चरण 24 महीने तक चलेगा और बाजार पर डिजिटल यूरो के संभावित प्रभाव का आकलन करेगा। यह डिजिटल यूरो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पर्यवेक्षित मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए एक कारोबार मॉडल का भी निर्धारण करेगा।

II.28 ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंकों के साथ बीआईएस इनोवेशन हब (बीआईएसआईएच), "प्रोजेक्ट डनबार" नामक एक बहु-केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (एम-सीबीडीसी) साझा प्लेटफ़ॉर्म को डिज़ाइन किया और उसे विकसित किया। यह प्लेटफ़ॉर्म कई केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय निपटान को सक्षम बना सकता है। प्रतिनिधि बैंकिंग मॉडल में बैंक एक-दूसरे के साथ विदेशी मुद्रा खाते रखते हैं, इसके विपरीत यह एक बहु-मुद्रा सामान्य निपटान प्लेटफ़ॉर्म है जो मध्यवर्ती संस्थाओं की आवश्यकता के बिना विभिन्न मुद्राओं में सीधे एक-दूसरे को भुगतान करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार सीमापार भुगतान के लिए समय, प्रयास, लागत और निपटान जोखिम को कम करता है। मार्च 2022 में प्रकाशित परियोजना के प्रारंभिक चरण के परिणाम, ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी पर विकसित दो प्रोटोटाइप के आधार पर एम-सीबीडीसी की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि करते हैं।

II.29 बीआईएसआईएच, खुदरा सीबीडीसी के लिए एक द्वि-स्तरीय वितरण मॉडल (खुदरा सीबीडीसी प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर केंद्रीय बैंक और निजी क्षेत्र द्वारा की जाने वाली ग्राहक-संबंधी गतिविधियां) के आधार पर एक प्रोटोटाइप भी विकसित कर रहा है, जो खुदरा भुगतान[30] के लिए केंद्रीय बैंक के खाता-बही को सुरक्षित परिवेश में निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के साथ परस्पर कार्य करने में सक्षम बना सकता है।

क्रिप्टो-आस्तियों का विनियमन

II.30 यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा से मौद्रिक नीति को आक्रामक रूप से सख्त करने के बाद, क्रिप्टो बाजारों[31] में उच्च अस्थिरता देखी गई है। यहां तक कि स्टेबलकॉइन[32] भी इससे बच नहीं पाये। क्रिप्टो-क्षेत्र का बाजार पूंजीकरण नवंबर 2021 में लगभग $3 ट्रिलियन के शीर्ष स्तर से गिरकर दिसंबर 2022 में $1 ट्रिलियन से भी कम हो गया[33]। कुछ प्रमुख क्रिप्टो लेंडिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने या तो अपने प्लेटफॉर्म से आहरण बंद कर दिया या फिर दिवालिएपन की घोषणा की[34]। एक प्रमुख क्रिप्टो सूचकांक की विफलता के बाद नवंबर 2022 में क्रिप्टो बाजार को उथल-पुथल के एक और प्रकरण का सामना करना पड़ा[35]।

[29] https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/governance/shared/files/ecb.degov220929.en.pdf

[30] https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/rosalind.htm

[31] https://fortune.com/2022/05/05/bitcoin-plummets-alongside-stocks-federal-reserve-decision/

[32] स्टेबलकॉइन्स, क्रिप्टो आस्तियों की विशेष श्रेणी हैं, जिनका उद्देश्य एक निर्दिष्ट आस्ति (आमतौर पर यूएस डॉलर), या आस्तियों का एक पूल या समूह, के सापेक्ष एक स्थिर मूल्य बनाए रखना है जो कि समर्थन रहित क्रिप्टो-आस्तियों के विपरीत है।

[33] https://coinmarketcap.com/charts/

[34] सेल्सियस नेटवर्क लिमिटेड, बेबेल फाइनेंस, कॉइनफ्लेक्स, वोयाजर डिजिटल, वॉल्ड और जिपमेक्स ने क्रमशः 12 जून 2022, 17 जून 2022, 23 जून 2022, 01 जुलाई 2022, 04 जुलाई 2022 और 20 जुलाई 2022 को निकासी पर रोक लगाने की घोषणा की। सेल्सियस नेटवर्क और वायेजर डिजिटल ने दिवालियापन के लिए दायर किया है। स्रोत: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-21/crypto-woes-spread-as-celsius-babel-links-hit-another-exchange?sref=QF6yuiF0

[35] https://www.nytimes.com/2022/11/10/technology/ftx-binance-crypto-explained.html

इन प्रकरणों ने एक बार फिर इन आस्तियों द्वारा उत्पन्न वित्तीय स्थिरता जोखिमों के मुद्दे को सामने ला दिया है। विश्व भर में नीति निर्माता और एसएसबी, इन आस्तियों के द्वारा प्रस्तुत जोखिमों के अनुरूप, क्रिप्टो-आस्तियों के प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित और प्रौद्योगिकी-तटस्थ नीतियों के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं।

II.31 एफएसबी ने क्रिप्टो-क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित दुर्बलताओं की पहचान की है जिनके वित्तीय स्थिरता संबंधी निम्न प्रभाव हो सकते हैं: क्रिप्टो-आस्ति बाजारों और विनियमित वित्तीय प्रणाली के बीच बढ़ती सहबद्धता; चलनिधि असंतुलन, ऋण और परिचालन संबंधी जोखिम जो स्टेबलकॉइन को उनकी आरक्षित निधियों का अचानक और हानिकारक उपयोग करने के लिए मजबूर करते हैं, और अल्पावधि निधीयन बाजारों में प्रभाव-विस्तार होने की संभावना; निवेश कार्यनीतियों में लीवरेज का बढ़ता उपयोग; ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का संकेंद्रण जोखिम; क्षेत्र की अस्पष्टता और विनियामक निगरानी की कमी; क्रिप्टो-आस्तियों को लेकर निवेशक और उपभोक्ता की समज का निम्न स्तर; धन शोधन; साइबर अपराध और रैन्समवेयर[36]।

II.32 एफएसबी ने चार संचरण चैनलों पर भी प्रकाश डाला है जिसके माध्यम से निम्न दुर्बलताओं से वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है: (i) वित्तीय क्षेत्र का क्रिप्टो-आस्तियों, संबंधित वित्तीय उत्पादों और संस्थाओं पर प्रत्यक्ष एक्सपोजर, जो इन आस्तियों से वित्तीय रूप से प्रभावित होते हैं; (ii) धन प्रभाव, *यानी,* क्रिप्टो-आस्तियों के मूल्य में परिवर्तन का वह स्तर जो उनके निवेशकों को वित्तीय प्रणाली पर आगामी प्रारंभिक प्रभावों के साथ असर डाल सकता है; (iii) विश्वास प्रभाव (कॉन्फ़िडेंस इफेक्ट) जिसके माध्यम से क्रिप्टो-आस्तियों से संबंधित घटनाक्रम क्रिप्टो-आस्ति बाजारों में निवेशकों के विश्वास, और संभावित रूप से व्यापक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं; और (iv) भुगतान और निपटान में क्रिप्टो-आस्तियों प्रयोग का विस्तार।

II.33 बीसीबीएस क्रिप्टो-आस्ति को समूह-1 क्रिप्टो-आस्ति और समूह-2 क्रिप्टो-आस्ति में विभाजित करता है, जिसमें समूह-1 क्रिप्टो-आस्ति पूरी तरह से वर्गीकरण शर्तों के सेट को पूरा करती हैं और समूह-2 में ऐसी आस्तियां हैं जो ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। समूह-1 की आस्तियों को आगे और विभाजित किया गया जिसमें समूह 1ए आस्तियों में टोकन वाली पारंपरिक आस्तियां और समूह 1बी में प्रभावी स्थिरीकरण तंत्र के साथ क्रिप्टो-आस्तियां शामिल हैं। समूह 1 की क्रिप्टो-आस्तियों को कम-से-कम समतुल्य जोखिम-आधारित पूंजी आवश्यकताओं के अधीन रखने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा बासेल पूंजी फ्रेमवर्क में निर्धारित अंतर्निहित एक्सपोजर पर जोखिम भार के आधार पर होंगी और समूह 2 की क्रिप्टो-आस्तियां और अधिक संतुलित पूंजी सुविधा के अधीन होंगी[37]।

II.34 जून 2022 में बीसीबीएस ने फ्रेमवर्क में कुछ परिवर्धन/परिवर्तन का सुझाव दिया जो निम्नलिखित हैं: (i) बासेल फ्रेमवर्क में शामिल करने के लिए मानक मसौदे का विस्तार; (ii) वर्गीकरण शर्तों का परिशोधन; (iii) सभी समूह 1 क्रिप्टो-आस्तियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिम को कवर करने के लिए जोखिम-भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में एक वर्धित मद (ऐड-ऑन) शुरुआत; (iv) समूह 2 की कुछ क्रिप्टो-आस्तियों के लिए बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) की स्वीकृति; और (v) एक्स्पोजर सीमा की शुरुआत, जो शुरुआत में समूह 2 की क्रिप्टो-आस्तियों के लिए बैंक के कुल एक्स्पोजर को टीयर 1 पूंजी के एक प्रतिशत तक सीमित कर देगी [38]।

II.35 जुलाई 2022 में एफएसबी ने क्रिप्टो क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण के संबंध में भावी मार्ग पर अंतरराष्ट्रीय रुख निर्धारित किया। इन शिफारिशों में शामिल है[39]। (i) क्रिप्टो-

[36] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160222.pdf

[37] https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.htm

[38] https://www.bis.org/bcbs/publ/d533.pdf

[39] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P110722.pdf

आस्तियों और बाजारों को प्रभावी विनियमन और निगरानी के अधीन लाया जाना चाहिए और यह उनके द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले उन जोखिमों के अनुरूप होना चाहिए; (ii) क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाताओं को हर समय अपने अधिकार क्षेत्रों में मौजूदा कानूनी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए; (iii) क्रिप्टो-आस्ति बाजारों में हाल की उथल-पुथल, एफएसबी के कार्य-क्षेत्रों में जारी प्रगति और क्रिप्टो-आस्तियों द्वारा उत्पन्न संभावित वित्तीय स्थिरता जोखिमों को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक तय करने वाले निकायों तथा तथाकथित स्टेबलकॉइन के महत्व पर प्रकाश डालती है और; (iv) यदि स्टेबलकॉइन को वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो इन्हें सुदृढ़ विनियमनों और संबंधित प्राधिकारियों की देखरेख के अधीन लाया जाना चाहिए। इस वक्तव्य में आगे घोषणा हुई है कि एफएसबी सदस्य मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानकों के पूर्ण और समय से कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं और एफएसबी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि क्रिप्टो-आस्तियां सुदृढ़ विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन हैं।

II.36 अक्टूबर 2022 में, एफएसबी ने क्रिप्टो-आस्ति गतिविधियों और बाजारों के विनियमन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए अनुशंसा की और 'वैश्विक स्टेबलकॉइन' व्यवस्था के विनियमन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पिछली सिफारिशों की समीक्षा की। ये प्रस्ताव क्रिप्टो-आस्ति गतिविधियों और बाजारों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की व्यापकता और अंतरराष्ट्रीय अनुरूपता का संवर्धन करना चाहते हैं[40, 41]।

4. वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन

II.37 महामारी के आगमन के समय वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति मजबूत थी और तब से अब तक वर्ष 2021 और 2022 के दौरान इसकी स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनी हुई है। इसका मुख्य कारण विभिन्न विनियामकीय और समष्टि-विवेकपूर्ण सुधारों का कार्यान्वयन है। इसके अलावा, विनियामकीय छूट और असाधारण मौद्रिक तथा राजकोषीय सहायता ने बैंकों को वास्तविक क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद की।

बैंक ऋण वृद्धि

II.38 कोविड-19 महामारी की शुरुआत में, वैश्विक वृद्धि में संकुचन और आवागमन संबंधी प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 की पहली छमाही में ऋण वृद्धि में गिरावट आई। वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में ऋण वृद्धि की बहाली अल्पकालिक सिद्ध हुई और केवल वर्ष 2021 की पहली छमाही तक बना रहा - और तब से कमजोर मांग चालकों के कारण एई और ईएमडीई में तीव्र गिरावट आई है (चार्ट II.3ए)। जहां अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण वृद्धि मंद रही, वहीं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2021 की दूसरी छमाही से सुधार के संकेत दर्शाये हैं (चार्ट II.3बी)। चीन के उल्लेखनीय अपवाद के साथ, अधिकांश ईएमई में एक समान बहाली देखी गई (चार्ट II.3सी)। इसके विपरीत, पूरे यूरो क्षेत्र में क्रेडिट वृद्धि निराशाजनक रही। वर्ष 2021 में ग्रीस में बैंक क्रेडिट वृद्धि में संकुचन लगातार ग्यारहवें वर्ष जारी रहा (चार्ट II.3डी)।

आस्ति गुणवत्ता

II.39 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कुल सकल ऋणों की तुलना में अनर्जक ऋणों के अनुपात (एनपीएल अनुपात) द्वारा मापी गई आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा (चार्ट II.4ए)। यूरो क्षेत्र में, ग्रीस में सरकार और संस्था-विशिष्ट मध्यक्षेपों से इसके बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ (चार्ट II.4बी)। ईएमई में वर्ष 2019 से इसमें सुधार हो रहा है, हालांकि रूस और

[40] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P111022-3.pdf
[41] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P111022-4.pdf

चार्ट II.3: निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण

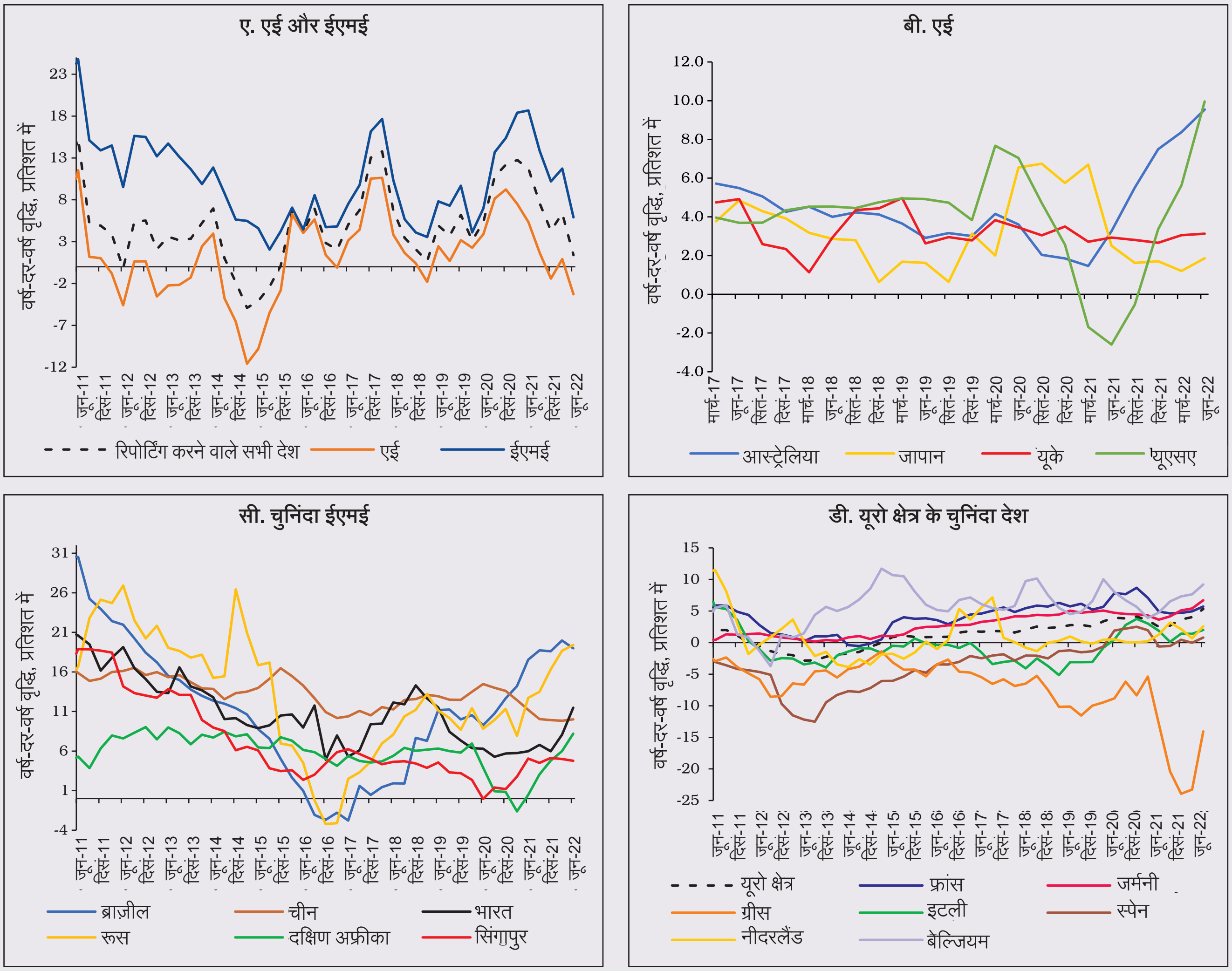

स्रोत: कुल ऋण सांख्यिकी, बीआईएस।

भारत में अन्य देशों *की तुलना में* एनपीएल अनुपात अधिक बना हुआ है (चार्ट II.4सी)।

प्रावधान कवरेज अनुपात

II.40 यूएसए और नॉर्वे जैसी कुछ एई में प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) उच्च बना रहा है, जो बैंकिंग बही में दबाव के प्रति अधिक सुदृढ़ता दर्शाता है (चार्ट II.5ए)। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच निम्न रहा है। वर्ष 2021 में यूरो क्षेत्र के कुछ देशों में पीसीआर में थोड़ी कमी आई (चार्ट II.5बी)। ईएमडीई के लिए, ब्राजील और अर्जेंटीना में गिरावट को छोड़कर पीसीआर स्थिर रहा, लेकिन यह 100 प्रतिशत से काफी अधिक रहा (चार्ट II.5सी)।

बैंक लाभप्रदता

II.41 निम्नतर ब्याज दरों के बावजूद, अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) के संदर्भ में मापी गई बैंक लाभप्रदता में सुधार जारी रहा। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क में ऋण हानि के उच्च प्रावधान के कारण लाभप्रदता में गिरावट आई (चार्ट

चार्ट II.4: आस्ति गुणवत्ता

(कुल सकल ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीएल)

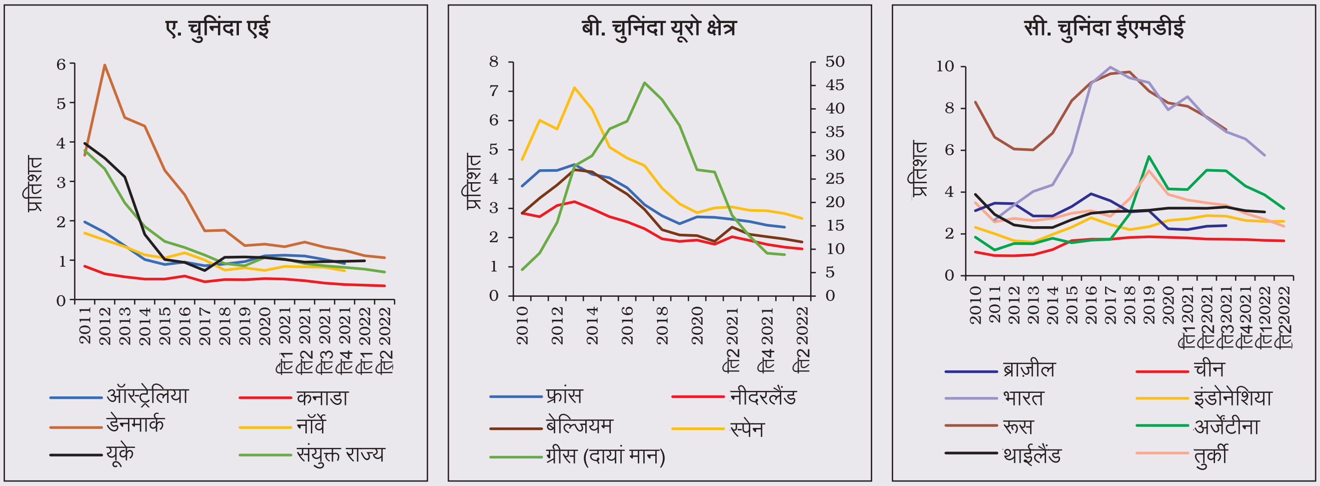

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

II.6ए)। स्पेन को छोड़कर यूरो क्षेत्र में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) बढ़ा। यद्यपि ग्रीस के लिए लाभप्रदता ऋणात्मक रही थी, इसमें वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही से सुधार हुआ (चार्ट II.6बी)। ईएमडीई में अनर्जक ऋणों के लिए निम्नतर प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के कारण आरओए मजबूत बना रहा (चार्ट II.6सी)।

पूंजी पर्याप्तता

II.42 बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), क्षेत्राधिकारों में बासेल III के निर्धारित स्तरों से काफी अधिक रहा, हालांकि हाल की तिमाहियों में डेनमार्क और यूएस जैसी एई में सामान्य गिरावट देखी गई है। यूरो क्षेत्र के देशों और ईएमडीई में पूंजी की स्थिति या तो स्थिर

चार्ट II.5: प्रावधान कवरेज अनुपात

(कुल सकल ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीएल प्रावधान)

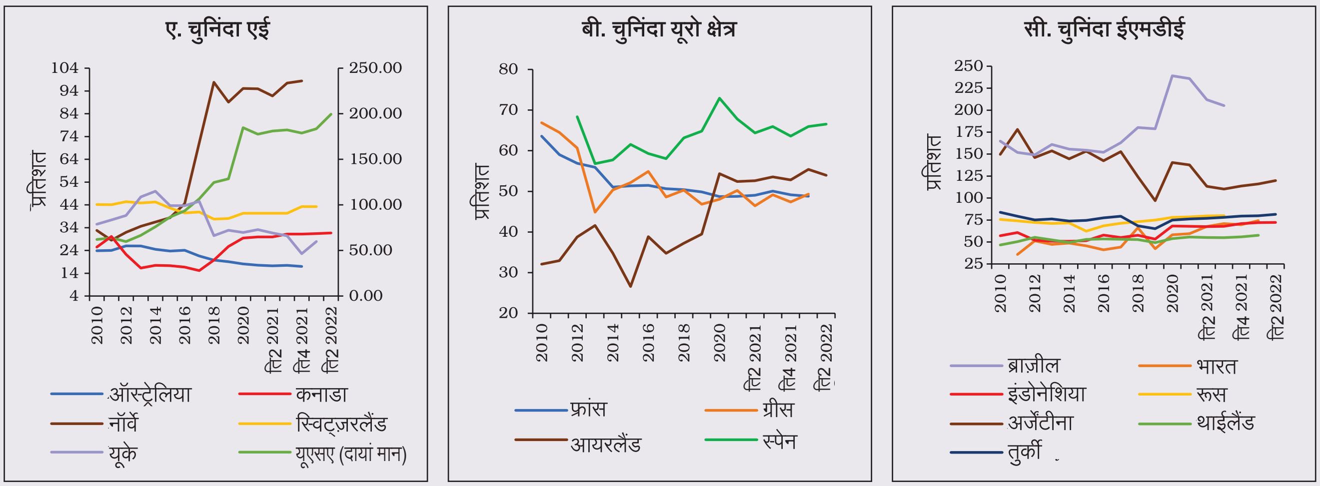

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

चार्ट II.6: आस्तियों पर प्रतिलाभ

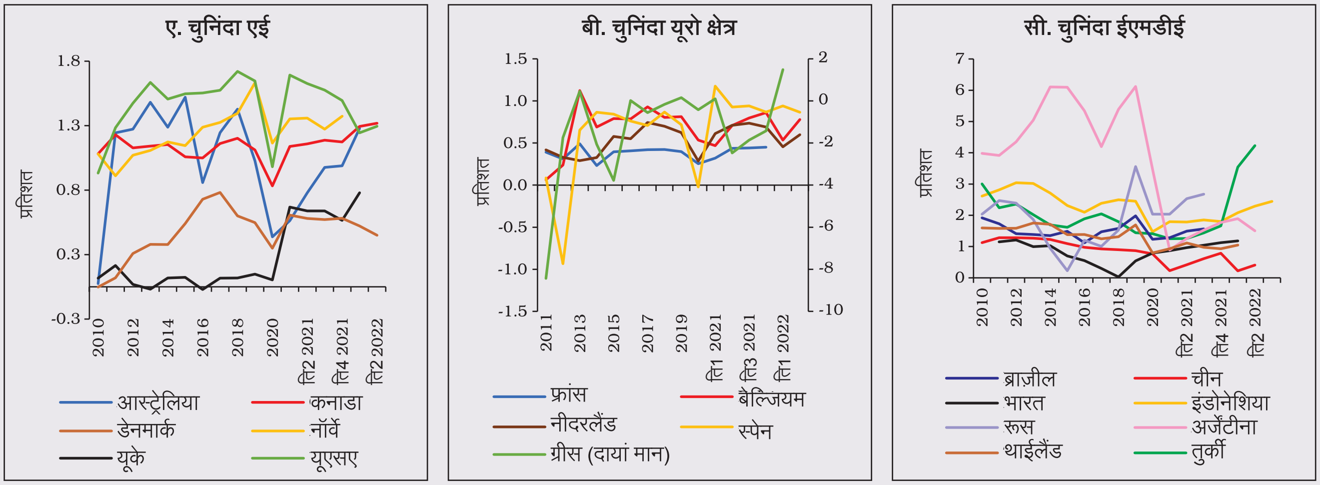

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

रही या उसमें सुधार हुआ (चार्ट II.7)।

लीवरेज अनुपात

II.43 लीवरेज अनुपात, *यानी* कुल आस्तियों के अनुपात में विनियामकीय टीयर-I पूंजी, बासेल III मानदंडों के तहत न्यूनतम 3 प्रतिशत से काफी अधिक रहा। एई में, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित स्तरों के दोगुने से अधिक का लीवरेज अनुपात बनाए रखा, हालांकि हाल की तिमाहियों में सामान्य गिरावट देखी गई थी। उच्च लीवरेज अनुपात बनाए रखने में यूरो क्षेत्र के बैंकों में जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल अगुवा हैं। ईएमडीई में, भारत और तुर्की ने वर्ष 2018 के बाद से अपने लीवरेज अनुपात में काफी सुधार किया है, जो पूंजीगत बफर की मजबूती का संकेत देता है (चार्ट II.8)।

चार्ट II.7: जोखिम-भारित आस्ति के लिए विनियामकीय पूंजी

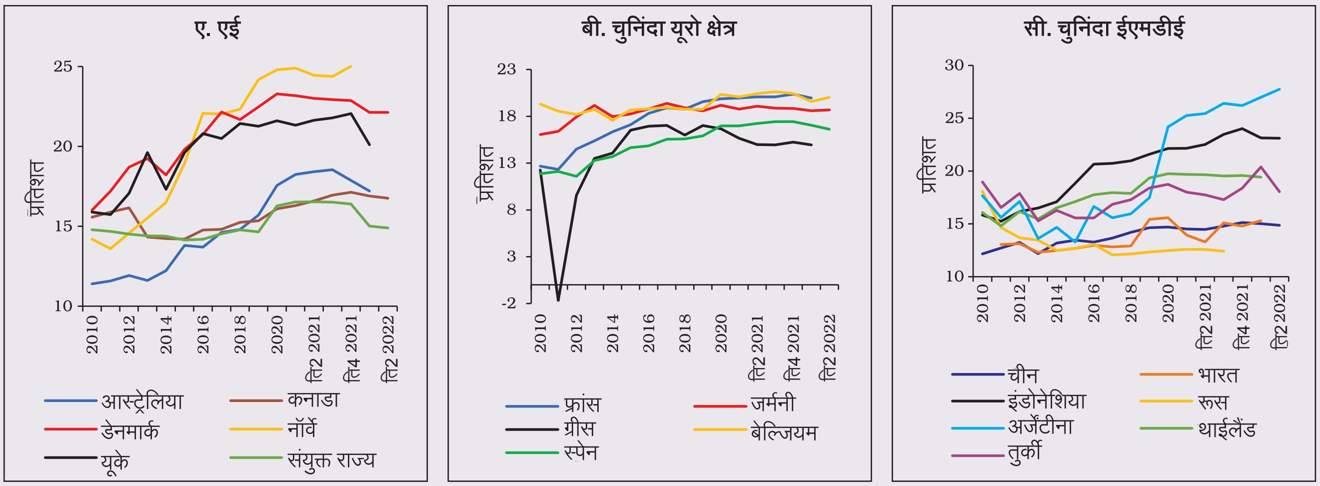

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

चार्ट II.8: लीवरेज अनुपात

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में विनियामकीय टीयर - I पूंजी)

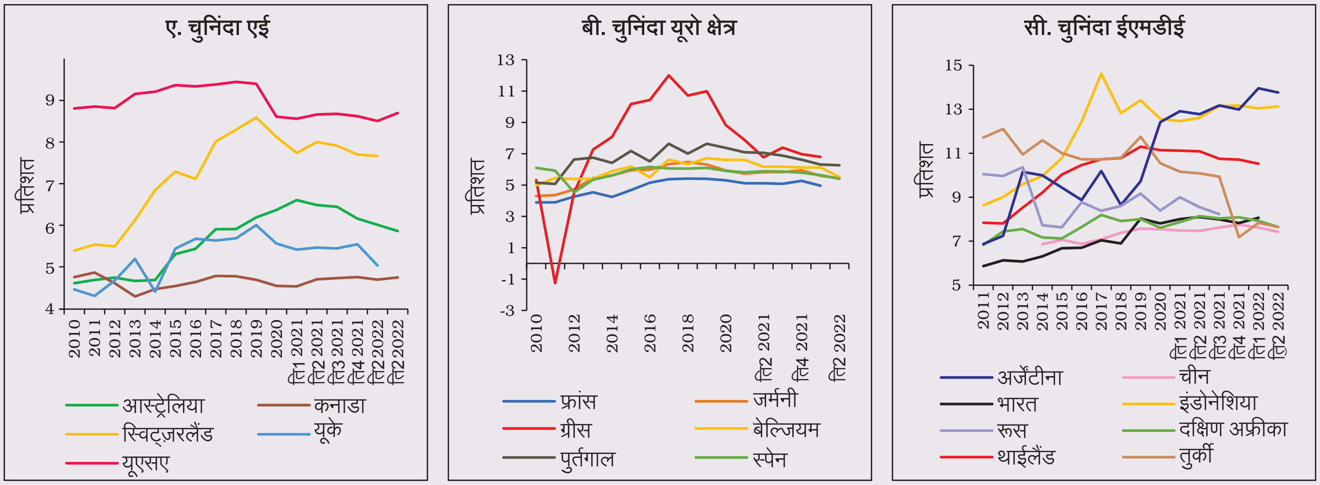

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

वित्तीय बाजार संकेतक

II.44 वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर बैंकिंग शेयरों में तेजी से गिरावट आई, लेकिन 2021 के दौरान केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि लगाने, आर्थिक गतिविधियों के कायापलट और धनात्मक वृद्धि दृष्टिकोण के माध्यम से सुधार हुआ। मार्च 2022 की शुरुआत में यूरोप में युद्ध से अनिश्चितता की नई स्थिति उत्पन्न होने से स्थिति उलट गई। तब से भारतीय बैंकों की इक्विटी कीमतों में सुधार हुआ है, जो मुख्य रूप से पूंजी की उनकी मजबूत स्थिति तथा लाभप्रदता और आस्ति की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। हाल के महीनों में अन्य एई और ईएमई में इक्विटी की कीमतों में भी सुधार हुआ है, लेकिन वे अभी भी पिछले चरम स्तर से नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं (चार्ट II.9ए)।

II.45 मार्च 2020 में अपने शीर्ष स्तर से गिरने के बाद, वर्ष 2022 की शुरुआत से बैंकों के ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड

चार्ट II.9: बैंक की सेहत के बाज़ार-आधारित संकेतक

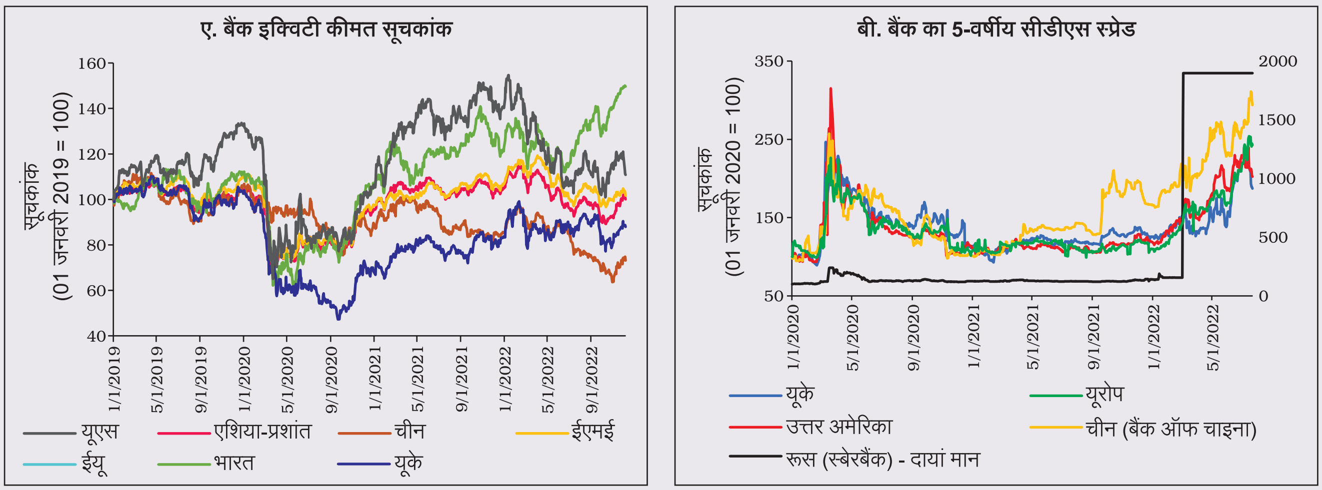

स्रोत: रेफिनिटिव डेटास्ट्रीम।

में काफी वृद्धि हुई है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक प्रतिबंधों और रेटिंग में गिरावट के कारण रूस में सीडीएस स्प्रेड में नाटकीय वृद्धि हुई है। अन्य बाजारों में बैंकों के सीडीएस विस्तार ने भी इसका अनुसरण किया; हालांकि, हाल के महीनों में स्प्रेड में कमी आई है (चार्ट II.9 बी)।

5. विश्व के सबसे बड़े बैंक

II.46 टीयर-1 पूंजी के आधार पर शीर्ष 100 बैंकों का देश-वार वितरण, वर्ष 2021 में काफी सीमा तक एक वर्ष पहले के समान रहा[42] (चार्ट II.10ए)। इसके अलावा, अन्य बैंकों की तुलना में सूची में शामिल चीन के 20 बैंकों में से 18 बैंकों की रैंकिंग में टीयर-1 के उच्चतर पूंजी संचयन के कारण सुधार हुआ है। परिणामस्वरूप, चीन स्थित बैंकों द्वारा धारित कुल आस्तियों का हिस्सा 2021 में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता गया जबकि इसी अवधि के दौरान एई में बैंकों की हिस्सेदारी घट गई (चार्ट II.10बी)।

II.47 आस्ति गुणवत्ता के संदर्भ में, शीर्ष 100 बैंकों के अनर्जक ऋणों (एनपीएल) में चीन के बैंकों की हिस्सेदारी वर्ष 2021 में बढ़ गई, जबकि एई के बैंकों की हिस्सेदारी में गिरावट आई (चार्ट II.11ए)। हालांकि, सूची में शामिल सभी चीन के बैंकों के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 100 प्रतिशत से अधिक था, जो संकट के मामले में हानि अवशोषण की उच्च क्षमता का संकेत देता है। इसके विपरीत, एई और ईएमडीई (चीन को छोड़कर) में लगभग आधे बैंकों के पीसीआर 100 प्रतिशत से अधिक थे (चार्ट II.11बी)।

II.48 वर्ष 2021 में बैंकों ने अपनी पूंजी को सुदृढ़ किया, सभी बैंकों ने जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को 12 प्रतिशत से अधिक और 64 बैंकों के सीआरएआर को 16 प्रतिशत से अधिक बनाए रखा (चार्ट II.12ए)। लीवरेज अनुपात (आस्ति-पूंजी अनुपात) के अनुसार बैंकों का विभाजन वर्ष 2021 में भी वर्ष 2020 की तरह ही बना रहा और केवल दो यूरोपीय बैंकों का लीवरेज अनुपात 3 प्रतिशत या उससे कम था। 64 बैंकों का लीवरेज अनुपात 6 प्रतिशत से अधिक था, जो उनकी पर्याप्त पूंजी स्थिति का सूचक है (चार्ट II.12बी)। बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में बैंकों ने 1 से 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत से अधिक की विस्तार सीमा में आरओए दर्ज किया (चार्ट II.12सी)।

चार्ट II.10: टीयर - I पूंजी के आधार पर शीर्ष 100 बैंकों का विभाजन

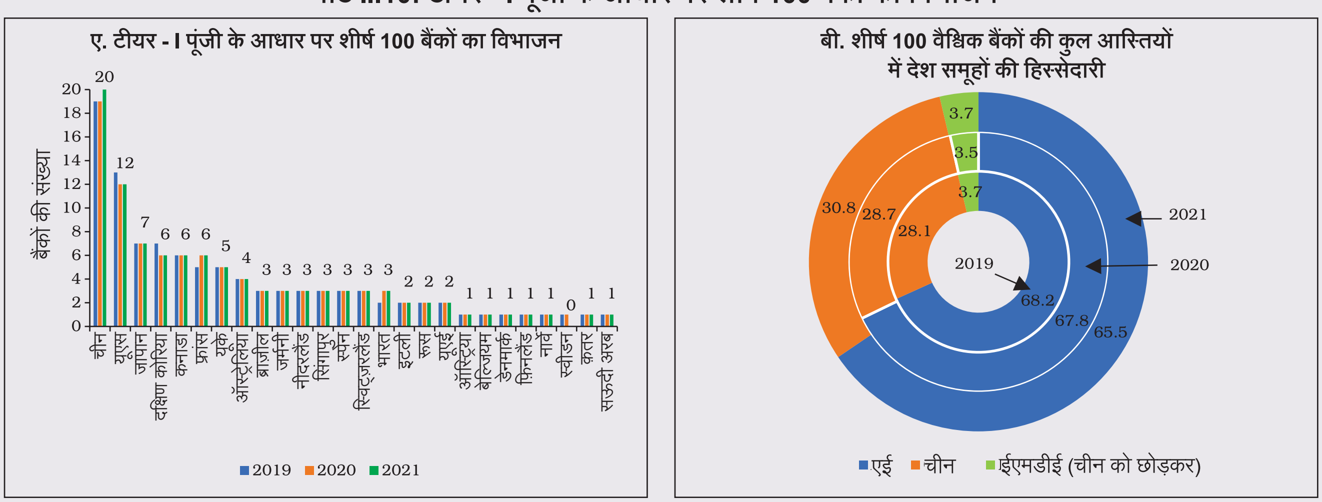

स्रोत: बैंकर्स डेटाबेस, फ़ाइनेंशियल टाइम्स।

[42] एकमात्र परिवर्तन यह था कि एक चीनी बैंक को सूची में जोड़ा गया और एक स्वीडिश बैंक को हटा दिया गया।

चार्ट II.11: शीर्ष 100 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

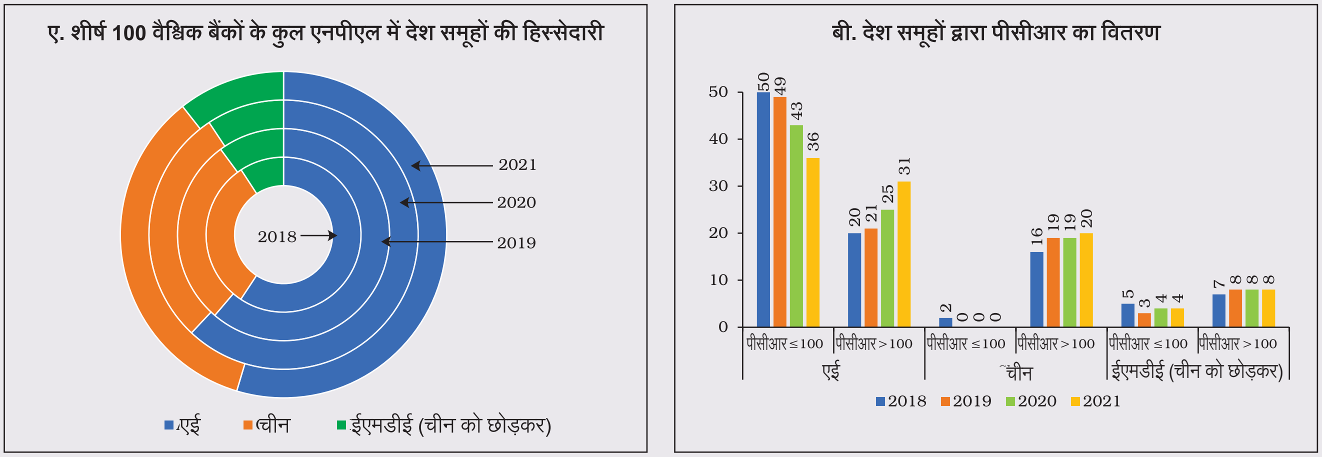

टिप्पणी: कुछ लुप्त मान के कारण बैंकों के आंकड़ों का जोड़ 100 से भिन्न हो सकता है।
स्रोत: बैंकर डेटाबेस, फ़ाइनेंशियल टाइम्स।

6. निष्कर्ष

II.49 वर्ष 2022 में वैश्विक वृद्धि कम होने से और 2023 में मंदी की बढ़ती संभावनाओं के साथ, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ऋण वृद्धि चक्रीय रूप से कम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की लाभप्रदता कम हो सकती है। आगे चलकर, जहां बैंकों ने उच्च पूंजी बफर और बेहतर आस्ति गुणवत्ता से महामारी का सामना किया, वहीं वे अत्यधिक अनिश्चित परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, सख्त मौद्रिक और चलनिधि की स्थिति और लाभप्रदता एवं आस्ति गुणवत्ता पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, नवोन्मेषों के एक नए दौर और जलवायु परिवर्तन जोखिमों के बीच वित्तीय प्रणाली में प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाने से वित्तीय स्थिरता के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं, जिसके लिए जोखिम कम करने वाले विनियामकीय और पर्यवेक्षी कार्यों की आवश्यकता होगी।

चार्ट II.12: शीर्ष 100 बैंकों की सुदृढ़ता

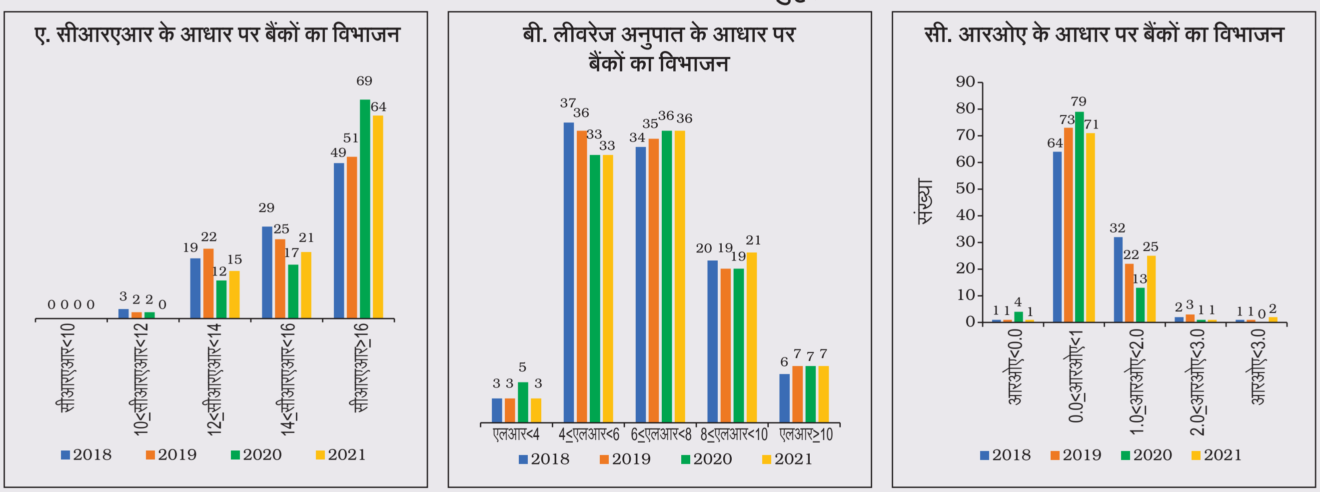

स्रोत: बैंकर डेटाबेस, फ़ाइनेंशियल टाइम्स।

III नीतिगत परिवेश

2021-22 में रिज़र्व बैंक की नीतियों का उद्देश्य महामारी के प्रभाव को कम करना और आर्थिक बहाली का पोषण करना था। 2022-23 के दौरान अब तक, नीतिगत ध्यान मूल्य स्थिरता हासिल करने पर केंद्रित हो गया है, जिसमें नीतिगत दर संबंधी कार्रवाई और उदार रुख को क्रमिक रूप से वापस लेना शामिल है। रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी नीति संबंधी उपाय विनियमित संस्थाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार करने के लिए किए गए थे।।

1. भूमिका

III.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतियों का ध्यान उदीयमान आर्थिक बहाली को सहारा देते हुए अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने पर केंद्रित करना जारी रखा। वर्ष की दूसरी छमाही में, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने और मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, नियत तारीखों के संबंध में महामारी से जुड़े उपायों को कालातीत होने देने और अपरंपरागत उपायों को समाप्त करते हुए चलनिधि को सुविचारित तरीके से वापस लेने की दिशा में क्रमिक बदलाव हुआ। 2022-23 के दौरान अब तक, स्फीतिकारी दबावों के मद्देनजर नीति का ध्यान मूल्य स्थिरता हासिल करने पर केंद्रित हो गया है। तदनुसार, नीति दर में वृद्धि और उदार रुख को क्रमिक रूप से वापस लेना शुरू हो गया है। इसके साथ ही, रिज़र्व बैंक ने प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी सुधार की भी शुरुआत की है, जिसमें संभावित कमजोरियों को कम करने, वित्तीय बाजारों के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने, वित्तीय सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार करने, भुगतान परिवेश में सुधार करने और डिजिटल बैंकिंग को अपनाने में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

III.2 इस पृष्ठभूमि में, खंड 2 में मौद्रिक और चलनिधि उपायों का ब्योरा देते हुए इस अध्याय की शुरूआत की गई है। इसके बाद खंड 3 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और क्रेडिट सहकारी समितियों के संबंध में विनियामक नीति में हुई प्रगति का अवलोकन किया गया है। खंड 4 में बैंकों और एनबीएफसी संबंधी पर्यवेक्षी कार्यनीतियों पर चर्चा की गई है, जबकि प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण से संबंधित नीतियों को खंड 5 में शामिल किया गया है। वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा, एवं ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेश से संबंधित नीतियां क्रमशः खंड 6 और 7 में शामिल हैं। खंड 8 में उपभोक्ता संरक्षण और खुदरा भागीदारी से संबंधित पहलों की समीक्षा की गई है, जबकि खंड 9 में भुगतान परिवेश के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के संबंध में रिज़र्व बैंक की पहलों को निर्धारित किया गया है। अंततः, खंड 10 में अध्याय का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

2. मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन

III.3 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने कोविड-19 की दूसरी लहर के गंभीर प्रभाव के बाद हुई कमजोर वापसी को सहारा देने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 2021-22 के दौरान 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और अन्य पण्य की कीमतों की वजह से 2021-22 की चौथी तिमाही में बना स्फीतिकारी दबाव 2022-23 की पहली छमाही में कम होने की उम्मीद थी। तदनुसार, एमपीसी ने 2021-22 के दौरान एक उदार मौद्रिक नीति रुख जारी रखने का निर्णय लिया।

III.4 वर्ष 2021-22 में एमपीसी की छठी और अंतिम बैठक से एक पखवाड़े के भीतर, भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया और इस प्रकार वैश्विक और घरेलू दृष्टिकोण में भारी बदलाव आया। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और अन्य पण्यों की बढ़ती कीमतों एवं खाद्य और ऊर्जा की कमी की वजहों से घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने और संवृद्धि संबंधी दृष्टिकोण में गिरावट का जोखिम बना। एमपीसी ने अपने अप्रैल 2022 के संकल्प में नीतिगत दर को बरकरार रखने का फैसला किया था। हालांकि, रिज़र्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन ढांचे को बहाल करने के जरिए उदार रुख को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ), स्थायी दर रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) को एलएएफ के फ्लोर के रूप में परवर्ती के ऊपर 40 आधार अंक (बीपीएस) की दर से प्रतिस्थापित करते हुए, प्रांरभ करने की बदौलत मौद्रिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से सख़्त किया गया क्योंकि मुद्रा बाजार की दरें उनके महामारी के निचले स्तर से बढ़ीं और चलनिधि की अधिकता को भिन्न-भिन्न परिपक्वता वाली परिवर्तनीय रिवर्स रेपो (वीआरआर) नीलामियों के माध्यम से कम किया गया। युद्ध के झटके के कारण पण्य की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गईं और मुद्रास्फीति संबंधी दृष्टिकोण बढ़ने का जोखिम उत्पन्न होने के साथ, एमपीसी ने मई 2022 में एक ऑफ-साइकिल बैठक में नीतिगत रेपो दर में 40 बीपीएस की बढ़ोतरी की, इसके बाद जून 2022, अगस्त 2022 और सितंबर 2022 प्रत्येक में 50 बीपीएस और दिसंबर 2022 में 35 बीपीएस की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार, मई 2022 के बाद से, रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने और बारंबार पड़ने वाले झटकों के दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने के लिए नीतिगत रेपो दर में संचयी तौर पर 225 बीपीएस की वृद्धि की है। भारत के अनुभवजन्य अनुमानों से संकेत मिलता है कि उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति ऋण बाजार के कामकाज के लिए हानिकारक है (बॉक्स III.1)।

2021-22 के दौरान चलनिधि प्रबंधन

III.5 रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2021 में द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) 1.0 की घोषणा की, ताकि भारी मात्रा में उधार लेने संबंधी केंद्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के मद्देनजर बाजार की भावनाओं को आत्मसात किया जा सके, इसके बाद 2021-22 की पहली छमाही में संचयी रूप से ₹2.2 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) खरीदने की प्रतिबद्धता के साथ जून 2021 में जी-एसएपी 2.0 लाया गया। जी-एसएपी के तहत, रिज़र्व बैंक ने परिपक्वता स्पेक्ट्रम में ऑन दि रन (लिक्विड) और ऑफ दि रन (इलिक्विड) दोनों तरह की प्रतिभूतियां खरीदीं, जिनमें से 68 प्रतिशत से अधिक खरीद 5 से 10 साल के परिपक्वता खंड में संकेंद्रित थी, इस प्रकार मीयाद संरचना के मध्य खंड के परिपक्वताओं के लिए चलनिधि प्रदान की गई। जी-एसएपी ने जी-सेक प्रतिफल में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करके मौद्रिक संचरण को भी सुगम बनाया, जो अन्य वित्तीय बाजार लिखतों के मूल्य निर्धारण के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करता है। अक्टूबर 2021 में अधिशेष चलनिधि की बहुतायत को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने जी-एसएपी को बंद कर दिया।

III.6 जी-एसएपी के अलावा, रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को ₹66,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान कीं; देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाने के लिए ₹50,000 करोड़ की सावधि चलनिधि सुविधा; लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ), जिनमें से ₹10,000 करोड़ प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के नए ऋण देने में लगाए जाने थे; और कतिपय संपर्क-गहन क्षेत्रों पर महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए ₹15,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि सुविधा। तनावग्रस्त क्षेत्रों की जरूरतों को देखते हुए प्रमुख लक्षित चलनिधि सुविधाओं की समय-सीमा भी बढ़ा दी गई थी: एसएफबी हेतु एसएलटीआरओ सुविधा 31 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध कराई गई थी, जबकि इसे ऑन-टैप पर भी उपलब्ध कराया गया था; आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ और संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ₹15,000 करोड़ की चलनिधि सुविधा को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

III.7 यह मानते हुए कि महामारी-प्रेरित उपायों से भारी मात्रा में चलनिधि की अधिकता जोखिम के गलत मूल्य-निर्धारण

बॉक्स III.1 मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव और ऋण वृद्धि

एरर करेक्शन के साथ ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल में (एआरडीएल-ईसी)[1 एवं 2] जनवरी 2009 से मार्च 2022 तक के मासिक डेटा का विश्लेषण किया गया। नतीजा दर्शाते हैं कि मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव दोनों भविष्य के नकदी प्रवाह के आसपास अनिश्चितता पैदा करके ऋण वृद्धि को घटाती हैं, जिससे निवेश योजना के संबंध में निर्णय लेने में देरी होती है (फ्रीडमैन, 1977 और फिशर, सहाय, और वेघ, 2002)। जबकि उच्च ब्याज दरों का ऋण वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, रिज़र्व बैंक के सूचकांक (बीईआई)[3] में सन्निहित कारोबारी प्रत्याशाएं ऋण वृद्धि के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं। लंबे समय तक चलने वाले संतुलन में गड़बड़ी को मध्यम गति से ठीक किया जाता है। इससे पता चलता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विश्वसनीय, फ्रंट-लोडेड कार्रवाइयों से झटके के बाद ऋण बाजार को तेजी से सामान्य बनाने में मदद मिल सकती है (सारणी 1)।

सारणी 1: एआरडीएल रिग्रेशन परिणाम

ऋण वृद्धि	गुणांक	मानक त्रुटि	टी-सांख्यिकी	पी>टी
एडीजे				
ऋण वृद्धि (एल1).	-0.1399	0.0395	-3.54	0.001***
एलआर				
Δ ब्याज (एल1).	-0.4377	0.2492	-1.76	0.081*
मुद्रास्फीति (एल 1).	-2.4329	1.2256	-1.99	0.049**
मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव (एल1).	2.4396	2.6719	0.91	0.363
बीईआई (एल1).	0.6967	0.1985	3.51	0.001***
जीडीपी वृद्धि (एल1).	0.1123	0.1655	0.68	0.499
कान्स्टन्ट	-73.7918	22.6043	-3.26	0.001***
एसआर				
ऋण वृद्धि				
एलडी.	-0.1647	0.0846	-1.95	0.054*
एल2डी.	-0.1022	0.0803	-1.27	0.205
एल3डी.	0.2086	0.0772	2.70	0.008***
Δ ब्याज				
डी1.	-0.0254	0.0277	-0.92	0.361
एलडी.	0.0814	0.0282	2.89	0.004***
एल2डी.	0.0848	0.0275	3.09	0.002***
मुद्रास्फीति (तिमाही)				
डी1.	-0.7663	0.1550	-4.95	0.000***
मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव				
डी1.	-2.8310	1.0854	-2.61	0.010**
बीईआई				
डी1.	0.0710	0.0407	1.75	0.083*
एलडी.	-0.1675	0.0449	-3.73	0.000***
एल2डी.	-0.0698	0.0446	-1.57	0.119
एल3डी.	-0.1035	0.0439	-2.36	0.020**
जीडीपी वृद्धि				
डी1.	0.0157	0.0228	0.69	0.491

नंबर ऑफ आब्जर्वेशन्स = 155
आर-स्क्वयर्ड = 0.3607
समायोजित आर-स्क्वयर्ड = 0.2761

टिप्पणियां: 1. बीईआई कारोबार प्रत्याशा सूचकांक है।
2. एल1, एल2, एल3 का तात्पर्य संगत अंतराल से है।
3. डी का तात्पर्य अंतर से है।
4. एलडी का तात्पर्य अंतराल के बीच अंतर से है।
5. एआरडीएल बाउंड्स परीक्षण बताता है कि निष्कर्ष मजबूत हैं।
6. *** पी<0.01, ** पी<0.05, * पी<0.1

संदर्भ

फिशर, एस., सहाय, आर., एंड वेग, सी.ए. (2002). मॉर्डन हाइपर एंड हाइ इन्फ्लेशन्स। *जर्नल ऑफ इकनामिक लिट्रेचर*।

फ्रीडमैन, एम. (1977). इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। *जर्नल ऑफ पोलिटिकल इकानमी*।

पेसरन, एम. एच., एंड शिन, वाई. (1997). एन ऑटोरिग्रेसिव लैग मॉडलिंग अप्रोच टु कोइंटीग्रेशन एनेलिसिस। *इकनोमेट्रिक्स एंड इकनामिक थियरी इन द 20थ सेंचुरी: द रागनार फ्रिश सेन्टेन्नियल सिम्पोसियम*। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

पेसरन, एम. एच., शिन, वाई., एंड स्मिथ, आर. जे. (2001). बाउंड्स टेस्टिंग अप्रोचस टु द एनेलिसिस ऑफ लेवल रिलेशनशिप्स। *जर्नल ऑफ अप्लाइड इकनोमेट्रिक्स*।

और वित्तीय स्थिरता चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है, रिज़र्व बैंक ने 2021-22 के दौरान चलनिधि की स्थिति को सामान्य अवस्था में लाना शुरू कर दिया ताकि उसे पनपते समष्टिआर्थिक बदलाव के अनुरूप किया जा सके। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को दो चरणों में निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत के अपने महामारी-पूर्व स्तर पर बहाल किया गया था, जिसमें से प्रत्येक में 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई थी, जो 27 मार्च 2021 और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी था।

[1] चूंकि विचाराधीन चर एकीकरण के विभिन्न क्रमों के हैं, इसलिए सह-एकीकरण के एंगल ग्रेंजर और जोहान्सन परीक्षणों को लागू नहीं किया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए एआरडीएल पद्धति को चुना गया।

[2] मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव की गणना एक एक्सपोनेंशियल जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिक (ईजीएआरसीएच (1,1)) मॉडल का उपयोग करके की गई थी क्योंकि यह मापदंडों पर नॉन-नेगेटिविटी कन्स्ट्रैन्ट्स को अधिरोपित नहीं करता है और मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले झटकों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव की अनुक्रियता में विषमता को पकड़ने में सक्षम है (काटूसाइम, 2018).

[3] कारोबार प्रत्याशा सर्वेक्षण (बीईआई) में नौ मापदंड शामिल हैं- (1) समग्र कारोबार स्थिति, (2) उत्पादन, (3) ऑर्डर बुक, (4) कच्चे माल की सूची, (5) तैयार माल की सूची, (6) लाभ मार्जिन, (7) रोजगार, (8) निर्यात और (9) क्षमता उपयोग। 100 से ऊपर का मान समग्र कारोबार गतिविधि के विस्तार को दर्शाता है और 100 से नीचे का मान संकुचन को दर्शाता है।

III.8 संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को बहाल करने के हिस्से के रूप में मुख्य चलनिधि प्रबंधन साधन के रूप में 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से, अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान ₹2.0 लाख करोड़ से दिसंबर 2021 के अंत तक ₹7.5 लाख करोड़ के पूर्व-घोषित कार्यक्रम के माध्यम से वीआरआरआर नीलामियों के आकार में वृद्धि की गई थी। नतीजतन, अधिशेष चलनिधि अवशोषण को दीर्घावधिक 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों की तुलना में ओवरनाइट एफआरआरआर विंडो के जरिए निर्बाध रूप से पुनर्संतुलित किया गया। इन परिचालनों को 28-दिवसीय वीआरआरआर और 3-8 दिनों की परिपक्वता वाले फाइन-ट्यूनिंग परिचालनों का सहारा मिला। इन गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए, एफआरआरआर के तहत अवशोषित राशि 2021-22 की पहली छमाही के दौरान ₹4.6 लाख करोड़ से भारी रूप से घटकर 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान औसतन ₹2.0 लाख करोड़ हो गई।

III.9 चलनिधि अधिशेष को अवशोषित करने की दिशा में एक अतिरिक्त कदम के रूप में, बैंकों को दिसंबर 2021 में एक और विकल्प प्रदान किया गया था ताकि वे मार्च-अप्रैल 2020 के दौरान आयोजित लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ 1.0 और 2.0) के तहत प्राप्त धन की बकाया राशि का पूर्व भुगतान कर सके। तदनुसार, बैंकों ने नवंबर 2020 में पहले भुगतान किए गए ₹37,348 करोड़ के अतिरिक्त दिसंबर 2021 में ₹2,434 करोड़ लौटाए।

III.10 महामारी के बाद की अवधि में अधिशेष चलनिधि स्थिति की वजह से बैंकों द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के लिए सीमित सहारे को देखते हुए, बैंकों को उनके एनडीटीएल के 2 प्रतिशत (महामारी के दौरान 3 प्रतिशत के बजाय) तक का उपयोग करने की अनुमति देने की सामान्य छूट को 1 जनवरी 2022 से बहाल कर दिया गया था।

III.11 सामान्य स्थिति उत्तरोत्तर रूप से कायम होने के साथ, रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी 2022 को घोषणा की कि (i) आरक्षित निधि बनाए रखने की अवधि के दौरान किसी अप्रत्याशित चलनिधि बदलावों से निपटने के लिए फाइन-ट्यूनिंग परिचालन के रूप में आवश्यकता पड़ने पर भिन्न-भिन्न अवधि के वीआरआर परिचालन किए जाएंगे, जबकि यदि आवश्यक हो तो लंबी परिपक्वता की नीलामी भी आयोजित की जाएगी; और (ii) एफआरआरआर और एमएसएफ परिचालन के लिए विंडो 1 मार्च 2022 से सभी दिनों में 17.30-23.59 बजे के दौरान उपलब्ध होगा (30 मार्च 2020 से 09.00-23.59 बजे के मुकाबले)। बाजार सहभागियों को सूचित किया गया कि वे एफआरआरआर से अपने शेष को वीआरआरआर नीलामी में स्थानांतरित करें और परिचालन सुविधा[4] के लिए ई-कुबेर पोर्टल में स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा का लाभ उठाएं।

2022-23 के दौरान चलनिधि प्रबंधन

III.12 आर्थिक बहाली की गति जोर पकड़ने और मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहनशील बैंड के ऊपर बनी रहने की पृष्ठभूमि में, 2022-23 के दौरान चलनिधि प्रबंधन का ध्यान गैर-बाधाकारी तरीके से उदार रुख को वापस लेने की ओर बदला।

III.13 अप्रैल 2022 में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, 3.75 प्रतिशत पर एसडीएफ को एफआरआरआर के स्थान पर एलएएफ कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में पेश किया गया था। इस प्रकार, एसडीएफ दर को उस समय प्रचलित नीतिगत दर (4.00 प्रतिशत) से 25 बीपीएस नीचे रखा गया था और यह ओवरनाइट जमाराशियों पर लागू था; हालांकि, एसडीएफ विंडो ने उचित मूल्य निर्धारण के साथ, यदि आवश्यक हो, लंबे परिपक्वता काल की चलनिधि को अवशोषित करने के लचीलेपन को बरकरार रखा। एमएसएफ दर को 4.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया था, अर्थात, नीतिगत रेपो दर से 25 बीपीएस ऊपर। इस प्रकार, एलएएफ कॉरिडोर के दायरे को नीतिगत रेपो दर के आसपास सममित रूप से +/- 25 बीपीएस के महामारी-पूर्व की स्थिति में लाया गया (चार्ट III.1)।

4 एएसआईएसओ अगस्त 2020 में पेश किया गया था ताकि बैंकों को उनके दिन के अंत में सीआरआर शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके, जिसके तहत बैंक एक विशिष्ट (या की सीमा) राशि को पूर्व निर्धारित करते हैं जिसे वे दिन के अंत में बनाए रखना चाहते हैं। एएसआईएसओ सुविधा के तहत, जैसा भी मामला हो, कोई कमी या बनाए रखा गया अधिक शेष स्वचालित रूप से एमएसएफ या रिवर्स रेपो बोलियां का आह्वान करेगा।

चार्ट III.1: प्रमुख मौद्रिक नीतिगत दरें

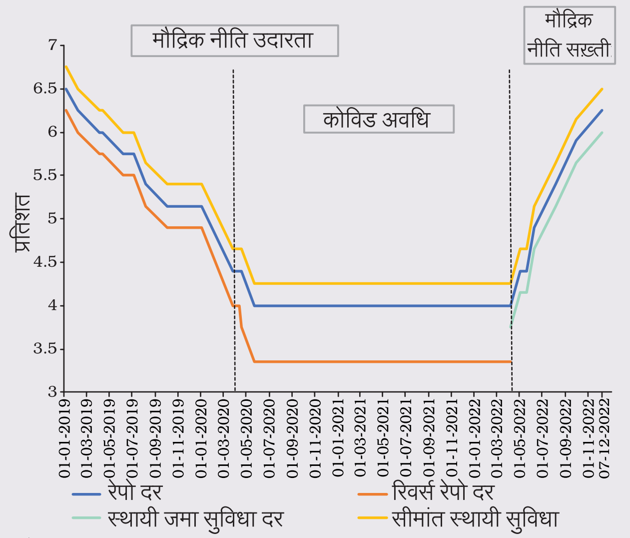

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था का डेटाबेस, आरबीआई।

एसडीएफ प्रारंभ करने के साथ, एफआरआरआर दर को 3.35 प्रतिशत पर बनाए रखा गया और इसे नीतिगत रेपो दर से अलग कर दिया गया। यह टूलकिट का हिस्सा बना रहेगा और समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए रिज़र्व बैंक के विवेक पर इसका उपयोग किया जाएगा। एमएसएफ के समान, एसडीएफ तक पहुंच बैंकों के विवेक पर है, रेपो/रिवर्स रेपो, खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) और सीआरआर के विपरीत जो रिज़र्व बैंक के विवेक पर हैं। केंद्रीय बैंक पर बाध्यकारी संपार्श्विक बाधा को दूर करके, एसडीएफ मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे को मजबूत करता है। इसके अलावा, यह चलनिधि प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एक वित्तीय स्थिरता साधन है।

III.14 दिनांक 4 मई 2022 को एक ऑफ-साइकिल बैठक में नीतिगत रेपो दर में वृद्धि के साथ, रिज़र्व बैंक ने सीआरआर को 50 बीपीएस बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत कर दिया (21 मई 2022 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी), और इस प्रकार ₹87,000 करोड़ की राशि की प्राथमिक चलनिधि बैंकिंग प्रणाली से वापस ले ली गई। उदारता को वापस लेने के रुख के अनुरूप, एलएएफ के तहत दैनिक औसत अवशोषण द्वारा इंगित अधिशेष चलनिधि मार्च 2022 के दौरान ₹7.5 लाख करोड़ से कम होकर दिसंबर 2022 (11 दिसंबर तक) में ₹2.6 लाख करोड़ हो गई। संचयी रूप से, इन उपायों ने धीरे-धीरे ओवरनाइट मुद्रा बाजार दरों को नीतिगत रेपो दर के करीब लाया। कर बहिर्वाह के कारण थोड़े समय के लिए चलनिधि कमी होने की वजह से अस्थायी चलनिधि तंगी को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई और 21 सितंबर 2022 को क्रमशः 3 दिन और 1 दिन की परिपक्वता वाली दो वीआरआर नीलामी की। आगे बढ़ते हुए, रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में अधिक मुस्तैद और लचीला होगा।

3. विनियामकीय नीतियां

III.15 रिज़र्व बैंक ने कोविड-पश्चात के मौद्रिक और चलनिधि संबंधी उपायों को विनियामकीय नीति में बदलाव के जरिए बल प्रदान किया ताकि वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए महामारी के प्रभाव को कम किया जा सके। वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान और 2022-23 में अब तक, रिज़र्व बैंक का ध्यान विनियमित संस्थाओं (आरई) और उनके ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोविड-पश्चात के नीतिगत आसरे और विनियमों को क्रमिक और गैर-हानिकारक रूप से वापस लेने पर केंद्रित रहा है।

3.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

सूक्ष्मवित्त ऋण के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क

III.16 एनबीएफसी - सूक्ष्मवित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के विनियामकीय फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से सभी आरई द्वारा सूक्ष्मवित्त ऋण देने के लिए एक समान विनियामक फ्रेमवर्क पेश किया गया था। सूक्ष्मवित्त ऋण की एक सामान्य परिभाषा शुरू करने और इन गतिविधियों में लगी 'लाभ के लिए नहीं' कंपनियों के मामाले में छूट को वापस लेने के अलावा दिशानिर्देशों में आरई को घरेलू आय और ऋणग्रस्तता के आकलन, सूक्ष्मवित्त ऋण

के मूल्य-निर्धारण, कर्मचारियों का आचरण और उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार सूक्ष्मवित्त ऋणों की चुकौती की आवधिकता में लचीलापन के संबंध में बोर्ड-अनुमोदित नीतियों को लागू करने की भी आवश्यकता है। सूक्ष्मवित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन शुरू करने के अलावा, इस ढांचे का उद्देश्य सूक्ष्मवित्त उधारकर्ताओं को डीलीवरेज करना, ग्राहक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाना और सूक्ष्मवित्त उधारकर्ताओं की ऋण जरूरतों को व्यापक तरीके से पूरा करने के लिए आरई को लचीला बनाना है।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक)[एफसीएनआर(बी)] योजना – संशोधित बेंचमार्क दर

III.17 बेंचमार्क दर के रूप में लंदन अंतरबैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) को बंद करने के मद्देनजर, नवंबर 2021 में यह निर्णय लिया गया था कि बैंकों को संबंधित मुद्रा के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर (ओ-एआरआर) का उपयोग करते हुए एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें पेश करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाली एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के लिए ब्याज दर सीमा को ओ-एआरआर या स्वैप प्लस 250 बीपीएस के रूप में संशोधित किया गया था। 3 वर्ष और उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक और सहित की जमाराशियों के लिए इसे ओ-एआरआर या स्वैप प्लस 350 बीपीएस के रूप में संशोधित किया गया था। दिनांक 6 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता और आगामी स्पिलओवर के कारण पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के उपाय के रूप में 31 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए सीमा को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था।

प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान आवश्यकता

III.18 आरई को अपनी दबावग्रस्त आस्तियां आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को अन्य चीजों के साथ-साथ एआरसी द्वारा जारी किए गए एसआर के बदले बेचने की अनुमति दी गई हैं, भले ही उनके पुराने मानदंड कुछ भी हों। ऐसे मामलों में जहां एसआर के बदले दबावग्रस्त आस्तियां बेची जाती हैं, अंतर्निहित एक्सपोजर के जोखिम प्रभावी रूप से बेचने वालों की बही से अलग नहीं होते हैं। इस चिंता को कम करने और ऐसी आस्तियों की 'वास्तविक बिक्री' सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2016 में रिज़र्व बैंक ने एक न्यूनतम सीमा के साथ उच्च प्रावधान निर्धारित किया था जब ऐसे विशिष्ट प्रतिभूतिकरण के तहत जारी किए गए एसआर में निवेश कुल एसआर का 50 प्रतिशत (बाद में घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया) से अधिक हो गया था। ये निर्देश 24 सितंबर 2021 को सभी उधारदाताओं पर लागू किए गए थे। सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एससीबी के अलावा आरई को 28 जून 2022 को सूचित किया गया कि अतिरिक्त प्रावधान को 31 मार्च 2022 को समाप्त, अर्थात, 2021-22 से 2025-26 तक, वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि में विस्तारित किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए अतिरिक्त प्रावधान कुल आवश्यक प्रावधानों के पांचवें हिस्से से कम नहीं होने चाहिए।

बृहत् एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ)

III.19 एक औपचारिक सीमापार समाधान व्यवस्था के अभाव में विदेशी बैंकों (एफबी) का अपने प्रधान कार्यालय (एचओ) पर एक्सपोज़र के लिए एक बृहत् एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) लागू किया गया था ताकि भारत में उनकी शाखाओं के परिचालन पर ध्यानपूर्वक नज़र रखा जा सके। यह देखते हुए कि इससे ऐसे बैंकों पर अतिरिक्त पूंजी का बोझ पड़ेगा, 9 सितंबर 2021 को एक नया ऋण जोखिम शमन (सीआरएम) प्रणाली जारी की गई। सीआरएम में नकद/बिना देनदारी वाली अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं, जिनके स्रोत एचओ से ब्याज-मुक्त धन या भारतीय बहीखातों (आरक्षित निधि) में रखे गए विप्रेषणीय अधिशेष होने चाहिएं। विदेशी बैंक शाखाओं के एचओ (विदेशी शाखाओं सहित) के सकल एक्सपोज़र को कुछ शर्तों के अधीन एलईएफ सीमाओं की गणना करते समय सीआरएम के साथ

ऑफसेट करने की अनुमति दी गई थी। विदेशी बैंक शाखाओं को एचओ पर डेरिवेटिव एक्सपोज़र की गणना करते समय 1 अप्रैल 2019 (ग्रैंडफादरिंग) से पहले निष्पादित सभी डेरिवेटिव संविदाओं को बाहर करने की अनुमति दी गई थी।

निदेशकों के लिए ऋण की सीमा

III.20 अन्य बैंकों के निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों (स्वयं के बैंकों के साथ-साथ अन्य बैंकों के भी) को बैंक के बोर्ड या प्रबंधन समिति की मंजूरी की आवश्यकता वाले ऋण की सीमा 1996 में ₹25 लाख तय की गई थी। सामान्य कीमतों में वृद्धि, विशेषज्ञ पेशेवरों को बोर्ड में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने और बोर्ड या प्रबंधन समिति के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों की संख्या को कम करने की दृष्टि से सीमा में संशोधन कर वृद्धि की आवश्यकता थी। तदनुसार, 23 जुलाई 2021 को, रिज़र्व बैंक ने अन्य बैंकों के निदेशकों को व्यक्तिगत ऋण और निदेशकों के रिश्तेदारों (स्वयं के बैंकों के साथ-साथ अन्य बैंकों के भी) और संबद्ध संस्थाओं को सभी ऋणों की मंजूरी के लिए सीमा को संशोधित कर ₹5 करोड़ कर दिया।

पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड में बैंकों के निवेश का उचित मूल्यांकन

III.21 दिनांक 31 मार्च 2022 को रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि 2021-22 से बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को उनके उचित मूल्य या परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में शुरू में दर्शाए गए बाजार मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा। निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर अधिग्रहण लागत और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को तुरंत लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाएगा ।

निवल स्थिर निधीयन अनुपात का कार्यान्वयन

III.22 बासेल III निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश 17 मई 2018 को जारी किए गए थे और 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाले थे। कोविड-19 संबंधी अनिश्चितता के कारण, इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को 30 सितंबर 2021 तक उत्तरोत्तर रूप से स्थगित कर दिया गया था और यह 1 अक्टूबर 2021 से लागू हुआ था।

एलसीआर और एनएसएफआर के लिए लघु कारोबार ग्राहकों की परिभाषा की समीक्षा

III.23 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और एनएसएफआर को बनाए रखने के लिए, मौजूदा दिशानिर्देश में गैर-वित्तीय लघु कारोबार ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशियों और निधियों के अन्य आयाम को खुदरा खातों की तरह ही समान चलनिधि जोखिम विशिष्टता रखने के रूप में माना गया है। पात्र होने के लिए, प्रत्येक ग्राहक से एकत्रित धन पर ₹5 करोड़ (समेकित आधार पर जहां लागू हो) की सीमा निर्धारित की गई थी। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को बेहतर ढंग से बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के मानकों के अनुरूप करने और बैंकों को अधिक प्रभावी ढंग से चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, 06 जनवरी 2022 से इस सीमा को बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ कर दिया गया।

केवाईसी का आवधिक अद्यतन

III.24 महामारी के दौरान ग्राहकों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए आरई को 5 मई 2021 को सूचित किया गया था कि जिन मामलों में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अद्यतन होना बाकी और लंबित था, उनके खातों के परिचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। इस छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था।

III.25 आरई को उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए क्रमशः 2 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष में कम से कम एक बार केवाईसी (पुनः केवाईसी) को समय-समय पर अद्यतन करना आवश्यक है। रिज़र्व बैंक ने 10 मई 2021 को इस प्रक्रिया को सरल किया। केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, ग्राहक द्वारा डिजिटल समेत विभिन्न चैनलों का उपयोग करके एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है। यह प्रावधान विधिक संस्थाओं (एलई) के संबंध में भी पेश किया गया था। केवल व्यक्तिगत ग्राहक के पते में परिवर्तन के मामले में, नए पते की स्व-घोषणा की अनुमति दी गई है, बशर्ते

आरई द्वारा दो महीने के भीतर 'सकारात्मक पुष्टि' के माध्यम से सत्यापन किया जाए। इन सरल उपायों से ग्राहकों को सुविधा मिलने और आरई को समय पर केवाईसी रिकॉर्ड अद्यतन करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जलवायु जोखिमों के लिए विनियामकीय प्रतिक्रिया

III.26 रिज़र्व बैंक 23 अप्रैल 2021 को वित्तीय प्रणाली हरितकरण नेटवर्क (एनजीएफएस) में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ और 3 नवंबर 2021 को अपना 'भारत की वित्तीय प्रणाली के हरितकरण के समर्थन हेतु प्रतिबद्धता वक्तव्य' प्रकाशित किया। जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के बढ़ते महत्व को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने मई 2021 में जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के क्षेत्र में विनियामक पहलों का नेतृत्व करने के लिए एक स्थायी वित्त समूह (एसएफजी) की स्थापना की, जिसमें बैंकों और अन्य आरई के लिए उपयुक्त जलवायु संबंधी प्रकटीकरण, स्थायी प्रथाओं का प्रचार और भारतीय संदर्भ में जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करना शामिल है। रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2022 में जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के संबंध में एक सर्वेक्षण किया (बॉक्स III.2).

बॉक्स III.2 जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त संबंधी सर्वेक्षण

27 जुलाई 2022 को रिज़र्व बैंक ने जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त संबंधी सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए, जिसमें भारत में 12 पीएसबी, 16 पीवीबी और 6 एफबी शामिल थे। इसका उद्देश्य जलवायु जोखिम के प्रबंधन में अग्रणी एससीबी के दृष्टिकोण, तैयारी के स्तर और प्रगति का आकलन करना था। सर्वेक्षण की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

- **बोर्ड स्तरीय भागीदारी और जिम्मेदारी :** जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के संबंध में बोर्ड स्तरीय भागीदारी अपर्याप्त है। सर्वेक्षण किए गए लगभग एक तिहाई बैंकों में, जलवायु जोखिम और स्थिरता से संबंधित पहलों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी अभी तक नहीं सौंपी गई थी। इसके अलावा, केवल कुछ बैंकों ने अपने शीर्ष प्रबंधन के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन में जलवायु जोखिम / स्थिरता / पर्यावरणीय, समाज और गवर्नन्स (ईएसजी) संबंधी प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक (केपीआई) शामिल किए हैं।

- **कार्यनीति :** अधिकांश बैंकों के पास स्थिरता और ईएसजी-संबंधी पहल के लिए एक अलग कारोबार इकाई या वर्टिकल नहीं था। केवल कुछ बैंकों के पास अपने कारोबार में ईएसजी सिद्धांतों को आत्मसात करने, अपने स्थायी वित्त पोर्टफोलियो को बढ़ाने और अपने मौजूदा जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु परिवर्तन जोखिमों को शामिल करने की कार्यनीति थी।

- **जोखिम प्रबंधन :** लगभग सभी सर्वेक्षण किए गए बैंकों ने इस मुद्दे की तात्कालिकता को पहचाना, और उनमें से अधिकांश ने जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों को अपने व्यवसाय के लिए एक भौतिक खतरा माना। भौतिक और ट्रान्जिशन जोखिमों को जलवायु से संबंधित जोखिमों के मुख्य स्रोतों के रूप में देखा गया था। कुछ बैंक एक निश्चित राशि से ऊपर क्रेडिट प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय जलवायु और पर्यावरण से संबंधित जोखिमों के अलावा सामाजिक और शासन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य अपने ऋण और निवेश पोर्टफोलियो की राशि को निर्धारित करने का भी प्रयास कर रहे हैं जो इस तरह के जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील है।

- **कम कार्बन एक्सपोजर की ओर अग्रसर :** सर्वेक्षण किए गए अधिकांश बैंकों ने आने वाले वर्षों में उच्च कार्बन पैदा करने वाले / प्रदूषणकारी कारोबार में उनके एक्सपोजर को धीरे-धीरे कम करने का फैसला किया है। कुछ बैंकों ने या तो हरित उधार और निवेश को बढ़ाने के लिए नई पूंजी जुटाई है या स्थायी वित्त के लिए वृद्धिशील उधार और निवेश के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिकांश बैंकों ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए कुछ ऋण उत्पाद पेश किए हैं, जबकि कुछ ने पर्यावरण-अनुकूल कारोबार हेतु उधार देने के लिए हरित जमाएं भी पेश किए हैं।

- **जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण :** अधिकांश बैंकों ने अपने जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण को किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत फ्रेमवर्क के अनुरूप नहीं किया है।

- **बैंकिंग परिचालनों में कम कार्बन वाले वातावरण की ओर बढ़ना :** अधिकांश बैंकों ने या तो कुछ उपाय किए हैं या उनके परिचालनों से उत्पन्न होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और उनकी कुल स्रोत बिजली में अक्षय ऊर्जा के अनुपात को बढ़ाने की योजना है। कुछ बैंकों ने या तो समयबद्ध योजनाओं की घोषणा की है या कार्बन-न्यूट्रल बनने के लिए अगले 12 महीनों में एक रोडमैप लाने की उनकी मंशा है।

- **क्षमता निर्माण और डेटा अंतराल :** अधिकांश बैंक जलवायु जोखिम के वित्तीय प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्षमता निर्माण पर विचार कर रहे हैं। अधिकांश बैंकों ने यह भी महसूस किया कि उपलब्ध डेटा जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के उचित मूल्यांकन के लिए अपर्याप्त थे और इन जोखिमों को मापने और निगरानी करने के लिए प्रक्रियाओं और पद्धतियों को भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया गया था।

सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि यद्यपि बैंकों ने जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के क्षेत्र में कदम उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस संबंध में ठोस प्रयास और अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है। इस अभ्यास से मिली अंतर्दृष्टि से जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के लिए रिज़र्व बैंक के नियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को आकार देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

3.2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

III.27 वास्तविक आर्थिक गतिविधि को सहारा देने एवं ऋण मध्यस्थता के एक अतिरिक्त चैनल के रूप में कार्य करते हुए बैंकों का साथ देने में एनबीएफसी के योगदान को भली-भांति स्वीकार किया गया है। हाल के वर्षों में, इस क्षेत्र के आकार, जटिलता और अंतरसंबद्धता में वृद्धि हुई है, जिससे कुछ संस्थाएं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसके कारण 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी स्केल-आधारित विनियामक (एसबीआर) दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। यह ढांचा एनबीएफसी को बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल), मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल), अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) और टॉप लेयर में विभाजित करता है, जिसमें विनियमन की गहनता में प्रगतिशील वृद्धि होती है। ग्लाइड पथ प्रदान किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसबीआर का कार्यान्वयन सुचारू और क्रमिक हो। विशेष रूप से, एनपीए वर्गीकरण मानदंडों और न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि आवश्यकता मानदंडों के लिए ग्लाइड पथ क्रमशः 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2027 तक हैं।

एनबीएफसी-यूएल के लिए बृहत् एक्सपोज़र फ्रेमवर्क

III.28 एसबीआर के अनुसार एनबीएफसी के अपर लेयर में वे शामिल हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से मापदंडों के एक सेट के आधार पर अधिक विनियामक ध्यान देने की आवश्यकता के रूप में पहचाना जाता है। एनबीएफसी-यूएल को उधार संबंधी विनियामकीय प्रतिबंधों और बृहत् एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) पर विस्तृत दिशानिर्देश 19 अप्रैल 2022 को जारी किए गए थे (सारणी III.1).

सारणी III.1: एनबीएफसी-अपर लेयर के लिए बृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क

निम्नलिखित को समग्र एक्सपोजर मूल्य का जोड़	पात्र पूंजी आधार के प्रतिशत के रूप में वृहद एक्सपोजर सीमा	
	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों को छोड़कर	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां
एकल प्रतिपक्षकार	• 20 प्रतिशत • बोर्ड के अनुमोदन से अतिरिक्त 5 प्रतिशत • यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण/ निवेश में एक्सपोजर है तो अतिरिक्त 5 प्रतिशत • (किसी भी स्थिति में एकल प्रतिपक्षकार सीमा 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)	• 25 प्रतिशत • बोर्ड के अनुमोदन से अतिरिक्त 5 प्रतिशत
संबद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह	• 25 प्रतिशत • यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण/ निवेश में एक्सपोजर है तो अतिरिक्त 10 प्रतिशत	• 35 प्रतिशत

स्रोत : आरबीआई।

एनबीएफसी-यूएल के लिए पूंजी आवश्यकताएं

III.29 विनियामक पूंजी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, एनबीएफसी-यूएल को जोखिम भारित आस्तियों के कम से कम 9 प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टिअर (सीईटी)-1 पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है। 19 अप्रैल 2022 को, रिज़र्व बैंक ने विनियामक समायोजन और सीईटी -1 पूंजी से कटौती के साथ-साथ घटकों पर विस्तृत निर्देश प्रदान करते हुए दिशानिर्देश जारी किए, जो मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी)[5] को छोड़कर एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचाने गए सभी एनबीएफसी पर लागू होते हैं।

एनबीएफसी-यूएल के लिए मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

III.30 एनबीएफसी-यूएल की बकाया वित्तपोषित आस्तियों के लिए प्रावधान संबंधी मानदंडों को वाणिज्यिक बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से, 6 जून 2022 को पूर्व के लिए मानक आस्ति प्रावधान मानदंड जारी किए गए थे। दिशानिर्देश 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो गए हैं और प्रावधान दरें व्यक्तिगत आवास ऋण एवं लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) के ऋणों के लिए 0.25 प्रतिशत से लेकर लुभावने आवास ऋणों के लिए 2.00 प्रतिशत तक हैं (सारणी III.2).

आढ़तियों (फैक्टर्स) का पंजीकरण

III.31 आढ़तियां (फैक्टरिंग) विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन के बाद, 14 जनवरी 2022 को रिज़र्व बैंक

[5] सीआईसी, निरंतर आधार पर, अपने मौजूदा निर्देशों के संदर्भ में समायोजित निवल मालियत बनाए रखना जारी रखेंगी।

सारणी III.2: एनबीएफसी-यूएल द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

आस्तियों की श्रेणी	वित्तपोषित राशि के बकाया के प्रतिशत के रूप में प्रावधान की दर
वैयक्तिक आवास ऋण एवं एसएमई को प्रदत्त ऋण	0.25 प्रतिशत
अति आकर्षक दर पर प्रदान किया गया आवास ऋण	2.00 प्रतिशत, जिस तारीख को दरों को पुनर्निधारित कर उच्च दर किया गया उस तारीख से एक साल बाद घटकर 0.40 प्रतिशत हो जाएगी (यदि खाता 'मानक' बना रहेगा)
वाणिज्यिक स्थावर संपदा – स्थानीय आवासीय (सीआरई-आरएच) क्षेत्र को अग्रिम	0.75 प्रतिशत
वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र (सीआरई-आरएच को छोड़कर) क्षेत्र को अग्रिम	1.00 प्रतिशत
पुनर्संरचित अग्रिम	अग्रिमों की पुनर्संरचना के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों में यथा निर्धारित
मध्यम उद्यमों को प्रदत्त ऋण समेत, ऊपर शामिल नहीं किए गए सभी अन्य ऋण और अग्रिम	0.40 प्रतिशत

स्रोत: आरबीआई।

ने एनबीएफसी को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट किए, जो फैक्टरिंग कारोबार करने का प्रस्ताव करते हैं। एनबीएफसी-फैक्टर्स के अलावा, ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली सभी जमाराशि नहीं लेने वाली एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) को फैक्टरिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाए। फैक्टरिंग कारोबार करने के लिए इच्छुक किसी भी अन्य एनबीएफसी-आईसीसी को एनबीएफसी-फैक्टर में बदलने के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क करना होगा।

सरफेसी अधिनियम के तहत वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के रूप में आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)

III.32 इससे पहले, एचएफसी को जमानती कर्ज में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के उद्देश्य से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत एफआई के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए कुछ निर्धारित मानदंडों[6] को पूरा करना होता था और उन्हें व्यक्तिगत इकाई आधार पर आवेदन करना आवश्यक था। प्रक्रिया को सरल बनाने और सरफेसी अधिनियम के उद्देश्यों की प्रवर्तनीयता में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने 17 जून 2021 को अधिसूचित किया कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत एचएफसी, जिनके पास ₹100 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति है, को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(एम)(iv) के तहत 'एफआई' के रूप में माना जा सकता है। तदनुसार, एचएफसी को अधिसूचित करने के लिए पूर्व में निर्धारित मानदंड को रिज़र्व बैंक द्वारा 25 अगस्त 2021 को वापस ले लिया गया था।

एचएफसी और एनबीएफसी की जमाराशियों के संबंध में न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग (एमआईजीआर) की समीक्षा

III.33 एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों की स्वीकृति से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देश अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) और उनके संगत एमआईजीआर की एक सूची निर्धारित करते हैं। दिनांक 02 मई 2022 को अनुमोदित रेटिंग को सेबी-पंजीकृत सीआरए में से किसी के लिए 'बीबीबी-' में समान रूप से मानकीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अन्य दीर्घकालिक कर्ज लिखतों और भिन्न-भिन्न सीआरए के साथ बेहतर तुलना हुई।

गैर-बैंक संस्थाओं के लिए आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण

III.34 धन शोधन रोकथाम (पीएमएल) अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राहकों की आधार संख्या का प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की अधिसूचना यूआईडीएआई और उपयुक्त विनियामक के परामर्श के बाद ही जारी की जानी है। तदनुसार,

[6] जैसे कि न्यूनतम पर्यवेक्षी रेटिंग का अनुपालन एवं अन्य प्राधिकारों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न प्राप्त हो।

13 सितंबर 2021 को, रिज़र्व बैंक ने आधार प्रमाणीकरण लाइसेंस-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस या उप-केयूए लाइसेंस (केयूए के माध्यम से प्रमाणीकरण करने के लिए) प्राप्त करने के इच्छुक सभी एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को जांच के लिए रिज़र्व बैंक को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाया ताकि आवश्यक सावधानी बरतने के बाद यूआईडीएआई को सिफारिश की जा सके।

एनबीएफसी में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के मुआवजे के संबंध में दिशानिर्देश

III.35 दिनांक 29 अप्रैल 2022 को, रिज़र्व बैंक ने प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और एनबीएफसी के वरिष्ठ प्रबंधन के मुआवजे को तय करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट जारी किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना चाहिए, जो मुआवजा नीति तैयार करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। एनआरसी प्रस्तावित और मौजूदा निदेशकों की 'योग्य और उचित' स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है और यह कि कंपनी के बोर्ड, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन में निदेशकों की नियुक्ति में हितों का कोई टकराव न हो। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि नियत और परिवर्तनीय वेतन वाले मुआवजा पैकेज को सभी प्रकार के जोखिमों के लिए समायोजित किया जा सकता है। परिवर्तनीय वेतन के एक निश्चित हिस्से में एक डिफरल व्यवस्था हो सकती है और डिफरल वेतन को मालस / क्लॉबैक व्यवस्था के अधीन किया जा सकता है।

एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) द्वारा गतिविधियों का विविधीकरण

III.36 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को, रिज़र्व बैंक ने एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के हिस्से के रूप में उपयोगकर्ताओं को सभी विदेशी मुद्रा बाजार-निर्माण की सुविधाएं पेश करने की अनुमति दी, जैसा कि वर्तमान में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 (एडी -1) को अनुमति दी गई है, ताकि प्राथमिक व्यापारी वाले कारोबार करने वाले बैंकों के बराबर बाजार निर्माताओं के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत किया जा सके। 01 जनवरी 2023 से, एसपीडी की संबंधित संस्थाओं द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए रुपये से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन को लेनदेन की तारीख के बाद कारोबार दिवस के दोपहर 12 बजे से पहले भारतीय समाशोधन निगम के ट्रेड रिपॉजिटरी को सूचित करना आवश्यक है।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा

III.37 अप्रैल 2021 में, रिज़र्व बैंक ने एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने और उन्हें दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने और अधिक पारदर्शी और कुशल तरीके से कार्य करने के लिए अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था। तदनुसार, समिति की सिफारिशों और हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर एआरसी के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे में संशोधन किया गया था (बॉक्स III.3).

3.3 सहकारी बैंक

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

III.38 दिनांक 25 जून 2021 को, रिज़र्व बैंक ने ₹5000 करोड़ या उससे अधिक के आस्ति आकार वाले सभी यूसीबी को उनके कारोबार के बढ़ते आकार और दायरे को देखते हुए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त करने की सलाह दी। यूसीबी के बोर्ड को सीआरओ की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करें।

यूसीबी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा

III.39 यूसीबी के लिए संशोधित नियामक ढांचा 19 जुलाई 2022 को, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया, जिसके तहत उनकी वित्तीय

बॉक्स III.3: एआरसी के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा

11 अक्टूबर 2022 को जारी एआरसी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचे का उद्देश्य एआरसी में कॉर्पोरेट गवर्नन्स को मजबूत करना, उनके कामकाज की पारदर्शिता बढ़ाना, विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उनकी भूमिका को सुकर बनाना था।

कॉर्पोरेट गवर्नन्स को मजबूत करना

प्रत्येक एआरसी को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना आवश्यक है और बोर्ड की बैठक में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं। पदाधिकारी प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक के लिए अधिकतम निरंतर कार्यकाल पंद्रह वर्षों तक सीमित कर दिया गया है ताकि सुदृढ़ शासन पद्धतियों की मजबूत संस्कृति और एआरसी के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके तथा स्वामित्व को प्रबंधन से अलग करने के सिद्धांत को अपनाया जा सके। एआरसी को बोर्ड की दो समितियों, अर्थात, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करने की भी आवश्यकता होती है, जिससे बोर्ड की प्रभावकारिता में वृद्धि होने और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सुधार होने की उम्मीद है।

पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ाना

संशोधित ढांचे में एआरसी के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण प्रदान करना शामिल है (i) एसआर निवेशकों के लिए सृजित रिटर्न, (ii) रिकवरी रेटिंग माइग्रेशन और (iii) पिछले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं की रेटिंग एजेंसी के साथ संव्यवहार। इसके अलावा, एआरसी के पिछले कार्य-निष्पादन के लिए प्रकटीकरण अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है और एआरसी को एसआर धारकों को एसआर की रेटिंग के पीछे के अनुमान और तर्क का प्रकटीकरण आवश्यक है। इन उपायों की बदौलत अर्हताप्राप्त क्रेताओं (क्यूबी) के व्यापक समूह से होने वाले निवेश सुविधाजनक होने की उम्मीद है, एआरसी और एसआर धारकों के बीच सूचना विषमता को दूर किया जा सकता है, एआरसी के बीच स्वस्थ होड़ को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्राप्त होने के लिए एआरसी को आस्तियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एआरसी को कम से कम 6 रेटिंग साइकिल (प्रत्येक छमाही के) के लिए सीआरए को बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है ताकि उनके साथ निरंतर संव्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।

विवेकपूर्ण मानदंडों का सुदृढ़ीकरण

संशोधित पद्धति में एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए एआरसी को पेशेवर विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा ओटीएस प्रस्तावों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद बोर्ड द्वारा आईएसी की सिफारिशों की समीक्षा की जाती है। नए ढांचे के तहत, एआरसी को केवल अंतर्निहित वित्तीय आस्तियों से शुरू की गई रिकवरी से कोई प्रबंधन शुल्क या प्रोत्साहन वसूलना अनिवार्य है। एआरसी के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता को भी ₹100 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया है ताकि एआरसी के तुलन-पत्र को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जा सके नतीजतन कर्ज-एकत्रीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

दबाववग्रस्त आस्तियों के समाधान में एआरसी की भूमिका को सुविधाजनक बनाना

दिशानिर्देशों में एआरसी को सभी मामलों में जारी कुल एसआर के 15 प्रतिशत की पिछली आवश्यकता की तुलना में एसआर में अंतरणकर्ताओं के निवेश का न्यूनतम 15 प्रतिशत या जारी किए गए कुल एसआर का 2.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, एसआर में निवेश करने की अनुमति दी गई है। इससे पूंजी का कुशल उपयोग होने की उम्मीद है जिससे एआरसी अधिक से अधिक सौदों में भाग लेने में सक्षम होंगी। एआरसी को कुछ अतिरिक्त अल्पावधि लिखतों जैसे मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, जमा प्रमाण पत्र और एए- या उससे अधिक रेटेड कॉर्पोरेट बॉण्ड/वाणिज्यिक पत्रों में अधिशेष निधि निवेश करने की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा, ₹1000 करोड़ के न्यूनतम एनओएफ वाले एआरसी को आईबीसी के तहत समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर, ऋणदाताओं को सभी दबावग्रस्त ऋणों को एआरसी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है, जबकि पहले केवल उन दबावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण की शर्त थी जो 60 दिनों से अधिक समय से चूक में थे। इससे दबावग्रस्त आस्तियों के बेहतर पुनर्निर्माण और रिकवरी के साथ-साथ कर्ज एकत्रीकरण सुविधाजनक होने की उम्मीद है।

सुदृढ़ता[7] को मजबूत करने के उद्देश्य से विभेदित विनियामक नुस्खे के साथ एक सरल चार-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया गया। इसने एकल जिले में काम करने वाले टिअर 1 यूसीबी के लिए ₹2 करोड़ और अन्य सभी यूसीबी (सभी स्तरों के) के लिए ₹5 करोड़ का न्यूनतम निवल मालियत निर्धारित किया ताकि उनकी वृद्धि के वित्तपोषण के लिए उनके लचीलेपन और क्षमता को मजबूत किया जा सके। इस मामले पर नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार जो यूसीबी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं उन्हें

[7] टिअर 1 - सभी यूनिट यूसीबी और वेतनभोगी यूसीबी (जमा आकार के निरपेक्ष) और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास ₹100 करोड़ तक की जमाराशि है; टिअर 2 - ₹100 करोड़ से अधिक और ₹1,000 करोड़ तक के जमाराशि वाले यूसीबी; टिअर 3 - ₹1,000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक के जमाराशि वाले यूसीबी; टिअर 4 - ₹10,000 करोड़ से अधिक जमाराशि वाले यूसीबी।

31 मार्च 2028 तक एक मध्यवर्ती लक्ष्य के साथ 31 मार्च 2026 तक या उससे पहले लागू न्यूनतम निवल मालियत का कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए एक ग्लाइड पथ प्रदान किया गया है ताकि ट्रान्समिशन को सुचारू बनाया जा सके।

III.40 टिअर 1 बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता को 9 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया था, जबकि टिअर 2, टिअर 3 और टिअर 4 यूसीबी के लिए इसे संशोधित कर 12 प्रतिशत किया गया था ताकि उनकी पूंजी संरचना को मजबूत किया जा सके। संशोधित सीआरएआर को पूरा नहीं करने वाले बैंकों को 31 मार्च 2024 तक 10 प्रतिशत, 31 मार्च 2025 तक 11 प्रतिशत और 31 मार्च 2026 तक 12 प्रतिशत सीआरएआर हासिल करने के लक्ष्य के साथ तीन साल का ग्लाइड पथ प्रदान किया गया था।

शाखा विस्तार के लिए स्वचालित मार्ग

III.41 संशोधित विनियामक ढांचे के तहत, रिज़र्व बैंक ने संशोधित वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंड[8] को पूरा करने वाले यूसीबी के शाखा विस्तार के लिए एक स्वचालित मार्ग शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के अंत को यथास्थिति शाखाओं की संख्या के 10 प्रतिशत तक नई शाखाएं खोलने की अनुमति मिली, बशर्ते न्यूनतम एक शाखा और अधिकतम पांच शाखाएं खोलीं जाएं। जबकि पूर्व अनुमोदन मार्ग के तहत शाखा विस्तार प्रस्तावों की जांच अब तक की तरह जारी रहेगी, अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

4. पर्यवेक्षी नीतियां

III.42 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने अपने पर्यवेक्षण को और अधिक जोखिम केंद्रित तथा दूरंदेशी बनाया है। चालू गतिविधियों और प्रस्तावित परियोजनाओं से ऑफ-साइट के साथ-साथ ऑन-साइट पर्यवेक्षण, जांच और निगरानी के दायरे और क्षमता में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यवेक्षी गहनता और प्रभावकारिता तेजी से बदलती वित्तीय प्रणाली के साथ समकालीन बनी रहे, निगरानी प्रणालियों को ज्यादा पैना, अधिक व्यापक और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

एनबीएफसी में मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)

III.43 एनबीएफसी में अनुपालन कार्य को मजबूत करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2022 को कुछ सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं निर्धारित कीं। अपर और मिडल लेयर की एनबीएफसी पर लागू किए गए दिशानिर्देशों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और अनुपालन कार्य को लागू करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें क्रमशः 1 अप्रैल 2023 और 1 अक्टूबर 2023 तक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की नियुक्ति शामिल है। अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारियों, सीसीओ की नियुक्ति और कार्यकाल संबंधी शर्तें और अनुपालन कार्य की स्वतंत्रता और दोहरी हैटिंग से न्यूनतम अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं।

एनबीएफसी के लिए कोर वित्तीय सेवा समाधान

III.44 दिनांक 01 अक्टूबर 2022 तक दस और इससे अधिक निर्धारित बिंदु सेवा सुपुर्दगी इकाइयों के साथ मिडल और अपर लेयर में एनबीएफसी को 30 सितंबर 2025 तक बैंकों द्वारा अपनाए गए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) की तरह चरणबद्ध तरीके से कोर वित्तीय सेवा समाधान (सीएफएसएस) को लागू करने के लिए अनिवार्य किया गया है। बेस लेयर में आने वाले एनबीएफसी और दस से कम निर्धारित बिंदु सेवा सुपुर्दगी इकाइयों वाले मिडल और अपर लेयर में आने वाले एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे अपने लाभ के लिए सीएफएसएस के कार्यान्वयन पर विचार करें।

[8] एफएसडब्ल्यूएम स्थिति निर्धारित करने के लिए संशोधित मानदंडों में निम्नलिखित शामिल है, सीआरएआर लागू न्यूनतम सीआरएआर से कम से कम 1 प्रतिशत अंक ऊपर होना चाहिए; निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक ना हो; पिछले चार वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए निवल लाभ और तुरंत पूर्व वर्ष में कोई निवल हानि नहीं हुई हो; पिछले वित्त वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर को बनाए रखने में कोई चूक नहीं हो; बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशकों के साथ सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली; कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पूर्णत: लागू हो; और पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान आरबाई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण बैंक पर कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया हो।

5. प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना

III.45 रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसने डिजिटल बैंकिंग इकाई मॉडल, डीबीयू में दी जाने वाली सुविधाओं, डीबीयू के कामकाज की निगरानी, साइबर सुरक्षा और अन्य आईटी संबंधित पहलुओं, और डिजिटल बैंकिंग जागरूकता फैलाने में डीबीयू की भूमिका के संबंध में अपनी सिफारिशें दीं। समिति की सिफारिशों के आधार पर, डीबीयू की स्थापना के संबंध में दिशानिर्देश 7 अप्रैल 2022 को जारी किए गए थे।

III.46 दिशानिर्देशों में डिजिटल बैंकिंग और डीबीयू की परिभाषाओं, डीबीयू द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों, पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं, निदेशक मंडल की भूमिका और ग्राहक शिकायत समाधान तंत्र पर स्पष्टता प्रदान की गई है। दिशानिर्देशों के अनुसार डीबीयू को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं पर ग्राहक शिक्षा प्रदान करके अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। वे ग्राहकों को पेपरलेस, कुशल, निरापद और सुरक्षित वातावरण में डिजिटल मोड के माध्यम से डिजिटल यात्रा शुरू करने में सुविधा प्रदान करेंगे। इससे वित्तीय समावेश में वृद्धि होने और जनता को निर्बाध और कुशल तरीके से वित्तीय उत्पादों की पूरी श्रृंखला उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया में डिजिटल बैंकिंग को खुदरा बैंकिंग के तहत एक अलग कारोबार खंड के रूप में भी स्वीकार किया गया है।

III.47 दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित किए गए। डीबीयू द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बचत, ऋण, निवेश और बीमा शामिल हैं। ऋण सुपुर्दगी के मोर्चे पर देखें तो, डीबीयू शुरुआती तौर पर, ऑनलाइन आवेदनों से लेकर संवितरण तक छोटे टिकट के खुदरा और एमएसएमई ऋणों की आदि-से-अंत तक डिजिटल प्रोसेसिंग प्रदान करेंगे। डीबीयू कुछ चिन्हित सरकार प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करेंगे। इन इकाइयों में उत्पादों और सेवाओं को दो मोड में प्रदान किया जाएगा अर्थात् स्व-सेवा और सहायक मोड जिसमें स्व-सेवा मोड 24 * 7 * 365 आधार पर उपलब्ध होगा।

डिजिटल उधार

III.48 हाल की अवधि में, प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण की बदौलत वित्तीय सेवाओं के विस्तार में दक्षता, उत्पादकता, गुणवत्ता, समावेश और प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेष रूप से डिजिटल उधार के क्षेत्र में। डिजिटल उधार गतिविधियों में तेजी आने की वजह से उत्पन्न व्यावसायिक आचरण और ग्राहक संरक्षण चिंताओं की पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उधार सहित डिजिटल उधार' (डब्ल्यूजीडीएल) के संबंध में एक कार्य समूह का गठन किया था, जिसने 18 नवंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखी थी। दिनांक 10 अगस्त 2022 को, रिज़र्व बैंक ने अपने आरई, उनके द्वारा नियोजित ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) और उनके संबंधित डिजिटल उधार एप्लिकेशन (डीएलए) के लिए एक विनियामक ढांचा जारी किया, ताकि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर डिजिटल उधार विधियों के माध्यम से ऋण सुपुर्दगी के व्यवस्थित विकास का समर्थन किया जा सके।

III.49 दिनांक 2 सितंबर 2022 को तत्काल कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत डब्ल्यूजीडीएल की सिफारिशें अभिनवता को बढ़ावा देते हुए ग्राहक सुरक्षा में इजाफा करने और डिजिटल उधार परिवेश को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर केंद्रित हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता के बैंक खातों और आरई के बीच एलएसपी या किसी तीसरे पक्ष के किसी भी पास-थ्रू / पूल खाते के बिना निष्पादित किए जाएंगे; (ii) ऋण मध्यस्थता प्रक्रिया में एलएसपी को देय कोई शुल्क या प्रभार सीधे आरई द्वारा भुगतान किया जाएगा, न कि उधारकर्ता द्वारा; (iii) ऋण संविदा निष्पादित करने से पूर्व उधारकर्ता को वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) समेत एक मानकीकृत मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान किया जाना; (iv) एक कूलिंग-ऑफ अवधि जिसके दौरान उधारकर्ता

ऋण संविदा के भाग के रूप में प्रदान किए जाने वाले किसी भी दंड के बिना मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकल सकते हैं; (v) आरई को यह सुनिश्चित करना है कि उनके और उनके द्वारा नियोजित एलएसपी के पास फिनटेक/डिजिटल उधार संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए एक समुचित नोडल शिकायत निवारण अधिकारी हो; (vi) डीएलए द्वारा एकत्रित डेटा आवश्यकता आधारित, स्पष्ट लेखा सत्यापन युक्त और केवल उधारकर्ता की पूर्व स्पष्ट सहमति से एकत्र होनें चाहिएं, जिसमें उधारकर्ता विशिष्ट डेटा के उपयोग के लिए सहमति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं; (vii) आरई को आवश्यक है कि वह डीएलए के जरिए मूल रूप से प्राप्त किए गए किसी उधार एवं मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर आरई द्वारा प्रदान किए गए समस्त नए डिजिटल उधार संबंधी उत्पाद, जिसमें अल्पावधि ऋण या आस्थगित भुगतान शामिल हैं, की जानकारी ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) दें। ये दिशानिर्देश 2 सितंबर 2022 से नए ऋण प्राप्त करने वाले नए ग्राहकों के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों पर लागू किए गए, जबकि मौजूदा डिजिटल ऋणों को 30 नवंबर 2022 तक दिशानिर्देशों का पालन करना था।

6. वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा

III.50 रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित और स्थिर वित्तीय बाजारों को विकसित करने की दृष्टि से सरकार और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय से बाजार सुधार और विनियामक नीतिगत परिवर्तन शुरू किए ताकि कुशल मूल्य का पता लगाने में सुविधा हो सके। नीति का उद्देश्य वित्तीय बाजारों की गहराई और चौड़ाई को बढ़ाना एवं व्यापार और जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त उत्पाद प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, इसका उद्देश्य पहुंच को आसान बनाना, भागीदारी बढ़ाना, अभिनवता को सुविधाजनक बनाना, उपयोगकर्ताओं की रक्षा करना और कारोबार के निष्पक्ष आचरण को बढ़ावा देना है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I (एडी -I) बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार

III.51 उधारकर्ताओं के एक बड़े समूह द्वारा, जिन्हें विदेशी बाजारों तक सीधे पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, विदेशी मुद्रा में उधार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 07 जुलाई 2022 को एडी-I बैंकों को अंतिम उपयोग के प्रयोजन से एक व्यापक समूह हेतु भारत में घटकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के लिए समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) का उपयोग करने की अनुमति दी। तथापि, यह बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए निर्धारित नकारात्मक सूची के अधीन है। इस तरह के उधार जुटाने की व्यवस्था 31 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध थी।

बैंकों और एसपीडी को ऑफ-शोर विदेशी मुद्रा में निपटान रुपया डेरिवेटिव बाजार में सौदा करने की अनुमति देना

III.52 ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को बढ़ावा देने, ऑन-शोर और ऑफ-शोर बाजारों के बीच विभाजन को दूर करने और मूल्य पता लगाने की दक्षता को बेहतर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी 2022 और 08 अगस्त 2022 को क्रमशः फेमा, 1999 की धारा 10(1) के तहत प्राधिकृत एडी-I बैंकों और एसपीडी को अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ ओवरनाइट मुंबई अंतरबैंक प्रस्तावित दर (माइबोर) बेंचमार्क के आधार पर ऑफ-शोर विदेशी मुद्रा में निपटान ओवरनाइट इंडेक्सड स्वैप (एफसीएस-ओआईएस) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी। एडी -1 बैंक भारत में अपनी शाखाओं, विदेशी शाखाओं या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों के माध्यम से ये लेनदेन कर सकते हैं।

भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान

III.53 निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए, 11 जुलाई 2022 को रिज़र्व बैंक ने आईएनआर में निर्यात और आयात की इन्वॉइसिंग, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की। तदनुसार, भारत में एडी बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से व्यापारिक लेनदेन के निपटान के लिए साझेदार व्यापार देश के प्रतिनिधि

बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई थी।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति का उदारीकरण

III.54 दिनांक 01 अगस्त 2022 को, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से ईसीबी के लिए स्वचालित मार्ग सीमा को 750 मिलियन अमरीकी डालर या समतुल्य से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमरीकी डालर या समतुल्य कर दिया और भारतीय सीआरए के निवेश ग्रेड रेटिंग वाले पात्र उधारकर्ताओं के लिए ईसीबी की समग्र लागत सीमा को 100 बीपीएस बढ़ाया। उपरोक्त व्यवस्थाएं 31 दिसंबर 2022 तक उपलब्ध होंगी।

नई विदेशी निवेश व्यवस्था को परिचालन में लाना

III.55 दिनांक 22 अगस्त 2022 को, रिज़र्व बैंक ने एक नई विदेशी निवेश व्यवस्था को परिचालन में लाने के निर्देश जारी किए। नई व्यवस्था ने भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस तरह के निवेश के संबंध में मौजूदा ढांचे को सरल बनाया, भिन्न-भिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को काफी कम कर दिया। विदेशी निवेश नियम और विनियम, 2022 के जरिए लाए गए निर्देशों की बदौलत कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलने और अनुपालन का बोझ एवं तत्संबंधी अनुपालन लागत कम होने की उम्मीद है। इन निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, 'कार्यनीतिक क्षेत्र' की अवधारणा की शुरूआत, निवेश/विनिवेश के लिए मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों में लचीलापन और कतिपय शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत गैर-वित्तीय क्षेत्र (बीमा और बैंकिंग को छोड़कर) की संस्थाओं द्वारा वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश शामिल है। इसके अतिरिक्त, देरी से रिपोर्टिंग को रिकॉर्ड पर लेने के लिए 'लेट सबमिशन शुल्क (एलएसएफ)' की व्यवस्था लाई गई।

7. ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेश

III.56 रिज़र्व बैंक ने बुनियादी औपचारिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की एक शृंखला तक पहुंच को बेहतर करने और वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए कई नीतियां बनाई हैं। वित्तीय समावेश हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) 2019-24 भारत में वित्तीय समावेश नीतियों के दृष्टिपथ और प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जिसमें डिजिटल वित्तीय समावेश को बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और देश में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) में पहल

III.57 विनिर्दिष्ट प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में बैंकों और एनबीएफसी के बीच विकसित की गई सहक्रियाओं को जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए कतिपय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को आगे उधार देने के प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एनबीएफसी को प्रदत्त ऋणों और एसएफबी द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई को प्रदत्त ऋणों के मामले में पीएसएल वर्गीकरण की सुविधा को सतत आधार पर अनुमति दी गई है। निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स (एनडब्ल्यूआर) या इलेक्ट्रॉनिक एनडब्ल्यूआर (ईएनडब्ल्यूआर)[9] के एवज में ऋण की पीएसएल सीमा को ₹50 लाख से बढ़ा कर ₹75 लाख प्रति उधारकर्ता कर दिया गया था ताकि उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके और कृषि उपज के गिरवी या दृष्टिबंधक पर किसानों को अत्यधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को संपार्श्विक मुक्त ऋण में वृद्धि

III.58 जुलाई 2021 में सरकार द्वारा सूक्ष्म वित्त ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) योजना में संशोधन के बाद, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एसएचजी को संपार्श्विक मुक्त ऋण की

[9] माल-गोदाम विकास और विनियामकीय प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और विनियमित माल-गोदामों द्वारा जारी एनडब्ल्यूआर और ईएनबडब्ल्यूआर।

राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋणों के लिए कोई जमानत नहीं ली जानी चाहिए और उनके बचत बैंक खाते पर कोई ग्रहणाधिकार अंकित नहीं किया जाना चाहिए। संपूर्ण ऋण (ऋण बकाया होने के बावजूद, भले ही यह बाद में ₹10 लाख से कम हो जाए) सीजीएफएमयू के तहत कवरेज के लिए पात्र होगा। इससे महिला एसएचजी अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करने योग्य होने की उम्मीद है।

8. उपभोक्ता संरक्षण और खुदरा भागीदारी

III.59 उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण रिज़र्व बैंक का मुख्य फोकस रहा है। इसने ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए आरई, ग्राहकों और रिज़र्व बैंक लोकपाल को कवर करते हुए विभिन्न स्तरों पर पहल करना जारी रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने जी-सेक में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए।

रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021

III. 60 लोकपाल तंत्र को सरल, कुशल और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 नवंबर 2021 को तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं, नामतः, बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), 2006; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना (ओएसएनबीएफसी), 2018 और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी), 2019 को एकीकृत करके आरबी-आईओएस शुरू किया। यह योजना 'सेवा में कमी' को बहिष्करण की एक निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में परिभाषित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं होने के कारण कोई भी शिकायत खारिज नहीं की जाएगी। यह प्रणाली 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल' सिद्धांत पर तैयार की गई है और इसमें 22 लोकपाल कार्यालयों में से प्रत्येक को सौंपे गए अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है। ऋण सूचना संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को भी 01 सितंबर 2022 से आरबी-आईओएस के दायरे में लाया गया था।

एनबीएफसी और सीआईसी के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना

III.61 आईओ योजना का उद्देश्य आरई स्तर पर ही शिकायतों के संतोषजनक समाधान को सक्षम करना है ताकि अन्य स्तरों पर शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता को कम किया जा सके। तदनुसार, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) को 15 नवंबर 2021 को निर्देश दिया गया था कि वे अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर एक आईओ नियुक्त करें। दिनांक 06 अक्टूबर 2022 को, सीआईसी को इस निर्देश के दायरे में लाया गया और ये 01 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। इन निर्देशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* आईओ के लिए नियुक्ति और कार्यकाल, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश, और निरीक्षण तंत्र शामिल हैं। धोखाधड़ी से संबंधित पहलुओं, और वाणिज्यिक निर्णयों, आंतरिक प्रशासन, कर्मचारियों के वेतन और परिलब्धियों और न्यायाधीन मामलों से संबंधित शिकायतों को छोड़कर आरई के आंतरिक शिकायत तंत्र द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज की गई सभी शिकायतों की समीक्षा शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय से अवगत कराने से पहले आईओ द्वारा की जानी आवश्यक है।

रिज़र्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना की शुरूआत

III.62 भारत सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक निवेशक आधार के विस्तार समेत जी-सेक बाजार के विकास में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जी-सेक में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, 12 जुलाई 2021 को 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना' की घोषणा की गई थी। दिनांक 12 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया

ऑनलाइन पोर्टल खुदरा निवेशकों के लिए रिज़र्व बैंक के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता खोलकर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) में निवेश करना और इन प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों के साथ-साथ उनके द्वितीयक बाजार दोनों में सरल, सुरक्षित और प्रत्यक्ष तरीके से भाग लेने को सुविधाजनक बनाता है।

III.63 इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 04 जनवरी 2022 को रिटेल डायरेक्ट बाजार निर्माण योजना को भी अधिसूचित किया, जिसमें प्राथमिक व्यापारियों को पूरे बाजार समय में तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म (ऑड लॉट्स और कोट्स सेग्मेंट्स हेतु अनुरोध) पर उपस्थित रहने और आरडीजी खाताधारकों से खरीद/बिक्री संबंधी अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए अनिवार्य किया।

9. भुगतान और निपटान प्रणाली

III.64 प्रौद्योगिकी और अभिनवता को अपनाने में वृद्धि की बदौलत, भारत में भुगतान परिवेश के त्वरित विकास ने देश को न केवल डिजिटल भुगतान में वृद्धि के संदर्भ में बल्कि निरापद, सुरक्षित, अभिनव और कुशल भुगतान प्रणालियों की उपलब्धता के माध्यम से वैश्विक भुगतान जगत में एक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में की गई पहलों ने भुगतान परिवेश को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया है और ईमानदारी, समावेश, अभिनवता, इन्स्टीट्यूश्नलाइजेशन और इंटरनेश्नलाइजेशन के पांच स्तंभों पर बनाया गया है, जैसा कि भुगतान विजन 2025 में परिकल्पित है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) में वृद्धि

III.65 यूपीआई123पे को मार्च 2022 में पेश किया गया था ताकि फीचर फोन उपयोगकर्ताओं द्वारा यूपीआई भुगतान किया जा सके। इसे चार विकल्पों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे, (i) ऐप-आधारित फंक्शनैलिटी, (ii) मिस्ड कॉल, (iii) इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), और (iv) प्रॉक्सिमिटी साउंड-आधारित भुगतान। इसने देश में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन ग्राहकों के लिए यूपीआई तक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। सितंबर 2022 में, यूपीआई लाइट पेश किया गया था ताकि ऑन-डिवाइस वॉलेट फीचर के माध्यम से ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के लेनदेन किए जा सकें। रिज़र्व बैंक ने जून 2022 में क्रेडिट कार्ड को यूपीआई नेटवर्क से जोड़ने की भी अनुमति दी थी, जिसमें रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए प्रारंभिक सुविधा की योजना बनाई गई थी। इस व्यवस्था से उम्मीद है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए भुगतान के लिए ग्राहकों को अधिक अवसर प्रदान करने में और आसानी होगी।

एटीएम में इंटरऑपरेबल कार्ड-रहित नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू)

III.66 सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्कों में इंटरऑपरेबल तरीके से कार्ड-रहित नकद निकासी सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने मई 2022 में एटीएम नेटवर्क के माध्यम से लेनदेन के निपटान के साथ यूपीआई का उपयोग करके ग्राहक को प्राधिकृत करने की अनुमति दी। कार्ड-रहित नकद निकासी की सुविधा से स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग और डिवाइस टेम्परिंग जैसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

ऑफलाइन भुगतान

III.67 इंटरनेट कनेक्टिविटी की गैर-मौजूदगी या अनियमितता, विशेष रूप से दूरदराज इलाकों में, डिजिटल भुगतान को अपनाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। सितंबर 2020 से जुलाई 2021 तक देश के विभिन्न हिस्सों में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकीय परीक्षण प्रारंभ करके देखा गया। पायलट कार्यक्रमों से मिले अनुभव और प्राप्त प्रतिक्रिया ने विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ऑफलाइन भुगतान समाधान की शुरुआत की गुंजाइश का संकेत दिया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 03 जनवरी 2022 को ऑफलाइन विधि से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रूपरेखा जारी की। इस रूपरेखा के तहत, ऑफलाइन लेनदेन को प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की आवश्यकता नहीं होती है और सभी लेनदेन

के लिए ₹2,000 की समग्र सीमा के साथ प्रति लेनदेन ₹200 की सीमा के अधीन होते हैं जब तक कि खाते में शेष राशि फिर से भरी नहीं जाती। एएफए में उपयोग की गई सीमा को पुनः भरना केवल ऑनलाइन मोड में अनुमत है।

आवर्ती भुगतान के लिए ई-मैनडेट – सीमा में वृद्धि

III.68 गतिशील भुगतान आवश्यकताओं और ग्राहक सुविधा के साथ कार्ड लेनदेन की सलामती और सुरक्षा को संतुलित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 21 अगस्त 2019 को आवर्ती लेनदेन के लिए सभी प्रकार के कार्ड पर ई-मैनडेट की प्रॉसेसिंग की इजाज़त दी थी। तदुपरांत 10 जनवरी 2020 को इन अनुदेशों में विस्तार किया गया ताकि यूपीआई लेनदेनों को शामिल किया जा सके। हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर और ग्राहकों को उपलब्ध पर्याप्त सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे लेनदेन की सीमा को 16 जून 2022 को प्रति लेनदेन ₹2,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई थी।

सप्ताह के सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की उपलब्धता

III.69 एनएसीएच प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित एक वेब-आधारित समाधान है जो अंतर-बैंक, उच्च मात्रा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है जो दोहराव और आवधिक प्रकृति के होते हैं। वर्ष 2021-22 में, एनएसीएच ने 421 करोड़ लेनदेन की प्रॉसेसिंग की, जिसमें 313 करोड़ क्रेडिट लेनदेन शामिल थे, जिनमें से 247 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) थे।

III.70 सरकार और बिलर्स की मांग को पूरा करने और पूरे वर्ष इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले सभी चैनलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के अंत और अन्य छुट्टियों समेत सप्ताह के सभी दिनों में एनएसीएच को परिचालन में लाया। तदुपरांत, इस परिवेश की दक्षता को और बढ़ाने के लिए एनएसीएच में अधिक सेटलमेंट साइकिल शुरू किए गए हैं। इस पहल ने डीबीटी तेजी से जमा होने और उसके उपयोग, कॉर्पोरेट्स और अन्य हितधारकों को सभी दिनों में लाभांश और ब्याज का भुगतान करने, और नियत तारीख को ऋण किस्तों, बीमा प्रीमियम और एसआईपी जैसी आवर्ती राशि की रिकवरी को सक्षम बनाने *के साथ-साथ* कई लाभ प्रदान किए।

भारत-नेपाल धन-प्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि

III.71 भारत-नेपाल धन-प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत प्रति लेनदेन की अधिकतम सीमा 1 अक्टूबर 2021 से ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई थी एवं भारत और नेपाल के बीच व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने और नेपाल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति-से-व्यक्ति धन-प्रेषण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से धन-प्रेषण की वार्षिक सीमा को हटा दिया गया था। इन इजाफों से नेपाल में बस चुके या स्थानांतरित हुए भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति और पेंशन के साथ-साथ भुगतान में सुविधा होने की उम्मीद है।

10. समग्र मूल्यांकन

III.72 वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अब तक रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्रतिक्रियाएं एक मजबूत, आघात-सहनीय और कुशल वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने के प्रमुख लक्ष्य के साथ-साथ तेजी से बदलते समष्टि-वित्तीय वातावरण, जिसे कई झटके सहने पड़े, के अनुरूप रहीं हैं। भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तूफान के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती और आघात-सहनीयता इसके तुलनात्मक रूप से बेहतर समग्र समष्टि दृष्टिकोण को सहारा देने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को नई चुनौतियों का सामना करने और इस गतिशील वातावरण में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा, साथ ही उचित कारोबार मॉडल, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, निरंतरता, स्थिरता, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेश पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। रिज़र्व बैंक की आगामी पहलों से इस दिशा में विनियमित संस्थाओं की प्रगति का मार्गदर्शन करने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित और संरक्षित करने एवं बाजारों के कुशल कामकाज में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

IV वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन एवं प्रदर्शन

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र 2021-22 और 2022-23 में अब तक सुदृढ़ बना हुआ है, क्योंकि बैंकों ने ऋण में व्यापक-आधारित तेजी के कारण अच्छी तुलन पत्र वृद्धि देखी है। कोविड-19 के कारण एहतियाती वृद्धि से जमा वृद्धि में कमी आई है। संवर्धित पूंजी बफर, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और बढ़ी हुई लाभप्रदता संकेतकों ने उनकी मजबूती को दर्शाया है। आने वाले समय में बढ़ी हुई नीतिगत ब्याज दर का पूर्ण संचरण जमा दरों तक करने से ऋण मांग को पूरा करने के लिए जमा वृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है। पुनर्गठित आस्तियों में चूक की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

1. भूमिका

IV.1 2021-22 के दौरान, वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र का विस्तार बहु-वर्षीय उच्च गति से हुआ। समय पर नीतिगत समर्थन ने बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन और सुदृढ़ता संकेतकों पर महामारी के प्रभाव को कम किया। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पूर्व से जारी चुनौती कम हो रही है और लाभप्रदता क्रमिक रूप से सुधरकर 2014-15 के स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही हानि में कमी तथा पूंजी बफर में मजबूती आई है।

IV.2 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में 2021-22 और 2022-23 की पहली छमाही के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन और प्रदर्शन पर चर्चा की गई है। उक्त के खंड 2 और 3 में क्रमशः तुलन पत्र संबंधी गतिविधियों और वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। खंड 4 में उनकी वित्तीय सुदृढ़ता की चर्चा की गई है, जिसके पश्चात खंड 5 में ऋणों के क्षेत्रवार अभिनियोजन के पैटर्न का मूल्यांकन किया गया है। खंड 6 से 11 में स्वामित्व का स्वरूप, कॉरपोरेट अभिशासन एवं क्षतिपूर्ति प्रथाएं, भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन, भुगतान प्रणालियों की गतिविधियाँ, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेश से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भुगतान बैंक (पीबी) से संबंधित विशिष्ट विषयों की समीक्षा अलग से खंड 12 से 15 में की गई है। खंड 16 में विश्लेषण के पश्चात सामने आए प्रमुख मुद्दों को उजागर करके और प्रगामी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके अध्याय का समापन होता है।

2. तुलन-पत्र विश्लेषण

IV.3 सात साल के अंतराल के बाद 2021-22 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) की समेकित तुलन पत्र में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई(चार्ट IV.1) । एक साल पहले कोविड-19

चार्ट IV.1: एससीबी की चुनिंदा समग्र राशियां

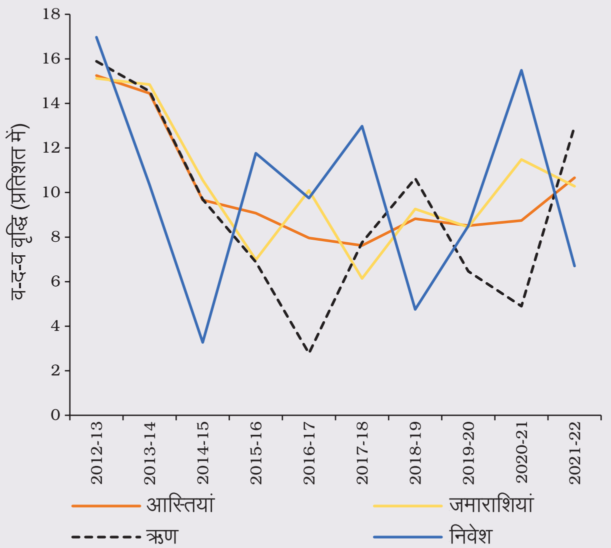

स्रोत: संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

उत्प्रेरित सावधानी के कारण जमा वृद्धि में कमी आई है। दो साल के अंतराल के बाद उधारी में सुधार के कारण देयताओं में वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष पर, मुख्य रूप से ध्यान पूरे वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि को मजबूत करने पर रहा। निवेश में संयमित रूप से कमी आई।

IV.4 हाल की नरमी के बावजूद, समेकित तुलन पत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का अब भी बड़ी हिस्सेदारी है। मार्च 2022 के अंत में, उनकी हिस्सेदारी एससीबी के कुल जमा शेष का 62 प्रतिशत और कुल ऋण और अग्रिमों का 58 प्रतिशत थी (सारणी IV.1)।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1. पूंजी	59,328	71,176	30,641	31,243	91,465	1,01,933	5,375	5,800	1,300	4,287	1,88,109	2,14,439
2. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	6,49,142	7,27,852	7,07,346	8,08,446	1,24,693	1,39,569	14,800	16,543	-704	-2,533	14,95,278	16,89,877
3. जमाराशियां	99,00,766	1,07,17,362	47,91,279	54,64,181	7,76,266	8,45,482	1,09,472	1,45,731	2,543	9,954	1,55,80,325	1,71,82,709
3.1. मांग जमाराशियां	6,84,451	7,23,259	6,82,092	7,83,883	2,37,412	2,78,677	3,964	5,770	19	2,155	16,07,938	17,93,745
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	34,62,923	38,20,484	14,55,976	17,47,958	87,032	92,120	22,198	43,577	2,524	7,799	50,30,653	57,11,938
3.3. मीयादी जमाराशियां	57,53,392	61,73,618	26,53,211	29,32,339	4,51,821	4,74,685	83,310	96,384	-	-	89,41,734	96,77,026
4. उधार	7,17,410	7,51,236	6,25,683	7,57,261	1,02,331	1,27,467	27,828	27,011	198	307	14,73,450	16,63,283
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	4,02,154	4,39,034	2,66,835	3,10,584	1,65,928	1,54,070	6,081	7,991	737	5,666	8,41,734	9,17,346
कुल देयताएँ/ आस्तियां	**1,17,28,799**	**1,27,06,661**	**64,21,784**	**73,71,715**	**12,60,682**	**13,68,521**	**1,63,557**	**2,03,076**	**4,072**	**17,681**	**1,95,78,895**	**2,16,67,655**
	(59.9)	**(58.6)**	**(32.8)**	**(34.0)**	**(6.4)**	**(6.3)**	**(0.8)**	**(0.9)**	**(0.0)**	**(0.1)**	**(100.0)**	**(100.0)**
1. आरबीआई में धारित नकदी और शेष	5,39,149	6,22,619	2,90,509	3,93,531	1,10,723	1,43,273	6,921	8,725	196	1,484	9,47,498	11,69,632
2. बैंको के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	5,91,125	6,42,484	2,75,256	3,33,745	1,02,108	1,17,739	12,309	10,212	790	3,273	9,81,588	11,07,452
3. निवेश	34,00,895	35,95,647	15,12,480	16,26,725	4,69,712	5,05,001	30,660	41,661	2,413	9,937	54,16,159	57,78,971
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (ए+बी)	28,07,934	29,75,938	12,57,135	13,68,694	4,20,141	4,47,584	27,142	36,683	2,412	9,924	45,14,765	48,38,822
ए) भारत में	27,70,643	29,32,482	12,36,660	13,50,959	3,86,490	3,98,009	27,142	36,683	2,412	9,924	44,23,347	47,28,057
बी) भारत के बाहर	37,292	43,456	20,476	17,735	33,651	49,575	-	-	-	-	91,418	1,10,765
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5
3.3 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में	5,92,949	6,19,704	2,55,345	2,58,031	49,570	57,417	3,517	4,978	1	13	9,01,382	9,40,144
4. ऋण और अग्रिम	63,47,417	70,43,940	39,29,572	45,62,780	4,20,780	4,65,484	1,08,613	1,35,802	0	2	1,08,06,381	1,22,08,009
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	1,45,894	2,33,191	1,19,295	1,50,703	60,380	64,595	124	585	-	-	3,25,694	4,49,074
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	24,90,604	26,61,563	11,46,858	13,62,842	1,79,873	2,01,228	8,929	12,582	-	-	38,26,263	42,38,214
4.3 मीयादी ऋण	37,10,919	41,49,187	26,63,419	30,49,235	1,80,527	1,99,661	99,560	1,22,636	0	2	66,54,424	75,20,720
5. अचल आस्तियां	1,06,826	1,09,784	39,714	44,456	4,457	4,964	1,676	2,001	222	370	1,52,895	1,61,575
6. अन्य आस्तियां	7,43,389	6,92,188	3,74,253	4,10,478	1,52,903	1,32,061	3,378	4,674	452	2,615	12,74,374	12,42,015

टिप्पणी: 1. शून्य/ नगण्य।
2. संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण घटकों का योग उनके संबंधित योग से भिन्न हो सकता है।
3. वार्षिक खातों पर विस्तृत बैंक-वार डेटा एकत्र किया जाता है और भारत में बैंकिंग से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों में प्रकाशित किया जाता है। जो https://www.dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सभी एससीबी में विभिन्न बैंक समूह की कुल आस्तियों/देयताओं का हिस्सा है।

स्रोत : संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.2 : तुलन पत्र की संरचना
(मार्च 2022 के अंत में)

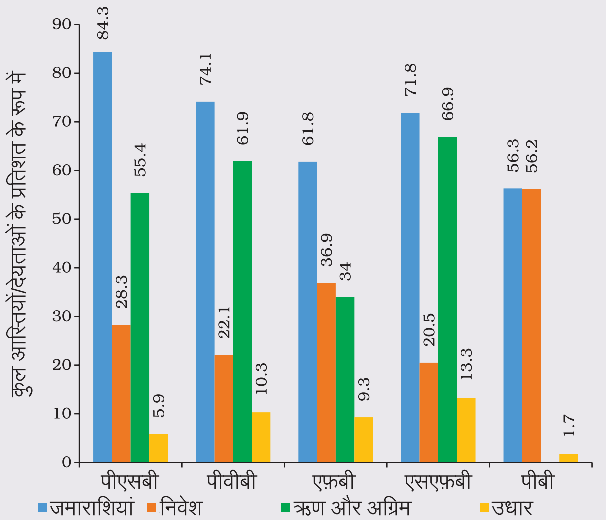

स्रोत: बैंक का वार्षिक लेखा।

IV.5 बैंक समूहों में तुलन पत्र संरचना पर करीब से नज़र डालने से उनकी परिचालन जटिलताओं पर प्रकाश पड़ता है। कुल देयताओं में जमा राशि के हिस्से के रूप में परिभाषित जमा - वित्त पोषण अनुपात, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में पीएसबी के लिए अधिक है। इससे पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंक ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उधार का सहारा लेते हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि पीवीबी की तुलना में पीएसबी का ऋण-आस्ति अनुपात ऐतिहासिक रूप से कम रहा है, इसका निवेश-आस्ति अनुपात अधिक रहा है, जो जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में उच्च निवेश को दर्शाता है (चार्ट IV.2)।

2.1. देयताएं

IV.6 घरेलू वित्तीय बचत दरें 2021-22 में घटकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गईं, जो कम जमा वृद्धि (चार्ट IV.3ए) में भी परिलक्षित हुई थी। जमा दरों में मई-अक्तूबर 2022 के दौरान रेपो दर में 190 आधार अंक (बीपीएस) के संचयी वृद्धि का संचरण होने पर,जमा वृद्धि दरों को बढ़ावा मिलने की संभावना है (चार्ट IV) 3बी)।

IV.7 2021-22 में एससीबी की उधारी में तेजी आई, क्योंकि जमा वृद्धि में ऋण मांग के साथ संतुलन बनाए नहीं रख सकी (चार्ट IV.4)। यह, उच्च वैधानिक आरक्षित अपेक्षाओं[1] के साथ

चार्ट IV.3: बचत और जमाराशियां

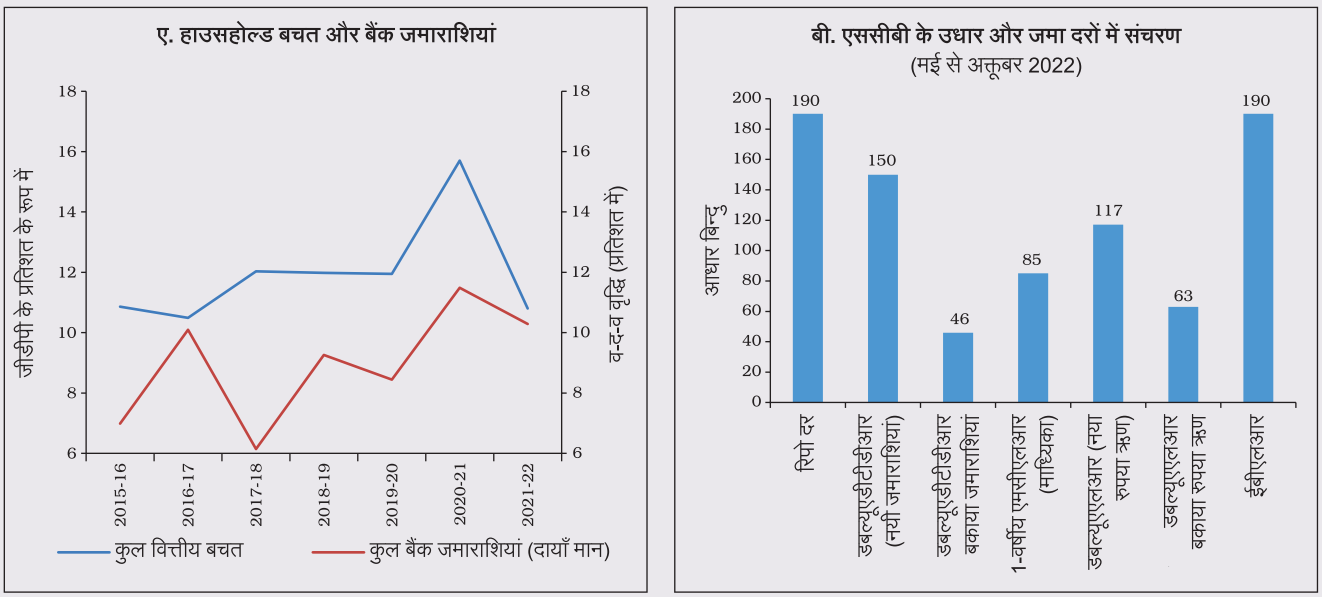

टिप्पणियाँ: डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर; एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाह्य मानदंड आधारित उधार दर।
स्रोत: एनएसओ, बैंकों और आरबीआई का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.4: उधार में वृद्धि

स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा।

जुड़ी हुई है, जिसमें प्रणाली से स्थायी चलनिधि की निकासी हुई, जिसने पीवीबी और विदेशी बैंकों (एफबी) को उधारी के लिए प्रेरित किया।

2.2. आस्तियां

IV.8 पीवीबी (चार्ट IV.5ए) के नेतृत्व में सितंबर 2022 की समाप्ति को ऋण वृद्धि दस वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण, जो 2018-19 की चौथी तिमाही से कम हो रहे थे, ने 2021-22 के दौरान स्थिर वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान वृद्धिशील ऋण का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा सावधि उधार के रूप में था, जो 10-तिमाही की उच्च गति से बढ़ा (चार्ट IV.5बी)।

IV.9 ऐतिहासिक रूप से, महानगरीय क्षेत्रों ने वृद्धिशील ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया है। हालांकि, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उच्च ऋण प्रवाह के कारण मार्च 2021 के अंत तक उनकी हिस्सेदारी घटकर 20 प्रतिशत रह गई। इसके बाद, जैसे-जैसे ऋण प्रवाह में पुनः वृद्धि हुई, महानगरीय क्षेत्रों ने अपना हिस्सा फिर से हासिल कर लिया (चार्ट IV.6)।

IV.10 एससीबी का लगभग 80 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में होता है और बैंकों की समग्र जी-सेक

चार्ट IV.5: अग्रिमों में वृद्धि

ए. समूह-वार बैंक[2]

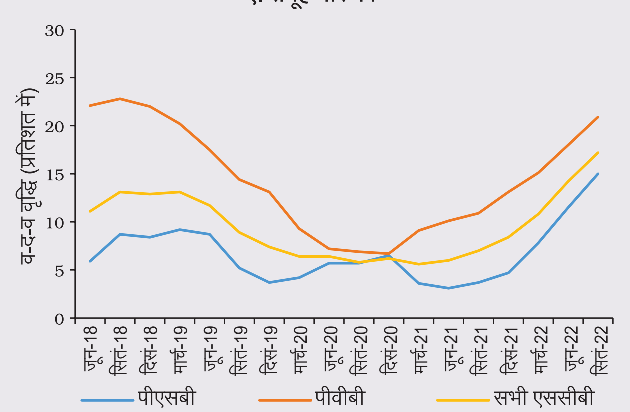

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों और ऋण पर तिमाही सांख्यिकी।

बी. प्रकार-वार लेखा

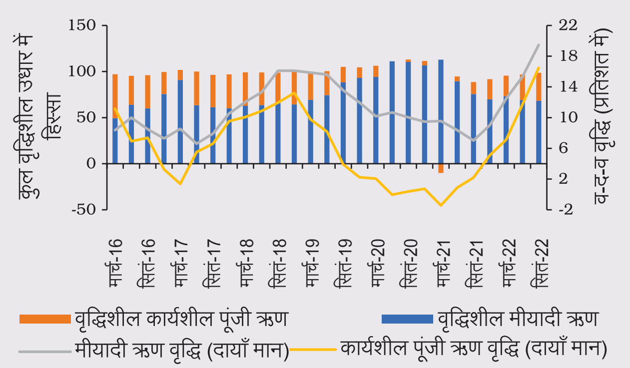

टिप्पणी: कार्यशील पूंजी को नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग ऋण के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। मीयादी ऋण को मध्यम और दीर्घावधि ऋणों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।

स्रोत: मूलभूत सांख्यिकी विवरणियां I, आरबीआई।

[1] नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 22 मई, 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके बाद, इसे 21 मई, 2022 से एनडीटीएल के 4.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

[2] आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को 21 जनवरी, 2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, मार्च 2019 के दौर से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समूह से बाहर रखा गया है और निजी क्षेत्र के बैंक समूह में शामिल किया गया है। 'लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड' (एक निजी क्षेत्र का बैंक) को 27 नवंबर, 2020 से 'डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड' (एक विदेशी बैंक) के साथ समामेलित किया गया था।

चार्ट IV.6: वृद्धिशील ऋण- जनसंख्या समूह-वार

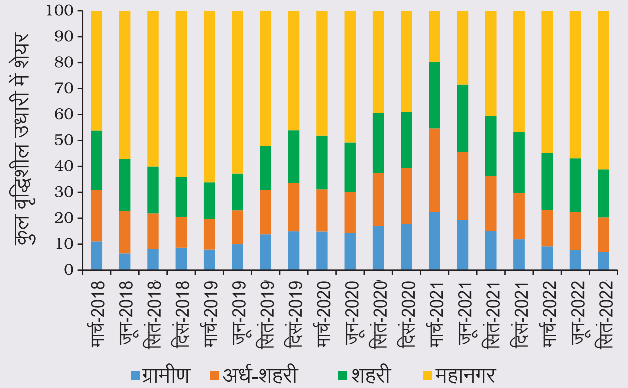

टिप्पणी: सभी केंद्रों को 2011 की जनगणना में उनकी आबादी के आधार पर निम्नलिखित चार जनसंख्या समूहों में वर्गीकृत किया गया है: ए) 'ग्रामीण' समूह में 10,000 से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। बी) 'अर्ध-शहरी' समूह में 10,000 और उससे अधिक लेकिन 100,000 से कम जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं। सी) 'शहरी' समूह में 100,000 और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं। डी) 'महानगर' समूह में दस लाख और उससे अधिक की आबादी वाले सभी केंद्र शामिल हैं।

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों और ऋण पर तिमाही सांख्यिकी।

धारिता ऋण मांग की स्थिति, जी-सेक की मांग-आपूर्ति गतिशीलता और ब्याज दर चक्र जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं। सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) हेतु पात्र प्रतिभूतियों के लिए बढ़ी हुई एचटीएम सीमाओं के विशेष वितरण ने बैंकों के लिए ऐसी प्रतिभूतियों[3] में निवेश करने के लिए अधिक गुंजाइश बन गई थी। इन कारकों के मेल को दर्शाते हुए, सभी बैंक समूहों में एससीबी के एसआरएल निवेश में वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

IV.11 2021-22 के दौरान चूँकि ऋण वृद्धि में तेजी आई और जमा वृद्धि में गिरावट आई, वृद्धिशील ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। निवेश में कमी के साथ ही वृद्धिशील निवेश-जमा (आई-डी) अनुपात में गिरावट आई (चार्ट IV.7)। आने वाले समय में उच्च नीतिगत ब्याज दर का जमा दरों तक पूर्ण संचरण करने से ऋण मांग को पूरा करने के लिए जमा प्रवाह में वृद्धि की संभावना है।

2.3. आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता प्रोफ़ाइल

IV.12 परिपक्वता परिवर्तन बैंकिंग व्यवसाय का सार है, और आस्ति-देयता परिपक्वता असंतुलन अपरिहार्य हैं क्योंकि बैंक अल्पकालिक जमा के बदले दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। हालांकि, 2021-22 के दौरान, परिपक्वता असंतुलन पिछले वर्ष की तुलना में सभी अवधियों में कम रहा, जो आस्ति-देयता प्रबंधन में सुधार को दर्शाता है (चार्ट IV.8)।

IV.13 बैंकों ने, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के, 2021-22 में उस वर्ष कम ब्याज दरों का लाभ उठाते हुए अल्पकालिक उधारी[4]

सारणी IV.2: एससीबी के निवेश
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफ़बी		एसएफ़बी		एससीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल निवेश (ए+बी)	34,09,289	36,03,007	15,21,942	16,32,570	4,49,403	4,77,085	30,709	41,695	54,11,343	57,54,358
ए. एसएलआर निवेश (I+II+III)	26,05,240	27,87,114	12,28,288	13,40,152	3,87,308	4,06,226	27,192	36,711	42,48,027	45,70,203
I. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	16,06,247	16,58,556	10,22,461	11,00,902	3,84,439	4,03,539	20,484	28,223	30,33,632	31,91,220
II. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	9,96,676	11,26,852	2,05,826	2,39,249	2,869	2,687	6,708	8,487	12,12,080	13,77,276
III. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	2,316	1,707	0	0	0	0	0	0	2,316	1,707
बी. गैर-एसएलआर निवेश (I+II)	8,04,049	8,15,893	2,93,654	2,92,419	62,095	70,858	3,517	4,985	11,63,316	11,84,154
I. कर्ज़ प्रतिभूतियाँ	7,56,313	7,61,390	2,76,043	2,75,903	61,645	70,482	3,498	4,922	10,97,499	11,12,698
II. इक्विटि	47,736	54,503	17,610	16,515	450	376	20	62	65,817	71,456

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

[3] वाणिज्यिक बैंकों को 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2021 के बीच अधिग्रहित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) वाली पात्र प्रतिभूतियों के लिए निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के 22 प्रतिशत की बढ़ी हुई परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) सीमा की प्रारंभिक विशेष छूट दी गई थी। इस सीमा को अप्रैल 2022 में बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया गया था, जिसे जून 2023 के अंत से धीरे-धीरे समाप्त किया जाना है।

[4] लघु-अवधि को 1 वर्ष तक, जबकि दीर्घ-अवधि को 3 वर्ष से अधिक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट IV.7: ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात

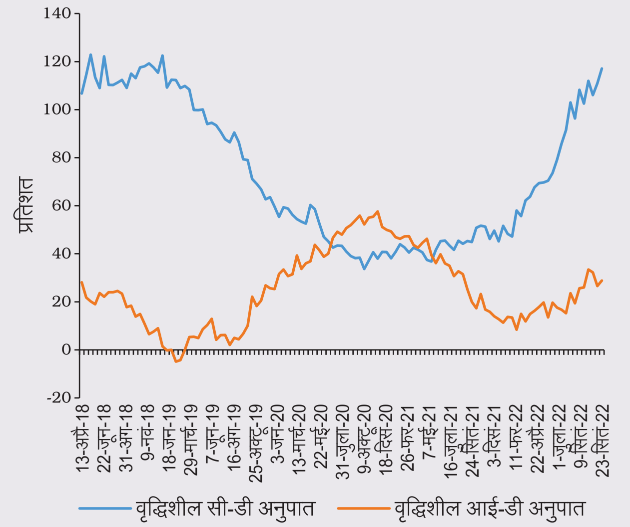

स्रोत: साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक, आरबीआई।

चार्ट IV.8: विभिन्न परिपक्वता खंडों में आस्तियों और देयताओं के अनुपात के बीच अंतराल

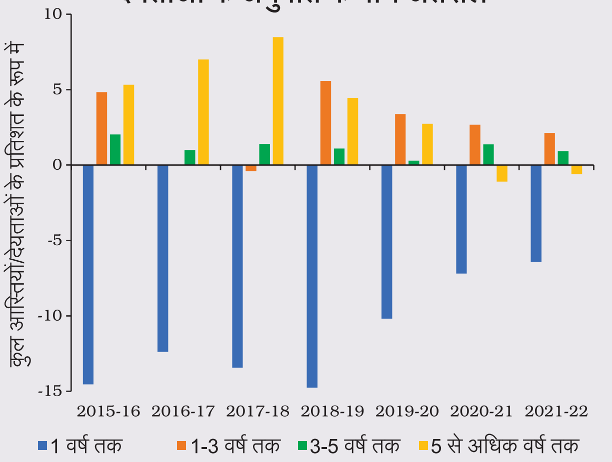

टिप्पणी: 1. आस्तियों में ऋण और अग्रिम और निवेश शामिल हैं। देयताओं में जमा और उधार शामिल हैं।
2. अंतराल की गणना आस्तियों से देयताओं को *घटा* कर की जाती है।

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा।

बढ़ाई। पीवीबी और एफबी का निवेश पोर्टफोलियो अल्पकालिक श्रेणी में केंद्रित है, जो इन बैंकों द्वारा सक्रिय निवेश जोखिम प्रबंधन का संकेत देता है (सारणी IV.3)।

सारणी IV.3: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

आस्तियां/देयताएं	पीएसबी		पीवीबी		एफ़बी		एसएफ़बी		पीबी		सभी एससीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियां												
ए) 1 वर्ष तक	36.2	35.0	34.2	32.3	62.4	62.8	53.6	50.2	13.0	10.3	37.0	35.6
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	21.9	21.9	28.9	30.2	30.8	29.2	42.1	46.0	87.0	89.7	24.7	25.2
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	11.3	12.7	9.2	9.7	6.7	8.0	1.7	1.6	0.0	0.0	10.3	11.4
डी) 5 वर्ष से अधिक	30.6	30.5	27.7	27.8	0.05	0.05	2.6	2.2	0.0	0.0	28.0	27.9
II. उधार												
ए) 1 वर्ष तक	54.5	53.9	41.4	50.0	83.8	80.5	46.9	37.1	100.0	100.0	50.8	53.9
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	20.9	22.9	34.0	29.2	11.8	16.3	37.3	49.5	0.0	0.0	26.1	25.7
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12.7	14.0	13.9	11.5	1.9	1.6	13.8	9.2	0.0	0.0	12.5	11.8
डी) 5 वर्ष से अधिक	11.9	9.2	10.6	9.3	2.4	1.6	2.1	4.2	0.0	0.0	10.5	8.6
III. ऋण और अग्रिम												
ए) 1 वर्ष तक	24.8	25.2	32.1	30.6	55.8	53.3	41.8	38.2	100.0	100.0	28.8	28.4
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	36.9	35.4	34.2	33.8	22.2	24.3	34.0	35.8	0.0	0.0	35.3	34.4
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	14.9	15.1	12.8	13.4	9.1	10.3	11.0	11.1	0.0	0.0	13.9	14.2
डी) 5 वर्ष से अधिक	23.4	24.4	20.9	22.3	12.9	12.1	13.2	14.9	0.0	0.0	22.0	23.0
IV निवेश												
ए) 1 वर्ष तक	23.7	25.2	50.7	48.8	84.9	83.2	58.1	53.8	97.4	98.7	36.8	37.3
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	16.7	16.4	20.7	22.4	10.5	10.8	25.4	25.6	1.9	0.8	17.3	17.6
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	13.2	13.2	6.5	7.8	2.3	2.5	2.9	4.9	0.4	0.1	10.3	10.7
डी) 5 वर्ष से अधिक	46.4	45.2	22.2	20.9	2.4	3.5	13.6	15.7	0.2	0.3	35.6	34.4

टिप्पणी: आंकड़े तुलन पत्र में प्रत्येक घटक में प्रत्येक परिपक्वता बकेट के हिस्से को दर्शाते हैं। पूर्णांकन के कारण घटकों का योग 100 नहीं हो सकता है।

स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा।

2.4. अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

IV.14 2021-22 के दौरान, भारत के पक्ष में ब्याज दर के अंतर से प्रोत्साहित होकर (परिशिष्ट सारणी IV.2), भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं, विशेष रूप से अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपए खातों और विदेशी मुद्रा उधारियों में काफी वृद्धि हुई। दूसरी ओर, ऋण और जमा तथा ऋण प्रतिभूतियों की धारिता के कारण अंतरराष्ट्रीय आस्ति में वृद्धि हुई थी। अनिवासियों को एक साल पहले की तुलना में ऋण कम हो गया, जबकि निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण और नोस्ट्रो जमा शेष में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.3)। इन कारकों को दर्शाते हुए, भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों देयताओं का अनुपात लगातार तीन वर्षों से बढ़ रहा है (चार्ट IV.9ए)।

IV.15 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय बैंकों के अंतरराष्ट्रीय दावों का हिस्सा अर्थात, विदेशी बैंकों को छोड़कर भारतीय बैंकों की घरेलू और विदेशी शाखाओं द्वारा विदेशों में रखी गई आस्तियां अल्पकालिक परिपक्वता की ओर स्थानांतरित हो गईं और गैर-वित्तीय निजी संस्थानों से शिफ्ट होकर बैंकों की ओर चली गईं (परिशिष्ट सारणी IV.4 और चार्ट IV.9बी)। संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस.) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय दावों की बैंकों की देश संरचना में भौगोलिक परिवर्तन हुए। (परिशिष्ट सारणी IV.5)।

2.5. तुलन-पत्र से इतर परिचालन

IV.16 अग्रिम विनिमय अनुबंधों, स्वीकृति और समर्थन में वृद्धि के कारण सभी एससीबी के लिए आकस्मिक देयताओं में 11 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि 23 प्रतिशत को पार कर गई (चार्ट IV.10ए)। तुलन पत्र आकार के अनुपात के रूप में, आकस्मिक देयताएं 2020-21 में 119 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 133 प्रतिशत हो गईं (परिशिष्ट सारणी IV.6)। एफबी की आकस्मिक देयताएं उनके तुलन पत्र आकार से 10 गुना अधिक हैं और बैंकिंग प्रणाली के कुल तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर का लगभग आधा हिस्सा हैं (चार्ट IV.10बी)। हालांकि, उनकी गैर-ब्याज़ आय उतनी नहीं बढ़ी है।

चार्ट IV.9: भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएँ और आस्तियां

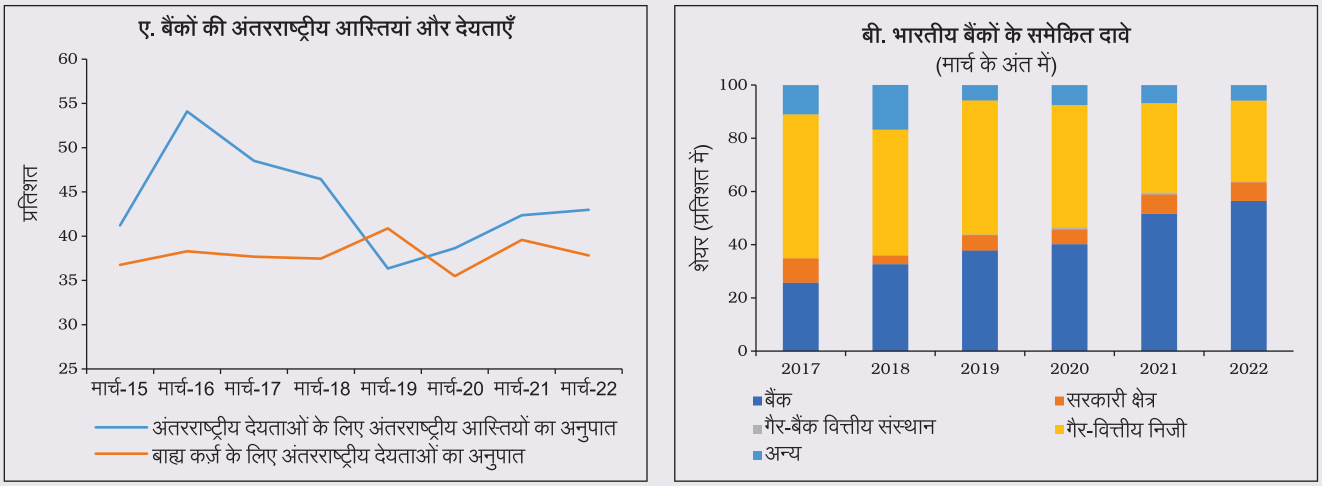

स्रोत: बैंकों और डीबीआईई का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.10: बैंकों की तुलनपत्रेतर देयताएँ

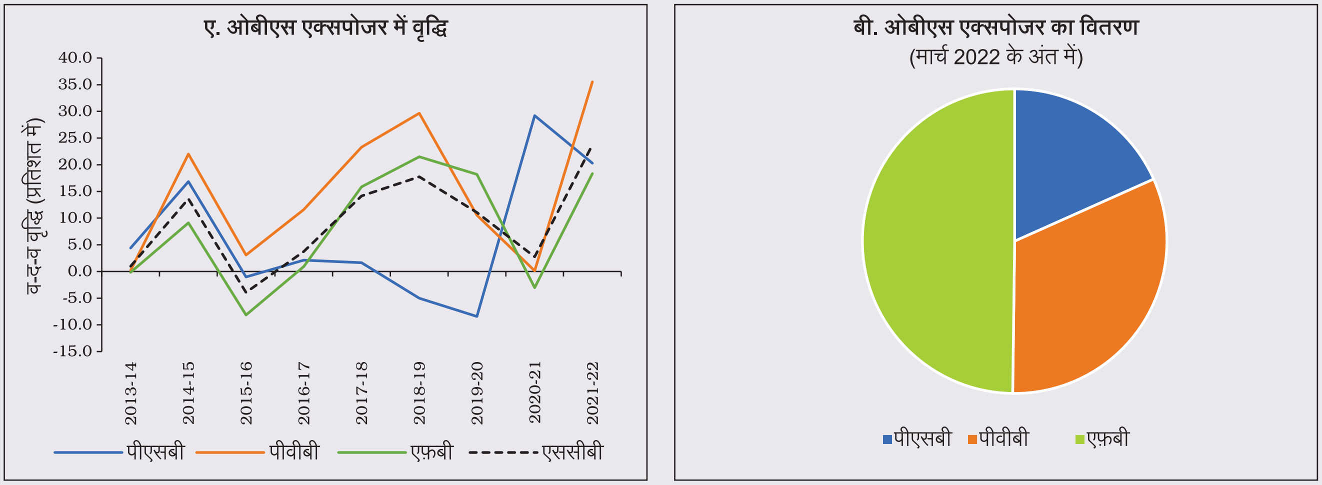

स्रोतः बैंकों का वार्षिक लेखा।

3. वित्तीय प्रदर्शन

IV.17 आस्ति निर्धारण में अधिक पारदर्शिता और मजबूत पूंजी और प्रावधान बफर के कारण बैंकों ने मजबूती के साथ महामारी का सामना किया। पोर्टफोलियो विविधीकरण के साथ-साथ ऋण निगरानी प्रक्रियाओं में वृद्धि ने हानि रोकने में मदद की और उनके तुलन पत्र को सशक्त बनाया। तदनुसार, इक्विटी पर आय और आस्तियों पर आय (आरओए) के संदर्भ में मापे जाने वाले एससीबी की लाभप्रदता, 2014-15 में आखिरी बार देखे गए स्तरों तक सुधर गया (चार्ट IV.11)।

IV.18 सशक्त बैंक लाभप्रदता मजबूत वित्तीय प्रणाली का एक संकेतक है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह है कि उच्च लाभप्रदता लीवरेज बाधाओं को कम कर सकती है और अधिक जोखिम लेने[5] का

चार्ट IV.11: लाभप्रदता अनुपात
(मार्च अंत में)

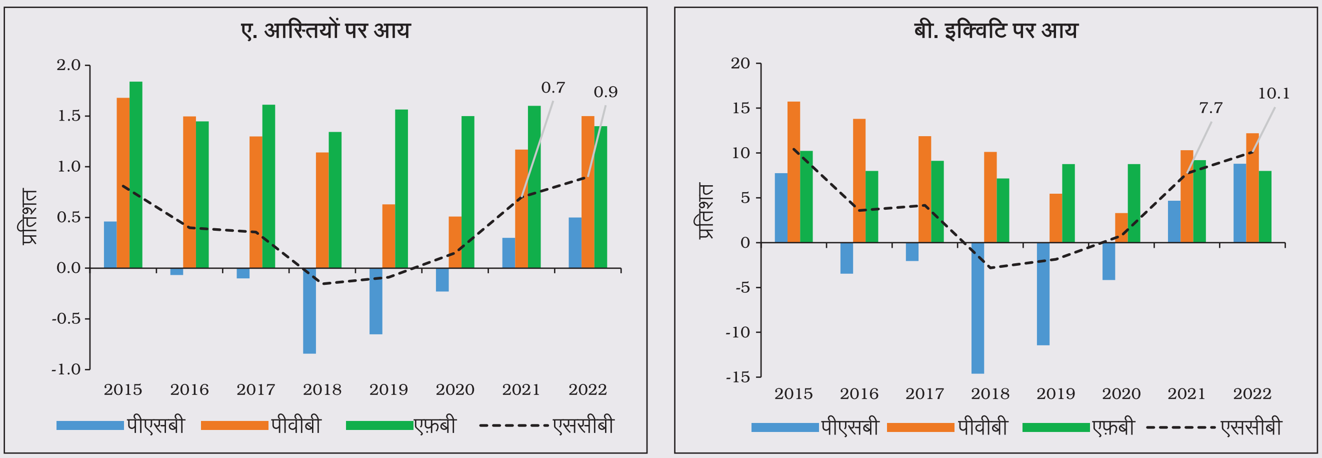

स्रोत: बैंकों और डीबीआईई का वार्षिक लेखा, आरबीआई।

[5] जू, तेंगतेंग और हू, कुन और दास, उदयबीर, (2019)। बैंक लाभप्रदता और वित्तीय स्थिरता। आईएमएफ वर्किंग पेपर। 19. 1. 10.5089/9781484390078.001.

कारण बन सकती है। भारत के लिए अनुभवजन्य अनुमान एक सीमा के अस्तित्व में होने की सूचना देते हैं जिसके पार उच्च बैंक लाभप्रदता वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकती है (बॉक्स IV.1)। मार्च 2022 के अंत में एससीबी का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.9 प्रतिशत था, जो उक्त सीमा से काफी नीचे बना हुआ है।

बॉक्स IV.1: वित्तीय स्थिरता पर बैंक की लाभप्रदता का प्रभाव

शास्त्रों के अनुसार, वित्तीय स्थिरता का पता इक्विटि कीमतों के ऐतिहासिक जोखिम मूल्य (वीएआर) द्वारा मापे गए विशेष प्रकार के जोखिम द्वारा लगाया जाता है (ज़ू, हू और दास, 2019)। इसके लिए 2008-2019[6] की अवधि के लिए 24 बैंकों के तिमाही स्टॉक विवरणियों के डेटा का उपयोग किया जाता है। एक निश्चित प्रभाव पैनल सीमा प्रतिगमन के माध्यम से एनआईएम के उस सीमा मूल्य का आकलन किया जाता है जिसके ऊपर उच्च लाभ वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। परिणाम एनआईएम और वित्तीय स्थिरता के बीच एक गैर-रैखिक संबंध का सुझाव देते हैं (चार्ट 1)। इसका तात्पर्य यह है कि एक सीमा से अधिक एनआईएम का वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एनआईएम का अंतर्जात रूप से निर्धारित सीमा मूल्य लगभग 5 प्रतिशत बैठता है[7]। बैंकों के सीआरएआर, जीएनपीए, कुल आस्तियों के लॉग द्वारा मापे गए आकार, अल्पावधि ब्याज दर (कॉल दर) और जीडीपी को नियंत्रित करने के बाद भी यह परिणाम मजबूत बना हुआ है (सारणी 1)।

चार्ट 1: बैंक की निवल ब्याज मार्जिन और वीएआर_95: 2008-2019

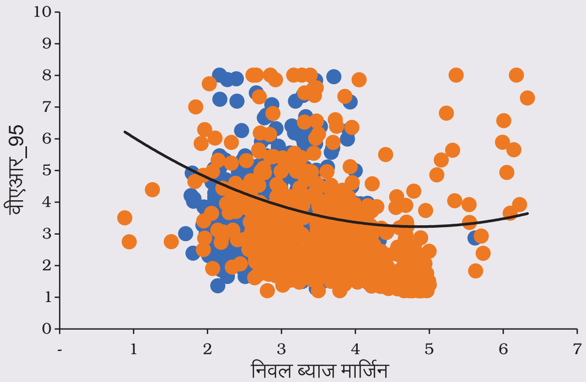

टिप्पणी: नीले रंग के निशान पीएसबी को दर्शाते हैं, और नारंगी रंग के निशान पीवीबी को दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना।

सारणी 1: दो पद्धतियों के साथ पैनल सीमा प्रतिगमन मॉडल का अनुमान

मॉडल	(1)	(2)
निर्भर चर	वीएआर_एच	वीएआर_95
सीमा	5.0011 (पी मान = 0.00)	5.0011 (पी मान = 0.00)
एनआईएम		
β_1	-0.130* (0.0756)	-0.213*** (0.0811)
β_2	0.153** (0.0729)	0.0568 (0.0782)
नियंत्रण चर		
सीआरएआर	-0.0371 (0.0227)	-0.0667*** (0.0244)
जीएनपीए	0.0275*** (0.00813)	0.0541*** (0.00872)
लॉग कुल आस्तियां	-0.358*** (0.117)	-0.313** (0.125)
एफ़सी (डमी चर)	1.757*** (0.133)	2.020*** (0.143)
कॉल दर	0.222*** (0.0198)	0.198*** (0.0213)
जीडीपी वृद्धि	-0.0332*** (0.0102)	-0.0276** (0.0109)
स्थिर	6.983*** (1.555)	7.484*** (1.667)
अवलोकन	1,152	1,152
आर-वर्गित	0.430	0.430
बैंकों की संख्या	24	24
प्रक्रियाओं की संख्या	500	500
समस्या>एफ़	0	0

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में मानक त्रुटियाँ।
2. *** पी <0.01, ** पी <0.05, * पी <0.1।
3: एफ़सी एक संकट डमी को संदर्भित करता है, जो वर्ष 2008 और 2009 के लिए 1 मान लेता है, और अन्यथा 0।

संदर्भ :

Claudiu Tiberiu Albulescu, Banks' Profitability and Financial Soundness Indicators: A Macro-level Investigation in Emerging Countries, *Procedia Economics and Finance*, Volume 23,2015,Pages 203-209,ISSN 2212-5671, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00551-1.

Zicchino, Lea & Tsomocos, Dimitrios & Segoviano, Miguel & Goodhart, Charles & Bracon, Oriol. (2006). Searching for a Metric for Financial Stability. *Financial Markets Group, FMG Special Papers*.

[6] 2019 के बाद की अवधि में कई बैंक विलय हुए, जिससे नियमित समय शृंखला डेटा की उपलब्धता बाधित हुई। इसे देखते हुए, विश्लेषण 2008-2019 की अवधि तक सीमित है।

[7] इष्टतम एनआईएम के लिए 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल (4.9733, 5.2333) है। यह परीक्षण करते हुए कि क्या इस गैर-रैखिक संबंध में एक से अधिक सीमा है, बूटस्ट्रैप पी-मान को महत्वपूर्ण नहीं पाए जाने के कारण दो और अधिक संख्या में सीमाओं की परिकल्पनाओं को निरस्त कर दिया गया था।

IV.19 वर्ष 2021-22 के दौरान उच्च लाभ में आय में वृद्धि और व्यय में संकुचन का योगदान रहा है (सारणी IV.4)। एससीबी की कुल आय का 84 प्रतिशत ब्याज से प्राप्त आय है, जिसने एक वर्ष पहले अनुभव किए गए संकुचन को उलट दिया। उच्च उधार और निवेश की मात्रा के कारण इन चैनलों से उच्च ब्याज आय प्राप्त हुई, भले ही उस समय ब्याज दरें कम रहीं। ब्याज में कमी और कम प्रावधानों और आकस्मिकताओं के कारण व्यय में कमी हुई ।

IV.20 भारत में आमतौर पर, जी-सेक प्रतिफल और बैंकों की गैर-ब्याज आय के बीच एक विपरीत संबंध देखा जाता है (चार्ट IV.12)। वर्ष के दौरान पीएसबी और एफबी की अन्य आय में गिरावट आई, जो आंशिक रूप से उनके निवेश पोर्टफोलियो पर हुई ट्रेडिंग हानि को दर्शाता है। इसके विपरीत, पीवीबी की अन्य आय में वृद्धि मुख्य रूप से कमीशन और ब्रोकरेज आय में वृद्धि से हुई थी, जो गैर-ब्याज आय का 60 प्रतिशत से अधिक है।

IV.21 दुनिया भर में जारी समकालिक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का बैंक लाभप्रदता के विभिन्न घटकों जैसे निवल ब्याज आय, गैर-ब्याज आय और ऋण हानि प्रावधानों पर असममित प्रभाव पड़ सकता है। ब्याज दर में वृद्धि से निवल ब्याज आय में वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर, चूंकि बैंकों को प्रतिफल बढ़ने की स्थिति में अपने राजकोषीय निवेश पर ट्रेडिंग हानि उठानी पड़ती है, इसलिए उनकी गैर-ब्याज आय में कमी हो सकती है। इन हानियों के साथ-साथ एनपीए के लिए प्रावधान

सारणी IV.4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय और व्यय में रुझान

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1. आय	8,30,345 (-0.5)	8,31,900 (0.2)	5,42,035 (-0.8)	5,72,397 (5.6)	80,356 (-3.4)	79,498 (-1.1)	22,418 (16.6)	25,060 (11.8)	1,004 (1733.5)	4,952 (393.2)	14,76,159 (-0.5)	15,13,806 (2.6)
ए) ब्याज आय	7,07,201 (-1.3)	7,09,132 (0.3)	4,51,439 (0.5)	4,70,943 (4.3)	63,688 (-4.5)	65,837 (3.4)	19,523 (15.2)	22,120 (13.3)	101 (120.1)	446 (343.3)	12,41,953 (-0.6)	12,68,479 (2.1)
बी) अन्य आय	1,23,144 (4.3)	1,22,768 (-0.3)	90,596 (-6.9)	1,01,454 (12.0)	16,669 (0.7)	13,660 (-18.0)	2,894 (27.4)	2,940 (1.6)	903 (9931.3)	4,505 (398.7)	2,34,206 (-0.03)	2,45,327 (4.7)
2. व्यय	7,98,527 (-7.2)	7,65,360 (-4.2)	4,72,559 (-10.4)	4,76,174 (0.8)	61,391 (-8.4)	61,113 (-0.5)	20,380 (18.1)	24,087 (18.2)	1,304 (235.4)	5,041 (286.6)	13,54,161 (-8.0)	13,31,774 (-1.7)
ए) खर्च किया गया ब्याज	4,31,627 (-7.8)	4,11,181 (-4.7)	2,32,370 (-9.9)	2,24,235 (-3.5)	21,560 (-25.2)	21,482 (-0.4)	9,122 (15.1)	9,513 (4.3)	55 (307.7)	156 (181.4)	6,94,735 (-8.9)	6,66,566 (-4.1)
बी) परिचालन व्यय	2,03,855 (5.8)	2,20,091 (8.0)	1,30,451 (3.0)	1,56,613 (20.1)	22,334 (3.5)	24,969 (11.8)	7,549 (5.6)	9,816 (30.0)	1,251 (156.6)	4,882 (290.3)	3,65,440 (4.8)	4,16,371 (13.9)
जिनमें से: वेतन बिल	1,24,612 (7.6)	1,32,747 (6.5)	50,280 (6.2)	58,851 (17.0)	7,891 (0.2)	9,178 (16.3)	4,304 (12.9)	5,305 (23.3)	398 (50.6)	788 (98.1)	1,87,485 (7.0)	2,06,870 (10.3)
सी) प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,63,045 (-18.3)	1,34,088 (-17.8)	1,09,737 (-23.0)	95,326 (-13.1)	17,498 (5.1)	14,662 (-16.2)	3,709 (70.8)	4,758 (28.3)	-2	3	2,93,987 (-18.5)	2,48,837 (-15.4)
3. परिचालन लाभ	1,94,863 (12.3)	2,00,628 (3.0)	1,79,214 (10.9)	1,91,549 (6.9)	36,463 (11.1)	33,047 (-9.4)	5,747 (38.8)	5,732 (-0.3)	-302	-87	4,15,985 (11.9)	4,30,869 (3.6)
4. निवल लाभ	31,818 -	66,540 (109.1)	69,477 (263.5)	96,223 (38.5)	18,965 (17.2)	18,385 (-3.1)	2,038 (3.5)	974 (-52.2)	-300	-90	1,21,998 (1018.1)	1,82,032 (49.2)
5. स्प्रेड (शून्य)	2,75,574 (11.0)	2,97,950 (8.1)	2,19,069 (14.7)	2,46,708 (12.6)	42,128 (11.3)	44,356 (5.3)	10,401 (15.3)	12,608 (21.2)	45 (40.7)	290 (541.7)	5,47,218 (12.6)	6,01,912 (10.0)
6. निवल ब्याज सीमा	2.45	2.44	3.58	3.58	3.30	3.37	7.02	6.88	1.58	2.67	2.91	2.92

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत भिन्नताओं को दर्शाते हैं।
2. प्रतिशत भिन्नता थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।
3. एनआईएम को औसत आस्ति के प्रतिशत में एनआईआई के रूप में परिभाषित किया गया है।

स्रोत: संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.12: एससीबी का जी-सेक प्रतिफल और गैर-ब्याज आय

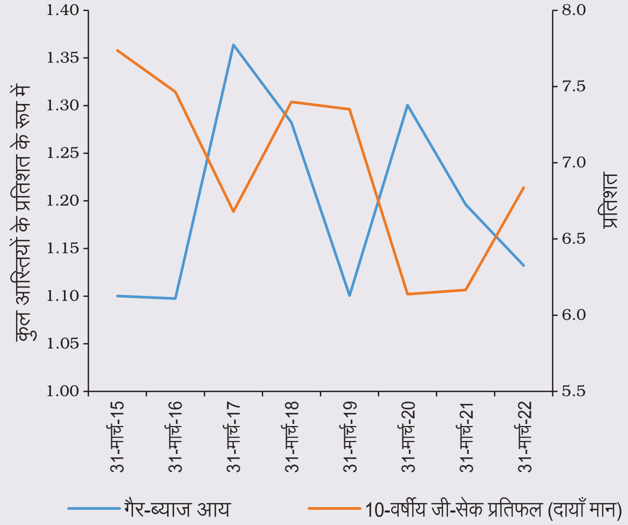

स्रोत: ब्लूमबर्ग और बैंकों का लेखा

बढ़ाने से लाभप्रदता और कम हो सकती है। बैंकों की लाभप्रदता पर मौद्रिक नीति का निवल प्रभाव इस प्रकार एक अनुभवजन्य समस्या है (बॉक्स IV.2)।

IV.22 ब्याज व्यय के कारण एससीबी के कुल व्यय में संकुचन हुआ, जिसमें कम जमा दरों के कारण गिरावट आई। चूंकि जमा राशि एफबी के तुलन पत्र का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है, इसलिए कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उनका ब्याज व्यय अन्य दो बैंक समूहों की तुलना में कम है (चार्ट IV.13 ए)। दूसरी ओर, लागत-आय अनुपात, जो परिचालन आय के लिए परिचालन व्यय का अनुपात है, पीएसबी के लिए उनके उच्च वेतन व्यय के कारण सबसे अधिक था (चार्ट IV.13 बी)।

IV.23 चूंकि बैंकों को महामारी के दौरान प्रदत्त अधिस्थगन के कारण निर्गत ऋणों पर उच्च प्रावधान बनाए रखने की

बॉक्स IV.2: बैंक की लाभप्रदता पर मौद्रिक नीति का प्रभाव

2010-2021 की अवधि के लिए ब्रिक्स देशों के 234 बैंकों पर एक वार्षिक डेटासेट के साथ विभिन्न समष्टि-आर्थिक कारकों जैसे कि अल्पावधिक ब्याज दरें, प्रतिफल, जीडीपी और मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति और बैंक लाभप्रदता के बीच संबंध का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया था[8]। गुडहार्ट (2019) के अनुरूप, अल्पावधिक ब्याज दरों को ओवरनाइट सूचकांक स्वैप (ओआईएस)[9] द्वारा अनुमानित किया गया था। प्रतिफल वक्र का झुकाव—जिसकी गणना 10-वर्ष और दो-वर्षीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल के बीच के अंतर के रूप में की जाती है, इसका उपयोग ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के बारे में अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।

एक निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन के परिणाम बैंकों के आरओए और अल्पावधिक ब्याज दरों के बीच अवतल संबंध का सुझाव देते हैं। इसी तरह का संबंध आरओए और प्रतिफल वक्र के स्लोप के बीच भी देखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक सीमा तक, गैर-ब्याज आय और प्रावधानों पर नीतिगत दरों में वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव निवल ब्याज आय पर सकारात्मक प्रभाव से अधिक है। बैंक-विशिष्ट कारक भी लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते पाए जाते हैं। एक उच्च कुल आस्तियों के लिए इक्विटि अनुपात और एक बड़ा आस्ति आकार उच्च लाभप्रदता से जुड़ा हुआ था। बैंक लाभप्रदता पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का प्रभाव सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है (सारणी 1)।

पार-देशीय साक्ष्य बताते हैं कि, बैंको के आरओए अल्पावधि दरों के साथ प्रतिफल वक्र के स्लोप के संबंध में गैर-रैखिक हैं।

सारणी 1: प्रतिगमन परिणाम

चर	निर्भर चर: आस्तियों पर प्रतिलाभ		
	(1)	(2)	(3)
निर्भर चर (-1)	0.244***	0.235***	0.148**
	(0.0599)	(0.0609)	(0.0598)
ओआईएस	0.168***	0.108**	0.158**
	(0.0402)	(0.0438)	(0.0692)
ओआईएस^2	-0.00705**	-0.00415	-0.00539
	(0.00301)	(0.00304)	(0.00396)
प्रतिफल वक्र स्लोप	0.168***	0.255***	0.307***
	(0.0571)	(0.0663)	(0.0816)
प्रतिफल वक्र स्लोप^2	-0.0642***	-0.0753***	-0.0816***
	(0.0135)	(0.0127)	(0.0139)
कुल आस्तियों के लिए इक्विटि			0.110***
			(0.0220)
आय के लिए लागत अनुपात			-0.00103
			(0.00120)
कुल आस्तियों का लॉग			0.256*
			(0.140)
जीडीपी वृद्धि		0.0266***	0.0207**
		(0.00805)	(0.00912)
मुद्रास्फीति		0.0378	0.0399
		(0.0249)	(0.0309)
स्थिर	0.127	0.0202	-3.757**
	(0.131)	(0.118)	(1.778)
अवलोकन	2,986	2,986	2,014
आर-वर्गित	0.411	0.414	0.452

कोष्ठक में मजबूत मानक त्रुटियां दी गई हैं।
*** पी <0.01, ** पी <0.05, * पी <0.1

संदर्भ:

Goodhart, C. A., & Kabiri, A. (2019). *Monetary Policy and Bank Profitability in a Low Interest Rate Environment: A Follow-up and a Rejoinder* . Centre for Economic Policy Research.

[8] बैंकिंग आंकड़ा बैंकर डेटाबेस से लिया गया है, जबकि वित्तीय और समष्टि-आर्थिक आंकड़े ब्लूमबर्ग और सीईआईसी से लिए गए हैं।

[9] ब्राजील को छोड़कर तीन महीने के ओआईएस को संदर्भित करता है, जहां यह एक साल के ओआईएस से संबंधित है।

चार्ट IV.13: एससीबी का व्यय

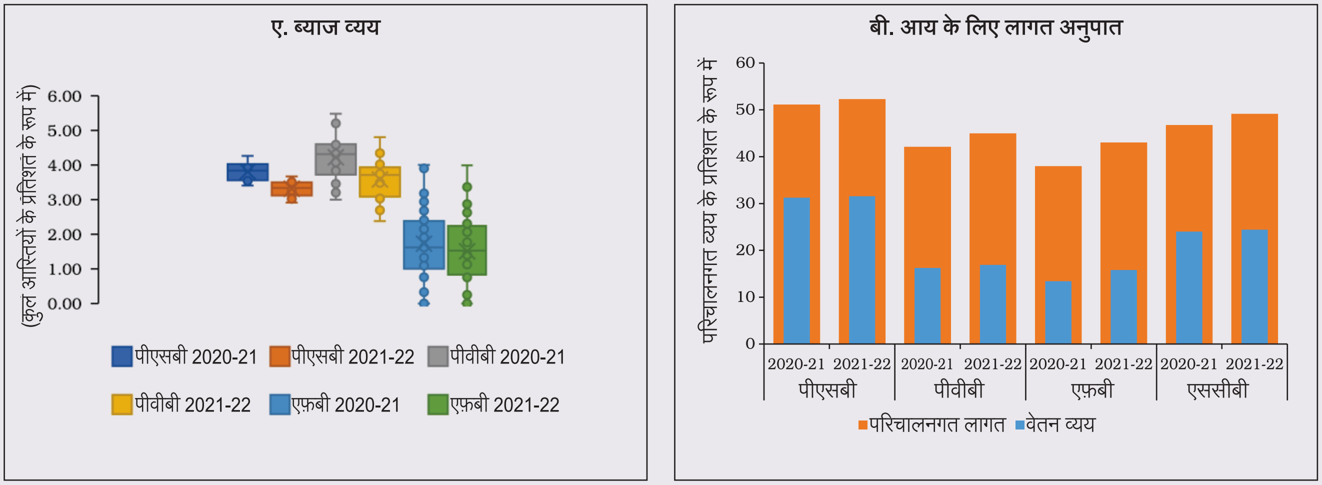

स्रोत: संबन्धित बैंकों का वार्षिक लेखा।

आवश्यकता थी, इसलिए 2019-20 और 2020-21 में उनका निवल लाभ बुरी तरह प्रभावित हुआ। 2021-22 के दौरान, उन प्रावधानों को कम करने से बैंकों के निवल लाभ में वृद्धि हुई (चार्ट IV.14ए)। इसके अलावा, जैसे-जैसे जीएनपीए में गिरावट आई, प्रावधान कवरेज अनुपात में वृद्धि हुई (चार्ट IV.14 बी)।

IV.24 चूंकि निधि पर आय में कमी निधि की लागत में कमी की तुलना में थोड़ी अधिक थी, इसलिए स्प्रेड में मामूली गिरावट आई। कुल जमा में चालू और बचत खाता (सीएएसए) जमा का हिस्सा बढ़ने से जमा की लागत कम हो गई। मार्च 2022 के अंत में एससीबी के बकाया अस्थिर दर वाले रुपये ऋण का 44 प्रतिशत हिस्सा बाह्य बेंचमार्क संबद्ध उधार दर (ईबीएलआर) पर था। पीएसबी और पीवीबी के लिए तुलनात्मक स्थिति क्रमशः 33 प्रतिशत और 62 प्रतिशत थी। मौजूदा अस्थिर दर वाले ऋण का उस समय की प्रचलित कम दरों पर पुनर्मूल्यांकन और कम दरों पर वृद्धिशील उधार

चार्ट IV.14: लाभप्रदता पर प्रावधानीकरण का प्रभाव

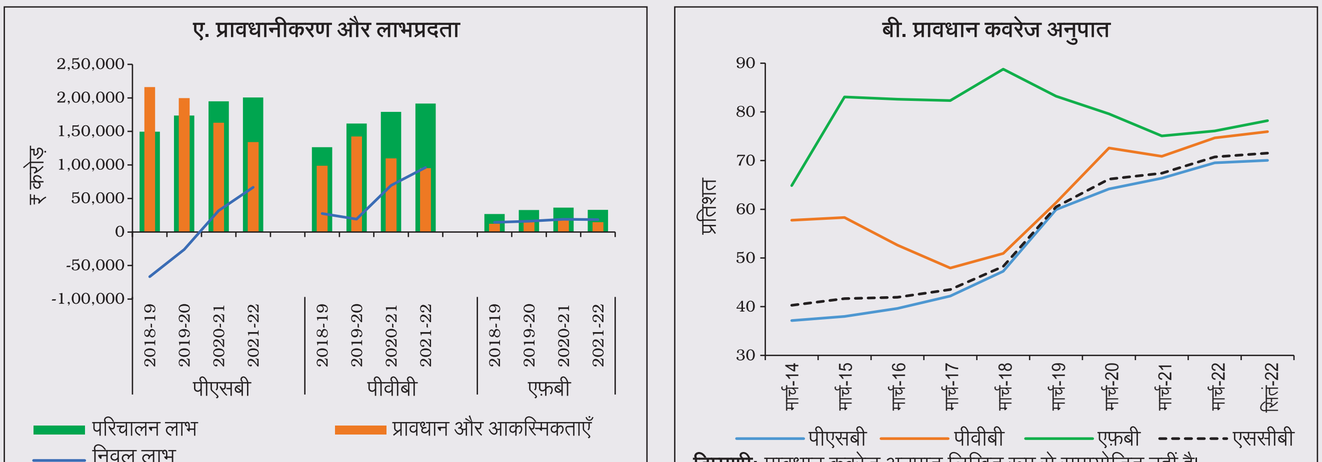

स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा।

टिप्पणी: प्रावधान कवरेज अनुपात लिखित रूप से समायोजित नहीं है।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.5: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

बैंक समूह/चर	वर्ष	जमाराशियों की लागत	उधार की लागत	निधियों की लागत	अग्रिमों पर प्रतिलाभ	निवेशों पर प्रतिलाभ	निधियों पर प्रतिलाभ	स्प्रेड
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5)
पीएसबी	2020-21	4.2	4.3	4.2	7.5	6.6	7.2	3.0
	2021-22	3.7	4.2	3.7	6.9	6.1	6.6	2.9
पीवीबी	2020-21	4.3	5.6	4.5	9.1	6.2	8.3	3.9
	2021-22	3.7	5.2	3.9	8.5	5.8	7.7	3.9
एफ़बी	2020-21	2.4	3.3	2.5	7.1	6.0	6.5	4.0
	2021-22	2.1	3.6	2.3	7.0	5.7	6.3	4.0
एसएफ़बी	2020-21	6.8	8.8	7.3	17.1	6.8	14.9	7.6
	2021-22	5.9	7.1	6.1	15.8	5.9	13.6	7.4
पीबी	2020-21	3.0	5.3	3.1	9.3	4.0	4.0	0.9
	2021-22	2.4	2.8	2.4	5.2	5.1	5.1	2.7
एससीबी	2020-21	4.2	4.9	4.2	8.1	6.4	7.6	3.4
	2021-22	3.6	4.6	3.7	7.6	6.0	7.0	3.3

टिप्पणी : 1. जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर दिया गया ब्याज /वर्तमान और पिछले वर्षों की जमाराशियों का औसत।
2. उधार की लागत = (व्यय किया गया ब्याज - जमा पर ब्याज)/ वर्तमान और पिछले वर्षों के उधार का औसत।
3. निधियों की लागत = (खर्च किया गया ब्याज) / वर्तमान और पिछले वर्षों का औसत (जमा + उधार)।
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों के अग्रिमों का औसत।
5. निवेश पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों के निवेश का औसत।
6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिम पर अर्जित ब्याज + निवेश पर अर्जित ब्याज)/ वर्तमान और पिछले वर्षों का औसत (अग्रिम + निवेश)।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र से की गई गणना।

दिये जाने के कारण अग्रिमों पर आय में कमी आई है (सारणी IV.5)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

IV.25 2021-22 के दौरान, एससीबी की पूंजी की स्थिति, आस्ति गुणवत्ता वर्ष और लीवरेज अनुपात में सुधार हुआ तथा चलनिधि की स्थिति मजबूत बनी रही। रिज़र्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत आने वाले बैंकों की संख्या मार्च 2021 के अंत में तीन से घटकर मार्च 2022 के अंत में एक रह गई। सितंबर 2022 के अंत में पीसीए ढांचे के तहत कोई बैंक नहीं था।

4.1. पूँजी पर्याप्तता

IV.26 आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) अवधि के पश्चात एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) क्रमिक रूप से बढ़ रहा है (सारणी IV.6)। जोखिम-

सारणी IV.6: एससीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफ़बी		एससीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1. पूंजीगत निधियां	**7,93,971**	**8,93,870**	**7,72,389**	**8,80,664**	**2,04,433**	**2,19,844**	**17,90,330**	**20,15,443**
i) टियर I पूंजी	6,49,082	7,35,753	7,01,622	8,06,457	1,86,369	2,01,196	15,54,796	17,62,613
ii) टियर II पूंजी	1,44,889	1,58,117	70,767	74,207	18,064	18,648	2,35,535	2,52,830
2. जोखिम भारित आस्तियां	**56,56,060**	**60,84,930**	**41,92,303**	**46,92,169**	**10,49,878**	**11,09,568**	**1,08,98,241**	**1,18,86,667**
3. सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)	**14.0**	**14.7**	**18.4**	**18.8**	**19.5**	**19.8**	**16.3**	**16.8**
जिनमें से: टियर I	11.7	12.7	16.9	17.1	17.7	18.2	14.1	15.7
टियर II	2.5	2.7	1.7	1.3	1.6	1.6	2.2	1.8

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, आरबीआई।

चार्ट IV.15: एससीबी की आरडब्ल्यूए और आस्तियों की वृद्धि
(मार्च अंत तक)

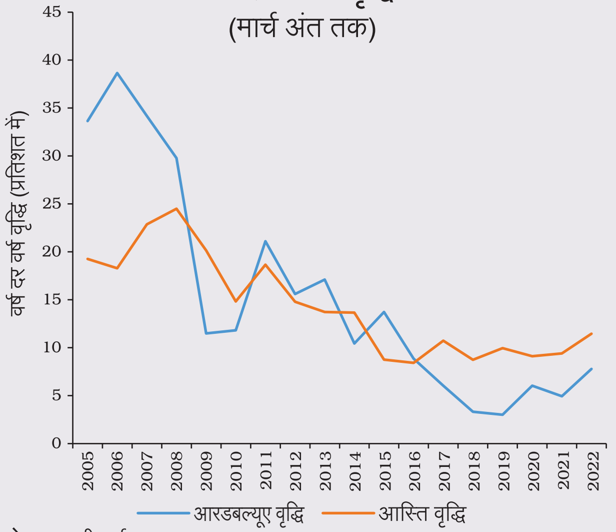

स्रोत: आरबीआई।

भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि के बावजूद, 2021-22 के दौरान इस वृद्धि ने गति बनाए रखी। 2016 के बाद से, आरडब्ल्यूए में वृद्धि समग्र आस्ति वृद्धि की तुलना में कम रही है, जो सुरक्षित आस्तियों की ओर एक कदम को दर्शाती है (चार्ट IV.15)। पूंजीगत निधियों में लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि बैंकों की टियर -1 पूंजी में वृद्धि से हुई थी, जो पूंजी बफर की मजबूती का संकेत है। सितंबर 2022 के अंत में एससीबी का सीआरएआर 16 प्रतिशत था।

IV.27 अक्तूबर 2021 में, अंतिम शृंखला के सक्रिय होने के साथ, बैंकों द्वारा बनाए जाने वाले कुल पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया, जिससे कुल न्यूनतम पूंजी आवश्यकता बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गई। मार्च 2022 के अंत में, सभी बैंकों ने इस नियामकीय न्यूनतम सीमा के साथ-साथ 8 प्रतिशत की सीईटी -1 अनुपात अपेक्षा को भी पूरा किया (चार्ट IV.16)।

IV.28 निजी आबंटन के माध्यम से बैंकों द्वारा संसाधन जुटाना, जो 2020-21 में तेज हो गया था, 2021-22 के दौरान धीमा हो गया। हालांकि 2021-22 में पीवीबी के लिए निर्गमों की संख्या तीन गुणी हो गई, लेकिन जुटाई गई कुल राशि में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 में निजी तौर पर शेयर आबंटन के माध्यम से पीवीबी द्वारा जुटाए गए अधिकांश संसाधन बॉण्ड/डिबेंचर के माध्यम से थे, जबकि 2020-21 के दौरान, यह पूरी तरह से इक्विटी जारी करने के माध्यम से था। (सारणी IV.7)।

4.2. लीवरेज और चलनिधि

IV.29 कुल एक्सपोजर के लिए टियर -1 पूंजी के अनुपात के रूप में गणना किया जाने वाला लीवरेज अनुपात (एलआर), जोखिम-भारित पूंजी आवश्यकताओं के लिए अंतिम न्यूनतम सीमा के रूप में कार्य करता है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण

चार्ट IV.16: पूंजी पर्याप्तता

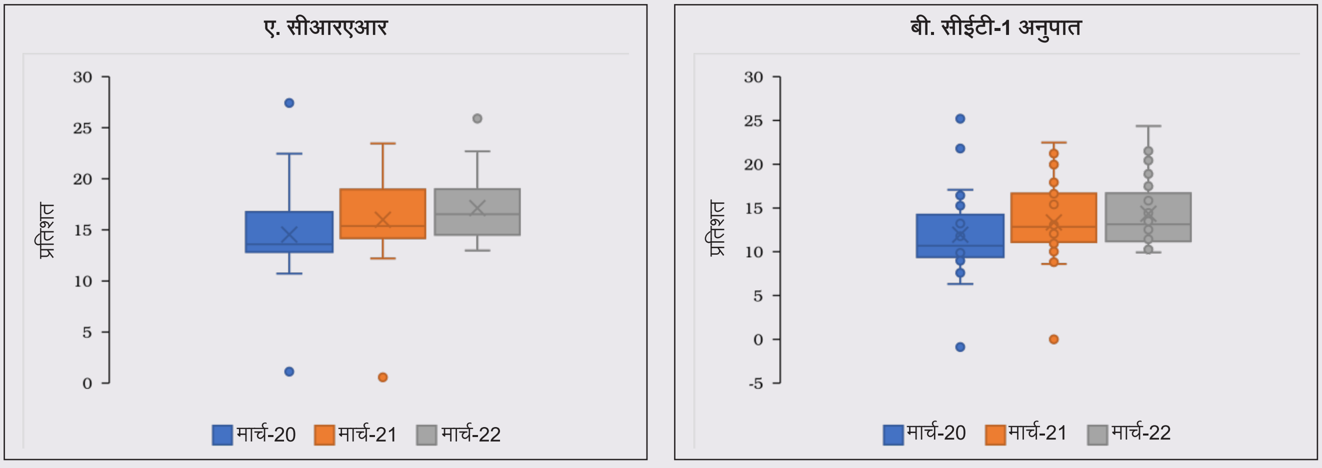

टिप्पणी : सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर आधारित।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, आरबीआई।

सारणी IV.7: निजी आबंटन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (नवंबर 2022 तक)	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
पीएसबी	20	29,573	36	58,697	29	50,719	13	27,234
पीवीबी	8	23,121	4	33,878	12	35,682	3	5,194
विदेशी बैंक	-	-	-	-	-	-	1	125

टिप्पणी: 1. इसमें कर्ज का निजी आबंटन और अर्हताप्राप्त संस्थागत आबंटन शामिल है। 2022-23 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. -: शून्य/नगण्य।
स्रोत : बीएसई, एनएसई, व्यापारी बैंक और प्राइम डेटाबेस।

घरेलू बैंकों और अन्य बैंकों के लिए इसे क्रमश: न्यूनतम 4 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता है। मार्च 2022 के अंत में, सभी बैंक समूहों ने निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया। पीवीबी और एफबी ने एलआर को आवश्यक स्तरों से बहुत ऊपर बनाए रखा।

IV.30 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में कहा गया है कि बैंकों को दबाव वाली परिस्थितियों में 30 दिनों के निवल नकदी बहिर्वाह को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को बनाए रखना चाहिए। हालांकि सभी बैंक समूहों ने मार्च 2022 के अंत में 100 प्रतिशत एलसीआर की बेसल आवश्यकता को पूरा किया, लेकिन यह अनुपात एक साल पहले की तुलना में कम था (चार्ट IV.17)।

चार्ट IV.17: लीवरेज और चलनिधि

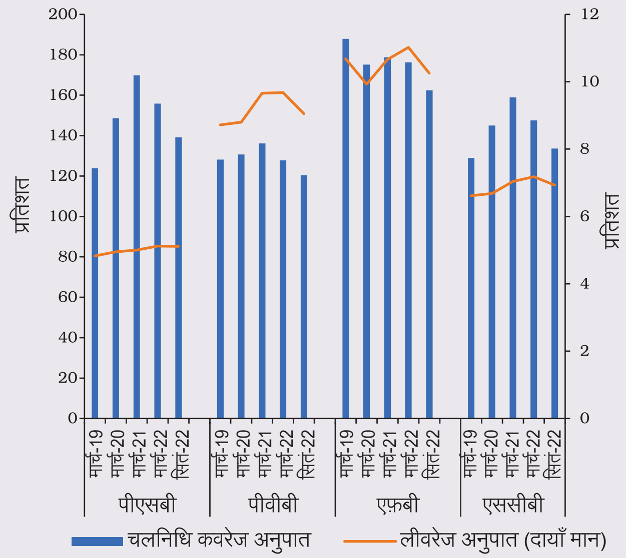

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

IV.31 निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) -- आवश्यक स्थिर वित्त पोषण के लिए उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण का अनुपात -- एक स्थायी वित्त संरचना का एक उपाय है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए एनएसएफआर का कार्यान्वयन 01 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी हो गया था। इसके साथ, बैंकों को एनएसएफआर को न्यूनतम 100 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे मार्च 2022 के अंत में सभी बैंक समूहों द्वारा पूरा किया गया था (सारणी IV.8)।

4.3. अनर्जक आस्तियां

IV.32 एनपीए, वसूली लागत को प्रभावित करने के अलावा, बढ़ते प्रावधान के माध्यम से बैंकों की लाभप्रदता, और उनकी पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एससीबी का जीएनपीए अनुपात 2017-18 के अपने सर्वाधिक स्तर से क्रमिक रूप से घटकर सितंबर 2022 के अंत में 5 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यह गिरावट निम्न हानि के साथ-साथ वसूली और बट्टे खाते में डाले

सारणी IV.8: निवल स्थिर निधीकरण अनुपात
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	उपलब्ध स्थिर निधिकरण	आवश्यक स्थिर निधिकरण	एनएसएफ़आर (प्रतिशत)
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	93,46,181	69,40,125	134.7
निजी क्षेत्र बैंक	51,12,372	39,01,260	131.0
विदेशी बैंक समूह	5,71,172	4,15,495	137.5
लघु वित्त बैंक समूह-अनुसूचित	1,39,917	1,10,157	127.0
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**1,51,69,642**	**1,13,67,038**	**133.5**

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, आरबीआई।

चार्ट IV.18: बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

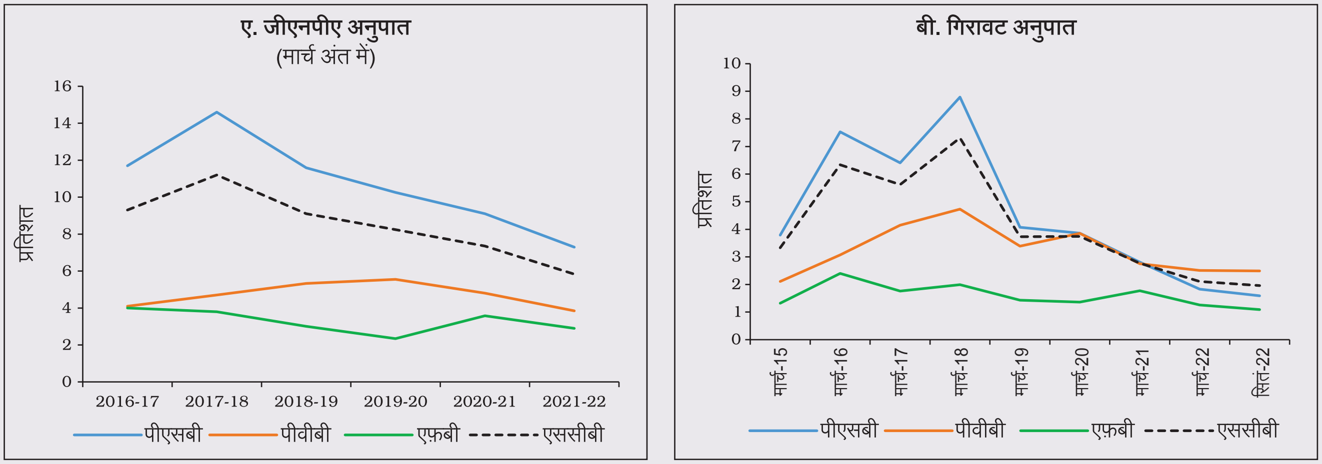

टिप्पणी: जीएनपीए अनुपात की गणना बैंकों के वार्षिक लेखे और ऑफ-साइट विवरणियों (वैश्विक परिचालन) का उपयोग करके की जाती है।
स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन)।

जाने के पश्चात बकाया जीएनपीए में कमी के कारण हुई थी (चार्ट IV.18)।

IV.33 वर्ष 2021-22 में, एनपीए में कमी मुख्य रूप से पीएसबी के मामले में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों द्वारा दिये गए योगदान के कारण था, जबकि पीवीबी के लिए आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋणों का उन्नयन प्राथमिक संवाहक था (चार्ट IV.19)।

चार्ट IV.19: जीएनपीए में कमी
(मार्च के अंत में)

स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा।

IV.34 बैंकों के वैश्विक परिचालन के लिए, सभी बैंक समूहों के लिए आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ। हाल के वर्षों में संचित उच्च प्रावधानों के साथ कम जीएनपीए ने निवल एनपीए में गिरावट में योगदान दिया (सारणी IV.9)।

IV.35 जहाँ तक बैंकों के घरेलू परिचालन का संबंध है, 2021-22 के दौरान कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों का अनुपात बढ़ गया और एफबी को छोड़कर, सभी बैंक समूहों के लिए जीएनपीए में समग्र कमी देखी गई (सारणी IV.10)।

IV.36 बड़े उधार खातों अर्थात 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले खातों में 2021-22 के कुल अग्रिमों का 47.8 प्रतिशत हिस्सा था, जो 2020-21 के 48.4 प्रतिशत से कम था। कुल एनपीए में उनकी हिस्सेदारी 2020-21 के 66.4 प्रतिशत से घटकर 63.4 प्रतिशत रह गई। विशेष उल्लेख खाता-0 (एसएमए-0) अनुपात, जो 0-30 दिनों से लंबित ऋण खातों का अनुपात है, मार्च 2022 के अंत में दोनों बैंक समूहों (पीएसबी और पीवीबी) के लिए समग्र रूप से तथा बड़े उधार खातों के दृष्टिकोण से बढ़ा, जो उधारकर्ताओं के बीच अस्थायी दबाव की ओर इशारा करता है

सारणी IV.9: अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पीएसबी	पीवीबी	एफ़बी	एसएफ़बी	सभी एससीबी
कुल एनपीए					
2020-21 के लिए अंतिम शेष	6,16,616	1,97,508	15,044	5,971	8,35,138
2021-22 के लिए प्रारंभिक शेष	6,16,616	1,97,508	15,044	5,971	8,35,138
वर्ष 2021-22 के दौरान योग	1,39,905	1,25,834	8,320	9,381	2,83,441
वर्ष 2021-22 के दौरान कमी (i+ii+iii)	2,14,347	1,42,559	9,578	8,441	3,74,926
i. वसूली	56,959	34,139	2,722	1,758	95,579
ii. उन्नयन	37,675	55,333	3,390	3,785	1,00,184
iii. बट्टे खाते में	1,19,713	53,087	3,466	2,898	1,79,163
2021-22 के लिए अंतिम शेष	5,42,174	1,80,782	13,786	6,911	7,43,653
कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में कुल एनपीए*					
2020-21	9.1	4.8	3.6	5.4	7.3
2021-22	7.3	3.8	2.9	4.9	5.8
निवल एनपीए					
2020-21 के लिए अंतिम शेष	1,96,451	55,377	3,241	2,981	2,58,050
2021-22 के लिए अंतिम शेष	1,54,745	43,733	3,023	2,725	2,04,226
निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए					
2020-21	3.1	1.4	0.8	2.7	2.4
2021-22	2.2	1.0	0.6	2.0	1.7

टिप्पणी: 1. #: इसमें विवेकपूर्ण और वास्तविक बट्टे खाते शामिल हैं।
2. *: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखों से कुल एनपीए और ऑफ-साइट विवरणियों (वैश्विक परिचालन) से कुल अग्रिम लेकर गणना की जाती है।
स्रोत: संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

(चार्ट IV.20)। एसएमए -1 और एसएमए -2, जो लंबे अवधि वाले बास्केट के लिए आसन्न दबाव का संकेत देते हैं, मार्च 2016 के अंत के बाद से सभी खाते अपने निम्नतम स्तर तक गिर गए।

IV.37 कोविड 19 की प्रतिक्रिया में, रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ दो पुनर्रचना योजनाओं की घोषणा की। अगस्त 2020 में, रिज़र्व बैंक ने समाधान ढांचा 1.0 की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित दबाव का

सारणी IV.10: बैंक समूह द्वारा ऋण आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मार्च अंत	मानक आस्तियां		उप-मानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
पीएसबी	2021	55,87,450	90.6	1,03,744	1.7	3,51,014	5.7	1,22,217	2.0
	2022	61,96,768	92.4	75,843	1.1	3,29,264	4.9	1,02,400	1.5
पीवीबी	2021	37,57,240	95.3	65,363	1.7	90,228	2.3	31,350	0.8
	2022	43,63,690	96.3	41,251	0.9	77,394	1.7	50,619	1.1
एफ़बी	2021	4,10,418	97.6	3,648	0.9	5,566	1.3	986	0.2
	2022	4,62,299	97.1	3,649	0.8	7,953	1.7	2,184	0.5
एसएफ़बी**	2021	1,05,619	94.6	4,965	4.4	841	0.8	165	0.1
	2022	1,33,093	95.0	5,039	3.6	1,908	1.4	39	0.0
सभी एससीबी	2021	98,60,726	92.7	1,77,720	1.7	4,47,648	4.2	1,54,717	1.5
	2022	1,11,55,849	94.1	1,25,782	1.1	4,16,519	3.5	1,55,243	1.3

टिप्पणी: 1. पूर्णांकित करने के कारण घटक मदों का योग कुल से भिन्न हो सकता है।
2. *: कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
3. **: अनुसूचित एसएफबी को संदर्भित करता है।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.20: बड़े उधार खातों में दबाव की तुलना में समग्र दबाव (मार्च 2022 के अंत में)

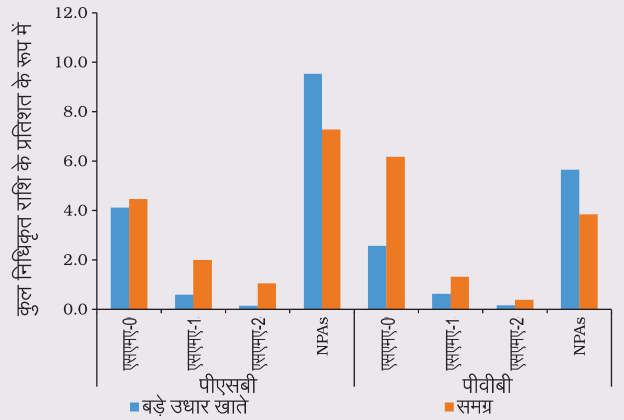

नोट: बड़े उधार खातों और समग्र खातों के अनुपात की गणना उनकी संबंधित राशि के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

स्रोत: 'बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस और ऑफ-साइट विवरणियां।

सामना करने वाले कॉरपोरेट एक्सपोजर और व्यक्तिगत ऋणों पर था। इस ढांचे को आरंभ करने के लिए 31 दिसंबर, 2020 की समय सीमा थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समाधान के लिए एक योजना पहले से ही 2019 से लागू थी। मई 2021 में घोषित और बाद में जून 2021 में संशोधित समाधान ढांचा 2.0 का उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए था, जिसे आरंभ करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2021 थी।

IV.38 इन योजनाओं के प्रभाव का आकलन पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात के माध्यम से किया जा सकता है, जो कुल सकल ऋण और अग्रिमों में आरएसए का हिस्सा है। 2020-21 के दौरान, आरएसए अनुपात सभी उधारकर्ताओं के लिए 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ा, जबकि बड़े उधारकर्ताओं के लिए तुलनात्मक वृद्धि 0.4 प्रतिशत अंक थी। इसके विपरीत, 2021-22 के दौरान, अनुपात में सभी उधारकर्ताओं के लिए 1.1 प्रतिशत अंक और बड़े उधारकर्ताओं के लिए 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई (चार्ट IV.21ए)। 2021-22 में सभी उधारकर्ताओं के आरएसए अनुपात में वृद्धि का उच्च क्रम यह संकेत देता है कि रिज़र्व बैंक के समाधान ढांचे 2.0 का उद्देश्य, अर्थात कोविड से संबंधित दबाव से निपटने में खुदरा ऋण और एमएसएमई की सहायता करना काफी हद तक सफल रहा।

IV.39 दोनों समाधान ढांचे 1.0 और 2.0 के माध्यम से पीवीबी द्वारा पुनर्रचित खातों की संख्या कई गुना, हालांकि कम आधार पर, बढ़ी। इसके विपरीत, पीएसबी ने समाधान ढांचे 1.0 के तहत कम खातों का पुनर्रचना किया था, लेकिन उन्होंने

चार्ट IV.21: पुनर्रचना

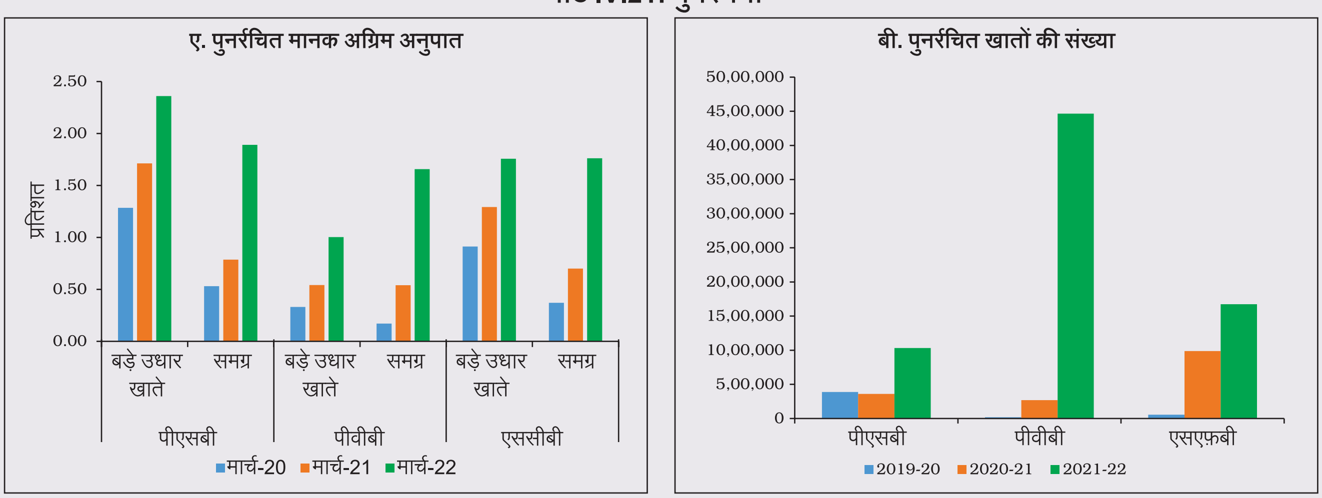

स्रोत: 'बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस और ऑफ-साइट विवरणियां।

समाधान ढांचा 2.0 (चार्ट IV.21बी) में गति पकड़ी। पीवीबी की तुलना में पीएसबी का अंतर व्यवहार बड़े उधार खातों में दबाव की विरासत को प्रतिबिंबित कर सकता है।

4.4. वसूलियाँ

IV.40 बैंक के पास कई चैनल हैं जिनके माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान किया जा सकता है। कोविड-19 के दौरान एक वर्ष के रोक के बाद नए दिवाला मामलों को स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए 2021-22 के दौरान आईबीसी के तहत स्वीकृत मामलों में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यद्यपि लोक अदालतों और सरफेसी अधिनियम के तहत संदर्भित मामलों की संख्या में क्रमशः 336 प्रतिशत और 335 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि इसमें शामिल राशि के मामले में आईबीसी तंत्र अग्रणी था (सारणी IV.11)। अंतरिम वर्षों में सुस्ती को धता बताते हुए सरफेसी और डीआरटी, आईबीसी तंत्र के तुलनीय वसूली दर दे रहे हैं। अप्रैल 2021 में एमएसएमई के लिए शुरू की गई प्री-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया अभी तक जोर नहीं पकड़ पाई है और चैनल में अब तक (सितंबर 2022 तक) केवल दो मामलों को स्वीकार किया गया है।

IV.41 आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) को दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री उनके लिए आस्ति समाधान का एक अन्य तरीका है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में एआरसी को बिक्री धीरे-धीरे कम हो गई है, और 2021-22 में, पिछले वर्ष के जीएनपीए का केवल 3.2 प्रतिशत एआरसी को बेचा गया था (चार्ट IV.22ए) । बही मूल्य की तुलना में अधिग्रहण लागत का अनुपात मामूली रूप से बढ़ा, जो बिक्री करने वाले बैंकों के लिए थोड़ी अधिक वसूली दर को दर्शाता है (चार्ट IV.22बी) ।

IV.42 हालांकि रिज़र्व बैंक बढ़ी हुई प्रावधानीकरण के माध्यम से बैंकों को अतिरिक्त प्रतिभूति रसीदें (एसआर) रखने से हतोत्साहित कर रहा है, लेकिन कुल जारी एसआर में बैंकों द्वारा लिए गए एसआर का हिस्सा 2021-22 में बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, एआरसी की हिस्सेदारी भी एक वर्ष पहले के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 18.1 प्रतिशत हो गई। एआरसी द्वारा जारी एसआर का मोचन, जो इस प्रक्रिया के माध्यम से वसूली का एक संकेतक है, वर्ष के दौरान बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल बकाया एसआर में गिरावट आई (सारणी IV.12)।

सारणी IV.11: विभिन्न चैनलों के माध्यम से एससीबी के एनपीए की वसूली

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली माध्यम	2020-21				2021-22 (P)			
	संदर्भित मामलों की संख्या	निहित राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम (4) कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में	संदर्भित मामलों की संख्या	निहित राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम (8) कॉलम (7) के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक अदालतें	19,49,249	28,084	1,119	4	85,06,648	1,19,005	2,777	2.3
डीआरटी	28,182	2,25,361	8,113	3.6	29,487	47,165	12,114	25.7
सरफेसी एक्ट	57,331	67,510	27,686	41	2,49,475	1,21,642	27,349	22.5
आईबीसी @#	536	1,35,319	27,311	20.2	885	1,99,250	47,421	23.8
कुल	**20,35,298**	**4,56,274**	**64,229**	**14**	**87,86,495**	**4,87,062**	**89,661**	**18.4**

टिप्पणी: 1. पी: अनंतिम।
2. *: निर्दिष्ट वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि के संदर्भ में जो निर्दिष्ट वर्ष के दौरान, साथ ही पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संदर्भित मामलों के विषय में हो सकता है।
3. डीआरटी: कर्ज वसूली न्यायाधिकरण।
4. @: कॉलम सं. 2 और 6 में दिये गए डेटा आईबीसी के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले हैं।
5. #: कॉलम सं. 3, 4 और 5 में दिये गए डेटा 121 मामलों और कॉलम सं. 7,8 और 9 में 143 मामलों से संबंधित हैं। जबकि प्रस्तावित योजना क्रमश: 2020-21 और 2021-22 के दौरान अनुमोदित की गई थी।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां, आरबीआई और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

चार्ट IV.22: एआरसी को दबावग्रस्त आस्ति की बिक्री

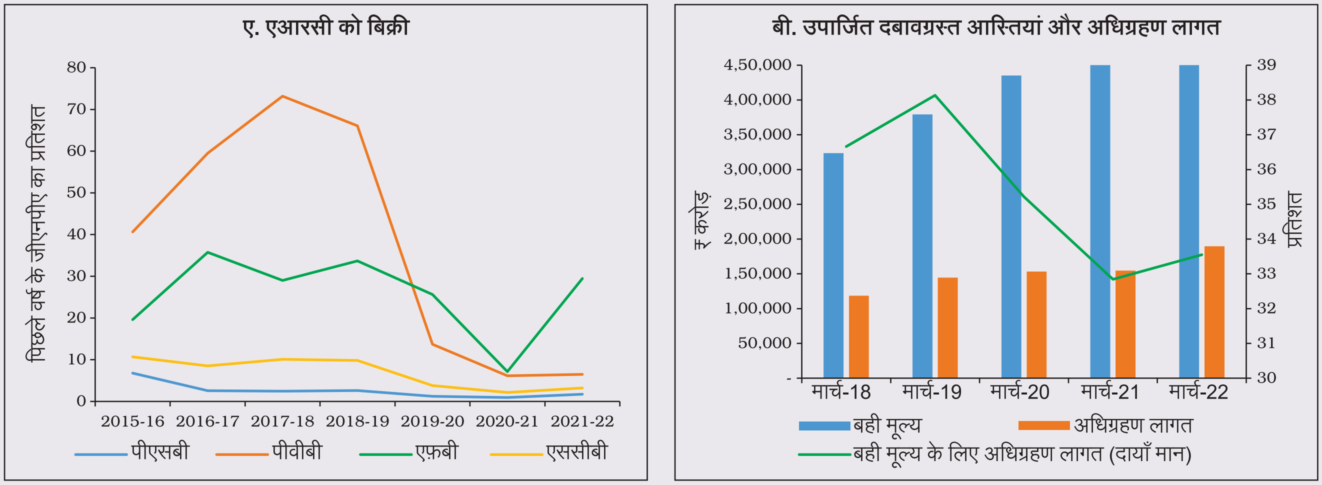

स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण और ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

4.5. बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी

IV.43 बैंकिंग धोखाधड़ी का प्रभाव वित्तीय स्थिरता पर पड़ता है; क्योंकि वे प्रणाली के संबंध में ग्राहकों के विश्वास को भी खतरे में डालने के साथ-साथ प्रतिष्ठा, परिचालन और व्यावसायिक जोखिम के स्रोत हैं। 2021-22 के दौरान, धोखाधड़ी[10] की औसत राशि में काफी कमी आई, जिसका अर्थ है कि छोटी -राशि वाले धोखाधड़ी भी अब रिपोर्ट की जा रही है (सारणी IV.13)।

सारणी IV.12: एआरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22
रिपोर्टिंग एआरसी की संख्या	28	24	28
1. उपार्जित आस्तियों का बही मूल्य	4,35,122	4,71,204	5,65,683
2. एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद	1,53,239	1,33,755	1,22,130
3. प्रतिभूति रसीदें जिनके द्वारा सदस्यता ली गई है			
(ए) बैंक	1,02,005	87,897	83,190
(बी) एससी/आरसी	30,167	23,359	22,105
(सी) एफआईआई	10,367	10,156	4,548
(डी) अन्य (योग्य संस्थागत खरीदार)	10,700	12,343	12,288
4. पूरी तरह से भुनाई गई प्रतिभूति रसीदों की राशि	18,213	23,131	23,396
5. बकाया प्रतिभूति रसीदें	1,09,168	85,298	69,219

स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

IV.44 धोखाधड़ी की घटना की तारीख के आधार पर, 2019-20 से पहले अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी सबसे बड़ी श्रेणी थी। हालांकि, इसके बाद बड़ी संख्या में धोखाधड़ी का तरीका कार्ड या इंटरनेट आधारित लेनदेन में बदल गया। इसके अतिरिक्त, नकद धोखाधड़ी भी बढ़ रही है (सारणी IV.14)।

IV.45 पीवीबी द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 2021-22 में लगातार दूसरे वर्ष पीएसबी द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों से अधिक थी। इसमें शामिल राशि के संदर्भ में, हालांकि, पीएसबी का हिस्सा 2021-22 में 66.7 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 59.4 प्रतिशत था (चार्ट IV.23)।

[10] धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि के रूप में परिभाषित किया गया है जो धोखाधड़ी की संख्या से विभाजित किया गया है।

सारणी IV.13: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(मामले संख्या में और राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2021-22 (अप्रैल-सितंबर)		2022-23 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि
अग्रिम	4,607	1,81,865	3,496	1,36,429	3,838	58,303	1,800	35,034	2006	18,746
तुलनपत्रेतर	34	2,445	23	535	21	1077	10	612	5	283
विदेशी मुद्रा लेनदेन	8	54	4	129	7	7	1	0	10	3
कार्ड/इंटरनेट	2,677	129	2,545	119	3,596	155	1532	60	2321	87
जमाराशियां	530	616	504	434	471	493	208	362	270	135
अंतर-शाखा खाते	2	0	2	0	3	2	0	0	2	0
नकद	371	63	329	39	649	93	245	51	589	81
चेक/डीडी, आदि।	201	39	163	85	201	158	107	149	73	12
समाशोधन खाते, आदि।	22	7	14	4	16	1	9	1	11	2
अन्य	250	173	278	54	300	100	157	47	119	136
कुल	**8,702**	**1,85,391**	**7,358**	**1,37,828**	**9,102**	**60,389**	**4,069**	**36,316**	**5,406**	**19,485**

टिप्पणियाँ: 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी उस वर्ष के पहले की भी हो सकती है।
4. इसमें निहित राशि रिपोर्ट के अनुसार है और नुकसान की राशि को प्रतिबिंबित नहीं करती है। वसूलियों के आधार पर होने वाला नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, ऋण खातों में निहित पूरी राशि को दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता है।

स्रोत : आरबीआई।

4.6. प्रवर्तन कार्रवाई

IV.46 2021-22 के दौरान, विनियमित संस्थाओं (आरई) पर मौद्रिक दंड लगाने के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ एक्सपोजर और आईआरएसी मानदंडों का अनुपालन न करना, धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा साइबर सुरक्षा ढांचे के दिशानिर्देशों का उल्लंघन शामिल था। वर्ष के दौरान, पीवीबी के लिए प्रति मामला औसत जुर्माना सबसे अधिक था और सहकारी बैंकों के लिए सबसे कम था (सारणी IV.15)।

सारणी IV.14: घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(मामले संख्या में और राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2019-20 से पहले		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि
अग्रिम	9,230	3,41,768	1,947	32,386	1,477	14,973	1112	6,042	181	174
तुलनपत्रेतर	66	3,860	8	423	8	31	1	26	0	0
विदेशी मुद्रा लेनदेन	3	47	8	135	4	2	9	8	5	2
कार्ड/इंटरनेट	766	55	2,717	144	2,435	124	3849	120	1372	46
जमाराशियां	508	651	495	402	387	524	328	82	57	20
अंतर-शाखा खाते	3	0	2	0	3	2	1	0	0	0
नकद	99	48	392	38	457	58	745	82	245	49
चेक/डीडी, आदि।	90	29	205	70	156	164	160	25	27	6
समाशोधन खाते, आदि।	19	7	16	2	9	3	14	2	5	0
अन्य	331	115	178	163	255	117	160	60	23	8
कुल	**11,115**	**3,46,580**	**5,968**	**33,763**	**5,191**	**15,998**	**6379**	**6,447**	**1915**	**305**

टिप्पणियाँ: 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. 'घटित होने की तिथि' पर आधारित डेटा कुछ समय के लिए बदल सकता है क्योंकि धोखाधड़ी की सूचना देर से दी जाती है लेकिन जो पहले घटित हो चुकी होती है वह जुड़ जाती है।
4. सारणी में दिया गया डेटा 2019-20 से 30 सितंबर, 2022 तक रिपोर्ट किए गए मामलों से संबंधित है।
5. निहित राशि रिपोर्ट के आधार पर है और इसमें हानि शामिल नहीं है, वसूली के आधार पर, हानि कम हो जाती है। इसके अलावा, ऋण खातों में निहित पूरी राशि को दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता है।

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.23: बैंक समूह-वार धोखाधड़ी

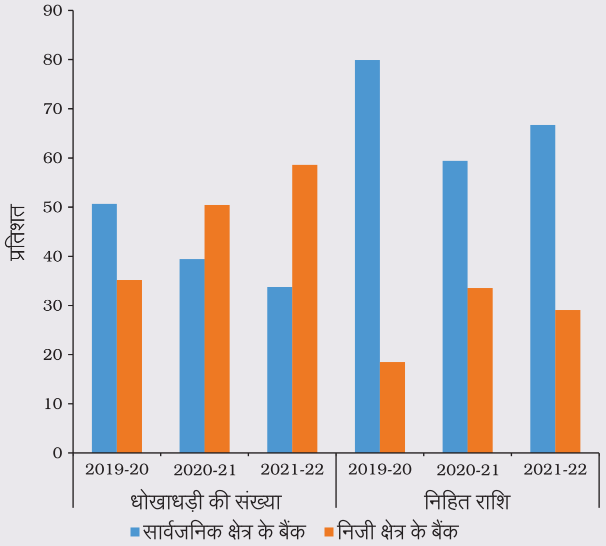

स्रोत: आरबीआई।

सारणी IV.15: प्रवर्तन कार्रवाइयाँ

विनियमित संस्थाएं	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक		अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक	
	जुर्माना लगाने के मामले	कुल जुर्माना (₹ करोड़)	जुर्माना लगाने के मामले	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4	9.50	13	17.55
निजी क्षेत्र के बैंक	3	5.92	16	29.39
सहकारी बैंक	43	3.89	145	12.10
विदेशी बैंक	3	8.00	4	4.25
भुगतान बैंक	1	1.00	-	-
लघु वित्त बैंक	-	-	1	1.00
एनबीएफसी	7	3.05	10	1.03
कुल	**61**	**31.36**	**189**	**65.32**

स्रोत: आरबीआई।

5. क्षेत्रवार बैंक ऋण : वितरण तथा एनपीए

IV.47 वर्ष 2021-22 के दौरान सेवाओं तथा खुदरा ऋणों, विशेष रूप से आवास ऋणों के कारण ऋण संवृद्धि बढ़ गई । पिछले वर्ष में हुए संकुचन के बाद से सेवा क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार आया । यह सुधार व्यापक आधार वाला था जिसमें वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ-साथ संपर्क-सघन घटक सम्मिलित थे (सारणी IV.16) ।

सारणी IV.16: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय विनियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	अंत में बकाया			प्रतिशत भिन्नता (व-द-व)		
		मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	**कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ**	**12,39,575**	**13,84,815**	**15,16,303**	**1.8**	**11.7**	**9.5**
2	**उद्योग,** *जिनमें से*	**32,52,801**	**32,53,636**	**35,08,744**	**-1.2**	**0.0**	**7.8**
	2.1 सूक्ष्म और लघु उद्योग	4,37,658	4,72,529	6,14,037	-0.5	8.0	29.9
	2.2 मध्यम	1,12,367	1,87,599	2,63,959	-9.3	67.0	40.7
	2.3 बड़ा	26,11,377	24,76,702	24,88,228	0.0	-5.2	0.5
3	**सेवाएं,** *जिनमें से*	**27,54,823**	**27,45,324**	**31,48,321**	**5.9**	**-0.3**	**14.7**
	3.1 व्यापार	6,28,142	7,14,210	7,76,737	8.8	13.7	8.8
	3.2 वाणिज्यिक अचल आस्तियां	2,66,357	2,52,696	2,90,623	9.6	-5.1	15.0
	3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	60,039	62,722	69,846	6.8	4.5	11.4
	3.4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	24,404	23,742	24,993	9.8	-2.7	5.3
	3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	7,36,447	7,98,241	9,27,520	17.4	8.4	16.2
4	**खुदरा ऋण,** *जिनमें से*	**26,59,249**	**29,86,457**	**33,94,028**	**15.4**	**12.3**	**13.6**
	4.1 आवास ऋण	13,96,444	15,61,913	17,54,298	15.9	11.8	12.3
	4.2 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	11,154	21,569	37,349	21.3	93.4	73.2
	4.3 क्रेडिट कार्ड प्राप्य	1,32,076	1,38,560	1,63,626	18.6	4.9	18.1
	4.4 ऑटो ऋण	2,89,366	3,29,522	3,79,139	7.3	13.9	15.1
	4.5 शिक्षा ऋण	79,056	78,823	84,677	3.7	-0.3	7.4
	4.6 सावधि जमा के एवज में अग्रिम (एफसीएनआर (बी), आदि सहित)	80,753	74,013	78,965	4.7	-8.3	6.7
	4.7 व्यक्तियों को शेयरों, बांडों आदि की जमानत पर अग्रिम	5,619	5,619	16,259	-39.8	0.0	189.4
	4.8 अन्य खुदरा ऋण	6,64,781	7,76,437	8,79,716	21.5	16.8	13.3
5	**अन्य गैर-खाद्य ऋण**	**1,38,439**	**2,09,869**	**2,27,268**	**126.9**	**51.6**	**8.3**
6	**गैर-खाद्य ऋण (1- 5)**	**1,00,44,887**	**1,05,80,100**	**1,17,94,665**	**6.0**	**5.3**	**11.5**
7	**सकल बैंक ऋण**	**1,00,98,420**	**1,06,40,808**	**1,18,53,392**	**6.0**	**5.4**	**11.4**

टिप्पणियाँ: 1. बैंकों के कवरेज में अंतर के कारण सारणी में दिए गए आंकड़े आरबीआई द्वारा हर महीने 'बैंक क्रेडिट के क्षेत्रीय विनियोजन' में जारी आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते हैं।
2. प्रतिशत बदलाव मार्च से मार्च के लिए हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, (घरेलू परिचालन) आरबीआई।

चार्ट IV.24: खुदरा ऋण

ए. पीएसबी के लिए कुल ऋणों में खुदरा ऋणों का हिस्सा

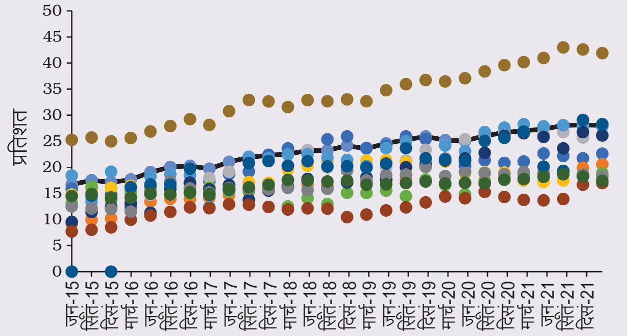

टिप्पणी: 1. प्रत्येक बिंदु उक्त तिमाही के अंत में कुल ऋणों में पीवीबी के खुदरा ऋणों के हिस्से को दर्शाता है।
2. रेखा पीएसबी के लिए कुल ऋण में खुदरा ऋण के हिस्से को दर्शाती है।

बी. पीवीबी के लिए कुल ऋणों में खुदरा ऋणों का हिस्सा

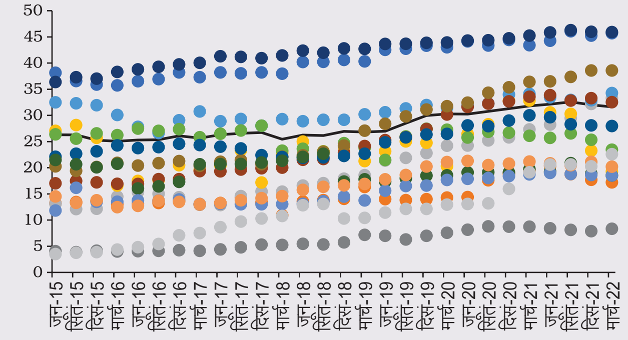

टिप्पणी: 1. प्रत्येक बिंदु उक्त तिमाही के अंत में कुल ऋणों में पीवीबी के खुदरा ऋणों के हिस्से को दर्शाता है।
2. रेखा पीएसबी के लिए कुल ऋण में खुदरा ऋण के हिस्से को दर्शाती है।

स्रोत: ऑसमॉस।

IV.48 उद्योग में ऋण 8 वर्षों में सबसे उच्च दर बढ़ गया। वृद्धिशील संदर्भ में, वर्ष के दौरान ऋण का 21 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र को गया, जबकि 2020-21 में यह 0.2 प्रतिशत था।

5.1 खुदरा ऋण

IV.49 हाल के वर्षों में, यह प्रतीत होता है कि भारतीय बैंकों ने 'एक समान व्यवहार' दिखाते हुए उधार देने में प्राथमिकता को औद्योगिक क्षेत्र से हटाकर खुदरा ऋणों के लिए कर दी है (चार्ट IV.24 ए तथा बी)। यह गिरावट सभी बैंकों में दृष्टिगोचर हो रही थी।

IV.50 अनुभवजन्य प्रमाण यह दर्शाते हैं कि खुदरा ऋणों में संकेन्द्रण का निर्माण प्रणालीगत जोखिम का कारण बन सकता है। रिज़र्व बैंक किसी भी प्रणालीगत जोखिम को अपने नीतिगत साधनों के माध्यम से संभालने के लिए सुसज्जित है (बॉक्स IV.3)।

बॉक्स IV.3: बैंक समूहीकरण और प्रणालीगत जोखिम

" एक समूह के रूप में प्रणालीगत " एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है, जिसमें ऐसी संस्थाएं जो व्यक्तिगत आधार पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, किन्तु वे बाजार के नेतृत्वकर्ता के समान व्यवहार करती हैं और इसके परिणामस्वरूप, सामान्य जोखिमों के संपर्क में आती हैं। यह बैंकों के प्रदर्शन के उच्च सह-गति के माध्यम से प्रणालीगत जोखिम को बढ़ा सकता है, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से अपने स्वचलित बैंक जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

सशर्त जोखिम मूल्य (सीओवीएआर) को प्रणालीगत जोखिम के लिए प्रतिनिधि के रूप में अनुमान लगाने के लिए, (एड्रियन और ब्रूनर्मियर, 2016), 2015-2022[11] के बीच सभी सूचीबद्ध बैंकों (15 पीवीबी और 12 पीएसबी) के दैनिक शेयर बाजार विवरणी का उपयोग किया गया था। तिमाही सीओवीएआर मापांक कुछ बैंक-विशिष्ट और समष्टि-आर्थिक नियंत्रण चरों के साथ खुदरा क्षेत्र के ऋणों के हिस्से के विलंबित मानों पर वापस आ गया था (हिराकाटा एवं अन्य, 2017)। परिणाम प्रणालीगत जोखिम पर खुदरा क्षेत्र के ऋणों में बैंक समूहीकरण के सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव का संकेत देते हैं (सारणी 1)। पीएसबी और पीवीबी द्वारा उत्पन्न जोखिम के बीच कोई अंतर नहीं है क्योंकि बैंक समूह डमी का गुणांक 0 है। इसके अतिरिक्त, दबावग्रस्त आस्तियों और बैंक के आकार में वृद्धि के साथ प्रणालीगत जोखिम बढ़ता है,

(जारी...)

[11] विशिष्ट समय अवधि को बैंक-वार क्षेत्रीय ऋण के लिए आंकड़े उपलब्धता के अनुसार चुना गया था। साथ ही, इस अवधि के दौरान विलय एवं अधिग्रहण के लिए आंकड़े को समायोजित किया गया है।

सारणी 1: प्रणालीगत जोखिम पर खुदरा क्षेत्र के ऋणों में समूहीकरण का प्रभाव

	Δसीओवीएआर (95)	Δसीओवीएआर (99)	Δसीओवीएआर (90)
खुदरा क्षेत्र के ऋणों का हिस्सा	.0052***	.0037	.0034**
	(.0019)	(.0031)	(.0014)
कुल आस्तियों का लॉग	.1592***	.295***	.1087***
	(.0352)	(.0573)	(.0256)
कुल आस्तियों में जमाराशियां	.0035	.0026	.0005
	(.0031)	(.0051)	(.0023)
दबावग्रस्त अग्रिम	.0473***	.0415	.0265**
	(.0173)	(.0281)	(.0125)
कुल ऋणों के लिए एनपीए प्रावधान	-.0079**	-.0022	-.0038
	(.0035)	(.0057)	(.0025)
नाममात्र जीडीपी वृद्धि	-.0117***	-.0184***	-.0083***
	(.0012)	(.0019)	(.0009)
स्थिर	-1.197**	-2.8125***	-.9427***
	(.4707)	(.7674)	(.3423)
बैंक समूह डमी	.0000	.0000	.0000
अवलोकन	756	756	756
आर-वर्गित	.2046	.1871	.1848

टिप्पणी: 1. *** पी<.01, ** पी<.05, *पी<.1
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
3. सभी सहचर को 95वें प्रतिशतक पर विंसोराइज किया गया है।
स्रोत: लेखक की गणना।

जबकि उच्च एनपीए प्रावधान अनुपात और उच्च जीडीपी वृद्धि कम प्रणालीगत जोखिम से जुड़े हैं। परिणाम सीओवीएआर के विभिन्न उपायों के अनुरूप हैं।

संदर्भ :

Adrian, Tobias, and Markus K. Brunnermeier. "CoVaR." The American Economic Review, vol. 106, no. 7, 2016, pp. 1705–41. JSTOR, available at http://www.jstor.org/stable/43861110. Accessed 28 Nov. 2022.

Hirakata, Naohisa, Yosuke Kido and Jie Liang Thum, "Empirical Evidence on "Systemic as a Herd" (2017): The Case of Japanese Regional Banks", Bank of Japan Working Paper Series, No.17-E-1, 2017, available at https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2017/data/wp17e01.pdf.

IV.51 2021-22 की पहली छमाही के दौरान, कम और घटते जीएनपीए अनुपात (चार्ट IV.25बी) के बावजूद पीवीबी (चार्ट IV.25ए) के नेतृत्व में आवास क्षेत्र को ऋण में वृद्धि हुई।

IV.52 इस क्षेत्र में उच्च एनपीए की पृष्ठभूमि पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के शिक्षा ऋण में मार्च 2016 से मंदी आई है। कुल खुदरा ऋण में शिक्षा ऋण की हिस्सेदारी कम हो गई है। वर्ष 2021-22 में, इस क्षेत्र को जारी ऋण में सुधार आया है, हालांकि इसका आधार कम था। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में, ऋण संवृद्धि घटते जा रहे जीएनपीए अनुपात को दर्शाती है (चार्ट IV.26)।

5.2 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

IV.53 कोविड महामारी के बाद की अवधि में, उद्योग क्षेत्र में एमएसएमई को ऋण संवृद्धि बड़े उद्योगों में हुई ऋण संवृद्धि की तुलना में भी साल-दर–साल आधार पर स्पष्ट रूप से उच्चतर थी

चार्ट IV.25: आवास ऋण

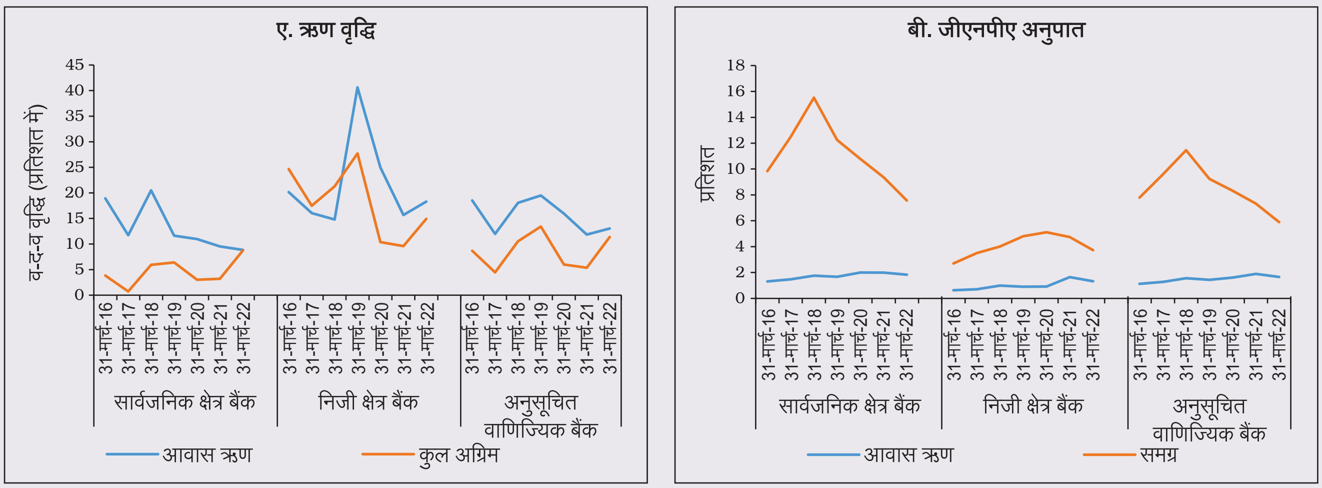

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, (घरेलू परिचालन) आरबीआई।

चार्ट IV.26: शिक्षा ऋण

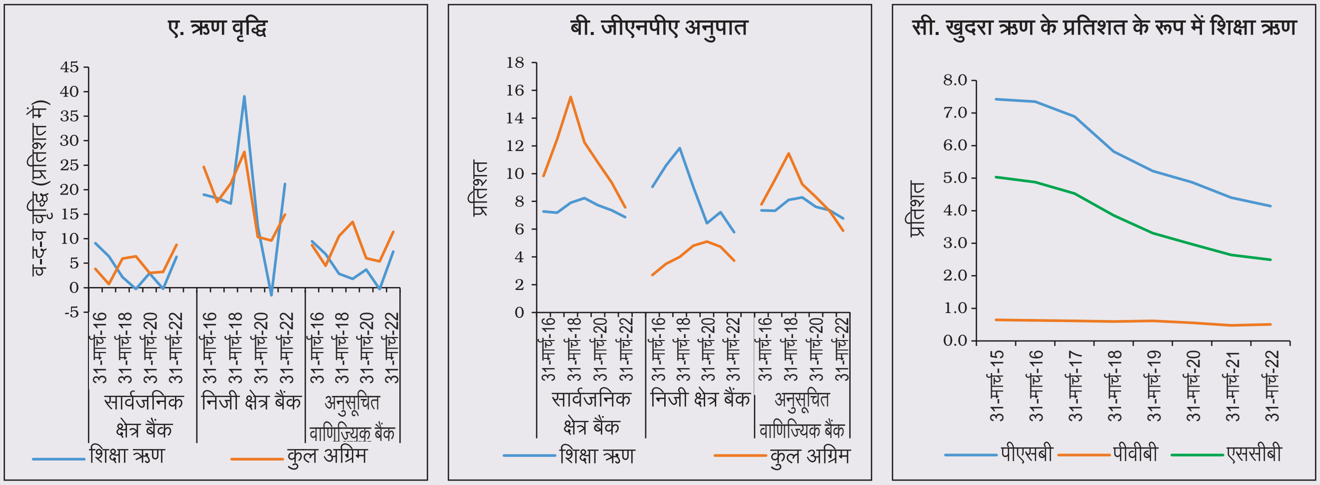

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, (घरेलू परिचालन) आरबीआई।

(चार्ट IV.27 ए) । आपात कालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) द्वारा दिये गए प्रोत्साहनों, साथ ही न्यूनतर जीएनपीए अनुपात, एमएसएमई को ऋण में वृद्धि करने में सहायक रहे हैं (चार्ट IV.27 बी) । इसके साथ ही, जुलाई 2021 से एमएसएमई श्रेणी में थोक तथा खुदरा व्यापार शामिल होने से एमएसएमई क्षेत्र को जारी समग्र ऋण में वृद्धि हुई ।

IV.54 वर्ष 2018-19 से, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई को दी गई ऋण संवृद्धि सार्वजनिक बैंकों द्वारा दी गई संवृद्धि से बहुत अधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2021-22 में भी बकाया ऋण में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी है (सारणी IV.17) ।

5.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

IV.55 वर्ष 2021-22 के दौरान, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के बकाया उधार में 12.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सभी बैंक समूह अपने समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए हैं, जबकि विदेशी बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों ने भी सभी

चार्ट IV.27: एमएसएमई बनाम बड़े उद्योग

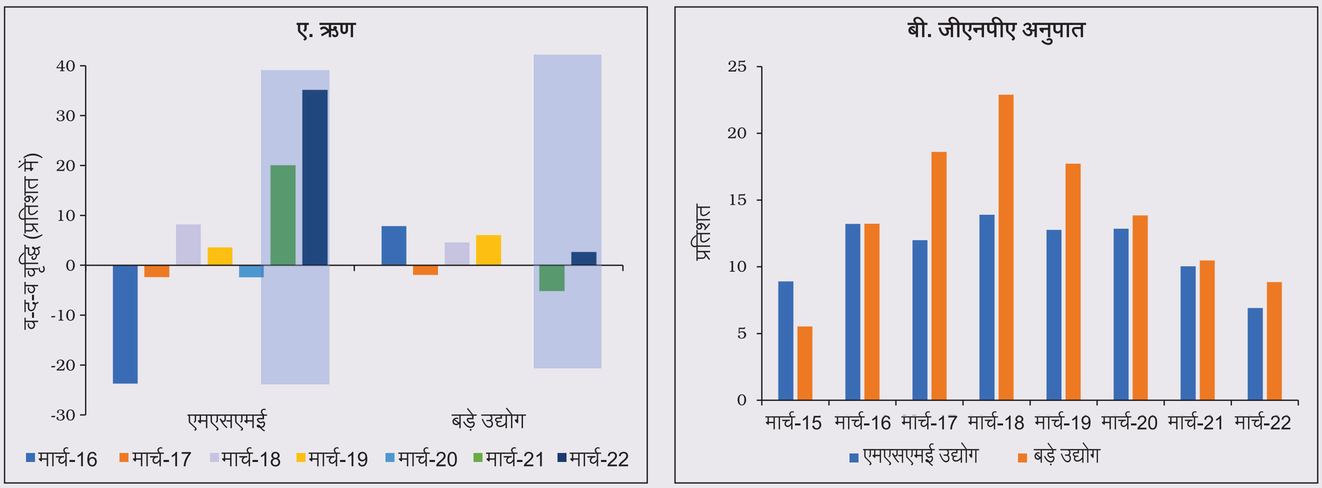

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, (घरेलू परिचालन) आरबीआई।

सारणी IV.17: एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मदें	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
पीएसबी	खातों की संख्या	112.97	110.82	150.77	149.70
		(1.76)	(-1.90)	(36.05)	(-0.71)
	बकाया राशि	8,80,032.90	8,93,314.83	9,08,659.06	9,55,860.38
		(1.79)	(1.51)	(1.72)	(5.19)
पीवीबी	खातों की संख्या	205.31	270.62	266.81	112.86
		(38.42)	(31.81)	(-1.41)	(-57.70)
	बकाया राशि	5,63,678.47	6,46,988.27	7,92,041.95	9,69,844.22
		(37.23)	(14.78)	(22.42)	(22.45)
एफ़बी	खातों की संख्या	2.40	2.74	2.60	2.11
		(9.14)	(14.17)	(-5.11)	(-18.84)
	बकाया राशि	66,939.14	73,279.06	83,223.79	85,352.38
		(36.94)	(9.47)	(13.57)	(2.56)
सभी एससीबी	खातों की संख्या	320.68	384.18	420.19	264.67
		(22.61)	(19.80)	(9.37)	(-37.01)
	बकाया राशि	15,10,650.52	16,13,582.17	17,83,924.80	20,11,056.98
		(14.08)	(6.81)	(10.56)	(12.73)

टिप्पणियाँ: 1. *- खातों की संख्या में कमी आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित नई एमएसएमई परिभाषा के तहत उद्यम पोर्टल पर नई अनिवार्य पंजीकरण आवश्यकता को दर्शाती है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) दर दर्शाते हैं।

स्रोत: वित्तीय समावेश और विकास विभाग, आरबीआई।

क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में चूक गए। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंकों ने केवल सूक्ष्म उद्यमों के लिए अपने लक्ष्य पूरे किये (सारणी IV.18)। 2020-21 में केवल 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने के बाद, परिचालित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत बकाया राशि 2021-22 के

सारणी IV.18: बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

(31 मार्च 2022 तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य/उप-लक्ष्य (एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत)	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		विदेशी बैंक^		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	**40/75***	**2649179.95**	**42.90**	**1685805.56**	**43.71**	**208106.50**	**42.65**	**73505.52**	**85.08**	**4616597.54**	**43.52**
जिसमें से											
सकल कृषि	18.00	1182377.52	19.15	622339.14	16.14	48876.88	19.27	21361.96	24.73	1874955.50	18.07
छोटे और सीमांत किसान	9.00	648227.14	10.50	286829.08	7.44	26336.73	10.38	17274.46	20.00	978667.40	9.43
गैर-सहकारी एकल किसान#	12.73	924640.55	14.97	415711.15	10.78	33116.26	13.05	27619.46	31.97	1401087.42	13.51
सूक्ष्म उद्यम	7.50	442596.73	7.17	318688.90	8.26	20524.93	8.09	23813.65	27.56	805624.21	7.77
कमजोर वर्ग	11.00	827895.58	13.41	386742.30	10.03	30411.53	11.99	38345.20	44.38	1283394.62	12.37

टिप्पणियाँ: 1. बकाया राशि और उपलब्धि प्रतिशत वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए बैंकों की औसत उपलब्धि पर आधारित है।

2. *: लघु वित्त बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य 75 प्रतिशत था।

3. #: गैर-सहकारी किसानों के लिए लक्ष्य पिछले तीन वर्षों की उपलब्धि के प्रणाली-व्यापी औसत पर आधारित है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागू प्रणाली व्यापी औसत आंकड़ा 12.73 प्रतिशत था।

4. ^: 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए, केवल 40 प्रतिशत का कुल पीएसएल लक्ष्य लागू है।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

चार्ट IV.28: पीएसएलसी की व्यापारिक मात्रा

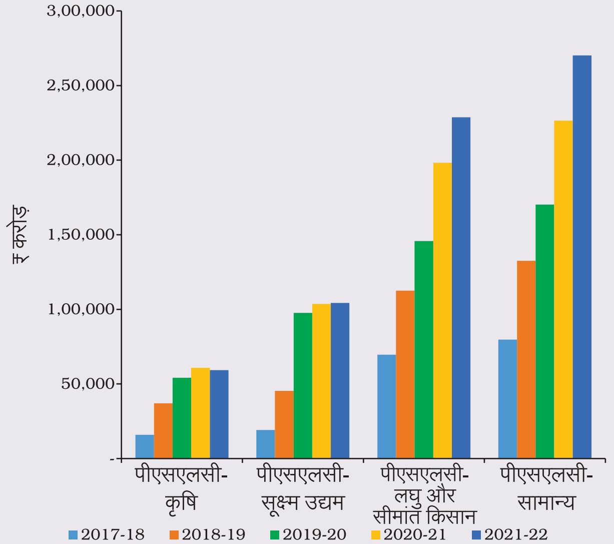

स्रोत: आरबीआई।

दौरान 24.5 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र – विशेष रूप से कर्नाटक का योगदान प्रमुख रहा (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

IV.56 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) की कुल कारोबार मात्रा में 12.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2021-22 में 6,62,389 करोड़ रुपये थी। चार पीएसएलसी श्रेणियों में, पीएसएलसी-सामान्य और पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान (एसएफ / एमएफ) में सबसे अधिक व्यापार देखा गया। (चार्ट IV.28)।

IV.57 2021-22 में पीएसएलसी-ए को छोड़कर पीएसएलसी की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत प्रीमियम (डब्ल्यूएपी) में वृद्धि हुई, जिसमें पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ का प्रीमियम सबसे अधिक था, (सारणी IV.19)।

IV.58 यद्यपि वर्ष 2020-21 में कुल ऋणों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों की हिस्सेदारी में 35.3 प्रतिशत से वर्ष 2021-22 में 35.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, कुल

सारणी IV.19: पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम

(प्रतिशत)

पीएसएलसी श्रेणी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 (अप्रै-सितं)	2022-23 (अप्रै-सितं)
पीएसएलसी-कृषि	0.79	1.17	1.55	1.37	2.00	0.88
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम	0.57	0.44	0.88	0.95	2.03	0.60
पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान	1.15	1.58	1.74	2.01	2.38	1.97
पीएसएलसी-सामान्य	0.31	0.35	0.46	0.6	0.85	0.22

स्रोत: आरबीआई।

जीएनपीए में उनकी हिस्सेदारी में कृषि क्षेत्र में ऋण न चुकाने के कारण 40.4 प्रतिशत से 43.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि, लघु वित्त बैंक अपने 76 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्रदान करते हैं, जो इस पोर्टफोलियो के एनपीए का 88 प्रतिशत है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कारण से असमान रूप से एनपीए की हिस्सेदारी कम हुई है (सारणी IV.20)।

5.4. *संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण*

IV.59 मार्च 2022 के अंत में संवेदनशील क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये ऋण में 95 प्रतिशत हिस्सेदारी स्थावर सम्पदा क्षेत्र की थी। कोविड अवधि के दौरान, मंदी के बाद जैसे ही स्थावर सम्पदा बाजार गतिविधि ने गति पकड़ी, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस क्षेत्र के लिए ऋण दिये जाने से इसमें वृद्धि होने लगी (चार्ट IV.29 ए)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी बाजार को प्रदत्त ऋण में वर्ष 2017-18 से गिरावट रही किन्तु इस वर्ष के दौरान इसमें वृद्धि हुई, जो आंशिक रूप से वृद्धिशील इक्विटी बाजार को दर्शाता है (चार्ट IV.29 बी तथा परिशिष्ट सारणी IV.8)।

सारणी IV.20: बैंकों के क्षेत्र-वार जीएनपीए
(मार्च अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	प्राथमिकता क्षेत्र		*जिनमें*						गैर-प्राथमिकता क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		लघु और सूक्ष्म उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
पीएसबी												
2021	2,57,858	44.69	1,14,911	19.92	1,01,786	17.64	41,161	7.13	3,19,116	55.31	5,76,974	100.00
2022	2,43,283	47.94	1,10,649	21.80	96,231	18.96	36,403	7.17	2,64,225	52.06	5,07,508	100.00
पीवीबी												
2021	50,557	27.04	18,900	10.11	23,473	12.56	8,184	4.38	1,36,384	72.96	1,86,941	100.00
2022	48,588	28.71	20,863	12.33	17,799	10.52	9,926	5.86	1,20,676	71.29	1,69,264	100.00
एफ़बी												
2021	1,802	17.67	329	3.23	1,194	11.70	279	2.74	8,397	82.33	10,199	100.00
2022	2,555	18.53	481	3.49	1,638	11.88	436	3.16	11,231	81.47	13,786	100.00
एसएफ़बी												
2021	4,974	83.31	1,510	25.28	2,049	34.32	1,415	23.70	996	16.69	5,971	100.00
2022	6,111	87.48	1,999	28.62	2,024	28.98	2,087	29.88	874	12.52	6,985	100.00
सभी एससीबी												
2021	3,15,192	40.40	1,35,650	17.39	1,28,502	16.47	51,039	6.54	4,64,893	59.60	7,80,085	100.00
2022	3,00,537	43.09	1,33,993	19.21	1,17,692	16.87	48,852	7.00	3,97,006	56.91	6,97,543	100.00

टिप्पणियाँ: 1. प्रतिशत: कुल एनपीए का प्रतिशत।
2. पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल योग से भिन्न हो।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

5.5 गैर-जमानती ऋण/उधार

IV.60 गैर-जमानती ऋण – अर्थात बिना संपार्श्विक का ऋण – बैंकों के लिए उच्चतर ऋण जोखिम पैदा करता है, जिसके लिए बड़े प्रावधान तथा जोखिम भार होते हैं। वर्ष 2015 से कुल ऋण में गैर-जमानती ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इस तरह के ऋणों से बैंकों को

चार्ट IV.29: संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर

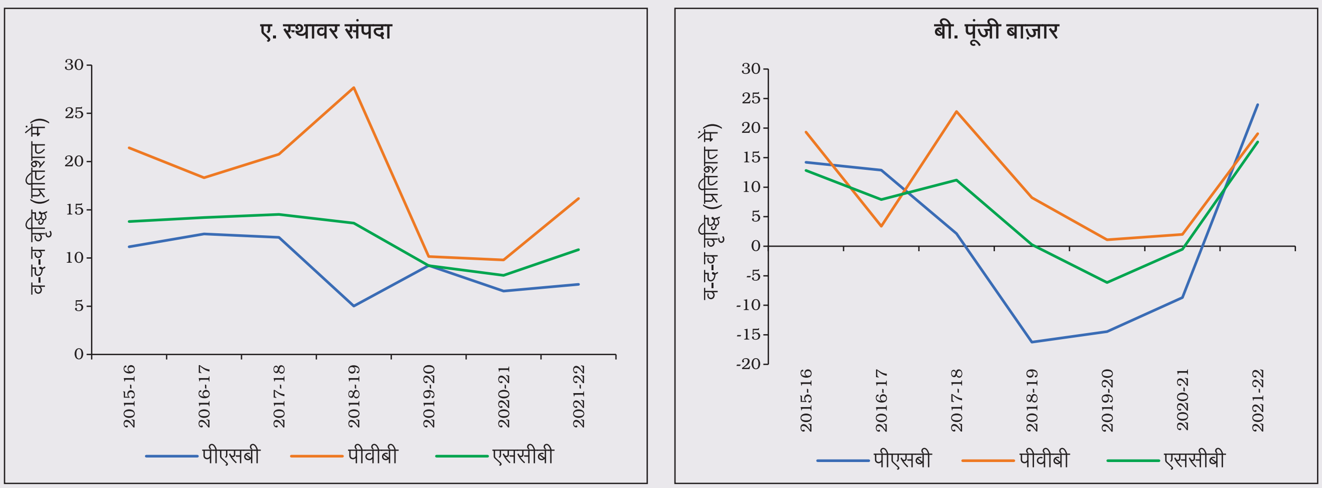

स्रोत: संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.30: गैर-ज़मानती अग्रिमों का हिस्सा

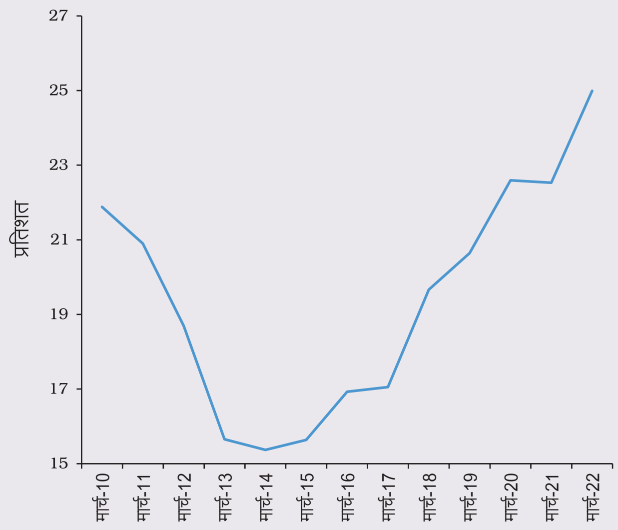

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

उच्चतर ब्याज आय अर्जन होता है (चार्ट IV.30)

6. वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व का स्वरूप [12]

IV.61 पीएसबी और पीवीबी के स्वामित्व का स्वरूप को उनके परिचालन को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण विशिष्ट कारक के रूप में प्रलेखित किया गया है (चव्हाण और गम्बाकोर्टा, 2016)[13] । पीवीबी के पास अपने सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अधिक विविध स्वामित्व है (चार्ट IV.31) ।

IV.62 बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नैशनल बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नई इक्विटी जारी करने के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता कम हो गई (चार्ट IV.32) । स्थानीय क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक और , निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अनिवासी शेयरधारिता 74 प्रतिशत की सीमाओं के भीतर थी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 20 प्रतिशत थी । (परिशिष्ट सारणी IV.9)

चार्ट IV.31: बैंक समूह-वार स्वामित्व स्वरूप
(मार्च 2022 के अंत में)

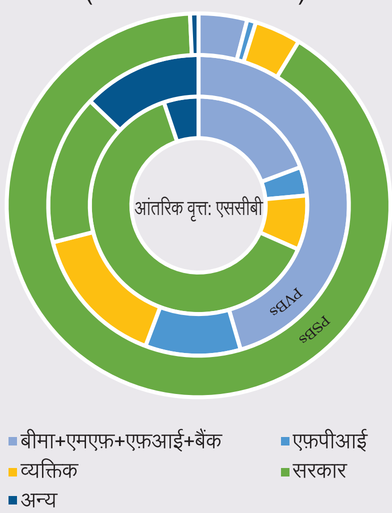

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट IV.32: पीएसबी में सरकार की हिस्सेदारी

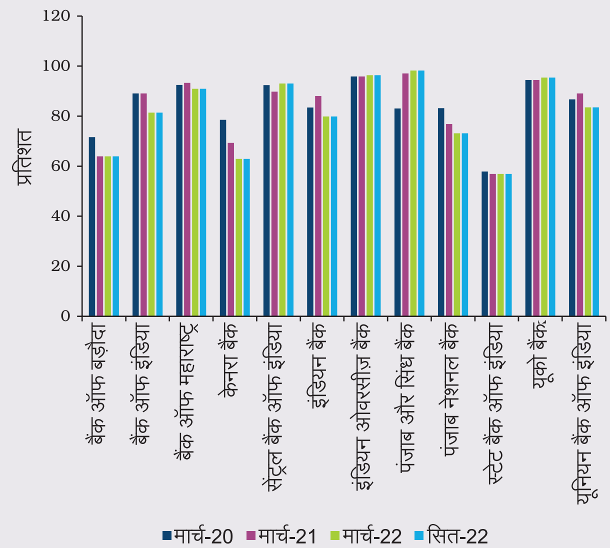

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

[12] स्रोत: शेयरधारिता का आंकड़ा 31 मार्च, 2022 तक एनएसई की वेबसाइट से प्राप्त किया गया है।

[13] चव्हाण, पल्लवी और गम्बाकोर्टा, लियोनार्डो (2016)। बैंक उधार और ऋण की गुणवत्ता: भारत का मामला। बीआईएस वर्किंग पेपर।

7. कॉरपोरेट अभिशासन

IV.63 कॉरपोरेट अभिशासन में, विशेष रूप से बड़े वित्तीय संस्थानों में, विफलताएँ तथा कमजोरियाँ एक महत्वपूर्ण कारक थे जिनके फलस्वरूप वैश्विक वित्तीय संकट आया। जोखिमों तथा दीर्घावधि परिणामों की पर्याप्त रूप से पहचान किए बिना अल्पावधि लाभ बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को अक्सर फायदा पहुंचाया गया। क्षतिपूर्ति, इस प्रकार विनियामकीय सुधारों के केंद्र में रहा है।

7.1 कार्यकारी क्षतिपूर्ति

IV.64 मुआवजे के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों[14] में कुल वेतन का लक्ष्य परिवर्तनीय वेतन (वीपी) घटक 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच और लक्ष्य वीपी का नकद घटक 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत [15] के बीच होना आवश्यक है। संयोग से, पीवीबी के लिए वास्तविक वीपी [16] मार्च 2020 के अंत में कुल पारिश्रमिक (टीआर) के 16 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 31 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, एसएफबी के लिए, यह इसी अवधि के दौरान लगभग 25 प्रतिशत पर स्थिर रहा है (चार्ट IV)। पीवीबी के लिए, वीपी के नकद घटक का हिस्सा मार्च 2020 के अंत में 31 प्रतिशत से घटकर मार्च 2021 के अंत में 22 प्रतिशत और एसएफबी के लिए इसी अवधि के दौरान 65 प्रतिशत से घटकर 59 प्रतिशत हो गया। दिशानिर्देशों में यह भी आवश्यक है कि कुल परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 60 प्रतिशत अनिवार्य रूप से स्थगन व्यवस्था के तहत होना चाहिए। इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप, एमडी और सीईओ के प्रदर्शन से जुड़े वेतन का स्थगित घटक पीवीबी के लिए 41 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत और एसएफबी के लिए 22 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया।

चार्ट IV.33: कुल पारिश्रमिक में परिवर्ती वेतन का हिस्सा

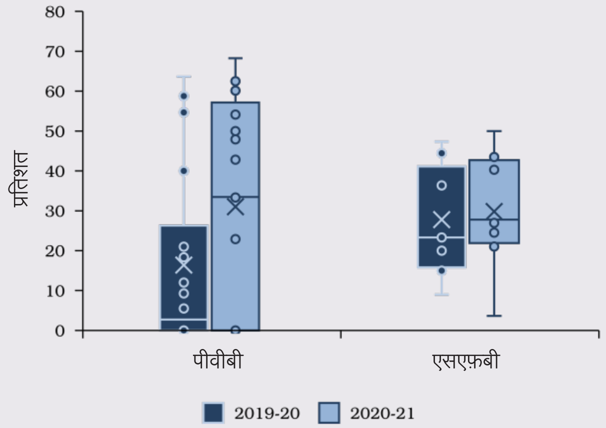

टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट के बॉक्स कुल पारिश्रमिक में परिवर्ती वेतन के अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का संकेत हैं। रंगीन बॉक्स पहले विभाजक और तीसरे विभाजक के बीच की दूरी को दर्शाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दर्शाती है जबकि 'एक्स' माध्य दर्शाता है।
स्रोत : आरबीआई।

IV.65 औसत कर्मचारी वेतन की तुलना में बैंक के एमडी और सीईओ को दिया जाने वाला पारिश्रमिक बैंक समूहों में भिन्न होता है। मार्च 2021 के अंत में, पीवीबी के लिए, औसतन, सीईओ ने औसत कर्मचारी पारिश्रमिक का 73 गुना अर्जित किया, जबकि एसएफबी में, सीईओ ने औसत कर्मचारी से 76 गुना अर्जित किया। यह किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बहुत अधिक है; जबकि औसतन, सीईओ ने औसत कर्मचारी पारिश्रमिक से 2.2 गुना अधिक आय अर्जित की है (चार्ट IV.34)।

7.2 बोर्डों का गठन

IV.66 निष्पक्ष निर्णय लेने तथा अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। कॉरपोरेट अभिशासन पर 26 अप्रैल, 2021[17] को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनिवार्य है कि बोर्ड की बैठकों में

[14] पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/सामग्री जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों के मुआवजे पर 4 नवंबर, 2019 को जारी दिशा-निर्देश 01 अप्रैल, 2020 से या उसके बाद शुरू होने वाले वेतन चक्रों के लिए प्रभावी हो गए।

[15] यदि परिवर्तनीय वेतन निश्चित वेतन का 200 प्रतिशत तक है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत और यदि परिवर्तनीय वेतन 200 प्रतिशत से अधिक है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 67 प्रतिशत गैर-नकद साधनों के माध्यम से होना चाहिए।

[16] यहां उपयोग किया जाने वाला वीपी बैंक द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि है।

[17] बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन।

चार्ट IV.34: सीईओ वेतन बनाम औसत कर्मचारी वेतन

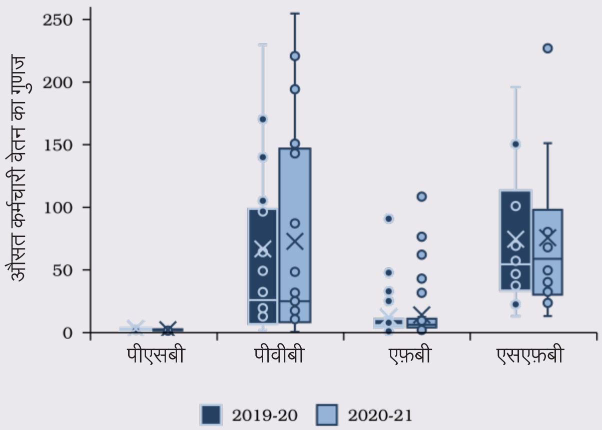

टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट के व्हिस्कर कुल पारिश्रमिक में परिवर्तनीय वेतन के अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का संकेत हैं। रंगीन बॉक्स पहले क्वांटाइल और तीसरे क्वांटाइल के बीच की दूरी को दर्शाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दर्शाती है जबकि 'एक्स' माध्य दर्शाता है। बॉक्स के बाहर के बिंदु आउटलायर दर्शाते हैं।

स्रोत : आरबीआई।

उपस्थित कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में 59 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 2022 के अंत में 63 प्रतिशत कर दी गई। इसी प्रकार, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) तथा नामांकन व पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में स्वतंत्र निदेशकों का अनुपात भी बढ़ा है (सारणी IV.21)।

IV.67 रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बोर्ड द्वारा गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) की अधिक संख्या के साथ एक आरएमसीबी का गठन करना अपेक्षित है। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का एक सदस्य होगा यदि उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता है। निजी क्षेत्र के बैंकों का अनुपात, जहां अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य नहीं है, मार्च 2021 के अंत में 29 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2022 के अंत में 39 प्रतिशत हो गया। लघु वित्त बैंकों में, इसी अवधि के दौरान यह अनुपात 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गया। मार्च 2021 के अंत में निजी क्षेत्र के बैंकों के लगभग 10 प्रतिशत की आरएमसीबी में कोई प्रबंधन उपस्थिति[18] नहीं थी तथा मार्च 2022 के अंत में हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि, लघु वित्त बैंकों के लिए 30 प्रतिशत से 33 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी।

सारणी IV.21: बोर्ड की विभिन्न समितियों पर स्वतंत्र निदेशक
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत में शेयर)

	आरएमसीबी		एनआरसी		बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
पीवीबी	58	65	76	80	79	76
एसएफ़बी	69	74	77	83	80	83

स्रोत : आरबीआई।

8. भारत में विदेशी बैंकों' का परिचालन तथा भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन

IV.68 वर्ष 2021-22 के दौरान, देश में कार्यरत विदेशी बैंकों (एफ़बी) की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ; हालांकि, शाखाओं की संख्या में कमी आयी (सारणी IV.22)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी विदेशी उपस्थिति में कमी की ताकि अपने परिचालनों को युक्तिसंगत बना सकें तथा कम लाभदायक परिचालनों को बंद करके लागत प्रभाव क्षमता को सुधार सकें। भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों ने, हालांकि वर्ष के दौरान और अधिक प्रतिनिधि कार्यालयों को खोलकर अपनी विदेशी उपस्थिति में वृद्धि की है (परिशिष्ट सारणी IV.10)

सारणी IV.22: भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

	शाखाओं के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक		प्रतिनिधि कार्यालयों वाले विदेशी बैंक
	बैंकों की संख्या	शाखाएं	
मार्च-17	44	295	39
मार्च-18	45	286	40
मार्च-19	45#	299*	37
मार्च-20	46#	308*	37
मार्च-21	45#	874*	36
मार्च-22	45#	861*	34

टिप्पणियाँ : 1. #: दो विदेशी बैंक शामिल हैं, अर्थात् एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां(डब्ल्यूओएस) मोड के माध्यम से काम कर रहे हैं।
2. *: एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की शाखाएं शामिल हैं (मार्च 2021 तक समामेलित इकाई यानी लक्ष्मी विलास बैंक की शाखाओं सहित) जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (डब्ल्यूओएस) मोड के माध्यम से काम कर रही हैं।

स्रोत : आरबीआई।

[18] एमडी और सीईओ सहित पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की उपस्थिति।

9. भुगतान प्रणालियाँ तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

IV.69 विश्व भर में विभिन्न नवोन्मेषी भुगतान प्रणालियों तथा लिखतों के आने से भुगतान का दायरा तेज गति से बढ़ता जा रहा है। कई भुगतान प्रणालियों तथा प्लेटफॉर्मों, उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भुगतान उत्पादों तथा सेवाओं की उपलब्धता होने तथा खुदरा भुगतान खंड में भुगतान के नए माध्यमों की शुरुआत तथा स्वीकृति होने के साथ भारतीय भुगतान प्रणाली विश्व में अग्रणी बनकर उभरी है।

IV.70 भारत की भुगतान प्रणालियों को बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए 2019 में एक परीक्षण शुरू किया गया था ताकि इसकी शक्तियों और कमियों का पता लगाया जा सके और 2022 में अनुवर्ती परीक्षण किया गया था। नवीनतम आकलन से पता चला है कि कुछ चुनौतियों के बावजूद, कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय भुगतान प्रणालियों की वृद्धि सुदृढ़ बनी हुई है। 20 अन्य अधिकार क्षेत्रों की तुलना में 40 संकेतकों में से 16 में भारत को 'अग्रणी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पिछले परीक्षण के बाद से भारत ने बिल भुगतान के लिए उपलब्ध डिजिटल भुगतान विकल्पों, सीमा पार प्रेषण के लिए उपलब्ध चैनलों और चेक उपयोग में कमी, बड़े मूल्य के भुगतान प्रणालियों, तीव्र भुगतान प्रणालियों में प्रगति का प्रदर्शन किया है। इस परीक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्वीकृति बुनियादी ढांचे यानी एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों में सुधार की गुंजाइश है। स्वीकृति बुनियादी ढांचे को समृद्ध करने और अंतर को पाटने के लिए भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना 2021 में लागू की गई थी।

9.1 डिजिटल भुगतान

IV.71 पिछले कुछ वर्षों में भुगतान के डिजिटल माध्यमों में तेजी से वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, परंपरागत कागज-आधारित लिखत जैसे कि चेक तथा डिमांड ड्राफ्ट की हिस्सेदारी भुगतानों की मात्रा तथा मूल्य दोनों में नगण्य हो गई है। (चार्ट IV.35)

IV.72 कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन और सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध, जीडीपी में तेज संकुचन के साथ, 2020-21 में भुगतान साधनों के मूल्य और मात्रा दोनों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कुल भुगतान की मात्रा में 2020-21 में 26.6 प्रतिशत से 2021-22 के दौरान 63.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें कुल भुगतान का 99 प्रतिशत डिजिटल मोड के माध्यम से किया गया। आर्थिक गतिविधि में तेजी को दर्शाते

चार्ट IV.35 : भुगतान प्रणालियों के घटक

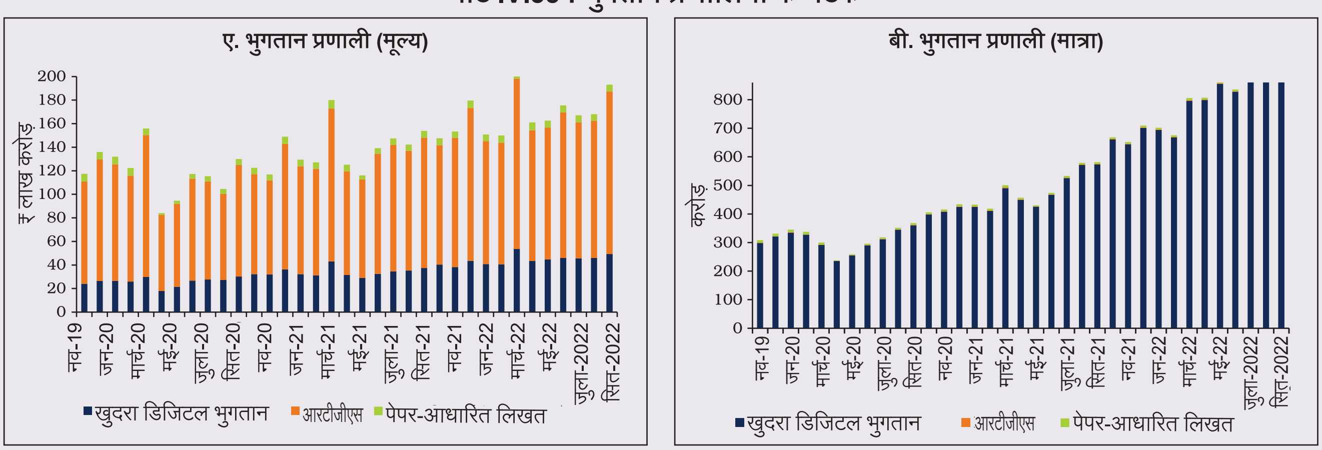

टिप्पणियाँ : खुदरा डिजिटल भुगतान में एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, एनएसीएच, बीएचआईएम आधार भुगतान, एईपीएस निधि अंतरण, एनईटीसी, कार्ड भुगतान और प्रिपेड भुगतान लिखत शामिल हैं।

स्रोत : आरबीआई।

सारणी IV.23: भुगतान प्रणाली संकेतक

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1. वृहत मूल्य ऋण अंतरण- आरटीजीएस	1,507	1,592	2,078	13,11,56,475	10,55,99,849	12,86,57,516
2. ऋण अंतरण	2,06,297	3,17,868	5,77,935	2,85,56,593	3,35,04,226	4,27,28,006
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण)	10	11	10	469	623	575
2.2 एपीबीएस	16,747	14,373	12,573	99,048	1,11,001	1,33,345
2.3 ईसीएस करोड़	18.3	0	0	5,146	0	0
2.4 आईएमपीएस	25,792	32,783	46,625	23,37,541	29,41,500	41,71,037
2.5 एनएसीएच	11,100	16,465	18,758	10,37,079	12,16,535	12,81,685
2.6 एनईएफटी	27,445	30,928	40,407	2,29,45,580	2,51,30,910	2,87,25,463
2.7 यूपीआई	1,25,186	2,23,307	4,59,561	21,31,730	41,03,658	84,15,900
3. नामे अंतरण और प्रत्यक्ष नामे	6,027	10,457	12,189	6,05,939	8,65,520	10,34,444
3.1 भीम आधार पे	91	161	228	1,303	2,580	6,113
3.2 ईसीएस डीआर	1.14	0	0	38.607	0	0
3.3 एनएसीएच	5,842	9,646	10,755	6,04,397	8,62,027	10,26,641
3.4 एनईटीसी	93	650	1,207	200	913	1,689
4. कार्ड भुगतान	72,384	57,787	61,783	14,34,813	12,91,799	17,01,851
4.1 क्रेडिट कार्ड	21,773	17,641	22,399	7,30,894	6,30,414	9,71,638
4.2 डेबिट कार्ड	50,611	40,146	39,384	7,03,920	6,61,385	7,30,213
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	53,941	49,366	65,783	2,14,860	1,97,095	2,79,416
6. कागज़-आधारित लिखत	10,414	6,704	6,999	78,24,822	56,27,108	66,50,333
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**3,40,155**	**4,37,068**	**7,19,768**	**16,19,68,681**	**14,14,58,488**	**17,44,01,233**
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	**3,49,063**	**4,42,180**	**7,24,689**	**3,86,37,028**	**4,14,85,747**	**5,23,94,049**
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	**3,50,570**	**4,43,772**	**7,26,767**	**16,97,93,503**	**14,70,85,596**	**18,10,51,565**

स्रोत : आरबीआई।

हुए,मूल्य के दृष्टिकोण से, कुल भुगतान में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.23)। लगभग सभी डिजिटल साधनों ने मार्च 2020 के अंत में देखे गए स्तरों को पार कर लिया है, हालांकि, आरटीजीएस लेनदेन अभी भी पीछे हैं।

IV.73 रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2021 में सम्मिश्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) की शुरुआत की ताकि देश में भुगतानों के डिजिटलीकरण के विस्तार का प्रभावी रूप से पता लगाया जा सके। यह सूचकांक पाँच मुख्य मापदंडो – भुगतान सक्षमकर्ताओं; भुगतान बुनियादी संरचना – मांग कारकों ; भुगतान बुनियादी संरचना – आपूर्ति कारकों ; भुगतान प्रदर्शन तथा उपभोक्ता केन्द्रीयता पर आधारित है; तथा इसको आधार मानकर मार्च 2018 से अर्ध-वार्षिक रूप से गणना की जाती है। आरबीआई-डीपीआई अंक ने बड़ी वृद्धि को दर्शाया है जो यह दर्शाती है कि हाल के वर्षों में देश में विभिन्न डिजिटल भुगतानों के माध्यमों की तेजी से स्वीकृति तथा पहुँच हुई है। सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2022 में 29.1 प्रतिशत बढ़ा है (चार्ट IV.36)।

चार्ट IV.36: आरबीआई- डिजिटल भुगतान सूचकांक

स्रोत: आरबीआई।

IV.74 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत बिल पे लिमिटेड द्वारा संचालित बिल भुगतानों का एक अंतर प्रचालनीय प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए दिशानिर्देश वर्ष 2014 में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए थे। बीबीपीएस के उपयोगकर्ताओं को मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था तथा निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। शुरुआत में बीबीपीएस के कार्यक्षेत्र तथा कवरेज में बिल बनाने वाले अर्थात डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), विद्युत, गैस, टेलिकॉम तथा पानी की पाँच श्रेणियाँ शामिल की गई थी। इसके दायरे का बाद में विस्तार किया गया था ताकि स्वैच्छिक आधार पर पात्र सहभागियों के रूप में, बार-बार बिलों की उगाही के लिए बिल बनाने वालों की सभी श्रेणियों को शामिल किया जा सके) बीबीपीएस प्रणाली में सितंबर 2019 में 168 बिल बनाने वाले थे तथा ₹1900 करोड़ के मूल्य के लिए 1.10 करोड़ लेन-देनों को पूरा किया था, जबकि नवंबर 2022 में 20,519 बिल बनाने वालों के साथ 16,585 करोड़ के मूल्य के लिए 9.49 करोड़ लेन-देनों को पूरा किया गया।

IV.75 नवम्बर 2022 की समाप्ति के समय में, भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के रूप में 43 बैंक तथा 10 गैर-बैंक सहभागिता करते हैं। मई 2022 में, गैर-बैंक बीबीपीओयू के लिए न्यूनतम निवल मालियत अपेक्षा को ₹ 100 करोड़ से ₹ 25 करोड़ तक कम कर दिया गया ताकि उनकी सहभागिता बढ़ायी जा सके तथा ग्राहक निधियां संभालने वाले तथा भुगतान प्रणालियों में उसी प्रकार की जोखिम प्रोफ़ाइल के अन्य गैर-बैंक सहभागियों के साथ उनकी निवल मालियत आवश्यकता को एक समान किया जा सके।

9.2 एटीएम

IV.76 मार्च 2022 के अंत में, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित कुल एटीएम में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी क्रमश: 63 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत रही। निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ व्हाईट लेबल एटीएम ने ऑन-साइट और ऑफ-साइट एटीएम वृद्धि को बढ़ावा दिया (सारणी IV.24 तथा परिशिष्ट सारणी IV.11)।

IV.77 मार्च 2022 के अंत में, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की हिस्सेदारी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से कम रही। जहां पीएसबी के एटीएम अधिक समान रूप से वितरित किए जाते हैं, अन्य बैंक समूहों के एटीएम शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में अधिक लगाए जाते हैं (सारणी IV.25)।

सारणी IV.24 : एटीएम की संख्या
(मार्च अंत में)

क्र. सं.	बैंक समूह	ऑन साइट एटीएम		ऑफ-साइट एटीएम		एटीएम की कुल संख्या	
		2021	2022	2021	2022	2021 (3+5)	2022 (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	पीएसबी	78,007	78,540	59,106	59,516	1,37,113	1,38,056
II	पीवीबी	35,282	38,254	38,087	37,289	73,369	75,543
III	एफ़बी	236	716	614	1,081	850	1,797
IV	एसएफ़बी*	2,079	2,237	52	25	2,131	2,262
V	पीबी#	1	1	111	70	112	71
VI	डबल्यूएलए	0	0	25,013	31,499	25,013	31,499
VII	सभी एससीबी (I से IV)	1,15,605	1,19,748	97,970	97,981	2,13,575	2,17,729
VIII	कुल (VI+VII)	1,15,605	1,19,748	1,22,983	1,29,480	2,38,588	2,49,228

टिप्पणी: 1. *: मार्च 2021 के अंत में 10 और मार्च 2022 के अंत में 12 अनुसूचित एसएफबी।
2. #: 6 अनुसूचित पीबी मार्च 2021 और मार्च 2022 के अंत में।
स्रोत : आरबीआई।

सारणी IV.25: एटीएम का भौगोलिक वितरण: बैंक समूह-वार @
(मार्च 2022 के अंत में)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महनगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
I. सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	29,252 (21.19)	39,812 (28.84)	35,103 (25.43)	33,889 (24.55)	1,38,056 (100)
II. निजी क्षेत्र बैंक	6,415 (8.49)	19,328 (25.58)	18,897 (25.01)	30,903 (40.90)	75,543 (100)
III. विदेशी बैंक	136 (7.57)	373 (20.76)	450 (25.04)	838 (46.63)	1,797 (100)
IV. लघु वित्त बैंक*	217 (9.59)	740 (32.71)	722 (31.92)	583 (25.77)	2,262 (100)
V. भुगतान बैंक #	9 (12.68)	14 (19.72)	27 (38.03)	21 (29.58)	71 (100)
सभी एससीबी (I से V)	36,029 (16.55)	60,267 (27.68)	55,199 (25.35)	66,234 (30.42)	2,17,729 (100)
सभी एससीबी (व-द-व वृद्धि)	4.39	2.83	-7.59	9.50	1.94
डबल्यूएलए	16,410 (52.09)	10,234 (32.48)	3,150 (10.00)	1,705 (5.41)	31,499 (100)
डबल्यूएलए (व-द-व वृद्धि)	24.44	25.38	37.19	24.63	25.93

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के अंतर्गत कुल एटीएम का प्रतिशत में हिस्सा दर्शाते हैं।
2. *: मार्च 2021 के अंत में 10 और मार्च 2022 के अंत में 12 अनुसूचित एसएफबी।
3. #: 6 अनुसूचित पीबी मार्च 2021 और मार्च 2022 के अंत में।
4. @: डेटा में एटीएम और नकद पुनर्चक्रण मशीनों (सीआरएम) की संख्या शामिल है।

स्रोत : आरबीआई।

10. उपभोक्ता संरक्षण

IV.78 रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी आरई के विरुद्ध ग्राहक शिकायतों का समाधान करने हेतु शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की जा रही हैं। 12 नवंबर 2021 से प्रभावी, रिज़र्व बैंक के लोकपाल फ्रेमवर्क की “एक राष्ट्र एक लोकपाल “दृष्टिकोण के साथ पुनर्संरचना की गई और अधिकार क्षेत्रों की सीमाओं से परे ग्राहक शिकायतों का निशुल्क केंद्रीकृत निवारण प्रदान करता है। यह केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) और संपर्क केंद्र (सीसी) द्वारा समर्थित है।

IV.79 वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक के लोकपालों द्वारा 4,18,184 शिकायतें प्राप्त की गई, इसमें वर्ष दर वर्ष 9.4[19] प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 98 प्रतिशत शिकायतों का निवारण/निपटारा किया गया। आरई के विरुद्ध शिकायतें जो आरबी-आईओएस के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन पर रिज़र्व बैंक के 30 कार्यालयों में स्थित ग्राहक शिक्षण एवं संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) द्वारा कार्रवाई की जाती है। वर्ष के दौरान सीईपीसी में 45,106 शिकायतें प्राप्त की गई थी। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार सीईपीसी की 98.5 प्रतिशत निपटान दर[20] रही।

IV.80 सीआरपीसी तथा सीसी सहित आरबी-आईओएस के कार्य की प्रभावशीलता का पता लगाने हेतु रिज़र्व बैंक ने दूरभाष साक्षात्कारों के माध्यम से पूरे भारत में एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में देश के 4,000 से अधिक उत्तर देने वालों ने भाग लिया। दोनों प्रणालियों अर्थात पूर्व लोकपाल योजनाओं में से एक तथा वर्तमान आरबी-आईओएस दोनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने वाले 60 प्रतिशत उत्तर देने वाले यह महसूस करते हैं कि आरबीआई ओएस के अंतर्गत समग्र प्रक्रिया में इस योजना के शुरू होने के पहले छह महीनों में सुधार आया है।

IV.81 लोकपाल ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन आने से आरबीआईओ में कार्रवाई की जा रही शिकायतों के प्रापण और निपटान में वर्ष-दर-वर्ष प्रवृति की तुलना नहीं हो सकती है। हालांकि, एटीएम/डेबिट कार्डों, मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, उचित व्यवहार संहिता का पालन न करने तथा क्रेडिट कार्डों से संबन्धित शिकायतें वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक थी तथा कुल शिकायतों में इनकी हिस्सेदारी 51.5 प्रतिशत थी (सारणी IV.26)

[19] 2020-21 में 3,82,292 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें बैंकिंग लोकपाल योजना, एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना के तहत प्राप्त शिकायतें शामिल हैं।

[20] निपटान दर की गणना इस प्रकार की जाती है: [(वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें) ÷ (पहले की शिकायतें + वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें)]।

सारणी IV.26: आरबीआईओ में शिकायतों की प्रकृति

श्रेणियाँ	2019-20	2020-21	2021-22#
एटीएम/डेबिट कार्ड	69,205	60,203	41,375
मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	39,627	44,385	40,597
उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	40,124	33,898	37,880
क्रेडिट कार्ड	26,616	40,721	34,828
ऋण और अग्रिम	14,731	20,218	30,734
प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता	22,758	35,999	22,031
जमा खाते	10,188	8,580	16,707
बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाना	17,268	20,949	14,516
पेंशन भुगतान	6,884	4,966	6,179
बीसीएसबीआई कोड का पालन न करना	11,758	14,490	4,816
प्रेषण	4,130	3,394	3,235
डीएसए और रिकवरी एजेंट	1,474	2,440	1,604
पैरा-बैंकिंग	1,134	1,236	1,480
नोट और सिक्के	551	332	296
बीओ योजना के दायरे से बाहर	9,412	10,250	7,363
अन्य	30,844	39,686	40,855
कुल	**3,06,704**	**3,41,747**	**3,04,496***

टिप्पणियाँ : 1. वर्ष संबंधित वर्ष के अप्रैल से मार्च तक संबंधित है;
2. #: आरबीआईओ को सौंपी गई शिकायतों में से;
3. *: सीआरपीसी द्वारा निपटाई जाने वाली 1,13,688 शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : आरबीआई।

IV.82 वर्ष 2021-22 के दौरान शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों से आयी शिकायतों की हिस्सेदारी प्राप्त हुई कुल शिकायतों की 73.8 प्रतिशत थी, जो यह दर्शाता है कि रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण व्यवस्थाओं के संबंध में इन क्षेत्रों में अधिक जागरूकता आयी है (चार्ट IV.37 ए)। निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध बिना पूर्व नोटिस के शुल्क लगाने संबंधी 46 प्रतिशत शिकायतें दर्ज की गई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध पेंशन से संबन्धित 98.2 प्रतिशत शिकायतें दर्ज की गई – पेंशनरों के लिए परंपरागत प्राथमिकता (चार्ट IV.37 बी तथा परिशिष्ट सारणी IV.12)।

IV.83 जमा बीमा प्रणाली की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने में, इस प्रकार लोगों का विश्वास कायम रहता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदान किए गए जमा बीमा में स्थानीय क्षेत्र के बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक कवर किए गए हैं। 80 प्रतिशत की अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में मार्च 2022 के अंत में भारत में जमा बीमा की वर्तमान सीमा ₹ 5 लाख के साथ, कुल खातों का 97.9 प्रतिशत पूर्ण रूप से सुरक्षित था। राशि के अनुसार, 20 से 30 प्रतिशत की अंतरराष्ट्रीय

चार्ट IV.37: शिकायतों का वितरण

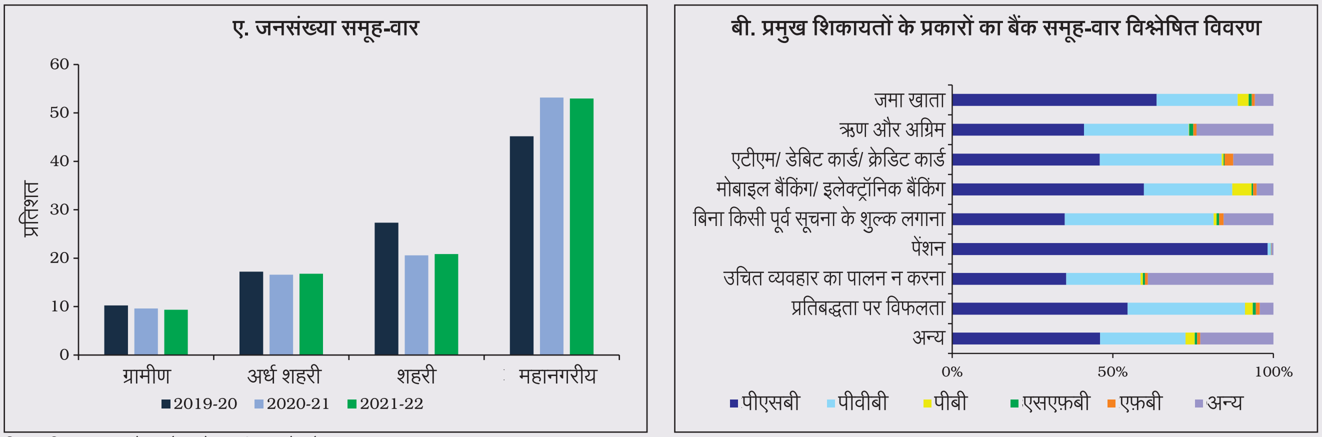

टिप्पणी: 1. आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं।
2. 2021-22 के दौरान 162,126 शिकायतों यानी 53 प्रतिशत शिकायतों के लिए जनसंख्या समूह पर डेटा उपलब्ध नहीं था। इसलिए, उपलब्ध डेटा से अनुपात को बनाए रखते हुए उपलब्ध डेटा को सभी शिकायतों के लिए बहिर्वेशित किया गया है।

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

सारणी IV.27: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशि
(मार्च 2022 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	कुल निर्धारणीय जमा (एडी)*	कुल बीमाकृत जमा (आईडी)*	एडी के प्रतिशत के रूप में आईडी
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	92,53,975	50,05,209	54.1
निजी क्षेत्र के बैंक**	39	49,66,447	19,20,359	38.7
विदेशी बैंक	45	8,00,107	86,728	10.8
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,92,966	4,08,744	82.9
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	981	750	76.4
सहकारी बैंक	1,899	10,35,154	6,88,642	66.5
कुल	**2,040**	**1,65,49,630**	**81,10,431**	**49.0**

टिप्पणियाँ: 1. *: सितंबर 2021 के जमा आधार के आधार पर यानी संदर्भ तिथि से छह महीने पहले।
2. **: निजी क्षेत्र के बैंकों के डेटा में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक शामिल हैं।

स्रोत: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम।

बेंचमार्क[21] की तुलना में निर्धारणीय जमा का 49.0 प्रतिशत बीमा द्वारा कवर किया गया था (सारणी IV.27)।

IV.84 डीआईसीजीसी अपने अधिशेष के अंतरण के माध्यम से अर्थात प्रत्येक वर्ष करों का भुगतान करने के बाद व्यय (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान तथा संबन्धित व्यय) घटाकर अतिरिक्त आय (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम को शामिल करते हुए, निवेशों से ब्याज आय तथा विफल बैंकों की आस्तियों से प्राप्त नकदी वसूली) द्वारा अपनी निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ़) का निर्माण करता है। परिसमापन/समामेलन में लिये गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करने के लिए यह निधि उपलब्ध है तथा 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार यह ₹ 1,46,842 करोड़ थी, जिससे 1.81 प्रतिशत का आरक्षित निधि अनुपात (आरआर)[22] प्राप्त हुआ।

IV.85 वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत निगम द्वारा ₹ 8,516.6 करोड़ [23] के संकलित दावों का निपटान किया गया। इसमें डीआईसीजीसी अधिनियम,1961 के खंड 17(1) के अंतर्गत 15 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में राशि ₹ 1,225.0 करोड़ के मुख्य दावे तथा पूरक दावे सम्मिलित हैं तथा पूर्व पंजाब तथा महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (पीएमसीबीएल) के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए यूनिटी लघु वित्त बैंक (यूएसएफ़बी) को राशि ₹ 3791.6 करोड़ दिये गए। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इसमें सभी समावेशी दिशानिर्देश (एआईडी) के अंतर्गत 22 शहरी सहकारी बैंकों की ₹ 3457.4 करोड़ की राशि के दावे भी शामिल हैं।

IV.86 वर्ष 2021-22 के दौरान, डीआईसीजीसी अधिनियम,1961 में संशोधन किया गया जिसके कारण एआईडी के अंतर्गत रखे गए बैंकों के लिए जमाकर्ताओं की बीमाकृत राशि का भुगतान किया जा सका। डीआईसीजीसी को अब यह अधिकार प्राप्त है कि वह 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्येक ₹5 लाख तक की राशि इन बैंकों के जमाकर्ताओं को चुकता करें। बीमाकृत बैंक से अपेक्षित है कि वह एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर अपने दावे प्रस्तुत करें, उसके बाद डीआईसीजीसी से अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के भीतर दावों का सत्यापन करवाएँ तथा अगले 15 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को भुगतान करें। बीमाकृत बैंक या डीआईसीजीसी के लिए संविधि द्वारा समय बढ़ाने के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, 45 दिनों के सांविधिक समय-सीमा के भीतर कुछ शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं के दावे की सूची प्रस्तुत न करने के दृष्टांत देखे गए हैं, जिससे ऐसे बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करने में डीआईसीजीसी को बाध्य होना पड़ा।

11. वित्तीय समावेश

IV.87 वित्तीय समावेश आर्थिक विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति प्रयास है। एक ओर जहां कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल तथा

[21] आईएडीआई (2013), प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए उन्नत मार्गदर्शन: जमा बीमा कवरेज, मार्गदर्शन पत्र, मार्च, www.iadi.org पर उपलब्ध है।

[22] बीमा निधि और बीमित जमा राशि का अनुपात।

[23] निगम की त्वरित दावा निपटान नीति के तहत तीन सहकारी बैंकों के मामले में ₹42.6 करोड़ की राशि के लिए निपटाए गए मुख्य दावों को शामिल किया गया।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन से इन प्रयासों को एक कार्यनीतिक बल प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय समावेश हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) 2019-24 इसके विज़न और मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करती है ताकि इसकी पहुँच बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो और निरंतर प्रगति बनी रहे। इस अति महत्वपूर्ण लक्ष्य द्वारा किफ़ायती रूप से औपचारिक वित्तीय सेवाओं को प्राप्त किया जा सकेगा और साथ ही वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।

IV.88 जनवरी 2020 में, रिज़र्व बैंक ने यह लक्ष्य बनाया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हर गांव और 500 परिवारों के छोटे गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट स्थापित किया जाएगा। 30 सितंबर 2022 की स्थिति अनुसार, इस लक्ष्य को 26 राज्यों तथा 7 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में प्राप्त कर लिया गया है। देश में पहचाने गए गाँवों तथा छोटे गाँवों की कवरेज 99.97 प्रतिशत पहुँच गई तथा केवल 2 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में और 1 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात लद्दाख में 40 गाँवों को कवर करना शेष है।

IV.89 आईएमएफ़ का नवीनतम वित्तीय पहुँच सर्वेक्षण (एफ़एएस) दर्शाता है कि तेज गति से डिजिटलीकरण के बावजूद पिछले दशक में भारत में बैंक शाखाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, डिजिटलीकरण के कारण पूरे विश्व में बैंक शाखाएँ कम हो गई हैं (चार्ट IV.38 ए)।

IV.90 यद्यपि स्थापित एटीएम की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है (चार्ट IV.38 बी)। पीओएस टर्मिनलों तथा आधार समर्थित भुगतान प्रणालियों (एईपीएस) का उपयोग करने वाले माइक्रो-एटीएम जैसी सुविधाएं इस कमी को पूरा करने में सहायक है।

IV.91 विश्व बैंक के ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस के अनुसार, वैश्विक औसत की तुलना में 78 प्रतिशत भारतीय वयस्कों (15 वर्ष या अधिक आयु की जनसंख्या) के पास वर्ष 2021 में बैंक खाता था। वर्ष 2021 में, विश्व में खाते स्वामित्व में जेंडर गैप[24] वर्ष 2014 में 7 प्रतिशत बिन्दु से 4 प्रतिशत बिन्दु तक गिरा, भारत में यह जेंडर गैप समाप्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ, भारत में नकद में वेतन प्राप्त कर रही वयस्क जनसंख्या का अनुपात अभी भी 43 प्रतिशत पर उच्चतर है जबकि विकासशील देशों का यह

चार्ट IV.38: जी-20 देशों में वित्तीय समावेश में प्रगति

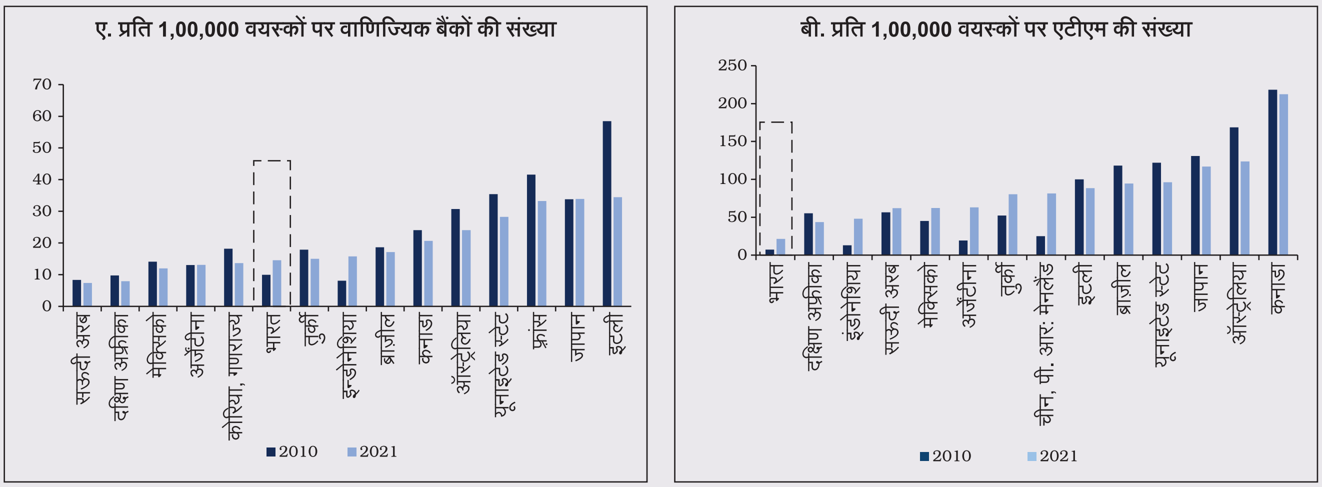

स्रोत: वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण, आईएमएफ।

[24] जेंडर गैप का संबंध बैंक खाता रखने वाले पुरुषों के प्रतिशत में से बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत घटाने से है।

चार्ट IV.39: वित्तीय समावेश संकेतक

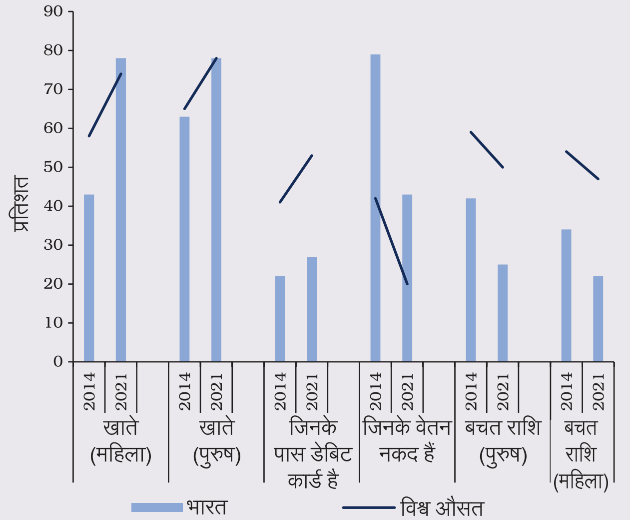

टिप्पणी: डेटा 15 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में।
स्रोत: वैश्विक फिनडेक्स डेटाबेस, विश्व बैंक।

औसत 26 प्रतिशत है तथा विश्व औसत 20 प्रतिशत है (चार्ट IV.39)।

IV.92 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफ़एल) नवोन्मेषी उपायों तथा लोगों की भागीदारी के माध्यम से देश में वित्तीय शिक्षण प्रयासों में सहयोग देते हैं। 01 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार, 1,112 सीएफ़एल स्थापित किए गए हैं तथा दिसंबर 2022 तक और 500 केन्द्रों को स्थापित करने की योजना है।

IV.93 इसके अतिरिक्त, वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफ़एलसी) द्वारा वित्तीय शिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 1,07,564 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 14-18 फरवरी 2022 के दौरान "डिजिटल अपनाएं, सुरक्षित रहें "थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया।

11.1 वित्तीय समावेश योजनाएं

IV.94 बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वित्तीय समावेश योजनाओं (एफ़आईपी) को लागू करें ताकि सतत रूप से वित्तीय समावेश के स्तर में वृद्धि करने की एक प्रणालीबद्ध पद्धति सुनिश्चित की जा सके। एफ़आईपी में विभिन्न मापदण्डों जैसे बैंकिंग आउटलेटों की संख्या (शाखाएँ तथा कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी)], बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीएस), इन खातों में प्राप्त की गई ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) तथा कारोबारी प्रतिनिधि – सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) माध्यम से की गई लेन-देन पर बैंकों की उपलब्धियां शामिल होती हैं।

IV.95 बीसी मॉडल पुरानी पारंपरिक शाखाओं की तुलना में तेज दर तथा कम लागत पर अंतिम छोर तक जाने तथा जमीनी स्तर पर पहुँचने की समस्या का निवारण करने में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वर्ष 2021- 22 में गाँवों में कुल बैंकिंग आउटलेटों में से 97.5 प्रतिशत बीसी आउटलेट्स हैं जबकि शाखाएँ कम हो गई हैं। बीसी- आईसीटी मॉडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रियता हासिल की है जैसा कि इसके बढ़ते उपयोग से स्पष्ट है (सारणी IV.28)।

IV.96 नियत-स्थान कारोबारी प्रतिनिधि (एफबीसी) का राज्यवार वितरण, हालांकि, असमान रहता है - 50 प्रतिशत से अधिक एफबीसी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्थित हैं (चार्ट IV.40)। मार्च 2018 के बाद से, एफबीसी की कुल संख्या में पीबी का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें पीवीबी की उपस्थिति नगण्य है (चार्ट IV.41)।

11.2. *वित्तीय समावेश सूचकांक*

IV.97 रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेश के प्रसार का विवरण ज्ञात करने के लिए एक समग्र वित्तीय समावेश सूचकांक (एफ़आई-इंडेक्स) तैयार किया है। इसके तीन उप-सूचकांक हैं, अर्थात् एफआई-एक्सेस, एफआई-उपयोग और एफआई-गुणवत्ता। सूचकांक में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ सरकार और क्षेत्रीय नियामकों से एकत्रित पेंशन क्षेत्र पर सूक्ष्मतम डेटा शामिल है। एफआई सूचकांक का मान मार्च 2021 में 53.9 की तुलना में मार्च 2022 के लिए 56.4 था, जिसमें सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि हुई थी।

सारणी IV.28: वित्तीय समावेश योजना में प्रगति
(मार्च के अंत में)

क्र.सं.	विवरण	2010	2015	2020	2021	2022*
1	गांवों में बैंकिंग आउटलेट- शाखाएं	33,378	49,571	54,561	55,112	53,287
2	गांवों में बैंकिंग आउटलेट>2000-बीसी	8,390	90,877	149,106	850,406	18,92,462^
3	गांवों में बैंकिंग आउटलेट<2000-बीसी	25,784	408,713	392,069	340,019	3,26,008
4	गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट – बीसी	34,174	499,590	541,175	1,190,425	22,18,470^
5	गांवों में बैंकिंग आउटलेट – अन्य मोड	142	4,552	3,481	2,542	2,479
6	गांवों में बैंकिंग आउटलेट – कुल	67,694	553,713	599,217	1,248,079	22,74,236^
7	बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	96,847	635,046	426,745	12,95,307^
8	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,103	2,616	2659	2,661
9	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	36,498	95,831	118,392	1,20,464
10	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	1,878	3,388	3,796	4,015
11	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	7,457	72,581	87,623	1,07,415
12	बीएसबीडीए - कुल (संख्या लाख में)	735	3,981	6,004	6455	6,677
13	बीएसबीडीए - कुल (राशि करोड़ में)	5,500	43,955	1,68,412	2,06,015	2,27,879
14	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा प्राप्त (संख्या लाख में)	2	76	64	60	68
15	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ (राशि करोड़ में)	10	1,991	529	534	731
16	केसीसी - कुल (संख्या लाख में)	240	426	475	466	473
17	केसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	4,38,229	6,39,069	6,72,624	7,10,715
18	जीसीसी - कुल (संख्या लाख में)	10	92	202	202	96
19	जीसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	3,500	131,160	1,94,048	1,55,826	1,70,203
20	आईसीटी-ए/सीएस-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में) #	270	4,770	32,318	30,551	28,533
21	आईसीटी-ए/सीएस-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में) #	700	85,980	8,70,643	8,49,771	9,05,252

टिप्पणी: 1. *: अनंतिम
2. #: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन।
3. ^: कुछ निजी क्षेत्र बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा में कुछ महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है।
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणी।

11.3. प्रधानमंत्री जन धन योजना

IV.98 प्रमुख वित्तीय समावेश कार्यक्रम पीएमजेडीवाई का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक खातों की उपलब्धता, आवश्यकता-आधारित ऋण, धनप्रेषण, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक

चार्ट IV.40: एफबीसी का राज्यवार वितरण

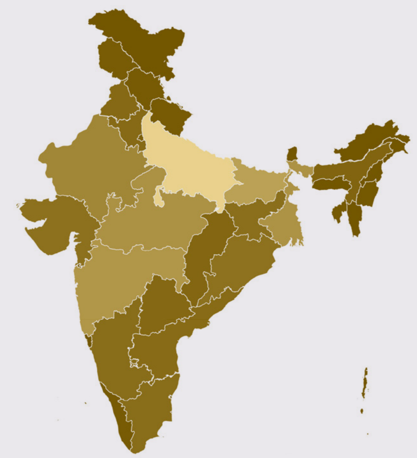

टिप्पणियाँ : हल्के रंग एफबीसी की अधिक संख्या से संबंधित हैं।
स्रोत : बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई)।

चार्ट IV.41: एफबीसी का बैंक समूह-वार वितरण

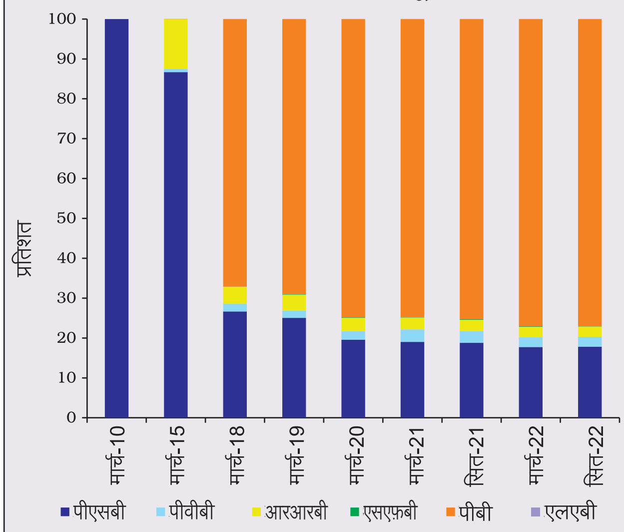

स्रोत : बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) और आरबीआई।

पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रारंभिक वर्षों में उच्च विकास चरण के बाद, हाल के वर्षों में नए पीएमजेडीवाई खातों की अभिवृद्धि की दर धीमी हो गई है। यह एक संकेत है कि कार्यक्रम वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के अपने इच्छित उद्देश्य के करीब है (चार्ट IV.42)।

IV.99 अपने परिचालन के आठ वर्षों में, पीएमजेडीवाई के तहत कुल जमा शेष राशि में वृद्धि हुई है, प्रति खाता औसत जमा भी बढ़ गया है (चार्ट IV.43ए)। अगस्त 2022 के अंत में, 56 प्रतिशत खाता धारक महिलाएं हैं और 67 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में थे (चार्ट IV.43बी)। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमजेडीवाई खाते को निष्क्रिय माना जाता है यदि इसमें दो साल तक ग्राहक-प्रेरित लेनदेन नहीं होता है। अगस्त 2022 तक, कुल 46.25 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 81.2 प्रतिशत सक्रिय थे, जो 2017[25] में 76 प्रतिशत था। केवल 8.2 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाते शून्य जमा शेष खाते थे।

चार्ट IV.42: पीएमजेडीवाई खातों की संख्या

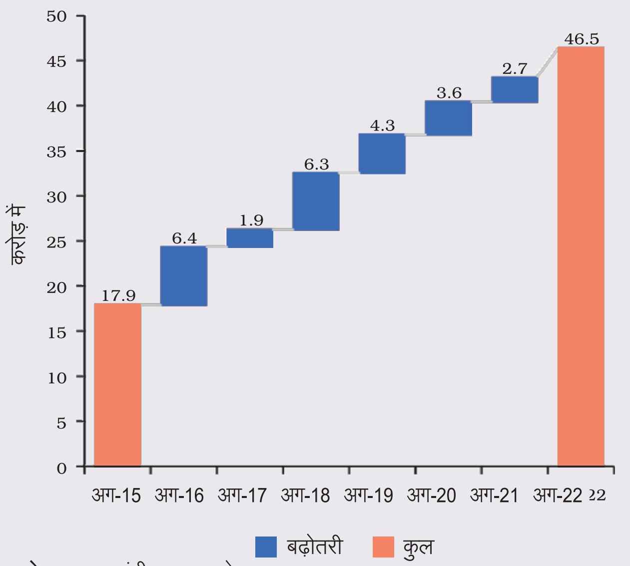

स्रोत : प्रधान मंत्री जन धन योजना, भारत सरकार।

11.4. एससीबी द्वारा नए बैंक शाखाएं

IV.100 लगातार दो वर्षों तक गिरावट के बाद, एससीबी द्वारा खोली गई नई बैंक शाखाओं में 2021-22 के दौरान 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। टियर 4, टियर 5 और टियर 6 केंद्रों में

चार्ट IV.43: पीएमजेडीवाई खातों का विवरण और औसत शेष

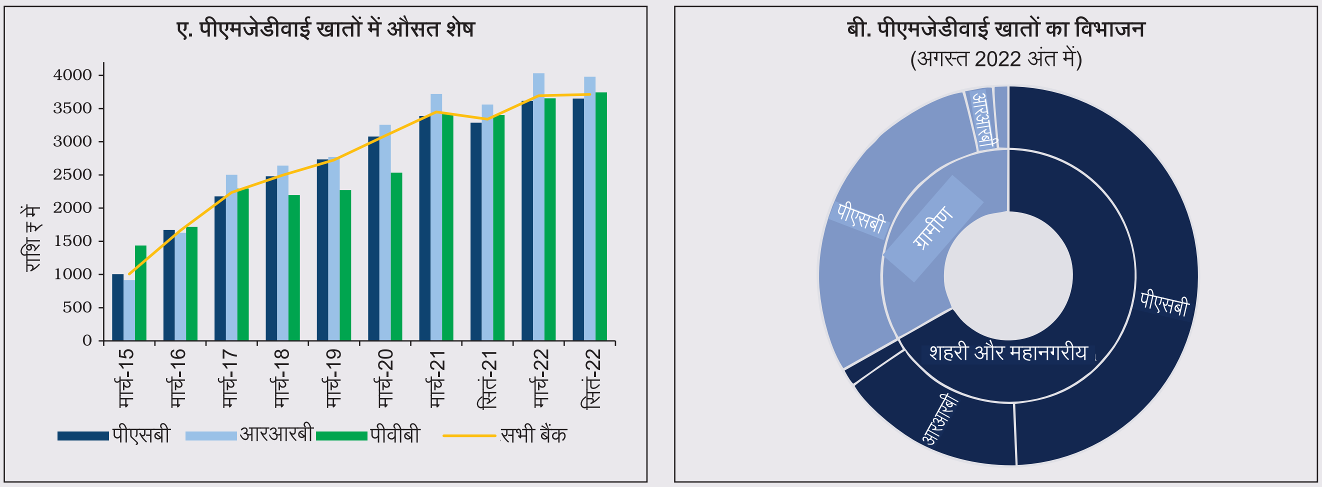

स्रोत: प्रधानमंत्री जन धन योजना, भारत सरकार।

[25] **स्रोत:** https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1854909

सारणी IV.29: एससीबी द्वारा नई खोली गई बैंक शाखाओं का स्तर-वार विश्लेषित-विवरण

केंद्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
स्तर 1	2,194 (47.4)	2,279 (52.4)	1,541 (49.9)	1,543 (47.7)
स्तर 2	519 (11.2)	367 (8.4)	279 (9.0)	235 (7.3)
स्तर 3	712 (15.4)	570 (13.1)	481 (15.6)	426 (13.2)
स्तर 4	363 (7.8)	355 (8.1)	262 (8.5)	293 (9.1)
स्तर 5	373 (8.1)	282 (6.5)	178 (5.7)	226 (7.0)
स्तर 6	465 (10.1)	500 (11.5)	348 (11.3)	509 (15.7)
कुल	**4,626 (100.0)**	**4,353 (100.0)**	**3,089 (100.0)**	**3,232 (100.0)**

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में खोली गई शाखाओं के अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. केंद्रों का स्तर-वार वर्गीकरण इस प्रकार है: 'स्तर 1' में 1,00,000 और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 2' में 50,000 से 99,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 3' में 20,000 49,999 तक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 4' में 10,000 से 19,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 5' में 5,000 से 9,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, और 'स्तर 6' में 5000 से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं।
3. डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।
4. सभी जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
5. 2018-19 से आगे के आकड़ों की तुलना के लिए, 1 सितंबर 2022 तक के सभी अनुसूचित बैंकों को लिया गया है।

स्रोत: सीआईएसबीआई, आरबीआई। सीआईएसबीआई के डेटा हमेशा बदलते रहते हैं और बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

खोली गई नई शाखाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। हालांकि नई शाखाओं में टियर 2 और टियर 3 केंद्रों की हिस्सेदारी एक साल पहले की तुलना में 2021-22 में घट गई, लेकिन वर्ष के दौरान खोली गई नई शाखाओं में से आधे से अधिक टियर 1 और टियर 3 केंद्रों में थीं (सारणी IV.29)।

IV.101 वर्ष 2021-22 के दौरान, पीवीबी द्वारा खोली गई नई शाखाओं में पिछले वर्ष में 30.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि पीवीबी ने सभी जनसंख्या समूहों में नई शाखाएं खोलीं, लेकिन महानगरीय क्षेत्रों में वृद्धि सबसे तेज थी। दूसरी ओर, पीएसबी ने 2021-22 में कम नई शाखाएं खोलीं। हालांकि, पीएसबी द्वारा नई खोली गई बैंक शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2020-21 में 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 20.8 प्रतिशत हो गई,

चार्ट IV.44: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नई खोली गई बैंक शाखाओं का विभाजन

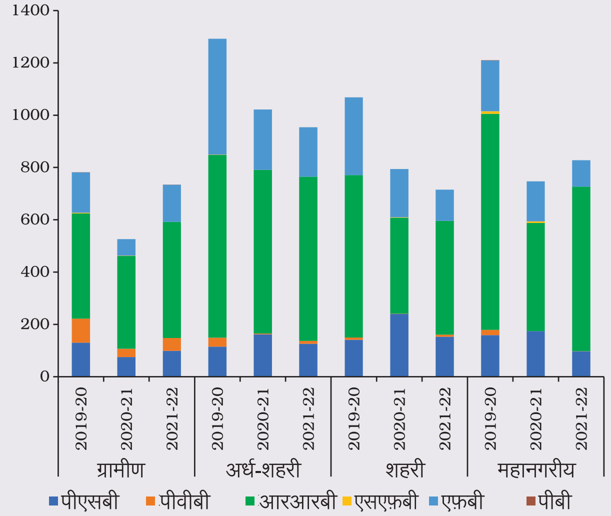

स्रोत : सीआईएसबीआई, आरबीआई।

जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्रों का संयुक्त हिस्सा इसी अवधि में 63.6 प्रतिशत से घटकर 52.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.44)।

11.5. सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम

IV.102 स्वयं सहायता समूह - बैंक संबद्ध कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी), जिसका उद्देश्य गरीबों को औपचारिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना है, दुनिया के सबसे बड़े सूक्ष्म वित्त आंदोलन के रूप में उभरा है। 2021-22 के दौरान, लगभग 34 लाख स्वयं सहायता समूहों ने बैंकों से ऋण लिया। वर्ष के दौरान वितरित ऋण के औसत आकार के साथ-साथ बकाया ऋण के आकार में मार्च 2021 के अंत में गिरावट आई थी, जो कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों को दर्शाता है। यह मार्च 2022 के अंत तक फिर से सक्रिय हुआ और मार्च 2019 के अंत के स्तर (चार्ट IV.45) को पार कर गया। दक्षिणी क्षेत्र (36 प्रतिशत) में 2021-22 के दौरान बचत से जुड़े एसएचजी का सबसे अधिक हिस्सा था, इसके बाद पूर्वी क्षेत्र (27.4 प्रतिशत) और पश्चिमी क्षेत्र (11.4 प्रतिशत) था (परिशिष्ट सारणी IV.13)। एसएचजी का एनपीए अनुपात 2020-21 में 4.73 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 3.80 प्रतिशत हो गया।

चार्ट IV.45: एसएचजी - औसत वितरित ऋण, औसत ऋण बकाया और एसएचजी की औसत बचत

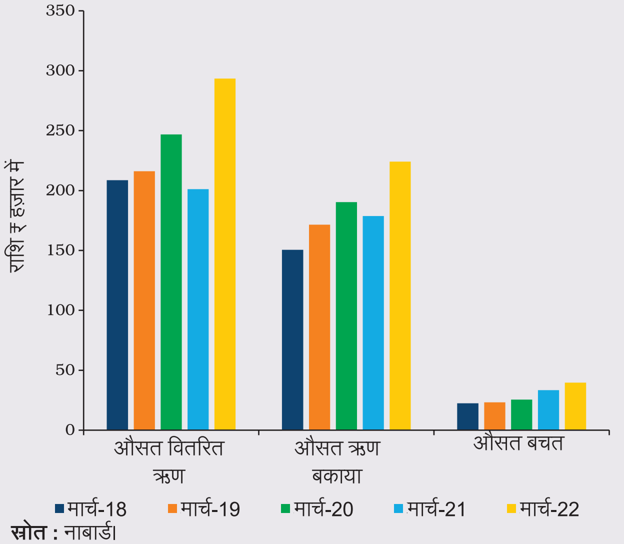

स्रोत : नाबार्ड।

IV.103 संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) पट्टेदार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों और छोटे/सीमांत किसानों और अन्य गरीब व्यक्तियों के रूप में भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को संपार्श्विक मुक्त ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप का एक साधन है। बैंकों द्वारा जेएलजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड ने 2017 में एक व्यवसाय मॉडल पेश किया, जिसके तहत बैंक (पीएसबी, आरआरबी और सहकारी बैंक) एमओयू में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर जेएलजी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करते हैं। बैंकों द्वारा जेएलजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड ने 2017 में एक व्यवसाय मॉडल पेश किया, जिसके तहत बैंक (पीएसबी, आरआरबी और सहकारी बैंक) एमओयू में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर जेएलजी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करते हैं। इस योजना के अंतर्गत, जेएलजी गठन और संबद्ध के लिए नाबार्ड से अनुदान सहायता का आश्वासन दिया जाता है। 2021-22 के दौरान, बैंकों द्वारा जेएलजी को वितरित ऋण में 93.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसमें 29.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। 31 मार्च 2022 तक प्रोत्साहित संचयी जेएलजी के संदर्भ में, दक्षिणी राज्यों ने 49 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की, इसके बाद पश्चिमी राज्यों में 48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

11.6. व्यापारिक प्राप्य-राशि बट्टाकरण प्रणाली (ट्रेड्स)

IV.104 ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जो एमएसएमई को अनेक वित्त-दाताओं के माध्यम से व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण / छूट की सुविधा प्रदान करके उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को प्रबंधित करने में मदद करता है। ये प्राप्तियां सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉरपोरेट और अन्य खरीददारों से बकाया हो सकती हैं। ट्रेड्स को 2014 में रिज़र्व बैंक द्वारा लाया गया था, और 2017 में तीन प्लेटफॉर्मों को संचालित करने के लिए लाइसेंस दिए गए थे। 2021-22 के दौरान, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपलोड और वित्तपोषित चालानों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई और सफलता दर[26] एक साल पहले 91.3 प्रतिशत से बढ़कर 94.7 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.30)।

11.7. क्षेत्रीय बैंकिंग की पहुँच

IV.105 मार्च 2022 के अंत में, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के संकेन्द्रण के कारण, अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक शाखा द्वारा सेवा की गई आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक थी। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों में अंतर कम रही थी (चार्ट IV.46)।

सारणी IV.30: टीआरईडीएस के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति

(बीजक संख्या में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अपलोड किया गया चालान		वित्तपोषित चालान	
	राशि	चालान	राशि	चालान
2018-19	251,695	6,699.57	232,098	5,854.48
2019-20	530,077	13,088.27	477,969	11,165.86
2020-21	861,560	19,669.84	786,555	17,080.14
2021-22	1,733,553	44,111.80	1,640,824	40,308.59

स्रोत : आरबीआई।

[26] अपलोड किए गए ऐसे चालानों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वित्तपोषित होते हैं।

चार्ट IV.46: प्रति बैंक शाखा क्षेत्रवार औसत जनसंख्या
(मार्च 2022 के अंत में)

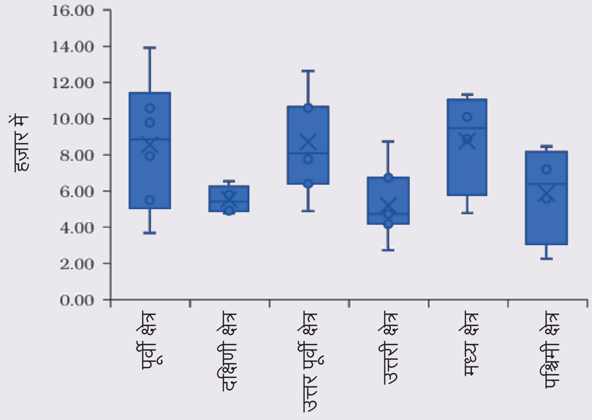

स्रोत : आरबीआई और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएस-पीआई)।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.106 मार्च 2022 के अंत में, 12 एससीबी द्वारा प्रायोजित 43 आरआरबी थे, जिसमें 21,892 शाखाएं थीं और इनका परिचालन 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख) में 29.7 करोड़ जमा खातों और 2.7 करोड़ ऋण खातों तक फैला हुआ था। उनकी 92 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थीं। दक्षिणी क्षेत्र में आरआरबी की संख्या सबसे अधिक थी, इसके बाद पूर्वी क्षेत्र की रही (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

12.1. तुलन पत्र विश्लेषण

IV.107 पिछले 46 वर्षों के दौरान, सभी हितधारकों (जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों) ने आरआरबी में 8,393 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है। इसके विपरीत, 2021-22 और 2022-23 के दौरान आरआरबी में 10,890 करोड़ रुपये लगाने का बजट है, जिसमें केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत योगदान, राज्य सरकारों से 15 प्रतिशत और शेष राशि प्रायोजक बैंकों से होगा। पूंजी निवेश से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को परिचालन और अभिशासन में सुधारों के साथ प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके लिए, एक सतत व्यवहार्यता योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य ऋण विस्तार, व्यापार विविधीकरण, एनपीए में कमी और लागत को तर्कसंगत बनाना है।

IV.108 2021-22 के लिए, 22 आरआरबी के लिए पुनर्पूंजीकरण सहायता के रूप में 8,168 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई । मार्च 2022 के अंत में, नाबार्ड ने प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा आनुपातिक राशि जारी करने के बाद 21 आरआरबी को 3,197.29 करोड़ रुपये का केंद्र सरकार का हिस्सा जारी किया था।

IV.109 वर्ष के दौरान, आरआरबी के समेकित तुलन पत्र की वृद्धि में ऋण और अग्रिमों के साथ-साथ आस्ति पक्ष में निवेश और देयताओं में जमा और उधार की वृद्धि में सुस्ती के कारण कमी आई। आरआरबी की जमा वृद्धि एससीबी की तुलना में कम थी। मार्च 2022 के अंत में, आरआरबी में एससीबी[27] की सभी श्रेणियों के बीच कम लागत वाली सीएएसए जमा (कुल जमा का 54.5 प्रतिशत) का उच्चतम हिस्सा था (सारणी IV.31)।

IV.110 आरआरबी को पिछले वर्ष के अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य है। 2021-22 के दौरान, 2 आरआरबी को छोड़कर अन्य सभी ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 90 प्रतिशत से अधिक ऋण देकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया, जिसमें से

[27] कुल जमा में पीएसबी की सीएएसए की हिस्सेदारी 43.8 फीसदी, पीवीबी की 47 फीसदी, एसएफबी की 40.5 फीसदी और विदेशी बैंकों की 43.8 फीसदी रही ।

सारणी IV.31: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	मार्च अंत में		व-द-व वृद्धि प्रतिशत में	
		2021	2022	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
1	शेयर पूंजी	8,393	14,880	6.9	77.3
2	आरक्षित	30,348	34,359	13.2	13.2
3	जमाराशियां	5,25,226	5,62,538	9.7	7.1
	3.1 चालू	11,499	12,042	7.0	4.7
	3.2 बचत	2,71,516	2,94,438	11.1	8.4
	3.3 मियादी	2,42,211	2,56,057	8.3	5.7
4	उधार	67,864	73,881	24.8	8.9
	4.1 नाबार्ड से	61,588	67,054	33.5	8.9
	4.2 प्रायोजक बैंक	3,444	3,879	-23.8	12.6
	4.3 अन्य	2,832	2,948	-24.6	4.1
5	अन्य देयताएं	19,754	19,742	-2.3	-0.1
	कुल देयताएं / आस्तियां	**6,51,585**	**7,05,400**	**10.8**	**8.3**
6	उपलब्ध नकद	2,954	3,119	3.3	5.6
7	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	18,947	22,174	13.2	17.0
8	चालू खाते में शेष राशि	5,987	8,127	-21.4	35.8
9	निवेश	2,75,658	2,95,665	9.9	7.3
10	ऋण और अग्रिम (शुद्ध)	3,15,181	3,42,479	12.5	8.7
11	अचल संपत्ति	1,229	1,256	-0.5	2.2
12	अन्य आस्तियां #	31,629	32,580	11.0	3.0
	12.1 संचित हानियाँ	8,264	9,062	27.8	9.7

टिप्पणी: 1. #: संचित घाटा शामिल है।
2. आंकडों को ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है। प्रतिशत भिन्नता थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

लगभग 70 प्रतिशत कृषि और 11.5 प्रतिशत एमएसएमई के लिए था (सारणी IV.32 और परिशिष्ट सारणी IV.15)।

सारणी IV.32: आरआरबी द्वारा उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उद्देश्य/मार्च अंत	2021	2022
1	2	3	4
I	**प्राथमिकता (i से v)**	**3,00,962**	**3,24,207**
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	90.1	89.4
	i. कृषि	2,33,145	2,52,890
	ii. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	39,543	41,609
	iii. शिक्षा	2,132	1,896
	vi. आवास	21,127	22,020
	v. अन्य	5,016	5,791
II	**गैर-प्राथमिकता (i से vi)**	**33,209**	**38,631**
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	9.9	10.6
	i. कृषि	29	0
	ii. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	434	35
	iii. शिक्षा	92	139
	iv. आवास	4,347	6,187
	v. व्यक्तिगत ऋण	8,311	10,088
	vi. अन्य	19,996	22,181
कुल (I+II)		**3,34,171**	**3,62,838**

टिप्पणी: कुल राशि ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण कुल के साथ मेल नहीं खाने की संभावना है।

स्रोत : नाबार्ड।

12.2. *वित्तीय प्रदर्शन*

IV.111 2018-19 और 2019-20 में लगातार दो वर्षों तक घाटे की रिपोर्ट करने के बाद, आरआरबी ने 2020-21 में निवल लाभ दर्ज किया, जिसमें 2021-22 में और सुधार हुआ। उनके सीआरएआर में भी काफी वृद्धि हुई (सारणी IV.33)। वर्ष के दौरान, 9 प्रतिशत की विनियामकीय आवश्यकता से कम सीआरएआर वाले आरआरबी की संख्या 16 से घटकर 13 हो गई और ऋणात्मक सीआरएआर वाले आरआरबी की संख्या 8 से घटकर 3 हो गई।

सारणी IV.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. मद	राशि		व-द-व परिवर्तन प्रतिशत में	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1 2	3	4	5	6
ए आय (i + ii)	**53,858**	**56,585**	**8.9**	**5.1**
i ब्याज आय	46,803	48,048	7.1	2.7
ii अन्य आय	7,055	8,537	22.6	21.0
बी व्यय (i+ii+iii)	**52,176**	**53,367**	**1.0**	**2.3**
i ब्याज व्यय किया गया	25,588	24,817	-1.5	-3.0
ii परिचालन व्यय	20,201	21,295	0.6	5.4
जिनमें से वेतन बिल	15,799	16,338	7.8	3.4
iii प्रावधान और आकस्मिकताएं	6,386	7,254	14.1	13.6
जिनमें से आय कर	1,279	1,278	37.5	-0.1
सी लाभ				
i परिचालन लाभ	7,872	10,337	164.9	31.3
ii निवल लाभ	1,682	3,219	--	91.3
डी कुल औसत आस्तियां	**6,17,305**	**6,66,532**	**11.1**	**8.0**
ई वित्तीय अनुपात #				
i परिचालन लाभ	1.3	1.6		
ii निवल लाभ	0.3	0.5		
iii आय (ए + बी)	8.7	8.5		
ए) ब्याज आय	7.6	7.2		
बी) अन्य आय	1.1	1.3		
iv व्यय (क+ख+ग)	8.5	8.0		
a) खर्च किया गया ब्याज	4.1	3.7		
बी) परिचालन व्यय	3.3	3.2		
जिनमें से वेतन बिल	2.6	2.5		
ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.0	1.1		
एफ विश्लेषणात्मक अनुपात (%)				
सकल एनपीए अनुपात	9.4	9.1		
सीआरएआर	10.2	12.7		

टिप्पणियाँ: 1: # वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के संबंध में प्रतिशत हैं।
2. --: आरआरबी पिछले वर्ष के घाटे से 2020-21 में लाभ में आ गए।
3. आंकडों को ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण योग का भिन्न हो सकता है।
4. प्रावधानों और आकस्मिकताओं में भुगतान किए गए आयकर/आयकर के लिए प्रावधान शामिल हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

IV.112 वर्ष के दौरान, ब्याज आय मामूली दर से बढ़ी, लेकिन ब्याज व्यय में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप निवल ब्याज आय के साथ-साथ निवल ब्याज मार्जिन भी अधिक रहा। लाभ कमाने वाले आरआरबी की संख्या 2020-21 में 30 से बढ़कर 2021-22 में 34 हो गई (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

12.3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

IV.113 चूंकि आरआरबी अपने कुल ऋण का लगभग 48 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) को उधार देते हैं, इसलिए वे पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ श्रेणी में प्रमुख विक्रेता हैं। चूंकि पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ का कारोबार पीएसएलसी-सामान्य श्रेणी की तुलना में प्रीमियम पर किया जाता है, आरआरबी प्रथम श्रेणी के तहत पीएसएलसी की अधिक बिक्री करते हैं और 75 प्रतिशत के समग्र पीएसएल लक्ष्य को पूरा करने के लिए द्वितीय श्रेणी के तहत पीएसएलसी खरीदकर इसकी भरपाई करते हैं (सारणी IV.34)।

IV.114 पीएसएलसी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विविध आय बढ़ाने के लिए अपने उच्च पीएसएल पोर्टफोलियो का लाभ उठाने में मदद की है (चार्ट IV.47)। हालांकि सभी एससीबी के कुल बैंक ऋण में आरआरबी का हिस्सा सिर्फ 3 प्रतिशत है, लेकिन कुल पीएसएलसी कारोबार मात्रा (निर्गम और खरीद) में उनकी हिस्सेदारी 2021-22 के दौरान 35 प्रतिशत थी।

सारणी IV.34: आरआरबी के पीएसएलसी लेनदेन

(राशि करोड़ रुपये में)

पीएसएलसी श्रेणी	जारी पीएसएलसी के मूल्य		खरीदे गए पीएसएलसी के मूल्य	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
पीएसएलसी कृषि	40,731	29,850	735	1,150
पीएसएलसी सामान्य	4,004	1,750	52,628	67,771
पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	3,580	7,644	7,125	6,223
पीएसएलसी एसएफ/एमएफ	78,837	1,17,163	4,953	865
कुल	**1,27,151**	**1,56,407**	**65,440**	**76,009**

स्रोतः ओएसएस विवरणी, सुनिश्चित पोर्टल, नाबार्ड।

चार्ट IV.47: विविध आय में पीएसएलसी का योगदान

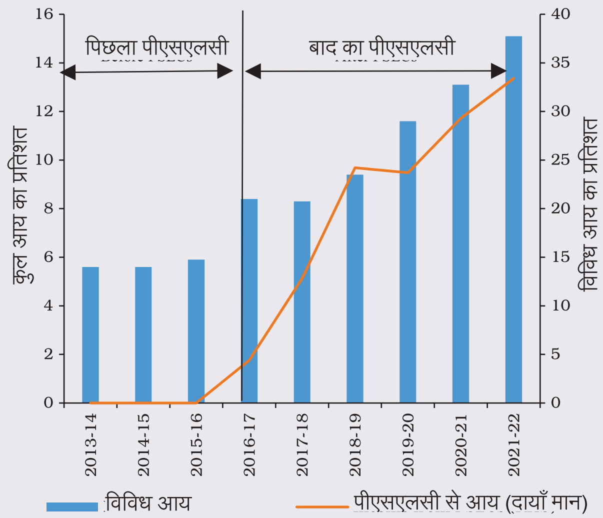

स्रोत : नाबार्ड।

13. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

IV.115 ग्रामीण बचतों को जुटाने के लिए तथा स्थानीय क्षेत्रों में निवेश हेतु उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, देश में 79 शाखाओं[28] सहित दो स्थानीय क्षेत्र के बैंक परिचालन में थे। वर्ष 2021-22 में, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की समेकित तुलन पत्रों में मंदी आयी। चूंकि ऋण में आई यह मंदी जमा में आई मंदी से कम थी, ऋण-जमा अनुपात वर्ष 2020-21 में 80.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 82 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.35)।

सारणी IV.35: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

	2020-21	2021-22
1. आस्तियां	1,166.2 (14.1)	1,273.2 (9.18)
2. जमाराशियां	952.5 (17.05)	1,020.3 (7.11)
3. सकल अग्रिम	769.2 (16.46)	838.0 (8.95)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

[28] स्रोत: बैंकिंग अवसंरचना के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई)।

13.1 स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

IV.116 वर्ष के दौरान, खर्च किए गए ब्याज के साथ-साथ अर्जित ब्याज आय दोनों में गिरावट आई, जिससे निवल लाभ स्थिर रहा। परिचालन व्यय, विशेष रूप से वेतन बिल में तेज वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन लाभ में धीमी वृद्धि देखी गई। (सारणी IV.36)।

सारणी IV.36: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

	राशि ₹ करोड़ में		व-द-व वृद्धि प्रतिशत में	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
ए. आय (i+ii)	**148**	**159**	**9.5**	**7.1**
i. ब्याज आय	123	130	14.8	6.2
ii. अन्य आय	25	28	-10.4	11.7
बी. व्यय (i+ii+iii)	**122**	**132**	**0.0**	**9.0**
i. खर्च किया गया ब्याज	55	58	6.5	4.7
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	20	22	42.8	11.9
iii. परिचालन खर्च	47	53	-16.7	12.8
जिनमें से वेतन बिल	22	25	5.1	12.5
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ/हानि	47	49	68.4	4.3
ii. निवल लाभ/ हानि	27	26	94.3	-1.4
डी. निवल ब्याज आय	**68**	**73**	**22.7**	**7.4**
ई. कुल आस्तियां	**1,166**	**1,273**	**14.1**	**9.2**
एफ़. वित्तीय अनुपात				
i. परिचालन लाभ	4.0	3.8		
ii. निवल लाभ	2.3	2.1		
iii. आय	12.7	12.5		
iv. ब्याज आय	10.5	10.2		
v. अन्य आय	2.2	2.2		
vi. व्यय	10.4	10.4		
vii. खर्च किया गया ब्याज	4.7	4.5		
viii. परिचालन खर्च	4.0	4.1		
ix. मजदूरी बिल	1.9	1.9		
x. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.7	1.7		
xi. निवल ब्याज आय	5.8	5.7		

टिप्पणी: 1. 2020-21 और 2021-22 के लिए वित्तीय अनुपात की गणना केवल वर्तमान वर्ष की आस्तियों के आधार पर की जाती है।
2. 'मजदूरी विधेयक' को कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधानों के रूप में लिया जाता है।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

14. लघु वित्त बैंक

IV.117 छोटी कारोबारी इकाइयों, छोटे तथा सीमांत किसानों, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को आवश्यकता अनुरूप निर्मित जमा उत्पादों तथा प्रौद्योगिकी आधारित कम-लागत के परिचालनों के माध्यम से ऋण प्रदान करने हेतु वित्तीय समावेश को गति देने के लिए 2016 में लघु वित्त बैंकों की स्थापना की गई थी। मार्च 2022 के अंत में, पूरे देश में 5,677 देशी शाखाओं सहित बारह लघु वित्त बैंक परिचालन में थे, इनमें शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड तथा यूनिटी स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल थे जिन्हें वर्ष 2021-22 में लाइसेंसीकृत किया गया था।

14.1. तुलन पत्र

IV.118 वर्ष 2021-22 के दौरान, लघु वित्त बैंकों की समेकित तुलन पत्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समेकित तुलन पत्र की तुलना में अधिक तेज गति से वृद्धि हुई। जमा वृद्धि के साथ-साथ ऋणों तथा अग्रिमों की वृद्धिभी साल-दर-साल त्वरित हुई। संतुलन पर, लघु वित्त बैंकों का ऋण जमा अनुपात एक वर्ष पहले के 99 प्रतिशत से वर्ष 2021-22 में 93.2 प्रतिशत तक कम हो गया, यद्यपि यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अनुपात से उच्चतर रहा (सारणी IV.37)।

14.2 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार

IV.119 लगातार तीन वर्षों के दौरान गिरावट के बाद वर्ष 2021-22 के दौरान लघु वित्त बैंकों के कुल उधार में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। पिछले वर्ष में अंतराल के बाद, वर्ष 2022 में लघु वित्त बैंकों ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के 75 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में, एमएसएमई पर फोकस रहा, उसके बाद यह कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों पर रहा (सारणी IV.38)।

14.3 वित्तीय कार्य-निष्पादन

IV.120 वर्ष 2021-22 के दौरान, लघु वित्त बैंकों का निवल लाभ तथा परिचालन लाभ संकुचित हो गये। यह गिरावट उच्चतर परिचालन व्ययों तथा अशोध्य ऋणों के

सारणी IV.37: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन पत्र
(मार्च अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राशि		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में)
		2021	2022	2021-22
1		3	4	5
1	शेयर पूंजी	5,375.4	5,800.2	7.9
2	आरक्षित और अधिशेष	14,800.3	16,543.5	11.8
3	स्तर II बांड स्तर II ऋण	2,468.0	1,687.7	-31.6
4	जमा	1,09,472.5	1,45,730.5	33.1
	4.1 वर्तमान मांग जमा	3,964.2	5,770.0	45.6
	4.2 बचत	22,198.3	43,576.8	96.3
	4.3 मीयादी	83,310.0	96,383.7	15.7
5	उधार (स्तर II बांड सहित)	27,828.2	27,011.3	-2.9
	5.1 बैंक	1,366.4	4,303.7	215.0
	5.2 अन्य	26,461.8	22,707.6	-14.2
6	अन्य देयताएं और प्रावधान	6,076.3	7,990.8	31.5
	कुल देयताएं / आस्ति	**1,63,552.5**	**2,03,076.2**	**24.2**
7	उपलब्ध नकद	1,052.2	1,235.0	17.4
8	आरबीआई के पास शेष	5,869.2	7,490.1	27.6
9	अन्य बैंक शेष/वित्तीय संस्थाओं के पास शेष	12,309.1	10,212.3	-17.0
10	निवेश	30,659.8	41,661.5	35.9
11	ऋण और अग्रिम	1,08,612.6	1,35,802.4	25.0
12	अचल संपत्ति	1,676.3	2,001.0	19.4
13	अन्य आस्तयां	3,373.2	4,674.0	38.6

टिप्पणी: डेटा मार्च 2021 के अंत में 10 और मार्च 2022 के अंत में 12 अनुसूचित एसएफबी से संबंधित है।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

लिए प्रावधानीकरण के कारण आयी थी। लघु वित्त बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष के दौरान मामूली सुधार आया (सारणी IV.39)।

सारणी IV.38: लघु वित्त बैंकों द्वारा उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम
(मार्च के अंत में)

उद्देश्य	2021	2022
I प्राथमिकता (i से v)	**70.5**	**75.6**
i. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	22.8	26.1
ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	27.1	28.8
iii. शिक्षा	0.1	0.1
iv. आवास	4.5	5.5
v. अन्य	16.0	15.1
II गैर-प्राथमिकता (i से vi)	**29.5**	**24.4**
कुल (I+II)	**100.0**	**100.0**

टिप्पणी: कुल अग्रिमों में हिस्सा।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.39: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. मद	राशि		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में)
	2020-21	2021-22	2021-22
1 2	3	4	5
ए. आय (i + ii)	**22,499.9**	**25,060.0**	**11.4**
i ब्याज आय	19,523.4	22,120.4	13.3
ii अन्य आय	2,976.4	2,939.6	-1.2
बी. व्यय (i+ii+iii)	**20,462.2**	**24,086.5**	**17.7**
i खर्च किया गया ब्याज	9,122.2	9,512.6	4.3
ii परिचालन खर्च	7,549.0	9,815.9	30.0
जिनमें से स्टाफ खर्च	4,301.8	5,304.5	23.3
iii प्रावधान और आकस्मिकताएं	3,791.0	4,758.0	25.5
सी. लाभ (कर पूर्व)	**2,580.9**	**1,283.8**	**-50.3**
i परिचालन लाभ (ईबीपीटी)	5,828.7	5,731.5	-1.7
ii निवल लाभ (पीएटी)	2,037.7	973.5	-52.2
डी. कुल आस्तियां	**1,63,552.5**	**2,03,076.2**	**24.2**
ई. वित्तीय अनुपात#			
i परिचालन लाभ	3.6	2.8	
ii निवल लाभ	1.2	0.5	
iii आय (ए + बी)	13.8	12.3	
ए. ब्याज आय	11.9	10.9	
बी. अन्य आय	1.8	1.4	
iv व्यय (क+ख+ग)	12.5	11.9	
ए. खर्च किया गया ब्याज	5.6	4.7	
बी. परिचालन खर्च	4.6	4.8	
जिनमें से, कर्मचारी व्यय	2.6	2.6	
सी. प्रावधान और आकस्मिकताएं	2.3	2.3	
एफ. विश्लेषणात्मक अनुपात (%)			
सकल एनपीए अनुपात	5.4	4.9	
सीआरएआर	22.1	19.3	
कोर सीआरएआर	20.1	17.6	

टिप्पणी: #: कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

15. भुगतान बैंक

IV.121 भुगतान बैंकों की स्थापना प्रवासी श्रमिक, निम्न-आय वाले परिवारों, छोटे कारोबारों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र संस्थाओं के लिए छोटी बचतों की सुविधा देने तथा उनको भुगतान तथा धन-प्रेषण सेवाएँ देने के लिए प्रमुख संस्थाओं के रूप में की गई थी। मार्च 2022 के अंत में, छह भुगतान बैंक परिचालन में थे, जिनमें से तीन अपने परिचालनों में लाभप्रदता हासिल कर सके।

सारणी IV.40: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन पत्र

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	2020	2021	2022
1	कुल पूंजी और आरक्षित	1,868	1,761	2,494
2	जमाराशियां	2,306	4,625	7,854
3	अन्य देयताएं और प्रावधान	4,254	6,083	8,172
	कुल देयताएं / आस्तियां	**8,429**	**12,469**	**18,520**
1	नकद और आरबीआई के पास शेष	785	1,255	1,560
2	बैंकों और मुद्रा बाज़ार में शेष	2,101	2,393	3,322
3	निवेश	4,077	7,116	10,178
4	अचल संपत्ति	351	355	372
5	अन्य आस्तियां	1,115	1,350	3,088

टिप्पणी: डेटा छह से संबंधित है।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.41: भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	2019-20	2020-21	2021-22
ए.	**आय (i+ii)**			
	i. ब्याज आय	348	360	460
	ii. गैर-ब्याज आय	3,115	3,562	5,416
बी.	**व्यय**			
	i. ब्याज खर्च	62	100	157
	ii. परिचालन खर्च	4,324	4,584	5,826
	प्रावधान और आकस्मिकताएं	-96	36	24
	जिसमें से			
	जोखिम प्रावधान	3	9	17
	कर प्रावधान	-100	22	5
सी.	**निवल ब्याज आय**	286	260	303
डी.	**लाभ**			
	i. परिचालन लाभ (ईबीपीटी)	-923	-762	-107
	ii. निवल लाभ/ हानि	-827	-798	-130

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

15.1. तुलन पत्र

IV.122 अपने अधिदेश के अनुसार, भुगतान बैंकों का आस्ति पक्ष एसएलआर निवेशों तथा अन्य बैंकों के पास मांग तथा अल्प सूचना पर दी गई मुद्रा राशि पर केन्द्रित है। उनकी देयताओं में 42.4 प्रतिशत जमा शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश मांग पर हैं। मार्च 2022 अंत में, सभी भुगतान बैंकों ने 15 प्रतिशत की विनियामकीय न्यूनतम सीआरएआर का पालन किया है (सारणी IV.40)।

15.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.123 ब्याज और गैर-ब्याज आय दोनों में वृद्धि के बावजूद, पीबी ने 2021-22 में उच्च परिचालन व्यय के कारण हानि का सामना किया (सारणी IV.41)। भुगतान बैंक मुख्य रूप से छह आय माध्यमों से अपने राजस्व अर्जित करते हैं जो इस प्रकार हैं (i) ग्राहकों को विप्रेषण तथा नकद आहरण सेवाएं प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम से आय; (ii) अन्य बैंकों को बीसी सेवाएं देकर ; (iii) यूटिलिटी बिल भुगतानों पर लेन-देन प्रभार; (iv) नकद प्रबंधन/ वसूली सेवाएँ देकर ; (v) पीओएस टर्मिनलों के माध्यम से लेन-देन पर कमीशन तथा एमडीआर प्रभारों तथा अन्य छोटी लेन-देन द्वारा ; तथा (vi) पैरा-बैंकिंग गतिविधियों द्वारा। चूंकि भुगतान बैंकों पर उत्पाद के रूप में ऋण की पेशकश करने की रोक लगी है, उनका आय अर्जन कम हैं।

IV.124 हालांकि लागत-आय अनुपात द्वारा मापी जाने वाली दक्षता में लगातार चौथे वर्ष सुधार हुआ, लेकिन लाभदायक पीबी के लिए भी मार्जिन कम रहे थे। अन्य प्रदर्शन मैट्रिक्स, जैसे आरओए, आरओई, परिचालन लाभ- कार्यशील निधि अनुपात और लाभ मार्जिन वर्ष के दौरान ऋणात्मक रहे, लेकिन नुकसान की सीमा काफी कम हो गई (सारणी IV.42)।

15.3 आवक तथा जावक विप्रेषण

IV.125 पीबी की आय का एक बड़ा हिस्सा विप्रेषण परिचालन से आय के रूप में प्राप्त हो रहा था विशेष रूप से उन्हें जिनका नेटवर्क एवं पहुंच बहुत अच्छी थी। मार्च 2020 से जून 2022 तक केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों (आरटीजीएस और एनईएफटी) में पीबी के लेनदेन में लगभग 19 गुना की वृद्धि हुई, जबकि लेनदेन में शामिल राशि में भी 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई (चार्ट IV.48)।

IV.126 वर्ष 2021-22 में, पीबी के माध्यम से आवक और जावक विप्रेषण की मात्रा में क्रमश 76.3 प्रतिशत और 84.5 वृद्धि

सारणी IV.42: भुगतान बैंकों के चुनिंदा वित्तीय अनुपात

(मार्च के अंत में)

क्र. सं.	Item	2020	2021	2022
1	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-9.8	-6.4	-0.7
2	इक्विटी पर प्रतिलाभ	-44.3	-45.3	-5.2
3	कुल आस्तियों में निवेश	48.4	57.1	55.0
4	निवल ब्याज मार्जिन	4.8	2.8	2.3
5	दक्षता (लागत-आय अनुपात)	124.8	116.9	99.1
6	कार्यशील निधियों को परिचालनगत लाभ	-10.9	-6.1	-0.6
7	लाभ मार्जिन	-23.9	-20.3	-2.2

टिप्पणी: डेटा 6 पीबी से संबंधित है।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

हुई है और आवक और जावक विप्रेषण दोनों के मूल्य में पिछले वर्ष में मूल्य और मात्रा दोनों में दर्ज की गई 20 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। आवक और जावक विप्रेषण की संख्या में यूपीआई का शेयर सबसे अधिक था, और आवक प्रवाह के मूल्य में हिस्से के रूप में

चार्ट IV.48: पीबी की भुगतान प्रणाली लेनदेन

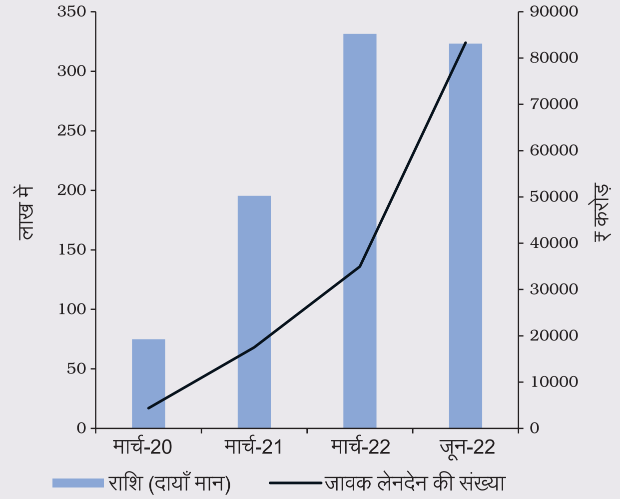

टिप्पणी: एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेन शामिल हैं।

स्रोत: एनईएफटी/आरटीजीएस में बैंक-वार मात्रा पर आरबीआई द्वारा जारी मासिक डेटा।

भी पहला स्थान इसी का था। तथापि, जावक विप्रेषण के मूल्य के संबंध में सबसे बड़ा हिस्सा आईएमपीएस का था (सारणी IV.3)।

सारणी IV.43: भुगतान बैंकों के माध्यम से विप्रेषण

(संख्या हज़ार में, राशि ₹ करोड़ में)

माध्यम	2020-21				2021-22			
	आवक विप्रेषण		जावक विप्रेषण		आवक विप्रेषण		जावक विप्रेषण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. एनईएफटी	13,893	26,295	8,259	60,649	37,036	37,999	7,238	64,610
	(0.9)	(9.8)	(0.5)	(19.8)	(1.3)	(6.7)	(0.2)	(7.1)
i) बिल भुगतान	94	17	233	28	472	82	391	34
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
ii) बिल भुगतान के अलावा अन्य	13,799	26,278	8,026	60,621	36,564	37,918	6,847	64,576
	(0.8)	(9.8)	(0.5)	(19.8)	(1.3)	(6.6)	(0.2)	(7.1)
2. आरटीजीएस	190	56,460	17	35,107	382	1,28,030	41	1,00,370
	(0.0)	(21.0)	(0.0)	(11.4)	(0.0)	(22.4)	(0.0)	(11.1)
3. आईएमपीएस	1,36,274	37,466	1,89,879	65,866	1,95,781	60,838	1,99,386	4,01,203
	(8.3)	(14.0)	(11.1)	(21.5)	(6.8)	(10.7)	(6.3)	(44.3)
4. यूपीआई	11,72,699	1,13,289	12,00,688	1,03,908	21,70,638	2,68,887	25,10,470	2,65,610
	(71.8)	(42.2)	(70.3)	(33.9)	(75.4)	(47.1)	(79.7)	(29.3)
5. ई – वॉलेट	2,31,624	20,406	3,01,499	38,317	2,61,540	33,202	3,85,949	66,899
	(14.2)	(7.6)	(17.7)	(12.5)	(9.1)	(5.8)	(12.2)	(7.4)
6. माइक्रो एटीएम (पीओएस)	32	20	144	45	1,361	499	57	27
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.1)	(0.0)	(0.0)
7. एटीएम	-	-	9	3	-	-	24	9
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
8. अन्य	78,208	14,384	7,185	2,866	2,12,792	41,322	48,237	7,266
	(4.8)	(5.4)	(0.4)	(0.9)	(7.4)	(7.2)	(1.5)	(0.8)
कुल	**16,32,920**	**2,68,321**	**17,07,680**	**3,06,761**	**28,79,529**	**5,70,777**	**31,51,403**	**9,05,994**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
2. डेटा 6 पीबी से संबंधित है।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

16. समग्र मूल्यांकन

IV.127 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने महामारी का बखूबी सामना किया और अधिक आघात-सहनीय और सुदृढ़ क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। समय पर प्रदत नीतिगत सहायता के कारण बैंकों ने बेहतर लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता, पूंजी बफर रिपोर्ट किया है। हाल ही में, बैंकों के तुलन-पत्रों में अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों के अधिक प्रवाह के साथ व्यापक ऋण वृद्धि सहित अच्छी तेजी दिखाई दी है। सरकार द्वारा ईसीएलजीएस के अंतर्गत गारंटी कवर से एमएसएमई को क्रेडिट को बढ़ावा मिला है।

IV.128. आगे यह अनिवार्य है कि बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए उचित सावधानी और सख्त क्रेडिट मूल्यांकन सुनिश्चित करें। वर्ष 2022-23 के दौरान विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बीच तेजी से बदलते समष्टि गत परिदृश्य में अनिश्चितताएं बैंकिंग क्षेत्र के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। यदि नकारात्मक जोखिमों का सामना करना पड़ता है तो आस्ति गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए, पुनर्निर्मित आस्तियों में गिरावट की सतत निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। आस्तियों के मूल्य में कमी को रोकने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों का समय पर समाधान अनिवार्य है।

IV.129 जीएएम त्रयी द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप जनसंख्या के बैंकिंग सेवा रहित और वंचित वर्ग तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में वृद्धि हुई है। यूपीआई की सफलता और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने के कारण विभिन्न चिंताएं जैसे कि तृतीय पक्षों के अनियंत्रित हस्तक्षेप, मिससेलिंग, आंकड़ों की निजता के उल्लंघन, अनुचित कारोबारी व्यवहार, अत्यधिक ब्याज दरों और वसूली के अनैतिक तरीके आदि सामने आई हैं। बैंकों को इन चुनौतियों को पार पाने के लिए उचित कारोबारी रणनीति तैयार करने, अपने अभिशासन फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने और साइबर सुरक्षा लागू करने जैसे कदम उठाने होंगे।

V सहकारी बैंकिंग घटनाक्रम

वर्ष 2021-22 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ, जिसमें पूंजीगत बफ़र्स में वृद्धि, सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में गिरावट और बेहतर लाभप्रदता संकेतक शामिल हैं। अल्पावधि सहकारी समितियों में, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) दोनों के तुलन-पत्रों में, पिछले वर्ष की मंदी के बाद, वर्ष 2020-21 में तेजी आई। यह उल्लेखनीय है कि डीसीसीबी की लाभप्रदता में सुधार हुआ।

1. भूमिका

V.1 सहकारी बैंक अंतिम छोर तक ऋण उपलब्ध कराने वाले मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देते हैं। तथापि, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जो स्वामित्व संरचना, त्रुटिपूर्ण कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं तथा जालसाजी की बढ़ती घटनाओं, साथ ही रिज़र्व बैंक एवं सरकार के दोहरे विनियमन से पैदा होने वाले मुद्दों के कारण उठ खड़ी हुई थीं। अतिरिक्त पूँजी की उगाही शेयरहोल्डिंग पैटर्नों और सांविधिक प्रावधानों के कारण बाधित होती है। कानूनी बाधाओं और अटपटे कारकों के कारण उनका त्वरित समाधान बाधित होता है।

V.2 कई वर्षों से, रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकिंग संरचना को मजबूत करने के लिए सुधार लाने के प्रयास कर रहा है। इसकी द्विआयामी रणनीति में वैधानिक सुधार और विनियामकीय समर्थन शामिल हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 2020 में संशोधन ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की पूँजी जुटाने की बाधाओं को कम कर दिया है। रिज़र्व बैंक को यूसीबी के पुनर्गठन या समामेलन का अधिकार दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने 19 जुलाई, 2022 को यूसीबी को नियंत्रित करने वाले विनियामकीय फ्रेमवर्क को भी संशोधित किया है। इस फ्रेमवर्क का मार्गदर्शन करने वाली दृष्टि यह है कि ग्राहक आधार में विविधता को पोषित करके मित्रवत पड़ोसी बैंकों के रूप में यूसीबी की स्थिति सुदृढ़ की जाए और क्रेडिट मध्यस्थता में योगदान को बढ़ाने के लिए मजबूत यूसीबी को परिचालन में और ज्यादा लचीलापन प्रदान किया जाए।

V.3 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय समीक्षाधीन अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रदर्शन पर केंद्रित है। खंड 2 में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना और उसके विनियमन का उल्लेख किया गया है। खंड 3 में लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूँजी पर्याप्तता के मामले में यूसीबी की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया गया है। खंड 4 में अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों और दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों के वित्तीय प्रदर्शन की पड़ताल की गयी है। खंड 5[1] में समग्र मूल्यांकन किया गया है।

2. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना

V.4 भारत में सहकारी बैंकिंग संरचना को वाणिज्यिक बैंकिंग संरचना के पूरक और अनुपूरक के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया था, जिसमें सीमांत उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। यूसीबी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,

[1] हालांकि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) और दीर्घकालिक सहकारी समितियां रिज़र्व बैंक के विनियामकीय दायरे से बाहर हैं, तथापि विश्लेषण की पूर्णता के लिए डेटा और उनकी गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में शामिल किया गया है।

चार्ट V.1: सहकारी बैंकों की संरचना

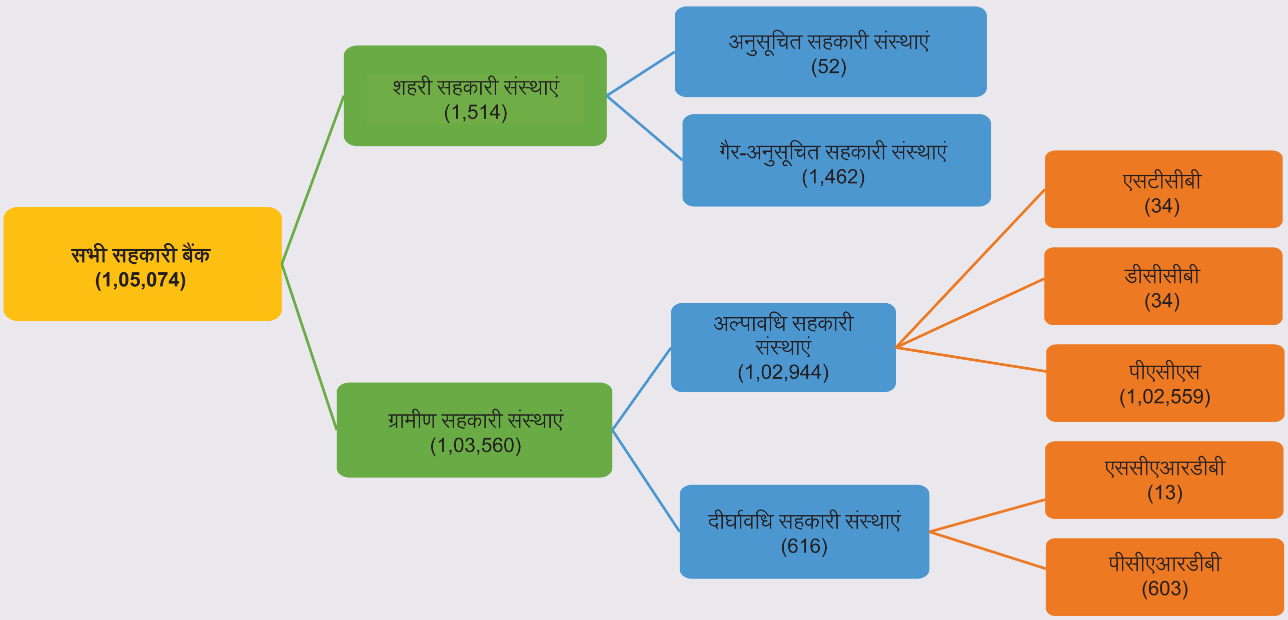

टिप्पणियां: 1. एसटीसीबी- राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी- राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2022 के अंत में यूसीबी को एवं मार्च 2021 के अंत में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को दर्शाते हैं।
3. तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंक लि. के अतिरिक्त डीसीसीबी।

स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

1934[2] की दूसरी अनुसूची में शामिल होने या नहीं होने, और उनकी भौगोलिक पहुंच (एकल-राज्य या बहु-राज्य) के आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सहकारी समितियों को उनकी गतिविधियों- अर्थात दीर्घावधि ऋण देने तथा अल्पावधि ऋण देने के आधार पर अलग किया जाता है। मार्च 2022 के अंत तक, इस क्षेत्र में 1,514 यूसीबी और 103,560 ग्रामीण सहकारी समितियाँ[3] शामिल थीं (चार्ट V.1)।

V.5 बैंकों की संख्या के साथ-साथ आस्ति-आकार के मामले में, अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों का इस क्षेत्र पर प्रभुत्व है (चार्ट V.2)।

V.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), ग्रामीण सहकारी समितियों और शहरी सहकारी समितियों के बीच

चार्ट V.2: आस्ति के आकार के अनुसार सहकारी बैंकों का विभाजन
(मार्च 2021 के अंत में)

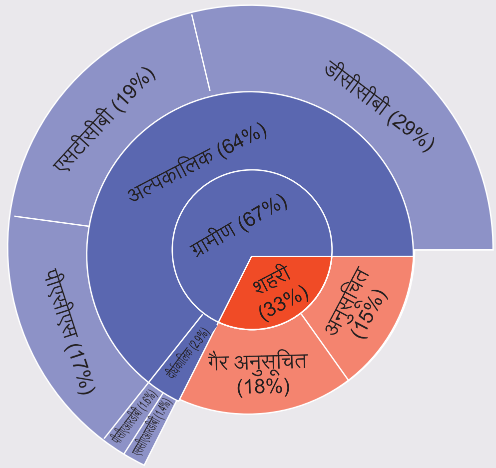

टिप्पणी: सनबर्स्ट चार्ट सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में स्तर को दर्शाता है। प्रत्येक चार्ट खंड का आकार क्षेत्र की कुल आस्तियों में इसकी हिस्सेदारी (कोष्ठक में वर्णित) के अनुपात में है।
स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

[2] अनुसूचित सहकारी बैंकों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी अधिनियम की एक ही अनुसूची में शामिल हैं।
[3] ग्रामीण सहकारी समितियों के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल के साथ उपलब्ध हैं, यानी वे वर्ष 2020-21 से संबंधित हैं।

सारणी V.1 कृषि के लिए ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक
1	2	3	4
2015-16	16.7	13.0	70.2
2016-17	13.4	11.6	75.0
2017-18	12.9	12.1	74.9
2018-19	12.1	11.9	76.0
2019-20	11.3	11.9	76.8
2020-21	12.1	12.1	75.8
2021-22	13.0	11.0	76.0

स्रोत: नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

का अंतर तेजी से समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि ये सभी, ग्राहकों के एक ही समूह को सेवा देने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यहां तक कि राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) जैसी अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियां, आवास और शिक्षा के लिए दीर्घकालिक ऋण देकर अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला रही हैं। परंपरागत ईंट-और-गारे वाले मॉडल के अलावा, एससीबी कारोबार प्रतिनिधियों पर भरोसा करते रहे हैं और अंतिम छोर तक न पहुँच पाने की समस्या को हल करने के लिए फिनटेक के लाभों का उपयोग कर रहे हैं। भीतरी इलाकों में वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती पैठ से सहकारी समितियों का सापेक्षिक आकार और प्रभाव कम होता जा रहा है। मार्च 2021 के अंत तक, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सकल तुलन पत्र का आकार ₹20 लाख करोड़ के साथ एससीबी के समेकित तुलन पत्र का 10.3 प्रतिशत था, जो मार्च 2005 के अंत में रहे 19.4 प्रतिशत से कम था।

V.7 हालांकि ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना कृषि क्षेत्र को ऋण देने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन इस क्षेत्र को कुल ऋण देने में उनकी हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक घटी, लेकिन उसके बाद इसमें मामूली सुधार हुआ है (सारणी V.1)।

3. शहरी सहकारी बैंक

V.8 1990 के दशक में अपनाई गई उदार लाइसेंसिंग नीति के कारण यूसीबी की संख्या में वृद्धि हुई। वर्षों से वित्तीय कमजोरियों के साथ-साथ उनकी संरचनाओं में निहित दुर्बलता के परिणामस्वरूप नए लाइसेंस प्राप्त यूसीबी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रुग्ण हो गया है। वर्ष 2004-05 के बाद से, रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें अव्यवहार्य यूसीबी का उनके व्यवहार्य समकक्षों के साथ समामेलन, अव्यवहार्य संस्थाओं को बंद करना और नए लाइसेंस जारी नहीं करना शामिल है। परिणामस्वरूप, यूसीबी की संख्या उत्तरोत्तर घटती गई (चार्ट V.3)।

चार्ट V.3: यूसीबी की संख्या

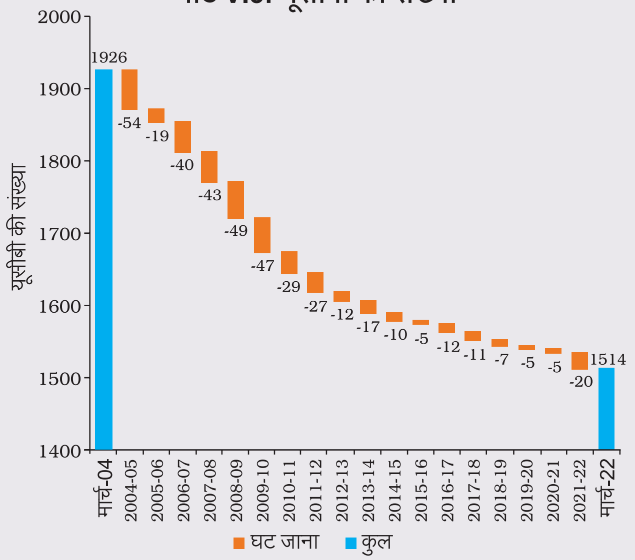

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.9 2021-22 के दौरान नौ गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय रूप से मजबूत बैंकों के साथ स्वैच्छिक विलय कर दिया गया। वर्ष 2004-05 के बाद से, इस क्षेत्र में 145 विलय किए गए हैं, जिनमें से सर्वाधिक विलय महाराष्ट्र में हुए हैं, और इसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश में हुए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, 10 यूसीबी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिससे वर्ष 2015-16 से यह संख्या बढ़कर 54 हो गई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (एसयूसीबी) से संबंधित एक समामेलन को छोड़कर, अन्य विलय और लाइसेंस निरस्तीकरण गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी) से संबंधित थे, जिससे वर्ष 2020-21 में रही उनकी संख्या 1,481 से गिरकर वर्ष 2021-22 में 1,462 हो गई (चार्ट V.4)।

चार्ट V.4: यूसीबी में समेकन अभियान

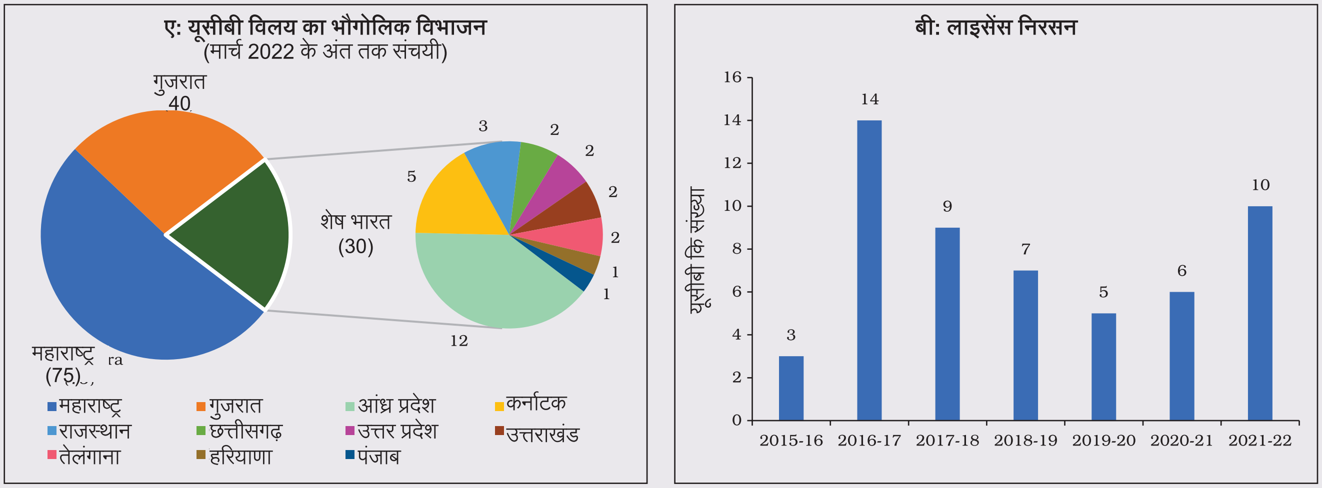

स्रोत: आरबीआई।

V.10 मुख्यत: जमा आकार के आधार पर, शहरी सहकारी बैंकों को टियर I और टियर II श्रेणियों[4,5] में विभाजित किया गया है। टीयर II बैंक इस सेगमेंट में प्रमुख खिलाड़ी बने हुए हैं और उनकी कुल आस्ति वर्ष 2016-17 में रहे 86.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 93.3 प्रतिशत हो गई है, हालांकि इसमें वर्ष 2021-22 में मामूली गिरावट आयी (सारणी V.2)। इसके बावजूद, टियर II यूसीबी का आस्ति-आकार, औसतन, उनके टियर I समकक्षों की तुलना में 13 गुना बड़ा है। उनका ऋण-आकार भी लगभग 14 गुना बड़ा है।

3.1 तुलन-पत्र

V.11 2004-05 से यूसीबी क्षेत्र के समेकन के परिणामस्वरूप शुरू में बड़े लाभ हुए। इस अभियान के बाद के दशक के दौरान उनके संयुक्त तुलन पत्र का आकार 11.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा, जबकि एससीबी के लिए यह 15.9 प्रतिशत था। तथापि, बाद में, दोनों खंडों की तुलन पत्र वृद्धि में नरमी आई; जहां एक ओर वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 के दौरान यूसीबी 4.8 प्रतिशत की सीएजीआर से

सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों का टीयर-वार वितरण
(मार्च 2022 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

टीयर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमाराशि		अग्रिम		कुल आस्तियां	
	संख्या	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
टीयर I	813	53.7	40,019	7.6	23,174	7.4	53,551	8.0
टीयर II	701	46.3	4,86,001	92.4	2,91,566	92.6	6,12,935	92.0
सभी यूसीबी	**1,514**	**100.0**	**5,26,021**	**100.0**	**3,14,741**	**100.0**	**6,66,486**	**100.0**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

4 (ए) टीयर I यूसीबी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: i) एक ही जिले में परिचालन कर रहे और ₹100 करोड़ से कम जमा वाले बैंक ii) एक से अधिक जिलों में परिचालन कर रहे लेकिन ₹100 करोड़ से कम जमा वाले बैंक को भी टीयर I माना जाएगा, बशर्ते निकटवर्ती जिलों में उसकी शाखाएं हों और एक जिले में शाखाओं की जमा और अग्रिम अलग से बैंक की कुल जमा और अग्रिम का कम से कम 95 प्रतिशत हिस्सा हो, और iii) ₹100 करोड़ से कम जमा वाले बैंक, जिनकी शाखाएँ मूल रूप से एक ही जिले में थीं लेकिन बाद में, जिले के पुनर्गठन के कारण ये बहु-जिला वाले बन गए, उन्हें भी टीयर I यूसीबी के रूप में माना जा सकता है।

(बी) अन्य सभी यूसीबी को टियर II यूसीबी के रूप में परिभाषित किया गया है।

5 जुलाई 2022 में, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए चार स्तरीय संरचना को अपनाने की घोषणा की।

बढ़ी, वहीं दूसरी ओर एससीबी में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट V.5)। इस अवधि के दौरान चक्रीय मंदी के अलावा, तुलन पत्र वृद्धि में इस गिरावट का श्रेय फिनटेक, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे अन्य योग्य खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा को दिया जा सकता है।

V.12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र में तेजी के विपरीत, वर्ष 2021-22 के दौरान, मुख्य रूप से एसयूसीबी के तुलन पत्र में संकुचन के कारण, शहरी सहकारी बैंकों के आस्ति-आकार में कमी आई (सारणी V.3)।

V.13 लगभग दो दशकों में पहली बार वर्ष 2021-22 के दौरान जमाराशियों में कमी आई, जिससे शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में गिरावट आई। वर्ष 2020-21 का उच्च आधार महामारी से प्रेरित एहतियात के तौर पर की गयी जमाराशियों

चार्ट V.5: आस्ति वृद्धि

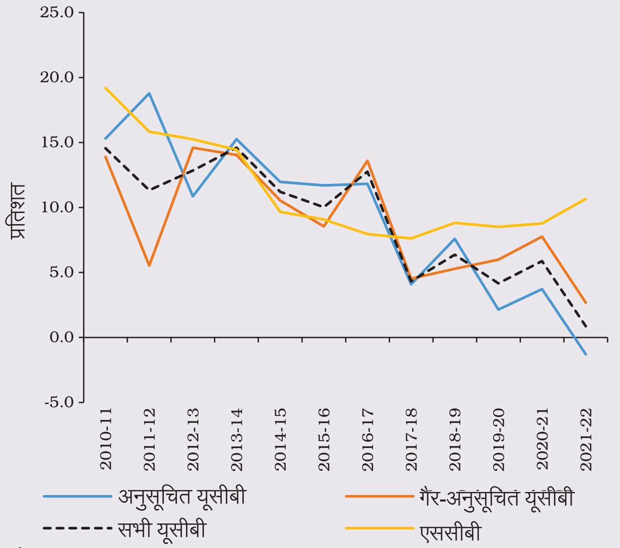

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		वृद्धि दर (%) सभी यूसीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएं								
1) पूंजी	4,467	4,193	9,844	10,065	14,311	14,258	1.4	-0.4
	(1.5)	(1.4)	(2.7)	(2.7)	(2.2)	(2.1)		
2) आरक्षित निधियां और अधिशेष	15,536	19,405	22,848	22,947	38,384	42,352	15.2	10.3
	(5.1)	(6.5)	(6.4)	(6.2)	(5.8)	(6.4)		
3) जमाराशियां	2,39,579	2,34,080	2,89,650	2,91,940	5,29,229	5,26,021	5.7	-0.6
	(79.4)	(78.6)	(80.7)	(79.2)	(80.1)	(78.9)		
4) उधारियां	4,755	5,418	333	242	5,089	5,660	-4.7	11.2
	(1.6)	(1.8)	(0.1)	(0.1)	(0.8)	(0.8)		
5) अन्य देयताएं और प्रावधान	37,455	34,810	36,280	43,385	73,736	78,196	4.6	6.0
	(12.4)	(11.7)	(10.1)	(11.8)	(11.2)	(11.7)		
आस्तियां								
1) उपलब्ध नकदी	1,676	1,855	4,230	4,426	5,906	6,281	1.2	6.3
	(0.6)	(0.6)	(1.2)	(1.2)	(0.9)	(0.9)		
2) आरबीआई में शेष जमाराशि	11,131	12,404	3,382	4,039	14,514	16,443	15.2	13.3
	(3.7)	(4.2)	(0.9)	(1.1)	(2.2)	(2.5)		
3) बैंकों में शेष जमाराशि	21,888	23,176	48,189	47,330	70,077	70,506	5.8	0.6
	(7.3)	(7.8)	(13.4)	(12.8)	(10.6)	(10.6)		
4) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय जमाराशि	5,087	3,505	1,910	1,488	6,998	4,993	-16.6	-28.6
	(1.7)	(1.2)	(0.5)	(0.4)	(1.1)	(0.7)		
5) निवेश	80,297	81,128	1,00,728	1,06,574	1,81,025	1,87,702	12.1	3.7
	(26.6)	(27.2)	(28.1)	(28.9)	(27.4)	(28.2)		
6) ऋण और अग्रिम	1,43,175	1,42,627	1,70,786	1,72,114	3,13,961	3,14,741	2.8	0.2
	(47.4)	(47.9)	(47.6)	(46.7)	(47.5)	(47.2)		
7) अन्य आस्तियां	38,538	33,211	29,729	32,608	68,267	65,819	6.3	-3.6
	(12.8)	(11.1)	(8.3)	(8.8)	(10.3)	(9.9)		
कुल देयताएं/ आस्तियां	3,01,793	2,97,906	3,58,955	3,68,580	6,60,748	6,66,486	5.9	0.9
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		

टिप्पणियां: 1. मार्च 2022 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियां (प्रतिशत में) के अनुपात में है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.6: जमाराशि एवं अग्रिम: यूसीबी

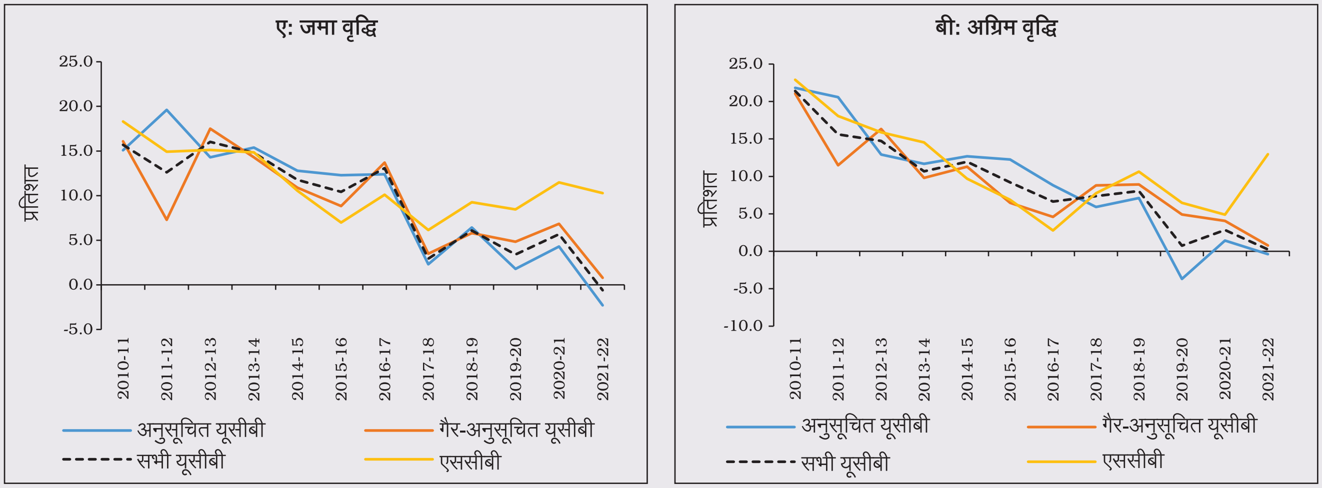

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

को दर्शाता है, जो वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य हो गया। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिम तथा निवेश दोनों में गिरावट आई (चार्ट V.6)।

V.14 एससीबी की तुलना में, यूसीबी, और विशेष रूप से एनएसयूसीबी का ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात, जमा पर अधिक निर्भरता और कम ऋण वितरण के कारण हमेशा काफी कम रहा है। हालांकि, लगातार तीन वर्षों तक गिरावट के बाद, यूसीबी का सी-डी अनुपात वर्ष 2021-22 में बढ़ गया। यह मुख्य रूप से एसयूसीबी की जमाराशियों में संकुचन के कारण था (चार्ट V.7)।

V.15 समेकन अभियान शुरू किए जाने से पहले, यूसीबी की संख्या के संदर्भ में, आस्ति-आकार दो मॉडल वाला था: ₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ और ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़। हालांकि, तब से वितरण दायीं दिशा में स्थानांतरित हो गया है, जो उच्चतर स्तर पर आस्ति संकेंद्रण का संकेत देता है (चार्ट V.8)।

चार्ट V.7: ऋण-जमा अनुपात: यूसीबी बनाम एससीबी

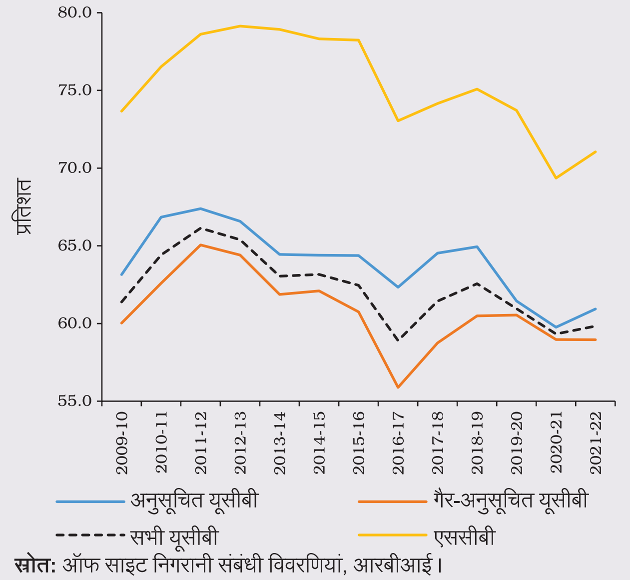

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.8: आस्ति के आकार के अनुसार यूसीबी का विभाजन

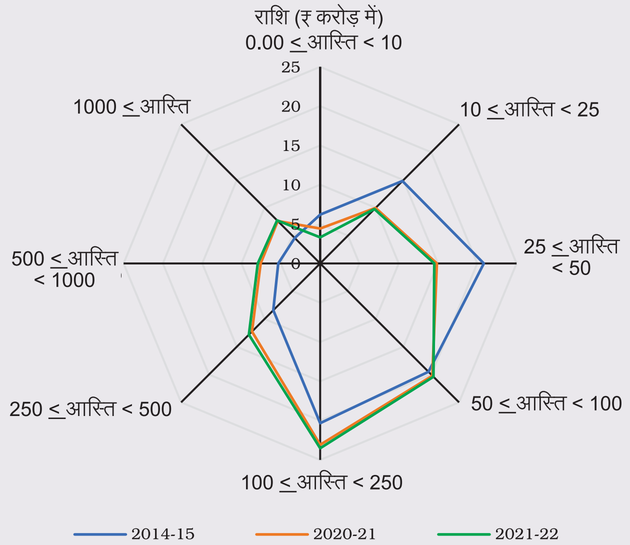

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.9: यूसीबी की जमाराशियां और अग्रिम का वितरण
(मार्च अंत तक)

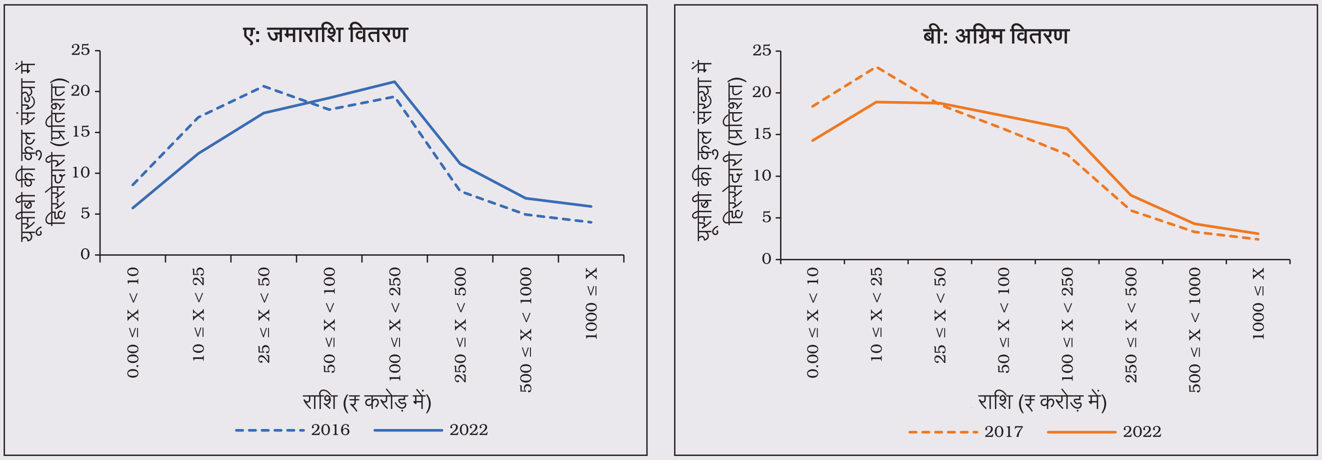

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.16 शहरी सहकारी बैंकों की संख्या के संदर्भ में, वर्ष 2015-16 में जमाराशियों का मॉडल वर्ग ₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ था। पिछले कुछ वर्षों में यह मार्च 2022 के अंत में ₹100 करोड़ से ऊपर उठते हुए, ₹250 करोड़ तक पहुंच गया है (चार्ट V.9ए)।

V.17 अग्रिमों के मामले में, वर्ष 2016-17 में मॉडल वर्ग ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ था, जो ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ और ₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ वाले वर्गों में मार्च 2022 के अंत में उच्चतम शेयर दर्ज करते हुए, द्विमॉडल बन गया है। (सारणी V.4 और चार्ट V.9बी)।

सारणी V.4: जमाराशियों और अग्रिमों के आकार के अनुसार यूसीबी का विभाजन
(31 मार्च 2022 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

जमाराशियां	यूसीबी की संख्या		कुल जमाराशि		अग्रिम	यूसीबी की संख्या		कुल जमाराशि	
	संख्या	% हिस्सेदारी	संख्या	% हिस्सेदारी		संख्या	% हिस्सेदारी	संख्या	% हिस्सेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00 ≤ ज < 10	87	5.7	532	0.1	0.00 ≤ अ < 10	216	14.3	1,241	0.4
10 ≤ ज < 25	188	12.4	3,257	0.6	10 ≤ अ < 25	286	18.9	4,895	1.6
25 ≤ ज < 50	263	17.4	9,793	1.9	25 ≤ अ < 50	284	18.8	10,081	3.2
50 ≤ ज < 100	291	19.2	20,799	4.0	50 ≤ अ < 100	261	17.2	18,892	6.0
100 ≤ ज < 250	321	21.2	51,128	9.7	100 ≤ अ < 250	238	15.7	37,807	12.0
250 ≤ ज < 500	169	11.2	59,480	11.3	250 ≤ अ < 500	117	7.7	40,226	12.8
500 ≤ ज < 1000	105	6.9	72,351	13.8	500 ≤ अ < 1000	65	4.3	44,863	14.3
1000 ≤ ज	90	5.9	3,08,681	58.7	1000 ≤ अ	47	3.1	1,56,736	49.8
कुल	**1,514**	**100.0**	**5,26,021**	**100.0**	**कुल**	**1,514**	**100.0**	**3,14,741**	**100.0**

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. "ज" और "अ" क्रमशः जमाराशि और अग्रिम की राशि को दर्शाते हैं।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	बकाया राशि (मार्च अंत में)			घट-बढ़ (%)	
	2020	2021	2022	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
कुल निवेश (ए+बी)	**1,61,696**	**1,81,025**	**1,87,702**	**12.0**	**3.7**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**		
ए. एसएलआर निवेश (i से iii)	**1,42,093**	**1,61,477**	**1,67,893**	**13.6**	**4.0**
	(87.9)	**(89.2)**	**(89.4)**		
i. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	96,471	1,02,033	1,04,728	5.8	2.6
	(59.7)	(56.4)	(55.8)		
II. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	44,428	58,951	62,643	32.7	6.3
	(27.5)	(32.6)	(33.4)		
III. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,194	492	522	-58.7	6.0
	(0.7)	(0.3)	(0.3)		
बी. एसएलआर से इतर निवेश	**19,603**	**19,549**	**19,809**	**-0.3**	**1.3**
	(12.1)	**(10.8)**	**(10.6)**		

टिप्पणियां: 1. वर्ष 2022 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल निवेश के अनुपात (प्रतिशत में) को दर्शाते हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.18 यूसीबी की तुलना में, एसयूसीबी के निवेश में तीव्र कमी उनके जमा आधार में संकुचन को दर्शाती है (सारणी V.5 और चार्ट V.10)।

चार्ट V.10: यूसीबी के निवेश

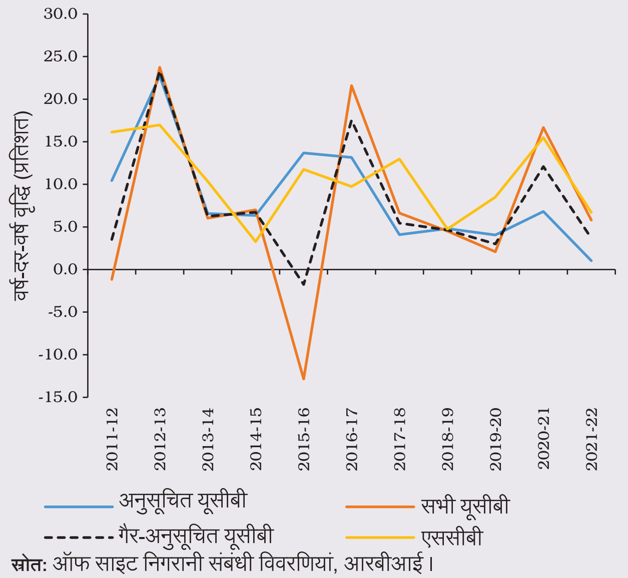

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

3.2 सुदृढ़ता

V.19 वर्ष 2021-22 के दौरान यूसीबी पर जुर्माना लगाने के दृष्टांत विगत वर्ष के 43 से बढ़कर 145 हो गए। तदनुसार, जुर्माने की राशि में पिछले वर्ष की गिरावट की तुलना में 211 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.15 देखें)। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाए गए दावे पूरी तरह से सहकारी बैंकों से संबंधित थे और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में आठ गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। यह आंशिक रूप से डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 में संशोधन को दर्शाता है, जिसने जमाकर्ताओं के बीमाकृत राशि के समयबद्ध संवितरण की सुविधा प्रदान की (पैरा IV.86 देखें)।

V.20 सीएएमईएलएस-आधारित रेटिंग प्रणाली[6] को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत यूसीबी को ए/बी+/बी/सी/डी (प्रदर्शन के घटते क्रम में) की रेटिंग दी गई है। मार्च 2022 के अंत में, 'बी' श्रेणी संख्या-वार और कारोबार (जमा और अग्रिम का योग) के अनुसार मॉडल वर्ग में थी। हालांकि,

[6] सीएएमईएलएस (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और सिस्टम एवं नियंत्रण) रेटिंग मॉडल में इसका वर्तमान स्वरूप अप्रैल 2008 में यूसीबी पर लागू हो गया।

सारणी V.6: यूसीबी का रेटिंग-वार वितरण

(मार्च 2022 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

रेटिंग	संख्या		जमाराशियां		अग्रिम	
	बैंक	कुल में % हिस्सेदारी	राशि	कुल में % हिस्सेदारी	राशि	कुल में % हिस्सेदारी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ए	153	10.1	30,240	5.7	17,190	5.5
बी+	203	13.4	83,152	15.8	49,642	15.8
बी	740	48.9	2,50,292	47.6	1,52,571	48.5
सी	345	22.8	1,48,925	28.3	85,794	27.3
डी	73	4.8	13,411	2.5	9,545	3.0
कुल	1,514	100.0	5,26,021	100.0	3,14,741	100.0

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. रेटिंग, ऑफसाइट रिटर्न में रिपोर्ट किए गए और यूसीबी से संग्रहित किए गए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।
4. प्रतिशत अंतर में थोड़ी भिन्नता हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का करोड़ रुपये में पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

पिछले वर्ष की तुलना में, कुल में इसकी हिस्सेदारी घट गई (सारणी V.6)। इन वर्षों में, कुल कारोबार में वितरण 'सी' श्रेणी की ओर अग्रसर होकर दाईं ओर स्थानांतरित हो गई है (चार्ट V.11)।

सारणी V.7: यूसीबी का सीआरएआर-वार वितरण

(मार्च 2022 के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर-अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	4	58	62
3 <= सीआरएआर < 6	0	12	12
6 <= सीआरएआर < 9	0	16	16
9 <= सीआरएआर < 12	7	115	122
12 <= सीआरएआर	41	1,261	1,302
कुल	**52**	**1,462**	**1,514**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

3.3 पूँजी पर्याप्तता

V.21 मार्च 2022 के अंत में 94 प्रतिशत यूसीबी ने जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूँजी को 9 प्रतिशत के विनियामकीय न्यूनतम से ऊपर बनाए रखा (सारणी V.7)। पिछले दशक में यूसीबी के पूँजी बफर में सुधार हुआ है और विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ बैंक असफल हुए हैं (चार्ट V.12)।

चार्ट V.11: शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और कारोबार का वितरण - रेटिंग के आधार पर (मार्च अंत तक)

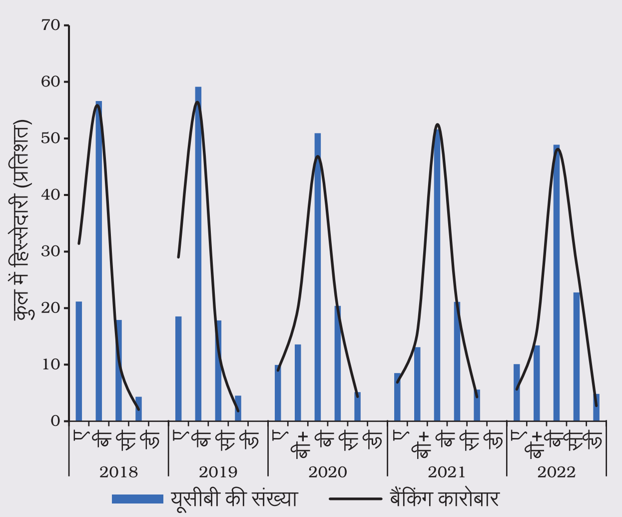

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.12: 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले यूसीबी की हिस्सेदारी

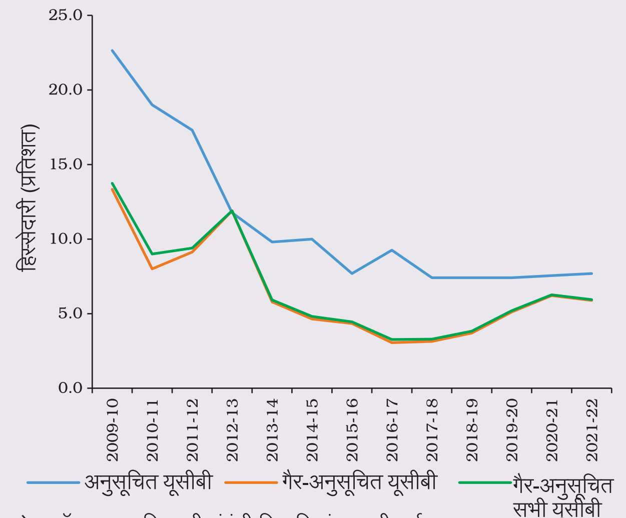

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.8: यूसीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

		अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	पूंजीगत निधियां	**13,520**	**20,955**	**25,543**	**27,916**	**39,063**	**48,871**
	i) टीयर I पूंजी	7,758	15,019	22,010	24,006	29,768	39,025
	ii) टीयर ii पूंजी	5,762	5,935	3,533	3,910	9,295	9,845
2	जोखिम भारित आस्तियां	**1,45,352**	**1,46,925**	**1,67,243**	**1,65,940**	**3,12,594**	**3,12,865**
3	सीआरएआर (2 के % के रूप में क्र. सं. 1)	**9.3**	**14.3**	**15.3**	**16.8**	**12.5**	**15.6**
	जिसमें से:						
	टीयर I	5.3	10.2	13.2	14.5	9.5	12.5
	टीयर II	4.0	4.0	2.1	2.4	3.0	3.1

टिप्पणी: वर्ष 2022 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.22 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान एसयूसीबी ने टिअर I पूँजी में वृद्धि के साथ, अपनी पूँजीगत स्थितियों में काफी सुधार किया। हालांकि यूसीबी क्षेत्र का सीआरएआर अभी भी एससीबी से कम है, फिर भी यह क्षेत्र टियर II से IV बैंकों[7] के लिए उच्च सीआरएआर की संशोधित विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है (सारणी V.8)।

3.4 आस्ति गुणवत्ता

V.23 सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात द्वारा मापी गई यूसीबी की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 के दौरान लगातार गिरावट आई, लेकिन वर्ष 2021-22 में सकल अनर्जक आस्तियों की राशि में गिरावट आने से वर्ष 2012-13 के बाद पहली बार इसमें सुधार हुआ। एसयूसीबी और एनएसयूसीबी दोनों के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को भी कम कर दिया गया है। हालांकि यूसीबी ने सावधानी दिखाई और उनके प्रावधान कवरेज अनुपात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई, लेकिन यह अभी भी एससीबी की तुलना में नीचे ही है (सारणी V.9)।

V.24 मार्च 2022 के अंत में यूसीबी के कुल निधिक ऋणों का 26 प्रतिशत और उनके एनपीए का 32 प्रतिशत उन बड़े उधार खातों से उत्पन्न हुआ जिनका ₹5 करोड़ और उससे अधिक

सारणी V.9: यूसीबी की अनर्जक आस्तियां
(मार्च अंत में)

क्र. सं	मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सकल एनपीए (₹ करोड़)	15,047	10,678	22,950	19,794	37,996	30,473
2	सकल एनपीए अनुपात (%)	10.5	7.5	13.4	11.6	12.1	9.7
3	निवल एनपीए (₹ करोड़)	5,746	4,116	11,037	8,798	16,783	12,914
4	निवल एनपीए अनुपात (%)	4.3	3.0	7.0	5.6	5.8	4.4
5	प्रावधानीकरण (₹ करोड़)	9,537	6,983	12,848	12,179	22,385	19,162
6	प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (%)	63.4	65.4	56.0	61.5	58.9	62.9

टिप्पणियां: वर्ष 2021-22 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

[7] रिज़र्व बैंक ने 19 जुलाई 2022 को यूसीबी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचे की घोषणा की। तदनुसार, सभी यूसीबी के लिए सीआरएआर - टीयर-1 यूसीबी को छोड़कर - को 9 प्रतिशत से संशोधित कर 12 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि अधिकांश बैंक पहले से ही इस मानदंड को पूरा करते हैं एवं जिन बैंकों के पास वर्तमान में पर्याप्त पूँजी बफर नहीं है उनके लिए मार्च 2026 के अंत तक निर्धारित किया गया है।

का एक्सपोजर था। इन उधारकर्ताओं के लिए एनएसयूसीबी का एक्सपोजर मार्च 2022 के अंत में उनके कुल ऋण का 10 प्रतिशत से कम था जबकि एसयूसीबी का एक्सपोजर 47 प्रतिशत था। बड़े उधार खातों से निकलने वाले यूसीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई, जो मुख्यत: एसयूसीबी में गिरावट के कारण थी। हालांकि, एनएसयूसीबी के मामले में यह अनुपात उच्च बना हुआ है और हाल ही में इसमें और भी गिरावट आई है (चार्ट V.13)।

3.5 वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता

V.25 कम ब्याज दर व्यवस्था में कमज़ोर ऋण वृद्धि ने वर्ष 2021-22 में यूसीबी की ब्याज आय को कम किया। हालांकि, ब्याज व्यय में संकुचन और भी तेज था जिससे उनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ। कर्ज में डूबे और दबावग्रस्त एसयूसीबी के लघु वित्त बैंक के साथ समामेलन से भी लाभप्रदता में सुधार लाने में मदद मिली। दूसरी ओर, विशेष रूप से कर्मचारियों की लागत में हुई वृद्धि से गैर-ब्याज व्यय में वृद्धि और गैर-ब्याज आय में तेजी से आई कमी ने मिलकर लाभप्रदता को शिथिल किया (सारणी V.10)।

चार्ट V.13 बड़े उधार खातों में दबाव

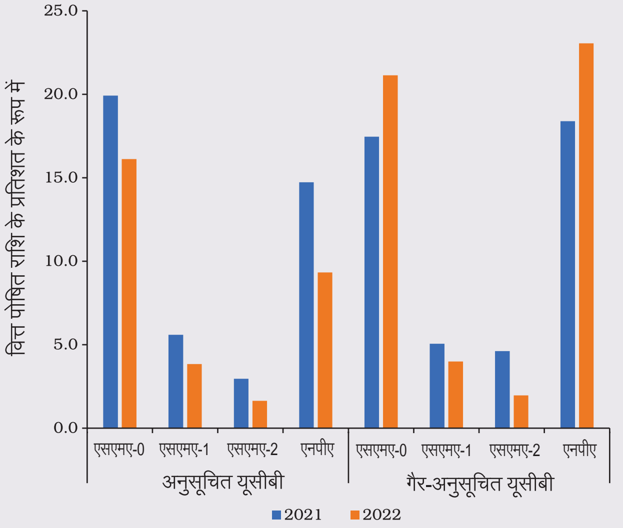

स्रोत: केंद्रीय बृहत ऋण सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस।

सारणी V.10: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी घट-बढ़ (%)
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2021-22
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ए. कुल आय (i+ii)	**22,301**	**20,743**	**30,148**	**29,879**	**52,449**	**50,622**	**-3.5**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	
i. ब्याज से होने वाली आय	19,463	18,551	27,837	28,022	47,300	46,573	-1.5
	(87.3)	(89.4)	(92.3)	(93.8)	(90.2)	(92.0)	
ii. ब्याज से इतर होने वाली आय	2,838	2,192	2,311	1,857	5,149	4,049	-21.4
	(12.7)	(10.6)	(7.7)	(6.2)	(9.8)	(8.0)	
बी. कुल व्यय (i+ii)	**18,884**	**17,017**	**25,773**	**24,875**	**44,657**	**41,892**	**-6.2**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	
i. ब्याज से होने वाली व्यय	13,503	11,398	18,613	17,311	32,116	28,709	-10.6
	(71.5)	(67.0)	(72.2)	(69.6)	(71.9)	(68.5)	
ii. ब्याज से इतर व्यय	5,381	5,619	7,160	7,565	12,541	13,183	5.1
	(28.5)	(33.0)	(27.8)	(30.4)	(28.1)	(31.5)	
जिसमें से: स्टाफ पर व्यय	2,745	2,876	3,923	4,144	6,668	7,020	5.3
सी. लाभ							
i. परिचालनगत लाभ की राशि	3,417	3,727	4,375	5,004	7,792	8,730	12.0
ii. प्रावधान, आकस्मिक निधियां	2,242	1,921	2,584	2,805	4,826	4,726	-2.1
iii. करों के लिए प्रावधान	597	306	811	817	1,408	1,124	-20.2
iv. कर पूर्व निवल लाभ राशि	1,175	1,805	1,791	2,199	2,966	4,004	35.0
v. कर पश्चात निवल लाभ राशि	578	1,499	980	1,382	1,558	2,881	85.0

टिप्पणियां: 1. वर्ष 2021-22 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को रु करोड़ में पूर्णांकित कर दिया गया है।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.11: यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.19	0.50	0.28	0.38	0.24	0.43
इक्विटी पर प्रतिलाभ	2.94	6.88	3.22	4.21	3.11	5.27
निवल ब्याज मार्जिन	2.01	2.39	2.67	2.94	2.36	2.69

टिप्पणियां: वर्ष 2021-22 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.26 यूसीबी की लाभप्रदता के प्रमुख उपायों - आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)- में लगातार दूसरे वर्ष सुधार हुआ (सारणी V.11 और चार्ट V.14)। जमाराशियों की औसत लागत में गिरावट, साथ ही अग्रिमों पर औसत प्रतिलाभ की कीमतों में वृद्धि होने के कारण एसयूसीबी की लाभप्रदता में सुधार हुआ (परिशिष्ट सारणी V.1)।

3.6 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार

V.27 सहकारी बैंकों की जमीनी स्तर की मजबूत उपस्थिति, वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सुगम बनाती है। यूसीबी के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने संबंधी मानदंड 13 मार्च 2020 को संशोधित किए गए थे – जिसके तहत उन्हें मार्च 2021, 2022, 2023 और 2024 के अंत तक समायोजित निवल बैंक ऋण का क्रमशः 45 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है।

चार्ट V.14 लाभप्रदता संकेतक - एसयूसीबी बनाम एनएसयूसीबी

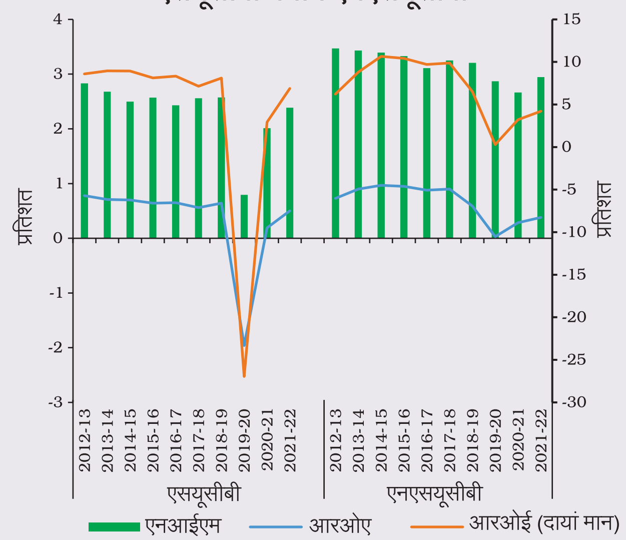

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.28 पिछले एक दशक में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिया गया ऋण हमेशा निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा है। यह प्रवृत्ति उच्च विनियामकीय लक्ष्य के साथ भी जारी रही और 2021-22 के दौरान यूसीबी के उधार का 55 प्रतिशत इस क्षेत्र को दिया गया था। एमएसएमई को इस ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ (सारणी V.12)। जून 2022 में, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा बढ़ा दी। आगे जाकर यह आवास क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण को बढ़ावा दे सकता है।

सारणी V.12 यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण का संघटन

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021		2022	
	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)
1. कृषि [(i+ii+iii)]	12,245	3.9	13,213	4.2
(i) कृषि ऋण	8,913	2.8	9,841	3.1
(ii) कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर	676	0.2	915	0.3
(iii) सहायक गतिविधियां	2,701	0.9	2,457	0.8
2. सूक्ष्म और लघु उद्यम [(i+ii+iii+iv)]	1,01,340	32.3	1,07,847	34.3
(i) सूक्ष्म उद्यम	34,301	10.9	37,681	12.0
(ii) लघु उद्यम	46,128	14.7	46,733	14.8
(iii) मध्यम उद्यम	20,547	6.5	22,894	7.3
(iv) केवीआई को अग्रिम (एमएसएमई को दिये गए अन्य वित्त सहित)	365	0.1	539	0.2
3. निर्यात ऋण	368	0.1	284	0.1
4. शिक्षा	2,374	0.8	2,629	0.8
5. आवास	25,211	8.0	26,803	8.5
6. सामाजिक गतिविधियां	1,185	0.4	1,114	0.4
7. अक्षय उर्जा	1,291	0.4	1,380	0.4
8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत "अन्य" श्रेणी	17,694	5.6	20,012	6.4
9. कुल (1 से 8)	1,61,708	51.5	1,73,282	55.1
जिसमें से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर तबकों को दिया गया ऋण	33,590	10.7	34,844	11.1

टिप्पणियां: 1. वर्ष 2022 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. प्रतिशत हिस्सेदारी यूसीबी के कुल ऋण के संदर्भ में है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.15: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

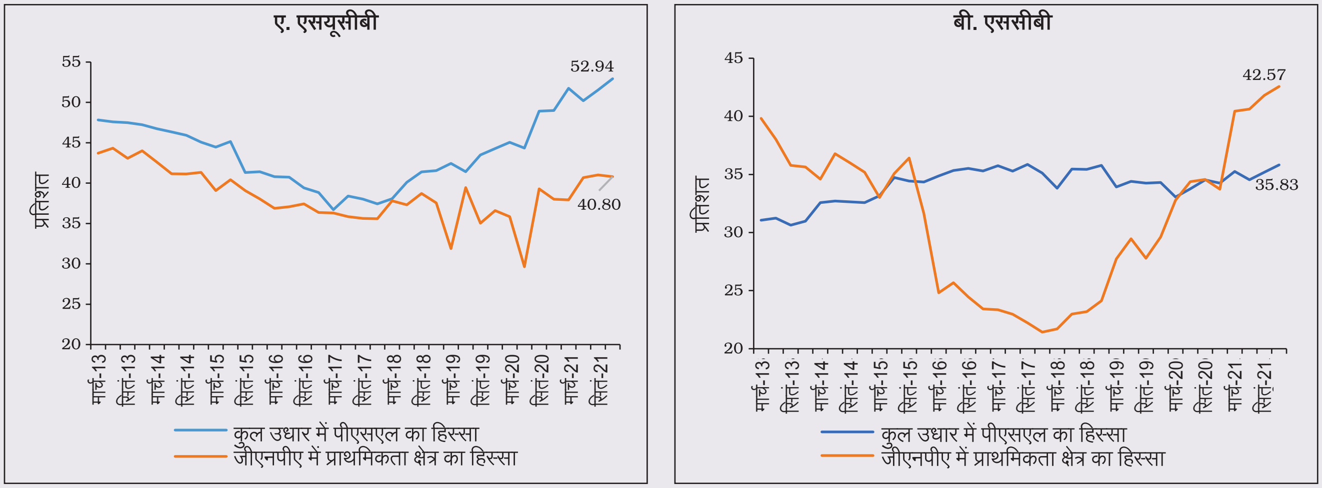

स्रोत: पर्यवेक्षी डेटा पर आधारित स्टाफ गणना।

V.29 एसयूसीबी के कुल ऋण में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद उनके जीएनपीए, विशेष रूप से एससीबी की तुलना में कम रहे हैं (चार्ट V.15ए और 15बी)।

V.30 अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि आस्ति की गुणवत्ता और पूँजी बफर एसयूसीबी की लाभप्रदता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार इसे कमजोर नहीं करते हैं (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के निर्धारक

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूबी) के लिए मार्च 2013 से दिसंबर 2021 की अवधि के लिए 54 संस्थाओं के तिमाही पैनल डाटा का उपयोग निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन फ्रेमवर्क में किया गया था। आश्रित चर यानी बैंकों की लाभप्रदता, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और या विकल्प के

सारणी 1ए: एसयूसीबी की लाभप्रदता पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का प्रभाव
मॉडल I: बैंक विशिष्ट कारक

	(1)	(2)	(3)	(4)
चर	आस्तियों पर प्रतिलाभ	एनआईएम	आस्तियों पर प्रतिलाभ	एनआईएम
पीएसएल	-0.00331 (0.00453)	0.000879 (0.00208)	-0.00466 (0.00473)	0.000587 (0.00210)
कुल जीएनपीए	-0.0284*** (0.00586)	-0.0220*** (0.00389)		
कुल आस्तियां	-0.0501 (0.367)	-0.587** (0.275)	0.0330 (0.351)	-0.466 (0.302)
सीआरएआर	0.0256*** (0.00515)	-0.00455 (0.00348)	0.0298*** (0.00730)	-0.000873 (0.00582)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का जीएनपीए			-0.0209*** (0.00687)	-0.0139** (0.00557)
नियतांक (कोंस्टंट)	1.466 (6.221)	12.19** (4.655)	0.0164 (5.878)	10.06* (5.066)
बैंक स्थिर प्रभाव	हां	हां	हां	हां
समय स्थिर प्रभाव	हां	हां	हां	हां
निष्कर्ष	1,938	1,938	1,938	1,938
आर वर्ग	0.254	0.764	0.206	0.740
बैंको की संख्या	55	55	55	55

कोष्ठक में सुदृढ़ मानक त्रुटियाँ दी गयी हैं।
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(जारी...)

रूप में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) द्वारा अनुमानित है। व्याख्यात्मक चर में बैंक के विशिष्ट कारक जैसे एसयूसीबी के कुल ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार अनुपात (पीएसएल अनुपात), सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात, कुल आस्ति, मॉडल I में सीआरएआर और प्राथमिकता क्षेत्र का जीएनपीए आदि शामिल हैं। मॉडल II में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और मुद्रास्फीति जैसे समष्टिआर्थिक चर पर नियंत्रण कर समान संबंध का परीक्षण किया जाता है।

निष्कर्ष सुझाते हैं कि कुल जीएनपीए अनुपात और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के जीएनपीए अनुपात द्वारा मापी गई आस्ति गुणवत्ता एसयूसीबी की लाभप्रदता से विपरीत रूप से संबंधित है जबकि पूँजी बफर का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं है। इनके परिणाम, मॉडल की विभिन्न विशिष्टताओं के अनुरूप हैं (सारणी 1ए)।

समष्टिआर्थिक चर पर नियंत्रण करने के बाद भी परिणाम सुसंगत रहते हैं जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और मुद्रास्फीति (सारणी 1बी), बैंक लाभप्रदता की प्र-चक्रीयता की ओर इशारा करती है जबकि उच्च मुद्रास्फीति लाभ मार्जिन को कम करती प्रतीत होती है। परिचालन आय से गैर-ब्याज आय का अनुपात आय विविधीकरण को दर्शाता है जिससे आरओए पर उल्लेखनीय और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सारणी 1बी: एसयूसीबी की लाभप्रदता पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का प्रभाव

मॉडल II: बैंक विशिष्ट कारक और समष्टि-आर्थिक नियंत्रण

चर	(1)	(2)
	आस्तियों पर प्रतिलाभ	आस्तियों पर प्रतिलाभ
पीएसएल	-0.00302	-0.00317
	(0.00452)	(0.00427)
कुल जीएनपीए	-0.0278***	-0.0281***
	(0.00600)	(0.00577)
सीआरएआर	0.0254***	0.0258***
	(0.00481)	(0.00506)
गैर-ब्याज आय से परिचालन आय		1.165**
		(0.498)
कुल आस्तियां	-0.0535	-0.00229
	(0.339)	(0.340)
वास्तविक जीडीपी	0.00555**	
	(0.00245)	
मुद्रास्फीति	-0.0138	
	(0.0106)	
डबल्यूएएलआर	0.0478	
	(0.0621)	
नियतांक (कोंस्टंट)	1.017	0.526
	(6.560)	(5.733)
बैंक स्थिर प्रभाव	हां	हां
समय स्थिर प्रभाव	नहीं	हां
निष्कर्ष	1,938	1,937
आर-वर्ग	0.209	0.265
बैंकों की संख्या	55	55

कोष्ठक में सुदृढ़ मानक त्रुटियां दी गयी हैं।

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

4. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.31 ग्रामीण ऋणग्रस्तता और गरीबी की दोहरी समस्या को दूर करने के लिए, ग्रामीण ऋण सहकारिता, सीमांत क्षेत्रों और गतिविधियों को सस्ती कीमत पर ऋण देने के लिए, एक संस्थागत तंत्र के रूप में अस्तित्व में आई। ग्रामीण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है - कुल आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी मार्च 2020 के अंत में 66.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 67.3 प्रतिशत हो गई।

V.32 ग्रामीण सहकारी बैंकों के लघु और दीर्घकालिक संस्थानों के नेटवर्क ने आउटरीच और व्यवसाय की मात्रा के कारण ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। जमाराशियाँ अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों के लिए धन का प्रमुख स्रोत हैं जबकि दीर्घकालिक ऋण सहकारी समितियाँ उधार पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों का वित्तीय प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर है जिसमें निवल लाभ में आनुपातिक रूप से उच्च हिस्सेदारी, एनपीए में कम हिस्सेदारी और मांग अनुपात में ऋण की उच्च वसूली भी शामिल हैं। (सारणी V.13 और चार्ट V.16)।

V.33 साथ ही, यह क्षेत्र संरचनात्मक और अस्थायी दोनों तरह की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। जहां एक व्यापक जमाकर्ता आधार यूसीबी को अपेक्षाकृत कम लागत पर धन जुटाने में सक्षम बनाता है, वहीं ग्रामीण सहकारी समितियाँ अपने कार्यों के लिए उधार पर बहुत अधिक निर्भर हैं। मार्च 2021 के अंत में यूसीबी की देनदारियों का लगभग 1 प्रतिशत उधार था जबकि ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए यह 29 प्रतिशत था। हालिया नरमी के बावजूद, घाटा उठाने वाली ग्रामीण सहकारी समितियों की संख्या उच्च बनी हुई है जो बड़े पैमाने पर आस्ति-गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दर्शाती है। कई संस्थानों के लिए पूँजी-पर्याप्तता भी एक कमजोर बिन्दु है।

सारणी V.13: ग्रामीण सहकारी संस्थानों का प्रोफाइल

(31 मार्च 2021के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी (पी)	पीसीएआरडीबी(पी)
1	2	3	4	5	6
ए. सहकारी संस्थाओं की संख्या	34*	351	102,559	13	603
बी. तुलन-पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी+ आरक्षित निधियां)	24,425	46,773	42,311	6,142	4,227
ii. जमाराशियां	2,23,057	3,81,825	1,70,922	2,546	1,551
iii. उधारियां	1,07,207	1,08,077	1,43,044	13,293	16,144
iv. ऋण और अग्रिम	2,11,794	3,04,990	2,29,443	20,918	15,325
v. कुल देयताएं/ आस्तियां	3,77,338	5,88,914	3,34,718	27,275	31,677
सी. वित्तीय निष्पादन					
i. लाभ में रहने वाले संस्थान					
ए. संख्या	32	308	47,297	10	311
बी. लाभ की राशि	1,669	2,091	5,298	180	193
ii. हानि में रहने वाले संस्थान					
ए. संख्या	2	43	37,419	3	292
बी. लाभ की राशि	268	669	4,320	17	665
iii. समग्र लाभ(+)/हानि(-)	1,402	1,422	978	163	-473
डी. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	14,113	34,761	72,550	6,942	6,818
ii. बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	6.7	11.4	33.5	33.2	44.5
ई. मांग-ऋण वसूली अनुपात *(प्रतिशत)**	90.5	74.9	71.1	46.5	41.8

टिप्पणियां:
1. एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
2. (पी) आंकड़े अनंतिम हैं।
3. * वित्तीय वर्ष 2019-20 तक , दमन और दीव एसटीसीबी के डेटा को गोवा एसटीसीबी के एक भाग के रूप में रिपोर्ट किया गया था। 31 मार्च 2021 तक की स्थिति के लिए गोवा एसटीसीबी और दमन और दीव एसटीसीबी की लेखा परीक्षा अलग से की गयी थी।
4. ** यह अनुपात बकाया अनर्जक ऋण राशि के उस हिस्से को दर्शाता है जिसकी वसूली वित्तीय वर्ष 30 जून को वसूली की जा चुकी है।

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफसीओबी (पीएसीएस डेटा)।

4.1 अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.34 अल्पावधि ऋण सहकारी समितियां अर्थात राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं वो फसल ऋण/कार्यशील पूँजी के प्रावधान के माध्यम से सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। वे कई गैर-वित्तीय सेवाएं जैसे इनपुट आपूर्ति, उत्पादन के भंडारण और विपणन के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति आदि भी प्रदान करती हैं।

V.35 वर्ष 2021 में एसटीसीबी द्वारा अर्जित लाभ का एक बड़ा हिस्सा दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त किया गया था (परिशिष्ट सारणी V.3)। डीसीसीबी, जिनकी मध्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत मजबूत उपस्थिति है, पश्चिमी क्षेत्र से अपने लाभ

चार्ट V.16: दीर्घावधि बनाम अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

(मार्च 2021 के अंत में)

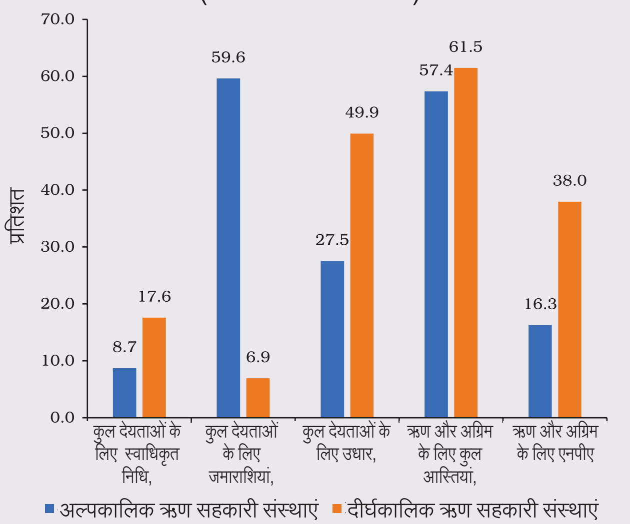

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

का उच्चतम हिस्सा अर्जित करते हैं (परिशिष्ट सारणी V.4)। दूसरी ओर, हालांकि पीएसीएस पश्चिमी क्षेत्र में अधिक केंद्रित हैं, वे मुनाफे के लिए उत्तरी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं (परिशिष्ट सारणी V.6)।

V.36 वित्तीय प्रदर्शन की तुलना से पता चलता है कि पीएसीएस अल्पावधि ग्रामीण सहकारी खंड में सबसे कमजोर कड़ी हैं। उधार पर उनकी उच्च निर्भरता, उच्च एनपीए अनुपात और कम वसूली अनुपात उनकी अंतर्निहित कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं (चार्ट V.17)।

4.1.1 राज्य सहकारी बैंक

V.37 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) ग्रामीण सहकारी संरचना में शीर्ष संस्थाएं हैं, जो टियर II और टियर III संस्थाओं को चलनिधि और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, इसके अलावा वे स्वयं ग्राहकों को ऋण देते हैं। मार्च 2021 के अंत में,

चार्ट V.17: अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की तुलना (तुलन-पत्र और वित्तीय-निष्पादन)
(मार्च 2021 के अंत में)

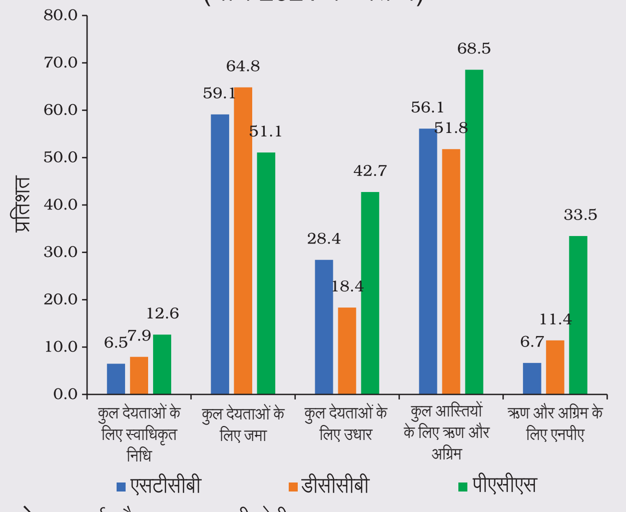

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[8] में उनकी 2,078 शाखाएँ थीं, जो विभिन्न कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करती थीं। एसटीसीबी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.38 राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) का तुलन पत्र 2020-21 में लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। पिछले वर्षों की तरह, जमाराशियाँ उनकी देयताओं का मुख्य आधार बनी हुई हैं। वर्ष 2020-21 में उपलब्ध उधारी की कम लागत का लाभ उठाते हुए, उधारी में तेज वृद्धि संसाधन जुटाने की उनकी गतिशील रणनीति को भी रेखांकित करती है। हालांकि, उस समय कमजोर ऋण मांग के कारण, जुटाए गए उच्चतर वृद्धिशील संसाधनों का उपयोग ऋण और अग्रिमों के विस्तार के लिए नहीं किया जा सका। इसके बजाय, इन संसाधनों को निवेश और नकद होल्डिंगों के रूप में लगाया गया (सारणी V.14)।

V.39 वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध पर्यवेक्षी डेटा, मजबूत ऋण-उठाव और तदनुरूप एसएलआर निवेश में कमी के साथ, एक पलटाव दिखाता है (सारणी V.15)।

लाभप्रदता

V.40 वर्ष 2019-20 के दौरान, ब्याज आय और खर्च किए गए ब्याज दोनों में संकुचन हुआ, लेकिन ब्याज-आय ने ब्याज-व्यय की तुलना में कहीं अधिक भरपाई की। परिणामस्वरूप, यह एसटीसीबी के लिए लाभदायक वर्ष साबित हुआ। यह वर्ष 2020-21 में उल्टा हो गया और जैसे ही ब्याज-व्यय में वृद्धि ब्याज-आय से अधिक हो गई, इस क्षेत्र में लाभप्रदता में गिरावट देखी गई।

[8] हालांकि 34 एसटीसीबी हैं तथापि जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 7 शाखाएं हैं।

सारणी V.14: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट-बढ़ (%)	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	7,459	8,577	0.4	15.0
	(2.2)	(2.3)		
2. आरक्षित निधियां	14,441	15,848	4.7	9.7
	(4.2)	(4.2)		
3. जमाराशियां	2,10,342	2,23,057	9.2	6.0
	(61.8)	(59.1)		
4. उधारियां	85,723	1,07,207	2.0	25.1
	(25.2)	(28.4)		
5.अन्य देयताएं	22,301	22,648	16.9	1.6
	(6.6)	(6.0)		
आस्तियां				
1. नकद और बैंक में जमा शेष	10,229	14,360	-32.6	40.4
	(3.0)	(3.8)		
2. निवेश	1,12,828	1,29,329	9.4	14.6
	(33.2)	(34.3)		
3. ऋण और अग्रिम	1,99,943	2,11,794	8.9	5.9
	(58.8)	(56.1)		
4. संचित हानि	1,232	1,405	25.0	14.0
	(0.4)	(0.4)		
5. अन्य	16,035	20,451	13.3	27.5
	(4.7)	(5.4)		
आस्तियां कुल देयताएं/ आस्तियां	**3,40,267**	**3,77,338**	**7.3**	**10.9**
	(100.0)	**(100.0)**		

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष –दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत: नाबार्ड।

मुख्य रूप से वेतन बिलों के कारण परिचालन व्यय में वृद्धि ने मुनाफे में संकुचन को और बढ़ा दिया (सारणी V.16)।

V.41 मुनाफे में संकुचन उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेज था। यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के एसटीसीबी के कारण रहा, जिसने ₹ 24,751 लाख रुपये की हानि दर्ज की। दक्षिणी क्षेत्र में लाभ में आयी कमी को भी शामिल करने से, पूरे देश में हुए लाभों में कमी आ गई (परिशिष्ट सारणी V.3)।

आस्ति गुणवत्ता

V.42 वर्ष 2019-20 में गिरावट के बाद, एसटीसीबी में एनपीए वृद्धि वर्ष 2020-21 में धीमी हुई। संदेहास्पद और हानि खातों में तीव्र वृद्धि ने अवमानक आस्तियों में सुधार के लिए प्रतिसंतुलनकारी बल के रूप में कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप, ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात पिछले वर्ष की तरह 6.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित ही रहा। पूर्वी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में एनपीए अनुपात में सुधार अन्य क्षेत्रों में गिरावट से प्रतिसंतुलित हो गया था (परिशिष्ट सारणी V.3)। रिकवरी अनुपात में गिरावट इस क्षेत्र में अंतर्निहित कमजोरी को उजागर करती है (सारणी V.17)।

4.1.2 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

V.43 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी), जो अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संरचना में दूसरे स्तर का गठन

सारणी V.15: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
जमाराशियां	90,277	98,768	1,10,559	1,87,456	1,97,751	2,11,784
	(13.5)	(9.4)	(11.9)	(69.6)	(5.5)	(7.1)
ऋण	1,10,934	1,17,989	1,31,399	1,94,310	2,06,322	2,28,194
	(3.3)	(6.4)	(11.4)	(47.9)	(6.2)	(10.6)
एसएलआर निवेश	26,225	33,411	33,130	54,181	67,788	77,677
	(8.3)	(27.4)	-(0.8)	(63.5)	(25.1)	(14.6)
ऋण तथा एसएलआर निवेश का जोड़	1,37,159	1,51,400	1,64,529	2,48,492	2,74,110	3,05,871
	(4.2)	(10.4)	(8.7)	(51.0)	(10.3)	(11.6)

टिप्पणियां: 1. आंकड़े संगत वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
3. *: उच्च वृद्धि मुख्य रूप से केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ 13 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के समामेलन के कारण है।

स्रोत: आरबीआई अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रपत्र बी।

सारणी V.16 राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	के दौरान		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**21,922 (100.0)**	**24,318 (100.0)**	**-1.6**	**10.9**
i. ब्याज से होनेवाली आय	20,014 (91.3)	23,177 (95.3)	-6.4	15.8
ii. अन्य आय	1,908 (8.7)	1,141 (4.7)	111.9	-40.2
बी. व्यय (i+ii+iii)	**20,198 (100.0)**	**22,916 (100.0)**	**-4.1**	**13.5**
i. व्ययगत ब्याज	14,871 (73.6)	17,318 (75.6)	-8.6	16.5
ii. प्रावधान और आकस्मिक निधियां	2,646 (13.1)	2,181 (9.5)	67.6	-17.6
iii. परिचालनगत व्यय	2,681 (13.3)	3,418 (14.9)	-16.4	27.5
जिसमें से: वेतन बिल	1,491 (7.4)	1,926 (8.4)	-14.3	29.1
सी. लाभ				
i. परिचालनगत लाभ	2,974	2,947	26.0	-0.9
ii. निवल लाभ	1,724	1,402	41.3	-18.7

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.17: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट बढ़ प्रतिशत	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	13,477	14,113	35.2	4.7
i. अवमानक	7,883 (58.5)	7,379 (52.3)	67.3	-6.4
ii. संदिग्ध	4,400 (32.6)	5,294 (37.5)	9.7	20.3
iii. हानि	1,195 (8.9)	1,440 (10.2)	-4.1	20.5
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**6.7**	**6.7**	-	-
सी. मांग-वसूली अनुपात (%)	**94.4**	**90.5**	-	-

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. निरपेक्ष संख्याओं का पूर्णांकन किया गया है, जिसके कारण प्रतिशत में थोड़ी भिन्नता आ सकती है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।
5. वसूली की स्थिति समान वित्तीय वर्ष की 30 जून की स्थिति के अनुसार है।

स्रोत: नाबार्ड।

करते हैं, 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13,610 शाखाओं के नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं जो मुख्य रूप से मध्य क्षेत्र में केंद्रित हैं। वे व्यक्तिगत उधारकर्ताओं एवं तीसरे स्तर के संस्थानों यथा पीएसीएस को उधार देने के लिए, सार्वजनिक जमाराशियों, राज्य सहकारी बैंकों से उधारी और नाबार्ड से पुनर्वित्त के माध्यम से धन जुटाते हैं। डीसीसीबी का लगभग 60 प्रतिशत ऋण पीएसीएस के माध्यम से होता है। जमाराशि जुटाने के लिए अपने व्यापक शाखा नेटवर्क का लाभ उठाने में सक्षम होने के कारण, डीसीसीबी एसटीसीबी की तुलना में उधारी पर कम निर्भर हैं। इससे एसटीसीबी की तुलना में, सीडी अनुपात भी कम होता है, तथापि डीसीसीबी का बकाया ऋण अपेक्षाकृत बड़ा है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.44 वर्ष 2019-20 में गिरावट के बाद, वर्ष 2020-21 में डीसीसीबी की समेकित तुलन-पत्र वृद्धि में पुनर्वृद्धि मुख्य रूप से देयताएं के पक्ष में जमा और उधारी से प्रेरित थी। यह ऋण एवं अग्रिम तथा आस्ति पक्ष में निवेश में तेजी से मेल खाता था। लगातार दूसरे वर्ष भी संचित हानियों में गिरावट एक मजबूत तुलन-पत्र का संकेत है (सारणी V.18)।

लाभप्रदता

V.45 हालांकि डीसीसीबी की आय और व्यय दोनों में गिरावट आई। हालांकि व्यय में वृद्धि आय की अपेक्षा बहुत कम थी जिसके परिणामस्वरूप लाभ में ज्यादा वृद्धि हुई (सारणी V.19)। विशेष रूप से, ब्याज आय में वृद्धि ने ब्याज व्यय में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया जिससे निवल ब्याज आय में वृद्धि हुई।

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट बढ़ प्रतिशत	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	20,913 (3.9)	22,391 (3.8)	3.9	7.1
2. आरक्षित निधियां	22,332 (4.2)	24,381 (4.1)	7.5	9.2
3. जमाराशियां	3,45,682 (64.5)	3,81,825 (64.8)	7.7	10.5
4. उधारियां	97,448 (18.2)	1,08,077 (18.4)	4.8	10.9
5. अन्य देयताएं	49,602 (9.3)	52,239 (8.9)	6.1	5.3
आस्तियां				
1. नकद और बैंक में जमा शेष	23,409 (4.4)	26,973 (4.6)	-8.7	15.2
2. निवेश	1,86,745 (34.8)	2,11,380 (35.9)	10.1	13.2
3. ऋण और अग्रिम	2,79,272 (52.1)	3,04,990 (51.8)	5.4	9.2
4. संचित हानि	6,721 (1.3)	7,046 (1.2)	9.5	4.8
5. अन्य आस्तियां	39,830 (7.4)	38,525 (6.5)	13.1	-3.3
कुल देयताएं/ आस्तियां	**5,35,977** **(100.0)**	**5,88,914** **(100.0)**	**6.9**	**9.9**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत: नाबार्ड।

V.46 सभी क्षेत्रों में लाभ कमाने वाली संस्थाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। अखिल भारतीय स्तर पर निवल लाभ में दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के डीसीसीबी की हिस्सेदारी अत्यधिक रही। पश्चिमी क्षेत्र में वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ में तेजी का मुख्य योगदानकर्ता महाराष्ट्र रहा, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान रहा (परिशिष्ट सारणी V.4)।

आस्ति गुणवत्ता

V.47 वर्ष 2016-17 से डीसीसीबी के आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आने लगी, जब कई राज्यों ने कृषि ऋण माफी योजना

सारणी V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	के दौरान		घट बढ़ प्रतिशत	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए: आय (i+ii)	**38,398** **(100.0)**	**39,982** **(100.0)**	**7.3**	**4.1**
i. ब्याज से होनेवाली आय	36,473 (95)	38,089 (95.3)	7.3	4.4
ii. अन्य आय	1,924 (5)	1,893 (4.7)	8.0	-1.6
बी: व्यय (i+ii+iii)	**37,552** **(100.0)**	**38,560** **(100.0)**	**6.9**	**2.7**
i. व्ययगत ब्याज	24,830 (66.1)	25,480 (66.1)	7.9	2.6
ii. प्रावधान और आकस्मिक निधियां	3,886 (10.3)	3,720 (9.6)	8.0	-4.3
iii. परिचालनगत व्यय	8,836 (23.5)	9,361 (24.3)	3.9	5.9
जिसमें से: वेतन बिल	5,663 (15.1)	5,864 (15.2)	5.4	3.6
सी: लाभ				
i. परिचालनगत लाभ	4,229	4,723	11.8	11.7
ii. निवल लाभ	846	1,422	28.4	68.1

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष –दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत: नाबार्ड।

की घोषणा की। वर्ष 2020-21 में, अवमानक आस्तियों में गिरावट और संदिग्ध आस्तियों में कमी के कारण आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। संयोग से, वर्ष 2016-17 के बाद से मांग के अनुपात में उनकी वसूली अपने उच्चतम स्तर पर रही। आस्ति गुणवत्ता और वसूली अनुपात में सुधार में उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों ने अपना योगदान दिया। दक्षिणी क्षेत्र में सबसे कम एनपीए अनुपात होने के साथ-साथ उच्चतम वसूली अनुपात भी है (सारणी V.20 और परिशिष्ट सारणी V.4)।

4.1.3 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

V.48 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी संरचना में जमीनी स्तर की संस्थाएं हैं। ऐतिहासिक रूप से, समितियां विशेषकर सीमांत

सारणी V.20: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट बढ़ प्रतिशत	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**35,298**	**34,761**	**10.3**	**-1.5**
i. अवमानक	15,885 (45)	13,940 (40.1)	1.6	-12.2
ii. संदिग्ध	16,990 (48.1)	18,367 (52.8)	22.1	8.1
iii. हानि	2,423 (6.9)	2,455 (7.1)	-0.6	1.3
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**12.6**	**11.4**	-	-
सी. मांग-वसूली अनुपात (%)	**70.2**	**74.9**	-	-

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष –दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।
5. वसूली की स्थिति समान वित्तीय वर्ष की 30 जून की स्थिति के अनुसार है।

स्रोत: नाबार्ड।

किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करने के लिए उधार और जमा दोनों के माध्यम से संसाधन जुटाती हैं। वे अपने सदस्यों के लिए कृषि निवेश संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण और उपज के विपणन सहित अन्य गतिविधियों से संबंधित भी काम करती हैं।

V.49 मार्च 2021 की समाप्ति तक, पीएसीएस ने 13.7 करोड़ सदस्यों और 5.4 करोड़ उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान की। पश्चिमी क्षेत्र (मुख्य रूप से महाराष्ट्र) में इसकी उपस्थिति प्रमुख रूप से है, इसके बाद पूर्वी क्षेत्र का स्थान है। सदस्य उधारकर्ता अनुपात - पीएसीएस का एक ऋण-संकेंद्रण मापक, वर्ष 2016-17 में 39.6 प्रतिशत से उत्तरोत्तर कम होकर वर्ष 2019-20 में 38 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वर्ष 2020-2021 के दौरान, यह अनुपात बढ़कर 39.1 प्रतिशत हो गया, जो मुख्य रूप से कुल सदस्यता में गिरावट और कुल उधारकर्ताओं[9] की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। ग्रामीण कारीगरों और 'अन्य तथा सीमांत किसानों' की सदस्यता में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी V.7)।

V.50 एसटीसीबी और डीसीसीबी के एनपीए अनुपात के संदर्भ में मापी गई आस्ति की गुणवत्ता, ऐतिहासिक रूप से, पीएसीएस से बेहतर रही है। इसके अतिरिक्त, उनका वसूली अनुपात भी लगातार दो वर्षों से अपने निम्नतम स्तर पर बना हुआ है (सारणी V.13 और चार्ट V.18)।

चार्ट V.18: अल्पावधिक सहकारी संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता: एक तुलना

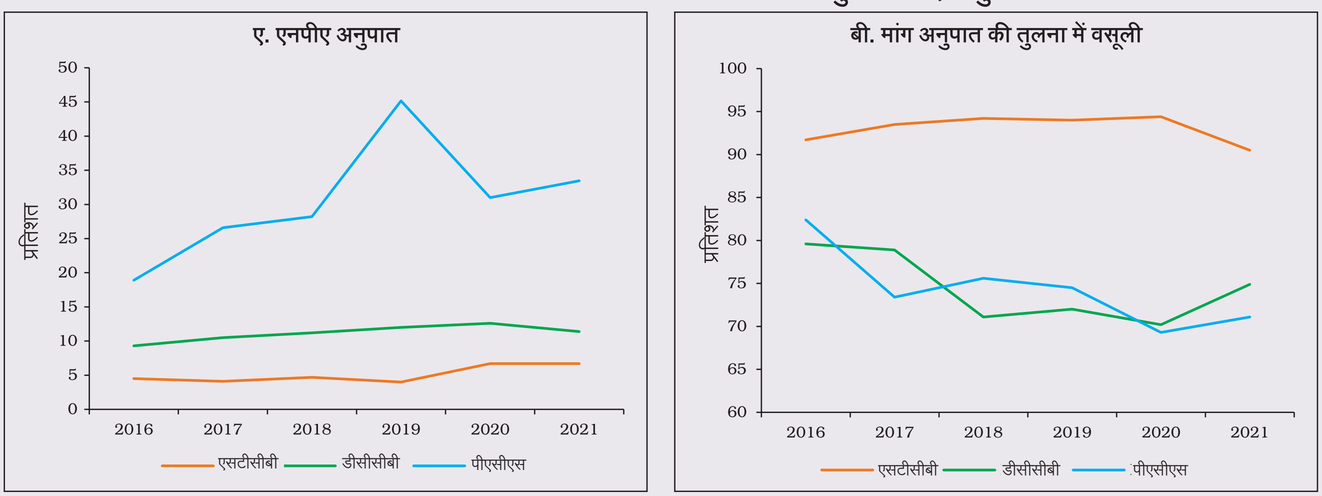

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

9 नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 - https://www.nabard.org/nabard-annual-report-2021-22.aspx पर उपलब्ध है।

V.51 वर्ष 2020-21 के दौरान पीएसीएस के कुल संसाधनों में गिरावट आई। सरकारी योगदान में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2020-21 में स्वामित्व वाली निधियों में कमी आई, जो सदस्यता आधार में गिरावट को दर्शाती है, और प्रदत्त पूंजी में नकारात्मक वृद्धि का कारण बनी (परिशिष्ट सारणी V.5)। अपने अधिदेश के अनुरूप, पीएसीएस मध्यम अवधि के ऋणों की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लघु और मध्यम अवधि के दोनों ऋणों में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस प्रकार कुल में अल्पावधि ऋणों की हिस्सेदारी 88 प्रतिशत बनी रही।

V.52 पीएसीएस का व्यापार मॉडल काफी हद तक कृषि को ऋण देने की ओर अग्रसर हुआ है। मार्च 2021 की समाप्ति तक कुल उधार में इसकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। हालांकि, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के आधार पर, इनका कृषि ऋण, पिछले वर्ष के 6.8 प्रतिशत की तुलना में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गया।

V.53 वर्ष के दौरान आधे से ज्यादा पीएसीएस लाभ में थे जिन्होंने नुकसान के बावजूद आधे से अधिक पीएसीएस ने लाभ अर्जित किया । क्षेत्र-वार संकलन से पता चलता है कि 70 प्रतिशत से अधिक समितियों के लाभ में होने से केवल उत्तरी क्षेत्र की समितियां लाभ में थीं, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान का योगदान था। दक्षिणी क्षेत्र में नुकसान सबसे अधिक था, जिसमें मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु का योगदान था (परिशिष्ट सारणी V.6)।

4.2 दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.54 दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की स्थापना कृषि में निवेश हेतु निधि उपलब्ध करवाने- जिसमें भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण और लघु सिंचाई - ग्रामीण उद्योग और आवास शामिल हैं, के लिए की गई थी। इसकी संरचना में राज्य स्तर पर कार्यरत 13 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा जिला/ब्लॉक स्तर पर संचालित 603 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल हैं। दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों की संरचना राज्यों में भिन्न-भिन्न होती हैं। जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पुडुचेरी जैसे राज्य एकात्मक संरचना का पालन करते हैं, अर्थात एससीएआरडीबी अपनी स्वयं की शाखाओं के माध्यम से संचालित होते हैं जिनमें कोई अलग पीसीएआरडीबी नहीं होता है। दूसरी ओर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य एक संघीय ढांचे का पालन करते हैं जिसमें एससीएआरडीबी, पीसीएआरडीबी के माध्यम से उधार देते हैं। दो राज्यों में यथा हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, एससीएआरडीबी, पीसीएआरडीबी के साथ-साथ अपनी स्वयं की शाखाओं के माध्यम से कार्य करती हैं।

V.55 एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी का व्यवसाय मॉडल उधार पर बहुत अधिक निर्भर करता है; उक्त में से पूर्व वाले प्रत्यक्ष उधार देने के लिए पीसीएआरडीबी के साथ-साथ उधार देने के लिए नाबार्ड जैसे संस्थानों से उधार लेते हैं। पीसीएआरडीबी की वित्तीय स्थिति एससीएआरडीबी की तुलना में अधिक नाजुक है क्योंकि उनके तुलन पत्र में संचित हानि का भाग ज्यादा है (चार्ट V.19) ।

4.2.1 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

V.56 794 शाखाओं के साथ एससीएआरडीबी 13 राज्यों में काम कर रही हैं, जिनमें से सबसे अधिक शाखाएँ उत्तर प्रदेश में हैं। एससीएआरडीबी की समेकित तुलन-पत्र में लगातार तीन वर्षों तक कमी देखने के बाद, वर्ष 2020-21 में मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी देनदारी पक्ष में जमाराशि द्वारा और आस्ति पक्ष में ऋणों और अग्रिमों में निरंतर तेजी द्वारा समर्थित थी (परिशिष्ट V.8) ।

V.57 हालांकि आय - ब्याज के साथ-साथ ब्याजेतर - और व्यय दोनों पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए हैं, आय में गिरावट, व्यय की तुलना में अधिक थी, जिससे लाभप्रदता में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.9) ।

चार्ट V.19: दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां : एक तुलना
(मार्च 2021 के अंत में)

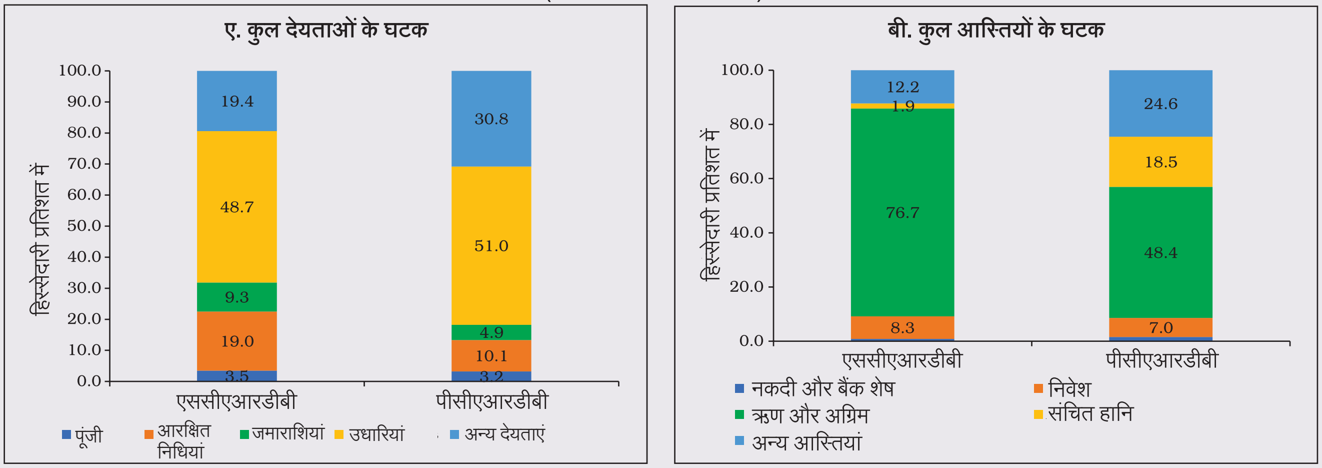

स्रोत: नाबार्ड।

V.58 अवमानक आस्तियों में संकुचन के कारण वर्ष 2020-21 में एससीएआरडीबी के एनपीए में कम वृद्धि देखी गई। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में मांग-वसूली अनुपात में सुधार हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल का योगदान रहा (परिशिष्ट सारणी V.10 और V.11)।

4.2.2 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

V.59 आस्ति पक्ष में ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ देयताएं पक्ष में उधार में संकुचन के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान पीसीएआरडीबी की समेकित तुलन-पत्र में कमी आई (परिशिष्ट तालिका V.12)।

V.60 व्यय से ज्यादा आय में वृद्धि होने से पीसीएआरडीबी के परिचालन लाभ में तेजी आई। हालांकि, उनकी प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं अधिक बनी रहीं तथा निवल घाटे की ऐतिहासिक प्रवृत्ति जारी रही (परिशिष्ट सारणी V.13)। सकारात्मक पक्ष यह है कि अवमानक आस्तियों में गिरावट के कारण वर्ष 2020-21 में एनपीए अभिवृद्धि धीमी हुई है (परिशिष्ट सारणी V.14)। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए मांग अनुपात के सुधार में कमी आई (परिशिष्ट तालिका V.15)।

5. समग्र मूल्यांकन

V.61 वर्ष 2021-22 के दौरान, यूसीबी का प्रदर्शन सभी मापदंडों - पूंजी बफर, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता - पर सुधरा। एक बड़े दबावग्रस्त यूसीबी के समामेलन ने इस क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद की, हालांकि, अन्य दबावग्रस्त और कमजोर यूसीबी की स्वयंसमर्थता सुनिश्चित करने के लिए ध्यान से निगरानी की आवश्यकता है। हालांकि, ग्रामीण सहकारी समितियों के कुछ क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने की जरूरत है। रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए विधिक और विनियामकीय उपायों से इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की संभावना है जिससे वे वित्तीय समावेश के कड़ी के रूप में अपनी भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें।

VI गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

वर्ष 2021-22 के दौरान, एनबीएफसी का तुलन पत्र, उनके ऋणों और अग्रिमों में गिरावट के कारण धीमी गति से बढ़ा। तथापि, मजबूत पूंजीगत स्थिति, बेहतर आस्ति गुणवत्ता, पर्याप्त प्रावधानीकरण और उच्च लाभप्रदता के मामले में इस क्षेत्र ने दृढ़ता दिखाई। मजबूती के कारण 2021-22 में आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के तुलन पत्र में मामूली वृद्धि हुई। मुख्य रूप से, निवेश, ऋण और अग्रिम में वृद्धि के कारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के तुलन पत्र में द्विअंकीय वृद्धि देखी गई।

1. भूमिका

VI.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने विभिन्न नीतिगत पहल की बदौलत महामारी का सामना किया। उन्होंने 2021-22 के दौरान तुलन पत्र समेकन, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार, संवर्धित पूंजी बफर और लाभप्रदता द्वारा चिह्नित वित्तीय सुदृढ़ता का निर्माण किया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान महामारी की दूसरी लहर में, स्थानीयकृत और क्षेत्र-विशिष्ट रोकथाम नीतियों को अपनाने और टीकाकरण की नियमित गति के कारण आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान सीमित था। हालांकि, एनबीएफसी क्षेत्र में संपर्क-गहन क्षेत्रों और छोटे व्यवसायों पर कड़ी मार पड़ी और उन्हें आस्ति गुणवत्ता और चलनिधि दबावों का सामना करना पड़ा। जैसे ही दूसरी लहर का प्रभाव कम हुआ और तीसरी लहर अल्पकालिक हो गई, रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा घोषित अग्रसक्रिय नीतिगत उपायों से एनबीएफसी क्षेत्र ने फिर से गति पकड़ ली। मांग में वृद्धि, कम ब्याज दरों, स्टांप शुल्क में कमी और घर से काम करने की प्राथमिकता के साथ श्रम बाजार की स्थितियों में बदलाव से प्रॉपर्टी की बिक्री में वृद्धि से प्रेरित आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) सुदृढ़ बनी रहीं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) ने भी रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सहायता से उत्साहित होकर आर्थिक सुधार में योगदान करने के लिए अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को पुनर्निर्धारित किया।

VI.2 यह अध्याय रिज़र्व बैंक[1] द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) के परिचालन और कार्य-प्रदर्शन का विश्लेषण करता है, जिसमें एनबीएफसी, एचएफसी, एआईएफआई और प्राथमिक व्यापारी (पीडी) शामिल हैं (चार्ट VI.1)। एनबीएफसी में सरकारी/ सार्वजनिक/ निजी लिमिटेड कंपनियाँ शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को उम्दा वित्तपोषण प्रदान करती हैं, जिसमें रियल एस्टेट और अवसंरचना से लेकर कृषि और सूक्ष्म ऋण शामिल हैं, जो बैंक ऋण की पूरक है। देश में आवास गतिविधि में मदद के लिए व्यक्तियों, सहकारी समितियों और कॉर्पोरेट निकायों को आवास वित्तपोषण प्रदान करना एचएफ़सी का विशिष्ट कार्य है।[2] एआईएफआई, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय अवसंरचना

[1] हालांकि मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक-ब्रोकिंग/ सब-ब्रोकिंग के कारोबार में लगी कंपनियां, निधि कंपनियां, वैकल्पिक निवेश फंड कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां एनबीएफसी हैं, उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है।

[2] वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन किया और आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) के विनियमन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ शक्तियाँ प्रदान कीं। अब से एचएफ़सी को विनियामक उद्देश्यों के लिए एनबीएफ़सी की श्रेणी के रूप में माना जाता है।

चार्ट VI.1: रिज़र्व बैंक के विनियमन के तहत एनबीएफ़आई की संरचना
(31 जुलाई 2022 तक)

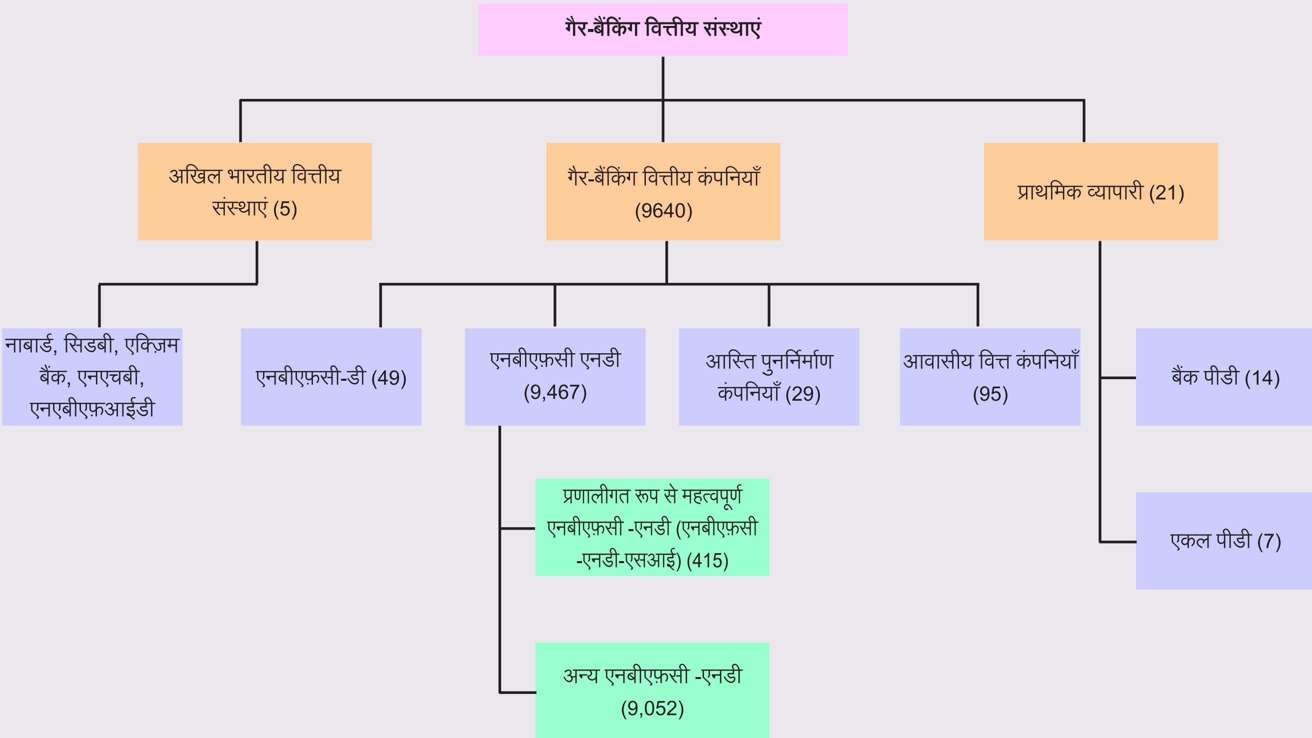

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या (अनंतिम) दर्शाते हैं।
2. हालांकि, एकल पीडी, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें इस चार्ट में पीडी के अंतर्गत भी रखा गया है।
3. अन्य एनबीएफसी-एनडी में 62 सीआईसी शामिल हैं।

स्रोत : आरबीआई।

वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफ़आईडी)[3], शीर्ष वित्तीय संस्थान हैं, जो क्रमशः कृषि, विदेशी व्यापार, लघु उद्योगों, आवास वित्त कंपनियों और अवसंरचना को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं। पीडी, सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के अलावा, जी-सेक के प्राथमिक निर्गम के लिए सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित करते हैं। शेष अध्याय को चार खण्डों में विभाजित किया गया है। खंड 2, एनबीएफसी क्षेत्र का अवलोकन करता है, जिसमें जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) शामिल हैं। एचएफसी की गतिविधियों और वित्तीय प्रदर्शन को भी इस खंड में शामिल किया गया है। एआईएफआई और प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के कार्यप्रदर्शन का मूल्यांकन क्रमशः खंड 3 और खंड 4 में प्रदान किया गया है। खंड 5 एक समग्र मूल्यांकन के साथ समाप्त होता है और भविष्य के लिए के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

[3] एनएबीएफ़आईडी को विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफ़आई) के रूप में स्थापित किया गया है और आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा एआईएफ़आई के रूप में इसका विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा।

2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)[4]

VI.3 भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी क्षेत्र का बढ़ता महत्व, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए ऋण की तुलना में, एनबीएफसी के ऋण में लगातार वृद्धि से परिलक्षित होता है (चार्ट VI.2ए और बी)।

VI.4 आस्ति/ देयता संरचनाओं के संदर्भ में, एनबीएफसी को जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी)- जो जनता की जमाराशियां स्वीकार करती हैं और रखती हैं - और जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) में विभाजित किया गया है। जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी में, ₹500 करोड़ या उससे अधिक की आस्ति वाले को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

VI.5 अक्टूबर 2022 में संपूर्ण विनियामकीय सुधार के बाद, एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और पाए गए जोखिम के स्तर के आधार पर चार लेयरों में विभाजित किया गया है, अर्थात् बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल), मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल), अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) और टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल)। आकार के संदर्भ में, एनबीएफसी-बीएल में ऐसे सभी एनबीएफसी-एनडी शामिल हैं, जिनकी आस्ति का आकार ₹1,000 करोड़ से कम है। ₹1,000 करोड़ से अधिक की आस्ति वाले एनबीएफसी-एनडी और एनबीएफसी-डी को एनबीएफसी-एमएल में रखा गया है। एनबीएफसी-यूएल में वे एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी सहित) शामिल हैं जिनकी विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के एक सेट के आधार पर निगरानी की जाती है। इस ढांचे में यह भी परिकल्पना की गई है कि आस्ति आकार के अनुसार शीर्ष दस एनबीएफसी को हमेशा एनबीएफसी-यूएल में रखा जाए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 16 एनबीएफसी (एचएफसी सहित) की पहचान की है और उन्हें एनबीएफसी-यूएल में रखा है। एनबीएफसी-टीएल, आदर्श रूप से खाली रहेगा और यदि रिज़र्व बैंक को एनबीएफसी-यूएल में विशिष्ट एनबीएफसी से संभावित प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव होता है तो उसे इस लेयर में रखा जाएगा। स्केल के अलावा, नया विनियामकीय ढांचा एनबीएफसी के लिए गतिविधि-आधारित विनियमन भी निर्धारित करता है (सारणी VI.1)। रिज़र्व बैंक ने इन खंडों पर अपनी निगरानी को और मजबूत करने के

चार्ट VI.2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण और जीडीपी की तुलना में एनबीएफसी के ऋण
(मार्च के अंत में)

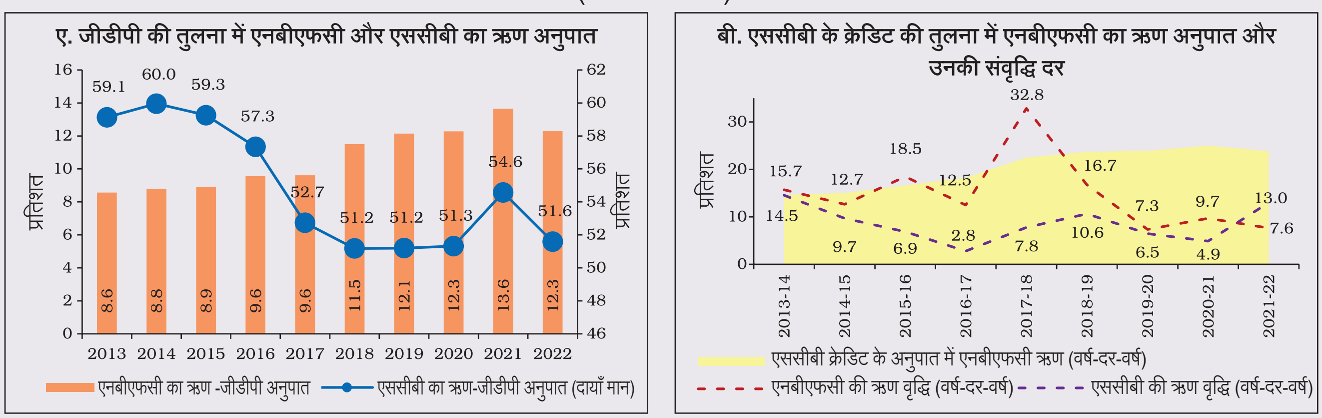

टिप्पणी: जीडीपी वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी को संदर्भित करता है (आधार: 2011-12)।
स्रोत: 1. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, विभिन्न अंक।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, विभिन्न अंक।

[4] यह खंड, सीआईसी और पीडी को छोड़कर, केवल एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर केंद्रित है।

सारणी VI.1: नए विनियामकीय ढांचे के तहत गतिविधि के आधार पर एनबीएफसी का वर्गीकरण

	एनबीएफसी का प्रकार	गतिविधि	लेयर
1.	एनबीएफसी निवेश और क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी)	उधार और निवेश	स्केल आधारित विनियामक ढांचे के मापदंडों के आधार पर कोई भी लेयर।
2.	एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी)	इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तपोषित करना।	मध्य लेयर या ऊपरी लेयर, जैसा भी मामला हो।
3.	मूल निवेश कंपनी (सीआईसी)	इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, ऋण, या समूह कंपनियों के ऋणों में निवेश।	मध्य लेयर या ऊपरी लेयर, जैसा भी मामला हो।
4.	एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (एनबीएफसी-आईडीएफ)	कम से कम एक वर्ष के संतोषजनक प्रदर्शन को पूरा करने वाली केवल अवसंरचना परियोजनाओं में पोस्ट कमेंसमेंट ऑपरेशंस में लंबी अवधि के ऋण के प्रवाह की सुविधा।	मध्य लेयर
5.	एनबीएफसी- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)	आर्थिक रूप से अल्प आय वाले परिवारों को संपार्श्विक मुक्त छोटे टिकट ऋण प्रदान करना।	स्केल आधारित विनियामक ढांचे के मापदंडों के आधार पर कोई भी लेयर।
6.	एनबीएफसी-फैक्टर्स	एक समनुदेशक की प्राप्य राशियों का अधिग्रहण या प्राप्य राशियों के सुरक्षा हित के प्रति छूट पर ऋण देना।	स्केल आधारित विनियामक ढांचे के मापदंडों के आधार पर कोई भी लेयर।
7.	एनबीएफसी-परिचालनेतर वित्तीय नियंत्रक कंपनी (एनबीएफसी-एनओएफएचसी)	नए बैंकों की स्थापना में प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूहों की सुविधा।	बेस लेयर
8.	एनबीएफसी बंधक गारंटी कंपनी (एनबीएफसी एमजीसी)	बंधक गारंटी व्यवसाय का उपक्रम।	स्केल आधारित विनियामक ढांचे के मापदंडों के आधार पर कोई भी लेयर।
9.	एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए)	ग्राहक की वित्तीय जानकारी एकत्र करना और ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट ग्राहक या अन्य को समेकित, संगठित और पुनर्प्राप्ति योग्य तरीके से प्रदान करना।	बेस लेयर
10.	एनबीएफसी-समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी)	धन जुटाने में मदद करने के लिए उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना।	बेस लेयर
11.	आवास वित्त कंपनी (एचएफ़सी)	आवासीय रिहाइश इकाइयों की खरीद/निर्माण/पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत के लिए वित्तपोषण।	मध्य लेयर या ऊपरी लेयर, जैसा भी मामला हो।

टिप्पणियाँ: 1. एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) मध्य लेयर में स्थित हैं।
2. सरकारी एनबीएफसी या तो बेस या मध्य लेयर में स्थित हैं।

स्रोत : आरबीआई।

लिए मिडिल और अपर लेयरों पर एनबीएफसी के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा भी निर्दिष्ट की है (बॉक्स VI.1)।

VI.6 वर्तमान विनियामकीय दिशानिर्देश अधिदेशित करते हैं कि केवल ₹10 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) वाली कंपनियाँ ही एनबीएफसी की

बॉक्स VI.1 : एनबीएफसी के लिए नया विनियामकीय ढांचा

पिछले कुछ वर्षों में, भारत में एनबीएफसी क्षेत्र ने तेजी से प्रगति की है, अपर्याप्त बैंकिंग-सेवा वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल वित्तीय उत्पादों की पेशकश कर वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाया गया है। हाल के वर्षों में, हालांकि, कई एनबीएफसी ने वित्तीय प्रणाली में अंतर-संबंधों के साथ प्रणालीगत महत्व को स्वीकार किया है। आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने हाल ही में एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) शुरू किया, जिससे परिचालनगत लचीलापन बरकार रखते हुए बैंकों और बड़े एनबीएफसी के बीच विनियामकीय मध्यस्थता को कम किया गया।

पर्यवेक्षी डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल आस्ति का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा, मिडिल और अपर लेयर वाली एनबीएफसी के पास है और जिससे प्रणालीगत जोखिम पैदा हो सकते हैं (चार्ट 1ए और बी)। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इन दो लेयरों में स्थित एनबीएफसी के लिए उत्तरोत्तर सख्त विनियामकीय व्यवस्था निर्धारित की है।

बैंकों के समान ही एनबीएफसी के लिए भी, रिज़र्व बैंक ने अपनी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे को लागू किया है, इसे मध्य और उपरी स्तरों के एनबीएफसी[5] तक विस्तारित किया गया है ताकि महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंड निर्धारित सीमा का उल्लंघन होने पर समय पर उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी के मामले में, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर), टियर- I पूंजी अनुपात और निवल

(जारी...)

[5] पीसीए ढांचा, टॉप लेयर की एनबीएफसी (एनबीएफसी-टीएल) पर भी लागू होता है। हालाँकि, वर्तमान में टॉप लेयर खाली है। सरकारी एनबीएफसी, एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी), जनता की जमाराशियां नहीं लेने वाली / नहीं लेना चाहने वाली एनबीएफसी, पर पीसीए ढांचा लागू नहीं होता है।

चार्ट 1: स्केल-आधारित विनियमन के तहत एनबीएफसी क्षेत्र
(मार्च 2022 के अंत में)

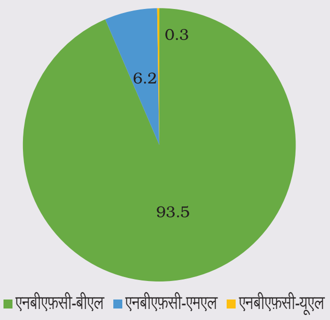

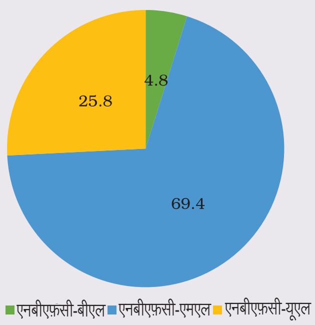

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।
2. सीआईसी, पीडी और एचएफसी सहित।
स्रोत : उपलब्ध पर्यवेक्षी आँकड़ों के आधार पर स्टाफ द्वारा गणना।

सारणी 1: एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी के लिए पीसीए ढांचे के तहत परिभाषित जोखिम सीमा।

संकेतक	आरटी-1	आरटी-2	आरटी-3
सीआरएआर	विनियामकीय न्यूनतम 15 प्रतिशत से कम लेकिन 12 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर।	12 प्रतिशत से कम लेकिन 9 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर।	9 प्रतिशत से कम।
टियर- I पूंजी अनुपात	विनियामकीय न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम लेकिन 8 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर।	8 प्रतिशत से कम लेकिन 6 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर।	6 प्रतिशत से कम।
एनएनपीए अनुपात	6 प्रतिशत से अधिक लेकिन 9 प्रतिशत से कम या इसके बराबर।	9 प्रतिशत से अधिक लेकिन 12 प्रतिशत से कम या उसके बराबर।	12 प्रतिशत से अधिक।

अनर्जक आस्ति अनुपात (एनएनपीए) प्रमुख संकेतक हैं जिनका उपयोग विभिन्न जोखिम सीमा का सीमांकन करने के लिए किया जाता है (आरटी)[6] (सारणी 1)।

पर्यवेक्षी डेटा यह प्रदर्शित करता है कि समग्र स्तर पर, एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल कम चूक (डेलिंक्वेंसी) अनुपात के साथ-साथ पर्याप्त पूंजीकृत हैं (चार्ट 2)। विभिन्न जोखिम सीमा (थ्रेसहोल्ड) वाली एनबीएफसी के अधिक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि 10 एनबीएफसी-यूएल[7], जिसमें तीन एनबीएफसी-डी और सात एनबीएफसी-एनडी-एसआई शामिल हैं, तीनों मापदंडों में विनियामकीय मानदंडों को पूरा करते हैं। रिज़र्व बैंक प्रणाली-स्तरीय सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए इन कंपनियों की निरंतर निगरानी करता है।

एनबीएफसी-एमएल के मामले में, विश्लेषण में विचार किए गए 90 प्रतिशत एनबीएफसी सभी तीन मापदंडों में विनियामकीय मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि, कुछ कंपनियां वर्तमान में दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा,

चार्ट : 2 एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल के लिए विभिन्न मापदंडों का औसत मूल्य (मार्च 2022 के अंत में)

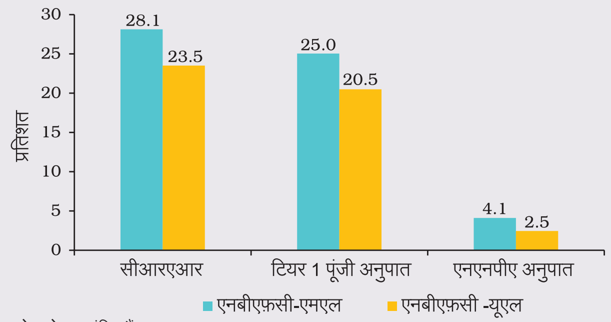

नोट: डेटा अनंतिम है।
स्रोत : उपलब्ध पर्यवेक्षी आँकड़ों के आधार पर स्टाफ द्वारा गणना।

2019 के तहत मध्यस्थता और समाधान की प्रक्रिया में हैं और निर्धारित जोखिम सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, यह अपेक्षा है कि एक बार जब ये कंपनियां समाधान से सफलतापूर्वक गुजरेंगी, तो वे स्वस्थ विवेकपूर्ण अनुपात बनाए रखने में सक्षम होंगी।

संदर्भ

स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा, आरबीआई, 22 अक्टूबर 2021
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT1127AD09AD866884557BD4DEEA150ACC91A.PDF

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा, आरबीआई, 14 दिसंबर 2021
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/139PCANBFCSC3389782516C440DAF56D30473BF005B.PDF

[6] सीआईसी के लिए निगरानी योग्य मानदंड, समायोजित निवल मालियत (नेट वर्थ) / सकल जोखिम भारित आस्तियां, लीवरेज अनुपात और एनएनपीए हैं।
[7] शेष छह एनबीएफसी-यूएल में पांच एचएफसी और एक सीआईसी शामिल हैं।

गतिविधियों[8] को शुरू कर सकती हैं। मौजूदा एनबीएफसी-आईसीसी, एनबीएफसी-एमएफआई और एनबीएफसी-फैक्टर से अपेक्षित है कि वे ग्लाइड-पाथ का अनुवर्तन करते हुए मार्च 2027 तक ₹10 करोड़ का एनओएफ प्राप्त करें।

VI.7 वर्ष 2021-22 के दौरान, एनबीएफसी के पंजीकरण की संख्या में मामूली गिरावट आई और रद्द होने वालों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई (चार्ट VI.3)। महामारी के कारण डिजिटल ऋणदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है क्योंकि ग्राहक तेजी से अल्पकालिक ऋण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। ऐसी कई एनबीएफसी ने, आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) पर मौजूदा विनियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और उनके लाइसेंस रद्द किए गए।

चार्ट VI.3: एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पंजीकरण और निरसन

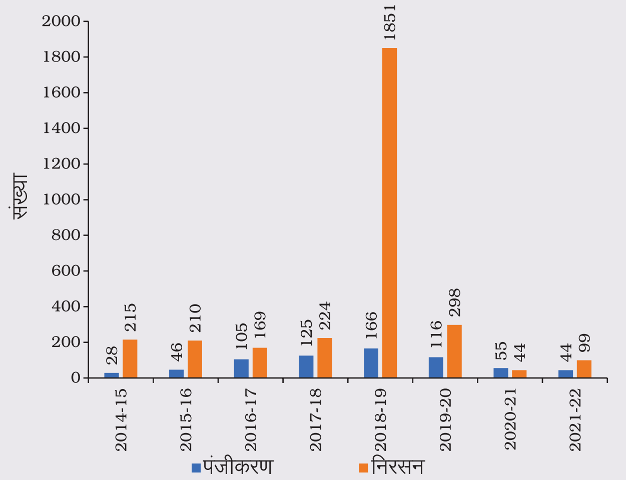

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई।

2.1 स्वामित्व का स्वरूप

VI.8 एनबीएफसी क्षेत्र की कुल आस्तियों में एनबीएफसी-एनडी-एसआई श्रेणी का हिस्सा मार्च 2022 के अंत तक लगभग 86 प्रतिशत है। हालांकि इस श्रेणी में बड़े पैमाने पर गैर-सरकारी कंपनियां आती हैं, कुछ सरकारी स्वामित्व वाले बड़े एनबीएफसी के पास एनबीएफसी-एनडी-एसआई उप-क्षेत्र की आस्ति का एक बड़ा हिस्सा है (सारणी VI.2)।

VI.9 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा एनबीएफ़सी-डी की जमाराशियों का बीमा नहीं किया जाता है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य किया है कि केवल निवेश ग्रेड एनबीएफसी-डी, अपने एनओएफ के 1.5 गुना की सीमा तक और केवल 12 से 60 महीने के अवधि के लिए, ब्याज दरों पर 12.5 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के साथ, जनता से सावधि जमा स्वीकार करेंगे। मई 2022 में, यह अधिदेश दिया गया था कि एनबीएफसी की जमाराशियों की सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से किसी से भी 'बीबीबी-' की न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए।

सारणी VI.2: एनबीएफसी का स्वामित्व स्वरूप
(मार्च 2022 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रकार	एनबीएफसी-एनडी-एसआई			एनबीएफसी-डी		
	संख्या	आस्ति का आकार	आस्ति शेयर प्रतिशत में	संख्या	आस्ति का आकार	आस्ति शेयर प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
ए. सरकारी कंपनियां	**19**	**14,91,617**	**45.4**	**4**	**64,729**	**11.7**
बी. गैर-सरकारी कंपनियां (1+2)	**403**	**17,96,727**	**54.6**	**45**	**4,87,848**	**88.3**
1. पब्लिक लिमिटेड कंपनियां	234	13,96,233	42.5	41	4,87,839	88.3
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	169	4,00,494	12.2	4	9	0
कुल (ए+बी)	**422**	**32,88,344**	**100.0**	**49**	**5,52,577**	**100.0**

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई।

8 ऐसे एनबीएफसी-पी2पी, एनबीएफसी-एए और एनबीएफसी के लिए जिनका कोई सार्वजनिक निधि नहीं है और कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है, एनओएफ 2 करोड़ बना हुआ है। इसके अलावा, एनबीएफसी-आईडीएफ, एनबीएफसी-आईएफसी, एनबीएफसी-एमजीसी, एचएफसी और एसपीडी के लिए मौजूदा विनियामक न्यूनतम एनओएफ में कोई बदलाव नहीं है।

VI.10 मार्च 2022 के अंत में, एनबीएफसी क्षेत्र की कुल आस्ति में एनबीएफसी-डी का हिस्सा 14.4 प्रतिशत था। एनबीएफसी-डी की कुल आस्तियों में गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां की हिस्सेदारी 88.3 प्रतिशत के साथ उनका इस श्रेणी में वर्चस्व रहा (सारणी VI.2)।

2.2 तुलन-पत्र

VI.11 वर्ष 2021-22 में एनबीएफसी के तुलन-पत्र का आकार धीमी गति से बढ़ा, जो कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधानों के बीच कमजोर मांग और जोखिम से बचने, दोनों को दर्शाता है। बैंकों से प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण एनबीएफसी को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, खासकर खुदरा क्षेत्र में। फिर भी, इस क्षेत्र ने पर्याप्त चलनिधि बफर, पर्याप्त प्रावधान और मजबूत पूंजीगत स्थिति बनाए रखा।

VI.12 इस क्षेत्र के ऋणों और अग्रिमों में गिरावट, एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा असुरक्षित ऋणों में पूर्ण गिरावट, से प्रेरित थी, जो आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में सुरक्षित आस्तियों के लिए उनकी प्राथमिकता को उजागर करता है। एनबीएफसी-एनडी-एसआई ने भी अपनी नकदी और बैंक शेष में द्विअंकीय वृद्धि के साथ अपनी चलनिधि में वृद्धि जारी रखा। सितंबर 2022 के अंत में, एनबीएफसी-एनडी-एसआई के निवेश में गिरावट के कारण एनबीएफसी के तुलन पत्र की वृद्धि में थोड़ी कमी आई। हालांकि, एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी दोनों का ऋण, दो अंकों में बढ़ा (परिशिष्ट सारणी VI.1, VI.2 और VI.3)।

VI.13 एनबीएफसी-डी द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दरों के आकर्षण ने 2021-22 में उनकी जनता की जमाराशियों में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की। जहाँ, उनकी ऋण बही ने एक मजबूत विस्तार प्रदर्शित किया, उनके निवेश, नकदी और बैंक जमा शेष में गिरावट आई (सारणी VI.3)।

सारणी VI.3: एनबीएफसी का संक्षिप्त तुलन पत्र

(राशि करोड़ ₹ में)

मदें	मार्च 2021 के अंत में			मार्च 2022 के अंत में			सितंबर 2022 के अंत में		
	एनबीएफसी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	एनबीएफसी-डी	एनबीएफसी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	एनबीएफसी-डी	एनबीएफसी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	एनबीएफसी-डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां	7,97,627	6,96,742	1,00,884	9,01,449	7,89,909	1,11,541	8,40,345	7,25,704	1,14,641
	(26.3)	(27.6)	(17.6)	(13.0)	(13.4)	(10.6)	(3.4)	(2.7)	(8.5)
2. जनता की जमाराशि	62,262	-	62,262	70,754	-	70,754	71,640	-	71,640
	(24.5)		(24.5)	(13.6)		(13.6)	(7.8)	-	(7.8)
3. डिबेंचर	9,82,576	8,83,895	98,681	10,06,496	8,97,508	1,08,988	10,09,804	8,98,490	1,11,314
	(8.4)	(10.1)	(-4.5)	(2.4)	(1.5)	(10.4)	(2.2)	(1.5)	(8.1)
4. बैंक उधार	7,75,099	6,60,285	1,14,815	9,04,715	7,85,089	1,19,625	9,23,732	7,88,646	1,35,086
	(11.5)	(15.7)	(-7.7)	(16.7)	(18.9)	(4.2)	(26.4)	(26.1)	(28.0)
5. वाणिज्यिक पत्र	72,597	64,074	8,523	70,117	62,218	7,899	72,340	57,560	14,780
	(8.6)	(7.9)	(14.0)	(-3.4)	(-2.9)	(-7.3)	(0.5)	(-4.7)	(27.2)
6. अन्य	8,14,174	6,80,946	1,33,228	8,87,389	7,53,619	1,33,770	9,00,311	7,64,012	1,36,298
	(-0.6)	(-3.2)	(15.0)	(9.0)	(10.7)	(0.4)	(7.1)	(9.1)	(-3.0)
कुल देयताएं / आस्तियाँ	**35,04,335**	**29,85,943**	**5,18,392**	**38,40,921**	**32,88,344**	**5,52,577**	**38,18,173**	**32,34,413**	**5,83,760**
	(10.6)	**(11.3)**	**(6.5)**	**(9.6)**	**(10.1)**	**(6.6)**	**(8.8)**	**(8.6)**	**(9.6)**
1. ऋण और अग्रिम	27,02,618	22,78,224	4,24,394	29,08,743	24,47,059	4,61,684	29,37,051	24,51,024	4,86,028
	(9.7)	(11.3)	(1.6)	(7.6)	(7.4)	(8.8)	(10.3)	(10.3)	(10.7)
2. निवेश	4,44,837	3,98,236	46,601	5,13,891	4,68,413	45,479	4,50,462	3,98,252	52,210
	(27.9)	(29.0)	(19.0)	(15.5)	(17.6)	(-2.4)	(-4.1)	(-5.9)	(11.5)
3. नकद और बैंक जमा शेष	1,57,708	1,23,474	34,235	1,80,341	1,48,174	32,167	1,80,066	1,48,793	31,272
	(20.0)	(8.1)	(98.2)	(14.4)	(20.0)	(-6.0)	(11.1)	(14.8)	(-3.4)
4. अन्य चालू आस्तियाँ	1,59,543	1,46,988	12,555	1,65,364	1,52,703	12,661	1,75,179	1,63,808	11,371
	(-11.5)	(-12.8)	(32.2)	(3.6)	(3.9)	(0.8)	(8.9)	(8.7)	(12.3)
5. अन्य आस्तियाँ	39,629	39,021	608	72,581	71,994	587	75,414	72,536	2,878
	(-13.1)	(-12.9)	(-80.3)	(83.2)	(84.5)	(-3.4)	(34.5)	(39.7)	(-30.6)

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.4: एनबीएफसी ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण
(मार्च के अंत में)

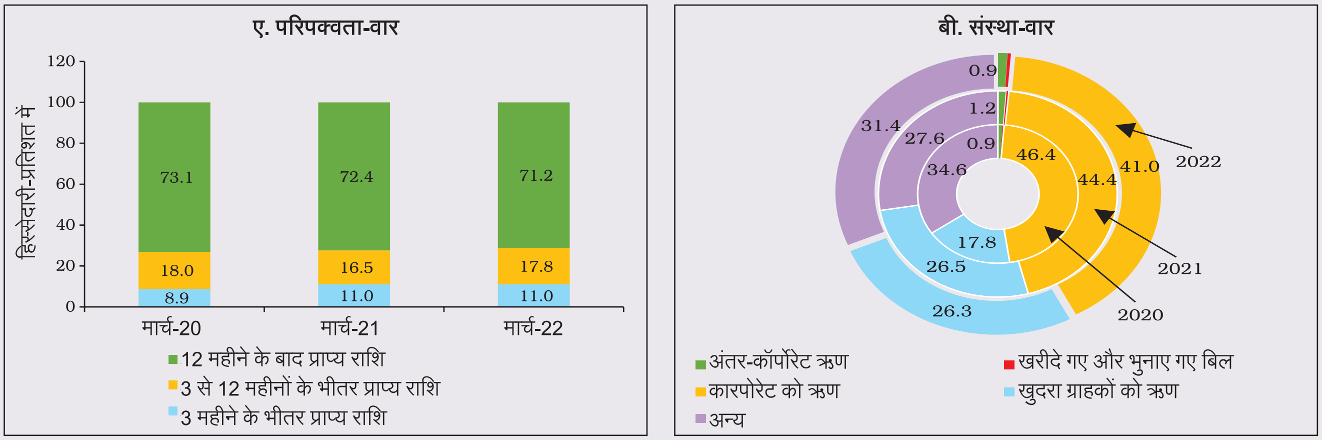

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

VI.14 एनबीएफसी के ऋण की परिपक्वता प्रोफ़ाइल इंगित करती है कि उनके दो-तिहाई से अधिक ऋण 12 महीनों के बाद प्राप्य हैं, हालांकि महामारी ने कम अवधि के ऋणों की ओर एक मामूली बदलाव को प्रेरित किया (चार्ट VI.4ए)। कॉर्पोरेट और खुदरा ग्राहक एनबीएफसी ऋण के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। मांग न होने के कारण, 2020 और 2022 में एनबीएफसी की ऋण बही में थोक ऋण का हिस्सा कम हुआ है। दूसरी ओर, विवेकाधीन व्यय में वृद्धि के कारण खुदरा ऋणों की हिस्सेदारी में जोरदार वृद्धि हुई (चार्ट VI.4बी)।

VI.15 एनबीएफसी-एनडी-एसआई के बीच, आईसीसी और आईडीएफ के तुलन-पत्रों में 2021-22 में वृद्धि जारी रही, जबकि आईएफसी का प्रदर्शन नरम रहा। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के मामले में, कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद संग्रह दक्षता और संवितरण में थोड़ी कमी के कारण वृद्धि धीमी हुई (सारणी VI.4)।

VI.16 वर्ष 2021-22 में एनबीएफसी-एनडी-एसआई की कुल आस्ति में आईसीसी और आईएफसी का हिस्सा लगभग 95 प्रतिशत था (चार्ट VI.5ए)। जहाँ पहला, बड़े पैमाने पर सेवाओं और खुदरा क्षेत्रों को उधार देता है, वहीं बाद वाले में मुख्य रूप से बड़े सरकारी एनबीएफसी शामिल हैं, जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कार्य करते हैं। सेवा क्षेत्र में उछाल के कारण आईसीसी द्वारा ऋण देने में वृद्धि हुई। विशेष रूप से, आर्थिक गतिविधियों में पुन:आरंभ, आवास ऋण पर कम ब्याज दरों और कुछ राज्यों में स्टैंप ड्यूटी में कटौती आदि के कारण, वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही से वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) खंड तेजी से बढ़ रहा है। एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम भी दो अंकों में बढ़े, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में गति धीमी रही।

VI.17 बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने, बिजली क्षेत्र में दो सरकारी आईएफ़सी को आत्मनिर्भर भारत अभियान (एबीए) के तहत, पात्र डिस्कॉम को उधार देने का निर्देश दिया था। परिणामस्वरूप, इन दोनों आईएफ़सी ने 2020-21 में बड़े संवितरण किए थे। एबीए के तहत संवितरण 2021-22 में जारी रहा लेकिन गति धीमी रही। एक अन्य सरकारी आईएफ़सी द्वारा रेलवे को दिया जाने वाला कर्ज 2020-21 में ₹1 लाख करोड़ से कम होकर 2021-22 में लगभग ₹60,000 करोड़ हो गया। इन तीन सरकारी आईएफ़सी जो एनबीएफ़सी-एनडी-एसआई की कुल आस्तियों का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं, के कारण आईएफ़सी क्रेडिट

सारणी VI.4: वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी-एनडी-एसआई की देयताओं और आस्तियों के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में राशि)

श्रेणी/देयता	मार्च 2021 के अंत में			मार्च 2022 के अंत में			सितंबर 2022 के अंत में			कुल देयताओं में प्रतिशत घट-बढ़	
	उधारियां	अन्य देयताएं	कुल देयताएं	उधारियां	अन्य देयताएं	कुल देयताएं	उधारियां	अन्य देयताएं	कुल देयताएं	(मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 में)	(मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एनबीएफसी-आईसीसी	9,30,742	6,28,683	15,59,426	10,25,201	6,99,637	17,24,838	10,31,564	6,28,668	16,60,232	8.1	10.6
एनबीएफसी-फैक्टर	1,839	2,039	3,878	1,477	1,418	2,895	1,203	659	1,862	-0.4	-25.4
एनबीएफसी-आईडीएफ	28,429	6,415	34,844	34,641	8,003	42,644	29,386	6,601	35,988	16.9	22.4
एनबीएफसी-आईएफसी	10,41,895	2,39,515	12,81,409	11,12,015	2,72,543	13,84,558	11,26,612	2,89,536	14,16,149	13.9	8.0
एनबीएफसी-एमएफआई	62,585	25,830	88,415	75,127	28,712	1,03,840	66,779	24,210	90,989	33.6	17.4
अन्य	77	17,893	17,970	1,900	27,670	29,569	2,086	27,108	29,194	26.8	64.6
कुल	**20,65,567**	**9,20,376**	**29,85,943**	**22,50,360**	**10,37,984**	**32,88,344**	**22,57,631**	**9,76,782**	**32,34,413**	**11.3**	**10.1**
श्रेणी/आस्ति	ऋण और अग्रिम	अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां	ऋण और अग्रिम	अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां	ऋण और अग्रिम	अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां	कुल आस्तियों में प्रतिशत घट-बढ़	
										(मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021में)	(मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 में)
एनबीएफसी-आईसीसी	10,07,142	5,52,283	15,59,426	10,85,372	6,39,466	17,24,838	10,82,404	5,77,828	16,60,232	8.1	10.6
एनबीएफसी-फैक्टर	2,961	917	3,878	2,296	599	2,895	1,767	96	1,862	-0.4	-25.4
एनबीएफसी-आईडीएफ	30,414	4,430	34,844	34,475	8,169	42,644	32,902	3,086	35,988	16.9	22.4
एनबीएफसी-आईएफसी	11,69,244	1,12,165	12,81,409	12,43,485	1,41,073	13,84,558	12,60,866	1,55,283	14,16,149	13.9	8.0
एनबीएफसी-एमएफआई	68,462	19,954	88,415	81,430	22,410	1,03,840	73,086	17,903	90,989	33.6	17.4
अन्य	-	17,970	17,970	1	29,569	29,569	-	29,194	29,194	26.8	64.6
कुल	**22,78,224**	**7,07,719**	**29,85,943**	**24,47,059**	**8,41,285**	**32,88,344**	**24,51,024**	**7,83,389**	**32,34,413**	**11.3**	**10.1**

टिप्पणी : डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

2021-22 में धीमी वृद्धि हुई। एनबीएफसी-फैक्टर एकमात्र श्रेणी थी जिसने ऋण वृद्धि में गिरावट दर्ज की, जो एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना किए गए नकदी प्रवाह अवरोधों को दर्शाता है (चार्ट VI.5बी)।

चार्ट VI.5: वर्गीकरण-वार एनबीएफसी-एनडी-एसआई: चुनिंदा संकेतक

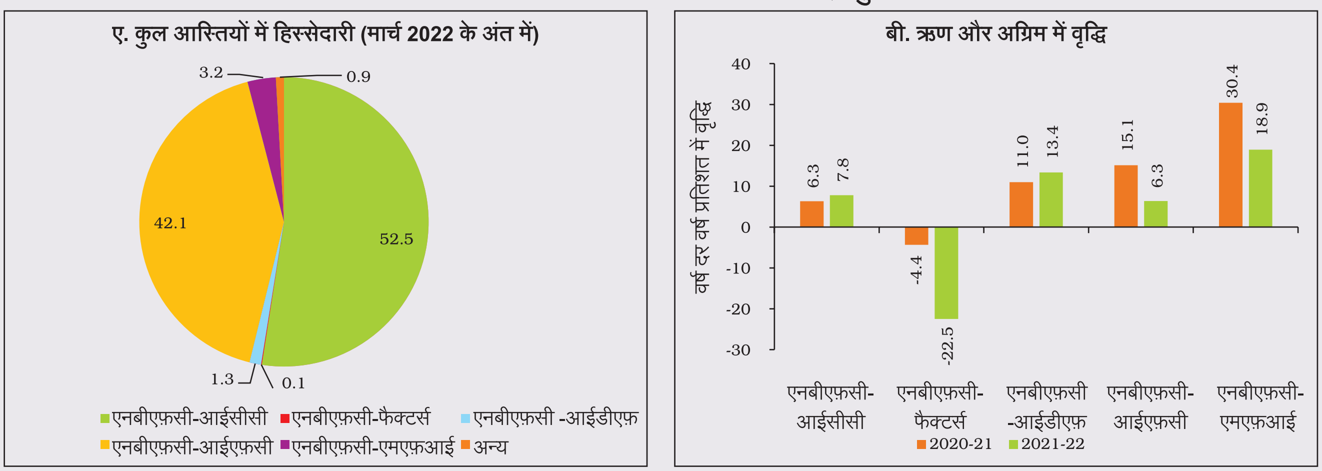

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोतः पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

चार्ट VI.6: एनबीएफसी ऋण का वितरण
(मार्च अंत तक की स्थिति)

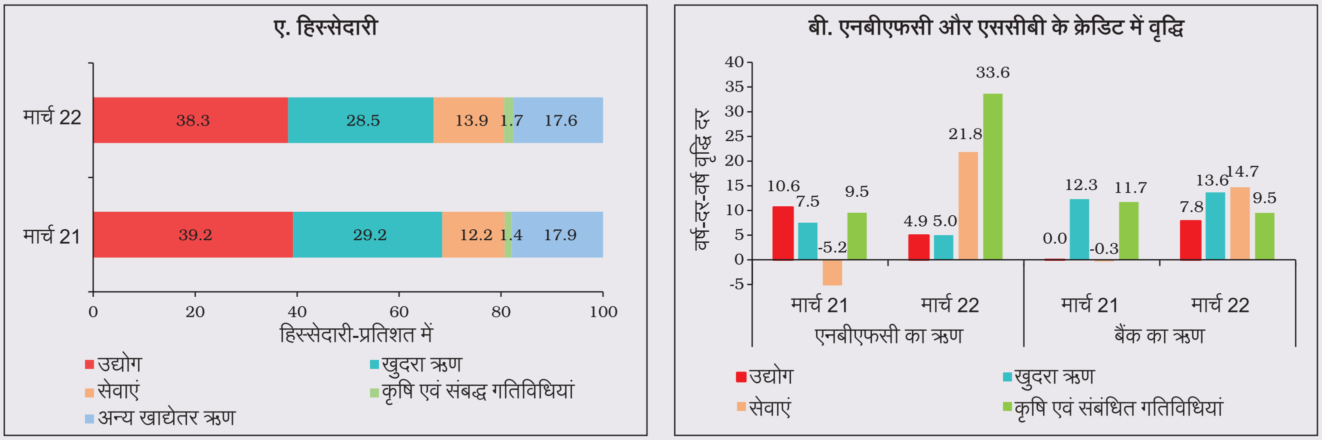

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

2.3 एनबीएफसी का क्षेत्रवार ऋण

VI.18 उद्योग ने परंपरागत रूप से एनबीएफसी क्षेत्र से सबसे अधिक ऋण प्राप्त किया है, इसके बाद खुदरा, सेवाओं और कृषि का स्थान रहा है (चार्ट VI.6ए और परिशिष्ट सारणी VI.4)। वर्ष 2021-22 में, उद्योग और खुदरा क्षेत्रों के लिए ऋण वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम रही, जबकि सेवा क्षेत्र के ऋण में द्विअंकीय वृद्धि दर्ज की गई।

VI.19 वर्ष 2021-22 के दौरान, जहाँ, उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए बैंकों का ऋण अनुकूल आधार प्रभाव से लाभान्वित हुआ, खुदरा खंड में बैंकों ने एनबीएफसी से बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट VI.6बी)।

VI.20 उद्योग में, लगभग 86 प्रतिशत औद्योगिक ऋण, बुनियादी ढाँचे को जाता है, जो 2021-22 में केवल 1.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा और समग्र ऋण वृद्धि को नीचे खींच लिया।

VI.21 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की ऋण जरूरतों को पूरा करने में भी एनबीएफसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं - सेवा क्षेत्र से जुड़े एमएसएमई को इसमें प्राथमिकता देते हुए (चार्ट VI.7)। सरकार द्वारा मई 2020 में शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ने एमएसएमई को वर्धित क्रेडिट प्राप्त करने में मदद की। रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 2020 में शुरू किए गए सह-उधार मॉडल ने भी एमएसएमई क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार किया। इसके बाद, केंद्रीय बजट 2022-23 ने ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है, जिसमें गारंटी कवर ₹50,000 करोड़ बढ़ाकर, कुल ₹5 लाख करोड़ कर दिया गया है।

चार्ट VI.7: एमएसएमई क्षेत्र को एनबीएफसी का ऋण
(मार्च के अंत में)

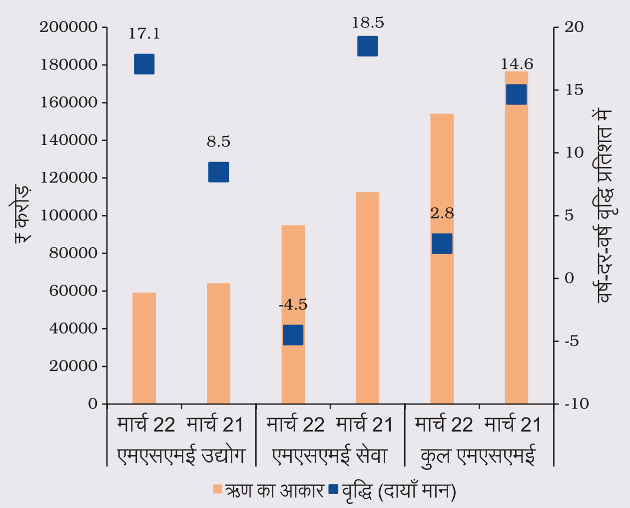

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

चार्ट VI.8: वाहन ऋण- एनबीएफसी *बनाम* एससीबी

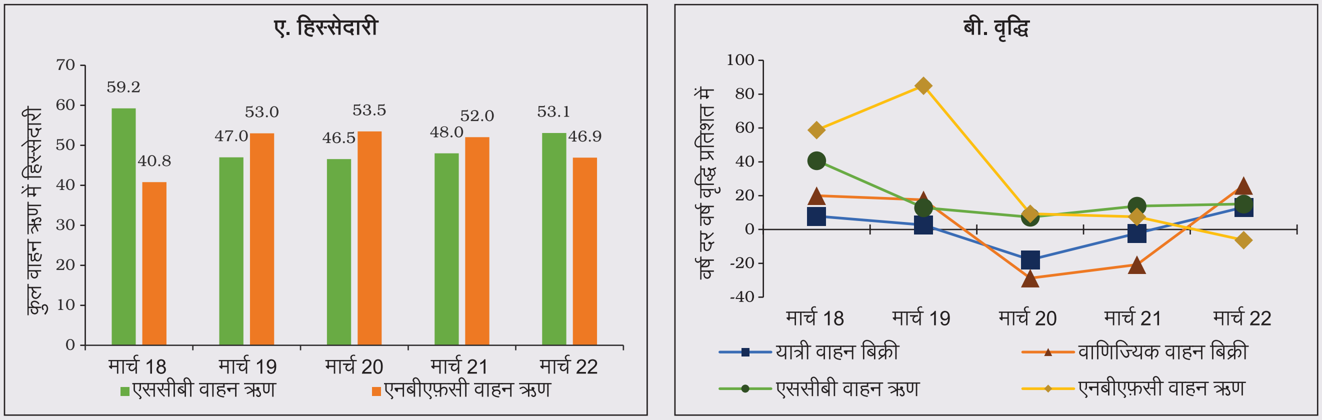

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: 1. पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।
2. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम)।
3. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसियेशन (एफएडीए)

VI.22 वाहन ऋण में, जो परंपरागत रूप से एनबीएफसी के खुदरा पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा घटक है, 2021-22 के दौरान गिरावट आई। तदनुसार, वाहन और ऑटो ऋण का हिस्सा, जो मार्च 2021 के अंत में एनबीएफसी के खुदरा पोर्टफोलियो का लगभग 45 प्रतिशत था, मार्च 2022 के अंत में गिरकर लगभग 40 प्रतिशत रह गया। हाल के वर्षों में, बैंकों ने वाहन ऋण क्षेत्र एनबीएफसी के लिए खाली छोड़ दिया था। वर्ष 2021-22 में यह उलट गया और इस क्षेत्र में बैंकों की हिस्सेदारी एनबीएफसी से अधिक हो गई (चार्ट VI.8ए)। वर्ष 2021-22 में, वाहनों की खुदरा बिक्री में पिछले वर्ष के संकुचन के बाद सुधार हुआ (चार्ट VI.8बी)।

VI.23 स्वर्ण के बदले अग्रिम देना वह विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें एनबीएफसी की बाजार में मजबूत उपस्थिति है। हालांकि, बैंकों को दी गई ऋण-मूल्य अपेक्षाओं (लोन टू वैल्यू) में छूट ने महामारी की अवधि के दौरान उनके स्वर्ण ऋण व्यवसाय को बढ़ावा दिया। परिणामस्वरूप, 2020-21 में स्वर्ण ऋण क्षेत्र में एनबीएफसी की हिस्सेदारी में कमी आई। इसके बाद, छूट समाप्त होने से 2021-22 के दौरान एनबीएफसी की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बहाल हो गई और उनके हिस्से में मामूली सुधार हुआ (चार्ट VI.9)।

VI.24 मार्च 2022 के अंत तक परिवहन ऑपरेटरों, खुदरा व्यापार और वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) खंडों में ऋण का तेजी से विस्तार हुआ। अनुकूल आधार प्रभाव के साथ

चार्ट VI.9: स्वर्ण के एवज में अग्रिमों का वितरण: एनबीएफसी और एससीबी

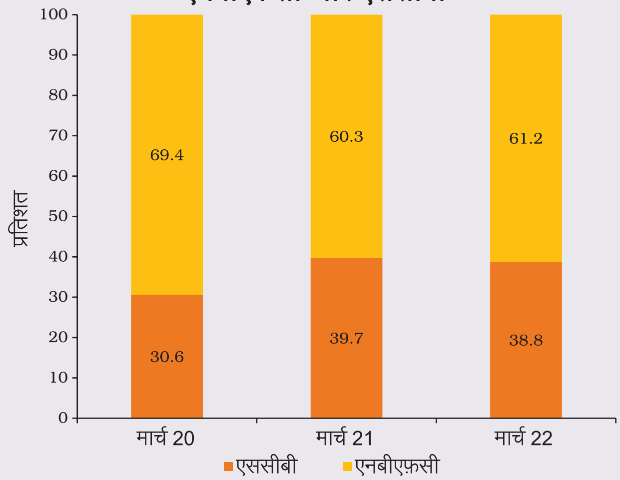

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: 1. पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।
2. सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई।

सारणी VI.5: एनबीएफसी द्वारा क्षेत्र-वार ऋण विनियोजन

(राशि करोड़ ₹ में)

मदें	मार्च 2021 के अंत में	मार्च 2022 के अंत में	सितंबर 2022 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़	
				2020-2021	2021-2022
1	2	3	4	5	6
I. सकल अग्रिम (II + III)	**27,02,618**	**29,08,743**	**29,37,051**	**9.7**	**7.6**
II. खाद्य ऋण	-	-	**1,752**		
III. खाद्येतर ऋण (1 से 5)	**27,02,618**	**29,08,743**	**29,35,299**	**9.7**	**7.6**
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	**37,728**	**50,422**	**46,464**	**9.5**	**33.6**
2. उद्योग	**10,60,411**	**11,12,852**	**11,15,749**	**10.6**	**4.9**
2.1 सूक्ष्म और लघु	44,235	46,967	49,966	21.4	6.2
2.2 मध्यम	14,910	17,186	15,103	5.9	15.3
2.3 बड़ा	8,54,546	8,94,102	8,99,619	7.5	4.6
2.4 अन्य	1,46,720	1,54,598	1,51,061	30.1	5.4
3. सेवाएं	**3,30,758**	**4,02,935**	**3,81,485**	**-5.2**	**21.8**
जिसमें,					
3.1 परिवहन ऑपरेटर	65,313	1,02,742	90,059	2.1	57.3
3.2 खुदरा व्यापार	26,719	40,390	45,066	0.0	51.2
3.3 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	80,480	88,123	79,754	-20.7	9.5
4. खुदरा ऋण	**7,90,073**	**8,29,485**	**8,79,571**	**7.5**	**5.0**
जिसमें,					
4.1 आवास ऋण	21,484	23,329	24,680	52.7	8.6
4.2 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	18,519	24,802	27,464	-3.4	33.9
4.3 वाहन/ऑटो ऋण	3,57,338	3,34,947	3,54,966	7.5	-6.3
4.4 व्यक्तियों को स्वर्ण के बदले अग्रिम	1,12,899	1,18,918	1,18,723	49.6	5.3
4.5 सूक्ष्म वित्त ऋण/एसएचजी ऋण	59,635	74,826	77,567	32.2	25.5
5. अन्य खाद्येतर ऋण	**4,83,648**	**5,13,050**	**5,12,031**	**24.9**	**6.1**

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

कार्यालय और खुदरा स्थानों के लिए नए सिरे से मांग ने इस बहाली में सहायता की। सामान्य मानसून के कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में सहायता मिली (सारणी VI.5)।

VI.25 आईएफ़सी के विपरीत, जो मुख्य रूप से उद्योगों को अपना ऋण प्रदान करते हैं, आईसीसी सभी क्षेत्रों में ऋण प्रदान करते हैं, जिसमें खुदरा क्षेत्र के लिए उच्चतम आबंटन किया गया है (चार्ट VI.10)। एनबीएफसी-एमएफआई ने जो संपार्श्विक-मुक्त छोटे ऋण प्रदान करते हैं, मार्च 2022 के अंत में ऋण संवितरण में तेजी दिखाई।

VI.26 वर्ष 2021-22 में एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रदान किए गए माइक्रोफाइनेंस ऋणों की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि हुई थी (चार्ट VI.11)। रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 में माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए एक सामान्य विनियामक ढांचा तैयार किया, जो

चार्ट VI.10: वर्गीकरण के अनुसार ऋण का क्षेत्रवार विभाजन
(मार्च के अंत में)

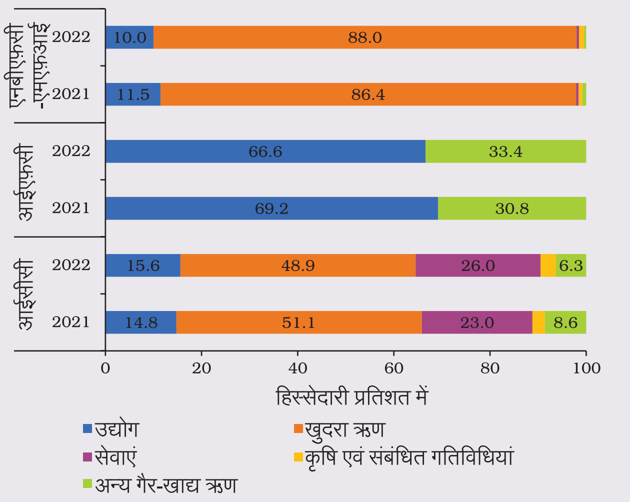

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

चार्ट VI.11: विनियमित संस्थाओं में बकाया माइक्रो-क्रेडिट ऋण
(मार्च के अंत में)

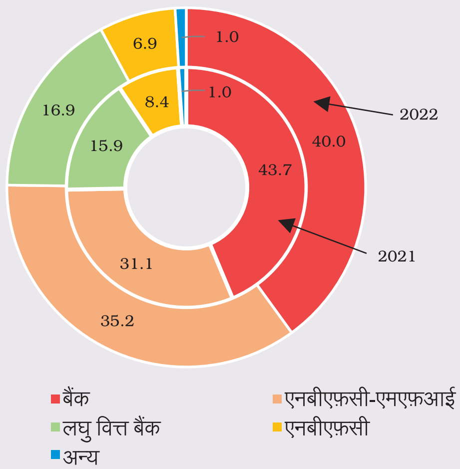

स्रोत: माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन)

सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) पर लागू होता है। आय सीमा में संशोधन करके ₹3 लाख और ब्याज दर कैप को हटाने जैसे प्रावधानों से इस क्षेत्र में ऋण विस्तार की सुविधा में मदद मिलनी चाहिए।

2.4 संसाधन जुटाना

VI.27 एनबीएफसी-डी के अलावा अन्य एनबीएफसी अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए उधार पर बहुत अधिक निर्भर हैं। मार्च 2022 के अंत में बाज़ारों और बैंकों से उधार, कुल उधार का लगभग 75 प्रतिशत था। कम ब्याज दर के माहौल ने बैंकों से उधार लेने संबंधी वृद्धि में योगदान दिया। वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में, मुख्य रूप से बैंकों से उधार लेने में वृद्धि के कारण कुल उधार में तेजी आई (सारणी VI.6)।

VI.28 जहाँ, एनबीएफसी धीरे-धीरे लंबी अवधि के उधार पर अधिक भरोसा कर रहे हैं, 2021-22 में तीन महीने या उससे कम समय में देय उधार के हिस्सा में मामूली वृद्धि हुई है (चार्ट VI.12)।

VI.29 एएए और एए रेटिंग वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का निजी एनबीएफसी के कुल निजी प्लेसमेंट में

सारणी VI.6: एनबीएफसी के उधार के स्रोत

(राशि करोड़ ₹ में)

मदें	मार्च 2021 के अंत में	मार्च 2022 के अंत में	सितंबर 2022 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़	
				2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
1. डिबेंचर	9,82,576 (41.8)	10,06,496 (39.5)	10,09,804 (39.1)	8.4	2.4
2. बैंक उधार	7,75,099 (33.0)	9,04,715 (35.5)	9,23,732 (35.7)	11.5	16.7
3. एफआई से उधार	57,355 (2.4)	66,418 (2.6)	70,875 (2.7)	-9.7	15.8
4. अंतर-कॉर्पोरेट उधार	77,840 (3.3)	86,663 (3.4)	95,573 (3.7)	-0.6	11.3
5. वाणिज्यिक पत्र	72,597 (3.1)	70,117 (2.7)	72,340 (2.8)	8.6	-3.4
6. सरकार से उधार	19,129 (0.8)	18,804 (0.7)	18,857 (0.7)	2.0	-1.7
7. गौण कर्ज	68,984 (2.9)	70,863 (2.8)	67,640 (2.6)	-6.9	2.7
8. अन्य उधार	2,98,099 (12.7)	3,27,015 (12.8)	3,25,874 (12.6)	-10.3	9.7
9. कुल उधार	**23,51,679**	**25,51,092**	**25,84,696**	**5.2**	**8.5**

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उधारी में हिस्सा दर्शाते हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

बड़ा हिस्सा है (चार्ट VI.13ए)।

VI.30 वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जारी किए गए कुल एनसीडी में दो साल और तीन साल की अवधि के एनसीडी

चार्ट VI.12: एनबीएफसी के उधारियों की चुकौती

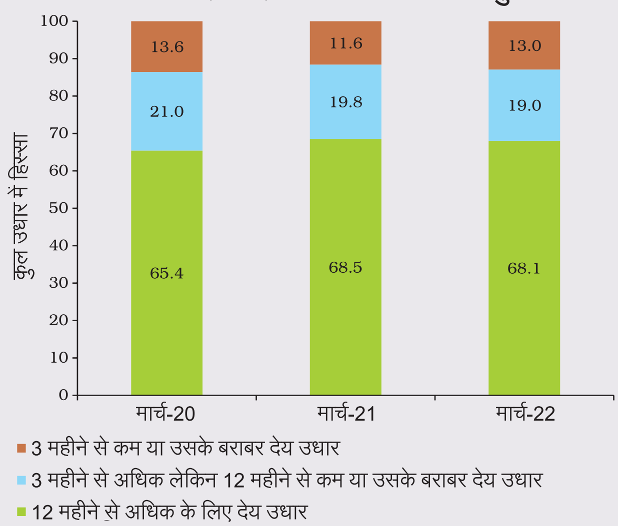

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

चार्ट VI.13: निजी एनबीएफसी के एनसीडी प्राइवेट प्लेसमेंट

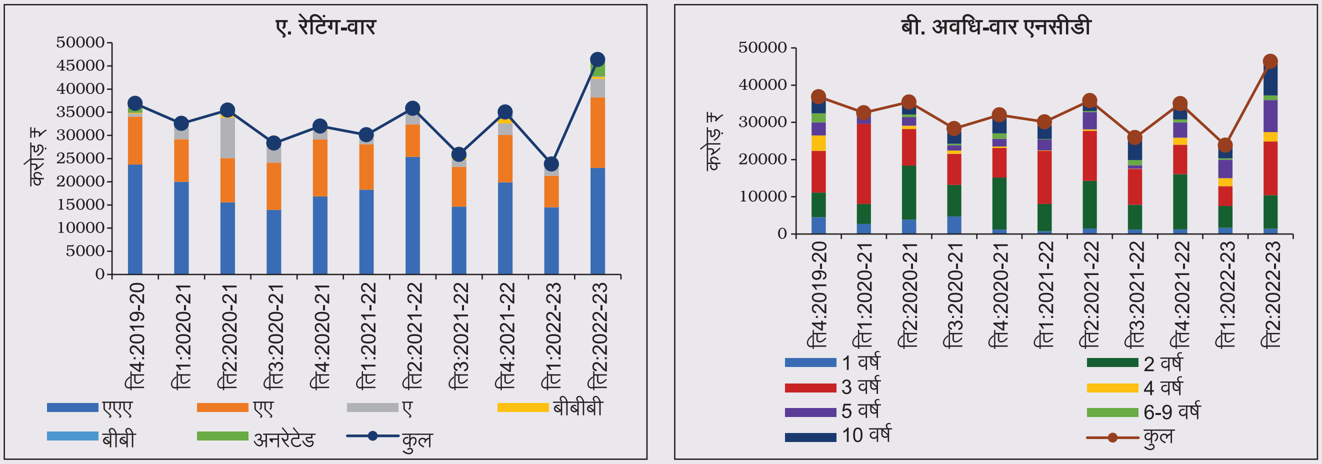

स्रोत: 1. स्टाफ द्वारा गणना।
2. प्राइम डेटाबेस।

मिलाकर लगभग आधे हैं। लंबी अवधि (10 वर्ष से अधिक) के एनसीडी मुख्य रूप से निजी स्वामित्व वाली प्रमुख एनबीएफसी ने जुटाए थे (चार्ट VI.13 बी)।

VI.31 रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित चलनिधि बढ़ाने के उपायों के कारण स्प्रेड में वृद्धि, जो महामारी की अवधि के दौरान देखी गई थी, कम हो गई। हाल के महीनों में, हालांकि, मौद्रिक नीति सामान्यीकरण, तेल की ऊँची कीमतें और बढ़ते वैश्विक प्रतिफल के कारण समान परिपक्वता के सरकारी-प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल की तुलना में एनबीएफसी बॉन्ड प्रतिफल के स्प्रेड में मामूली विस्तार हुआ है (चार्ट VI.14ए और बी)।

VI.32 जैसा कि पहले बताया गया है, एनबीएफसी अपने फंड के लिए एससीबी पर बहुत अधिक निर्भर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) प्रमुख ऋणदाता हैं, इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) और विदेशी बैंक (एफबी) आते हैं (चार्ट VI.15ए और बी)।

चार्ट VI.14: एनबीएफसी बॉन्डों का प्रतिफल: तदनुरूप परिपक्वता अवधि के जी-सेक पर स्प्रेड

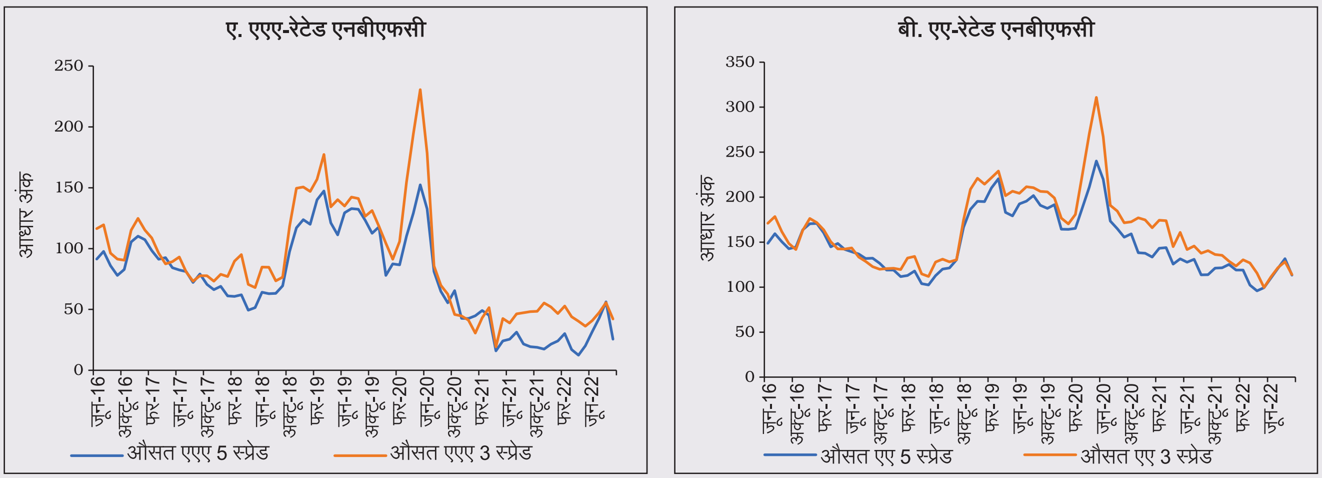

स्रोत: 1. एफआईएमएमडीए
2. ब्लूमबर्ग।

चार्ट VI.15: एनबीएफसी को बैंक ऋण, समूह-वार

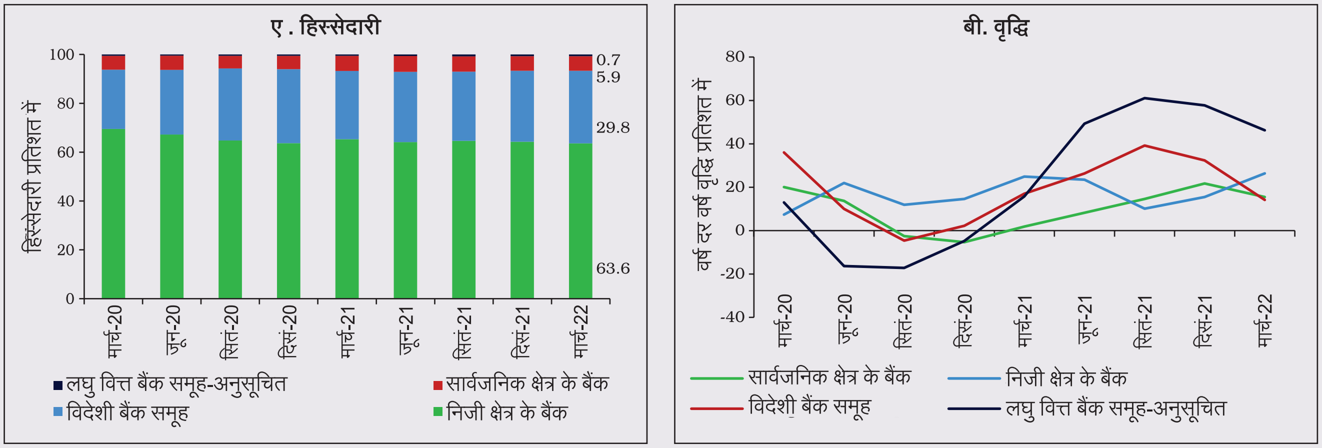

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोतः पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

VI.33 एनबीएफसी में बैंकों का एक्सपोजर मुख्य रूप से प्रत्यक्ष ऋण में वृद्धि के कारण बढ़ा, जो एनबीएफसी क्षेत्र को कुल बैंक वित्तपोषण (फंडिंग) का 86.5 प्रतिशत था (चार्ट VI.16ए)। बैंक, एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) भी सब्सक्राईब हैं। वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के बाद से एनबीएफसी द्वारा जारी सीपी की बैंकों द्वार सब्सक्रिप्शन में बड़ा बदलाव आया है (चार्ट VI.16बी)।

2.5 एनबीएफसी-डी: जमाराशियाँ

VI.34 मार्च 2022 के अंत में एनबीएफसी-डी की कुल देनदारियों में जनता की जमाराशि का हिस्सा 12.8 प्रतिशत था। मजबूत क्रेडिट रेटिंग के साथ प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की पेशकश ने उनकी सतत वृद्धि में योगदान दिया। तथापि, ऐसी जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु अधिकृत कंपनियों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है (चार्ट VI.17)।

चार्ट VI.16: एनबीएफसी को बैंक ऋण की लिखतें

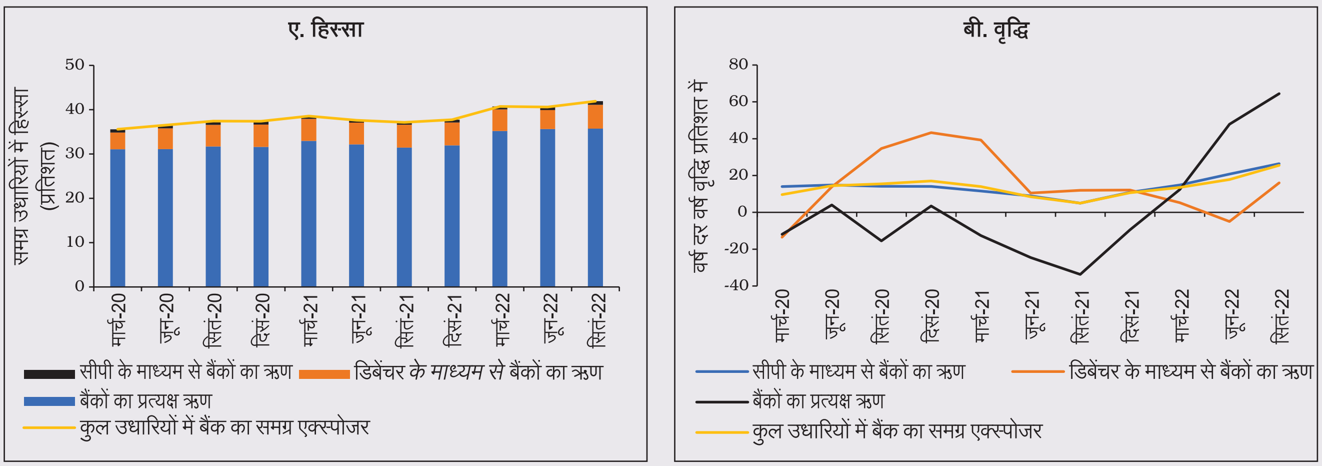

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोतः पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

चार्ट VI.17: एनबीएफसी-डी में जनता की जमाराशियाँ
(मार्च के अंत में)

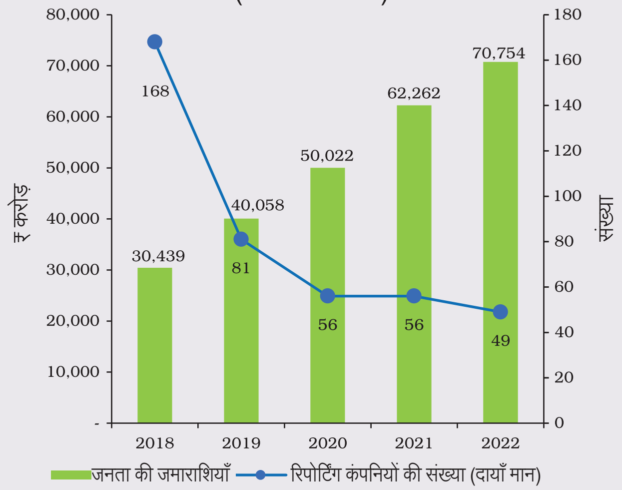

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

चार्ट VI.18: एनबीएफसी-डी में जमाराशियों का वितरण
(मार्च 2022 के अंत में)

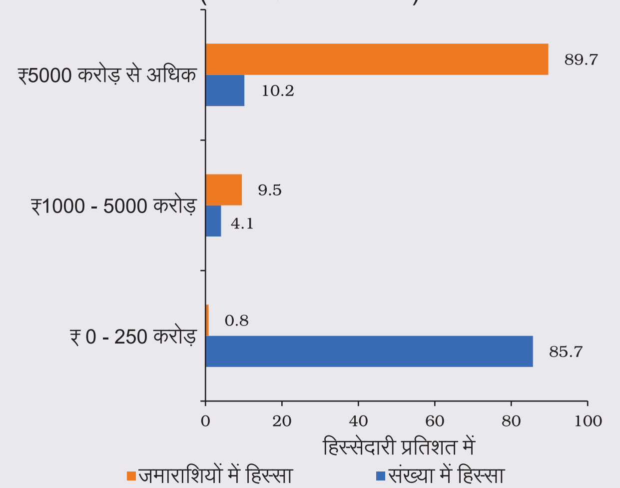

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई

VI.35 जनता की जमाराशियां, इन कंपनियों को सिर्फ बैंकों और पूंजी बाजारों पर निर्भर रहने के बजाय, अपने निधिगत स्रोतों में विविधता लाने की अनुमति देते हैं। लगभग 90 प्रतिशत जमाराशि, 5 एनबीएफसी-डी द्वारा रखे गए थे, जिनमें से सभी की कुल जमाराशि ₹5,000 करोड़ से अधिक थी (चार्ट VI.18)।

2.6 आस्ति की बिक्री और प्रतिभूतिकरण

VI.36 आस्ति की बिक्री एनबीएफसी को अपने एक्सपोजर को पुनर्संतुलित करके और चलनिधि बढ़ाकर अपने तुलन पत्र को मजबूत करने की अनुमति देती है। दिसंबर 2021 में मामूली गिरावट के बाद आस्ति की बिक्री में तेजी आई और मार्च 2022 में यह बिक्री पूर्व-कोविड स्तर को पार कर गई (चार्ट VI.19ए)। प्रतिभूतिकरण, एनबीएफसी को, आस्ति की कार्यनीतिक बिक्री के विपरीत, बैंकों, बीमा कंपनियों और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों सहित एक व्यापक निवेशक आधार के लिए ऋण जोखिम विस्तार में मदद करता है। यह उन्हें अतिरिक्त निधिगत स्रोत भी प्रदान करता है। जून 2021 के बाद से प्रतिभूतिकृत

चार्ट VI.19: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की ऋण बिक्री और प्रतिभूतिकरण

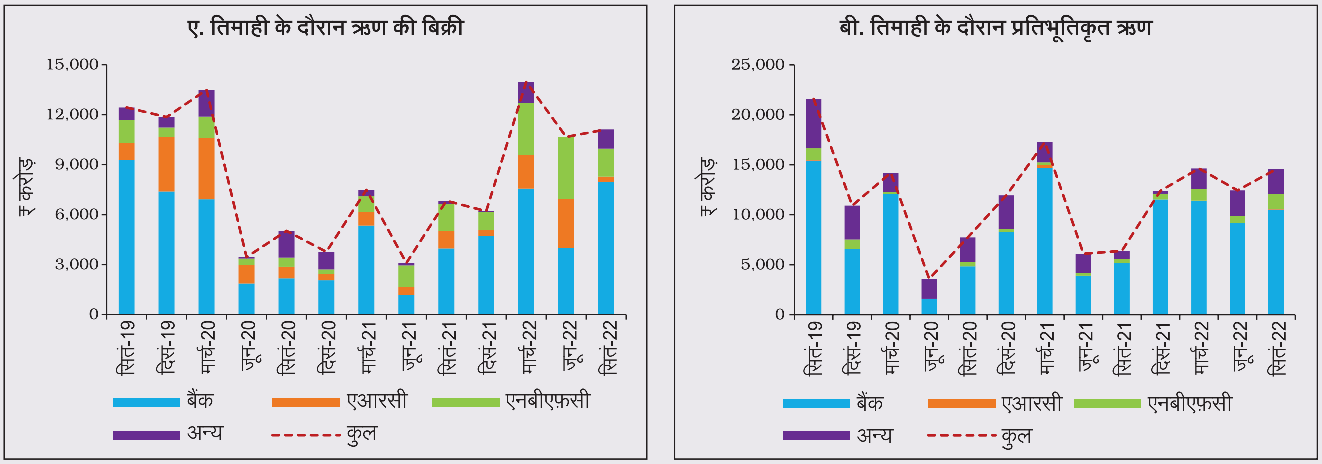

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई

आस्ति क्रमिक आधार पर गति प्राप्त कर रही है (चार्ट VI.19बी)। फिर भी, प्रतिभूतिकरण की मात्रा अभी पूर्व-कोविड स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। एनबीएफसी द्वारा की गई आस्ति की बिक्री और प्रतिभूतिकरण दोनों में, बैंक मुख्य प्रतिपक्ष हैं, जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने की अपेक्षाओं के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इन व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं।

2.7 एनबीएफसी का आस्ति-देयता प्रोफाइल

VI.37 एनबीएफसी की चलनिधि की स्थिति का मूल्यांकन चलनिधि बेमेल की निगरानी द्वारा किया जाता है, जो कि एक निश्चित समयावधि के लिए अंतर्वाह और बहिर्वाह के बीच का अंतर है। बेमेल में सुधार, पर्याप्त चलनिधि स्थिति को इंगित करता है जिसका श्रेय अंतर्वाह में वृद्धि या बहिर्वाह में कमी को दिया जा सकता है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए लघु अवधि बेमेल यानी 1-30/31 दिनों की बकेट महत्वपूर्ण है। बहिर्वाह में गिरावट के कारण, इस बकेट में, मार्च 2021 के अंत की तुलना में मार्च 2022 के अंत में संचयी बेमेल में सुधार देखा गया। छह महीने से एक वर्ष और पांच वर्ष से अधिक को छोड़कर सभी समय बकेट में मार्च 2022 के अंत में सुधार दर्ज किया गया, जिसमें एक वर्ष से कम के बकेट में कोई संचयी ऋणात्मक बेमेल नहीं है (चार्ट VI.20)।

2.8 एनबीएफसी का वित्तीय प्रदर्शन

VI.38 एनबीएफसी की आय एक साल पहले की तुलना में 2021-22 में उच्चतर दर से बढ़ी, जो मुख्य रूप से एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी की फंड-आधारित आय से प्रेरित थी। 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, एनबीएफसी के निवल लाभ में सुधार, मुख्य रूप से फंड आधारित आय में बदलाव से हुआ (परिशिष्ट सारणी VI.5 और VI.6)।

VI.39 व्यय पक्ष पर, एनबीएफसी के परिचालन व्यय में भारी वृद्धि हुई। दूसरी ओर, एनपीए के विरुद्ध प्रावधानों में गिरावट आई, जो आस्ति की गुणवत्ता की चिंताओं में कमी को दर्शाता है। कुल मिलाकर, कम प्रावधानों और बैंक ऋणों और अंतर-कॉर्पोरेट जमाओं पर ब्याज व्यय में कमी के कारण इस क्षेत्र के समग्र व्यय में गिरावट आई। परिणामत: निवल लाभ में एक ख़ासी वृद्धि हुई। एनबीएफसी क्षेत्र के सभी श्रेणियों में लागत - आय अनुपात में गिरावट उनके परिचालन में दक्षता बढ़त दर्शाती है (सारणी VI.7)। वर्ष 2022-23 में (सितंबर के अंत तक), कुल व्यय में वृद्धि को पार करते हुए कुल आय में बदलाव आया।

चार्ट VI.20: एनबीएफसी की संरचनात्मक चलनिधि विवरणी
(मार्च/सितंबर के अंत में)

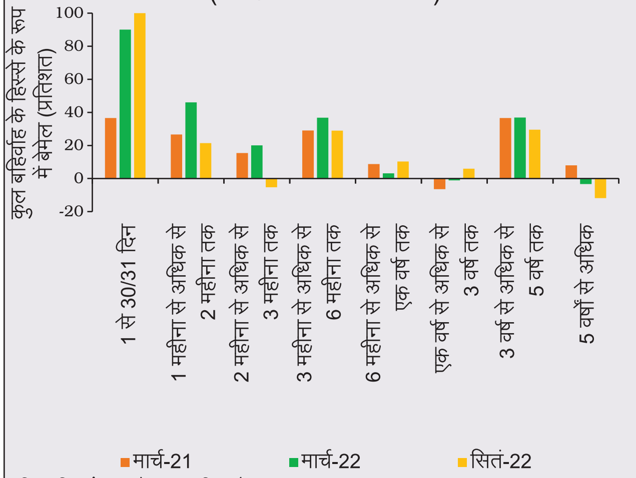

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. बेमेल को इनफ्लो माइनस आउटफ्लो के रूप में परिभाषित किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

2.9 लाभप्रदता संकेतक

VI.40 लाभप्रदता संकेतक – आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) – में 2021-22 में वृद्धि हुई। मार्च 2022 के अंत में एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी के निवल लाभ में संवृद्धि (बॉटम लाइन ग्रोथ) देखी गई (चार्ट VI.21)। सभी लाभप्रदता संकेतकों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में सुधार दिखाया।

सारणी VI.7: एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय मापदंड

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	2020-21			2021-22			छ1: 2022-23		
	एनबीएफसी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	एनबीएफसी-डी	एनबीएफसी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	एनबीएफसी-डी	एनबीएफसी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	एनबीएफसी-डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. आय	3,56,252 (3.9)	2,89,157 (4.7)	67,095 (0.8)	3,76,563 (5.7)	3,03,831 (5.1)	72,732 (8.4)	2,09,589 (20.0)	1,69,696 (21.7)	39,893 (13.2)
बी. व्यय	3,00,373 (4.8)	2,44,869 (4.2)	55,504 (7.9)	2,94,928 (-1.8)	2,39,645 (-2.1)	55,282 (-0.4)	1,53,366 (10.9)	1,25,955 (16.4)	27,411 (-8.9)
सी. निवल लाभ	41,578 (6.5)	32,901 (16.2)	8,677 (-19)	61,843 (48.7)	48,523 (47.5)	13,319 (53.5)	45,204 (55.9)	35,766 (44.7)	9,437 (120.7)
डी. कुल आस्ति	35,04,335 (10.6)	29,85,943 (11.3)	5,18,392 (6.5)	38,40,921 (9.6)	32,88,344 (10.1)	5,52,577 (6.6)	38,18,173 (8.8)	32,34,413 (8.6)	5,83,760 (9.6)
ई. वित्तीय अनुपात (कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में)									
(i) आय	10.2	9.7	12.9	9.8	9.2	13.2	11.0	10.5	13.7
(ii) व्यय	8.6	8.2	10.7	7.7	7.3	10.0	8.0	7.8	9.4
(iii) निवल लाभ	1.2	1.1	1.7	1.6	1.5	2.4	2.4	2.2	3.2
एफ. लागत-आय अनुपात (प्रतिशत)	84.3	84.7	82.7	78.3	78.9	76.0	73.2	74.2	68.7

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

VI.41 एनबीएफसी-आईडीएफ को छोड़कर, एनबीएफसी-एनडी-एसआई में सभी खंडों ने मार्च 2022 के अंत में आरओए और आरओई में सुधार दर्ज किया (चार्ट VI.22)।

2.10 आस्ति गुणवत्ता

VI.42 वर्ष 2021-22 में, इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ - जैसा कि जीएनपीए और एनएनपीए दोनों अनुपातों

चार्ट VI.21: एनबीएफसी के लाभप्रदता अनुपात

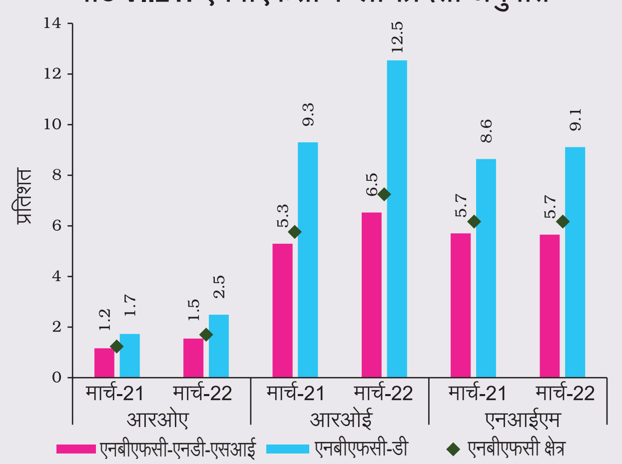

आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)= कुल औसत आस्तियों से निवल लाभ
इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)= औसत कुल इक्विटी से निवल लाभ
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) = कुल औसत आस्तियों से निवल ब्याज आय
टिप्पणी : डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.22: एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लाभप्रदता संकेतक

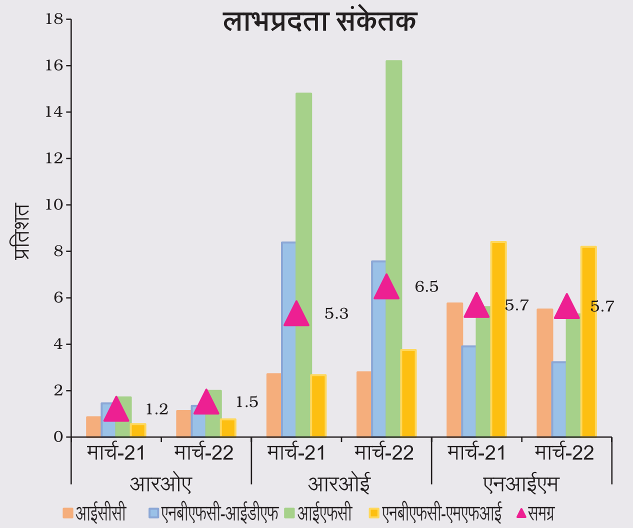

टिप्पणी : डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.23: एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता
(मार्च के अंत में)

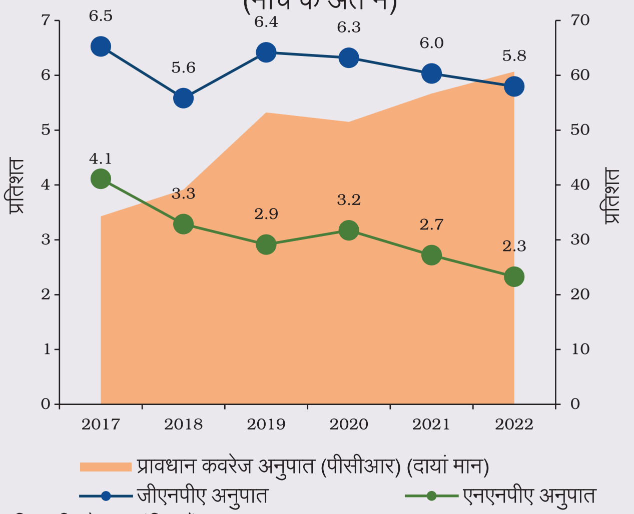

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.24: एनबीएफसी का प्रावधान कवरेज अनुपात
(मार्च के अंत में)

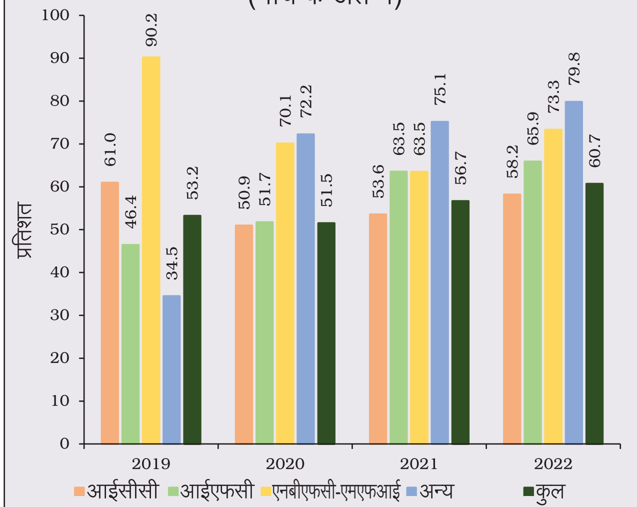

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

में गिरावट से स्पष्ट है। जहाँ कारोबार की स्थिति में सुधार हुआ, रिज़र्व बैंक द्वारा एनपीए उन्नयन मानदंडों[9] में आस्थगन, बेहतर वसूली और कमतर नई अभिवृद्धि ने इस अवधि के दौरान एनपीए की गिरावट में मदद की। प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) में मार्च 2021 के अंत में 56.7 प्रतिशत से मार्च 2022 के अंत में 60.7 प्रतिशत की वृद्धि से सुदृढ़ता में वृद्धि का पता चलता है (चार्ट VI.23)। 2022-23 में (सितंबर के अंत तक), इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार देखा गया।

VI.43 मार्च 2022 के अंत में, एनबीएफसी-एनडी-एसआई की सभी श्रेणियों ने पिछले वर्ष की तुलना में उच्च पीसीआर बनाए रखा जो यह दर्शाता है कि वे ऋण हानि जोखिम से निपटने के लिए तैयार हैं (चार्ट VI.24)।

VI.44 उस अवधि के आधार पर जिसके लिए कोई आस्ति अनर्जक रहती है, एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानिगत आस्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2021-22 में, मानक आस्तियों के अनुपात में मामूली सुधार हुआ (चार्ट VI.25)।

चार्ट VI.25: एनबीएफसी आस्तियों का वर्गीकरण
(मार्च के अंत में)

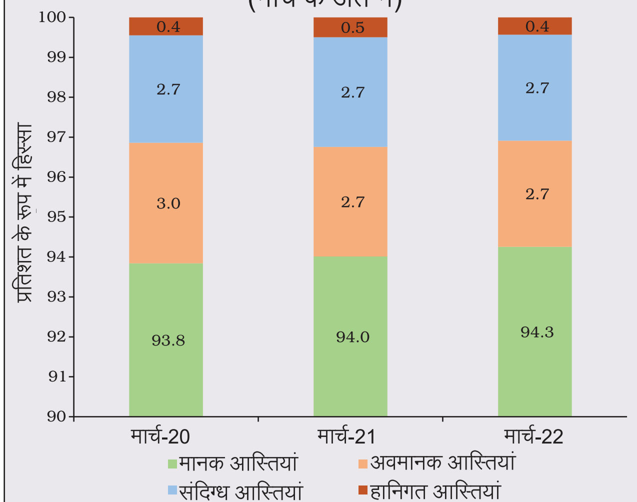

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

[9] https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12230&Mode=0

VI.45 अर्जक ऋणों में, मार्च 2022 के अंत तक वर्ष-दर-वर्ष समग्र चूक (डेलिंक्वेंसी) अनुपात में कमी आई। पहली बकेट, यानी - 30 दिनों से कम में - अतिदेय ऋण सबसे अधिक थे, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में स्थिति में सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अर्जक ऋणों की बकाया राशि में समग्र कमी आई (चार्ट VI.26)। कुल अर्जक ऋणों में बिना किसी अतिदेय वाली मानक आस्तियों की हिस्सेदारी 2020-21 में 87.7 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 90.6 प्रतिशत हो गई।

VI.46 कुल मिलाकर, एनबीएफसी-एनडी-एसआई के जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात ने 2021-22 में सुधार दिखाया क्योंकि आईसीसी को छोड़कर सभी क्षेत्रों में आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट VI.27 ए और बी)। वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में, जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात में गिरावट जारी रही।

VI.47 एनबीएफसी की चूकग्रस्त (डेलिंक्वेंट) आस्तियों के क्षेत्रीय वितरण से पता चलता है कि उद्योग, जो परंपरागत रूप से एनबीएफसी से ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, के पास भी मार्च 2022 के अंत में एनपीए का प्रमुख हिस्सा था, जिसके बड़े हिस्से के लिए बड़े उद्योग जिम्मेदार थे। खुदरा और सेवा क्षेत्र के ऋणों में क्रमशः वाहन/ ऑटो ऋण और वाणिज्यिक अचल संपत्ति खंड में क्षत आस्ति (इम्पेयर्ड असेट) का सबसे बड़ा हिस्सा है (चार्ट VI.28)। सितंबर 2022 के अंत में, सभी क्षेत्रों में एनपीए अनुपात में व्यापक गिरावट आई।

VI.48 एनबीएफसी-डी के मामले में, जीएनपीए अनुपात में गिरावट को ऋण और अग्रिम में तेज वृद्धि से सहायता मिली।

चार्ट VI.26: अर्जक आस्तियों में चूक (डेलिंक्वेंसी)

(मार्च के अंत में)

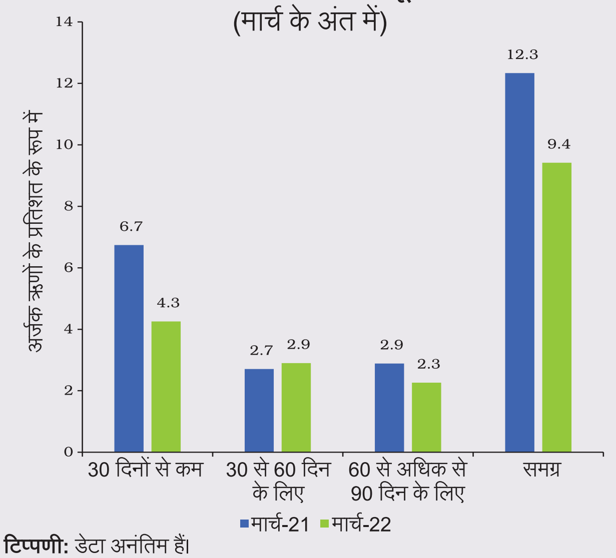

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.27: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की अनर्जक आस्तियां

(मार्च के अंत में)

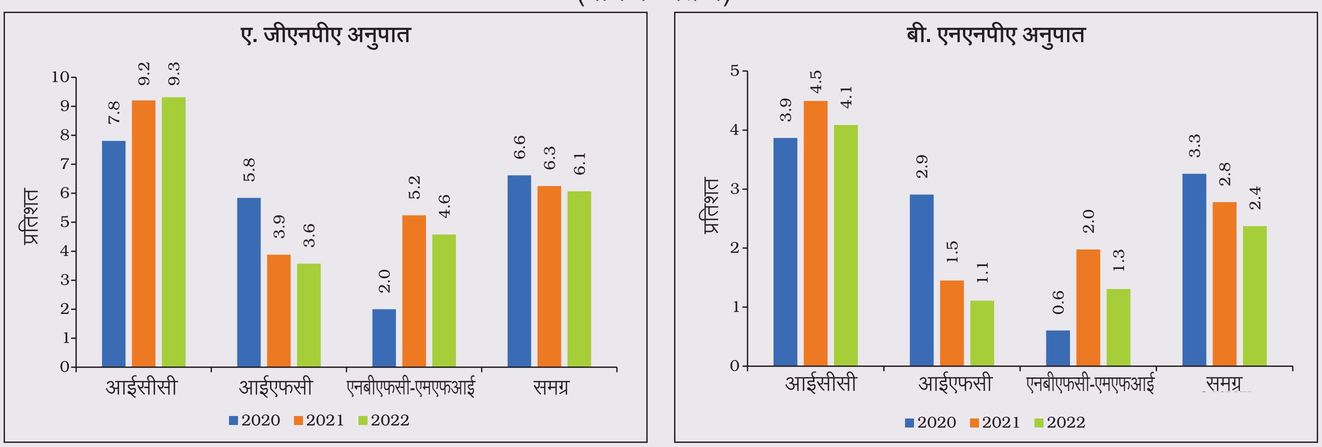

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.28: एनबीएफसी की अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार वितरण (मार्च 2022 के अंत में)

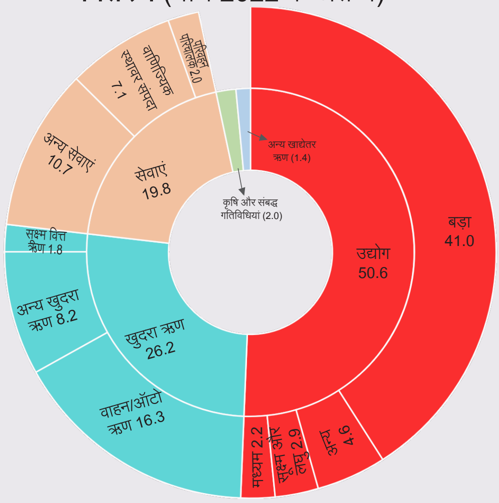

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.29: एनबीएफसी-डी के सकल और निवल एनपीए अनुपात (मार्च के अंत में)

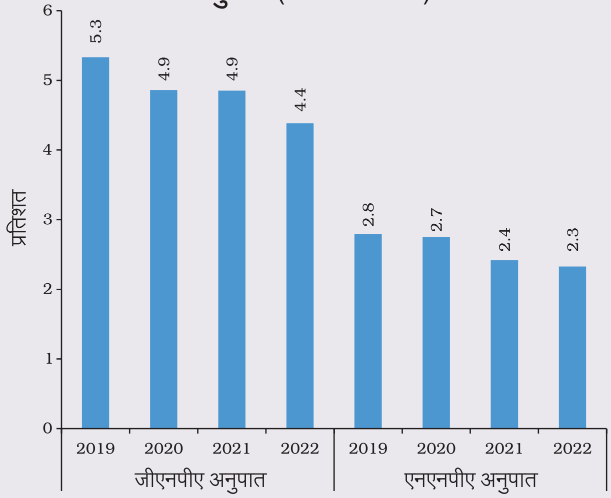

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

इसी अवधि में एनएनपीए अनुपात में भी मामूली कमी दर्ज की गई (चार्ट VI.29)। वर्ष 2022-23 में अब तक (सितंबर तक) आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ है।

VI.49 बड़े उधार खाते (₹5 करोड़ और उससे अधिक का एक्सपोजर) एनबीएफसी द्वारा दिए गए सकल अग्रिमों का 51.3 प्रतिशत है। हालांकि, उन्होंने मार्च 2022 के अंत में कुल एनपीए में लगभग 76.6 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट VI.30ए)। विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) अर्जक आस्तियों में शुरुआती दबाव का संकेत देते हैं। जहाँ, एसएमए-0 में वृद्धि हुई, एसएमए-2, जिसमें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की कगार पर स्थित ऋण शामिल हैं, में वर्ष के दौरान गिरावट आई। बड़े उधार खातों में जीएनपीए अनुपात में वृद्धि इस खंड में दबाव निर्माण का संकेत देती है, भले ही जीएनपीए और एनएनपीए सकल स्तर पर गिर गए (चार्ट VI.30बी)।

चार्ट VI.30: बड़े उधार खातों में दबाव

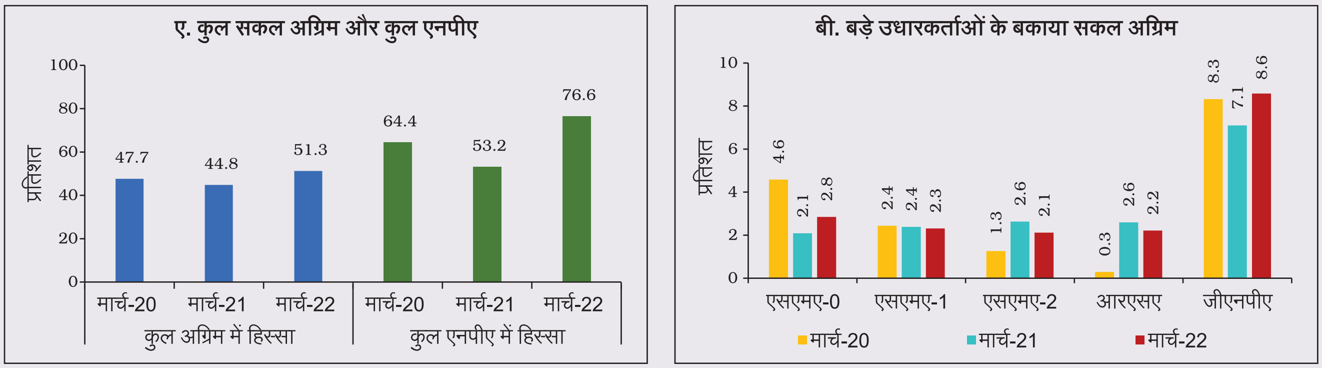

आरएसए: पुनर्रचित मानक अग्रिम;
एसएमए-0, जहां मूलधन या ब्याज भुगतान 30 दिन से अधिक के लिए अतिदेय नहीं था, लेकिन खाते ने प्रारंभिक दबाव के संकेत दिखाए;
एसएमए-1, जहां मूलधन या ब्याज भुगतान 31-60 दिनों के लिए अतिदेय था;
एसएमए-2, जहां मूलधन या ब्याज भुगतान 61-90 दिनों के लिए अतिदेय था।
टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस

2.11 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)

VI.50 मौजूदा विनियम के अनुसार, एनबीएफसी को न्यूनतम पूंजी अनुपात, कुल जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 15 प्रतिशत बनाए रखना आवश्यक है (इसमें तुलन पत्र पर और तुलन पत्र से इतर दोनों तरह के जोखिम शामिल हैं)। एनबीएफसी क्षेत्र सुरक्षित है और सीआरएआर विनियामक अपेक्षा से काफी ऊपर है (चार्ट VI.31)।

VI.51 वर्ष 2021-22 में, एनबीएफसी-एनडी-एसआई में, आईएफसी ने अपने सीआरएआर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया, जो टीयर I पूंजी में वृद्धि से उत्साहित है। अन्य श्रेणियों में, आईसीसी ने मामूली सुधार दर्ज किया, जबकि एनबीएफसी-आईडीएफ और एनबीएफसी-एमएफआई के सीआरएआर में गिरावट आई (चार्ट VI.32ए)। एनबीएफसी-डी ने पर्याप्त पूंजी बनाए रखना जारी रखा जो निर्धारित मानदंड से काफी अधिक है (चार्ट VI.32बी)।

2.12 संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर

VI.52 संवेदनशील क्षेत्रों की आस्तियाँ, मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति अतिसंवेदनशील होती हैं, जिसके कारण वे वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) में, पूंजी बाजार को अग्रिम और निवेश तथा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में निवेश के लिए व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं। कुल संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर (एसएसई) में सीएमई की हिस्सेदारी मार्च 2020 के अंत से लगभग अपरिवर्तित बनी हुई है। रियल एस्टेट एक्सपोजर (आरईई), जिसमें रियल एस्टेट में क्रेडिट और निवेश शामिल हैं, की कुल एसएसई में हिस्सेदारी गिर रही है।

चार्ट VI.31: एनबीएफसी क्षेत्र की पूंजीगत स्थिति
(मार्च के अंत में)

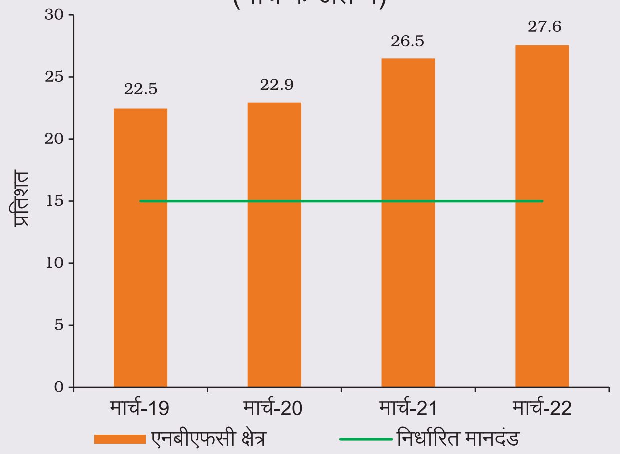

टिप्पणी: 1. सीआरएआर: जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात = टीयर I जोड़ टीयर II पूंजी बटे जोखिम-भारित आस्तियां
2. डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.32: एनबीएफसी का सीआरएआर - श्रेणीवार
(मार्च के अंत में)

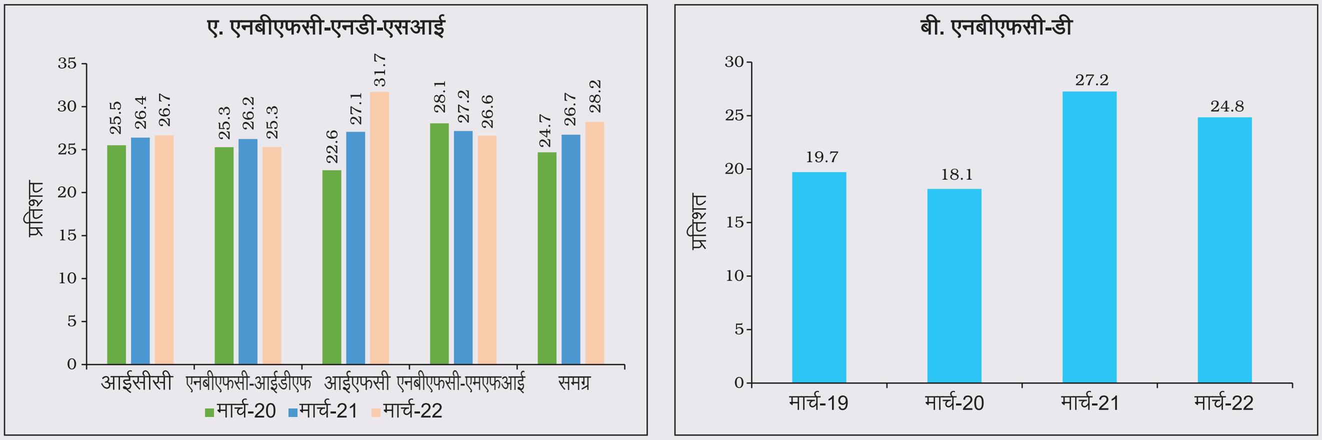

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.33: संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर
(मार्च के अंत में)

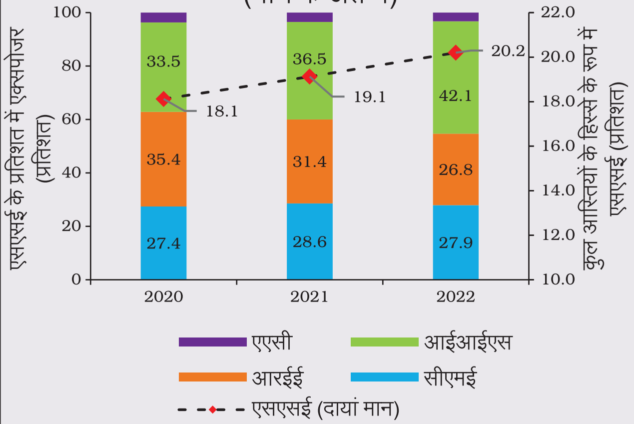

एएसी: कमोडिटी के बदले अग्रिम; आईआईएस: प्रतिभूतियों में निवेश; आरईई: स्थावर संपदा एक्सपोजर; सीएमई: पूंजी बाजार एक्सपोजर; एसएसई: संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर।
टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट VI.34: एचएफसी और एससीबी द्वारा आवास क्षेत्र को क्रेडिट (मार्च के अंत में)

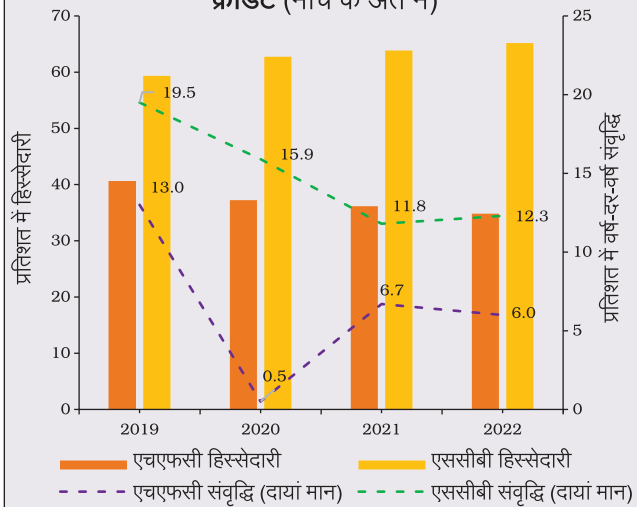

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: एनएचबी और पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

प्रतिभूतियों में निवेश (आईआईएस), जिसमें कोट की गई और न कोट की गई प्रतिभूतियों और इक्विटी में निवेश शामिल हैं, आरईई की कीमत पर हिस्सेदारी प्राप्त कर रहा है। एनबीएफसी के एसएसई ने, ज्यादातर प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि के कारण, कुल आस्ति के हिस्से के रूप में 2021-22 में वृद्धि दर्ज की (चार्ट VI.33)।

2.13 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)

VI.53 भारत में आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) विशिष्ट संस्थाएं हैं जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ आवास ऋण का विस्तार करती हैं। 9 अगस्त 2019 से प्रभावी एनएचबी अधिनियम,1987 में संशोधन द्वारा एचएफसी का विनियमन रिज़र्व बैंक को हस्तांतरित होने के बाद, एचएफसी को एनबीएफसी की एक श्रेणी के रूप में विनियमित किया जा रहा है। उसके बाद, एचएफसी और एनबीएफसी के बीच विनियमन में चरणबद्ध तरीके से संगति लाने के दृष्टिकोण से आवास वित्त कंपनियों में कई विधायी/ विनियामकीय परिवर्तन हुए हैं। समीक्षा के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 22 अक्टूबर 2020 को एचएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया और बाद में एचएफ़सी पर लागू मौजूदा विनियमों को 17 फरवरी 2021 को जारी मास्टर निदेश में संकलित किया गया।

VI.54 वर्ष 2021-22 में हाउसिंग सेक्टर को दिए गए एचएफसी के ऋण में गिरावट आई। यह गिरावट, मुख्य रूप से, एक दबावग्रस्त एचएफसी की ऋण आस्तियों के मूल्यांकन में हुए बदलाव के बाद, एक अन्य एचएफसी में इसके समामेलन के परिणामस्वरूप आई। हालांकि, आवास वित्त कंपनियों ने आवास ऋण बाजार में एक बड़ा हिस्सा बनाए रखा। वर्ष 2021-22 में आवास खंड में एससीबी के ऋण में तेजी आई जो अधिशेष तरलता और विभिन्न नीतिगत उपायों, जैसे कि स्टांप शुल्क में कमी, ब्याज दरों में कमी और परिवारों (हाउसहोल्ड) को प्रदत्त राजकोषीय मदद से उत्साहित थी (चार्ट VI.34)।

VI.55 मार्च 2022 के अंत में, 95 एचएफसी थे, जिनमें से केवल 15 जमाराशि लेने वाली संस्थाएं थीं। जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करने से पहले इनमें से छ: को एनएचबी से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है। गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ इस खंड में हावी हैं, जिनके पास कुल आस्तियों की 94.3 प्रतिशत आस्ति है। इन संस्थाओं के संयुक्त तुलन पत्र में,

सारणी VI.8: एचएफसी के स्वामित्व का स्वरूप
(मार्च के अंत में)

(₹ करोड़)

प्रकार	2021		2022	
	संख्या	आस्ति आकार	संख्या	आस्ति आकार
1	2	3	4	5
ए. सरकारी कंपनियां	**1**	**76,959**	**1**	**80,939**
बी. गैर-सरकारी कंपनियां (1+2)	**99**	**14,05,904**	**94**	**14,46,022**
1. पब्लिक लिमिटेड कंपनियां	78	14,01,522	73	14,39,592
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	21	4,382	21	6,430
कुल (ए+बी)	**100**	**14,82,863**	**95**	**15,26,961**

टिप्पणियां: 1. जिन दो कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया गया है और उन्होंने डेटा प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के लिए उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं किया गया है।
2. डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: एनएचबी

हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में, 2021-22 के दौरान धीमी गति से वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 में इकलौती सरकारी एचएफसी का आस्ति आकार बढ़ा (सारणी VI.8)।

2.13.1. तुलन पत्र

VI.56 एचएफसी का समेकित तुलन पत्र 2021-22 में एक दबावग्रस्त एचएफसी के समाधान और अन्य एचएफसी के अपने मूल एनबीएफसी के साथ विलय के कारण घट गया, जिसके परिणामस्वरूप निवेश में संकुचन के साथ-साथ ऋण और अग्रिमों में धीमी वृद्धि हुई। देनदारियों के पक्ष में, इंटरकॉर्पोरेट उधारों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि, जैसे, डिबेंचर, एनएचबी से उधार, वाणिज्यिक पत्र, सरकार से उधारियाँ और अन्य उधारियों में गिरावट आई (सारणी VI.9)।

सारणी VI.9: एचएफसी का समेकित तुलनपत्र
(मार्च के अंत में)

(₹ करोड़)

	मदें	2020	2021	2022	प्रतिशत घट-बढ़	
					2021	2022
1		2	3	4	5	6
1	शेयर पूंजी	36,858	37,696	40,357	2.3	7.1
2	आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	1,45,053	1,70,359	2,24,698	17.4	31.9
3	जनता की जमाराशियां	1,19,795	1,26,691	1,25,236	5.8	-1.1
4	डिबेंचर	3,97,949	3,97,816	3,56,320	0.0	-10.4
5	बैंक उधारियां#	3,53,214	3,29,835	3,74,803	-6.6	13.6
6	एनएचबी से उधारियां	49,673	67,341	59,551	35.6	-11.6
7	अंतर-कॉर्पोरेट उधारियां	6,206	19,182	1,24,969	209.1	551.5
8	वाणिज्यिक पत्र	46,631	54,554	50,216	17.0	-8.0
9	सरकार से उधारियां*	1,282	19,313	2,587	1406.9	-86.6
10	गौण ऋण	17,348	19,168	15,363	10.5	-19.9
11	अन्य उधारियां	1,49,404	1,31,818	71,410	-11.8	-45.8
12	चालू देयताएं	20,446	8,100	28,922	-60.4	257.0
13	प्रावधान^	7,499	64,303	33,793	757.5	-47.4
14	अन्य**	42,508	36,686	18,738	-13.7	-48.9
15	**कुल देयताएं/आस्तियां**	**13,93,865**	**14,82,863**	**15,26,961**	**6.4**	**3.0**
16	ऋण एवं अग्रिम	11,83,561	12,77,653	13,28,070	7.9	3.9
17	किराया खरीद और लीज आस्तियां	33	10	20	-70.4	106.5
18	निवेश	97,931	1,29,961	1,04,625	32.7	-19.5
19	नकद और बैंक जमा शेष	56,955	36,864	39,968	-35.3	8.4
20	अन्य आस्तियां***	55,384	38,375	54,277	-30.7	41.4

^ एक बड़े एचएफसी द्वारा रिपोर्ट किए गए बड़े प्रावधान के कारण मार्च 2021 के अंत में प्रावधानों में यह औचक वृद्धि है।
* इसमें विदेशी सरकारों से भी उधारियां शामिल हैं।
** इसमें आस्थगित कर देयताएं और अन्य देयताएं शामिल हैं।
*** इसमें मूर्त और अमूर्त आस्तियां, अन्य आस्तियां और आस्थगित कर आस्ति शामिल हैं।
टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: एनएचबी

चार्ट VI.35: एचएफसी द्वारा जुटाए गए संसाधन
(मार्च के अंत में)

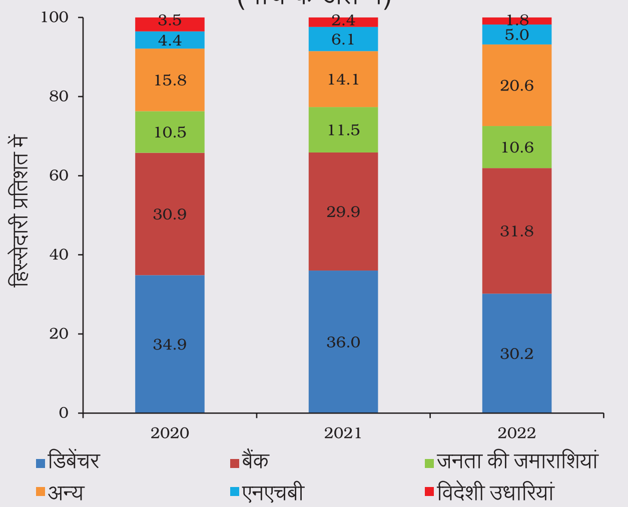

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: एनएचबी

चार्ट VI.36: एचएफसी में जनता की जमाराशियां
(मार्च के अंत में)

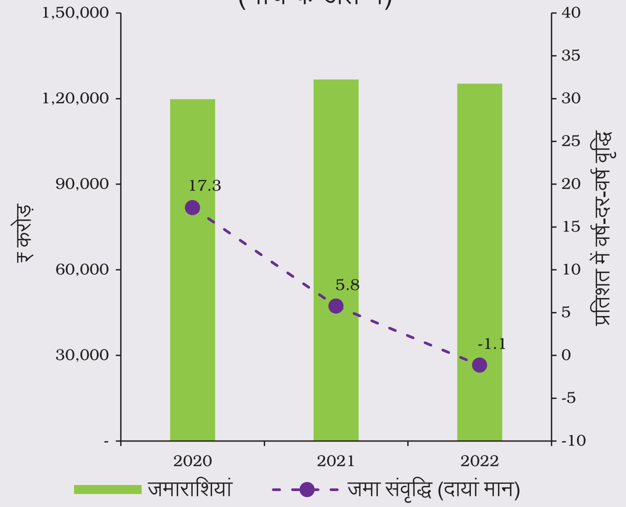

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: एनएचबी

2.13.2. एचएफसी का संसाधन-प्रोफाइल

VI.57 एचएफसी अनिवार्य रूप से क्रेडिट मध्यस्थता कार्य करने के लिए बैंकों से डिबेंचर और उधार पर निर्भर हैं। ये दोनों स्रोत मिलकर मार्च 2022 के अंत में जुटाए गए कुल संसाधनों का लगभग 62 प्रतिशत हैं। डिबेंचर का हिस्सा 2021-22 में थोड़ा कम हो गया, जबकि बैंकों पर एचएफसी की निर्भरता बढ़ गई (चार्ट VI.35)।

VI.58 जनता की जमाराशियाँ - जो वित्त पोषण का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं – में वर्ष 2021-22 में गिरावट आई (चार्ट VI.36)। इसके अलावा, एचएफसी की कुल देयताओं में जमाराशि का हिस्सा, 2019-20 को छोड़कर, 2016-17 से लगातार घट रहा है।

VI.59 वर्ष 2021-22 में एचएफसी के पास जमाराशियों के विभाजन से पता चलता है कि 6-9 प्रतिशत ब्याज दर ब्रैकेट

चार्ट VI.37: एचएफसी में जनता की जमाराशियों का विभाजन (मार्च के अंत में)

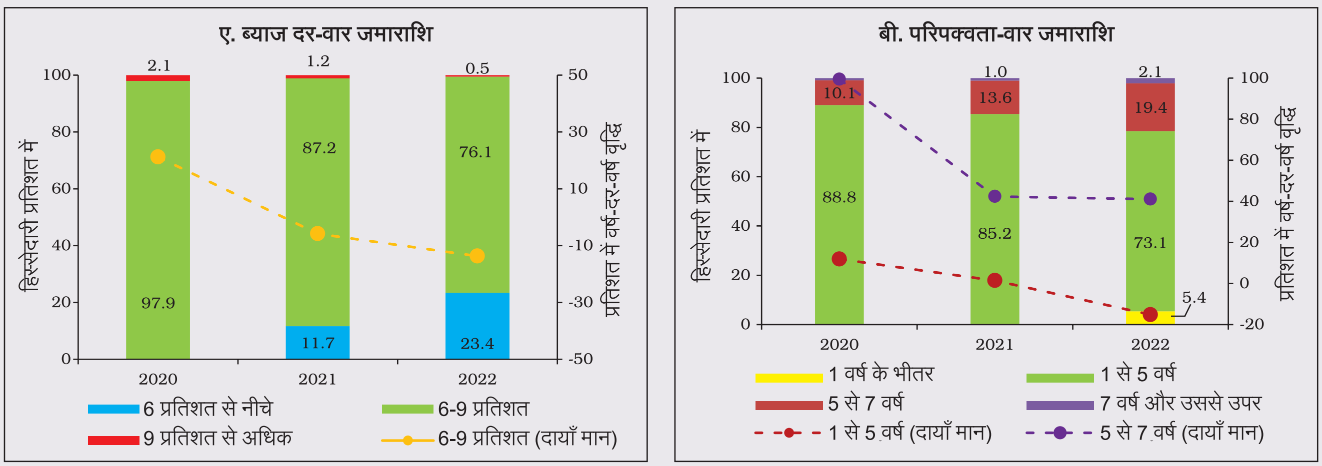

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: एनएचबी

में संकेंद्रण है। सर्वव्यापी नरम ब्याज दर व्यवस्था के कारण 6 प्रतिशत से कम ब्याज दर ब्रैकेट में जमाराशियों में वृद्धि देखी गई (चार्ट VI.37ए)। परिपक्वता के लिहाज से जमाराशियों का अधिकतम हिस्सा 1 से 5 वर्ष की अवधि का था (चार्ट VI.37बी)।

2.13.3 वित्तीय प्रदर्शन

VI.60 निधि आय और शुल्क आय दोनों में गिरावट के कारण 2021-22 में एचएफसी की समेकित आय में कमी आई। तथापि, प्रावधानों/ मूल्यह्रास में वृद्धि के कारण व्यय में मामूली वृद्धि हुई। नतीजतन, 2021-22 में लागत-आय अनुपात में वृद्धि हुई। मुख्य रूप से एक प्रमुख एचएफसी के समाधान के कारण एचएफसी के निवल लाभ में सुधार हुआ। आरओए में भी सुधार हुआ और यह धनात्मक हो गया (सारणी VI.10)।

2.13.4 सुदृढ़ता संकेतक

VI.61 पिछले वर्ष - जब दो प्रमुख एचएफसी के जीएनपीए अनुपात में वृद्धि हुई थी - की तुलना में 2021-22 में इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। हालांकि, एक प्रमुख एचएफसी के समाधान के कारण मार्च 2022 के अंत में जीएनपीए और एनएनपीए दोनों अनुपातों में गिरावट आई (चार्ट VI.38)।

सारणी VI.10: एचएफसी के वित्तीय मानदंड
(मार्च के अंत में)

₹ करोड़

	2019-20	2020-21	2021-22	प्रतिशत घट-बढ़	
				2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
कुल आय*	**1,41,692**	**1,29,476**	**1,25,425**	**-8.6**	**-3.1**
1. निधिगत आय	1,39,683	1,27,924	1,22,998	-8.4	-3.9
2. शुल्क आय	2,009	1,537	1,376	-23.5	-10.5
कुल व्यय**	**1,22,128**	**98,965**	**1,00,264**	**-19.0**	**1.3**
1. वित्तीय व्यय	89,041	79,392	74,467	-10.8	-6.2
2. परिचालन व्यय	33,087	19,199	10,638	-42.0	-44.6
कर प्रावधान	8,561	13,135	4,766	53.4	-63.7
निवल लाभ (पीएटी)	**-2,669**	**210**	**20,395**	**-107.9**	**9624.1**
कुल आस्तियाँ	13,93,865	14,82,863	15,26,961	6.4	3.0
लागत-आय अनुपात#	86.2	76.4	79.9		
आस्तियों पर प्रतिलाभ@ आरओए	-0.2	0.0	1.3		

* कुल आय में गैर-वित्तीय कारोबार से होने वाली आय भी शामिल है।
** कुल व्यय में मूल्यह्रास/प्रावधान भी शामिल हैं।
# कुल व्यय / कुल आय
@ पीएटी / कुल आस्तियाँ
टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: एनएचबी

चार्ट VI.38: एचएफसी के जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात
(मार्च के अंत में)

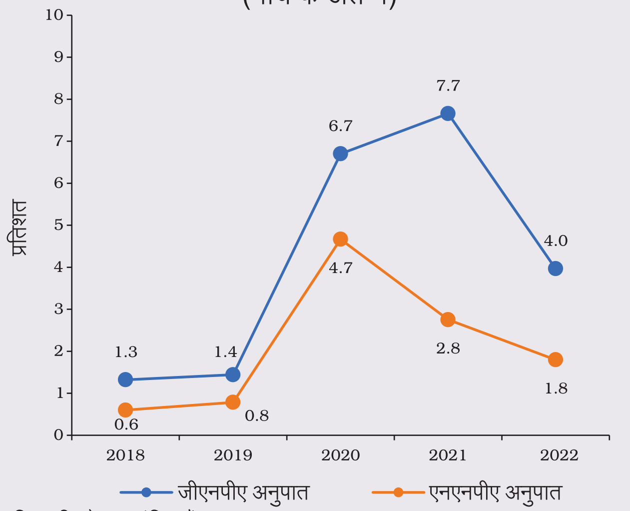

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: एनएचबी

VI.62 संक्षेप में, 2021-22 में, समष्टि-आर्थिक स्थितियों में सुधार के कारण एचएफसी ने सुदृढ़ता दिखाई। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लिए अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा के साथ-साथ समय पर रिज़र्व बैंक के विनियामक और चलनिधि उपायों ने चलनिधि बढ़ाने में मदद की। कम ब्याज दर के महौल से सामर्थ्य में सुधार हुआ जिससे आवास ऋणों की मांग-पुनरुत्थान में सहायता मिली।

VI.63 भविष्य में, एचएफसी से अपने क्रेडिट संवितरण में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, उन्हें उधार लेने की बढ़ती लागत और एससीबी से प्रतिस्पर्धा के संबंध में सतर्क रहने की जरूरत है। स्केल-आधारित विनियमन के कार्यान्वयन के साथ, कुछ एचएफसी को उपरी लेयर में शामिल किया गया है, जो भारतीय वित्तीय परिदृश्य में उनके प्रणालीगत महत्व पर प्रकाश डालता है। एनबीएफसी और बैंकों के बीच विनियामक मध्यस्थता धीरे-धीरे कम हो रही है, जो हाल ही में एक प्रमुख एचएफसी द्वारा अपनी मूल इकाई के साथ विलय हेतु दायर आवेदन से परिलक्षित होता है।

3. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

VI.64 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई) कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, छोटे उद्योगों, आवास वित्त कंपनियों, एनबीएफसी, एमएफआई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्षेत्र-विशिष्ट दीर्घकालिक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करते हैं। मार्च 2021 के अंत में, चार एआईएफआई, अर्थात्- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक), रिज़र्व बैंक में पंजीकृत थे। 19 अप्रैल 2021 से प्रभावी, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) अधिनियम 2021 के अधिनियमन के बाद से, एनएबीएफआईडी[10] को पांचवें एआईएफआई के रूप में स्थापित किया गया है, जो भारत के अवसंरचना क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा इसका विनियमन और पर्यवेक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल और 45 एन के तहत एआईएफआई के रूप में किया जाएगा।

3.1. एआईएफआई का परिचालन [11]

VI.65 मुख्य रूप से नाबार्ड की स्वीकृतियों में संकुचन के कारण - चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत कोई नया ऋण स्वीकृत नहीं किया गया - वर्ष 2021-22 के दौरान एआईएफआई द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता में कमी आई। इसके अलावा, 2021-22 में कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी, जबकि पिछले वर्षों में स्वीकृत चालू परियोजनाओं के लिए किश्तों का संवितरण किया गया। एक्ज़िम बैंक और सिडबी द्वारा संवितरण में 2021-22 के दौरान गति आई, जो व्यापार को बढ़ावा देने और एमएसएमई और विनिर्माण पर बल को इंगित करता है। कुल स्वीकृतियों के हिस्से के रूप में 2021-22 में एआईएफ़आई के कुल संवितरण में सुधार हुआ (सारणी VI.11 और परिशिष्ट सारणी VI.7)।

सारणी VI.11: एआईएफआई द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

संस्थाएं	स्वीकृत		संवितरित	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
एक्जिम बैंक	36,521	54,807	34,122	52,271
नाबार्ड	4,59,849	3,80,396	3,50,022	3,78,387
एनएचबी	37,791	22,330	34,230	19,313
सिडबी	98,354	1,48,550	98,115	1,46,402
कुल	**6,32,515**	**6,06,083**	**5,16,489**	**5,96,373**

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

3.2 तुलन पत्र

VI.66 वर्ष 2021-22 में, एआईएफआई का समेकित तुलन पत्र द्विअंकीय दर से बढ़ता रहा। यह, मुख्य रूप से नाबार्ड और सिडबी द्वारा निवेश और ऋण और अग्रिम में वृद्धि के कारण

सारणी VI.12: एआईएफआई का तुलन पत्र

(₹ करोड़)

	2021	2022	प्रतिशत घट-बढ़
			2021-22
1	2	3	4
1. पूंजी	32,221 (3.0)	35,008 (2.9)	8.6
2. आरक्षित निधि	71,025 (6.6)	81,538 (6.7)	14.8
3. बॉन्ड और डिबेंचर	3,27,427 (30.4)	3,56,901 (29.2)	9.0
4. जमाराशियां	4,12,001 (38.3)	4,36,057 (35.7)	5.8
5. उधारियां	1,70,820 (15.9)	2,43,121 (19.9)	42.3
6. अन्य देयताएं	62,023 (5.8)	68,612 (5.6)	10.6
कुल देयताएं/आस्तियां	**10,75,517**	**12,21,236**	**13.5**
1. नकद और बैंक जमा शेष	34,595 (3.2)	28,379 (2.3)	-18.0
2. निवेश	79,275 (7.4)	1,06,329 (8.7)	34.1
3. ऋण और अग्रिम	9,44,318 (87.8)	10,69,116 (87.5)	13.2
4. भुनाये/पुनः भुनाये गए बिल	1,410 (0.1)	3,058 (0.3)	116.9
5. अचल आस्तियां	1,273 (0.1)	1,268 (0.1)	-0.4
6. अन्य आस्तियां	14,646 (1.4)	13,087 (1.1)	-10.6

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिये गए डेटा कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

[10] एनएबीएफआईडी ने अभी तक आरबीआई को पर्यवेक्षी डेटा प्रस्तुत करना शुरू नहीं किया है। इसलिए, इस खंड में चार एआईएफआई अर्थात् एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है।

[11] एक्ज़िम बैंक, सिडबी और नाबार्ड का वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है और एनएचबी के लिए यह जुलाई से जून तक होता है।

था। एआईएफआई की कुल आस्ति में ऋण और अग्रिम का हिस्सा सबसे बड़ा है, इसके बाद निवेश का स्थान है। देयताओं में, एआईएफ़आई की उधारी में तेजी से वृद्धि हुई और उसके बाद बॉण्ड और डिबेंचर में मध्यम वृद्धि हुई (सारणी VI.12)। पहला, मुख्य रूप से, एमएसएमई के पुनरुद्धार और वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए सिडबी द्वारा उधार में तेजी से वृद्धि के कारण हुआ।

VI.67 रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान एआईएफआई के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें 2020-21 में ₹ 75,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा शामिल है। नई संवृद्धि को पोषित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 2021-22 में नए ऋण देने के लिए तीन एआईएफआई को ₹50,000 करोड़ का नया सहयोग दिया। इसमें नाबार्ड को ₹25,000 करोड़ की एक विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ), आवास क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए एनएचबी को ₹10,000 करोड़ का एसएलएफ और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़ शामिल थे। नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी ने एसएलएफ के तहत पूरी राशि का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, छोटे एमएसएमई और ऋण की कमी वाले और आकांक्षी जिलों (एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट) सहित कारोबारों, पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ एमएसएमई की लघु और मध्यम अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए सिडबी को 2021-22 के दौरान ₹16,000 करोड़ का एसएलएफ प्रदान किया गया।

VI.68 एनएचबी को छोड़कर सभी एआईएफआई द्वारा जुटाए गए कुल संसाधनों में 2021-22 में वृद्धि हुई। नाबार्ड ने सबसे अधिक हिस्सा जुटाया, उसके बाद सिडबी, एक्ज़िम बैंक और एनएचबी का स्थान रहा। नाबार्ड और सिडबी ने मिलकर कुल संसाधनों का 87 प्रतिशत हिस्सा जुटाया। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में अल्पावधिक निधियों पर एआईएफआई की निर्भरता बढ़ी। एक्ज़िम बैंक विदेशी स्रोतों से संसाधन जुटाने वाला एकमात्र एआईएफ़आई बना हुआ है (सारणी VI.13)।

सारणी VI.13: वर्ष 2021-22 में एआईएफआई द्वारा जुटाये गए संसाधन

(₹ करोड़)

संस्थाएं	जुटाये गए कुल संसाधन				कुल बकाया
	दीर्घावधिक	अल्पावधिक	विदेशी मुद्रा	कुल	
1	2	3	4	5	6
एक्जिम बैंक	0	39,123	18,302	57,425	1,07,477
नाबार्ड	1,34,919	2,11,051	0	3,45,970	6,29,586
एनएचबी	8,576	2,605	0	11,182	65,641
सिडबी	62,780	53,211	0	1,15,991	2,14,024
कुल	2,06,275	3,05,990	18,302	5,30,567	10,16,728

टिप्पणियां: दीर्घावधिक के रुपया संसाधनों में बांड/ डिबेंचर, मियादी ऋण, एलटी प्रकृति के पीएसएल जमा के माध्यम से उधार शामिल हैं; जबकि अल्पावधि संसाधनों में सीपी, मियादी जमाराशियां, आईसीडी, सीडी, रिज़र्व बैंक से एसएलएफ और मियादी मुद्रा बाजार से उधार और एसटी ऋण शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में अधिकांश, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बांड जारी करके, उधार लेना शामिल है।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

VI.69 नाबार्ड और सिडबी मिलकर मुद्रा बाजार से एआईएफआई द्वारा जुटाए गए कुल संसाधनों का लगभग 81 प्रतिशत हिस्सा जुटाया। जहाँ, जमा प्रमाणपत्र के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में वृद्धि हुई, वहीं, वर्ष के दौरान वाणिज्यिक पत्र जारी करने में गिरावट आई। 2021-22 में समावेशी सीमा (अम्ब्रेला लिमिट) का उपयोग बढ़ा (सारणी VI.14)।

सारणी VI.14: एआईएफआई द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाये गए संसाधन (मार्च के अंत में)#

(₹ करोड़)

लिखत	2020-21	2021-22
1	2	3
ए. कुल	94,604	97,709
i) मीयादी जमाराशियां	3,396	5,258
ii) मीयादी धन	3,602	1,987
iii) अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियां	-	-
iv) जमा प्रमाणपत्र	21,275	38,170
v) वाणिज्यिक पत्र	66,331	52,294
मेमो:		
बी. समावेशी सीमा ^^	1,34,662	1,32,240
सी. समावेशी सीमा का उपयोग* (बी के प्रतिशत के रूप में ए)	70.3	73.9

एनएचबी के लिए अंतिम जून * ए के अंतर्गत जुटाये गए संसाधन
^^: बोर्ड द्वारा खातों की स्वीकृति के बाद
टिप्पणियां: एआईएफआई को समग्र 'समावेशी सीमा' के भीतर संसाधन जुटाने की अनुमति है, जो संबंधित एफआई के अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) से जुड़ा हुआ है। समावेशी सीमा इन पाँच लिखतों पर लागू है- मीयादी जमाराशियां, मीयादी मुद्रा उधारियां, जमा प्रमाणपत्र (सीडी), वाणिज्यिक पत्र (सीपी); और अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियां।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

3.3. निधियों के स्रोत और उपयोग

VI.70 वर्ष 2021-22 में एआईएफ़आई द्वारा जुटायी और विनियोजित की गई निधियों में कमी आई। यद्यपि, आंतरिक निधियां प्रमुख स्रोत के रूप में बनी रहीं, बाह्य निधियों में तेजी से वृद्धि हुई। जुटाए गए संसाधनों में पिछले उधारों के पुनर्भुगतान के हिस्से में मामूली कमी आई (सारणी VI.15)।

3.4. उधार लेने और देने की परिपक्वता एवं लागत

VI.71 सिडबी को छोड़कर, एआईएफआई, कम दरों पर उधार लेने में सक्षम थे क्योंकि मौद्रिक नीति के सहयोग के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसी) कम हो गई थी। एनएचबी को छोड़कर सभी एआईएफआई के रुपया संसाधनों की भारित औसत परिपक्वता में कमी आई (चार्ट VI.39ए और बी)। एक्ज़िम बैंक की दीर्घकालिक मूल उधार दर (पीएलआर) में मामूली कमी आई, जबकि यह 2021-22 में एनएचबी और सिडबी के संबंध में यह स्थिर थी (चार्ट VI.40)।

3.5. वित्तीय प्रदर्शन

VI.72 एआईएफआई ने 2021-22 के दौरान मुख्य रूप से गैर-ब्याज आय में गिरावट के कारण आय में मामूली गिरावट दर्ज की। ब्याज आय, जो कुल आय का लगभग 97 प्रतिशत है, स्थिर रही। दूसरी ओर, 2021-22 के दौरान व्यय में मामूली

सारणी VI.15: एआईएफआई के संसाधनों का स्वरूप और निधियों का विनियोजन

(₹ करोड़)

मदें	2020-21	2021-22	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4
ए. निधियों के स्रोत (i+ii+iii)			
i. आंतरिक	43,78,840	45,88,852	4.8
	(82.3)	(78.0)	
ii. बाह्य	8,82,814	12,31,852	39.5
	(16.6)	(20.9)	
iii. अन्य@	60,018	65,124	8.5
	(1.1)	(1.1)	
कुल (i+ii+iii)	**53,21,672**	**58,85,828**	**10.6**
	(100)	**(100)**	
बी. निधियों का विनियोजन (i+ii+iii)			
i. नए विनियोजन	8,03,936	8,60,062	7.0
	(15.1)	(14.6)	
ii. पिछली उधारियों का पुनर्भुगतान	31,36,755	34,42,379	9.7
	(59.0)	(58.5)	
iii. अन्य विनियोजन	13,74,471	15,77,707	14.8
	(25.9)	(26.8)	
जिनमें से : ब्याज भुगतान	39,344	39,590	0.6
	(0.7)	(0.7)	
कुल (i+ii+iii)	**53,15,161**	**58,80,149**	**10.6**
	(100)	**(100)**	

@ इसमें बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद और जमा शेष शामिल हैं।
टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल योग का प्रतिशत हैं।
2. डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

चार्ट VI.39: एआईएफआई द्वारा जुटाये गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

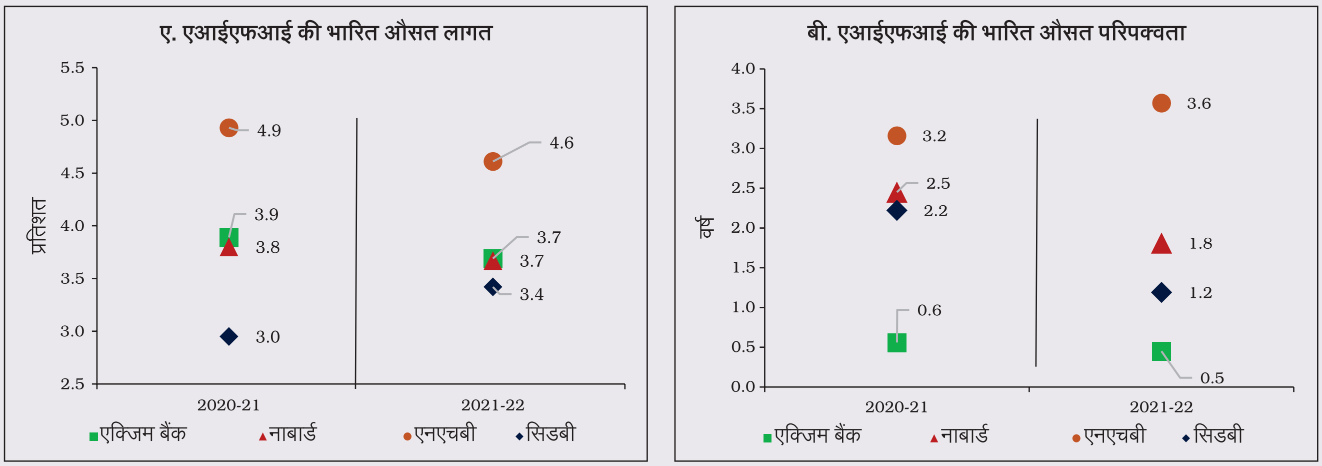

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

चार्ट VI.40: चुनिन्दा एआईएफआई की दीर्घावधि पीएलआर संरचना

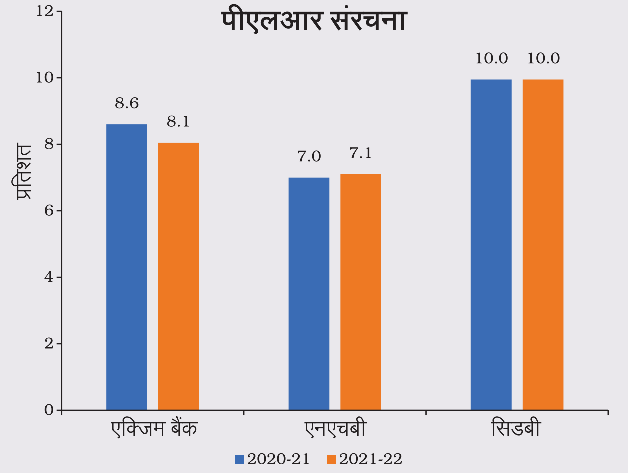

टिप्पणियां: 1. एक्जिम बैंक, आधार दर पर आधारित दीर्घावधि न्यूनतम उधार दर का उपयोग कर रहा है।
2. डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

वृद्धि हुई- मुख्य रूप से ब्याज व्यय और परिचालन व्यय में वृद्धि के कारण। एआईएफआई के निवल लाभ में 2021-22 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई (सारणी VI.16)।

सारणी VI.16: एआईएफआई का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़)

	2020-21	2021-22	प्रतिशत घट-बढ़	
			2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
ए) आय	**59,291**	**59,022**	**1.4**	**-0.5**
ए) ब्याज आय	57,597 (97.1)	57,543 (97.5)	1.3	-0.1
बी) ब्याजेतर आय	1,694 (2.9)	1,479 (2.5)	6.1	-12.7
बी) व्यय	**42,913**	**43,671**	**-3.6**	**1.8**
ए) ब्याज व्यय	39,829 (92.8)	40,280 (92.2)	-3.4	1.1
बी) परिचालनगत व्यय	3,084 (7.2)	3,390 (7.8)	-5.5	9.9
जिनमें से, वेतन बिल	2,203	2,270	-5.2	3.0
सी) कराधान हेतु प्रावधान	**2,409**	**4,064**	**7.4**	**68.7**
डी) लाभ				
परिचालनगत लाभ (पीबीटी)	16,378	15,351	17.3	-6.3
निवल लाभ (पीएटी)	7,635	9,698	17.6	27.0

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए डेटा कुल आय/ व्यय के प्रतिशत हैं।
2. डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

VI.73 एआईएफआई के वित्तीय अनुपात से पता चलता है कि कुल औसत आस्तियों के अनुपात के रूप में परिचालन लाभ में 2021-22 के दौरान गिरावट आई, जबकि वर्ष के दौरान निवल लाभ में थोड़ी वृद्धि हुई। हालांकि, अन्य सभी वित्तीय अनुपातों में वर्ष-दर-वर्ष कमी आई (चार्ट VI.41)।

VI.74 वर्ष 2021-22 के दौरान, सभी एआईएफआई के लिए औसत कार्यशील निधियों के अनुपात के रूप में ब्याज आय में गिरावट आई, जिसका कारण कम ब्याज दर का माहौल है। एक्ज़िम बैंक और एनएचबी के संदर्भ में, औसत कार्यशील निधियों के अनुपात के रूप में बेहतर परिचालन लाभ, कार्यशील निधियों के कुशल उपयोग को दर्शाता है; हालांकि, सिडबी और नाबार्ड के लिए, वर्ष के दौरान इसमें कमी आई (सारणी VI.17)।

VI.75 सिडबी को छोड़कर, सभी एआईएफआई के आरओए में 2021-22 में मामूली सुधार हुआ (चार्ट VI.42)। एआईएफआई ने सीआरएआर को विनियामकीय अपेक्षा से ऊपर बनाए रखा, जो एक सहज पूंजी स्थिति को दर्शाता है। एक्ज़िम बैंक और एनएचबी के सीआरएआर में 2021-22 में सुधार हुआ, जबकि नाबार्ड और सिडबी के सीआरएआर में थोड़ी कमी आई।

चार्ट VI.41: एआईएफआई के वित्तीय अनुपात

टिप्पणियां: 1. कुल औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
2. डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

सारणी VI.17: एआईएफआई के चुनिन्दा वित्तीय मापदंड

	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधियां (प्रतिशत)		ब्याजेतर आय/औसत कार्यशील निधियां (प्रतिशत)		परिचालनगत लाभ/औसत कार्यशील निधियां (प्रतिशत)		निवल लाभ प्रति कर्मचारी (₹ लाख)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्जिम बैंक	6.4	6.3	0.5	0.3	2.3	2.5	73	216
नाबार्ड	6.1	5.5	0.0	0.0	1.5	1.2	127	160
एनएचबी	5.5	5.1	0.1	0.6	1.3	1.9	436	1192
सिडबी	5.7	4.3	0.5	0.2	2.3	1.3	237	199

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

3.6. सुदृढ़ता संकेतक

VI.76 वर्ष 2021-22 के दौरान सभी एआईएफआई के निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात में कमी आई। सिडबी को छोड़कर सभी एआईएफआई ने एनपीए के लिए पूर्ण प्रावधान के कारण शून्य प्रतिशत एनएनपीए रिपोर्ट किया (चार्ट VI.43)।

VI.77 कुल मिलाकर, मानक आस्तियों के अनुपात में वृद्धि हुई, जबकि संदिग्ध आस्तियों के अनुपात में गिरावट आई। यह आस्ति गुणवत्ता में सुधार का सूचक है (चार्ट VI.44)।

VI.78 चूंकि, एआईएफ़आई जरूरी बैकवर्ड और फ़ॉरवर्ड लिंकेज के साथ अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। इसके लिए, रिज़र्व बैंक ने 22 अक्टूबर 2021 को एआईएफ़आई के लिए विवेकपूर्ण विनियमन पर मसौदा मास्टर निदेश जारी किया, ताकि एआईएफ़आई तक बेसल III पूंजी ढांचे का विस्तार किया जा सके।

चार्ट VI.42: एआईएफआई के चुनिंदा वित्तीय मापदंड

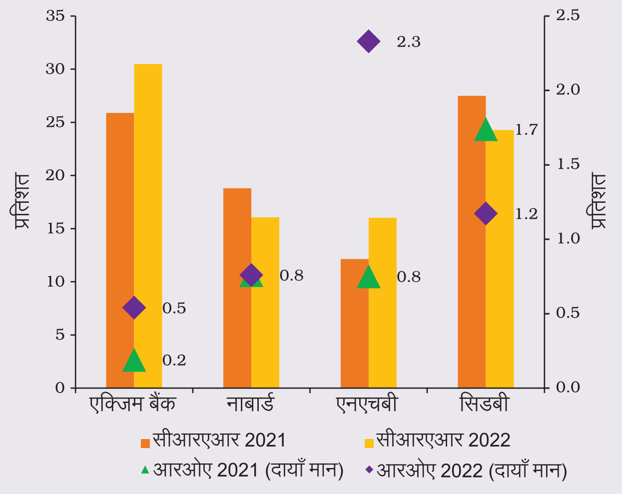

टिप्पणियां: 1. आरओए से तात्पर्य है - औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ
2. डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

चार्ट VI.43: एआईएफआई के एनएनपीए अनुपात

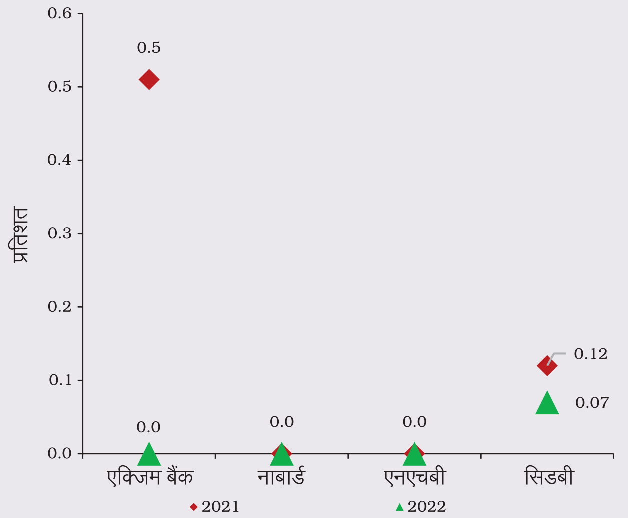

टिप्पणियां: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

चार्ट VI.44: एआईएफआई का आस्ति वर्गीकरण

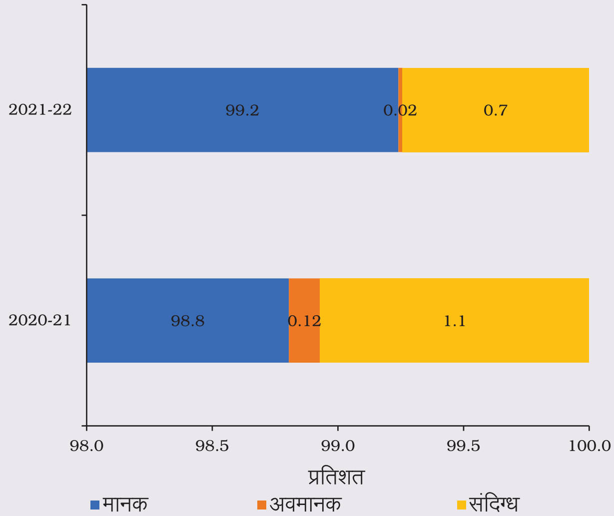

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं

4. प्राथमिक व्यापारी

VI.79 31 मार्च 2022 तक 21 प्राथमिक व्यापारी (पीडी) थे, जिनमें से 14 बैंक विभागों के रूप में और 7 एकल पीडी (एसपीडी) के रूप में कार्य करते हैं। बाद वाले प्राथमिक व्यापारी, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हैं।

4.1. प्राथमिक व्यापारियों का परिचालन और कार्यनिष्पादन [12]

VI.80 प्राथमिक व्यापारी (पीडी) वित्तीय मध्यवर्ती-संस्थाएँ हैं, जिनको, प्राथमिक और द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार की समग्र गतिविधि में भाग लेने, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमन की हामीदारी करने और प्राथमिक नीलामियों में भाग लेने के लिए, अधिदेशित किया गया है। उन्हें यह भी अधिदेश दिया गया है कि वे, खजाना बिल और नकद प्रबंधन बिलों (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी में न्यूनतम 40 प्रतिशत का सफलता अनुपात (बोली प्रतिबद्धता के अनुपात के रूप में स्वीकृत बोलियां) हासिल करें, जिनका अर्ध-वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2021-22 में, सभी प्राथमिक व्यापारियों ने अपनी न्यूनतम बोली प्रतिबद्धताओं से अधिक हासिल किया और वर्ष के दौरान जारी किए गए खजाना बिलों की कुल मात्रा का 76.9 प्रतिशत सब्सक्राइब किया, जबकि 2020-21 में यह 68.9 प्रतिशत था। प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत बोलियों की वास्तविक मात्रा, हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, प्राथमिक व्यापारियों ने जारी किए गए खजाना बिलों की कुल मात्रा का 69.3 प्रतिशत सब्सक्राइब किया। दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में घटी, लेकिन 2022-23 की पहली छमाही के दौरान बढ़ गई (सारणी VI.18)।

VI.81 पिछले वर्ष में ₹1,30,562 करोड़ की राशि के 15 मामलों के मुकाबले 2021-22 के दौरान ₹97,938 करोड़ की राशि के 17 मामलों में पीडी संबंधी आंशिक न्यागमन (डीवोल्वमेंट) हुआ। 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, पीडी संबंधी कुल ₹14,799 करोड़ के आंशिक न्यागमन (डीवोल्वमेंट) के 7 उदाहरण थे। प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को भुगतान किया गया

सारणी VI.18: प्राथमिक बाजार में पीडी का कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़)

मदें	2020-21	2021-22	छ1:2022-23
1	2	3	4
खजाना बिल और सीएमबी			
(ए) बोली प्रतिबद्धता	17,35,783	15,37,735	8,07,225
(बी) प्रस्तुत वास्तविक बोलियां	49,05,302	37,21,906	18,00,182
(सी) स्वीकृत बोलियाँ	10,24,732	9,59,380	4,88,867
(डी) सफलता अनुपात (सी)/(ए) (प्रतिशत में)	59.0	62.4	60.6
(ई) कुल आबंटन में पीडी का शेयर (प्रतिशत में)	68.9	76.9	69.3
केंद्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां			
(एफ) अधिसूचित राशि	12,85,000	10,80,000	8,12,000
(जी) प्रस्तुत वास्तविक बोलियां	24,54,253	22,22,924	14,13,444
(एच) स्वीकृत बोलियां	6,80,763	5,33,201	4,38,580
(आई) पीडी का शेयर (एच)/(एफ) (प्रतिशत)	49.7*	47.3**	55.1***

*₹13,70,324 करोड़ की कुल स्वीकृत राशि के संबंध में गणना की गई है।
** ₹11,27,382 करोड़ की कुल स्वीकृत राशि के संबंध में गणना की गई है।
*** ₹ 7,96,000 करोड़ की कुल स्वीकृत राशि के संबंध में गणना की गई है।
स्रोत: पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियां

[12] यह खंड सभी 21 प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) का विश्लेषण करता है।

कुल हामीदारी कमीशन 2020-21 में ₹455 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹413 करोड़ हो गया और उसी अवधि में हामीदारी कमीशन की औसत दर में वृद्धि हुई (चार्ट VI.45)। 2022-23 में (सितंबर के अंत तक), प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन ₹88 करोड़ था।

VI.82 द्वितीयक बाजार में, सभी प्राथमिक व्यापारियों ने व्यक्तिगत रूप से, अपेक्षित न्यूनतम वार्षिक कुल कारोबार अनुपात हासिल किया। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में, रीपो और एकमुश्त के लिए न्यूनतम कारोबार अनुपात 5 गुना निर्धारित किया गया और उनके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के औसत माह-अंत स्टॉक के एकमुश्त लेनदेन, के लिए 3 गुना निर्धारित किया गया। खजाना-बिलों के लिए, संबंधित न्यूनतम लक्ष्य क्रमशः 10 गुना और 6 गुना निर्धारित किए गए हैं।

4.2. एकल प्राथमिक व्यापारियों का कार्यनिष्पादन [13]

VI.83 द्वितीयक बाजार एकमुश्त खंड में, एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) का कुल कारोबार 2021-22 के दौरान – समान अवधि में कुल बाजार कारोबार में कमी के बावजूद - पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा। रीपो खंड में, एसपीडी का कुल कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। इस वर्ष के दौरान कुल बाजार कारोबार में एसपीडी के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है (सारणी VI.19)।

4.3. एसपीडी की निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

VI.84 वर्ष 2021-22 में एसपीडी द्वारा जुटाई गई निधि में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ोतरी हुई। एसपीडी की निधियों का प्रमुख स्रोत उधारियाँ रहीं। इस अवधि के दौरान ज़मानती और गैर-ज़मानती ऋणों की कुल मात्रा में वृद्धि हुई। एसपीडी के निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा चालू आस्तियों के रूप में रखा गया है (सारणी VI.20)।

4.4. एसपीडी का वित्तीय प्रदर्शन

VI.85 एसपीडी ने पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में कर पश्चात लाभ में पर्याप्त कमी दर्ज की, जो कि कारोबारी लाभ में कमी

चार्ट VI.45: पीडी के हामीदारी कमीशन की औसत दर

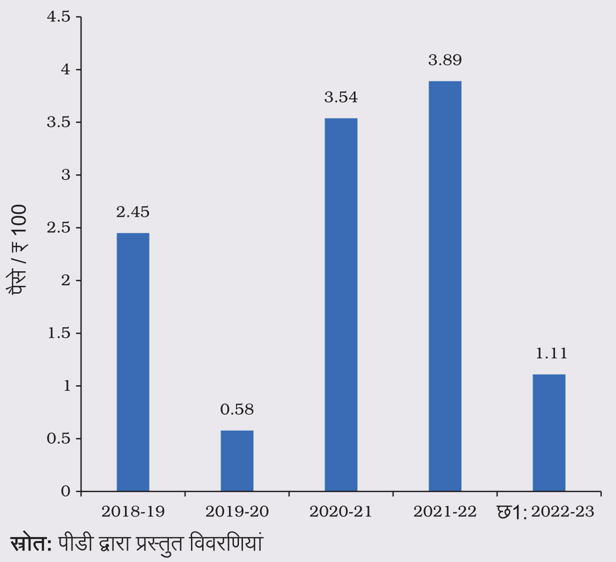

स्रोत: पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियां

सारणी VI.19: जी-सेक द्वितीयक बाजार में एसपीडी का प्रदर्शन

(₹ करोड़)

मदें	2020-21	2021-22	छ1:2022-23
1	2	3	4
एकमुश्त			
एसपीडी का कुल कारोबार	24,71,523	25,91,788	18,09,980
बाजार कुल कारोबार	1,00,32,187	87,98,428	53,35,981
एसपीडी के शेयर (प्रतिशत)	24.6	29.5	33.9
रीपो			
एसपीडी का कुल कारोबार	90,75,360	95,60,700	57,89,793
बाजार कुल कारोबार	2,27,70,547	2,55,25,641	1,59,61,220
एसपीडी के शेयर (प्रतिशत)	39.9	37.5	36.3
कुल (एकमुश्त+रीपो)			
एसपीडी का कुल कारोबार	1,15,46,883	1,21,52,488	75,99,774
बाजार कुल कारोबार	3,28,02,734	3,43,24,069	2,12,97,200
एसपीडी के शेयर (प्रतिशत)	35.2	35.4	35.7

टिप्पणी : बाजार सहभागियों / एकल पीडी के लिए कुल कारोबार में एकमुश्त और रीपो प्रथम चरण के निपटान की मात्रा शामिल है।

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल)।

[13] सात एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) रिजर्व बैंक में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हैं।

सारणी VI.20: एसपीडी की निधियों के स्रोत और उपयोग

(₹ करोड़)

मदें	2020-21	2021-22	छ1: 2022-23	प्रतिशत घट-बढ़ 2020-21 की तुलना में 2021-22 में
1	2	3	4	5
निधियों के स्रोत	**71,986**	**86,669**	**79,157**	**20.4**
1. पूंजी	1,849	1,849	1849	0.0
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	7,011	7,425	7,199	5.9
3. ऋण (ए+बी)	63,127	77,394	70,109	22.6
(ए) ज़मानती	50,374	61,188	55,262	21.5
(बी) गैर-ज़मानती	12,752	16,207	14,847	27.1
निधियों का उपयोग	**71,986**	**86,669**	**79,157**	**20.4**
1. अचल आस्तियां	44	71	82	58.8
2. एचटीएम निवेश (ए+बी)	154	2,870	5,704	1767.2
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	0	2,688	5,522	0.0
(बी) अन्य	154	182	182	18.7
3. चालू आस्तियां	72,389	80,841	75,836	11.7
4. ऋण और अग्रिम	1,986	7,048	4,861	254.8
5. चालू देयताएं	2,616	4,118	7,280	57.4
6. आस्थगित कर	33	-35	-38	-206.7
7. अन्य	-3	-8	-8	153.1

स्रोत: पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियां

और ब्याज और डिस्काउंट आय में मामूली कमी के कारण हुआ (सारणी VI.21 और परिशिष्ट सारणी VI.8)। परिणामस्वरूप, वर्ष

सारणी VI.21: एसपीडी का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़)

मदें	2020-21	2021-22	छ1: 2022-23	प्रतिशत में घट-बढ़ 2020-21 की तुलना में 2021-22
1	2	3	4	5
ए. आय (i से iii)	**5,386**	**4,002**	**2,055**	**-25.7**
(i) ब्याज और बट्टा	4,173	4,139	2441	-0.8
(ii) कारोबारी लाभ	1,008	-244	-396	-124.2
(iii) अन्य आय	205	107	10	-47.9
बी. व्यय (i से ii)	**2,493**	**2,622**	**1995**	**5.1**
(i) ब्याज	2,130	2,238	1794	5.1
(ii) अन्य व्यय#	364	384	201	5.5
सी. कर-पूर्व लाभ	**2,582**	**1,253**	**153**	**-51.4**
डी. कर-पश्चात लाभ	**1,938**	**937**	**102**	**-51.6**

#: स्थापना और प्रशासनिक लागत सहित।
टिप्पणी: पूर्णांकन (राउंडिंग-ऑफ) के कारण आंकड़ों का जोड़ भिन्न होगा।
स्रोत: पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियां

सारणी VI.22: एसपीडी के वित्तीय संकेतक

(₹ करोड़)

संकेतक	2020-21	2021-22	छ1: 2022-23
1	2	3	4
(i) निवल लाभ	1,938	937	102
(ii) औसत आस्तियां	77,357	79,085	91,155
(iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	2.6	1.2	0.1
(iv) निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	26.0	11.6	0.9
(v) लागत-आय अनुपात (प्रतिशत)	11.2	21.8	76.8

स्रोत: पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियां

के दौरान निवल मालियत पर एसपीडी का प्रतिलाभ भी घटा (सारणी VI.22)।

VI.86 सभी एसपीडी का संयुक्त सीआरएआर 2021-22 में बढ़ा और पूंजीगत बफर में सुधार के कारण 15 प्रतिशत के अधिदेश से ऊपर रहा। हालांकि, 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, संयुक्त सीआरएआर, मुख्य रूप से उनकी जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि के कारण, कम हुआ (चार्ट VI.46 और परिशिष्ट सारणी VI.9)।

चार्ट VI.46: एसपीडी की पूंजी और जोखिम-भारित आस्तियों की स्थिति

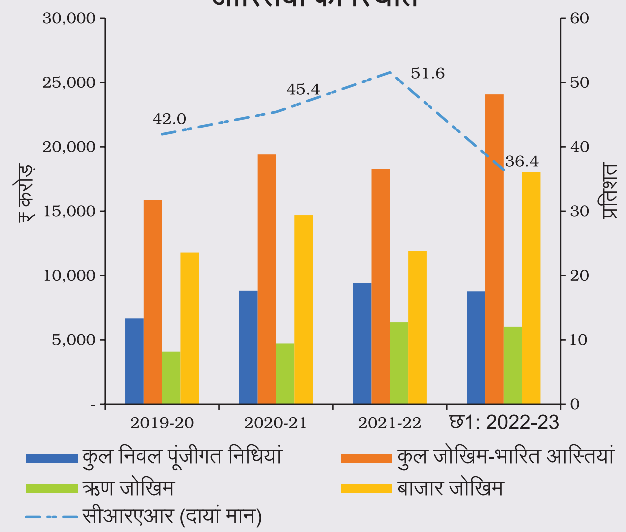

स्रोत: पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियां

5. समग्र मूल्यांकन

VI.87 एनबीएफआई ने कोविड-19 के आघात का सामना करने में उल्लेखनीय सुदृढ़ता प्रदर्शित की। 2021-22 के दौरान, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पुनरुत्थान की अलग-अलग गति और उधारकर्ताओं द्वारा सामना किए गए नकदी प्रवाह व्यवधानों के बावजूद उनके परिचालनों में तेजी आई। इस अस्थिर वातावरण में मजबूत पूंजीगत बफर और पर्याप्त प्रावधान आश्वस्त करने वाले हैं। आर्थिक गतिविधि में मजबूती की बदौलत निकट अवधि में एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार होने की उम्मीद है। तीक्ष्ण विनियामक निरीक्षण, आस्ति गुणवत्ता वर्गीकरण में पुनर्निर्धारण और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई मानदंड, स्थिरता को और मजबूती प्रदान करेंगे।

VI.88 एनबीएफसी को बढ़ती ब्याज दर चक्र और वैश्विक आघातों के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्हें, बैंकों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से - वाहन और स्वर्ण ऋण क्षेत्रों में - जहाँ एनबीएफसी की अच्छी उपस्थिति थी। तेजी से बढ़ता डिजिटल ऋण परितंत्र नई चुनौतियाँ पेश कर रहा है। विनियमित संस्थाओं को अनैतिक वसूली प्रथाओं और डेटा गोपनीयता के मुद्दों पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन संस्थाओं को, तीसरे पक्ष के एजेंटों द्वारा उनके ग्राहकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए, आउटसोर्स गतिविधियों पर अपने निरीक्षण सशक्त बनाने की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक ने अपनी ओर से इन मुद्दों को अग्रसक्रिय ढंग से हल करने का प्रयास किया है और समय पर विनियामक मार्गदर्शन प्रदान किया है।

VI.89 एचएफसी अपने तुलन पत्र में मध्यम विस्तार के साथ महामारी से बाहर निकल आए। हालांकि, एचएफसी को एससीबी से तेज प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी पहुंच सस्ती दरों पर प्राप्त निधियों तक है। संवितरण में सुधार और लाभप्रदता में वृद्धि के कारण एआईएफआई की वृद्धि प्रभावशाली रही है। प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) ने प्राथमिक बाजार में न्यूनतम सफलता अनुपात और न्यूनतम बोली प्रतिबद्धताओं को हासिल किया और द्वितीयक बाजार में भी कुल कारोबार अनुपात हासिल किया और इस प्रकार, सरकार के उधार कार्यक्रम को सहायता मिली। बढ़ता मजबूत बैंक ऋण जो अर्थव्यवस्था में संसाधनों के उपलब्ध भंडार की मांग बढ़ा रहा है और घरेलू वित्तीय प्रणाली और बाजारों पर चल रहे वैश्विक प्रभाव-विस्तार को देखते हुए, बाजार में व्यवस्थित स्थिति सुनिश्चित रखने में, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी।

परिशिष्ट सारणी IV.1: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, एक नज़र में

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
		2021	2022*	2020-21	2021-22*
1	2	3	4	5	6
1	**तुलन-पत्र परिचालन**				
	1.1 कुल देयताएं/आस्तियां	1,95,78,895	2,16,67,655	8.7	10.7
	1.2 जमाराशियां	1,55,80,325	1,71,82,709	11.5	10.3
	1.3 उधारियां	14,73,450	16,63,283	-13.1	12.9
	1.4 ऋण तथा अग्रिम	1,08,06,381	1,22,08,009	4.9	13.0
	1.5 निवेश	54,16,159	57,78,971	15.5	6.7
	1.6 तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (तुलन पत्र की देयताओं के प्रतिशत के रूप में)	118.8	132.8	-	-
	1.7 कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	6,13,794	7,29,114	6.1	18.8
2.0	**लाभप्रदता**				
	2.1 निवल लाभ	1,21,998	1,82,032	-	-
	2.2 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) (प्रतिशत)	0.7	0.9	-	-
	2.3 इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) (प्रतिशत)	7.7	10.1	-	-
	2.4 निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) (प्रतिशत)	2.9	2.9	-	-
3.0	**पूंजी पर्याप्तता**				
	3.1 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) @	16.3	16.8	-	-
	3.2 स्तर I पूंजी (कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में) @	86.8	87.5	-	-
	3.3 सीआरएआर (स्तर I) (प्रतिशत) @	14.1	15.7	-	-
4.0	**आस्ति गुणवत्ता**				
	4.1 सकल एनपीए	8,35,138	7,43,653	-7.2	-11.0
	4.2 निवल एनपीए	2,58,050	2,04,226	-10.8	-20.9
	4.3 सकल एनपीए अनुपात (सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए)	7.3	5.8	-	-
	4.4 निवल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए)	2.4	1.7	-	-
	4.5 प्रावधान कवरेज अनुपात (प्रतिशत)**	67.4	70.8	-	-
	4.6 गिरावट अनुपात (प्रतिशत)**	2.8	2.1	-	-
5.0	**बैंक ऋण का क्षेत्रीय अभिनियोजन**				
	5.1 सकल बैंक ऋण	1,06,40,808	1,18,53,392	5.4	11.4
	5.2 कृषि	13,84,815	15,16,303	11.7	9.5
	5.3 उद्योग	32,53,636	35,08,744	0.0	7.8
	5.4 सेवाएं	27,45,324	31,48,321	-0.3	14.7
	5.5 व्यक्तिक ऋण	29,86,457	33,94,028	12.3	13.6
6.0	**प्रौद्योगिकीय विकास**				
	6.1 क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या (लाख में)	620	736	7.5	18.7
	6.2 डेबिट कार्डों की कुल संख्या (लाख में)	8,982	9,177	8.4	2.2
	6.3 एटीएम और सीआरएम की संख्या	2,38,588	2,49,228	1.8	4.5
7.0	**ग्राहक सेवाएं**				
	7.1 वर्ष के दौरान बैंकों के खिलाफ प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या	3,41,747	2,68,085#	11.4	-21.6
	7.2 वर्ष के दौरान निपटान## की गई शिकायतों की संख्या	3,81,473	2,79,422^	16.0	-26.8
	7.3 समाधान की गई शिकायतों की संख्या	3,71,395	2,74,116***	21.5	-26.2
	7.3 निपटान की गई शिकायतों का प्रतिशत	97.4	98.1	-	-
8.0	**वित्तीय समावेश**				
	8.1 ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	69.4	71.1	-	-
	8.2 खोली गई नई बैंक शाखाओं की संख्या	3,089	3,232	-29.0	4.6
	8.3 गांवो में खोले गए बैंकिंग आउटलेट की संख्या (कुल)	12,48,079	22,74,236^^	108.3	82.2

टिप्पणियां:

1. * : अनंतिम।
2. **: ऑफ-साइट विवरणियों के आधार पर।
3. @ : आंकड़े बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार हैं।
4. प्रतिशत घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि राशियों को लाख/ करोड़ रुपये में पूर्णांकित किया गया है।
5. #: सीआरपीसी के तहत शिकायतों के निपटान को छोड़कर।
6. ##: शिकायतों के निपटान में दर्ज की गई शिकायतों के साथ पिछले वर्ष की आगे बढ़ायी गई शिकायतें भी शामिल हैं।
7. ^: इसमें पिछले वर्ष की शिकायतें शामिल हैं, जिसे ईमेल के माध्यम से 31 मार्च 2022 से पूर्व प्राप्त किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद रजिस्टर किया गया है।
8. ***: निपटाई गई शिकायतों की स्थिति 31 मार्च 2022 तक है। 31 मार्च 2022 तक लंबित शिकायतों का निपटान अब तक किया गया है।
9. ^^: कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

परिशिष्ट सारणी IV.2: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - लिखतों के प्रकार के आधार पर

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताओं के प्रकार	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2021 (पीआर)	2022 (पीआर)	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
1. ऋण और जमाराशियां	**11,42,402 (68.8)**	**12,05,274 (67.6)**	**-2.2**	**5.5**
ए) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] योजना	1,33,986 (8.1)	1,05,587 (5.9)	-20.8	-21.2
बी) विदेशी मुद्रा उधार*	54,998 (3.3)	81,575 (4.6)	-53.4	48.3
ग) अनिवासी बाह्य (एनआरई) रुपया खाते	7,20,626 (43.4)	7,49,061 (42.0)	8.6	3.9
घ) अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया खाते	1,17,500 (7.1)	1,41,240 (7.9)	14.2	20.2
2. प्रतिभूतियों/बांडों के निजी निर्गम	**2,468 (0.1)**	**3,039 (0.2)**	**-59.7**	**23.1**
3. अन्य देयताएं	**5,14,748 (31.0)**	**5,74,436 (32.2)**	**63.0**	**11.6**
जिसमें :				
ए) एडीआर/जीडीआर	86,860 (5.2)	92,255 (5.2)	79.6	6.2
बी) अनिवासी द्वारा धारित बैंकों की इक्विटि	2,96,355 (17.9)	3,22,215 (18.1)	122.6	8.7
सी) पूंजी/ भारत में विदेशी बैंकों और अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताओं के विप्रेषणीय लाभ	1,31,534 (7.9)	1,59,966 (9.0)	-2.1	21.6
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**16,59,618 (100.0)**	**17,82,749 (100.0)**	**11.4**	**7.4**

टिप्पणियाँ: 1. पीआर: आंशिक रूप से संशोधित।
2. *: भारत में और विदेशों से अंतर-बैंक उधार और बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार।
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
4. प्रतिशत भिन्नता थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.3: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - लिखतों के प्रकार के आधार पर

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्तियों का प्रकार	बकाया राशि (मार्च अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2021 (पीआर)	2022 (पीआर)	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
1. ऋण और जमा	**6,56,688 (93.4)**	**6,79,018 (88.6)**	**22.3**	**3.4**
जिसमें कि:				
(ए) अनिवासियों को ऋण	1,49,800 (21.3)	1,40,708 (18.4)	75.3	-6.1
(बी) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण	1,27,869 (18.2)	1,34,290 (17.5)	-16.9	5.0
(सी) बकाया निर्यात बिल	57,283 (8.1)	53,191 (6.9)	-21.8	-7.1
(डी) उपलब्ध विदेशी मुद्रा, यात्री चेक इत्यादि।	5,663 (0.8)	342 (0.0)	82.8	-94.0
(ई) नॉस्ट्रो शेष और विदेश में स्थानन	3,16,074 (45.0)	3,50,487 (45.7)	43.0	10.9
2. धारित ऋण प्रतिभूतियां	**39,024 (5.6)**	**71,331 (9.3)**	**67.7**	**82.8**
3. अन्य अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**7,293 (1.0)**	**15,924 (2.1)**	**-52.7**	**118.4**
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां*	**7,03,005 (100.0)**	**7,66,273 (100.0)**	**22.1**	**9.0**

टिप्पणियां: 1. *: सभी शाखाओं से अधूरे डेटा कवरेज को देखते हुए, स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) के तहत रिपोर्ट किए गए डेटा सभी शाखाओं से डेटा प्राप्त करने वालों के साथ पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।
2. पीआर: आंशिक रूप से संशोधित।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग नहीं जुड़ सकता है।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.4: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे: अवशिष्ट परिपक्वता और क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता/क्षेत्र	बकाया राशि (मार्च अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2021 (पीआर)	2022 (पीआर)	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**6,13,794** **(100)**	**7,29,114** **(100)**	**6.1**	**18.8**
अवशिष्ट परिपक्वता				
अल्पकालिक	4,81,320 (78.4)	5,89,366 (80.8)	8.7	22.4
दीर्घकालिक	1,28,699 (21.0)	1,34,978 (18.5)	-2.0	4.9
अनाबंटित	3,774 (0.6)	4,771 (0.7)	-8.4	26.4
क्षेत्र				
बैंक	3,16,642 (51.6)	4,11,443 (56.4)	36.2	29.9
आधिकारिक क्षेत्र	44,611 (7.3)	51,320 (7.0)	37.4	15.0
गैर-बैंक वित्तीय संस्थान	4,248 (0.7)	3,083 (0.4)	12.8	-27.4
गैर-वित्तीय निजी	2,06,419 (33.6)	2,20,398 (30.2)	-22.5	6.8
अन्य	41,873 (6.8)	42,871 (5.9)	-3.7	2.4

टिप्पणियाँ: 1. पीआर: आंशिक रूप से संशोधित।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग नहीं जुड़ सकता है।
4. अवशिष्ट परिपक्वता 'अनाबंटित' में परिपक्वता लागू नहीं (उदाहरण के लिए, इक्विटी के लिए) और परिपक्वता की जानकारी उपलब्ध नहीं शामिल है।
5. आधिकारिक क्षेत्र में आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकरण, सामान्य सरकार और बहुपक्षीय एजेंसियां शामिल हैं।
6. गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र में गैर-वित्तीय निगम और हाउसहोल्ड जिनमें गैर-लाभकारी संस्थाओं में सेवारत हाउसहोल्ड (एनपीआईएसआईएस) शामिल हैं।
7. अन्य में गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अनाबंटित क्षेत्र शामिल हैं।
8. प्रतिशत भिन्नता थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.5: भारत के अलावा अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(राशि ₹ करोड़ में)

देश	बकाया राशि (मार्च अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2021 (पीआर)	2022 (पीआर)	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**6,13,794**	**7,29,114**	**6.1**	**18.8**
जिसमें कि				
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	1,94,023	2,46,092	24.7	26.8
	(31.6)	(33.8)		
2. यूनाइटेड किंगडम	67,652	89,813	19.0	32.8
	(11.0)	(12.3)		
3. हांगकांग	35,828	30,054	67.5	-16.1
	(5.8)	(4.1)		
4. सिंगापुर	45,049	41,744	10.0	-7.3
	(7.3)	(5.7)		
5. यूनाइटेड अरब अमीरात	79,446	89,522	-5.0	12.7
	(12.9)	(12.3)		
6. जर्मनी	27,116	31,090	76.6	14.7
	(4.4)	(4.3)		

टिप्पणियां: 1. पीआर: आंशिक रूप से संशोधित।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
3. प्रतिशत भिन्नता थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.6: भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक*	
	2021-22	**प्रतिशत घट-बढ़**	**2021-22**	**प्रतिशत घट-बढ़**	**2021-22**	**प्रतिशत घट-बढ़**	**2021-22**	**प्रतिशत घट-बढ़**	**2021-22**	**प्रतिशत घट-बढ़**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. वायदा विनिमय संविदा@	39,18,689 (30.8)	21.0	83,54,591 (113.3)	38.6	1,31,87,671 (963.6)	17.7	-	-	2,54,60,950 (117.5)	24.4
2. दी गई गारंटी	5,58,797 (4.4)	3.1	4,73,427 (6.4)	2.2	1,92,320 (14.1)	10.2	1,539 (0.8)	107.9	12,26,083 (5.7)	3.9
3. स्वीकृति, पृष्ठांकन, आदि।	7,93,145 (6.2)	32.1	3,44,959 (4.7)	25.3	9,45,228 (69.1)	30.1	878.6 (0.4)	27.1	20,84,242 (9.6)	30.0
आकस्मिक देयताएं	52,70,631 (41.5)	20.3	91,72,977 (124.4)	35.5	1,43,25,220 (1046.8)	18.4	2,417 (1.2)	68.9	2,87,71,276 (132.8)	23.7

टिप्पणी: 1. - : शून्य/नगण्य।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित बैंक-समूह की कुल देयताओं का प्रतिशत हैं।
3. अंकों को पूर्णांकित करने के कारण, घटक मदों का जोड़ कुल योग से भिन्न हो सकता है।
4. @: स्वीकार्य के रूप में सभी डेरिवेटिव उत्पाद (ब्याज दर स्वैप सहित) शामिल हैं।
5. *: भुगतान बैंकों सहित।

स्रोत: संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

परिशिष्ट सारणी IV.7: किसान क्रेडिट कार्ड योजना*: राज्य-वार प्रगति *(जारी)*

(मार्च 2022 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में तथा जारी कार्डों की संख्या '000 में)

क्रम सं.	राज्य/ संघशासित क्षेत्र	सहकारी बैंक				क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
		परिचालनगत केसीसी की संख्या		परिचालनगत केसीसी के तहत बकाया राशि		परिचालनगत केसीसी की संख्या		परिचालनगत केसीसी के तहत बकाया राशि	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	**5,409**	**5,318**	**30,415.00**	**37,239.93**	**1,372**	**1,417**	**31,809.30**	**34,814.48**
1	हरियाणा	1,179	1,169	11,436.20	12,059.26	276	287	7,697.00	8,270.90
2	हिमाचल प्रदेश	111	115	1,742.00	1,869.99	63	69	829.70	932.00
3	जम्मू और कश्मीर	8	8	58.60	61.56	118	124	883.50	988.89
4	लद्दाख	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
5	नई दिल्ली #$%	0	0	4.50	2.01	0	0	0.00	0.00
6	पंजाब	961	976	7,162.70	7,495.56	155	157	5,306.90	5,779.20
7	राजस्थान	3,150	3,050	10,011.00	15,751.55	760	780	17,092.20	18,843.49
8	चंडीगढ़ #$	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**114**	**114**	**174.20**	**169.49**	**442**	**454**	**1,748.50**	**1,925.69**
9	असम	1	1	19.30	17.95	280	282	1,218.70	1,295.40
10	अरुणाचल प्रदेश #	1	1	4.90	7.40	3	3	24.30	23.41
11	मेघालय #	16	16	32.00	32.02	25	31	144.30	175.29
12	मिजोरम #	1	1	5.70	5.74	14	19	153.10	220.99
13	मणिपुर #	2	2	17.00	10.18	10	10	38.00	40.45
14	नगालैंड #	4	4	20.20	20.23	1	1	1.60	1.61
15	त्रिपुरा #	88	88	73.30	73.27	109	109	168.50	168.53
16	सिक्किम #$	1	1	1.80	2.70	0	0	0.00	0.00
	पश्चिमी क्षेत्र	**4,348**	**4,505**	**30,411.30**	**34,226.52**	**975**	**1,088**	**11,206.40**	**13,301.52**
17	गुजरात	954	965	11,589.70	13,098.40	384	414	6,621.50	7,391.86
18	महाराष्ट्र	3,392	3,539	18,806.00	21,111.68	591	674	4,584.90	5,909.66
19	गोवा $	2	1	15.60	16.44	0	0	0.00	0.00
20	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव @#$	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	मध्य क्षेत्र	**8,076**	**8,229**	**30,752.00**	**33,742.79**	**4,155**	**4,118**	**50,443.90**	**52,243.40**
21	उत्तर प्रदेश	2,661	2,682	6,759.50	7,375.41	3,541	3,517	41,838.90	44,985.55
22	उत्तराखंड	279	295	1,191.20	1,548.66	41	39	295.50	286.76
23	मध्य प्रदेश	3,792	3,851	19,375.50	20,798.16	439	425	7,484.50	5,978.01
24	छत्तीसगढ़	1,344	1,401	3,425.80	4,020.57	134	136	825.00	993.08
	दक्षिणी क्षेत्र	**7,245**	**8,006**	**38,185.90**	**1,76,075.24**	**3,318**	**3,483**	**38,160.20**	**42,040.12**
25	कर्नाटक	2,925	3,125	17,172.70	1,44,511.43	606	668	9,777.20	11,701.01
26	केरल	584	667	4,017.30	5,324.11	298	365	3,961.80	5,561.23
27	आंध्र प्रदेश	1,463	1,535	10,879.20	12,136.26	931	946	10,823.20	11,569.01
28	तमिलनाडु	1,373	1,744	1,360.20	9,124.19	34	39	311.00	502.40
29	तेलंगाना	894	928	4,746.20	4,968.60	1,448	1,465	13,274.30	12,695.94
30	लक्षद्वीप @$	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
31	पुदुचेरी #	6	6	10.30	10.64	1	1	12.70	10.51
	पूर्वी क्षेत्र	**4,989**	**4,959**	**17,042.60**	**17,828.11**	**2,630**	**2,788**	**16,047.70**	**17,734.38**
32	ओडिशा	3,000	2,901	12,216.60	12,809.27	440	433	2,298.70	2,402.98
33	पश्चिम बंगाल	1,732	1,787	4,355.10	4,501.22	391	401	1,751.10	1,916.02
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह @$	6	7	16.30	17.50	0	0	0.00	0.00
35	बिहार	238	251	417.60	464.47	1,420	1,572	10,035.40	11,261.49
36	झारखंड	13	13	37.00	35.65	379	382	1,962.50	2,153.89
	कुल	**30,181**	**31,131**	**1,46,981.00**	**2,99,282.08**	**12,892**	**13,348**	**1,49,416.00**	**1,62,059.58**

परिशिष्ट सारणी IV.7: किसान क्रेडिट कार्ड योजना *: राज्य-वार प्रगति *(समाप्त)*
(मार्च 2022 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में तथा जारी कार्डों की संख्या ‘000 में)

क्रम सं.	राज्य/ संघशासित क्षेत्र	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक				कुल			
		परिचालनगत केसीसी की संख्या		परिचालनगत केसीसी के तहत बकाया राशि		परिचालनगत केसीसी की संख्या		परिचालनगत केसीसी के तहत बकाया राशि	
		2021	**2022***	**2021**	**2022***	**2021**	**2022**	**2021**	**2022**
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	उत्तरी क्षेत्र	**5,847**	**5,455.26**	**1,36,112.69**	**1,44,350.74**	**12,628**	**12,190**	**1,98,336.99**	**2,16,405.15**
1	हरियाणा	809	796	26,222.75	27,719.06	2,264	2,253	45,355.95	48,049.22
2	हिमाचल प्रदेश	218	240	4,054.50	4,507.33	392	424	6,626.20	7,309.32
3	जम्मू और कश्मीर	883	802	5,575.98	5,241.42	1,009	934	6,518.08	6,291.87
4	लद्दाख	30	190	281.02	4,225.76	30	190	281.02	4,225.76
5	नई दिल्ली #$%	4	3	90.87	53.39	4	3	95.37	55.39
6	पंजाब	1,128	1,036	42,056.38	42,504.87	2,244	2,169	54,525.98	55,779.63
7	राजस्थान	2,705	2,387	57,533.94	59,991.67	6,615	6,216	84,637.14	94,586.72
8	चंडीगढ़ #$	71	1	297.26	107.24	71	1	297.26	107.24
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**585**	**491**	**3,176.83**	**3,289.28**	**1,141**	**1,058**	**5,099.53**	**5,384.46**
9	असम	456	375	2,517.09	2,582.70	737	658	3,755.09	3,896.06
10	अरुणाचल प्रदेश #	5	6	32.82	45.42	9	10	62.02	76.23
11	मेघालय #	20	19	113.99	112.70	61	66	290.29	320.02
12	मिजोरम #	10	8	32.61	41.91	25	27	191.41	268.64
13	मणिपुर #	6	6	46.39	60.28	18	18	101.39	110.91
14	नगालैंड #	23	22	125.22	131.60	28	26	147.02	153.44
15	त्रिपुरा #	59	49	276.58	270.94	256	246	518.38	512.74
16	सिक्किम #$	6	6	32.13	43.72	7	7	33.93	46.43
	पश्चिमी क्षेत्र	**4,453**	**4,205**	**66,274.16**	**71,643.99**	**9,776**	**9,798**	**1,07,891.86**	**1,19,172.03**
17	गुजरात	1,554	1,500	33,909.45	36,450.35	2,892	2,879	52,120.65	56,940.61
18	महाराष्ट्र	2,885	2,696	32,244.34	35,069.20	6,868	6,910	55,635.24	62,090.54
19	गोवा $	12	7	98.39	93.96	14	8	113.99	110.40
20	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव @#$	1	1	21.98	30.48	1	1	21.98	30.48
	मध्य क्षेत्र	**7,697**	**6,524**	**1,20,761.57**	**1,22,146.69**	**19,928**	**18,870**	**2,01,957.47**	**2,08,132.89**
21	उत्तर प्रदेश	5,079	4,272	69,467.22	70,672.67	11,281	10,471	1,18,065.62	1,23,033.63
22	उत्तराखंड	286	212	5,624.07	4,852.19	606	547	7,110.77	6,687.61
23	मध्य प्रदेश	2,043	1,794	41,367.31	41,837.06	6,274	6,070	68,227.31	68,613.22
24	छत्तीसगढ़	288	246	4,302.97	4,784.77	1,766	1,782	8,553.77	9,798.43
	दक्षिणी क्षेत्र	**7,979**	**7,133**	**1,08,631.27**	**1,14,023.45**	**18,542**	**18,622**	**1,84,977.37**	**3,32,138.81**
25	कर्नाटक	1,292	944	19,139.79	19,013.66	4,823	4,737	46,089.69	1,75,226.10
26	केरल	981	905	18,766.03	17,068.52	1,863	1,937	26,745.13	27,953.85
27	आंध्र प्रदेश	2,211	2,096	30,576.42	32,420.05	4,605	4,577	52,278.82	56,125.33
28	तमिलनाडु	1,566	1,273	18,193.36	21,982.65	2,973	3,055	19,864.56	31,609.25
29	तेलंगाना	1,918	1,880	21,800.90	22,946.79	4,260	4,273	39,821.40	40,611.34
30	लक्षद्वीप @$	0	25	2.65	376.03	0	25	2.65	376.03
31	पुदुचेरी #	9	10	152.12	215.75	16	18	175.12	236.91
	पूर्वी क्षेत्र	**4,136**	**3,063**	**21,779.82**	**20,816.50**	**11,755**	**10,810**	**54,870.12**	**56,378.98**
32	ओडिशा	898	666	4,804.77	5,108.97	4,338	4,000	19,320.07	20,321.21
33	पश्चिम बंगाल	1,589	1,034	7,536.68	7,366.58	3,712	3,222	13,642.88	13,783.82
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह $	2	2	17.70	27.96	8	9	34.00	45.46
35	बिहार	1,113	834	6,931.67	5,854.90	2,771	2,657	17,384.67	17,580.87
36	झारखंड	533	527	2,488.99	2,458.09	925	922	4,488.49	4,647.62
	कुल	**30,696**	**26,870**	**4,56,736.33**	**4,76,270.65**	**73,769**	**71,349**	**7,53,133.33**	**9,37,612.31**

टिप्पणियां: 1. %: नगण्य।
2. #: राज्य सहकारी बैंक केंद्रीय वित्तीय एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।
3. @ इन संघशासित क्षेत्रो में कोई सहकारी बैंक नहीं है।
4. $: इन राज्यों में/ संघशासित क्षेत्रों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।
5. *: डेटा अनंतिम है।
6. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ उनके संबंधित कुल से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विवरणियाँ।

परिशिष्ट सारणी IV.8: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक*	
	2021-22	प्रतिशत में घट-बढ़	2021-22	प्रतिशत में घट-बढ़	2021-22	प्रतिशत में घट-बढ़	2021-22	प्रतिशत में घट-बढ़	2021-22	प्रतिशत में घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूंजी बाज़ार #	48,278 (0.7)	24.0	96,618 (2.1)	19.1	9,079 (2.0)	-17.0	323 (0.2)	187.2	1,54,311 (1.3)	17.7
2. स्थावर संपदा @	14,75,735 (21.0)	7.3	11,62,001 (25.5)	16.2	1,39,153 (29.9)	6.3	23,056 (17.0)	24.0	27,99,945 (22.9)	10.9
3. कमोडिटी	0		0		0		0		0	
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	15,24,013 (21.6)	8.0	12,58,619 (27.6)	16.4	1,48,233 (31.8)	4.5	23,379 (17.2)	24.9	29,54,256 (24.2)	11.2

टिप्पणियां: 1. #: पूंजी बाज़ार के प्रति एक्सपोजर में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।
2. @: स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण दोनों शामिल हैं।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित बैंक समूह के कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत दर्शाते हैं।
4. *: भुगतान बैंकों सहित।
5. - : शून्य / नगण्य।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे ।

परिशिष्ट सारणी IV.9: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(जारी)*

(मार्च 2022 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और आरबीआई– निवासी	वित्तीय संस्थाएं -निवासी	वित्तीय संस्थाएं-अनिवासी	अन्य कॉर्पोरेट-निवासी	अन्य कॉर्पोरेट-अनिवासी	कुल व्यक्ति-निवासी	कुल व्यक्ति-अनिवासी	कुल-निवासी	कुल-अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक									
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	64	15	9.2	3.5	0	8	0.4	90.5	9.5
2	बैंक ऑफ इंडिया	81.4	10.8	0.9	6.6	0.1	0	0	98.9	1.1
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	91	3.7	0.1	0.4	0	4.7	0.1	99.7	0.3
4	केनरा बैंक	62.9	12.6	0	4	8.5	10.8	1.2	90.3	9.7
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	93.1	2.8	0.1	0.3	0	3.7	0.1	99.8	0.2
6	इंडियन बैंक	79.9	11.1	0	0.7	1.7	6.5	0.2	98.1	1.9
7	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	96.4	1.3	0.1	0.2	0	2	0.1	99.9	0.1
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	98.3	0.6	0	0.1	0	1	0	100	0
9	पंजाब नेशनल बैंक	73.2	11.6	1.4	1	0	12.6	0.3	98.4	1.6
10	भारतीय स्टेट बैंक	56.9	24.4	9.9	0.9	1.2	6.5	0.3	88.7	11.3
11	यूको बैंक	95.4	1.3	0	0.1	0	3.1	0.1	99.9	0.1
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	83.5	1	1.2	6.8	0	7.4	0.1	98.7	1.3

परिशिष्ट सारणी IV.9: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(जारी)*
(मार्च 2022 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और आरबीआई– निवासी	वित्तीय संस्थाएं -निवासी	वित्तीय संस्थाएं- अनिवासी	अन्य कॉर्पोरेट- निवासी	अन्य कॉर्पोरेट- अनिवासी	कुल व्यक्ति- निवासी	कुल व्यक्ति- अनिवासी	कुल- निवासी	कुल- अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	निजी क्षेत्र के बैंक									
1	ऐक्सिस बैंक लिमि.	-	37.5	48.1	3.2	4.4	6.6	0.3	47.3	52.8
2	बंधन बैंक लिमि.	-	8.5	30.3	50.5	4.1	6.3	0.4	65.3	34.7
3	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	-	8.4	-	12.7	55.3	16.6	7	37.7	62.3
4	सिटी यूनियन बैंक लिमि.	-	41.2	18.1	3.2	-	36.6	0.9	81	19
5	डीसीबी बैंक लिमि.	0.2	37.5	-	7.8	22.9	30.1	1.5	75.6	24.4
6	फेडरल बैंक लिमि.	-	42.7	27	2.5	-	22.9	4.8	68.1	31.9
7	एचडीएफसी बैंक लिमि.	0.1	20	68.6	1.7	-	9.5	0.1	31.3	68.7
8	आईसीआईसीआई बैंक लिमि.	0.2	25.3	54.7	12.5	-	7	0.4	44.9	55.1
9	आईडीबीआई बैंक लिमि.	45.5	49.6	-	0.7	-	3.9	0.4	99.6	0.4
10	आईडीएफसी बैंक लिमि.	4.2	3.9	13.5	44.2	7.6	25.3	1.3	77.6	22.4
11	इंडसइंड बैंक लिमि.	-	20.1	50.7	4.3	16	8.3	0.6	32.7	67.3
12	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमि.	70.1	2.1	0.7	2.5	-	23.8	0.8	98.5	1.5
13	कर्नाटक बैंक लिमि.	-	5.3	-	4.6	11.9	75.3	2.9	85.2	14.8
14	करूर वैश्य बैंक लिमि.	-	21.9	-	4.6	15.4	57	1.2	83.5	16.5
15	कोटक महिंद्रा बैंक लिमि.	-	16.6	42.5	3	1.6	35.8	0.5	55.4	44.6
16	नैनीताल बैंक लिमि.	-	98.6	-	-	-	1.4	-	100	-
17	आरबीएल बैंक लिमि.	0.4	18.9	2.4	7.4	38.8	30.7	1.5	57.3	42.7
18	साउथ इंडियन बैंक लिमि.	-	-	-	21.8	7.4	63.2	7.7	85	15
19	तमिलनाड मर्कैंटाइल बैंक लिमि.	-	-	-	13.5	24.9	61.5	0.1	75	25
20	दी धनलक्ष्मी बैंक लिमि.	0.5	0.4	-	10.7	11.5	57.8	19.1	69.4	30.6
21	येस बैंक लिमि.	-	44	-	8	11	35.5	1.6	87.5	12.5

परिशिष्ट सारणी IV.9: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(समाप्त)*

(मार्च 2022 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और आरबीआई– निवासी	वित्तीय संस्थाएं -निवासी	वित्तीय संस्थाएं- अनिवासी	अन्य कॉर्पोरेट- निवासी	अन्य कॉर्पोरेट- अनिवासी	कुल व्यक्ति- निवासी	कुल व्यक्ति- अनिवासी	कुल- निवासी	कुल- अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	लघु वित्त बैंक									
1	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	11.22	34.31	13.59	3.21	36.85	0.82	61.66	38.34
2	कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड		21.86	9.83	0.22	-	50.79	17.3	72.87	27.13
3	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	16.68	3.62	74.68	-	4.86	0.16	96.22	3.78
4	एसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	66.63	-	17.21	-	7.43	8.73	91.27	8.73
5	फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	80.29	-	6.67	10.72	2.31	0.01	89.27	10.73
6	जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	5.67	47.59	45.87	-	0.87	-	52.41	47.59
7	नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	-	-	100	-	-	-	100	-
8	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	-	-	7.69	-	92.31	-	100	-
9	सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	21.27	-	7.16	28.46	42.98	0.13	71.41	28.59
10	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	-	-	84.51	0.15	14.69	0.65	99.2	0.8
11	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	-	-	-	89.36	10.25	0.39	-	89.75	10.25
	स्थानीय क्षेत्र बैंक									
1	कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	-	-	-	25	-	47.91	27.09	72.91	27.09
2	कृष्ण भीम समृद्धि लैब लिमिटेड	-	-	-	24.67	-	75.33	-	100	-

टिप्पणी : शून्य/नगण्य।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.10: भारतीय बैंको के विदेशी परिचालन

(मार्च के अंत में)

क्र. सं.	मद	शाखा		अनुषंगी		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		अन्य कार्यालय*		कुल	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**	**111**	**108**	**22**	**21**	**13**	**13**	**7**	**7**	**35**	**35**	**188**	**184**
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	33	30	7	7	0	0	2	2	10	10	52	49
2	बैंक ऑफ इंडिया	23	23	4	4	1	1	0	0	0	0	28	28
3	केनरा बैंक	5+1#	6	1	1	1	1	0	0	0	0	8	8
4	इंडियन बैंक	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
5	इंडियन ओवरसीज बैंक	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	6	6
6	पंजाब नेशनल बैंक	2	2	2	2	2#	2	2	2	0	0	8	8
7	भारतीय स्टेट बैंक	35	35	7	6	7	7	3	3	23	23	75	74
8	सिंडीकेट बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	यूको बैंक	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
10	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	6	5
11	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**15**	**15**	**3**	**3**	**21**	**25**	**0**	**0**	**1**	**1**	**40**	**44**
13	ऐक्सिस बैंक	2	2	1	1	4	4	0	0	0	0	7	7
14	एचडीएफसी बैंक लिमि.	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	6	6
15	आईसीआईसीआई बैंक लिमि.	8	8	2	2	6	10	0	0	1	1	17	21
16	आईडीबीआई बैंक लिमि.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	इंडसइंड बैंक लिमि.	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
18	फेडरल बैंक लिमि.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
19	कोटक महिंद्रा बैंक लिमि.	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2
20	येस बैंक लिमि.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
21	साउथ इंडियन बैंक लिमि.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	सभी बैंक	**126**	**123**	**25**	**24**	**34**	**38**	**7**	**7**	**36**	**36**	**228**	**228**

टिप्पणियां: 1. *: अन्य कार्यालयों में विपणन / उप-कार्यालय, विप्रेषण केंद्र आदि शामिल हैं।

2. 01 अप्रैल, 2020 से सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

परिशिष्ट सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2022 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम और सीआरएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	शाखा स्थित	शाखेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**28,762**	**23,157**	**16,134**	**16,203**	**84,256**	**78,540**	**59,516**	**1,38,056**
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,840	2,071	1,480	1,777	8,168	8,756	2,730	11,486
2	बैंक ऑफ इंडिया	1,844	1,455	813	934	5,046	5,197	2,751	7,948
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	611	507	414	490	2,022	1,693	435	2,128
4	केनरा बैंक	3,041	2,754	1,981	1,958	9,734	8,073	4,135	12,208
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,602	1,328	786	812	4,528	2,389	587	2,976
6	इंडियन बैंक	1,940	1,494	1,159	1,139	5,732	4,304	625	4,929
7	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	902	960	653	684	3,199	2,738	616	3,354
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	570	278	357	325	1,530	657	19	676
9	पंजाब नेशनल बैंक	3,853	2,453	2,036	1,757	10,099	8,233	5,117	13,350
10	भारतीय स्टेट बैंक	7,948	6,500	3,997	3,826	22,271	26,364	39,088	65,452
11	यूको बैंक	1,076	815	610	558	3,059	2,094	223	2,317
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,535	2,542	1,848	1,943	8,868	8,042	3,190	11,232

परिशिष्ट सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2022 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम और सीआरएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	शाखा स्थित	शाखेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9	10
	निजी क्षेत्र के बैंक	**7,856**	**11,971**	**7,976**	**10,069**	**37,872**	**38,254**	**37,289**	**75,543**
1	ऐक्सिस बैंक लिमि.	800	1,424	1,128	1,521	4,873	5,748	11,174	16,922
2	बंधन बैंक लिमि.	1,996	2,088	1,024	531	5,639	466	5	471
3	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमि.	126	277	148	170	721	1,110	622	1,732
4	सिटी यूनियन बैंक लिमि.	47	316	119	124	606	407	52	459
5	डीसीबी बैंक लिमि.	72	105	111	112	400	341	8	349
6	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	19	106	62	58	245	214	44	258
7	फेडरल बैंक लिमि.	164	687	237	212	1,300	1,505	380	1,885
8	एचडीएफसी बैंक लिमि.	1,148	2,038	1,307	1,845	6,338	8,703	9,427	18,130
9	आईसीआईसीआई बैंक लिमि.	1,127	1,581	1,074	1,575	5,357	8,402	8,175	16,577
10	आईडीबीआई लिमि.	405	582	469	428	1,884	2,221	1,182	3,403
11	आईडीएफसी बैंक लिमि.	51	201	254	346	852	505	214	719
12	इंडसइंड बैंक लिमि.	294	453	565	731	2,043	1,492	1,275	2,767
13	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमि.	527	176	107	166	976	840	613	1,453
14	कर्नाटक बैंक लिमि.	201	204	230	242	877	822	626	1,448
15	करूर वैश्य बैंक लिमि.	134	305	161	230	830	1,362	861	2,223
16	कोटक महिंद्रा बैंक लिमि.	265	304	365	766	1,700	1,385	1,314	2,699
17	नैनीताल बैंक लिमि.	53	34	44	33	164	-	-	-
18	आरबीएल बैंक लिमि.	64	75	72	290	501	373	41	414
19	साउथ इंडियन बैंक लिमि.	109	457	172	197	935	852	418	1,270
20	तमिलनाड मर्कैंटाइल बैंक लिमि.	106	245	80	78	509	475	668	1,143
21	येस बैंक लिमि.	148	313	247	414	1,122	1,031	190	1,221

परिशिष्ट सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(समाप्त)*

(मार्च 2022 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम और सीआरएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	शाखा स्थित	शाखेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विदेशी बैंक	**124**	**183**	**166**	**388**	**861**	**716**	**1,081**	**1,797**
1	एबी बैंक लिमिटेड	-	-	-	1	1	-	-	-
2	अबू धाबी कमर्शियल बैंक (पी.जे.एस.सी)	-	-	-	1	1	-	-	-
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन	-	-	-	1	1	-	-	-
4	ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमि.	1	-	1	1	3	-	-	-
5	बैंक ऑफ अमेरिका, नैशनल असोसिएशन	-	-	-	4	4	-	-	-
6	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी	-	1	-	3	4	4	0	4
7	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	1	1	-	-	-
8	बैंक ऑफ चाइना लिमि.	-	-	-	1	1	-	-	-
9	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	-	2	2	-	-	-
10	बरक्लैज बैंक पीएलसी	-	1	-	2	3	-	-	-
11	बीएनपी पारिबास	-	-	-	5	5	-	-	-
12	सिटीबैंक एन.ए	-	-	4	31	35	47	441	488
13	कॉपरेटिव रेबोबैंक यू.ए.	-	-	-	1	1	-	-	-
14	क्रेडिट एग्रिकोल कॉर्पोरेट ऐंड इन्वेस्टमेंट बैंक	-	-	-	5	5	-	-	-
15	क्रेडिट सुइस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-
16	सिटिबीसी बैंक को. लिमि.	-	1	-	1	2	-	-	-
17	डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड*	116	177	127	171	591	500	521	1021
18	ड्यूश बैंक एजी	1	-	5	11	17	13	19	32
19	दोहा बैंक क्यू.पी.एस.सी	-	-	1	2	3	3		3
20	एमिरेटस एनबीडी बैंक (पी.जे.एस.सी)	-	-	-	1	1	-	-	-
21	फर्स्ट अबू धाबी बैंक (पी.जे.एस.सी)	-	-	-	1	1	-	-	-
22	फ़र्स्टरैंड बैंक लिमि.	-	-	-	1	1	-	-	-
23	हांगकांग एन्ड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमि.	-	-	4	22	26	46	28	74
24	इंडस्ट्रियल एन्ड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना	-	-	-	1	1	-	-	-
25	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया	-	-	-	1	1	-	-	-
26	जेपी मोर्गन चेस बैंक नैशनल असोसिएशन	2	-	-	2	4	-	-	-
27	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
28	केईबी हना बैंक	-	1	-	1	2	1		1
29	कूकमीन बैंक	-	-	1	-	1	1		1
30	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं.लिमि.	-	-	-	1	1	-	-	-
31	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	1	1	-	-	-
32	मिज़ुओ बैंक लिमि.	-	1	1	3	5	-	-	-
33	एमयूएफजी बैंक लिमि.	1	-	-	4	5	-	-	-
34	नाटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी	-	-	-	1	1	-	-	-
35	पीटी बैंक मेबैंक इंडोनेशिया टीबीके	-	-	-	1	1	-	-	-
36	कतर नैशनल बैंक (क्यू.पी.एस.सी)	-	-	-	1	1	-	-	-
37	स्बेर बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
38	एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमि.	1	-	-	7	8	6		6
39	सिनहान बैंक	1	-	-	5	6	-	-	-
40	सोसाइटे जनरल	-	-	-	2	2	-	-	-
41	सोनाली बैंक	-	-	1	1	2	-	-	-
42	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1	1	20	78	100	95	72	167
43	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-	3	3	-	-	-
44	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमि.	-	-	-	1	1	-	-	-
45	वूरी बैंक	-	-	1	2	3	-	-	-

टिप्पणियां: (ए) जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 'ग्रामीण' में 10,000 से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'अर्ध-शहरी' में 10,000 और उससे अधिक लेकिन एक लाख से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'शहरी' में एक लाख और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं और 'महानगर' में 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। सभी जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।

(बी) शाखाओं के डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।

(सी)-: शून्य।

स्रोत: बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस (पूर्व में मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम) के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली, आरबीआई। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेटा के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली का स्वरूप गतिशील है। बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर डेटा अद्यतन किए जाते हैं और हमारे द्वारा संसाधित किए जाते हैं।

परिशिष्ट सारणी IV.12: आरबीआई लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(अप्रैल से मार्च 2021-22)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रमुख श्रेणियों में शिकायतों की संख्या								अन्य	कुल
		जमा खाता	ऋण और अग्रिम	एटीएम/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड	मोबाइल बैंकिंग / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	पूर्व सूचना के बिना प्रभार लगाना	पेंशन	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	प्रतिबद्धता पूरी न करना और बीसीएसबीआई संहिता की प्रतिबद्धता में असफलता		
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**10,632**	**12,609**	**35,037**	**24,226**	**5,087**	**6,070**	**13,445**	**14,669**	**25,250**	**147,025**
1	भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई कार्ड को छोड़कर)	3,858	4,889	13,003	12,275	1,862	2,710	5,047	5,390	9,610	58,644
2	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,080	1,283	3,214	1,734	630	256	1,549	1,259	2,369	13,374
3	बैंक ऑफ इंडिया	452	602	2,923	966	215	217	608	530	1,319	7,832
4	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	123	145	624	320	92	30	110	111	398	1,953
5	केनरा बैंक	980	1,202	1,992	1,111	581	343	1,256	1,463	2,042	10,970
6	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	417	527	2,346	904	140	373	585	513	1,033	6,838
7	इंडियन बैंक	757	792	1,940	1,168	275	429	777	741	1,361	8,240
8	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	201	351	492	290	98	46	265	251	400	2,394
9	पंजाब एंड सिंध बैंक	61	82	207	134	31	7	60	210	156	948
10	पंजाब नेशनल बैंक	1,600	1,430	4,492	2,909	645	1,192	1,785	2,789	3,776	20,618
11	यूको बैंक	206	236	464	384	84	76	221	262	498	2,431
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	897	1,070	3,340	2,031	434	391	1,182	1,150	2,288	12,783

परिशिष्ट सारणी IV.12: आरबीआई लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*
(अप्रैल से मार्च 2021-22)

क्र. सं.	बैंक का नाम	निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रमुख श्रेणियों में शिकायतों की संख्या								अन्य	कुल
		जमा खाता	ऋण और अग्रिम	एटीएम/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड	मोबाइल बैंकिंग / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	पूर्व सूचना के बिना प्रभार लगाना	पेंशन	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	प्रतिबद्धता पूरी न करना और बीसीएसबीआई संहिता की प्रतिबद्धता में असफलता		
	निजी क्षेत्र के बैंक	**4,215**	**10,025**	**28,903**	**11,180**	**6,727**	**62**	**8,762**	**9,805**	**14,596**	**94,275**
1	ऐक्सिस बैंक लिमि.	856	1,499	5,685	1,694	1,730	7	1,424	1,779	2,318	16,992
2	बंधन बैंक लिमि.	48	134	184	106	21	1	83	54	138	769
3	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमि.	7	19	15	7	10	-	24	12	25	119
4	सिटी यूनियन बैंक लिमि.	18	54	49	60	19	-	34	20	53	307
5	डीसीबी बैंक लिमि.	31	188	35	26	50	1	90	108	119	648
6	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	6	16	6	5	4	-	7	7	13	64
7	फेडरल बैंक लिमि.	77	119	241	207	38	-	118	66	175	1,041
8	एचडीएफसी बैंक लिमि.	834	2,077	5,950	2,673	1,248	18	1,849	2,305	3,090	20,044
9	आईसीआईसीआई बैंक लिमि.	1,050	2,529	5,815	3,158	1,698	21	2,102	2,298	3,372	22,043
10	आईडीबीआई बैंक लिमि.	179	392	383	301	217	5	250	252	521	2,500
11	आईडीएफसी बैंक लिमि.	136	790	406	289	232	1	527	493	913	3,787
12	इंडसइंड फ़र्स्ट बैंक लिमि.	221	467	1,960	515	298	-	488	614	860	5,423
13	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमि.	28	59	190	143	31	2	52	29	123	657
14	कर्नाटक बैंक लिमि.	36	76	98	106	45	-	55	89	87	592
15	करूर वैश्य बैंक लिमि.	48	103	69	79	27	1	83	57	69	536
16	कोटक महिंद्रा बैंक लिमि.	326	765	2,152	1,048	503	5	706	785	1,451	7,741
17	नैनीताल बैंक लिमि.	6	8	11	12	3	-	9	5	7	61
18	आरबीएल बैंक लिमि.	114	234	4,856	294	297	-	433	417	657	7,302
19	साउथ इंडियन बैंक लिमि.	32	89	88	77	31	-	67	36	80	500
20	तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक लिमि.	30	43	49	51	28	-	69	17	43	330
21	येस बैंक लिमि.	132	364	661	329	197	-	292	362	482	2,819

परिशिष्ट सारणी IV.12: आरबीआई लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(अप्रैल से मार्च 2021-22)

क्र. सं.	बैंक का नाम	विदेशी बैंकों की प्रमुख श्रेणियों में शिकायतों की संख्या								अन्य	कुल
		जमा खाता	ऋण और अग्रिम	एटीएम/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड	मोबाइल बैंकिंग / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	पूर्व सूचना के बिना प्रभार लगाना	पेंशन	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	प्रतिबद्धता पूरी न करना और बीसीएसबीआई संहिता की प्रतिबद्धता में असफलता		
	विदेशी बैंक	**163**	**318**	**2,085**	**458**	**203**	**6**	**355**	**326**	**550**	**4,464**
1	एबी बैंक लिमिटेड	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3
2	अबू धाबी कमर्शियल बैंक पी.जे.एस.सी	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन	1	2	233	4	26	-	14	19	10	309
4	बरक्लैज बैंक पीएलसी	2	1	6	1	1	-	-	2	6	19
5	बैंक ऑफ अमेरिका , नैशनल असोसिएशन	-	-	-	2	-	-	2	-	4	8
6	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
7	बीएनपी पारिबास	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
8	सिटीबैंक एन.ए	33	34	777	136	41	-	98	80	162	1,361
9	डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड*	54	27	56	105	20	2	48	40	81	433
10	ड्यूश बैंक एजी	7	38	4	3	5	-	15	18	34	124
11	दोहा बैंक	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
12	एमिरेट्स एनबीडी बैंक (पी.जे.एस.सी.)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	फ़र्स्टरैंड बैंक लिमि.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
14	हांगकांग एन्ड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमि.	14	26	217	27	11	-	32	21	31	379
15	इंडस्ट्रियल एन्ड कामर्शियल बैंक ऑफ चाइना	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
16	जेपी मॉर्गन चेस बैंक नैशनल असोसिएशन	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
17	मिजुओ बैंक लिमि.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
18	एमयूएफजी बैंक लिमि.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
19	नाटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी (पूर्ववर्ती दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी)	-	-	4	-	-	-	2	4	1	11
20	एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमि.	10	6	66	11	1	-	2	9	10	115
21	सिनहान बैंक	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3
22	सोनाली बैंक	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
23	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	41	177	720	168	98	3	138	129	206	1,680
24	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमि.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
25	वूरी बैंक	-	3	-	-	-	-	-	2	-	5

परिशिष्ट सारणी IV.12: आरबीआई लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(समाप्त)*

(अप्रैल से मार्च 2021-22)

क्र. सं.	बैंक का नाम	लघु वित्त बैंकों की प्रमुख श्रेणियों में शिकायतों की संख्या								अन्य	कुल
		जमा खाता	ऋण और अग्रिम	एटीएम/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड	मोबाइल बैंकिंग / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	पूर्व सूचना के बिना प्रभार लगाना	पेंशन	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	प्रतिबद्धता पूरी न करना और बीसीएसबीआई संहिता की प्रतिबद्धता में असफलता		
	लघु वित्त बैंक	**155**	**388**	**196**	**189**	**115**	**1**	**243**	**263**	**389**	**1,939**
1	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	39	160	62	60	45	-	88	103	172	729
2	कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	1	10	2	4	1	-	-	16	7	41
3	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	28	85	24	35	19	-	49	39	61	340
4	ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	3	9	13	8	4	-	10	7	14	68
5	फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	26	22	21	20	10	-	17	19	27	162
6	जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	16	42	31	5	12	-	36	33	38	213
7	नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	1	1	2	-	-	-	1	-	-	5
8	सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	6	4	1	-	2	-	10	1	9	33
9	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	23	49	33	43	19	1	24	33	49	274
10	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	12	6	7	14	3	-	8	12	12	74
	भुगतान बैंक	**578**	**44**	**461**	**2,433**	**133**	**1**	**278**	**645**	**1,564**	**6,137**
1	एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	346	5	102	1,167	92	1	131	397	821	3,062
2	फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	15	3	50	34	3	-	15	23	62	205
3	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	32	2	53	84	7	-	15	33	61	287
4	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	1	-	1	9	-	-	1	1	1	14
5	एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	17	2	2	10	7	-	8	15	28	89
6	पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	167	32	253	1,129	24	-	108	176	591	2,480
	अन्य (एसबीआई कार्ड + प्राथमिक) शहरी सहकारी बैंक+आरआरबी+अन्य)	964	7,350	9,521	2,111	2,251	39	14,797	1,139	12,484	50,656

टिप्पणी : शून्य/नगण्य।

स्रोत: आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी IV.13 : सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रगति

(मार्च के अंत में)

मद	स्वयं सहायता समूह									
	संख्या					राशि (₹ करोड़ में)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	2,261,132 (1,377,278)	2,698,400 (1,777,763)	3,146,002 (2,208,182)	2,887,394 (1,696,299)	3,398,267 (2,474,719)	47,186 (27,479)	58,318 (36,819)	77,659 (55,590)	58,071 (31,755)	99,729 (68,917)
बैंकों का बकाया ऋण	5,020,358 (3,083,143)	5,077,332 (3,510,238)	5,677,071 (3,956,504)	5,780,244 (3,601,395)	6,739,957 (4,781,201)	75,598 (43,576)	87,098 (58,432)	108,075 (73,184)	103,289 (61,393)	151,051 (101,840)
बैंकों के पास बचत	8,744,437 (4,608,745)	10,014,243 (6,019,185)	10,243,323 (6,258,085)	11,223,400 (3,601,395)	11,893,053 (7,764,906)	19,592 (11,785)	23,324 (14,482)	26,152 (15,836)	37,477 (21,308)	47,240 (31,077)
	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं									
	संख्या					राशि (₹ करोड़ में)				
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	1,902	1,913	4,746	28,542	24,628	22,228	13,721	19,133	12,120	23,173
बैंकों का बकाया ऋण	4,973	5,404	15,141	61,111	58,753	26,172	16,045	27,256	21,063	34,865
	संयुक्त देयता समूह									
	संख्या					राशि (₹ करोड़ में)				
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण (वित्तीय वर्ष के दौरान)	10.2	16	41.8	41.3	54.1	13,955	30,947	83,103	58,312	112,773

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत शामिल एसएचजी का विवरण देते हैं।

2. बैंकों से ऋण लेने वाले एमएफआई की वास्तविक संख्या खातों की संख्या से कम होगी, क्योंकि अधिकांश एमएफआई एक ही बैंक से कई बार और एकाधिक बैंकों से भी ऋण लेते हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.14: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य वित्तीय संकेतक: राज्य-वार *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र/ राज्य	2020-21						2021-22					
	आरआरबी की संख्या	लाभ कमाने वाले		घाटे में चल रहे		निवल लाभ/ हानि	आरआरबी की संख्या	लाभ कमाने वाले		घाटे में चल रहे		निवल लाभ/ हानि
	मार्च-2021	संख्या	राशि	संख्या	राशि		मार्च-2022	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य क्षेत्र	**7**	**5**	**468**	**2**	**224**	**245**	**7**	**6**	**253**	**1**	**125**	**128**
छत्तीसगढ़	1	1	12	0	-	12	1	1	27	0	-	27
मध्य प्रदेश	2	0	-	2	224	-224	2	1	33	1	125	-93
उत्तर प्रदेश	3	3	454	0	-	454	3	3	186	0	-	186
उत्तराखंड	1	1	2	0	-	2	1	1	7	0	-	7
पूर्वी क्षेत्र	**8**	**3**	**112**	**5**	**1,116**	**-1,004**	**8**	**5**	**154**	**3**	**486**	**-332**
बिहार	2	0	-	2	432	-432	2	0	-	2	386	-386
झारखंड	1	1	32	0	-	32	1	1	73	0	-	73
ओडिशा	2	0	-	2	623	-623	2	2	7	0	-	7
पश्चिम बंगाल	3	2	80	1	61	19	3	2	74	1	100	-26
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**7**	**4**	**246**	**3**	**121**	**124**	**7**	**5**	**228**	**2**	**5**	**223**
अरुणाचल प्रदेश	1	1	6	0	-	6	1	1	12	0	-	12
असम	1	0	-	1	114	-114	1	1	0	0	-	0
मणिपुर	1	0	-	1	5	-5	1	0	-	1	4	-4
मेघालय	1	1	1	0	-	1	1	1	23	0	-	23
मिजोरम	1	1	39	0	-	39	1	1	49	0	-	49
नगालैंड	1	0	-	1	2	-2	1	0	-	1	1	-1
त्रिपुरा	1	1	200	0	-	200	1	1	143	0	-	143
उत्तरी क्षेत्र	**7**	**5**	**435**	**2**	**49**	**386**	**7**	**5**	**851**	**2**	**61**	**790**
हरियाणा	1	1	18	0	-	18	1	1	141	0	-	141
हिमाचल प्रदेश	1	1	9	0	-	9	1	1	5	0	-	5
जम्मू और कश्मीर	2	0	-	2	49	-49	2	0	-	2	61	-61
पंजाब	1	1	53	0	-	53	1	1	109	0	-	109
राजस्थान	2	2	355	0	-	355	2	2	597	0	-	597
दक्षिणी क्षेत्र	**10**	**10**	**2,117**	**0**	**-**	**2,117**	**10**	**10**	**2,410**	**0**	**-**	**2,410**
आंध्र प्रदेश	3	3	565	0	-	565	3	3	780	0	-	780
कर्नाटक	2	2	21	0	-	21	2	2	79	0	-	79
केरल	1	1	33	0	-	33	1	1	124	0	-	124
पुदुचेरी	1	1	9	0	-	9	1	1	10	0	-	10
तमिलनाडु	1	1	185	0	-	185	1	1	229	0	-	229
तेलंगाना	2	2	1,304	0	-	1,304	2	2	1,187	0	-	1,187
पश्चिमी क्षेत्र	**4**	**3**	**172**	**1**	**357**	**-185**	**4**	**3**	**219**	**1**	**220**	**-1**
गुजरात	2	2	119	0	-	119	2	2	214	0	-	214
महाराष्ट्र	2	1	54	1	357	-304	2	1	5	1	220	-215
अखिल भारत	**43**	**30**	**3,550**	**13**	**1,867**	**1,682**	**43**	**34**	**4,116**	**9**	**897**	**3,219**

परिशिष्ट सारणी IV.14: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य वित्तीय संकेतक: राज्य-वार *(समाप्त)*

क्षेत्र/ राज्य	सकल एनपीए (%)		सीआरएआर (%)	
	मार्च- 2021	मार्च- 2022	मार्च- 2021	मार्च- 2022
1	14	15	16	17
मध्य क्षेत्र	**10.4**	**9.6**	**9.9**	**11.8**
छत्तीसगढ़	3.1	2.6	20.4	19.3
मध्य प्रदेश	19.7	13.0	-0.1	9.2
उत्तर प्रदेश	8.8	9.5	11.4	11.9
उत्तराखंड	7.9	7.2	6.2	11.0
पूर्वी क्षेत्र	**23.1**	**25.1**	**0.6**	**7.8**
बिहार	29.3	38.4	1.9	7.8
झारखंड	9.2	6.4	10.9	11.7
ओडिशा	26.5	22.1	-10.8	4.8
पश्चिम बंगाल	14.7	12.2	1.7	8.4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**19.0**	**15.6**	**13.1**	**15.7**
अरुणाचल प्रदेश	5.6	3.9	10.6	12.2
असम	33.5	27.7	1.8	7.6
मणिपुर	28.7	17.5	2.4	7.2
मेघालय	11.0	7.6	13.9	12.7
मिजोरम	6.1	5.3	9.5	11.5
नगालैंड	4.1	1.9	-2.9	8.2
त्रिपुरा	8.3	6.8	26.8	29.2
उत्तरी क्षेत्र	**5.6**	**4.7**	**11.4**	**12.1**
हरियाणा	9.3	7.2	13.6	14.1
हिमाचल प्रदेश	5.4	5.7	10.1	9.5
जम्मू और कश्मीर	8.9	6.8	-1.7	-2.1
पंजाब	7.5	6.6	15.5	15.6
राजस्थान	3.1	2.8	10.8	11.9
दक्षिणी क्षेत्र	**5.2**	**5.2**	**13.4**	**15.4**
आंध्र प्रदेश	1.5	1.3	15.4	17.8
कर्नाटक	14.0	14.5	11.2	11.1
केरल	3.6	3.1	6.6	11.4
पुदुचेरी	2.0	2.1	12.0	10.6
तमिलनाडु	2.2	1.9	12.2	13.0
तेलंगाना	1.4	1.9	17.2	20.6
पश्चिमी क्षेत्र	**7.3**	**5.8**	**5.9**	**9.6**
गुजरात	3.5	2.9	10.8	13.1
महाराष्ट्र	11.4	8.7	0.6	6.2
अखिल भारत	**9.4**	**9.1**	**10.2**	**12.7**

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ सटीक कुल से भिन्न हो सकता है।
स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.15: आरआरबी- पीएसएल लक्ष्य और उपलब्धि- 2021-22

क्षेत्र/ उप क्षेत्र	लक्ष्य (%)	उपलब्धि (%)	लक्ष्य/ उप-लक्ष्य को पूरा न कर पाने वाले आरआरबी
समग्र प्राथमिकता क्षेत्र	75	90.1	मेघालय ग्रामीण बैंक (71.5%) नगालैंड ग्रामीण बैंक (69.3%)
कृषि	18	46.4	-
लघु और सीमांत किसान	9	26.8	-
गैर- कॉर्पोरेट किसान	12.73	89.6	-
सूक्ष्म उद्यम	7.5	12.0	-
कमजोर वर्ग	15	78.9	-

टिप्पणी: लक्ष्य और उपलब्धि पिछले वर्ष की इसी दिनांक के अनुसार एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी IV.16: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	1,564	672	1,525	1,162	1,734	1,055	1,750	721	1,976	1,388	2,190	1,263	2,382	2,740
कार्ड/ इंटरनेट	26	3	144	6	491	11	679	15	1,036	37	1,215	35	763	21
जमाराशियां	374	28	325	28	384	49	458	79	599	66	666	195	790	583
तुलनपत्रेतर	6	33	7	25	4	4	6	8	9	22	10	370	10	212
विदेशी मुद्रा लेनदेन	16	14	10	30	28	7	25	30	15	14	16	28	19	148
नकदी	75	4	89	16	87	7	99	5	141	36	143	14	154	21
चेक/ मांग पत्र आदि	108	15	110	9	141	10	192	17	234	15	202	17	184	27
अंतर-शाखा खाते	31	6	36	7	18	1	22	3	16	5	18	2	10	1
समाशोधन आदि खाते	20	2	23	4	35	12	30	9	52	45	51	7	34	11
अनिवासी खाते	11	2	9	0	17	1	9	4	26	2	13	2	9	2
अन्य	204	16	148	29	88	51	97	26	146	39	146	64	179	56
कुल योग	**2,435**	**795**	**2,426**	**1,316**	**3,027**	**1,208**	**3,367**	**917**	**4,250**	**1,669**	**4,670**	**1,997**	**4,534**	**3,822**

परिशिष्ट सारणी IV.16: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	1,953	3,552	2,087	6,530	1,985	8,334	2,256	17,123	2,120	17,367	2,320	20,556
कार्ड/ इंटरनेट	629	23	793	49	978	54	845	52	1,191	40	1,372	42
जमाराशियां	857	219	791	291	774	331	875	437	759	809	693	903
तुलनपत्रेतर	5	373	18	1,527	15	1,088	10	699	4	132	5	63
विदेशी मुद्रा लेनदेन	22	130	10	98	9	144	16	899	17	51	16	2,201
नकदी	173	20	140	23	145	24	153	43	160	22	239	37
चेक/ मांग पत्र आदि	172	40	141	22	180	19	254	26	234	25	235	40
अंतर-शाखा खाते	24	8	6	3	7	1	4	0	4	10	1	0
समाशोधन आदि खाते	38	31	36	7	36	24	29	7	17	87	27	6
अनिवासी खाते	11	3	17	3	38	10	23	8	8	9	10	3
अन्य	207	98	197	112	135	64	179	162	176	146	153	77
कुल योग	**4,091**	**4,497**	**4,236**	**8,665**	**4,302**	**10,093**	**4,644**	**19,456**	**4,690**	**18,698**	**5,071**	**23,928**

परिशिष्ट सारणी IV.16: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	2,525	22,558	3,602	64,508	4,607	1,81,865	3,496	1,36,429
कार्ड/ इंटरनेट	2,059	110	1,866	71	2,677	129	2,545	119
जमाराशियां	691	457	593	148	530	616	504	434
तुलनपत्रेतर	20	16288	33	5538	34	2445	23	535
विदेशी मुद्रा लेनदेन	9	1426	13	695	8	54	4	129
नकदी	218	40	274	56	371	63	329	39
चेक/ मांग पत्र आदि	207	34	189	34	201	39	163	85
अंतर-शाखा खाते	6	1	3	0	2	0	2	0
समाशोधन आदि खाते	37	6	24	209	22	7	14	4
अनिवासी खाते	6	5	3	0	8	1	1	0
अन्य	138	242	197	244	242	172	277	54
कुल योग	**5,916**	**41,167**	**6,797**	**71,503**	**8,702**	**1,85,391**	**7,358**	**1,37,828**

टिप्पणियां: 1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी का संदर्भ है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई साल पहले के हो सकते हैं।
4. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियां हैं और नुकसान की मात्रा को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। वसूली के आधार पर, उपगत हानियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं कि ऋण खातों में शामिल पूरी राशि का विचलन हो।

स्त्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.1: अनुसूचित यूसीबी के चुनिंदा वित्तीय मानदंड *(जारी)*

(31 मार्च, 2022 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाराशियों की औसत लागत	अग्रिमों पर प्राप्त औसत प्रतिफल	कुल आस्तियों की तुलना में निवल ब्याज आय (स्प्रेड)	कार्यकारी निधियों की तुलना में निवल ब्याज आय	कार्यकारी निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय	आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	सीआरएआर	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अभ्युदय को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.84	8.48	1.73	1.72	0.66	0.02	9.02	6.23	0.00
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.36	8.62	3.23	3.15	1.61	2.48	28.86	10.34	0.21
3	अकोला जनता कमर्शियल को. ऑप,बैंक लिमिटेड, अकोला	4.17	10.06	3.13	3.09	0.91	0.56	22.97	4.87	0.02
4	अकोला अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, अकोला	4.18	10.18	3.68	3.49	0.99	0.58	14.80	4.23	0.02
5	अमानथ को.ऑप.बैंक.लिमिटेड, बेंगलुरु	2.68	1.54	1.78	1.78	3.88	1.30	1.26	1.67	0.02
6	आंध्र प्रदेश महेश को.ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड	6.03	11.42	2.77	2.77	0.78	0.97	28.49	7.08	0.06
7	अपना सहकारी बैंक लिमिटेड	5.05	9.51	2.56	2.79	1.21	0.35	9.43	8.39	0.02
8	बसिन कैथोलिक को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.46	9.47	2.59	2.54	0.52	0.76	17.38	19.85	0.12
9	भारत को.ऑप.बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	5.51	9.73	2.40	2.36	0.84	0.29	13.98	13.10	0.03
10	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	4.51	8.94	2.37	2.41	0.47	0.02	19.72	8.67	0.00
11	बॉम्बे मर्केंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड	3.17	9.75	4.06	3.62	1.64	0.10	17.22	3.58	0.00
12	सिटिजन क्रेडिट को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.07	8.99	2.67	3.05	0.48	0.63	24.76	9.60	0.06
13	कॉसमॉस को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.73	9.13	2.90	3.07	2.71	0.38	13.19	10.85	0.03
14	डोम्बिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	4.38	9.57	2.44	2.59	3.44	0.49	14.99	7.89	0.03
15	गोवा अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.35	9.23	3.00	3.00	0.51	0.72	19.96	5.31	0.03
16	गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	4.49	9.73	3.30	3.25	0.48	1.02	22.31	6.92	0.06
17	ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.96	9.51	2.52	2.43	1.74	0.29	16.33	9.50	0.02
18	इंडियन मर्केंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड, लखनऊ	3.50	5.68	3.41	4.05	0.45	0.44	23.16	1.46	0.01
19	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.59	10.56	3.47	3.50	1.07	0.83	14.37	8.58	0.05
20	जलगांव पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.10	9.98	3.12	3.15	0.70	0.04	13.49	6.78	0.00
21	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.87	10.40	3.08	2.99	0.43	0.05	10.08	8.91	0.00
22	जनलक्ष्मी को.ऑप.बैंक लिमिटेड, नासिक	5.32	18.78	2.95	5.57	5.59	1.32	35.41	1.31	0.03
23	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	5.00	8.90	2.31	2.15	1.48	0.01	15.06	10.82	0.00
24	कल्लाप्पण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.63	10.41	2.94	2.94	0.48	0.44	13.88	7.13	0.02
25	कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.80	8.40	2.80	2.64	0.80	1.46	18.87	16.89	0.18
26	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	4.88	9.85	2.57	2.54	1.20	0.56	11.70	10.53	0.04
27	कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	2.59	5.18	0.61	0.59	0.26	-3.98	-347.90	2.19	-0.16

परिशिष्ट सारणी V.1: अनुसूचित यूसीबी के चुनिंदा वित्तीय मानदंड *(समाप्त)*

(31 मार्च, 2022 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जमाराशियों की औसत लागत	अग्रिमों पर प्राप्त औसत प्रतिफल	कुल आस्तियों की तुलना में निवल ब्याज आय (स्प्रेड)	कार्यकारी निधियों की तुलना में निवल ब्याज आय	कार्यकारी निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय	आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	सीआरएआर	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.37	9.74	2.94	2.89	0.57	0.28	16.91	5.96	0.01
29	खामगांव अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खामगांव	3.81	9.73	3.71	3.88	0.63	0.46	20.75	4.76	0.02
30	महानगर को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.99	9.94	3.30	3.39	0.51	0.56	15.51	7.28	0.03
31	मेहसाना अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.65	10.23	3.66	3.31	0.52	1.42	14.77	21.82	0.19
32	नगर अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	5.39	7.35	1.89	2.57	1.35	-2.88	-8.81	3.08	-0.11
33	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.70	5.45	2.20	2.55	2.26	0.12	12.30	6.62	0.01
34	नासिक मर्चेंट को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.25	10.04	3.95	3.95	2.26	1.30	37.58	3.81	0.04
35	न्यू इंडिया को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.70	9.76	2.05	2.07	0.81	0.08	9.03	13.38	0.01
36	एनकेजीएसबी को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.95	11.24	2.38	2.51	0.77	0.20	13.07	10.84	0.02
37	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	5.88	8.39	1.86	1.66	0.90	0.61	16.68	12.65	0.05
38	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	5.57	10.96	3.37	3.23	1.01	0.42	14.42	5.67	0.02
39	राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड	6.13	10.01	2.68	2.68	0.27	0.46	12.80	9.06	0.03
40	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.04	9.92	3.16	3.04	0.50	1.37	18.41	8.43	0.08
41	रुपी को.ऑप.बैंक लिमिटेड	1.76	1.30	1.03	2.60	0.14	0.08	-749.39	4.11	0.01
42	सांगली अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, सांगली	5.41	8.82	2.16	2.40	0.52	-0.65	11.29	6.14	-0.03
43	सारस्वत को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	4.63	8.52	2.12	2.04	1.03	0.56	13.94	15.28	0.06
44	एसबीपीपी को.ऑप.बैंक.लिमिटेड, किल्ला परदी	4.54	9.82	3.44	3.31	0.32	0.89	20.89	8.40	0.06
45	शामराव विठ्ठल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.85	8.76	2.50	2.93	0.90	0.71	13.32	13.60	0.07
46	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	4.71	11.06	2.36	2.94	0.80	0.04	11.71	4.82	0.00
47	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.22	10.65	2.93	3.41	0.83	0.55	14.70	7.54	0.04
48	सूरत पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.79	8.60	1.90	1.84	0.37	0.75	13.73	24.48	0.12
49	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	4.37	11.08	4.07	4.29	0.90	0.46	13.70	7.52	0.03
50	टीजेएसबी सहकारी बैंक	4.72	9.72	3.23	2.94	0.59	1.12	15.28	12.54	0.10
51	वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	5.54	9.23	1.91	1.93	0.60	0.34	14.84	10.05	0.03
52	जोरास्ट्रियन को.ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	4.58	9.33	2.22	2.38	0.52	0.30	27.65	7.18	0.02

टिप्पणियां: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : ऑफ साइट सर्विलान्स रिटर्न्स, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी V.2: वित्तीय प्रदर्शन के संकेतक : अनुसूचित यूसीबी *(जारी)*

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	ब्याज आय		परिचालन लाभ		कर पश्चात निवल लाभ	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभ्युदय को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.5	5.8	0.3	-0.4	0.0	0.0
2	अहमदाबाद मर्केटाइल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	7.4	7.0	2.3	2.2	1.5	1.3
3	अकोला जनता कमर्शियल को.ऑप,बैंक लिमिटेड, अकोला	6.2	6.4	0.5	1.0	0.3	0.5
4	अकोला अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, अकोला	7.1	6.8	1.4	1.4	0.3	0.5
5	अमानथ को.ऑप.बैंक.लिमिटेड, बेंगलुरु	-0.1	0.4	-0.3	0.1	-0.3	0.1
6	आंध्र प्रदेश महेश को.ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड	8.2	8.2	1.6	1.8	1.0	1.0
7	अपना सहकारी बैंक लिमिटेड	7.2	7.0	0.7	0.7	-1.7	0.3
8	बसिन कैथोलिक को.ऑप.बैंक लिमिटेड	7.4	6.7	1.9	1.6	0.6	0.7
9	भारत को.ऑप.बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	7.3	7.1	0.7	0.9	0.0	0.2
10	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	6.4	6.0	0.9	0.7	0.4	-0.1
11	बॉम्बे मर्केटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड	4.9	4.5	0.4	0.6	0.0	0.1
12	सिटिजन क्रेडिट को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.6	6.5	0.9	1.2	0.3	0.7
13	कॉसमॉस को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.6	6.8	2.3	1.8	0.2	0.1
14	डोम्बिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	6.9	6.6	2.4	3.3	0.8	2.1
15	गोवा अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	7.1	7.1	1.3	1.5	0.8	0.7
16	गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	7.3	6.9	1.2	1.3	0.4	1.0
17	ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप.बैंक लिमिटेड	7.1	6.5	1.6	1.7	0.1	0.3
18	इंडियन मर्केंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड, लखनऊ	6.2	5.3	1.4	0.8	-7.7	0.4
19	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.5	7.2	2.1	2.1	0.5	0.6
20	जलगांव पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.9	6.7	0.9	1.1	0.0	0.2
21	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	7.2	6.5	0.8	1.2	0.0	0.0
22	जनलक्ष्मी को.ऑप.बैंक लिमिटेड, नासिक	3.2	5.8	-1.1	1.6	-1.1	1.6
23	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	6.6	6.4	1.3	1.1	-1.2	-0.3
24	कल्लाप्पण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.4	7.1	1.3	1.5	0.4	0.4
25	कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	6.5	5.7	2.2	2.1	1.3	1.3
26	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	7.2	6.9	0.8	0.8	0.5	0.5
27	कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.8	2.2	-3.3	-1.7	-4.5	-4.2
28	कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.8	7.0	1.8	1.2	0.6	0.3
29	खामगांव अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खामगांव	7.1	6.8	2.0	1.6	0.6	0.5
30	महानगर को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	7.7	7.1	1.7	1.4	0.6	0.6
31	मेहसाना अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.9	7.6	2.6	2.7	1.2	1.3
32	नगर अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	5.7	5.0	-0.2	0.5	-6.8	-3.5
33	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	6.6	6.4	0.4	1.1	0.0	-0.4
34	नासिक मर्चेंट को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7.3	7.3	2.3	3.5	0.7	2.7
35	न्यू इंडिया को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.0	5.4	0.3	0.4	-0.2	0.2
36	एनकेजीएसबी को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	7.6	6.7	1.0	0.9	0.3	0.2
37	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	6.2	6.1	0.7	0.5	0.3	0.1
38	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	8.1	7.8	2.0	1.7	0.2	0.4
39	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	2.3	उ.न.	-3.0	उ.न.	-3.0	उ.न.
40	राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड	7.8	7.8	1.2	1.5	0.4	0.4
41	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	6.9	7.0	2.1	2.1	1.2	1.3
42	रुपी को.ऑप.बैंक लिमिटेड	2.2	2.3	1.2	0.4	0.9	0.1
43	सांगली अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, सांगली	7.1	6.5	1.1	0.5	-0.1	-0.6
44	सारस्वत को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	5.7	5.2	1.2	1.0	0.4	0.4
45	एसबीपीपी को.ऑप.बैंक.लिमिटेड, किल्ला परदी	6.6	6.4	1.3	1.4	-0.9	0.8
46	शामराव विठ्ठल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.7	6.3	1.2	1.2	0.8	0.8
47	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	5.5	5.8	-0.6	0.2	-0.8	-0.1
48	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.8	7.2	1.1	1.9	-0.4	0.6
49	सूरत पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	6.9	6.7	0.7	0.9	0.5	0.7
50	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	7.6	8.3	1.5	1.7	0.2	0.6
51	टीजेएसबी सहकारी बैंक	7.0	6.3	1.5	1.4	1.0	0.9
52	वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	7.2	6.7	1.1	0.3	0.3	0.3
53	जोरास्ट्रियन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	6.9	5.7	0.5	0.5	-0.3	0.3

टिप्पणी: 2021-22 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : ऑफ साइट सर्विलान्स रिटर्न्स, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी V.2: वित्तीय प्रदर्शन के संकेतक : अनुसूचित यूसीबी *(समाप्त)*

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	व्ययकृत ब्याज		ब्याजेतर व्यय		प्रावधान और आकस्मिकताएं	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	2	9	10	11	12	13	14
1	अभ्युदय को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.7	4.1	2.5	2.7	0.3	1.0
2	अहमदाबाद मर्केटाइल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.1	3.8	1.5	1.4	0.3	0.4
3	अकोला जनता कमर्शियल को.ऑप,बैंक लिमिटेड, अकोला	4.1	3.4	2.7	2.8	0.2	0.3
4	अकोला अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, अकोला	3.8	3.4	2.4	2.9	1.2	0.9
5	अमानथ को.ऑप.बैंक.लिमिटेड, बेंगलुरु	0.2	0.2	0.6	0.5	0.0	0.0
6	आंध्र प्रदेश महेश को.ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड	5.1	5.3	1.8	1.9	0.4	0.5
7	अपना सहकारी बैंक लिमिटेड	5.1	4.3	2.4	2.5	2.8	0.2
8	बसिन कैथोलिक को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.8	4.2	1.2	1.3	1.0	0.6
9	भारत को.ऑप.बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	5.4	4.8	1.9	2.1	0.6	0.8
10	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	4.3	3.8	1.6	1.9	0.4	0.8
11	बॉम्बे मर्केटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड	2.2	1.9	3.4	3.2	0.4	0.8
12	सिटिजन क्रेडिट को.ऑप.बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.2	3.5	2.1	2.3	0.3	0.2
13	कॉसमॉस को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.8	3.9	1.9	2.0	1.8	1.6
14	डोम्बिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	4.7	4.0	2.2	2.8	1.7	1.0
15	गोवा अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.2	4.1	2.0	1.9	0.1	0.5
16	गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	4.2	3.7	2.3	2.3	0.7	0.1
17	ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.5	4.1	2.2	2.3	1.4	1.2
18	इंडियन मर्केंटाइल को.ऑप बैंक लिमिटेड, लखनऊ	3.4	2.1	2.7	2.8	9.0	0.4
19	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.4	3.9	2.0	2.1	1.2	1.0
20	जलगांव पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.2	3.6	2.4	2.6	0.9	0.9
21	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.6	3.6	2.4	2.2	0.8	1.4
22	जनलक्ष्मी को.ऑप.बैंक लिमिटेड, नासिक	2.1	2.3	2.6	5.4	0.0	0.0
23	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	4.7	4.3	1.5	1.7	2.5	1.4
24	कल्लाप्पणा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.1	4.4	1.5	1.5	0.7	0.8
25	कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	3.8	3.3	1.3	1.1	0.4	0.3
26	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	5.0	4.4	2.1	2.3	0.2	0.2
27	कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	2.5	1.6	3.0	2.5	1.2	2.5
28	कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	5.0	4.3	2.2	2.1	0.9	0.8
29	खामगांव अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खामगांव	3.7	3.0	2.1	2.8	0.8	0.9
30	महानगर को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.5	3.9	2.1	2.3	1.0	0.6
31	मेहसाना अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.9	4.3	1.0	1.1	0.9	0.9
32	नगर अर्बन को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	4.1	3.0	2.5	1.9	6.7	4.1
33	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.4	3.9	2.4	2.3	0.3	1.3
34	नासिक मर्चेंट को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.2	3.6	1.9	2.4	1.1	0.3
35	न्यू इंडिया को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.4	3.6	2.3	2.0	0.5	0.2
36	एनकेजीएसबी को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.5	4.2	2.1	2.3	0.5	0.6
37	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	4.8	4.4	1.7	1.7	0.3	0.2
38	प्रवर सहकारी बैंक लिमिटेड	5.3	4.6	2.4	2.5	1.8	1.3
39	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.4	उ.न.	1.2	उ.न.	0.0	उ.न.
40	राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड	5.6	5.2	1.5	1.4	0.8	1.0
41	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.6	4.1	1.3	1.4	0.5	0.4
42	रुपी को.ऑप.बैंक लिमिटेड	1.1	1.0	1.0	0.9	0.3	0.3
43	सांगली अर्बन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, सांगली	5.0	4.3	2.1	2.2	1.1	1.1
44	सारस्वत को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	4.1	3.4	1.5	1.6	0.5	0.5
45	एसबीपीपी को.ऑप.बैंक.लिमिटेड, किल्ला परदी	3.4	3.3	2.3	1.9	1.9	0.3
46	शामराव विठ्ठल को.ऑप.बैंक लिमिटेड	4.4	3.8	1.9	2.0	0.2	0.3
47	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	4.2	3.4	2.6	2.6	0.3	0.4
48	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.3	4.2	1.8	1.8	1.3	1.1
49	सूरत पीपल्स को.ऑप.बैंक लिमिटेड	5.7	4.9	1.9	1.3	0.2	0.2
50	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	4.4	4.2	2.6	3.3	1.1	0.9
51	टीजेएसबी सहकारी बैंक	4.3	3.6	1.8	1.8	0.1	0.2
52	वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	4.9	4.8	1.6	2.2	0.7	0.0
53	जोरास्ट्रियन को.ऑप.बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	4.7	3.5	2.1	2.1	0.6	0.3

टिप्पणी: 2021-22 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : ऑफ साइट सर्विलान्स रिटर्न्स, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी V.3: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के संकेतक

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	क्षेत्र/ राज्य	लाभ/हानि की राशि		ऋण और बकाया के प्रतिशत के रूप में एनपीए		मांग की तुलना में वसूली (%)	
		2019-20	2020-21	31-मार्च-20	31-मार्च-21	30-जून-19	30-जून-20
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र	**22,210**	**1,275**	**2.1**	**3.3**	**98.8**	**98.3**
1	चंडीगढ़	341	259	6.2	6.8	80.7	74.5
2	दिल्ली	2,072	2,653	1.4	1.3	97.0	97.7
3	हरियाणा	5,150	6,136	0.1	0.1	100.0	100.0
4	हिमाचल प्रदेश	5,049	7,934	8.0	9.0	51.2	38.8
5	जम्मू और कश्मीर	1,489	-24,751	5.1	50.1	79.5	73.4
6	पंजाब	2,269	2,463	1.0	1.0	99.6	99.4
7	राजस्थान	5,840	6,581	0.2	0.2	98.8	98.9
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**5,956**	**6,022**	**8.6**	**8.7**	**46.9**	**69.7**
8	अरुणाचल प्रदेश	-1,550	-2,006	54.2	48.5	1.8	9.1
9	असम	736	1,045	6.8	7.4	25.9	67.8
10	मणिपुर	200	201	29.5	35.3	44.7	45.4
11	मेघालय	1,128	1,204	7.4	7.2	22.1	22.1
12	मिजोरम	1,262	2,032	5.6	4.4	67.8	60.6
13	नगालैंड	1,272	816	13.7	14.6	62.0	58.4
14	सिक्किम	1,132	764	4.2	3.8	38.9	17.3
15	त्रिपुरा	1,775	1,967	3.8	4.8	86.9	95.4
	पूर्वी क्षेत्र	**17,051**	**25,949**	**4.7**	**3.7**	**93.2**	**88.9**
16	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	367	720	48.1	39.7	38.4	43.0
17	बिहार	4,885	7,677	4.9	1.9	77.7	54.9
18	झारखंड	264	518	51.6	38.9	64.3	76.2
19	ओडिशा	8,181	6,850	1.4	1.3	98.3	98.4
20	पश्चिम बंगाल	3,354	10,184	4.2	4.1	91.6	91.3
	मध्य क्षेत्र	**19,918**	**15,742**	**5.6**	**5.2**	**91.3**	**90.7**
21	छत्तीसगढ़	2,576	2,712	3.0	2.9	93.9	83.5
22	मध्य प्रदेश	12,789	7,387	5.4	5.2	92.9	92.1
23	उत्तर प्रदेश	4,328	4,547	5.9	5.4	83.3	85.3
24	उत्तराखंड	225	1,095	9.3	7.6	97.2	96.9
	पश्चिमी क्षेत्र	**40,115**	**44,228**	**8.6**	**9.6**	**82.8**	**84.5**
25	दमन और दीव	-	1,222	-	5.9	-	84.9
26	गोवा	4,442	1,124	10.4	11.2	85.9	82.9
27	गुजरात	3,173	5,441	1.3	1.5	94.8	96.8
28	महाराष्ट्र	32,500	36,441	10.8	11.6	79.3	82.1
	दक्षिणी क्षेत्र	**67,152**	**46,962**	**8.6**	**7.9**	**98.5**	**90.9**
29	आंध्र प्रदेश	9,991	14,768	1.2	0.9	99.7	99.7
30	कर्नाटक	5,100	6,000	3.7	4.5	97.2	95.1
31	केरल	37,475	6,199	15.3	14.5	98.4	85.6
32	पुदुचेरी	2,343	567	16.3	17.1	87.1	85.7
33	तमिलनाडु	9,017	14,795	2.7	4.1	99.6	99.4
34	तेलंगाना	3,226	4,634	0.2	0.1	98.6	98.0
	अखिल भारतीय	**1,72,401**	**1,40,178**	**6.7**	**6.7**	**94.4**	**90.5**

टिप्पणियां: 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
2. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली के आंकड़े 30 जून की स्थिति में हैं।
3. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल में 14 डीसीसीबी में से 13 (मल्लपुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल राज्य सहकारी बैंक में समामेलन हुआ।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 तक, दमन और दीव के राज्य सहकारी बैंकों का डेटा गोवा के राज्य सहकारी बैंकों के एक भाग के रूप में रिपोर्ट किया जाता था। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार गोवा और दमन और दीव के सहकारी बैंकों की लेखा परीक्षा अलग-अलग करवायी जाती थी।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.4: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाले प्रमुख संकेतक:

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	क्षेत्र/ राज्य	2019-20					2020-21					2020		2021	
		डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		ऋण अनुपात की तुलना में एनपीए (%)	मांग की तुलना में वसूली (%) (जून के अंत में)*	ऋण अनुपात की तुलना में एनपीए (%)	मांग की तुलना में वसूली (%) (जून के अंत में)*
			डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि		डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**73**	**58**	**15,599**	**15**	**16,950**	**73**	**64**	**16,238**	**9**	**11,195**	**10.8**	**75.1**	**11.3**	**74.7**
1	हरियाणा	19	17	5,289	2	867	19	19	6,053	0	-	6.3	65.2	7.1	68.2
2	हिमाचल प्रदेश	2	1	712	1	4,033	2	2	1,140	0	-	25.2	74.2	27.8	61.3
3	जम्मू और कश्मीर	3	0	-	3	4,276	3	0	-	3	4,145	37.2	39.2	38.4	30.9
4	पंजाब	20	12	2,185	8	7,563	20	15	2,843	5	5,243	10.3	76.7	11.1	75.8
5	राजस्थान	29	28	7,412	1	211	29	28	6,201	1	1,807	8.9	83.5	8.4	85.1
	पूर्वी क्षेत्र	**58**	**51**	**24,682**	**7**	**5,711**	**58**	**53**	**20,612**	**5**	**2,909**	**9.3**	**67.3**	**8.9**	**77.5**
6	बिहार	23	16	1,415	7	5,711	23	20	1,651	3	2,013	17.7	29.7	9.2	27.9
7	झारखंड	1	1	219	0	-	1	1	212	0	-	63.4	17.2	17.4	28.6
8	ओडिशा	17	17	14,791	0	-	17	17	9,988	0	-	7.3	67.1	7.8	82.3
9	पश्चिम बंगाल	17	17	8,258	0	-	17	15	8,761	2	896	9.8	76.9	10.4	75.8
	मध्य क्षेत्र	**104**	**73**	**25,754**	**31**	**29,547**	**104**	**76**	**30,108**	**28**	**48,300**	**21.2**	**55.4**	**19.7**	**61.8**
10	छत्तीसगढ़	6	6	6,465	0	-	6	6	6,277	0	-	14.5	70.2	13.6	82.0
11	मध्य प्रदेश	38	25	6,699	13	19,686	38	24	9,799	14	41,130	26.7	47.7	25.8	53.6
12	उत्तर प्रदेश	50	32	8,289	18	9,861	50	36	9,325	14	7,169	13.9	62.6	12.8	67.5
13	उत्तराखंड	10	10	4,301	0	-	10	10	4,707	0	-	12.1	75.0	9.3	67.9
	पश्चिमी क्षेत्र	**49**	**45**	**75,883**	**4**	**47,935**	**49**	**48**	**83,914**	**1**	**4,480**	**16.2**	**61.9**	**13.4**	**71.6**
14	गुजरात	18	18	18,093	0	-	18	18	20,869	0	-	5.4	90.5	4.6	92.4
15	महाराष्ट्र	31	27	57,790	4	47,935	31	30	63,044	1	4,480	20.1	49.7	16.4	62.6
	दक्षिणी क्षेत्र	**67**	**64**	**46,738**	**3**	**3,922**	**67**	**67**	**58,196**	**0**	**-**	**6.9**	**87.7**	**6.8**	**87.7**
16	आंध्र प्रदेश	13	12	4,773	1	1,411	13	13	9,938	0	-	5.8	90.8	5.2	85.8
17	कर्नाटक	21	20	14,152	1	1,788	21	21	16,303	0	-	6.1	88.1	5.3	90.6
18	केरल	1	1	315	0	-	1	1	326	0	-	15.5	77.8	13.7	64.3
19	तमिलनाडु	23	23	24,641	0	-	23	23	26,688	0	-	7.1	85.6	8.9	89.3
20	तेलंगाना	9	8	2,857	1	723	9	9	4,940	0	-	7.5	87.0	6.1	81.8
	अखिल भारतीय	**351**	**291**	**1,88,656**	**60**	**1,04,066**	**351**	**308**	**2,09,067**	**43**	**66,884**	**12.6**	**70.2**	**11.4**	**74.9**

टिप्पणियां: 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

2. वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली संबंधी आंकड़े 30 जून की स्थिति में हैं।

3. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल में 14 डीसीसीबी में से 13 (मल्लपुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल राज्य सहकारी बैंक में समामेलन हुआ और बिहार में सुपौल डीसीसीबी बना।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.5: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	3,47,788	3,56,277	10.7	2.4
2. स्वाधिकृत निधियां (ए+बी)	43,741	42,311	3.7	-3.3
ए. चुकता पूंजी	2,2,994	19,115	0.8	-16.9
जिसमें से, सरकार का अंशदान	649	900	-50.9	38.7
बी. कुल आरक्षित निधियां	20,747	23,196	7.1	11.8
3. जमाराशियां	1,65,476	1,70,922	24.4	3.3
4. उधारियां	1,38,571	1,43,044	-0.3	3.2
5. कार्यशील पूंजी	3,25,322	3,34,718	9.7	2.9
आस्तियां				
1. कुल बकाया ऋण (ए+बी)	2,12,360	2,16,862	84.6	2.1
ए) अल्पावधि	1,86,249	1,90,111	98.3	2.1
बी) मध्यावधि	26,111	26,751	23.6	2.5

टिप्पणी: वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का ₹ करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार (*जारी*)

(31 मार्च 2021 में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	पैक्स की संख्या	जमाराशियां	कार्यशील पूंजी	बकाया ऋण तथा अग्रिम		लाभ वाली समितियां	
					कृषि	कृषितर	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	**14,112**	**16,74,999**	**48,55,498**	**14,30,282**	**67,077**	**9,613**	**3,07,165**
1	चंडीगढ़	17	-	5	0	-	13	0
2	हरियाणा	730	49,956	13,41,057	5,95,645	25,747	49	1,06,743
3	हिमाचल प्रदेश	2,178	5,99,288	7,57,818	1,16,989	18,610	1,903	6,625
4	जम्मू और कश्मीर*	620	323	3,772	4,659	670	484	58
5	पंजाब	3,998	7,72,226	13,28,203	7,12,988	22,050	2,062	22,908
6	राजस्थान*	6,569	2,53,206	14,24,642	उ.न.	उ.न.	5,102	1,70,832
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**9,440**	**1,04,856**	**1,59,398**	**36,682**	**32,016**	**781**	**8,739**
7	अरुणाचल प्रदेश	35	43	4,772	-	-	18	16
8	असम*	766	-	11,123	575	20	309	7,639
9	मणिपुर*	261	162	682	48	31	131	26
10	मेघालय	179	1,569	5,297	3,453	60	65	91
11	मिजोरम	154	2,075	485	705	210	30	396
12	नगालैंड	7,601	97,313	1,17,058	30,245	31,586	उ.न.	उ.न.
13	सिक्किम	176	452	2,451	1,117	105	114	52
14	त्रिपुरा	268	3,241	17,530	539	4	114	519
	पूर्वी क्षेत्र	**18,627**	**3,80,959**	**16,25,883**	**7,45,225**	**43,121**	**4,342**	**8,504**
15	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	58	114	1,251	1,625	568	19	17
16	बिहार*	8,463	17,533	50,816	-	-	1,180	604
17	झारखंड*	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
18	ओडिशा	2,701	1,52,712	10,70,176	5,94,324	13,039	751	4,418
19	पश्चिम बंगाल	7,405	2,10,601	5,03,639	1,49,275	29,514	2,392	3,465
	मध्य क्षेत्र	**15,708**	**2,67,520**	**16,63,203**	**7,88,169**	**60,220**	**8,077**	**24,326**
20	छत्तीसगढ़*	1,617	63,145	5,49,825	2,06,713	10,435	842	9,041
21	मध्य प्रदेश*	4,457	81,731	6,45,546	3,39,959	11,892	2,153	13,124
22	उत्तराखंड	705	1,15,824	3,41,905	1,61,466	37,893	546	387
23	उत्तर प्रदेश*	8,929	6,820	1,25,927	80,031	-	4,536	1,774
	पश्चिमी क्षेत्र	**29,273**	**1,32,901**	**36,91,512**	**22,70,689**	**3,10,959**	**15,247**	**17,568**
24	गोवा	74	9,478	16,282	2,585	2,876	42	108
25	गुजरात	9,048	1,00,366	15,91,662	12,60,378	38,022	6,466	16,854
26	महाराष्ट्र*	20,151	23,057	20,83,568	10,07,727	2,70,061	8,739	607
	दक्षिणी क्षेत्र	**15,399**	**1,45,30,981**	**2,14,76,348**	**39,83,152**	**17,42,973**	**9,237**	**1,63,468**
27	आंध्र प्रदेश	2,101	3,34,612	19,25,470	12,14,591	1,66,867	1,346	13,718
28	तेलंगाना	852	39,996	5,13,014	4,90,713	50,687	537	6,167
29	कर्नाटक	6,248	15,33,365	36,25,724	20,76,140	4,15,348	4,140	44,067
30	केरल*	1,643	1,15,90,200	1,30,12,397	उ.न.	उ.न.	964	78,897
31	पुदुचेरी	53	19,900	28,494	40	20,308	15	209
32	तमिलनाडु	4,502	10,12,907	23,71,250	2,01,667	10,89,764	2,235	20,409
	अखिल भारतीय	**1,02,559**	**1,70,92,217**	**3,34,71,841**	**92,54,198**	**22,56,366**	**47,297**	**5,29,769**

ला.न: लागू नहीं। एन.ए.: उपलब्ध नहीं।

टिप्पणियां: 1. *: डेटा पिछले वर्ष से संबंधित है।

2. पूर्णांकन के कारण सटीक कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(समाप्त)*

(31 मार्च 2021 में)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	हानिग्रस्त समितियां		अर्थक्षम	संभावित रूप से अर्थक्षम	निष्क्रिय	अप्रचलित	अन्य
		संख्या	राशि					
1	2	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**3,917**	**88,650**	**5,135**	**1,731**	**295**	**234**	**6,717**
1	चंडीगढ़	4	0	13	0	0	4	0
2	हरियाणा	681	29,155	612	91	26	1	0
3	हिमाचल प्रदेश	197	692	547	1,481	107	9	34
4	जम्मू और कश्मीर*	105	2	458	48	12	91	11
5	पंजाब	1,513	6,619	3,505	111	150	129	103
6	राजस्थान*	1,417	52,182	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	6,569
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**816**	**11,887**	**8,995**	**239**	**59**	**57**	**90**
7	अरुणाचल प्रदेश	14	6	30	0	0	5	0
8	असम*	419	9,909	709	57	0	0	0
9	मणिपुर*	99	40	122	71	23	45	0
10	मेघालय	114	771	70	73	36	0	0
11	मिजोरम	2	1	32	32	0	0	90
12	नगालैंड	उ.न.	उ.न.	7,601	0	0	0	0
13	सिक्किम	14	3	169	0	0	7	0
14	त्रिपुरा	154	1,157	262	6	0	0	0
	पूर्वी क्षेत्र	**9,844**	**27,991**	**14,172**	**2,866**	**586**	**413**	**590**
15	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	120	41	12	3	2	0
16	बिहार*	3,962	94	8,463	0	0	0	0
17	झारखंड*	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
18	ओडिशा	1,854	26,305	1,717	608	10	1	365
19	पश्चिम बंगाल	4,001	1,472	3,951	2,246	573	410	225
	मध्य क्षेत्र	**4,747**	**25,749**	**12,544**	**2,471**	**392**	**168**	**133**
20	छत्तीसगढ़*	491	7,610	1,178	439	0	0	0
21	मध्य प्रदेश*	2,129	17,824	3,663	720	4	0	70
22	उत्तराखंड	159	162	588	43	6	5	63
23	उत्तर प्रदेश*	1,968	153	7,115	1,269	382	163	0
	पश्चिमी क्षेत्र	**13,338**	**17,882**	**20,856**	**7,505**	**651**	**176**	**85**
24	गोवा	20	7	67	3	3	1	0
25	गुजरात	1,649	17,132	5,370	2,838	594	161	85
26	महाराष्ट्र*	11,669	743	15,419	4,664	54	14	0
	दक्षिणी क्षेत्र	**4,757**	**2,59,825**	**10,846**	**3,185**	**358**	**62**	**948**
27	आंध्र प्रदेश	617	9,197	1,667	255	46	12	121
28	तेलंगाना	278	18,749	703	136	1	0	12
29	कर्नाटक	1,274	11,214	4,303	1,570	106	50	219
30	केरल*	632	1,86,138	1,643	0	0	0	0
31	पुदुचेरी	38	2,968	15	38	0	0	0
32	तमिलनाडु	1,918	31,560	2,515	1,186	205	0	596
	अखिल भारतीय	**37,419**	**4,31,984**	**72,548**	**17,997**	**2,341**	**1,110**	**8,563**

ला.न: लागू नहीं। उ.न. : उपलब्ध नहीं।

टिप्पणियां: 1. *: डेटा पिछले वर्ष से संबंधित है।

2. पूर्णांकन के कारण सटीक कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.7: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों और उधारकर्ताओं का विवरण

(संख्या हजार में)

अखिल भारत	सदस्य		उधारकर्ता	
	2020	**2021**	**2020**	**2021**
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति	15,886	14,183	4,044	4,390
अनुसूचित जनजाति	9,087	8,482	2,572	2,666
लघु कृषक	35,959	35,507	12,449	12,559
ग्रामीण कारीगर	2,996	3,231	762	820
अन्य और सीमांत किसान	74,230	75,767	32,728	33,217

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.8: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2020	2021P	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	939	949	-0.1	1.2
	(3.5)	(3.5)		
2. आरक्षित निधियां	4,928	5,193	38.8	5.4
	(18.2)	(19)		
3. जमाराशियां	2,409	2,546	-1.0	5.7
	(8.9)	(9.3)		
4. उधारियां	13,740	13,293	-9.0	-3.3
	(50.7)	(48.7)		
5. अन्य देयताएं	5,090	5,293	-14.8	4.0
	(18.8)	(19.4)		
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	174	234	-32.2	34.4
	(0.6)	(0.9)		
2. निवेश	2,498	2,272	-24.4	-9.0
	(9.2)	(8.3)		
3. ऋण तथा अग्रिम	20,704	20,918	0.3	1.0
	(76.4)	(76.7)		
4.संचित हानि	611	518	7.5	-15.2
	(2.3)	(1.9)		
5. अन्य आस्तियां	3,119	3,332	-3.1	6.8
	(11.5)	(12.2)		
कुल देयताएं/ आस्तियां	**27,106**	**27,275**	**-3.2**	**0.6**
	(100.0)	**(100.0)**		

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियां का अनुपात (प्रतिशत में) हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. पी- अनंतिम

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.9: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मद	की अवधि में		प्रतिशत में घट-बढ़	
		2019-20	**2020-21P**	**2019-20**	**2020-21**
1	2	3	4	5	6
ए	**आय (i+ii)**	**2,584**	**2,343**	**2.9**	**-9.3**
		(100.00)	**(100.00)**		
	i ब्याज आय	2,376	2,156	-2.1	-9.3
		(92)	(92)		
	ii अन्य आय	208	187	149.2	-10.1
		(8)	(8)		
बी	**व्यय (i+ii+iii+iv)**	**2,333**	**2,180**	**-8.8**	**-6.6**
	i व्ययकृत ब्याज	1,297	1,175	-5.7	-9.4
		(55.6)	(53.9)		
	ii प्रावधान और आकस्मिकताएं	453	465	14.7	2.7
		(19.4)	(21.3)		
	iii परिचालन व्यय	399	404	-12.1	1.3
		(17.1)	(18.5)		
	जिसमें से : वेतन बिल	349	351	-7.4	0.4
		(15)	(16.1)		
	iv अन्य व्यय	185	136	-44.8	-26.3
		(7.9)	(6.2)		
सी	**लाभ**				
	i परिचालन लाभ	703	627	103.7	-10.8
	ii निवल लाभ/ हानि	250	163		

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल आय/ व्यय का अनुपात (प्रतिशत में) हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. पी- अनंतिम।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.10: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2020	2021P	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**6,836**	**6,942**	**24.8**	**1.5**
i) अवमानक	2,518	2,337	18.9	-7.2
	(36.8)	(33.7)		
ii) संदिग्ध	4,285	4,570	28.9	6.6
	(62.7)	(65.8)		
iii) हानि	34	35	-0.8	4.5
	(0.5)	(0.5)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**33.0**	**33.2**		
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	**43.0**	**46.5**		

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल एनपीए का अनुपात (प्रतिशत में) हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.11: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य वित्तीय संकेतक

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	क्षेत्र / राज्य	शाखाएं	लाभ/ हानि		ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)		वसूली अनुपात (%) (जून के अंत तक)	
		2021	2020	2021P	2020	2021P	2020	2021P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र							
1	हरियाणा @	19	6,392	2,381	81.0	76.1	16.7	12.5
2	हिमाचल प्रदेश #	51	-1,210	109	33.0	39.0	33.3	39.7
3	जम्मू और कश्मीर*	51	-2,237	-1,462	32.1	41.5	33.3	30.6
4	पंजाब @	89	227	247	27.7	32.3	41.6	32.9
5	राजस्थान @	2	2,971	1,679	51.1	52.9	28.8	20.8
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र							
6	असम*	-	-	-	-	-	-	-
7	त्रिपुरा*	5	-3	-63	98.2	99.4	40.5	उ.न.
	पूर्वी क्षेत्र							
8	बिहार*	-	-	-	-	-	-	-
9	ओडिशा@	-	-	-	-	-	-	-
10	पश्चिम बंगाल #	11	358	1,060	24.0	23.5	22.0	32.9
	मध्य क्षेत्र							
11	छत्तीसगढ़@	-	-	-	-	-	-	-
12	मध्य प्रदेश@	-	-	-	-	-	-	-
13	उत्तर प्रदेश*	323	9,770	2,323	72.1	83.7	27.1	25.5
	पश्चिमी क्षेत्र							
14	गुजरात*	176	2,525	1,150	56.3	61.4	34.6	32.0
15	महाराष्ट्र@	-	-	-	-	-	-	-
	दक्षिणी क्षेत्र							
16	कर्नाटक@	25	76	2,411	31.4	27.1	38.1	44.0
17	केरल @	16	2,868	2,646	5.8	6.1	88.0	100.0
18	पुदुचेरी*	1	-146	-171	7.6	13.2	92.8	89.7
19	तमिलनाडु@	25	3,440	3,948	12.1	11.9	86.2	87.7
	अखिल भारतीय	**794**	**25,032**	**16,258**	**33.0**	**33.2**	**43.0**	**46.5**

@: संघीय संरचना, #: मिश्रित संरचना, *: एकल संरचना, -: लागू नहीं।

टिप्पणियां: 1. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ सटीक कुल से भिन्न हो सकता है।

2. छत्तीसगढ़ में 2014-15 के दौरान अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के साथ विलय कर दिया गया। उसी प्रकार असम, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एससीएआरडीबी अब कार्यात्मक नहीं है।

3. *वित्तीय वर्ष के लिए वसूली के आंकड़े 30 जून की स्थिति में है।

4. 2021 के लिए अनंतिम आंकड़े।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.12: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2020	2021P	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,056	1,024	-1.1	-3.1
	(3.4)	(3.2)		
2. आरक्षित निधियां	2,603	3,203	49.5	23.1
	(8.3)	(10.1)		
3. जमाराशियां	1,372	1,551	5.3	13.0
	(4.4)	(4.9)		
4. उधारियां	16,643	16,144	3.4	-3.0
	(53.1)	(51)		
5. अन्य देयताएं	9,663	9,755	-2.3	1.0
	(30.8)	(30.8)		
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	378	503	-14.3	33.1
	(1.2)	(1.6)		
2. निवेश	2,065	2,213	2.3	7.2
	(6.6)	(7)		
3. ऋण तथा अग्रिम	15,810	15,325	1.4	-3.1
	(50.5)	(48.4)		
4. संचित हानि	5,479	5,854	13.1	6.8
	(17.5)	(18.5)		
5. अन्य आस्तियां	7,605	7,783	5.5	2.3
	(24.3)	(24.6)		
कुल देयताएं/ आस्तियां	**31,337**	**31,677**	**4.1**	**1.1**
	(100.0)	**(100.0)**		

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियां का अनुपात (प्रतिशत में) हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2021 के लिए डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.13: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	की अवधि में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2019-20	2020-21P	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**2,651**	**3,114**	**5.1**	**17.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	2,008	1,999	2.9	-0.5
	(75.8)	(64.2)		
ii. अन्य आय	643	1,115	12.7	73.4
	(24.2)	(35.8)		
बी. व्यय (i+ii+iii)	**3,230**	**3,587**	**8.9**	**11.1**
i. व्ययकृत ब्याज	1,733	1,791	0.5	3.4
	(53.6)	(49.9)		
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	1,013	1,061	31.3	4.8
	(31.4)	(29.6)		
iii. परिचालन व्यय	484	734	3.3	51.7
	(15.0)	(20.5)		
जिनमें : वेतन बिल	274	304	-13.9	11.0
	(8.5)	(8.5)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	435	589	31.8	35.4
ii. निवल लाभ	-578	-473		

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल आय/ व्यय के अनुपात (प्रतिशत में) है।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2021 के लिए डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.14 : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2020	2021पी	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**6,773**	**6,818**	**10.6**	**0.7**
i) अवमानक	3,493	3,247	11.3	-7.1
	(51.6)	(47.6)		
ii) संदिग्ध	3,259	3,553	10.9	9.0
	(48.1)	(52.1)		
iii) हानि	21	19	-52.3	-11.1
	(0.3)	(0.3)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**43**	**44**	-	-
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	**47**	**42**	-	-

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल एनपीए के अनुपात हैं।

2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन किया गया है।

3. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

4. 2021 के लिए डेटा अनंतिम है।

5. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली के आंकड़े 30 जून की स्थिति में हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.15: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य वित्तीय संकेतक

(राशि ₹ लाख में)

राज्य	2019-20				2020-21P				ऋण की तुलना में एनपीए का अनुपात (प्रतिशत में)		वसूली अनुपात (जून के अंत में) (%)	
	लाभ		हानि		लाभ		हानि					
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	2020	2021	2019	2020
1	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी क्षेत्र	**42**	**2,815**	**103**	**27,331**	**26**	**1,122**	**119**	**41,560**	**68**	**72**	**25**	**19**
हरियाणा	4	264	15	9,411	0	0	19	18,598	82	84	22	10
हिमाचल प्रदेश	0	0	1	442	1	16	0	0	51	31	49	53
पंजाब	18	1,131	71	12,750	7	406	82	16,758	73	80	25	20
राजस्थान	20	1,419	16	4,728	18	699	18	6,205	45	45	30	29
मध्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वी क्षेत्र	**8**	**527**	**16**	**2,089**	**10**	**1,226**	**14**	**4,278**	**34**	**35**	**36**	**39**
ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	8	527	16	2,089	10	1,226	14	4,278	34	35	36	39
पश्चिमी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दक्षिणी क्षेत्र	**177**	**4,471**	**256**	**36,239**	**275**	**16,903**	**159**	**20,694**	**32**	**34**	**73**	**64**
कर्नाटक	41	1,709	137	10,444	127	9,703	51	1,715	25	21	72	70
केरल	18	554	57	25,030	23	4,759	53	18,359	36	40	64	56
तमिलनाडु	118	2,208	62	765	125	2,441	55	620	10	9	93	81
अखिल भारतीय	**227**	**7,813**	**375**	**65,659**	**311**	**19,251**	**292**	**66,532**	**43**	**44**	**47**	**42**

टिप्पणियां: 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

2. छत्तीसगढ़ में 2014-15 के दौरान अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के साथ विलय कर दिया गया। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा की संरचनाएं अब क्रियाशील नहीं हैं।

3. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली के आंकड़े 30 जून की स्थिति में है।

4. 2020-21 के लिए डेटा अनंतिम है।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी VI.1: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में	मार्च 2020 के अंत में	मार्च 2021 के अंत में	मार्च 2022 के अंत में	सितंबर 2022 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़ 2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1. शेयर पूंजी	94,807	103,244	125,801	126,474	131,241	127,088	3.8
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	390,222	445,614	505,865	671,153	770,209	713,257	14.8
3. जनता की जमाराशियां	30,129	40,057	50,022	62,262	70,754	71,640	13.6
4. कुल उधारियां (ए + बी)	1,684,663	2,002,808	2,235,336	2,351,679	2,551,092	2,584,696	8.5
ए. जमानती उधार	919,538	1,106,917	1,305,214	1,330,129	1,473,253	1,487,012	10.8
ए.1 डिबेंचर	490,070	521,003	513,108	554,477	574,102	579,789	3.5
ए.2 बैंकों से लिया गया उधार	353,415	489,732	572,253	617,897	728,266	737,356	17.9
ए.3 एफआई से लिया गया उधार	22,885	29,027	57,610	46,279	57,305	62,821	23.8
ए.4 उपचित ब्याज	20,692	16,958	17,732	19,264	20,052	14,607	4.1
ए.5 अन्य	32,476	50,196	144,510	92,213	93,528	92,438	1.4
बी. गैर-जमानती उधार	765,125	895,891	930,122	1,021,549	1,077,838	1,097,684	5.5
बी.1 डिबेंचर	336,171	340,905	393,392	428,099	432,394	430,015	1.0
बी.2 बैंकों से लिया गया उधार	59,746	119,964	122,657	157,203	176,448	186,376	12.2
बी.3 एफआई से लिया गया उधार	8,318	9,700	5,906	11,076	9,113	8,054	-17.7
बी.4 रिश्तेदारों से लिया गया उधार	2,324	1,994	2,642	4,196	2,824	1,631	-32.7
बी.5 अंतर कंपनी उधार	54,100	72,103	78,279	77,840	86,663	95,573	11.3
बी.6 वाणिज्यिक पत्र	136,072	142,966	66,865	72,597	70,117	72,340	-3.4
बी.7 उपचित ब्याज	21,165	17,598	19,000	19,477	18,207	18,025	-6.5
बी.8 अन्य	147,228	190,661	241,381	251,062	282,070	285,669	12.4
5. चालू देयताएं और प्रावधान	155,439	233,415	252,111	292,768	317,625	321,492	8.5
कुल देयताएं/ कुल आस्तियां	**2,355,260**	**2,825,139**	**3,169,135**	**3,504,335**	**3,840,921**	**3,818,173**	**9.6**
1. ऋण और अग्रिम	1,943,494	2,295,371	2,463,943	2,702,618	2,908,743	2,937,051	7.6
1.1 जमानती	1,500,477	1,649,728	1,858,735	1,964,895	2,242,969	2,254,593	14.2
1.2 गैर जमानती	443,017	645,643	605,208	737,723	665,774	682,458	-9.8
2. निवेश	219,795	259,008	347,875	444,837	513,891	450,462	15.5
2.1 सरकारी प्रतिभूतियां	10,330	17,328	68,777	47,439	65,287	75,538	37.6
2.2 इक्विटी शेयर	110,412	135,395	144,453	263,932	298,740	220,378	13.2
2.3 अधिमानी शेयर	7,479	6,644	6,439	6,073	6,681	5,968	10.0
2.4 डिबेंचर और बॉण्ड	40,865	35,446	34,696	26,747	33,757	31,363	26.2
2.5 म्यूचुअल फ़ंड यूनिट	31,608	44,421	65,106	66,936	66,710	68,218	-0.3
2.6 वाणिज्यिक पत्र	2,135	1,390	1,275	1,450	1,714	929	18.2
2.7 अन्य निवेश	16,965	18,384	27,129	32,261	41,003	48,068	27.1
3. नकदी और बैंक शेष	67,429	96,030	131,459	157,708	180,341	180,066	14.4
3.1 हाथ में नकदी	3,367	6,770	6,260	4,458	7,963	5,094	78.6
3.2 बैंकों में जमाराशियां	64,062	89,260	125,199	153,250	172,378	174,972	12.5
4. अन्य चालू आस्तियां	98,803	124,170	180,281	159,543	165,364	175,179	3.6
5. अन्य आस्तियां	25,739	50,560	45,577	39,629	72,581	75,414	83.2
मेमो आइटम					0		
1. पूंजी बाज़ार का एक्स्पोज़र	161,874	139,965	162,749	191,616	219,054	226,992	14.3
जिनमें से : इक्विटी शेयर	59,876	70,611	89,565	110,125	142,457	139,976	29.4
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	6.9	5.0	5.1	5.5	5.7	5.9	
3. लीवरेज अनुपात	3.9	4.1	4.9	4.5	4.3	4.6	

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।

2. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन एक दशमलव बिंदु में किया गया है।

3. सीआईसी और पीडी को छोड़कर।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.2: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में	मार्च 2020 के अंत में	मार्च 2021 के अंत में	मार्च 2022 के अंत में	सितंबर 2022 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़ 2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1. शेयर पूंजी	91,545	98,041	118,610	118,011	124,241	122,112	5.3
2. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	339,179	383,655	427,288	578,731	665,668	603,592	15.0
3. जनता की जमाराशियाँ	-	-	-	-		-	-
4. कुल उधार ली गई रकम (ए + बी)	1,472,716	1,732,680	1,940,954	2,065,567	2,250,360	2,257,631	8.9
ए. जमानती उधार	752,488	885,800	1,051,652	1,082,638	1,213,224	1,212,569	12.1
ए.1 डिबेंचर	407,105	423,738	413,555	460,918	471,208	475,121	2.2
ए.2 बैंकों से लिया गया उधार	283,386	383,654	448,215	503,397	608,726	602,420	20.9
ए.3 एफआई से लिया गया उधार	19,430	24,051	49,542	33,609	45,946	51,924	36.7
ए.4 उपचित ब्याज	15,499	13,839	14,404	14,782	16,397	12,272	10.9
ए.5 अन्य	27,067	40,518	125,935	69,931	70,946	70,832	1.5
बी. गैर जमानती उधार	720,228	846,880	889,302	982,930	1,037,136	1,045,062	5.5
बी.1 डिबेंचर	335,698	339,013	389,607	422,977	426,300	423,369	0.8
बी.2 बैंकों से लिया गया उधार	58,420	119,813	122,307	156,888	176,363	186,226	12.4
बी.3 एफआई से लिया गया उधार	8,318	9,700	5,906	11,076	9,113	8,054	-17.7
बी.4 रिश्तेदारों से लिया गया उधार	2,223	1,909	2,561	4,127	2,779	1,588	-32.7
बी.5 अंतर कंपनी उधार	48,905	64,713	69,750	69,934	75,564	79,994	8.1
बी.6 वाणिज्यिक पत्र	117,899	124,854	59,386	64,074	62,218	57,560	-2.9
बी.7 उपचित ब्याज	16,969	13,953	15,509	18,523	17,142	16,935	-7.5
बी.8 अन्य	131,796	172,926	224,277	235,332	267,657	271,335	13.7
5. चालू देयताएं और प्रावधान	110,709	188,933	195,461	223,633	248,075	251,078	10.9
कुल देयताएं/ कुल आस्तियां	**2,014,150**	**2,403,310**	**2,682,313**	**2,985,943**	**3,288,344**	**3,234,413**	**10.1**
1. ऋण और अग्रिम	1,634,294	1,916,352	2,046,134	2,278,224	2,447,059	2,451,024	7.4
1.1 जमानती	1,244,815	1,342,155	1,529,828	1,671,935	1,884,879	1,875,417	12.7
1.2 गैर जमानती	389,479	574,197	516,306	606,289	562,180	575,607	-7.3
2. निवेश	207,838	235,117	308,724	398,236	468,413	398,252	17.6
2.1 सरकारी प्रतिभूतियां	5,392	11,790	59,659	29,706	39,613	47,875	33.3
2.2 इक्विटी शेयर	107,302	128,494	134,110	253,551	287,756	207,395	13.5
2.3 अधिमानी शेयर	6,784	6,419	6,174	5,789	6,678	5,964	15.3
2.4 डिबेंचर और बॉण्ड	39,197	34,091	34,199	26,453	33,443	31,047	26.4
2.5 म्यूचुअल फ़ंड यूनिट	31,272	39,615	49,803	55,738	62,187	63,672	11.6
2.6 वाणिज्यिक पत्र	1,641	533	423	939	1,614	901	72.0
2.7 अन्य निवेश	16,250	14,175	24,356	26,061	37,123	41,398	42.4
3. नकदी और बैंक शेष	58,634	86,244	114,184	123,474	148,174	148,793	20.0
3.1 हाथ में नकदी	3,041	6,323	6,120	4,081	7,326	4,427	79.5
3.2 बैंकों में जमाराशियां	55,593	79,920	108,063	119,393	140,848	144,366	18.0
4. अन्य चालू आस्तियां	89,371	116,638	168,481	146,988	152,703	163,808	3.9
5. अन्य आस्तियां	24,013	48,959	44,790	39,021	71,994	72,536	84.5
मेमो आइटम					-		
1. पूंजी बाज़ार का एक्सपोज़र	153,542	130,334	152,724	179,375	203,294	214,899	13.3
जिनमें से : इक्विटी शेयर	59,439	70,095	84,051	104,378	141,899	139,441	35.9
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	7.6	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	
3. लीवरेज अनुपात	3.7	4.0	4.9	4.4	4.3	4.6	

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।

2. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन एक दशमलव बिंदु में किया गया है।

3. सीआईसी और पीडी को छोड़कर।

स्रोत: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.3: एनबीएफसी-डी का समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में	मार्च 2020 के अंत में	मार्च 2021 के अंत में	मार्च 2022 के अंत में	सितंबर 2022 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़ 2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1. शेयर पूंजी	3,262	5,202	7,191	8,463	7,000	4,976	-17.3
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	51,043	61,959	78,577	92,422	104,541	109,665	13.1
3. जनता की जमाराशियां	30,129	40,057	50,022	62,262	70,754	71,640	13.6
4. कुल उधार ली गई रकम (ए + बी)	211,947	270,128	294,382	286,111	300,731	327,065	5.1
ए. जमानती उधार	167,050	221,117	253,562	247,492	260,029	274,443	5.1
ए.1 डिबेंचर	82,964	97,265	99,553	93,559	102,894	104,668	10.0
ए.2 बैंकों से लिया गया उधार	70,029	106,079	124,038	114,499	119,540	134,936	4.4
ए.3 एफआई से लिया गया उधार	3,455	4,976	8,068	12,670	11,359	10,897	-10.3
ए.4 उपचित ब्याज	5,193	3,119	3,328	4,482	3,655	2,335	-18.5
ए.5 अन्य	5,408	9,678	18,576	22,282	22,581	21,606	1.3
बी. गैर जमानती उधार	44,897	49,010	40,820	38,620	40,702	52,622	5.4
बी.1 डिबेंचर	473	1,892	3,785	5,122	6,094	6,646	19.0
बी.2 बैंकों से लिया गया उधार	1,326	151	350	315	85	150	-73.0
बी.3 एफ़आई से लिया गया उधार	-	-	-	-	-	-	-
बी.4 रिश्तेदारों से लिया गया उधार	101	86	82	69	45	43	-34.2
बी.5 अंतर कंपनी उधार	5,195	7,390	8,529	7,906	11,099	15,580	40.4
बी.6 वाणिज्यिक पत्र	18,173	18,112	7,478	8,523	7,899	14,780	-7.3
बी.7 उपचित ब्याज	4,197	3,645	3,491	955	1,066	1,089	11.6
बी.8 अन्य	15,432	17,736	17,104	15,730	14,414	14,334	-8.4
5. चालू देयताएं और प्रावधान	44,729	44,209	56,653	69,135	69,551	70,414	0.6
कुल देयताएं/ कुल आस्तियां	**341,110**	**421,829**	**486,825**	**518,392**	**552,577**	**583,760**	**6.6**
1. ऋण और अग्रिम	309,199	379,019	417,807	424,394	461,684	486,028	8.8
1.1 जमानती	255,662	307,573	328,907	292,960	358,091	379,176	22.2
1.2 गैर जमानती	53,538	71,446	88,899	131,434	103,593	106,851	-21.2
2. निवेश	11,957	23,891	39,151	46,601	45,479	52,210	-2.4
2.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4,938	5,538	9,118	17,733	25,674	27,664	44.8
2.2 इक्विटी शेयर	3,111	6,901	10,343	10,381	10,985	12,984	5.8
2.3 अधिमानी शेयर	695	225	265	284	3	3	-98.9
2.4 डिबेंचर और बॉण्ड	1,668	1,355	496	294	314	316	6.9
2.5 म्यूचुअल फ़ंड यूनिट	336	4,807	15,302	11,198	4,523	4,546	-59.6
2.6 वाणिज्यिक पत्र	494	857	852	511	100	28	-80.4
2.7 अन्य निवेश	714	5,272	2,773	6,200	3,880	6,670	-37.4
3. नकदी और बैंक शेष	8,795	9,786	17,275	34,235	32,167	31,272	-6.0
3.1 हाथ में नकदी	326	447	139	377	636	666	68.6
3.2 बैंकों में जमाराशियाँ	8,469	9,339	17,136	33,857	31,530	30,606	-6.9
4. अन्य चालू आस्तियां	9,432	7,531	9,494	12,555	12,661	11,371	0.8
5. अन्य आस्तियां	1,727	1,601	3,093	608	587	2,878	-3.4
मेमो मदें							
1. पूंजी बाज़ार का एक्स्पोज़र	8,331	9,630	10,025	12,241	15,761	12,092	28.8
जिनमें से: इक्विटी शेयर	437	516	5,514	5,747	558	536	-90.3
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	2.4	2.3	2.1	2.4	2.9	2.1	
3. लीवरेज अनुपात	5.3	5.7	5.0	4.5	4.2	4.4	

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।

2. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन एक दशमलव बिंदु में किया गया है।

स्रोत: एनबीएफ़सी-डी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.4: एनबीएफसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ऋण

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2020 के अंत में	मार्च 2021 के अंत में	मार्च 2022 के अंत में	सितंबर 2022 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़ 2021-22
1	2	3	4	5	6
I. सकल अग्रिम (II + III)	**2,463,943**	**2,702,618**	**2,908,743**	**2,937,051**	**7.6**
II. खाद्य ऋण	**75**	**-**	**-**	**1,752**	**-**
III. खाद्येतर ऋण (1 से 5)	**2,463,868**	**2,702,618**	**2,908,743**	**2,935,299**	**7.6**
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	**34,448**	**37,728**	**50,422**	46,464	**33.6**
2. उद्योग (2.1 से 2.4)	**958,468**	**1,060,411**	**1,112,852**	**1,115,749**	**4.9**
2.1 सूक्ष्म और लघु	36,441	44,235	46,967	49,966	6.2
2.2 मध्यम	14,077	14,910	17,186	15,103	15.3
2.3 बड़े	795,188	854,546	894,102	899,619	4.6
2.4 अन्य, यदि कोई है, तो विनिर्दिष्ट करें	112,762	146,720	154,598	151,061	5.4
3. सेवाएं (3.1 से 3.10)	**348,901**	**330,758**	**402,935**	**381,485**	**21.8**
3.1 परिवहन परिचालन	63,963	65,313	102,742	90,059	57.3
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,391	1,706	1,659	1,462	-2.7
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	7,035	8,453	7,673	7,177	-9.2
3.4 नौपरिवहन	165	140	172	167	22.9
3.5 पेशेवर सेवाएं	14,664	16,396	20,749	21,592	26.5
3.6 व्यापार	33,864	33,594	49,928	54,951	48.6
3.6.1 थोक व्यापार (खाद्य की खरीद के अलावा)	7,142	6,875	9,538	9,885	38.7
3.6.2 खुदरा व्यापार	26,722	26,719	40,390	45,066	51.2
3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	101,454	80,480	88,123	79,754	9.5
3.8 एनबीएफसी	26,647	28,671	34,292	32,757	19.6
3.9 विमानन	801	948	1,143	1,301	20.5
3.10 अन्य सेवाएं	98,917	95,058	96,455	92,265	1.5
4. खुदरा ऋण (4.1 से 4.10)	**734,795**	**790,073**	**829,485**	**879,571**	**5.0**
4.1 आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त आवास क्षेत्र सहित)	14,071	21,484	23,329	24,680	8.6
4.2 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ	19,171	18,519	24,802	27,464	33.9
4.3 क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि	24,606	25,991	32,710	40,166	25.8
4.4 वाहन/ ऑटो ऋण	332,449	357,338	334,947	354,966	-6.3
4.5 शैक्षणिक ऋण	9,049	9,277	14,264	7,879	53.8
4.6 मीयादी जमाराशि पर अग्रिम (एफसीएनआर(बी), आदि सहित)	44	31	42	213	36.2
4.7 शेयर, बॉण्ड, आदि पर वैयक्तिक अग्रिम	7,940	8,298	12,998	13,398	56.6
4.8 स्वर्ण पर वैयक्तिक अग्रिम	75,451	112,899	118,918	118,723	5.3
4.9 लघु वित्त ऋण/ एसएचजी ऋण	45,107	59,635	74,826	77,567	25.5
4.10. अन्य खुदरा ऋण	206,907	176,600	192,648	214,513	9.1
5. अन्य खाद्येतर ऋण	**387,256**	**483,648**	**513,050**	**512,031**	**6.1**

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन एक दशमलव बिंदु में किया गया है।
3. सीआईसी और पीडी को छोड़कर।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.5 : एनबीएफसी-एनडीएसआई का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020	2021	2022 (पी)	छ1: 2022-23
1	2	3	4	5
ए. कुल आय	**276,203**	**289,157**	**303,831**	**169,696**
(i) निधि आधारित आय	259,320 (93.9)	270,172 (93.4)	281,508 (92.7)	145,440 (85.7)
(ii) शुल्क आधारित आय	8,692 (3.1)	8,233 (2.8)	11,340 (3.7)	7,074 (4.2)
बी. व्यय	**235,021**	**244,869**	**239,645**	**125,955**
(i) वित्तीय व्यय	147,014 (62.6)	144,816 (59.1)	142,896 (59.6)	74,449 (59.1)
जिनमें से, ब्याज का भुगतान	67,730 (28.8)	68,738 (28.1)	67,450 (28.1)	34,705 (27.6)
(ii) परिचालन व्यय	42,258 (18)	39,334 (16.1)	48,479 (20.2)	25,046 (19.9)
(ii) अन्य	45,749 (19.5)	60,719 (24.8)	48,270 (20.1)	26,460 (21)
सी. कर प्रावधान	**12,872**	**11,387**	**15,663**	**7,975**
डी. कर से पहले लाभ	**41,182**	**44,288**	**64,186**	**43,741**
ई. निवल लाभ	**28,310**	**32,901**	**48,523**	**35,766**
एफ. कुल आस्तियां	**2,682,313**	**2,985,943**	**3,288,344**	**3,234,413**
जी. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
(i) आय	10.3	9.7	9.2	10.5
(ii) निधिगत आय	9.7	9.0	8.6	9.0
(iii) शुल्क आय	0.3	0.3	0.3	0.4
(iv) व्यय	8.8	8.2	7.3	7.8
(v) वित्तीय व्यय	5.5	4.8	4.3	4.6
(vi) परिचालन व्यय	1.6	1.3	1.5	1.5
(vii) कर प्रावधान	0.5	0.4	0.5	0.5
(viii) निवल लाभ	1.1	1.1	1.5	2.2
एच. आय के लिए लागत (प्रतिशत)	**85.1**	**84.7**	**78.9**	**74.2**

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. कुल आय में गैर-वित्तीय आय भी शामिल है, जो सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है।
3. मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर।
4. कोष्ठकों में दिये आंकड़े संबंधित कुल का शेयर (प्रतिशत में) है।
5. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन एक दशमलव बिंदु में किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी-एनडीएसआई, आरबीआई की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.6: जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020	2021	2022 (पी)	छ1: 2021-22
1	2	3	4	5
ए. कुल आय	**66,574**	**67,095**	**72,732**	**39,893**
I. निधि आधारित आय	64,278 (96.6)	65,547 (97.7)	70,478 (96.9)	38,411 (96.3)
II. शुल्क आधारित आय	131 (0.2)	107 (0.2)	301 (0.4)	172 (0.4)
बी. व्यय	**51,461**	**55,504**	**55,282**	**27,411**
I. वित्तीय व्यय	27,893 (54.2)	28,386 (51.1)	29,620 (53.6)	14,560 (53.1)
जिसमें से, ब्याज भुगतान	11,620 (22.6)	13,435 (24.2)	15,653 (28.3)	7,289 (26.6)
II. परिचालन व्यय	12,514 (24.3)	11,371 (20.5)	12,983 (23.5)	8,116 (29.6)
III. अन्य	11,054 (21.5)	15,747 (28.4)	12,680 (22.9)	4,735 (17.3)
सी. कर प्रावधान	**4,398**	**2,913**	**4,130**	**3,045**
डी. कर पूर्व लाभ	**15,114**	**11,591**	**17,449**	**12,482**
ई. निवल लाभ	**10,716**	**8,677**	**13,319**	**9,437**
एफ. कुल आस्तियां	**4,86,823**	**5,18,392**	**5,52,577**	**5,83,760**
जी. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
i. आय	13.7	12.9	13.2	13.7
ii. निधि आय	13.2	12.6	12.8	13.2
iii. शुल्क आय	0.0	0.0	0.1	0.1
iv. व्यय	10.6	10.7	10.0	9.4
v. वित्तीय व्यय	5.7	5.5	5.4	5.0
vi. परिचालन व्यय	2.6	2.2	2.3	2.8
vii. कर प्रावधान	0.9	0.6	0.7	1.0
viii. निवल लाभ	2.2	1.7	2.4	3.2
एच. आय के लिए लागत (प्रतिशत)	**77.3**	**82.7**	**76.0**	**68.7**

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. कुल आय में गैर-वित्तीय आय भी शामिल है, जो सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है।
3. कोष्ठकों में दिये आंकड़े संबंधित कुल का शेयर (प्रतिशत में) है।
4. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन एक दशमलव बिंदु में किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी-डी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी VI.7 : वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्थाएं	ऋण*							
	2020-21		2021-22		अप्रै-सितं 2021		अप्रै-सितं 2022	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 4)	6,32,385	523,958	611,600	601,320	197,937	203,381	266,391	266,596
1. नाबार्ड	459,205	349,470	379,618	377,748	118,766	127,551	86,717	90,270
2. सिडबी	96,718	97,542	146,668	145,311	43,206	42,530	144,940	142,478
3. एक्जिम बैंक	36,521	34,122	54,807	52,271	27,603	19,452	20,263	23,561
4. एनएचबी@	39,941	42,824	30,507	25,990	8,362	13,847	14,470	10,286
बी. विशिष्ट वित्तीय	469	457	237	277	174	124	142	111
संस्थाएं (5, 6 तथा 7)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-
6. आईसीआईसीआई वेंचर	469	457	237	277	174	124	142	111
7. टीएफसीआई	13	0.46	0	0	0	0	0	0
सी. निवेश संस्थाएं (8 तथा 9)	13	0.46	0	0	0	0	0	0
8. एलआईसी	0	0	0	0	0	0	0	0
9. जीआईसी	632,867	524,416	611,837	601,597	198,111	203,505	266,533	266,706
डी. वित्तीय संस्थाएं (ए+बी+सी)	6,473	5,497	5,828	4,578	..	..	..	..
ई. राज्य स्तरीय संस्थाएं (10 तथा 11)	6,473	5,497	5,828	4,578	..	..	..	..
10. एसएफसी^	..	..	..	..	..	..	..	..
11. एसआईडीसी	639,340	529,913	617,665	606,176	198,111	203,505	266,533	266,706
एफ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (डी+ई)								

एस: संस्वीकृत, डी: संवितरित, -: शून्य, ..- उपलब्ध नहीं, एनएम: सार्थक नहीं।

*: ऋण में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल है।

@: आंकड़े अप्रैल-मार्च से संबंधित हैं जबकि एनएचबी का वित्तीय वर्ष जुलाई-जून है।

#: अन्य में गारंटी शामिल है।

^ : डेटा दस एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी VI.7: वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्थाएं	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान							
	2020-21		2021-22		अप्रै-सितं 2021		अप्रै-सितं 2022	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	10	11	12	13	14	15	16	17
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 4)	1,631	573	1,871	1,091	350	456	160	579
1. नाबार्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
2. सिडबी	1,631	573	1,871	1,091	350	456	160	579
3. एक्जिम बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0
4. एनएचबी@	0	0	0	0	0	0	0	0
बी. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (5, 6 तथा 7)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. आईवीसीएफ	0	0	0	0	0	0	0	0
6. आईसीआईसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-
7. टीएफसीआई	0	0	0	0	0	0	0	0
सी. निवेश संस्थाएं (8 तथा 9)	123,128	42,182	95,527	38,163	51,327	13,344	43,731	22,844
8. एलआईसी	123,128	42,182	95,527	38,163	51,327	13,344	43,731	22,844
9. जीआईसी	0	0	0	0	0	0	0	0
डी. वित्तीय संस्थाएं (ए+बी+सी)	124,759	42,755	97,398	39,254	51,677	13,799	43,891	23,423
ई. राज्य स्तरीय संस्थाएं (10 तथा 11)	0	0	0	0	..	..	..	..
10. एसएफसी^	0	0	0	0	..	..	..	..
11. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..
एफ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	124,759	42,755	97,398	39,254	51,677	13,799	43,891	23,423

एस: संस्वीकृत, डी: संवितरित, -: शून्य, ..- उपलब्ध नहीं, एनएम: सार्थक नहीं।

*: ऋण में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल है।

@: आंकड़े अप्रैल-मार्च से संबंधित हैं जबकि एनएचबी का वित्तीय वर्ष जुलाई-जून है।

#: अन्य में गारंटी शामिल है।

^ : डेटा दस एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी VI.7: वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्थाएं	अन्य#							
	2020-21		2021-22		अप्रै-सितं 2021		अप्रै-सितं 2022	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	18	19	20	21	22	23	24	25
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 4)	7,071	3,623	14,844	4,623	4,746	2,117	8,530	1,328
1. नाबार्ड	644	552	778	639	155	160	248	152
2. सिडबी	5	-	11	-	1	-	3	-
3. एक्जिम बैंक	6,422	3,071	14,055	3,984	4,590	1,957	8,279	1,176
4. एनएचबी@	-	-	-	-	-	-	-	-
बी. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (5, 6 तथा 7)	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आईवीसीएफ	-	-	-	-	-	-	-	-
6. आईसीआईसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-
7. टीएफसीआई	-	-	-	-	-	-	-	-
सी. निवेश संस्थाएं (8 तथा 9)	200	192	1,829	370	1,350	233	250	118
8. एलआईसी	200	192	1,829	370	1,350	233	250	118
9. जीआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-
डी. वित्तीय संस्थाएं (ए+बी+सी)	7,271	3,815	16,673	4,993	6,096	2,350	8,780	1,446
ई. राज्य स्तरीय संस्थाएं (10 तथा 11)	-	-	-	-	..	..	..	..
10. एसएफसी^	-	-	-	-	..	..	..	..
11.एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..
एफ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	7,271	3,815	16,673	4,993	6,096	2,350	8,780	1,446

एस: संस्वीकृत, डी: संवितरित, -: शून्य, ..- उपलब्ध नहीं, एनएम: सार्थक नहीं।

*: ऋण में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल है।

@: आंकड़े अप्रैल-मार्च से संबंधित हैं जबकि एनएचबी का वित्तीय वर्ष जुलाई-जून है।

#: अन्य में गारंटी शामिल है।

^ : डेटा दस एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी VI.7: वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्थाएं	कुल								प्रतिशत घट-बढ़			
	2020-21		2021-22		अप्रै-सितं 2021		अप्रै-सितं 2022		2021-22		अप्रै-सितं 2022 (वर्ष -दर -वर्ष)	
	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
ए. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (1 से 4)	641,087	528,154	628,315	607,034	203,033	205,953	275,081	268,502	-2.0	14.9	35.5	30.4
1. नाबार्ड	459,849	350,022	380,396	378,387	118,921	127,711	86,965	90,423	-17.3	8.1	-26.9	-29.2
2. सिडबी	98,354	98,115	148,550	146,402	43,558	42,985	145,104	143,057	51.0	49.2	233.1	232.8
3. एक्जिम बैंक	42,943	37,193	68,862	56,255	32,193	21,410	28,542	24,737	60.4	51.3	-11.3	15.5
4. एनएचबी@	39,941	42,824	30,507	25,990	8,362	13,847	14,470	10,286	-23.6	-39.3	73.0	-25.7
बी. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (5, 6 तथा 7)	469	457	237	277	174	124	142	111	-49.4	-39.3	-18.1	-10.9
5. आईवीसीएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	एनएम	एनएम	एनएम	एनएम
6. आईसीआईसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. टीएफसीआई	469	457	237	277	174	124	142	111	-49.4	-39.3	-18.1	-10.9
सी. निवेश संस्थाएं (8 तथा 9)	123,341	42,374	97,356	38,533	52,677	13,577	43,981	22,963	-21.1	-9.1	-16.5	69.1
8. एलआईसी	123,341	42,374	97,356	38,533	52,677	13,577	43,981	22,963	-21.1	-9.1	-16.5	69.1
9. जीआईसी	0	0	0	0	0	0	0	0	एनएम	एनएम	एनएम	एनएम
डी. वित्तीय संस्थाएं (ए+बी+सी)	764,897	570,985	725,908	645,844	255,884	219,654	319,205	291,576	-5.1	13.1	24.7	32.7
ई. राज्य स्तरीय संस्थाएं (10 तथा 11)	6,473	5,497	5,828	4,578	..	..	..	..	-10.0	-16.7	..	..
10. एसएफसी^	6,473	5,497	5,828	4,578	..	..	..	..	-10.0	-16.7	..	..
11. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
एफ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (डी+ई)	771,370	576,482	731,736	650,422	255,884	219,654	319,205	291,576	-5.1	12.8	24.7	32.7

एस: संस्वीकृत, डी: संवितरित, -: शून्य, ..- उपलब्ध नहीं, एनएम: सार्थक नहीं।

*: ऋण में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल है।

@: आंकड़े अप्रैल-मार्च से संबंधित हैं जबकि एनएचबी का वित्तीय वर्ष जुलाई-जून है।

#: अन्य में गारंटी शामिल है।

^ : डेटा दस एसएफसी से संबंधित है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी VI.8: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय प्रदर्शन *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	वर्ष	आय			
			ब्याज आय (बट्टा आय सहित)	व्यापारिक लाभ	अन्य आय	कुल आय
1	2	3	4	5	6	7
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमि.	2020-21	449	173	7	629
		2021-22	600	27	(48)	579
		छ1: 2022-23	365	-61	-21	282
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमि.	2020-21	730	32	16	779
		2021-22	631	29	16	676
		छ1: 2022-23	400	-22	3	381
3	आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमि.	2020-21	999	554	70	1624
		2021-22	846	109	64	1019
		छ1: 2022-23	471	-63	16	425
4	पीएनबी गिल्टस लिमि.	2020-21	779	272	21	1072
		2021-22	971	-137	21	855
		छ1: 2022-23	619	-121	5	503
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राईवेट लिमि.	2020-21	607	-12	54	650
		2021-22	648	-157	19	511
		छ1: 2022-23	345	-66	1	280
6	नोमूरा फिक्सड इनकम सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमि.	2020-21	452	-6	17	462
		2021-22	288	-83	11	216
		छ1: 2022-23	135	-46	1	91
7	गोल्डमैन सेचस (इंडिया) कॅपिटल मार्केट प्राईवेट लिमि.	2020-21	157	-6	19	170
		2021-22	155	-31	24	147
		छ1: 2022-23	106	-17	5	93
8	**कुल**	**2020-21**	**4,173**	**1,008**	**205**	**5,386**
		2021-22	**4,139**	**(244)**	**107**	**4,002**
		छ1: 2022-23	**2,441**	**-396**	**10**	**2,055**

टिप्पणी: सभी राशियां निकटतम करोड़ में पूर्णांकित की गई हैं।

स्रोत: प्राथमिक डीलरों द्वारा प्रस्तुत की गईं विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी VI.8: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय प्रदर्शन *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	प्राथमिक व्यापारी का नाम	वर्ष	व्यय			कर पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ	निवल मूल्य पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)
			ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
1	2	3	8	9	10	11	12	13
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमि.	2020-21	294	28	322	307	228	33.4
		2021-22	415	27	442	137	100	13.3
		छ1: 2022-23	283	16	299	-17	-13	-1.7
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमि.	2020-21	379	42	421	346	251	22.5
		2021-22	336	43	378	191	142	11.5
		छ1: 2022-23	297	21	319	-74	-56	-4.7
3	आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमि.	2020-21	504	118	622	762	569	40.2
		2021-22	472	132	603	444	330	21.4
		छ1: 2022-23	372	67	439	153	114	7.5
4	पीएनबी गिल्टस लिमि.	2020-21	395	41	436	617	464	35.3
		2021-22	510	37	547	210	166	11.9
		छ1: 2022-23	441	22	463	-114	-97	-7.3
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राईवेट लिमि.	2020-21	291	60	350	278	204	11.5
		2021-22	306	55	361	237	178	8.1
		छ1: 2022-23	233	28	261	114	85	3.7
6	नोमूरा फिक्सड इनकम सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमि.	2020-21	204	39	243	217	181	17.3
		2021-22	133	52	184	-4	-4	-0.3
		छ1: 2022-23	89	22	112	86	64	5.7
7	गोल्डमैन सेचस (इंडिया) कॅपिटल मार्केट प्राईवेट लिमि.	2020-21	63	35	98	55	41	6.8
		2021-22	67	39	105	37	25	3.8
		छ1: 2022-23	78	23	102	6	5	0.7
8	**कुल**	2020-21	**2,130**	**364**	**2,493**	**2,582**	**1,938**	**26.0**
		2021-22	**2,238**	**384**	**2,622**	**1,253**	**937**	**11.6**
		छ1: 2022-23	**1,794**	**201**	**1,995**	**153**	**102**	**1.2**

टिप्पणी: सभी राशियां निकटतम करोड़ में पूर्णांकित की गई हैं।

स्रोत: प्राथमिक डीलरों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी VI.9: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राथमिक व्यापारियों के नाम	पूंजी निधि (टिअर I + टिअर II + पात्र टिअर III)					सीआरएआर (प्रति शत)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	छ1: 2022-23	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	छ1: 2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमि.	493	493	731	777	740	23.3	23.0	29.0	32.0	19.5
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमि.	954	1,054	1,245	1,311	1,172	67.0	35.0	33.0	42.0	32.3
3	आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमि.	1,453	1,456	1,723	1,899	1,690	28.0	39.0	44.0	48.0	40.6
4	पीएनबी गिल्टस लिमि.	886	1,043	1,316	1,427	1,241	37.0	34.0	46.0	66.4	22.0
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राईवेट लिमि.	919	1,118	2,105	2,290	2,277	62.0	81.0	51.9	58.5	79.7
6	नोमूरा फिक्सड इनकम सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमि.	797	919	1,077	1,068	1,021	40.0	41.5	60.2	49.0	32.3
7	गोल्डमैन सेचस (इंडिया) कॅपिटल मार्केट प्राईवेट लिमि.	547	582	625	648	630	133.0	170.0	109.2	116.2	74.1
	कुल	**6,049**	**6,665***	**8,822***	**9,420**	**8,771**	**40.7**	**41.9***	**45.4***	**51.6**	**36.4**

टिप्पणी: 1. सभी राशियां निकटतम करोड़ में पूर्णांकित की गई हैं।
2. *: संशोधित आंकड़े।

स्रोत: प्राथमिक डीलरों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी VI.9: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	सरकारी प्रतिभूतियों के स्टॉक और खज़ाना बिल (बाज़ार मूल्य)					कुल आस्तियां (वर्तमान देयताओं और प्रावधानों का निवल)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	छ1: 2022-23	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	छ1: 2022-23
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमि.	8,219	7,151	11,230	13,616	12,794	9,361	8,187	11,423	12,024	10,408
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमि.	4,955	7,892	6,840	12,390	15,691	7,152	11,328	9,958	12,659	15,851
3	आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमि.	7,723	14,748	14,044	15,864	16,989	11,431	15,815	18,099	17,534	16,031
4	पीएनबी गिल्टस लिमि.	6,584	10,664	9,316	15,273	15,409	9,141	13,207	11,190	14,887	13,788
5	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राईवेट लिमि.	9,891	10,821	10,564	13,646	6,916	10,264	11,655	13,029	15,078	8,844
6	नोमूरा फिक्सड इनकम सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमि.	3,938	3,997	2,737	4,849	4,387	5,248	5,704	4,452	5,629	5,568
7	गोल्डमैन सेचस (इंडिया) कॅपिटल मार्केट प्राईवेट लिमि.	2,411	2,616	3,457	3,468	2,119	2,535	3,675	3,836	4,723	2,926
	कुल	43,722	57,888	58,187	79,106	74,306	55,133	69,573	71,986	82,535	73,416

टिप्पणी: सभी राशियां निकटतम करोड़ में पूर्णांकित की गई हैं।

स्रोत: प्राथमिक डीलरों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियां।

स्वामित्व: भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
डॉ. स्नेहल एस. हेरवाडकर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 001 की ओर से मुद्रित व प्रकाशित
तथा ऐक्मे पैक्स एंड प्रिंट्स (इं) प्रा. लि., ए विंग, गाला नं. 73, विरवानी इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगाँव - पूर्व, मुंबई - 400 063 में मुद्रित

Owner: Reserve Bank of India, Mumbai
Printed and Published by Dr. Snehal S. Herwadkar, on behalf of the Reserve Bank of India, Shahid Bhagat Singh Road,
Fort, Mumbai – 400 001 and Printed at ACME Packs & Prints (I) Pvt. Ltd.,
A Wing, Gala No.73, Virwani Industrial Estate, Goregaon - East, Mumbai - 400 063.